मानव संसाधन विकास मंत्रालय

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
1988-89

NIEPA DC
D05410

भाग-I

PART-I

शिक्षा विभाग
DEPARTMENT OF EDUCATION

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

1989

National Institute of Educational
Planning and Administration
Sri Aurobindo Marg, New Delhi-110016
DOC. No. D-5410
Date 13-9-90

Printed at Bengal Offset Works, New Delhi

विषय-सूची

1.	भूमिका	1
2.	प्राक्कथन	3
3.	प्रशासन	7
4.	प्रारम्भिक शिक्षा	10
5.	माध्यमिक शिक्षा	16
	उच्च शिक्षा और अनुसंधान	44
	सातवीं शिक्षा	66
	प्रौढ़ शिक्षा	83
9.	संघ राज्य क्षेत्रों में शिक्षा	91
10.	छात्रवृतियाँ	99
11.	पुस्तक सम्वर्धन और कापीराइट	104
12.	भाषाओं की प्रोन्नति	109
13.	सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम	117
14.	बीस सूत्री कार्यक्रम और सुविधावंचित वर्गों के लिए शिक्षा की सुलभता	118
15.	प्रबंध, मानीटरिंग और मूल्यांकन	120
16.	अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग	125
17.	उपलब्धियां 1985-86 से	132
	– वित्तीय आबंटन	139
	– 1987-88 के दौरान एक लाख रुपये और इससे अधिक आवर्ती सहायता अनुदान प्राप्त करने वाले प्राइवेट और स्वैच्छिक संगठनों के नाम	
	– प्रशासनिक चार्ट	175

प्रकाशन संख्या 1647
PUBLICATION NUMBER 1647

भूमिका

1.1.0. सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बुनियादी कार्यनीतियों में से एक कार्यनीति मानव संसाधन विकास रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में अंत में यह कहा गया है :–

> "सबसे बड़ा काम है शैक्षिक पिरामिड की बुनियाद को सुदृढ़ बनाना, उस बुनियाद को जिसमें इस शताब्दी के अंत तक लगभग सौ करोड़ लोग होंगे। यह सुनिश्चित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि जो इस पिरामिड के शिखर पर हों, वे विश्व में सर्वोत्तम स्तर के हों। अतीत में इन दोनों छोरों को हमारी संस्कृति के मूल-स्रोतों ने भलीभांति सिंचित रखा, लेकिन विदेशी अधिपत्य और प्रभाव के कारण इस प्रक्रिया में विकार पैदा हो गया। अब मानव संसाधन विकास का एक राष्ट्व्यापी प्रयास पुनश्च शुरू होना चाहिये जिसमें शिक्षा अपनी बहुमुखी भूमिका पूर्ण रूप से निभाए।"

1.2.0 राष्ट्रसंघ बाल निधि (यूनिसेफ) 1989 में विश्व के बच्चों की दशा पर अपनी रिपोर्ट में इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि विश्व के कई विकासशील देशों में मानव संसाधन विकास पर पूंजी निवेश में अत्यधिक कमी आई है, सार्वजनिक व्यय पर कटौती के कारण शिक्षा पर प्रति व्यक्ति व्यय में लगभग 50% की गिरावट हुई है; कि राज्यों को कार्यसूची में मानव संसाधन विकास कार्यक्रमों को उच्च प्राथमिकता प्रदान करनी चाहिए; कि वास्तविक विकास पैक्ट" एक न्यू मार्शल योजना" कार्यान्वित की जानी चाहिए जिसके अधीन उन्नत देश विकासशील देशों के लिए वास्तविक संसाधनों तक उनकी पहुंच को पर्याप्त रूप से बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे, और ये देश भी अपनी निवेश-नीतियों को वास्तविक विकास की प्रवृत्ति की ओर पुनः अभिमुख करेंगे ताकि गरीब व्यक्ति को सबसे पहले प्राथमिकता मिले।

1.3.0 मानव संसाधन विकास में शिक्षा, युवा, महिलाओं एवं बच्चों, कलाओं, संस्कृति तथा खेलों के क्षेत्रों में मानवीय क्षमताओं के विकास के लिए समन्वित एवं सर्वतोमुखी प्रयास किये जाने की अपेक्षा की गई है।

1.4.0 रिपोर्ट के निम्नलिखित पांच भागों में, विभिन्न पहलुओं में, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निष्पादन की तस्वीर प्रस्तुत की गई है –:

भाग I	शिक्षा विभाग
भाग II	संस्कृति विभाग
भाग III	कला विभाग
भाग IV	महिला तथा बाल विकास विभाग
भाग V	युवा कार्य तथा खेल विभाग

1.5.1 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के अधीन विभिन्न कार्यक्रमों को कार्यान्वित करते समय, मानव संसाधन विकास संबंधी बातों का ख्याल रखते हुये निम्नलिखित क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान दिया गया :

* प्रारम्भिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण;
* प्रौढ़ साक्षरता जिसमें कौशल विकास तथा मूल्यों का संचार करना शामिल है;
* सुविधाहीन वर्गों–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों तथा महिलाओं के लिए शिक्षा तक पहुंच;
* शिक्षा की विषय-वस्तु तथा प्रक्रिया में सुधार।

1.5.2 उपर्युक्त क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने के लिए निम्नलिखित 3 महत्वपूर्ण कार्य-नीतियां अपनाई गई :— औपचारिक पद्धति से बाहर (चाहे अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों द्वारा अथवा सुदूर शिक्षा द्वारा) शिक्षा तक पहुंच का प्रावधान करना; ग्रामीण निर्धन व्यक्ति के लाभ के लिए—जन शक्ति विकास के लिए, प्रौद्योगिकियों आदि का हस्तांतरण जैसे कि सामुदायिक पालिटेक्निकों की योजना के अधीन और (प्रौढ़ साक्षरता के लिए अर्थात कालेज छात्रों, एन.सी.सी. कैडेट्स, एन.एस.एस. स्वयंसेवकों, भूतपूर्व सैनिकों आदि की सेवाओं का उपयोग करते हुये) शैक्षिक प्रयासों के लिए जन सहयोग प्राप्त करना।

1.6.0 सांस्कृति विभाग ने क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों तथा सहायता संसाधनों के जरिए देश की सांस्कृतिक परम्पराओं के परिरक्षण, संवर्धन तथा समृद्धि के लिए अपने प्रयास जारी रखे। चालू वर्ष के दौरान भारत में सोवियत रूस तथा फ्रांस महोत्सवों का आयोजन, जापान में भारत महोत्सव का प्रारम्भ, बम्बई में अपना उत्सव, देश तथा विदेश में सांस्कृतिक प्रसार के क्षेत्र में प्रमुख उपलब्धियां रही हैं। 56 देशों के साथ सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम तथा 75 देशों के साथ करार भी कार्यान्वित किये जा रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न देशों के लोगों को भारत के लोगों के और निकट आने में सहायता मिली है।

1.7.0 कला विभाग ने इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र (इ.गां.रा.क.के.) के लिए अवस्थापना सुविधाएं स्थापित करने का अपना कार्य लगभग पूरा कर लिया गया। इ.गां.रा.क.के. के पांच प्रमुख प्रभाग अर्थात कला निधि, कला कोश, जनपद सम्पदा, कला दर्शन तथा सूत्रधारा ने केन्द्र के विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों पर अपना ध्यान केन्द्रित किया। केन्द्र के अधीन परिकल्पित प्रमुख गतिविधियां इस प्रकार हैं :—

* सहायता सुविधायें, पुस्तकालय, अभिलेखागारों आदि सहित कला, मानविकी और सांस्कृतिक परम्पराओं से संबंधित डाटा बैंक तथा कम्प्यूटरीकृत राष्ट्रीय सूचना पद्धति का सृजन।
* कलाओं तथा शिल्प कलाओं संबंधी शब्दकोशों, भारतीय कलाओं की पाठ्य पुस्तकों, लेखों के पुनर्मुद्रण, भारतीय कलाओं के विश्वकोशों के बहु-संस्करण इत्यादि के निर्माण के कार्यक्रमों के जरिए मौलिक अनुसंधान।
* लोक तथा जन जातीय कलाओं एवं शिल्प कला का प्रलेखन और
* अंतर-विषयक संगोष्ठियों का आयोजन।

1.8.0 राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (रा.प्र.यो.) 1988-2000 ई. को भावी कार्यनीतियों के आधार के रूप में अंतिम रूप दिया गया ताकि महिलाओं के विकास, विशेष कर महिलाओं के सामाजिक तथा आर्थिक स्तर को ऊपर उठाने के कार्यक्रम पर मुख्य बल दिया जा सके। महिला एवं बाल विकास विभाग ने प्रारम्भिक बाल विकास सेवाएं प्रदान करने को प्राथमिकता देना जारी रखा। एकीकृत बाल सेवाओं का विस्तार कर उसमें वर्ष के दौरान लगभग 2000 परियोजनाएं 0-6 आयु वर्ग के बच्चों तथा गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली महिलाओं के लाभ के लिए शामिल की गई।

1.9.0 विस्तृत विश्व व्यापी परामर्श के बाद नवम्बर, 1988 में युवाओं संबंधी एक राष्ट्रीय नीति संसद के सम्मुख रखी गई। नीति में देश के युवाओं के व्यक्तित्व तथा कार्यात्मक क्षमताओं के विकास के लिए अवसर पैदा करने की परिकल्पना की गई है। देश के विभिन्न भागों में आयोजित सामूहिक राष्ट्रीय एकता शिविरों ने युवाओं में राष्ट्रीय एकता की भावना को सर्वोपरि बनाये रखने में सहायता की। नेहरू युवक केन्द्र संगठन ने अपने कार्यकलापों का विस्तार किया हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण (भा.प्रा.) 1990 में बीजिंग में होने वाले एशियाई खेलों के लिए खिलाड़ियों के प्रशिक्षण पर ध्यान दे रहा है। दक्षिण ध्रुव अंतर्राष्ट्रीय स्की अभियान जैसे उत्साही कार्यक्रम, भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा प्रतिभा की खोज, खेल-कूद कार्यकलापों के लिए अवस्थापना सुविधायें, खेल-कूद परियोजना विकास क्षेत्र योजना का आरम्भ करना, युवा कार्य तथा खेल विभाग की अन्य प्रमुख उपलब्धियां रही हैं। भारत के संविधान में भी खेल-कूद को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में रखते हुये राज्य सभा में संविधान (61वां) संशोधन विधेयक 1988 पुरःस्थापित करके भारत सरकार ने स्वयं को खेलों में और अधिक मात्रा में शामिल करने का प्रयास किया है।

प्राक्कथन

निधियों का आबंटन और उनका उपयोग

2.1.0 वर्ष 1987-88 के दौरान शिक्षा विभाग के लिए कुल बजट आवंटन 1,211 करोड़ रुपये (800 करोड़ रुपये योजनागत के अंतर्गत, 386 करोड़ रुपये योजनेतर (बी.ए.डी.पी. के अंतर्गत) के लिए था। सम्पूर्ण आवंटन खर्च हो गया है। सभी योजनागत कार्यक्रम राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के पूरे सहयोग से, परियोजनोन्मुख आधार पर तैयार किये गये, और कार्यान्वित किए गए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के संदर्भ में कार्यान्वित सभी योजनाओं के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रगति हुई। इन योजनाओं में प्रमुख हैं:- आपरेशन ब्लैक बोर्ड, अनौपचारिक शिक्षा, अध्यापक शिक्षा की पुर्नसरचना और पुनर्गठन, शिक्षा का व्यावसायीकरण, नवोदय विद्यालय, शिक्षा प्रौद्योगिकी, स्कूलों में विज्ञान शिक्षण, प्रौढ़ शिक्षा, सुदूर शिक्षा, और तकनीकी शिक्षा की पुरानी और अनुपयुक्त प्रणालियों को हटा कर इसका आधुनिकीकरण।

2.2.0 वर्ष 1988-89 के लिए 1595 करोड़ रुपये (800 करोड़ रुपये योजनागत, 45 करोड़ रुपये सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत और 750 करोड़ रुपये योजनेत्तर के तहत) की धनराशि आवंटित की गई थी।

2.3.0. विभिन्न कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान दिया गया।

* राज्य और केन्द्र सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों की राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समितियों के जरिए मन्जूरी पत्रों को जारी करना (इससे परिहार्य पत्र व्यवहार को दूर करने, निर्णयों में शीघ्रता लाने और प्रस्तावों की सावधानीपूर्वक जांच में सहायता मिली है)
* राष्ट्र स्तरीय सम्मेलनों में राज्य के शिक्षा सचिवों और निदेशकों के साथ बार-बार मध्यावधि परामर्श,
* केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड और इसकी समितियों की बैठकों में मध्यावधि परामर्श और समीक्षाएं।

प्रारम्भिक शिक्षा

2.4.1 सातवीं योजना और राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के परिप्रेक्ष्य और कार्यनीतियों के अनुरूप प्रारंभिक शिक्षा पर विशेष बल दिया गया। 800 करोड़ रुपये के कुल योजनागत आवंटन में से चालू वर्ष के लिए प्रारम्भिक शिक्षा हेतु 233.40 करोड़ रुपये का आवंटन है जो कि कुल राशि का 29% बैठता है। वर्ष 1987-88 के दौरान प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वसुलभ बनाने के अभियान में निम्नलिखित उपलब्धियां रहीं:

* आपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता - 27 राज्य संघ राज्य क्षेत्र
* लाभान्वित स्कूलों की संख्या 1.13 लाख (देश के स्कूलों का 21.43)
* शिक्षकों के अतिरिक्त स्वीकृत पदों की संख्या - 37000
* अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के तहत लाभान्वित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की संख्या - 15
* स्वीकृत अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों की संख्या - 1.85 लाख
* स्कूल शिक्षकों के व्यापक प्रशिक्षण के तहत प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या - 4.55 लाख

* स्वीकृत, पुनर्गठित शिक्षक संस्थानों की संख्या - 116
(101 डी.आई.ई.टी., 8 सी.टी.ई.एस. और 7 आई.ए.एस.आई.)

2.4.2 वर्ष 1988-89 के दौरान उपरोक्त कार्य-कलापों का दूसरा चरण पूरे जोर से चल रहा है। इन कार्यकलापों से इस दिशा में एक चेतना पैदा हुई है और प्राथमिक विद्यालायों में कम से कम न्यूतम अवस्थापना उपलब्ध करवाने, औपचारिक स्कूलों में न जाने वाले, बच्चों के दरवाजों तक शिक्षा पहुंचाने और शिक्षा प्रणाली के व्यावसायीकरण को दिशा प्राप्त हुई हैं।

2.4.3 प्रारम्भिक शिक्षा के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में केन्द्र और राज्यों द्वारा किए गए निवेशों से ठोस परिणाम प्राप्त करने के उद्देश्य से एक नई मानीटरिंग प्रणाली स्थापित करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। यह प्रणाली प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने की दिशा में हुई प्रगति का मूल्यांकन कर सकेगी।

2.4.4 केन्द्रीय क्षेत्र में शिक्षा के लिए अपेक्षित संसाधनों के संबंध में शिक्षा विभाग ने मई, 1988 में नौवें वित्त आयोग को एक विवरण प्रस्तुत किया था। आयोग द्वारा वर्ष 1989-90 की अपनी रिपोर्ट में (शैक्षिक रूप से पिछड़े दस राज्यों में स्कूल भवनों की व्यवस्था के लिए)। प्रारम्भिक शिक्षा हेतु 200 करोड़ रुपये के आवंटन की सिफारिश की है। इसके अलावा उन्होंने 12 राज्यों में शिक्षा क्षेत्र के स्तर ऊंचे करने के लिए 41.92 करोड़ रुपये के आवंटन की भी सिफारिश की है।

माध्यमिक शिक्षा

2.5.1 माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा को कार्य-जगत से जोड़ने, विज्ञान-शिक्षण शिक्षा, प्रौद्योगिकी के प्रयोग और ग्रामीण प्रतिभाशाली बच्चों के लिए विशेष प्रयास करने पर बल दिया गया है। उपरोक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यान्वित योजनाओं अर्थात् शिक्षा का व्यावसायीकरण, विज्ञान-शिक्षण के सुदृढ़ीकरण, शिक्षा प्रौद्योगिकी और नवोदय विद्यालयों के संबंध में वर्ष 1987-88 में प्राप्त सार्थक प्रगति की रफ्तार वर्ष 1988-89 के दौरान भी जारी रही।

2.5.2 माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में वर्ष 1987-88 के दौरान विशिष्ट उपलब्धियां निम्नलिखित हैं:-

* 1000 स्कूलों में 3100 व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए 18 राज्यों को सहायता दी गई,
* विज्ञान शिक्षा के लिए 18 राज्यों को सहायता दी गई (6,900 स्कूलों की प्रयोगाशालाओं का स्तर बढ़ाने, 8,900 स्कूलों के पुस्तकालयों के विकास हेतु यह 80 जिला संसाधन केन्द्रों की स्थापना के अतिरिक्त हैं),
* 6-11 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए, मुख्य रूप से सप्ताह में पांच दिन शिक्षा कार्यक्रमों का 45 मिनट का इन्सेट प्रसारण, हिन्दी, उड़िया, तेलुगु, मराठी और गुजराती में।
* 13 राज्यों के स्कूलों में वितरण के लिए 10,000 से अधिक टी.वी. सेट और 37,000 टू-इन-वन-रेडियो-कैसेट प्लेयर उपलब्ध करवाये गये,
* 34,000 से भी अधिक ग्रामीण प्रतिभाशाली बच्चों को लाभान्वित करते हुये देश के विभिन्न भागों में 256 नवोदय विद्यालयों की शुरूआत।

2.5.3 नवोदय विद्यालयों के बच्चों से संबंधित आंकड़ों के विश्लेषण से निम्नलिखित तथ्य स्पष्ट हो जाते है:

* ग्रामीण बच्चे	79%
* अनुसूचित जाति के बच्चे	18%
* अनु. जनजाति के बच्चे	12%
* गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों के बच्चे	41%
* 12,000 रुपये की वार्षिक आय से कम आय वाले परिवारों के बच्चे	63%

उच्च शिक्षा

2.6.1 उच्च शिक्षा के क्षेत्र में दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। जनवरी, 1989 की स्थिति के अनुसार इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय खुले विश्वविद्यालय के विभिन्न डिग्री, डिप्लोमा तथा प्रमाण पत्र स्तरीय पाठ्यक्रमों में 54,000 छात्र नामांकित थे। अब इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला वि.वि. अपने 12 क्षेत्रीय केन्द्रों तथा 112 अध्ययन केन्द्रों के नेटवर्क के माध्यम से सिक्किम, पाण्डिचेरी तथा लक्षद्वीप के अलावा सभी राज्य व संघ शासित क्षेत्रों को लाभ पहुंचा रहा है।

2.6.2 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विभिन्न कार्यक्रमों के तहत 100 विश्वविद्यालयों तथा 4500 से अधिक कालेजों को विभिन्न प्रयोजनों के लिए सहायता प्रदान की गई। 92 कालेजों के संबंध में स्वायत्त स्तर के लिए मंजूरी दे दी गई है। अधिकांश राज्यों द्वारा शिक्षकों के संशोधित तथा परिवर्तित वेतनमानों का

कार्यन्वयन शुरू कर दिया गया है। राज्य शिक्षकों की सेवा-शर्तों में सुधार की योजना के अभिन्न अंग के रूप में कार्य-मूल्यांकन तथा सतत् शिक्षा शुरू हो गई हैं। विश्वविद्यालय तथा कालेज शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए 48 अकादमिक स्टाफ कालेज स्थापित हो चुके हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा बहुत से उच्च अध्ययन केन्द्रों तथा अनुसंधान विकास तथा उत्कृष्टता केन्द्रों के संवर्धन के लिए विश्वविद्यालय विभागों को सहायता दी गई।

प्रौढ़ शिक्षा

2.7.1 राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का कार्यान्वयन पूरे जोरों पर है। 2.71 लाख प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र चल रहे हैं जिनमें 81 लाख प्रौढ़ छात्र पढ़ रहे हैं। इस काम में 500 से अधिक स्वैच्छिक एजेन्सियों का सहयोग लिया जा रहा है। नवसाक्षरों को सतत शिक्षा प्रदान करने के लिए 14,000 जन शिक्षण निलयम कार्यरत हैं।

2.7.2 प्रधान मंत्री महोदय, द्वारा मई, 1988 में व्यापक प्रेरणा अभियान प्रारम्भ किया गया। तमिलनाडु, केरल तथा गुजरात के कुछ जिलों में "आपरेशन साक्षरता-1991 की जनगणना तक" नामक एक विशेष कार्यक्रम भी प्रारम्भ किया गया। इस कार्यक्रम को अन्य राज्यों तथा 10 महानगरों में शुरू करने के प्रयास किये जा रहे हैं। बढ़िया ब्लैकबोर्डों, स्लेटों तथा धूलरहित चॉकों, प्रकाश के लिए सौर ऊर्जा पैकों, संगणकीकृत प्रबंध सूचना प्रणाली, द्रुतगामी साक्षरता पद्धतियों के प्रयोग आदि जैसे महत्वपूर्ण तकनीकी एवं शैक्षिक साधनों की सहायता से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के कार्यक्रम को एक उल्लेखनीय बल प्राप्त हुआ हैं।

तकनीकी शिक्षा

2.8.1 तकनीकी शिक्षा के सुनियोजित विकास तथा स्तरों के समन्वित अनुरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए अखिल-भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् को ए आई सी टी ई अधिनियम द्वारा सांविधिक बल प्रदान किया गया है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा पाठ्यक्रमों व संस्थाओं, शुल्क व प्रवेश संबंधी दिशा-निर्देशों, राज्य निदेशालयों के लिए माडलों आदि के संबंध में अपने विनियम नीतियां तथा स्तर निश्चित किये गये हैं। अखिल भा. तक. शि. परिषद् द्वारा नए संस्थानों/पाठ्यक्रमों को शुरू करने के लिए प्राप्त 89 प्रस्तावों में से 39 को मंजूरी दी गई है।

2.8.2 ध्यान केन्द्रित करने के लिए तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत से महत्वपूर्ण क्षेत्र निर्धारित किये गये हैं। 10,000 से अधिक प्रयोगशाला आधुनिकीकरण के लिए निर्धारित की गई हैं। वर्ष 1987-88 के दौरान आधुनिकीकरण व महत्वपूर्ण क्षेत्र विकास के लिए 700 से अधिक परियोजनाओं को मंजूरी दी गई तथा वर्ष 1988-89 में भी इतनी ही परियोजनाओं को मंजूरी दिए जाने की आशा है।

2.8.3 ग्रामीण समुदाय को महत्वपूर्ण लाभ पहुंचाने के लिए सामुदायिक पालिटेक्निकों ने सेवाएं प्रदान करना शुरू कर दिया है। आज तक 109 सामुदायिक पालिटेक्निक कार्यरत हो चुके हैं। अब तक इनमें 94,000 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इन पालिटेक्निकों द्वारा 3000 से अधिक गांवों को तकनीकी सेवायें प्रदान की गई हैं।

पहले से चल रहे अन्य कार्यक्रम

2.9.0 शिक्षा की विषय वस्तु तथा प्रक्रिया में सुधार, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति, अल्पसंख्यकों तथा महिलाओं तक शिक्षा को पहुंचाने, भारत के अन्दर तथा विदेशों में रह रहे पात्र व्यक्तियों को छात्रवृत्तियां प्रदान करने तथा पुस्तक संवर्धन एवं भाषाओं के विकास से संबंधित पहले से चले आ रहे कार्यक्रमों को जारी रखा गया।

संगणकीकरण

2.10.0 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 तथा कार्रवाई योजना में की गई परिकल्पना के अनुसार तथा शिक्षा के विकास के लिए किये जा रहे अखिल भारतीय प्रयासों के अनुरूप राष्ट्रीय सूचना केन्द्र की सहायता से शिक्षा विभाग में कार्य निर्वाह के साथ-साथ प्रबंध सूचना के लिए संगणकीकरण का काम उल्लेखनीय रूप से शुरू कर दिया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

2.11.0 वर्ष के दौरान भारत द्वारा यूनेस्को की तीसरी माध्यावधि योजना तैयार करने के लिए विभिन्न स्तरों पर आयोजित चर्चाओं में सक्रिय रूप से भाग लिया गया। यूनेस्को के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग द्वारा किये गये कार्य में से अन्य उल्लेखनीय कार्य है:

अक्तूबर, 1988 में नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष संबंधी क्षेत्रीय कार्यदल की बैठक तथा दिसम्बर, 1988 में नई दिल्ली में, विकासशील देशों के बीच तकनीकी सहयोग (टी सी डी सी) बढ़ाने के लिए आयोजित उप-क्षेत्रीय संगोष्ठी। यूनेस्को के महा-निदेशक श्री फ्रेडरिको मेयर द्वारा दिसम्बर, 1988 में भारत की यात्रा की गई तथा उन्होंने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया। उन्होंने मानव संसाधन विकास मंत्री तथा प्रधान मंत्री जी से भी भेंट की।

प्रशासन

संगठनात्मक संरचना

3.1.1 शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक अंग है और मानव संसाधन विकास मंत्री के समग्र कार्य प्रभार के अधीन राज्य मंत्री इसके कार्य प्रभारी हैं। सचिव इस विभाग के सचिवालय प्रमुख है, उनकी सहायता के लिए एक अपर सचिव तथा शिक्षा सलाहकार (तकनीकी) हैं। इस विभाग में अनेक ब्यूरो, प्रभाग, डेस्क, अनुभाग तथा एकक हैं। प्रत्येक ब्यूरो के प्रभारी एक संयुक्त सचिव/संयुक्त शिक्षा सलाहकार हैं और उनकी सहायता प्रभागाध्यक्षों द्वारा की जाती है। विभाग का संगठनात्मक स्वरूप रिपोर्ट के साथ संलग्न प्रशासनिक चार्ट में दर्शाया गया है।

अधीनस्थ कार्यालय स्वायत्त संगठन

3.1.2 पिछले अनेक वर्षों के दौरान इस विभाग के अधीन बहुत से अधीनस्थ कार्यालय तथा संगठन बने हैं। उच्च शिक्षा के स्तरों के निर्धारण एवं समन्वय के लिए संसद द्वारा पारित एक अधिनियम के अंतर्गत 1956 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई थी। इसके अतिरिक्त, विशिष्ट जिम्मेदारियां निभाने के लिए अनेक संगठन स्थापित किए गए हैं। इनमें से एक है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद जो समूचे देश में स्कूली शिक्षा के गुणवत्ता संबंधी पक्ष को बेहतर बनाने की दिशा में प्रयत्नशील हैं। अन्य महत्वपूर्ण संगठन हैं:-

- राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली।
- भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला।
- भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली।
- भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली।
- भारतीय दर्शन अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली।
- केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली।
- नवोदय विद्यालय समिति, नई दिल्ली।
- केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली।
- केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर।
- केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा।
- केन्द्रीय अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा संस्थान, हैदराबाद।
- केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, नई दिल्ली।
- वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, नई दिल्ली।
- राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली।
- राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली।
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय, नई दिल्ली।

तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में हैं:- भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर भारतीय खान स्कूल, धनबाद; राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, बंबई; राष्ट्रीय ढलाई तथा गढ़ाई प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची; आयोजना और वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली; भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कालेज, हैदराबाद; अहमदाबाद, बंगलौर, कलकत्ता और लखनऊ स्थित चार भारतीय प्रबंध संस्थान; भोपाल, कलकत्ता, चण्डीगढ़ और मद्रास स्थित चार तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान; बंबई, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर और मद्रास स्थित पांच भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान; और देश भर में फैले सत्रह क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज।

कार्य :

3.2.0 शिक्षा विभाग के मुख्य कार्य हैं : सभी पहलुओं से शिक्षा नीति का विकास और उच्च शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा के स्तरों का निर्धारण तथा समन्वय; कापीराइट अधिनियम लागू करना; पाठ्य-पुस्तकों की कोटि में सुधार; छात्रवृत्तियों तथा अन्य योजनाओं का संचालन; यूनेस्को के साथ सहायता कार्यक्रमों तथा अन्य कार्यकलापों का समन्वय; सामाजिक विज्ञानों में अनुसंधान का प्रोत्साहन तथा समन्वय; संस्कृत तथा अन्य प्राचीन भाषाओं में अध्ययन और अनुसंधान का विकास और संवर्धन;· अनौपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में कार्यकलापों को बढ़ावा देना; और प्रौढ़ शिक्षा की प्रोन्नति।

सतर्कता कार्यकलाप

3.3.1 वर्ष के दौरान, दो अधिकारियों के विरुद्ध (जिनमें एक राजपत्रित अधिकारी) अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई। इसके अतिरिक्त तीन राजपत्रित अधिकारियों (जिनमें से दो कर्मचारी अधीनस्थ कार्यालयों के थे) और एक अराजपत्रित अधिकारी के विरुद्ध जो अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई थी, वह अभी चल रही है।

3.3.2 शिक्षा विभाग के संलग्न 48 स्वायत्त संगठनों/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में से 39 ने अब तक केन्द्रीय सतर्कता के परामर्शी क्षेत्राधिकार को स्वीकार कर लिया है। 18 संगठनों में मुख्य सतर्कता अधिकारी नियुक्त किए जा चुके हैं जबकि शेष संगठनों में मुख्य सतर्कता अधिकारी की नियुक्ति के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। मुख्य सतर्कता अधिकारियों/शिक्षा विभाग से सम्बद्ध स्वायत्त संगठनों में सतर्कता से संबंधित कार्य संचालन करने वाले अधिकारियों का एक सम्मेलन 24 अक्तूबर, 1988 को आयोजित किया गया, जिसमें सभी सतर्कता अधिकारियों ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग के क्षेत्राधिकार को स्वीकार कर लिया। इस सम्मेलन में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी किए गए भ्रष्टाचार विरोधी तरीकों से कार्यवाई योजना के प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता पर बल दिया गया।

3.3.3 अनुशासन और समय-निष्ठा (पाबन्दी) के अनुपालन पर जोर दिया गया।

सरकारी काम काज में हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

3.4.1 आलोच्य वर्ष के प्रारम्भ में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 1988-89 का वार्षिक कार्यक्रम विभाग में तथा इसके अधीनस्थ कार्यालयों/स्वायत्त संगठनों/संस्थाओं आदि में इस अनुरोध के साथ परिचालित किया गया कि इस कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की भरसक कोशिश की जाए और इसकी प्रगति की समीक्षा विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में नियमित रूप से की जाए।

3.4.2 विभाग के 82 अनुभागों, 9 अधीनस्थ कार्यालयों और 70 स्वायत्त संगठनों में राजभाषा अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों, विनियमों एवं प्रशासनिक आदेशों के अनुपालन की स्थिति पर हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्टों के माध्यम से नज़र रखी गई। इनसे उक्त रिपोर्ट नियमित रूप से मंगवाई जाती रही और विभाग में उसकी समीक्षा की गई और उसमें पाई गई कमियों को दूर करने के लिए संबंधित कार्यालयों के ध्यान में लाया गया।

3.4.3 मानव संसाधन विकास मंत्रालय में पहले सभी विभागों की एक ही संयुक्त हिन्दी सलाहकार समिति थी। अब राजभाषा विभाग के निर्देशों के अनुसार शिक्षा विभाग की पृथक हिन्दी सलाहकार समिति गठित की गई है।

3.4.4 इस विभाग की अपनी राजभाषा कार्यान्वयन समिति भी है। आलोच्य वर्ष के दौरान इसकी तीन बैठकें हुईं। यह बहुत बड़ा विभाग होने के फलस्वरूप राजभाषा नियमों की जानकारी अनुभाग स्तर तक देने के लिए और उस स्तर पर हिन्दी के प्रयोग में आने वाली कठिनाइयों का पता लगाने और उनके निराकरण ढूंढने के लिए प्रत्येक प्रभागाध्यक्ष को प्रत्येक प्रभाग की अलग-अलग राजभाषा कार्यान्वयन समिति बनाने का अनुरोध किया गया। तदनुसार अब अधिकांश प्रभागों ने अपनी-अपनी राजभाषा कार्यान्वयन समितियां बना ली हैं और उनकी बैठकें भी हो रही हैं। शेष प्रभागों से भी यह समितियां शीघ्र बनाने का अनुरोध किया गया हैं।

3.4.5 नोटिंग/ड्राफ्टिंग में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए और हिन्दी का प्रयोग करने में कर्मचारियों की झिझक दूर करने के लिए दो हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। इसके अलावा, समेकित प्रशासनिक शब्दावली और बार-बार प्रयोग में आने वाले प्रशासनिक वाक्यांशों की सूचियां भी सभी

अनुभागों/अधिकारियों को उपलब्ध कराई गईं।

3.4.6 संसदीय राजभाषा समिति के सम्मुख आलोच्य वर्ष में 17.9.1988 को शिक्षा सचिव का मौखिक साक्ष्य हुआ और इस विभाग के कामकाज में हिन्दी के प्रयोग की स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए संसदीय राजभाषा समिति की पहली उप समिति ने 13.1.1989 को इस विभाग का निरीक्षण किया।

3.4.7 आलोच्य वर्ष के दौरान राजभाषा विभाग के हिन्दी शिक्षण योजना केन्द्रों में हिन्दी के विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए सैंत्तीस कर्मचारियों को नामित किया गया। दो क्लर्कों को हिन्दी टाइपिंग तथा छः स्टेनोग्राफरों को हिन्दी शॉर्ट-हैंड ट्रेनिंग के लिए भेजा गया।

3.4.8 राजभाषा संबंधी आदेशों आदि के अनुपालन की स्थिति का जायजा लेने के लिए तथा हिन्दी के प्रयोग में आने वाली कठिनाइयों का पता लगाने के लिए इस विभाग में एक निरीक्षण दल गठित किया गया और इस दल ने ग्यारह कार्यालयों का निरीक्षण किया। निरीक्षण दल द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट पर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने संबंधित कार्यालयों के प्रमुखों से चर्चा की और इस संबंध में आने वाली कठिनाइयों का समाधान किया।

3.4.9 इस विभाग द्वारा 14 सितम्बर से 20 सितम्बर 1988 तक हिन्दी सप्ताह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मानव संसाधन विकास मंत्री जी की ओर से सन्देश, शिक्षा एवं संस्कृति मंत्री जी की ओर से अपील और शिक्षा सचिव महोदय की ओर से निर्देश जारी किए गए।

3.4.10 आलोच्य वर्ष के दौरान विभाग के नौ (9) कार्यालयों को राजभाषा नियम 1976 के नियम 10(4) के अधीन अधिसूचित किया गया। इसके लिए इस विभाग के लगभग 45 विषयों को राजभाषा नियम 1976 के नियम 8(4) के अधीन विनिर्दिष्ट करने का निर्णय किया गया है।

प्रकाशन

3.5.1 प्रकाशन एकक ने वर्ष 1988-89 के दौरान, द्विभाषी (अंग्रेजी और हिन्दी शीर्षक सहित) अंग्रेजी में कुल 45 प्रकाशन और एक त्रैमासिक पत्रिका "दि एज्यूकेशन क्वार्टरली" प्रकाशित किये। "दि एज्यूकेशन क्वार्टरली" नामक पत्रिका के प्रकाशन का यह 40वां वर्ष है। केन्द्र तथा राज्यों में "शैक्षिक विकास" संबंधी मासिक सारांश प्रत्येक माह हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में निकाला जाता है जिसका सीमित परिचालन होता है। इसके अतिरिक्त, इस एकक ने आई.एन.सी. न्यूजलैटर भी प्रकाशित किया।

3.5.2 हिन्दी प्रकाशन एकक ने इस अवधि के दौरान दो त्रैमासिक पत्रिकाओं "शिक्षा-विवेचन" और "संस्कृति" सहित 15 प्रकाशन निकाले। इसके अतिरिक्त, यह एक "यूनेस्को न्यूजलैटर" का हिन्दी रूपान्तर भी प्रकाशित करता है।

3.6.0. वर्ष 1987-88 के दौरान विदेश भेजे गए सरकारी अधिकारियों तथा गैर-सरकारी व्यक्तियों के शिष्टमंडल/प्रतिनिधि मंडल

शिष्टमंडलों/ प्रतिनिधि मंडलों की संख्या	प्रतिनिधि मंडलों/ शिष्टमंडलों में शामिल व्यक्तियों की संख्या	कुल खर्च (रुपयों में)	विदेशी मुद्रा घटक (रुपयों में)
63	103	28,62,677.00	19,45,795.00

बजट अनुमान

3.7.0 शिक्षा विभाग के संबंध में वर्ष 1988-89 और 1989-90 के लिए बजट-प्रावधान निम्नवत हैं :-

(रुपये लाखों में)

	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	बजट अनुमान
	1988-89	1988-89	1989-90
ब्यौरे	158486.00	160415.00	158142.00

मांग संख्या 48

शिक्षा विभाग

निम्नलिखित के लिए प्रावधान :-
मंत्रालय का सचिवालय जिसमें वेतन और लेखा कार्यालय तथा स्वागत और मनोरंजन भी शामिल हैं सामान्य शिक्षा-विभाग के अन्य राजस्व खर्च जिसमें केन्द्रीय/केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान सहायता देने का प्रावधान है तथा केन्द्रीय एवं केन्द्र प्रायोजित योजनाओं हेतु ऋण का प्रावधान भी शामिल है।

प्रारम्भिक शिक्षा

प्रारंभिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण

4.1.1 प्रारम्भिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण शैक्षिक विकास का बुनियादी लक्ष्य है। यह बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था से संबंधित है। राज्य की नीति के निदेशक तत्वों (संविधान का अनुच्छेद 45) में निर्धारित किया गया है। निश्चित शब्दों में इसमें कहा गया है कि "राज्य इस संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की अवधि के शुरू में सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए प्रबंध करने का प्रयास करेगा।"

4.1.2 देश के बहुत से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के लिए कानून बना लिये गए हैं। बहुत अधिक संख्या होने और सामाजिक-आर्थिक विविधताओं के कारण बच्चों को स्कूल से दूर रखा गया है। इसलिए इन कानूनों में दंड व्यवस्था लागू करना मुश्किल है।

4.1.3 यद्यपि प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति अभी भी संभव नहीं हुई है, फिर भी, सभी क्षेत्रों में सामान्य तौर पर शिक्षा संबंधी वृद्धि में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।

शिक्षा में वृद्धि

4.2.1 वर्ष 1950-51 से शिक्षा संस्थाओं की संख्या, शिक्षा स्तर के अनुसार छात्रों की संख्या (नामांकन), शिक्षा स्तरों के अनुसार बालिकाओं का नामांकन, शिक्षकों की संख्या की दृष्टि से शिक्षा की वृद्धि बाद में दिए गए चार्टों में दर्शाई गई है :–

5वें अखिल भारतीय शिक्षा सर्वेक्षण के निष्कर्ष

4.2.2 चौथे अखिल भरतीय शिक्षा सर्वेक्षण (1978) के समय प्राप्त स्थिति की तुलना में पांचवें अखिल भारतीय सर्वेक्षण (1986) के निष्कर्ष के अनुसार शिक्षा में हुई वृद्धि नीचे दी गई है:–
– नामांकन और शिक्षकों की संख्या में वृद्धि नीचे दी गई है :–

नामांकन में वृद्धि	सभी क्षेत्रों में	ग्रामीण क्षेत्रों में	अनुसूचित जातियों में	अनुसूचित जन-जातियों में
1	2	3	4	5
प्राथमिक स्तर	26 प्रतिशत	28.6 प्रतिशत	49 प्रतिशत	62 प्रतिशत
उच्चतर प्राथमिक स्तर	51 प्रतिशत	62.3 प्रतिशत	102 प्रतिशत	126 प्रतिशत
माध्यमिक स्तर	63 प्रतिशत	80.8 प्रतिशत	121 प्रतिशत	124 प्रतिशत
उच्चतर माध्यमिक स्तर	88 प्रतिशत	127.5 प्रतिशत	132 प्रतिशत	185 प्रतिशत

बलिकाओं के
नामांकन में वृद्धि

प्राथमिक स्तर	36 प्रतिशत	92 प्रतिशत
उच्चतर प्राथमिक स्तर	64 प्रतिशत	87 प्रतिशत
माध्यमिक स्तर	74 प्रतिशत	87 प्रतिशत
उच्चतर माध्यमिक स्तर	132 प्रतिशत	329 प्रतिशत

शिक्षकों की
संख्या में वृद्धि

प्राथमिक स्तर	17 प्रतिशत
उच्चतर प्राथमिक स्तर	24 प्रतिशत
माध्यमिक स्तर	49 प्रतिशत
उच्चतर माध्यमिक स्तर	62 प्रतिशत

- 300 या इससे अधिक जनसंख्या की 32,000 बस्तियों को अभी एक किलोमीटर की दूरी के अन्दर प्राथमिक स्कूल की सुविधा प्रदान की जानी है।
- 13.5 प्रतिशत प्राइमरी स्कूल और 4 प्रतिशत उच्चतर प्राथमिक स्कूल अभी भी किसी प्रकार के बिना भवन के हैं।
- प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या निम्न प्रकार है :–

प्राथमिक और उच्चतर प्राथमिक स्तर	13 प्रतिशत
माध्यमिक स्तर	10 प्रतिशत
उच्चतर माध्यमिक स्तर	11 प्रतिशत

स्रोत : रा.शै.अनु.प्र. परिषद

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के अधीन सर्वसुलभीकरण प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य

4.3.1 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 बनाते समय शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त प्रगति की समीक्षा की गई थी और उसका मूल्यांकन किया गया था। जहां तक प्राथमिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण का संबंध है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के लक्ष्यों को निम्न प्रकार कहा गया है :-

एक संकल्प

नई शिक्षा नीति में स्कूल छोड़ जाने वाले बच्चें की समस्या को सुलझाने को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। बच्चों को बीच में स्कूल छोड़ने से रोकने के लिए स्थानीय परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में, इस समस्या का बारीकी से अध्ययन किया जाएगा और तदनुसार प्रभावशाली उपाय खोज कर दृढ़ता के साथ उनके प्रयोग हेतु देशव्यापी योजना बनाई जाएगी। इस प्रयत्न का अनौपचारिक शिक्षा कीं व्यवस्था के साथ पूरा तालमेल होगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि 1990 तक जो बच्चे 11 वर्ष के हो जाएंगे, उन्हें विद्यालय में 5 वर्ष की शिक्षा याअनौपचारिक धारा में इसके समतुल्य शिक्षा अवश्य मिल जाए। इसी प्रकार 1985 तक 14 वर्ष की अवस्था वाले सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अवश्य दी जाएगी।"

4.3.2 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के अनुरूप प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में जैसा कि नीचे के पैरों में कहा गया है, सार्थक कार्यक्रम तैयार किया गया और उसका कार्यान्वयन किया गया।

4.3.3 आपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना का मुख्य उद्देश्य सरकार, स्थानीय निकायों, पंचायती राज और मान्यता प्राप्त तथा सहायता प्राप्त संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे प्राथमिक स्कूलों में सुविधाओं में पर्याप्त सुधान लाना है। इसके तीन परस्पर आश्रित घटक हैं अर्थात्

- ऐसे भवन की व्यवस्था जिसमें सभी ऋतुओं में उपयोग में लाने वाले दो बड़े कमरे, खुला बरामदा और बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय सुविधा हो।
- प्रत्येक स्कूल में कम से कम दो शिक्षक, जहां तक संभव हो उनमें एक महिला; और
- ब्लैक बोर्ड, नक्शे, चार्ट, खिलौने और कार्य अनुभव के लिए उपकरण।

4.3.4 स्कूल भवनों के निर्माण के लिए मुख्यत: निधि की व्यवस्था राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार कार्यक्रम (एन आर ई पी) और ग्रामीण भूमिहीन रोज़गार गारंटी कार्यक्रम (आर एल ई जी पी) के अधीन की जाती है। अन्य घटकों के लिए निधि शिक्षा विभाग द्वारा प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत देश में सभी खंडों, नगरपालिका क्षेत्रों के प्राथमिक स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से सम्मिलित किया जाएगा। 1987-88 के दौरान 20 प्रतिशत खण्डों/नगरपालिका क्षेत्रों को सम्मिलित करने का लक्ष्य रखा गया है जिनमें से 1988-89 के दौरान 30 प्रतिशत और 1989-90 के दौरान 50 प्रतिशत का लक्ष्य है।

4.3.5 वर्ष 1987-88 के दौरान निम्नलिखित कार्यों के लिए 24 राज्यों और 3 संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता के रूप में 110.61 करोड़ रुपए की धन राशि दी गई थी।

- 1,13,417 स्कूलों के लिए (देश के प्राथमिक स्कूलों का 21 प्रतिशत से अधिक) और
- 36,891 अतिरिक्त शिक्षकों की व्यवस्था (उपर्युक्त स्कूलों के लिए)

अनौपचारिक शिक्षा

4.4.1 छठी पंच वर्षीय योजना के दौरान आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, जम्मू और काश्मीर, मध्य प्रदेश और पश्चिमी बंगाल राज्यों के शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में केन्द्रीय सहायता प्राप्त स्कीम के रूप में अनौपचारिक शिक्षा स्कीम लागू की गई थी और 1987 में इसमें अरुणाचल प्रदेश के अतिरिक्त और सभी अन्य राज्यों में शहरी गंदी बस्तियों, पर्वतीय रेगिस्तानी और जनजाति क्षेत्रों की परियोजनाओं में भी कामकाजी बच्चों के लिए भी शामिल करने के लिए इसका विस्तार किया गया। संशोधित स्कीम के अधीन राज्यों को सामान्य अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों और बालिका अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों को चलाने के लिए क्रमशः 50:50 और 90:10 के अनुपात से सहायता दी जा रही है। स्वैच्छिक एजेंसियों को शतप्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जा रही है।

4.4.2 संशोधित स्कीम की मुख्य-मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :-

संगठनात्मक लचीलापन, पाठ्यचर्या की प्रासंगिकता, पढ़ने वालों की आवश्यकता के अनुरूप शिक्षण कार्यकलापों में विविधता और सुदृढ़, विकेन्द्रीकृत

शैक्षिक संस्थाओं की वृद्धि

	1950-51	1960-61	1970-71	1980-81	1986-87
प्राथमिक स्कूलों की संख्या (हजार)	210	330	408	494	537
माध्यमिक स्कूलों की संख्या (हजार)	14	50	91	119	137
माध्यमिक / उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की संख्या (हजार)	7	17	37	51	69
सामान्य शैक्षिक डिग्री स्तर और उससे उच्च स्तर के कालेजों की संख्या	542	1082	2285	3421	4151
व्यावसायिक शिक्षा के कालेजों की संख्या डिग्री और उससे उच्च स्तर	182	810	992	1156	1280*

* 1982-83 से सम्बन्धित

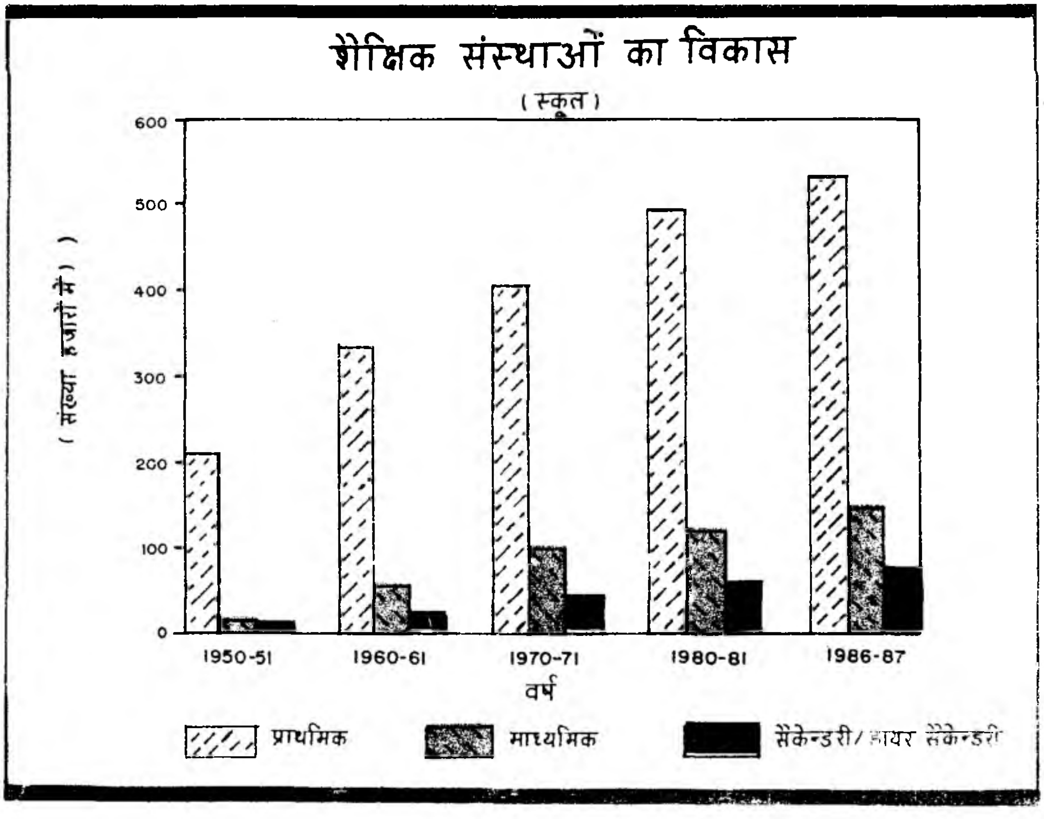

शैक्षिक स्तर पर छात्रों की संख्या

	1950-51	1960-61	1970-71	1980-81	1986-87
कक्षाओं में छात्रों की संख्या (लाख)					
I – V	192 (43.1)	350 (62.4)	570 (72.6)	738 (80.5)	900 (96.0)
VI – VIII	31 (12.9)	67 (22.5)	133 (34.2)	207 (41.9)	288 (53.14)
IX – XI/XII	14	33	76	119	176
डिग्री और उससे उच्च स्तर के पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या (लाख)	2	6	25	30	34

टिप्पणी : 6 – 11 और 11 – 14 वर्षों की आयु वर्ग के बच्चों की कुल जनसंख्या में से ।

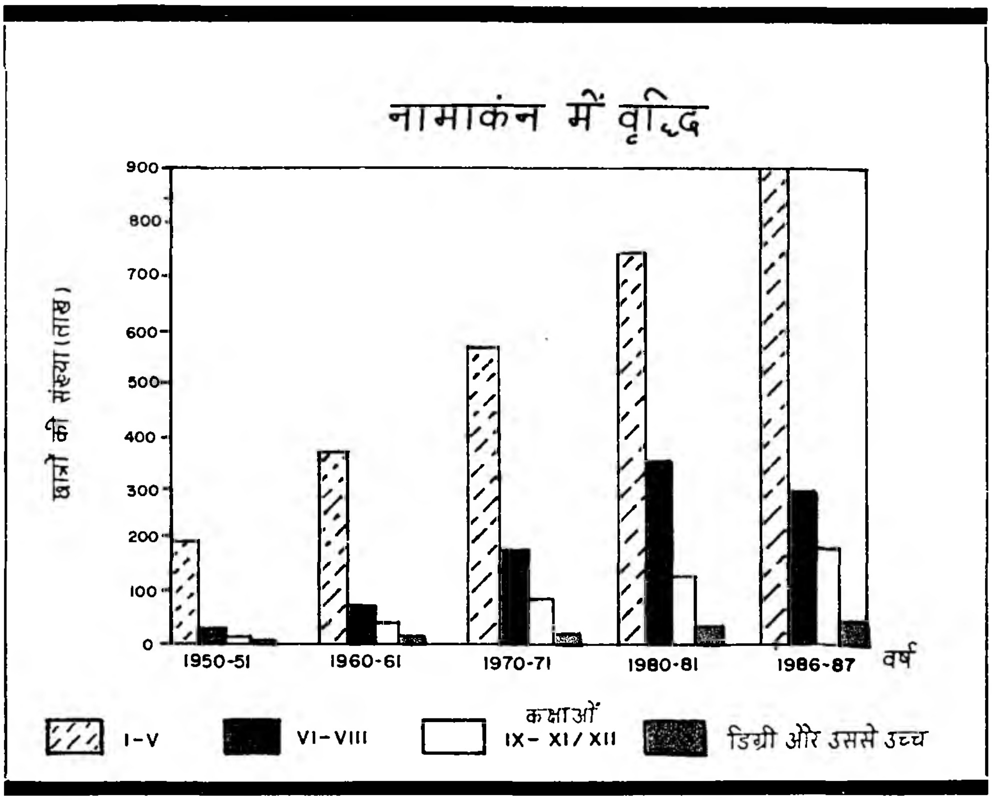

स्तर-वार स्त्रियों का नामांकन

(लाख रुपए)

स्तर	1950-51	1960-61	1970-71	1980-81	1986-87
प्राथमिक	54 (28.1)	114 (32.6)	213 (37.4)	285 (38.6)	361 (40.1)
माध्यमिक	5 (16.1)	16 (23.9)	39 (29.3)	88 (32.9)	102 (35.4)
माध्यमिक / उच्चतर माध्यमिक / 10 + 2 / इन्टरमीडिएट (IX और उससे उच्च स्तर)	2 (14.3)	6 (18.2)	19 (25.0)	35 (29.4)	54 (30.7)
उच्च शिक्षा (डिग्री और उससे उच्च स्तर)	.20 (10.0)	1 (16.7)	4 (20.0)	8 (26.7)	10* (29.4)

* 1982 – 83 से सम्बन्धित

टिप्पणी : प्रतिशत में आंकडें कुल नामांकनों (बालक-बालिकाओं) के द्योतक हैं ।

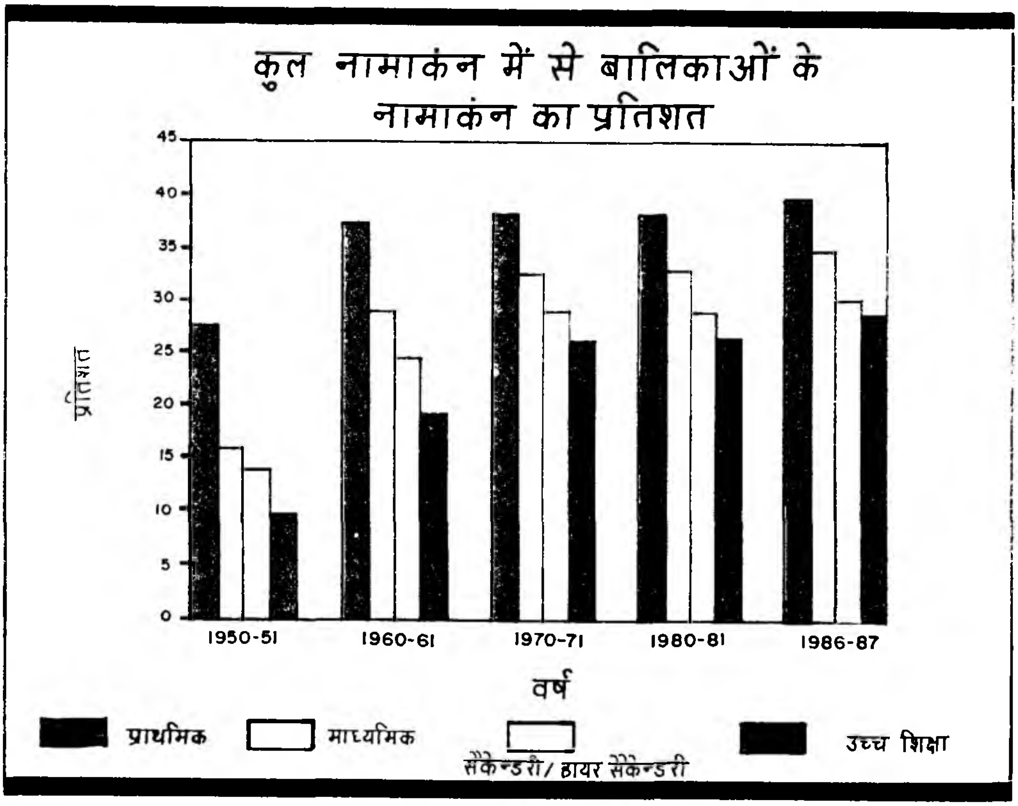

शिक्षकों की संख्या

(हजारों में)

	1950-51	1960-61	1970-71	1980-81	1986-87
प्राथमिक स्कूल	535	742	1060	1363	1522
माध्यमिक स्कूल	85	345	638	852	979
माध्यमिक / उच्चतर माध्यमिक स्कूल	127	296	629	912	1199

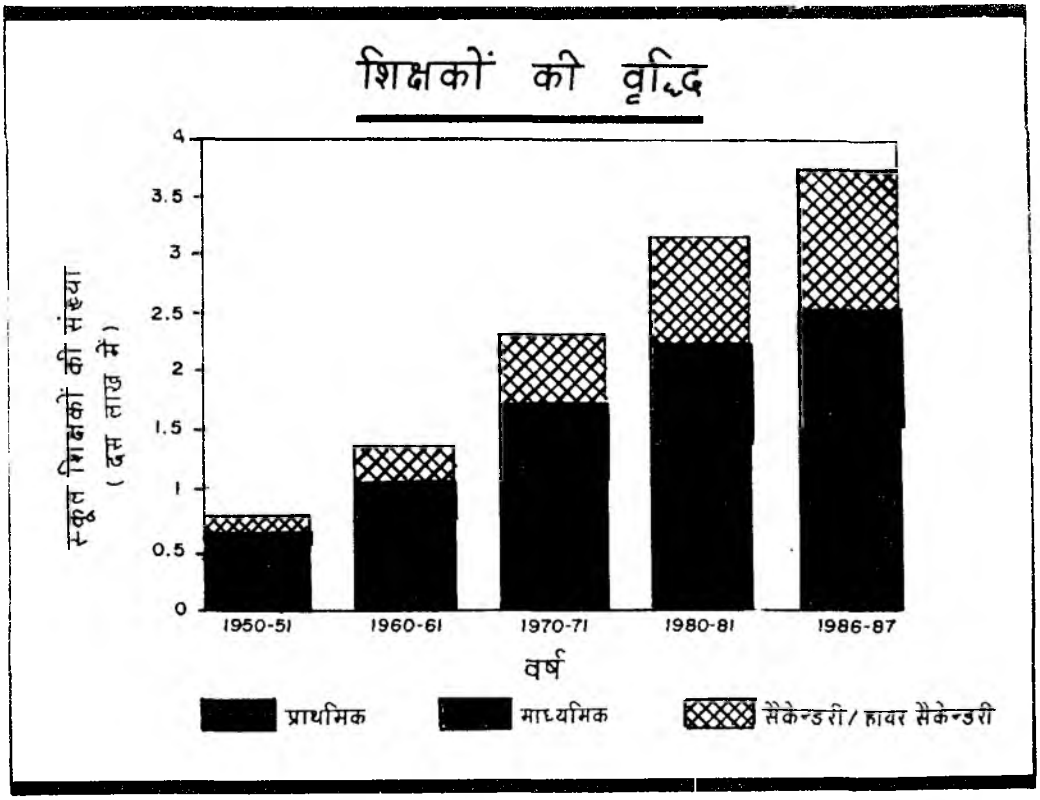

भारत सरकार, शिक्षा विभाग का एक प्रतिबद्ध अवर सचिव, रयाल सीमा सेवा समिति द्वारा संचालित अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र, तिरुपति में शिक्षण-विधि स्पष्ट करते हुए।

प्रबन्ध। यह कार्यक्रम अब परियोजना आधार पर कार्यान्वित किया जा रहा है। (आमतौर पर परियोजना लगभग 100 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के सामुदायिक विकास खण्ड के साथ कोटर्मिनस है। स्वैच्छिक एजेंसियों, पंचायती राज संस्थाएं इस कार्यक्रम में सार्थक तरीके से सम्मिलित हैं।

4.4.3 इस स्कीम के कार्यान्वयन पर 1987-88 के दौरान 38.07 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च की गई थी। निम्नलिखित कार्यों के लिए 15 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को सहायता स्वीकृत की गई थी :-

- 1.85 लाख अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों को चलाने।
- 104 स्वैच्छिक एजेंसियों द्वारा केन्द्र चलाने।
- आठ प्रायोगिक और नवीकरण परियोजनाएं।

4.4.4 चालू वर्ष में वास्तविक लक्ष्य 2650 परियोजनाओं (लगभग 2,65,000 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र केन्द्र और स्वैच्छिक एजेंसियों की ·100 परियोजनाएं) का है। चालू वर्ष के दौरान पहले से स्वीकृत अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण पर विशेष कर प्रक्षेपी दल की दृष्टि से बल दिया जाएगा।

4.4.5 कार्यक्रम के लिए मानीटरिंग प्रणाली की रूपरेखा बना ली गई है और इसका क्षेत्र में परीक्षण किया जा रहा है। साथ ही इलैक्ट्रानिकी विभाग की सहायता से उपयुक्त निर्णय सहायता प्रणाली की व्यवस्था करने के लिए और सूचना का नियमित प्रवाह के लिए कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है।

शिक्षाकर्मी परियोजना

4.4.6 स्वीडिश अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (एस. आई. डी. ए.) की सहायता से कार्यान्वित किए जा रहे शिक्षा कर्मी परियोजना–अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम 1987-88 में 10 खंडों में जारी रही और 1988-89 में 20 से अधिक खंडों में इसका विस्तार किया गया। परियोजना का प्रयोजन सुदूरवर्ती और पिछड़े गांवों में सुधार लाने और इसका विस्तार करने के लिए अनौपचारिक और नवीन दृष्टिकोण अपनाना है। शिक्षा कर्मियों के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उन्हें शिक्षकों की भांति औपचारिक शैक्षिक अर्हता प्राप्त हो बल्कि उनकी उपयुक्तता, उनके उत्साह, समर्पण भावना, रुचि और अभिरुचि के आधार पर आंकी जाएगी। वे दिन और सायंकालीन दोनों प्राथमिक कक्षाओं को चलाते है और अभिप्राय यह है कि अध्यापन बच्चों पर अधिक केन्द्रित हो और सुधारात्मक हो।

महिला समाख्या

4.4.7 राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 के पैरा 4.2 और कार्य-योजना के अध्याय 12 के अनुसरण में "महिला समाख्या" नाम का कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसमें 1989-90 तक चरणबद्ध तरीके में 3 राज्यों में 10 जिलों के 2,000 गांवों में महिला कार्यकलाप केन्द्र स्थापित करने का प्रयास किया गया है।

4.4.8 इस कार्यक्रम में उत्प्रेरक या प्रेरक के रूप में काम करने के लिए प्रत्येक गांव की कुछ महिलाओं को प्रशिक्षण देने की संरचना की गई है जो स्वास्थ्य, जल, ईंधन, चारा और शिक्षा से संबंधित उन समस्याओं तथा इस सबके अलावा समाज में अपने व्यक्तित्व और छवि से संबंधित समस्याओं के बारे में भी जिनका सामना उन्हें करना पड़ता है, चर्चा करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इस प्रकार की चर्चाओं से महिलाओं की जीवन स्थिति के विश्लेषण में महत्वपूर्ण चिन्तन में सहायता मिलेगी और परिवर्तन लाने के लिए सामूहिक कार्रवाई को प्रोत्साहन मिलेगा। महिला संघ के लिए काफी बड़ा बरामदा युक्त एक छोटे से मकान की व्यवस्था की जानी है (यह मकान समाज के कार्यकलापों के लिए गांवों के मकानों के समीप हो और यह गांव द्वारा दी गई भूमि पर बनाया जाए)। महिला संघ में उठाये गये महिलाओं के विचारों को शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों जैसे ई सी सी ई एन एफ ई, ए०ई०, जे एस एन आदि में सम्मिलित किया जाता है। ग्राम स्कूल शिक्षकों, अनौपचारिक और प्रौढ़ शिक्षा अनुदेशकों को गहन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर दिया जाएगा ताकि वे समुदाय अर्थात् महिला संघ के प्रति अपने दायित्व को समझ सके। आवासी संस्थाओं में 100 महिलाओं के लिए छात्रावास सुविधाएं दी जानी हैं और महिलाओं के लिए और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की बालिकाओं के लिए भी अल्पकालिक और दीर्घकालिक व्यावसायिक पाठ्यक्रम चलाए जाने हैं।

4.4.9 इस कार्यक्रम का अभिप्राय जिलों में महिलाओं के लिए कार्य करने वाले स्वैच्छिक एजेंसियों की विश्वसनीयता और विशेज्ञता तैयार करना है। कार्यक्रम बनाने और शुरू करने दोनों अवसरों पर इन एजेंसियों के साथ और सरकारी अधिकारियों के साथ भी राज्य, जिला और खंड स्तरों पर कई बार चर्चा की है।

4.4.10 यह आशा की जाती है कि यह कार्यक्रम आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भी चलता रहेगा और चरणबद्ध तरीके से अन्य राज्यों में भी शुरू होगा। यह कार्यक्रम केन्द्रीय सेक्टर स्कीम के रूप में सितम्बर, 1988 मे स्वीकृत हुआ था और जिसके अधीन तीन राज्यों में पंजीकृत महिला समाख्या सोसाईटियों को 100% वित्तीय सहायता दी जाएगी।

4.5.0 भारत सरकार दो महत्वपूर्ण स्कीमें चला रही है, ताकि स्कूल के बच्चों के फायदे के लिए उचित दामों पर पाठ्यपुस्तकों, अभ्यास-पुस्तिकाओं और परीक्षा प्रश्नों के उत्तर-पत्रकों का उत्पादन किया जा सके। इन स्कीमों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

शैक्षिक प्रयोजनों के लिए रियायती दर पर सफेद प्रिंटिंग कागज की सप्लाई

4.5.1 कागज़ नियंत्रण आदेश और कागज़ (उत्पादन विनियम) आदेश, 1978 को 22 जनवरी, 1987 से निरस्त करने के फलस्वरूप भारत सरकार ने उसे नई स्कीम के साथ प्रस्तुत किया है जिसके अधीन शिक्षा के क्षेत्र को सफेद प्रिंटिंग कागज़ की सप्लाई सुनिश्चित की गई है। नई स्कीम के अधीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 7,560 रु० प्रति मीट्रिक टन पर रियायती कागज़ मिलता रहेगा। हिन्दुस्तान कागज़ निगम, भारत सरकार के एक उद्यम को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 7,560 रु० प्रति मीट्रिक टन की दर पर कागज सप्लाई करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है और बताई गई कीमत 10,910 रु० पर शिक्षा विभाग से आर्थिक सहायता की मांग करेगा बशर्ते कि कीमत 3,000 रु० प्रति मीट्रिक टन से अधिक न हो।

4.5.2 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को शिक्षा क्षेत्र के लिए कलैण्डर वर्ष के दौरान कुल मात्रा 80,000 टन पहले ही आवंटित किया गया है।

नार्वे से सफेद प्रिंटिंग कागज़ की प्राप्ति

4.5.3 भारत सरकार और नार्वे राज्य के बीच द्विपक्षी करार के अधीन नार्वे से स्कूल की पाठ्य-पुस्तकें छापने के लिए उपहार के रूप में सफेद प्रिंटिंग कागज़ मिला है। योजना परिचालन 1988-89 के अधीन 38 मिलियन क्रोनर मूल्य के कागज़ मिलने की आशा है। आगे 15 मिलियन क्रोनर कीमत का अतिरिक्त कागज़ देना स्वीकार किया गया है। यह सब कागज़ एन०सी०ई०आर०टी० को स्कूल की पाठ्यपुस्तकें छापने के लिए आबंटित किया जाएगा।

शिक्षक शिक्षा

4.6.1 शिक्षक शिक्षा की पुन:संरचना और पुनर्गठन की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम को निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए सातवी पंचवर्षीय योजना के अधीन कार्यान्वित किया जा रहा है:-

- शिक्षकों को शिक्षण क्षमता से सुसज्जित करने के लिए उन्हें सेवापूर्व और सेवाकालीन प्रशिक्षण देना
- व्यावसायिक दृष्टि से गठित शिक्षक शिक्षा संस्थाओं के माध्यम से औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा के साथ ही प्रौढ़ शिक्षा को भी सार्थक शैक्षिक सहायता की व्यवस्था।

स्कीम के निम्नलिखित पांच घटक हैं अर्थात्

- शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संकल्पित मुख्य-मुख्य विविधताओं की जानकारी देने और उन्हें व्यावसायिक दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए 1989-90 तक प्रति वर्ष लगभग 5,00,000 स्कूल शिक्षकों को सामूहिक पुन:प्रशिक्षण;
- लगभग 400 जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों (डी. आई. ई. टी.) की स्थापना या तो मौजूदा उपयुक्त प्रारंभिक शिक्षक शिक्षा संस्थाओं का ग्रेड बढ़ाकर या जहां आवश्यक हो, नई संस्थाएं स्थापित करके ताकि जिला स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा प्रणाली को पूर्णत: शैक्षिक और प्रशिक्षण सहायता प्रदान की जा सके।
- लगभग 250 माध्यमिक शिक्षक शिक्षा संस्थाओं (एस०टी०ई०आई०) का सुदृढ़ीकरण और उनमें से लगभग 50 का उच्च शिक्षा अध्ययन संस्थान (ए. एस. ई.) के रूप में विकास;
- राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषदों (एस. सी. ई. आर. टी.) का सुदृढ़ीकरण; और
- विश्वविद्यालयों में शिक्षा विभागों की स्थापना और उनका सुदृढ़ीकरण

4.6.2 1987-88 के दौरान उपर्युक्त शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों के अधीन पन्द्रह राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र को निम्नलिखित कार्यों के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में 32.47 करोड़ रुपये दिए गये थे:-

- पांच लाख स्कूल शिक्षकों का पुनः प्रशिक्षण
- 101 जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना
- 15 एस. टी. ई. आई. का सी. टी. ई. के रूप में सुदृढ़ीकरण
- 7 एस. टी. ई. टी. का आई. ए. एस. ई. के रूप में सुदृढ़ीकरण

4.6.3 शिक्षा विभाग ने 24-26 अक्तूबर 1988 को "शिक्षक शिक्षा की पुर्नसंरचना और पुनर्गठन में शैक्षिक अनुसंधान" पर एक कार्यशाला आयोजित की।

4.6.4. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयों के शिक्षा विभागों के सुदृढ़ीकरण के ब्यौरे तैयार कर रहा है।

माध्यमिक शिक्षा

5.1.0 माध्यमिक शिक्षा की वृद्धि प्रारम्भिक शिक्षा से संबंधित भाग में दी गई तालिकाओं और ग्राफों में पहले ही प्रस्तुत की गई है।

5.2.0 उच्चतर माध्यमिक सहित माध्यमिक शिक्षा को यह मानते हुए कि यह उनकी अंतिम परीक्षा है जो इस स्तर के बाद कार्य जगत में प्रवेश करते हैं, और अन्य के लिए जो उच्चतर शिक्षा की तैयारी में जुटते हैं, इस क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण स्कीमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के अधीन कार्यान्वित की जा रही हैं। इन स्कीमों में तथा पीछे से चली आ रही स्कीमों में प्राप्त प्रगति नीचे दर्शाई गई है:-

माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण

5.3.1 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में व्यावसायिक शिक्षा को अत्यन्त उच्च प्राथमिकता दी गयी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया है कि "एक सुव्यवस्थित, सुनियोजित और सुकार्यान्वित व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम की शुरूआत, शिक्षा के प्रस्तावित पुनर्गठन में अत्यन्त महत्वपूर्ण है" उच्चतर माध्यमिक स्तर के 10 प्रतिशत विद्यार्थी 1990 तक और 25 प्रतिशत 1995 तक, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में नामांकित कर दिए जाएंगे।

5.3.2 राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा कार्रवाई योजना में निर्दिष्ट मार्गदर्शी रूपरेखाओं तथा राज्य सरकारों और विशेषज्ञों के साथ हुई चर्चा के आधार पर माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायिकरण की एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना, वर्ष 1987-88 से शुरू की गयी है जिसके अन्तर्गत स्कूलों में +2 स्तर तक व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को लागू करने के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना में राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा की संयुक्त परिषद की स्थापना की परिकल्पना की गयी हैं ताकि विभिन्न संगठनों/एजेंसियों द्वारा चलाये जा रहे व्यावसायिक कार्यक्रमों की नीति, आयोजना और समन्वय किया जा सके। इस कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय/राज्य/जिला और संस्थागत स्तरों की प्रबंध संरचना को उपयुक्त रूप से सुदृढ़ बनाया जाएगा। योजना के मानदंडों के अनुसार इसके अन्तर्गत जिला व्यावसायिक सर्वेक्षणों, पाठ्यचर्या और संसाधन सामग्रियों के विकास, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए अपेक्षित उपस्करों, कार्यशैडों का निर्माण, शिक्षकों का प्रशिक्षण पाठ्यपुस्तक आर्थिक सहायता आदि, मूल्यांकन और अनुश्रवण आयोजित करने के लिए राज्य/संघ शासित प्रदेशों को शत प्रतिशत आर्थिक सहायता दी गई है। शिक्षकों तथा स्कूलों में अन्य व्यावसायिक कर्मचारियों के वेतन और भत्तों पर व्यय का पचहत्तर प्रतिशत और शिक्षा निदेशालय, राज्य शै०आ० तथा प्र० परिषद और जिला शिक्षा अधिकारियों में व्यावसायिक विंगों में स्टाफ पर व्यय का 50 प्रतिशत केन्द्र द्वारा वहन किया गया है। तथापि कच्चे माल और फुटकर व्यय, व्यावसायिक मार्गदर्शन तथा परीक्षण और प्रमाणीकरण की शत-प्रतिशत जिम्मेदारी राज्यों की है। व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोगात्मक तथा नवाचारी कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए इस योजना में स्वैच्छिक संगठनों को भी सहायता प्रदान की जाती है।

5.3.3 इस योजना के अंतर्गत प्रारंभ किए गए पाठ्यक्रमों को इस प्रकार तैयार किया जाता है कि इन

पाठ्यक्रमों को उत्तीर्ण करने वाले छात्रों के लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर होंगे अथवा छात्र स्व-रोजगार प्राप्त करने में समर्थ हो सकेंगे। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा शुरू की गयी एक नवाचारी योजना महानगरों में के०मा०शि०बो० के चुनिन्दा स्कूलों में जनरल इंश्योरेंस कारपोरेशन आफ इंडिया के सहयोग से जनरल इन्शयोरेंस में व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू करने की है जिसके अन्तर्गत इस पाठ्यक्रम को सफलता पूर्वक पूरा करने वाले छात्रों के रोजगार को सुनिश्चित किया है। राज्य सरकारों को भी सलाह दी गयी है कि वे भी अपने क्षेत्र में ऐसे नियोक्ताओं का पता लगाएं और उनके साथ सहयोग से इसी प्रकार के पाठ्यक्रम विकसित करें ताकि छात्रों के लिए रोजगार के अवसर सुनिश्चित और नियोक्ताओं के लिए उपयुक्त प्रशिक्षित जनशक्ति प्रदान की जा सके।

5.3.4 स्वास्थ्य संबंधित क्षेत्रों में सही ढंग से प्रशिक्षित जनशक्ति की जरूरत को काफी लम्बे समय से मद्दे नजर रखते हुए प्रोफेसर जे०एस० बजाज की अध्यक्षता में "स्वास्थ्य जनशक्ति - आयोजना उत्पादन और प्रबंध" पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मई, 1986 में किया गया। इस समिति ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की सिफारिश की जिन्हें स्कूलों में शुरू किया जा सकता है। राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों से अनुरोध किया गया है कि वे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करने का पता लगाते समय बजाज समिति की सिफारिशों पर विचार करें।

5.3.5 वर्ष 1987-88 के दौरान लगभग 1000 उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में लगभग 3100 व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करने के लिए 18 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को केन्द्रीय सहायता के रूप में 32.26 करोड़ रुपए की राशि संस्वीकृत की गयी। वर्ष 1988-89 के दौरान भी राज्यों ने कार्यक्रम के अंतर्गत पर्याप्त केन्द्रीय सहायता के लिए प्रस्ताव भेजे है।

स्कूलों में विज्ञान शिक्षा में सुधार

5.4.1 स्कूली बच्चों की सामान्य शिक्षा योजना में विज्ञान के स्थान को शायद ही कम किया जा सकता है। कोठारी आयोग और शिक्षा नीति संकल्प (1968) में स्कूल स्तर पर विज्ञान शिक्षण को उच्च प्राथमिकता दी गई थी, तथापि, इस समय के स्तर पर विज्ञान शिक्षण कुछ कमजोर ही है। विज्ञान शिक्षण के लिए मात्र अध्यापन ही पर्याप्त नहीं अपितु इसके लिए प्रदर्शन और प्रयोग की भी आवश्यकता होती है। तथापि, देश के अधिकांश स्कूलों में पर्याप्त प्रयोगशाला सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।

5.4.2 राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में विज्ञान शिक्षा कार्यक्रमों को मजबूत बनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। विशेषज्ञों ने यह महसूस किया कि पर्याप्त भौतिक सुविधाएं प्रदान करने के साथ ही अध्यापकों में सुधार लाना भी आवश्यक है। तदनुसार वर्ष 1987-88 की अंतिम तिमाही के दौरान स्कूलों में विज्ञान शिक्षा के सुधार से संबंधित एक केन्द्रीय प्रयोजित योजना शुरू की गयी है जिसके अन्तर्गत राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को वित्तीय सहायता दी जाएगी ताकि वे अपर प्राइमरी स्कूलों को विज्ञान किटें प्रदान कर सकें, माध्यमिक और उच्चतर स्कूलों में अपेक्षित स्तर तक प्रयोगशालाओं को स्तरोन्नत कर सकें, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में पुस्तकालयों को स्तरोन्नत करें और विज्ञान शिक्षा के लिए जिला संसाधन केन्द्रों की स्थापना कर सकें जो विज्ञान शिक्षकों के प्रशिक्षण तथा अध्ययन-अध्यापन सामग्री का विकास करने के साथ-साथ एक ऐसे मंच की भूमिका निभाएंगे जहां विज्ञान अध्यापक अपनी समस्याएं रख सकते हैं और विचारों का आदान-प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा योजना के अन्तर्गत स्कूलों के विज्ञान और गणित शिक्षकों के लिए एक व्यापक सेवाकालीन कार्यक्रम भी प्रारंभ किया जाएगा। इस योजना के अन्तर्गत विज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय स्वैच्छिक एजेंसियों को भी सहायता दी जाती है ताकि वे वैज्ञानिक चेतना के विकास और विज्ञान शिक्षा की जागरूकता की प्रौन्नति के लिए नवाचारी कार्यक्रम प्रारंभ कर सकें। राष्ट्रीय उच्चतर गणित बोर्ड से यह अनुरोध किया है कि स्कूलों में गणित के शिक्षण को सुदृढ़ बनाने के लिए कार्यक्रम शुरू करने की संभाव्यता की जांच करे जिससे प्रत्येक वर्ष आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मैथेमेटिकल ओलम्पियाड में भाग लने के लिए छात्रों को तैयार किया जा सके।

5.4.3 वर्ष 1987-88 के दौरान अन्य बातों के साथ—साथ लगभग 21,000 प्रदेशों को उच्चतर प्राथमिक स्कूलों को विज्ञान किटें देने, 6900 माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में प्रयोगशालाओं का स्तरोन्नत करने और 80 जिलों में जिला संसाधन केन्द्रों

की स्थापना के लिए 19 राज्यों/संघ शासित 29.27 करोड़ रुपए की राशि के केन्द्रीय राज्यों को शामिल किए जाने का प्रस्ताव है। स्वैच्छिक संगठनों ने भी इस योजना के प्रति प्रोत्साहित प्रतिक्रिया दर्शायी है। विभिन्न स्वैच्छिक एजेंसियों से विज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए कई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और एकलव्य, भोपाल, तमिलनाडु साइंस फोरम, मद्रास, पाण्डिचेरी साइंस, फोरम, पाण्डिचेरी, केरल शास्त्र साहित्य परिषद, त्रिवेन्द्रम, बाल भवन सोसायटी (भारत) नई दिल्ली को पहले ही सहायता संस्वीकृत कर दी गयी है। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद् के प्रस्ताव हेतु 25 जिलों के लिए, प्रत्येक जिले में दो की दर से, स्कूल विज्ञान केन्द्रों के, गठन का अनुमोदन किया गया है। ये स्कूल विज्ञान केन्द्रों, छात्रों में वैज्ञानिक चेतना का विकास जैसे माडल तथा चार्ट बनाना, प्रदर्शनियों, नाटकों, निबंधों और प्रश्नावली प्रतियोगिताओं आदि का आयोजन करके विज्ञान शिक्षा के प्रसार के लिए विभिन्न कार्यकलाप आयोजित करेंगे।

स्कूली शिक्षा के लिए पर्यावरणात्मक अनुस्थापन

5.5.1 विश्व में वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिक विकास के साथ पर्यावरणात्मक विषयों का महत्व बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) ने इस विषय पर यथासंभव महत्व दिया हैं और, अन्य बातों के साथ साथ, यह बताया गया है कि "पर्यावरण की सुरक्षा" का मूल्य, एक ऐसा मूल्य है जिसे कुछ अन्य विशेष महत्वपूर्ण मूल्यों के साथ शिक्षा के सभी स्तरों पर पाठ्यचर्या का एक अभिन्न अंग अवश्य बनाना चाहिए। तद्नुसार राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् ने सभी अध्ययन करनेवालों के लिए अनिवार्य अध्ययन परिणाम निर्धारित करने के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा विकसित किया है। रा०शै०अ०एवं०प्र० परिषद् राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए पाठ्यक्रमों, पाठ्य-पुस्तकों तथा अन्य शिक्षण अध्ययन सामग्रियों का भी विकास कर रही है। शिक्षक प्रशिक्षण प्रबन्धों में भी पर्यावरणात्मक अनुस्थापन दिया जा रहा है। तथापि, चूंकि ये कार्यक्रम राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय परिप्रेक्ष्यों में रूपांकित और कार्यान्वित किए जाएंगे, फिर भी पर्यावरणात्मक शिक्षा का पूरा सार प्राप्त नहीं किया जा सकता क्योंकि पर्यावरणात्मक विषय स्थान-विशेष से सम्बद्ध होते हैं और, इसलिए सार्वदेशिक समाधान इन पर लागू नहीं होते हैं। अतः इन प्रयासों को और अधिक गहन स्थानीय विशेष प्रयासों में बदलने की जरूरत होगी।

5.5.2 तद्नुसार, स्कूल शिक्षा के प्रति पर्यावरणात्मक अनुस्थापन की एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना चालू वित्तीय वर्ष से आरम्भ की गई है जिसके अन्तर्गत पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों तथा स्वैच्छिक संगठनों को शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। छात्रों तथा समाज में पर्यावरण संबंधी जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रम सदृश पर्यावरण स्थितियों वाले चुनिन्दा क्षेत्रों में परियोजना आधार पर आयोजित किए जाएंगे। परियोजना कार्यकलापों में पाठ्यचर्या का पुनरीक्षण, संशोधित पाठ्यपुस्तकों की तैयारी, पाठ्यचर्या तथा पाठ्येत्तर सामग्रियां, आम सूचनाप्रद पुस्तकें/विवरणिकाएं/पोस्टर्स/श्रव्य-दृश्य सामग्रियों की तैयारी, अध्ययन तथा अनुरक्षण के लिए स्कूलों द्वारा स्मारकों को अपनाना, पास पड़ोस में पर्यावरणात्मक समस्याओं का अध्ययन, संरक्षण परियोजनाओं में सहभागिता आदि शामिल होंगे। पर्यावरण तथा वन राज्य विभागों तथा राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड की सहायता से स्कूल की नर्सरियों की स्थापना करना, महत्वपूर्ण कार्यकलापों में से एक हैं। यह योजना पर्यावरण शिक्षा से सम्बन्धित नवीन परियोजनाओं में स्वैच्छिक संगठनों को शामिल करने की व्यवस्था भी करती है।

5.5.3 चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, हिमाचल प्रदेश, असम तथा मिजोरम के प्रस्ताव पहले ही स्वीकृत किए जा चुके हैं और कुछ अन्य विचाराधीन हैं। इस योजना को स्वैच्छिक संगठनों से बहुत अच्छा प्रोत्साहन मिला है और कई प्रस्ताव इस योजना के अन्तर्गत परियोजनाएं शुरू करने के लिए प्राप्त हो रहे हैं। पहले से ही स्वीकृत कुछ प्रस्ताव जो निम्नलिखित से प्राप्त हुए हैं :

- उत्तराखण्ड सेवा निधि अल्मोड़ा, उत्तर प्रदेश के कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्रों की प्राथमिक शिक्षा का पर्यावरणात्मक अनुस्थापन
- समाज के विकास की अत्यावश्यक परियोजना, जिसमें प्राकृतिक विपदाओं तथा पर्यावरणात्मक अवनति के बीच सम्पर्क स्थापित करने का प्रयत्न है, के लिए संचालन फाउन्डेशन, नई दिल्ली
- पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे

एन०जी०ओ० को शामिल करने के लिए नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करने के लिए पर्यावरण शिक्षा, केन्द्र (सी.ई.ई.) अहमदाबाद जिससे उनके चारों और स्कूल समूहों में स्थानीय विशेष कार्यकलाप शुरू किए जा सकें। यह पर्यावरण शिक्षा केन्द्र एन०जी०ओ० के मुख्य कार्यकर्ताओं को अनुस्थापन प्रदान करेगा, और अपने कार्यक्रमों में उनके साथ सहयोग तथा मार्गदर्शन करेगा। इस प०शि०केन्द्र द्वारा पहचाने गए एन०जी०ओ० को पर्यावरण शिक्षा केन्द्र के जरिए अनुदान दिए जाएंगे, जो स्कूलों में इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन का अनुश्रवण तथा पर्यवेक्षण करेंगे।

शैक्षिक प्रौद्योगिकी कार्यक्रम

5.6.1 शैक्षिक प्रौद्योगिकी कार्यक्रम चौथी योजना अवधि के दौरान 1972 में केन्द्रीय क्षेत्र में शिक्षा तक व्यापक पहुंच और उसमें गुणवत्तात्मक सुधार लाने के लिए केन्द्रीय क्षेत्र में एक शैक्षिक प्रौद्योगिकी कार्यक्रम शुरू किया गया।

5.6.2 वर्ष 1982 में, इन्सेट ट्रान्समिशन चालू करने के साथ ही यह निर्णय किया गया था कि ई.टी.वी. कार्यक्रम का निर्माण करना शैक्षिक प्राधिकारियों की जिम्मेदारी होगी। तद्नुसार, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद में एक केन्द्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान (सी.आई.ई.टी.) तथा छह राज्यों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में राज्य शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थाओं (एस.आई.ई.टी.एस.) की स्थापना करके एक विकेन्द्रीकृत आधार पर शैक्षिक क्षेत्र के भीतर शैक्षिक टेलिविजन (ई.टी.वी.) कार्यक्रम निर्माण सुविधाओं के सृजन और अन्य राज्यों में ई.टी. सैलों को सुदृढ़ करने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक योजना बनाई गई थी।

5.6.3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बताया गया है कि संरचनात्मक द्विविधता से बचने के क्रम में, आधुनिक शैक्षिक प्रौद्योगिकी को तुलनात्मक प्रभाव तथा आसान सुलभता के क्षेत्रों के साथ एक ही समय सर्वाधिक सुदूर क्षेत्रों तथा लाभ प्राप्त करने वालों के सर्वाधिक वंचित वर्गों तक अवश्य पहुंचना चाहिए। ऐसा प्रयास प्रसारण प्रणालियों के प्रयोग का उनके अत्यधिक पहुंच, प्रबन्ध एवं लागत प्रभावशीलता की सुविधा के निहित लाभ के साथ मूलभूत रूप से समर्थन करेगा। इसे ध्यान में रखते हुए, एक संशोधित योजना इस विभाग द्वारा तैयार की गई है जो इनसेट उपयोगिता कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्तमान प्रयासों को समेकित करने, शैक्षिक क्षेत्र में विस्तृत कार्यक्रम निर्माण क्षमताएं अर्जित करने तथा रिसीविंग सैट प्रदान करके क्रमशः एक लाख और पांच लाख प्रारंभिक स्कूलों में रेडियो तथा टी.वी. कवरेज प्रदान करने का प्रयत्न करती हैं। इस योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया और वर्ष 1987-88 में शुरू कर दी गई है।

5.6.4 सी.आई.ई.टी. तथा एस.आई.ई.टी. में कार्यक्रम निर्माण शुरू कर दिया गया हैं। चालू शैक्षिक वर्ष से, कार्यक्रम निर्माण के लिए जिम्मेदारी जो अब तक दूरदर्शन तथा सी.आई.ई.टी. के बीच में 50:50 के आधार पर बांटी जा रही थी अब सी.आई.ई.टी. को पूर्णतः सौंप दी गई है।

5.6.5 ई.टी.वी. कार्यक्रम पांच क्षेत्रीय भाषाओं, अर्थात् हिन्दी, गुजराती, मराठी, उड़िया तथा तेलुगु में आवंटित समय के आधार पर (प्रत्येक भाषा के लिए 45 मिनट) लगभग 220 स्कूल दिवसों के दौरान 3 घंटे तथा 45 मिनटों के लिए सुबह दैनिक रूप से प्रसारित किए जाते हैं। पांच भाषाओं में कार्यक्रम सोमवार से शुक्रवार तक स्कूल में और स्कूल के बाहर दोनों में छह से आठ तथा नौ से ग्यारह वर्षों की आयु के बच्चों के लिए, निर्मित और प्रसारित किए जाते हैं। प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों के लिए कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार को प्रसारित किए जाते हैं। छः इनसेट राज्यों तथा अन्य हिन्दी भाषी राज्यों में सभी एच.पी.टी. तथा एल.पी.टी. द्वारा ई.टी.वी. कार्यक्रम रिले किए जाते हैं।

5.6.6 सी.आई.ई.टी. ने वर्ष 1984 से 350 ई.टी.वी. कार्यक्रमों तथा 700 भाषा रूपान्तरों का निर्माण किया है। नवम्बर, 1988 के अन्त तक, सी.आई.टी. ने हिन्दी में 50 नए ई.टी.वी. कार्यक्रम निर्मित किए और इन कार्यक्रमों के उड़िया रूपान्तर तैयार किए। पूर्ववर्ती वर्षों के अनुसार, सी.आई.ई.टी. ने, इस वर्ष भी, स्कूल शिक्षकों का जन अनुस्थापन के राष्ट्रीय कार्यक्रम के ई.टी.वी. संघटक तैयार किए। हिन्दी तथा अंग्रेजी में निर्मित कार्यक्रम 13 विभिन्न भाषाओं के सिनोप्सिस से प्रारम्भ होते हैं। विभिन्न कोर महत्वपूर्ण पाठयचर्या क्षेत्रों तथा मुद्रण सामग्री के लिए सहायता देने पर बल दिया जाता है। 4.5 लाख से भी अधिक शिक्षक प्रतिवर्ष इन कार्यक्रमों का लाभ प्राप्त करते हैं। विभिन्न प्रशिक्षण के

पाठ्यक्रम अन्तर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त एजेन्सियों के सहयोग से आयोजित किए जाते हैं। वर्ष 1988-89 के दौरान 94 व्यक्ति विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में भाग लेंगे। लगभग 30 देशों में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी श्रव्य और दृश्य निर्माण के विभिन्न पक्षों में एस.आई.ई.टी. तथा सी.आई.ई.टी. के 600 व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान करके आयोजित किए गए हैं।

5.6.7 यद्यपि, सी.आई.ई.टी. ने उच्च स्तर की निर्माण क्षमता के कार्यक्रम तैयार किए हैं, परन्तु एस.आई.ई.टी. ने इस बारे में कुछ धीमी प्रगति की हैं। उन्होंने प्रबन्ध समस्याओं के साथ-साथ तकनीकी मानवशक्ति संबंधी समस्याओं का सामना किया हैं। एक कार्यकारी दल प्रबन्ध संरचना की जांच करने तथा एस.आई.ई.टी. के कार्यकरण को सुधारने के लिए उपाय सुझाने के लिए गठित किया गया था। इस दल ने अन्य बातों सहित यह सिफारिश की कि एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में एक स्वायत्तशासी संगठन राज्य सरकार के तत्वावधान में गठित किया जाना चाहिए ताकि राज्य शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थानों के कार्यों का प्रबन्ध किया जा सके। इसके अनुसरण में प्रारूप उप नियम बनाए गए हैं तथा विभिन्न उपाय इन राज्य शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थानों के पुनर्गठन करने के लिए विचाराधीन हैं।

5.6.8 इस वर्ष के दौरान, सी.आई.ई.टी. में शैक्षिक श्रव्य निर्माण, कोर पाठ्यचर्या क्षेत्रों पर बल दिया गया और 72 नए श्रव्य कार्यक्रम निर्मित हुए। भूमि तथा लोगों पर एक भौगोलिक श्रृंखला में पश्चिमी तट पर तीन 16 एम.एम. रंगीन फिल्में पूरी की गईं। इसके साथ, 'रावली रेन्जिस' तथा 'अनौपचारिक शिक्षा' पर दो अन्य फिल्में लगभग पूरी हो रही हैं। ई.टी.वी. कार्यक्रमों के निर्माण में निजी निर्माताओं को शामिल करने के लिए भी प्रयास किए गए हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने सी.आई.ई.टी. के लिए वीडियो/फिल्में निर्मित करने के लिए बाहरी निर्माताओं को शामिल करने हेतु एक निश्चित मात्रा (मोडेलिटी) तैयार करने के लिए एक समिति गठित की है। एस.आई.ई.टी., लखनऊ भी ई.टी.वी. कार्यक्रमों के लिए निजी निर्माताओं को नियुक्त करने की सम्भावनाओं का पता लगा रहा है।

5.6.9 शिक्षा के लिए उपग्रह के प्रयोग से संबंधित विषय जिसमें मीडिया की समय आवश्यकता, मानवशक्ति संबंधी जरूरतों और सम्पूर्ण शैक्षिक क्षेत्र के लिए वित्त संबंधी आवश्यकताएं शामिल हैं, पर विचार करने के लिए, एक दल का गठन भी श्री किरण कार्तिक के संयोजन में किया गया। इस दल द्वारा शीघ्र ही रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आशा की गई है।

5.6.10 जनवरी, 1988 में अनुमोदित नई ई.टी.वी. योजना में सातवीं पचंवर्षीय योजना अवधि के अन्तिम तीन वर्षों के दौरान प्रारम्भिक स्कूलों के लिए एक लाख टी.वी. सैट तथा पांच लाख रेडियो व कैसेट प्लेयर्स की पूर्ति परिकल्पित थी। वर्ष 1987-88 के दौरान, 10,049 टी.वी. सैटों की कुल संख्या तथा लगभग 38,000 रेडियो व कैसेट प्लेयर्स प्रारम्भिक स्कूलों को देने के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को स्वीकृत किए गए हैं। टी.वी. सैटों तथा रेडियो एवं कैसेट प्लेयर्स की खरीदारी के लिए मानकीकरण सुनिश्चित करने के लिए, उनकी डिजाइन संबंधी विशेषताओं को सी.आई.ई.टी., शिक्षा निदेशक, दूरदर्शन/रेडियो के परामर्श से अन्तिम रूप दिया गया और इनको खरीदारी प्रक्रियाओं के लिए मार्गदर्शी रूपरेखाओं के साथ राज्यों को परिचालित किया गया था।

स्कूलों में संगणक शिक्षा

5.7.1 वर्ष 1984-85 में इलैक्ट्रानिकी विभाग तथा शिक्षा विभाग ने सामूहिक रूप से 248 माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में नामक (क्लास) प्रायोगिक परियोजना शुरू की गयी ताकि छात्रों और शिक्षकों को पढ़ाई के माध्यम के रूप में संगणक अनुप्रयोगों और इसकी विविधता के क्षेत्र से परिचित कराया जा सके। यह परियोजना वर्ष 1987-88 से वर्ष दर वर्ष आधार पर 1700 और अधिक अतिरिक्त स्कूलों (वर्ष 1987-88 के दौरान शामिल किए गए 700 स्कूल भी इसमें शामिल हैं) में जारी रखी गयी। स्कूल अध्यापकों को प्रशिक्षित करने तथा सहभागी स्कूलों को संभारतंत्र (लाजिस्टिक्स) सहायता देने के लिए तिरपन संसाधन केन्द्रों का गठन किया गया। हार्डवेयर के रखरखाव और इसे लगाने की जिम्मेदारी संगणक अनुरक्षण निगम (सी.एम.सी.) को सौंपी गयी। इस परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद प्रमुख एजेंसी मानी गयी। इस परियोजना की शुरूआत से लेकर 1986-87 तक, इस परियोजना को पूर्णतया इलैक्ट्रानिकी विभाग द्वारा वित्त-पोषित किया गया। वर्ष 1984-85, 1985-86, 1986-87 और 1987-88 के दौरान इलैक्ट्रनिकी विभाग ने क्रमशः 2.2 करोड़ रुपए, 4.00 करोड़ रुपए तथा 4.00 करोड़ रुपए और 90 लाख रुपए आवंटित किए। वर्ष 1987-88 के दौरान इस परियोजना पर शिक्षा विभाग ने 5.39 करोड़ रुपए खर्च किए।

शिक्षा सचिव, श्री अनिल बोर्दिया नवोदय विद्यालय, लेह (जम्मू और कश्मीर) के बच्चों के साथ, उनके गणतंत्र दिवस समारोह, 1989 में भाग लेने के बाद।

5.7.2 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद तथा सी.एम.सी. के माध्यम से स्वदेशी साफ्टवेयर का उत्पादन प्रारम्भ करने का प्रयास किया गया। वे 14 पैकेज विकसित करने में सफल रहे जिन्हें 1987-88 के अन्य पैकेजों के साथ स्कूलों को भेज दिया गया। सी.एम.सी. ने अब तक मराठी, उड़िया तेलुगु, हिन्दी, तमिल, कन्नड़, मलयालम, गुरूमुखी, गुजराती, बंगाली और असमी अर्थात् ग्यारह भाषाओं में कुंजी पटल तथा रोम विकसित किए हैं। कार्य अभी जारी है।

5.7.3 परियोजना अनुभव के मूल्यांकन की दृष्टि से इलैक्ट्रनिकी विभाग ने अंतरिक्ष प्रयोग केन्द्र, अहमदाबाद को मूल्यांकन अध्ययन का कार्य सौंप दिया था। उनकी रिपोर्ट से यह पता चला कि परियोजना को सरल बनाने का लक्ष्य आंशिक रूप से ही प्राप्त किया जा सका।

5.7.4 अब तक प्राप्त मूल्यांकन और अनुभव के परिणामों को ध्यान में रखते हुए इस परियोजना को सातवीं योजना के शेष वर्षों में बड़े पैमाने पर कार्यान्वित करने के लिए इलैक्ट्रानिकी विभाग और शिक्षा विभाग द्वारा सामूहिक रूप से एक प्रस्ताव तैयार किया गया है। जिसमें देश भर में 13000 उच्चतर माध्यमिक स्कूलों को शामिल करने का लक्ष्य है। इस कार्यक्रम के लिए पहले वर्ष में 89.03 करोड़ रुपए तथा वर्ष 1988-89 में 89.03 करोड़ रुपए तथा दूसरे वर्ष में 109.39 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय प्रावधान अनुमान लगाया गया है। अभी सरकार ने अन्तिम रूप में इस प्रस्ताव को स्वीकार करना है।

नवोदय विद्यालय

5.8.1 ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभावान बच्चों को उच्च कोटि की आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने प्रत्येक ज़िले में औसतन एक नवोदय विद्यालय स्थापित करने के लिए एक योजना प्रारंभ की है। अब तक देश भर में 22 राज्यों तथा 7 संघ शासित प्रदेशों में दो सौ छप्पन नवोदय विद्यालय है।

5.8.2 नवोदय विद्यालय में दाखिला कक्षा VI से किया जाता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस प्रकार दाखिल अधिकांश छात्रों ने पहले मातृ भाषा/क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से अध्ययन किया होता है अतः उन्हें कक्षा VI अथवा VIII तक उसी माध्यम से पढ़ाया जाता है, इस समय अवधि के दौरान भाषा के रूप में तथा सह-माध्यम के रूप में अंग्रेजी/हिन्दी का गहन शिक्षण दिया जाता है। तत्पश्चात्, हिन्दी/अंग्रेजी समान माध्यम होगा। इस स्तर पर विभिन्न भाषायी क्षेत्रों में एक नवोदय विद्यालय से दूसरे नवोदय विद्यालय में 20 प्रतिशत छात्रों का प्रवास (माइग्रेशन) होता है। यह प्रवास मुख्यतः हिन्दी और अहिन्दी भाषी जिलों के मध्य होता है। छात्रों के प्रथम बैच ने नवोदय विद्यालय झज्जर और नवोदय विद्यालय, अमरावती पारस्परिक प्रवास किया चूंकि ये दोनों विद्यालय इस वर्ष कक्षा-IX तक पहुंच गए है। नवोदय विद्यालयों में त्रिभाषा सूत्र का अनुसरण किया जाता है। इस समय हिन्दी भाषी राज्यों में 123 तथा अहिन्दी भाषा राज्यों में 133 नवोदय विद्यालय हैं तथा इन सभी विद्यालयों में तृतीय भाषा को लागू किया गया है।

प्रवेश

5.8.3 नवोदय विद्यालयों में प्रवेश राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा आयोजित एक परीक्षा के आधार पर किया जाता है। इस परीक्षा का माध्यम मातृ भाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा होती है। परीक्षा अधिकतर अमौखिक स्वरूप, वर्ग-भेद विहीन और इस प्रकार से तैयार की जाती है ताकि ग्रामीण स्कूलों के प्रतिभावान बच्चों को उपेक्षित हुए बिना इसमें भाग लेने योग्य बन सकें इसकी सुनिश्चित व्यवस्था की जा सकें।

5.8.4 सभी जिलों में जहां नवोदय विद्यालय कार्य कर रहे है, शैक्षिक सत्र 1988-89 के लिए परीक्षा 15.5.88 को आयोजित की गयी थी। यह परीक्षा 18 भाषाओं में आयोजित की गयी।

5.8.5 256 नवोदय विद्यालयों के लिए चुनिन्दा छात्रों का ब्यौरा निम्नलिखित है :–

ग्रामीण	10934	लड़के	11298
शहरी	2870	लड़कियां	2506
	----	अनु. जा.	2360
	13804	अनु. ज. जा.	1602
		सामान्य	9842

5.8.6 नवोदय विद्यालय में सह-शिक्षा होती है और इनमें मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे होते है। अतः शहरी क्षेत्रों के बच्चों का दाखिला एक-चौथाई तक प्रतिबंधित है। यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं कि नवोदय विद्यालयों में एक तिहाई छात्र लड़कियां हों।

5.8.7 अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति से संबंधित बच्चों के लिए सीटों के आरक्षण की परिकल्पना

की गयी है जो कि संबंधित जिले में उनकी जनसंख्या के अनुपात में होगी बशर्ते कि किसी भी जिले से ऐसा आरक्षण औसत से कम न हो।

निर्माण कार्यक्रम

5.8.8 नवोदय विद्यालयों के निर्माण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की मुख्य एजेंसी के रूप में पद नामित किया गया है। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए समिति में निर्माण समन्वय समिति का गठन किया गया है। छब्बीस निर्माण एजेंसियों का पता लगाया गया है और उन्हें विद्यालय आवंटित किए गए हैं। समिति ने प्रथम चरण के रूप में 100 विद्यालयों में छठी कक्षा से नौवीं कक्षा के लिए निर्माण कार्य और केवल 120 विद्यालयों में नलाकार बंध सहित निर्माण संरचना की अनुमति दी हैं।

प्रिंसिपल और शिक्षक

5.8.9 इस समय 256 प्रिंसिपलों तथा 2719 शिक्षकों सहित 256 विद्यालय काम कर रहे हैं।

5.8.10 चूंकि सभी नवोदय विद्यालय आवासीय हैं तथा दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित हैं अतः अच्छे शिक्षकों/प्रिंसिपलों को आकर्षित करने के लिए निम्नलिखित प्रोत्साहन दिए गए हैं :–

i) उस स्थान पर रहने के लिए आंशिक रूप से सुसज्जित किराया-रहित आवास उपलब्ध कराना।
ii) दो बच्चों तक प्रति बच्चे के लिए प्रतिमाह 150/- रुपए की दर से बाल शिक्षा भत्ता।
iii) छात्रों के साथ रह रहे हाउस मास्टरों और शिक्षकों को निःशुल्क छात्रावास सुविधा।
iv) सभी शिक्षकों को निःशुल्क मध्याहन् भोजन।
v) समिति के नियमानुसार पति/पत्नी की नियुक्ति के लिए सुविधाएं।
vi) बिना प्रवेश परीक्षा के शिक्षकों के बच्चों को दाखिला और ऐसे बच्चों को निःशुल्क छात्रावास सुविधाएं जहां शिक्षक तैनात हैं।
vii) 100/- रुपए प्रतिमाह शिक्षण भत्ता।

नवोदय विद्यालयों को वाहनों का प्रावधान

5.8.11 कुछ विद्यालय दूरस्थ स्थानों में स्थित हैं और मुख्य सड़क, बाजार, डाकघर, बैंक आदि से काफी दूर हैं। अब तक ऐसे 60 विद्यालयों का पता लगाया गया है और उन्हें कार्यालय प्रयोग हेतु वाहन प्रदान किए गए हैं।

प्रशिक्षण कार्यक्रम

5.8.12 प्रिंसिपलों के लिए दो सेवारत पाठ्यक्रम और शिक्षकों की विभिन्न श्रेणियों अर्थात् टी.जी.टी. और पी.जी.टी. के लिए सेवारत पाठ्यक्रमों का आयोजन किया गया ताकि उन्हें आवासीय स्कूलों के कार्य प्रचालन से अवगत कराया जा सके।

महत्वपूर्ण शैक्षिक कार्यकलाप

– 14-15 फरवरी, 1988 को रा.पु. न्यास के सहयोग से नवोदय विद्यालय समिति द्वारा प्रतिभावान बच्चों के लिए विकसित पाठ्यचर्या कार्यनीतियों पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया और इसके सेमिनार की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में ''स्कूल भिन्न कार्यनीतियों के जरिए रचनात्मक अध्ययन पर्यावरण'' नामक विषय पर एक अन्य कार्यशाला का आयोजन 22-23 नवम्बर, 1988 को किया गया।
– विज्ञान, गणित और सामाजिक-अध्ययन में समिति द्वारा समृद्ध पाठ्यचर्या कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यह समृद्ध पाठ्यक्रम नवोदय विद्यालयों के शिक्षकों और छात्रों के लिए उपयोगी होगा।
– समिति के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अन्तर क्षेत्रीय विज्ञान और सामाजिक विज्ञान प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया।

खुला स्कूल

5.9.1 केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 1979 में स्थापित खुला स्कूल उन सभी को शिक्षा प्रदान करने के लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं जो आर्थिक, सामाजिक और अन्य कमियों के कारण नियमित स्कूल में प्रवेश नहीं ले पाते हैं परन्तु अपनी शैक्षिक योग्यता बढ़ाने के इच्छुक होते हैं। मुख्य रूप से यह पढ़ाई बीच में छोड़ जाने वालों, महिलाओं, कार्यरत प्रौढ़ों तथा समाज के अन्य उपेक्षित वर्गों को शिक्षा प्रदान करने पर बल दे रहा है।

गहन प्रचार अभियान

5.9.2 आलोच्य वर्ष के दौरान. देश भर में राष्ट्रीय

तथा क्षेत्रीय समाचार पत्रों में लगभग 36 विज्ञापन दिए गए ताकि दूरवर्ती क्षेत्रों में बसे हुए लोगों के बीच खुला स्कूल प्रणाली का प्रचार किया जा सके। प्रचार सामग्री को राज्यों में शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय के.मा.शि.बो. से संबद्ध स्कूलों, प्रायोजित एजेंसियों तथा संसाधन-एवं-अध्ययन केन्द्रों को प्रचार सामग्री भी भेजी गयी ताकि वे इसे अन्य इच्छुक व्यक्तियों एवं एजेंसियों को अग्रेषित कर सकें।

छात्रों की संख्या

5.9.3 खुला स्कूल वर्ष 1979 में स्थापना के साथ ही माध्यमिक स्कूल परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम प्रदान कर रहा था। जिन छात्रों ने माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है उनके लिए सतत् शिक्षा की जरूरतों को पूरा करने के लिए इसने चालू वर्ष में टंकण विद्या, आशुलिपि और सचिवालय पद्धति में व्यावसायिक पाठ्यक्रम के पैकेज सहित विज्ञान, वाणिज्य तथा मानविकी में सीनियर सैकण्डरी पाठ्यक्रम शुरू किए। इस प्रयोजनार्थ 5600 छात्रों ने दाखिला लिया।

5.9.4 इस योजना के अंतर्गत पहली परीक्षा अप्रैल, 1983 में आयोजित की गयी। नामांकन में प्रथम वर्ष के 1634 के मुकाबले 1987-88 में 17052 तक की वृद्धि हुई है। वर्ष 1988-89 के दौरान अब तक 18167 छात्रों की दाखिल किया गया और इस संख्या के 20000 तक बढ़ जाने की आशा है। एक बार दाखिल छात्र अधिकतम पांच वर्ष की अवधि तक अथवा जब तक वह पाचों विषय उत्तीर्ण नहीं कर लेता, दाखिल रह सकता है। इस समय माध्यमिक पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों का कुल संचयी दाखिला 57,337 है।

प्रकाशन

5.9.5 खुला स्कूल प्रत्येक वर्ष कई विवरणिकाएं प्रकाशित करता है और उन्हें अध्ययन सामग्री के रूप में छात्रों को भेजता है। वर्ष 1988-89 में 90 प्रकाशन मुद्रित कराए गए।

नए संसाधन एवं-अध्ययन केन्द्र

5.9.6 सप्ताह के अन्त और छुट्टियों के दौरान खुला स्कूल अपने संसाधन एवं-अध्ययन केन्द्रों में व्यक्तिगत सम्पर्क कार्यक्रमों का आयोजन करता है। मद्रास, जयपुर, सिक्किम तथा अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह को शामिल करते हुए पूरे भारत में इस प्रयोजनार्थ इक्कीस संसाधन-एवं-अध्ययन केन्द्र पहले ही कार्य कर रहे हैं। कलकत्ता में अब एक नया केन्द्र खोला जा रहा है। आलोच्य वर्ष के दौरान दिल्ली में भी एक नया केन्द्र अर्थात् माउन्ट कारमल स्कूल, आनन्द निकेतन नई दिल्ली में खोला गया।

5.9.7 इसके अलावा, खुला स्कूल, संसाधन-एवं-अध्ययन केन्द्र, सुस्थापित संस्थानों को खुला स्कूल पाठ्यक्रमों के लिए उम्मीदवारों के प्रयोजन के लिए तथा संसाधन एवं-अध्ययन केन्द्रों के अनुरूप उनके लिए सम्पर्क कक्षाएं आयोजित करने के लिए प्रत्यायित करता है। वर्ष 1988-89 में चौबीस नयी संस्थाओं को प्रत्यायित किया गया जिससे इन संस्थाओं की संख्या 72 हो गयी।

5.9.8 राष्ट्रीय खुला स्कूल पर एक परियोजना रिपोर्ट तैयार की गयी जिसकी जांच की जा रही है। राष्ट्रीय खुला स्कूल के गठन का निर्णय यथाशीघ्र लिया जाएगा।

विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा

5.10.1 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में सामान्य स्कूलों में सामान्य बच्चों के साथ कम विकलांगता वाले बच्चों की समन्वित शिक्षा पर इस उद्देश्य से बल दिया गया है ताकि ऐसे बच्चों का सामान्य विकास हो सके तथा वे जीवन का सामना उत्साह और विश्वास से कर सकें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति और रा.शि.नी. के कार्यान्वयन के लिए तैयार की गयी कार्रवाई योजना में निहित मार्गदर्शी रूपरेखाओं को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1987-88 के दौरान विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की योजना की पूर्णतया समीक्षा की गयी तथा इसे संशोधित किया गया। स्कूलों में अपेक्षित सुविधाओं का सृजन करने के लिए इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों/स्वैच्छिक संगठनों को शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। विकलांग बच्चों को पुस्तक एवं लेखन भत्ता, यात्रा भत्ता, वर्दी भत्ता, पाठक भत्ता (केवल नेत्रहीन बच्चों के लिए जिनमें विकलांगता अधिक हो) उपस्कर भत्ता छात्रावास प्रभार (जहां आवश्यक हों) जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं इसके अलावा, इस योजना में अध्यापकों के वेतन और प्रोत्साहन, संसाधन और मूल्यांकन कक्षों की स्थापना, शिक्षकों के प्रशिक्षण, स्कूलों में वास्तुशिल्पीय संबंधी बाधाओं के उन्मूलन, विकलांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षण सामग्री का विकास और प्रकाशन आदि की लागत को पूरा करने की व्यवस्था है। विकलांग बच्चों के शिक्षकों के लिए विशेष शिक्षा पाठ्यक्रम चलाने वाले

चुनिन्दा विश्वविद्यालयों/संस्थाओं को वि.अ.आर. के जरिए भी सहायता दी जाती है। रा.शै.अ. तथा प्र.प. और क्षेत्रीय शिक्षा कालेजों द्वारा शिक्षण सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

5.10.2 यह योजना इस समय 18 राज्यों तथा दो संघ शासित प्रदेशों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, नागालैण्ड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, दिल्ली तथा अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में कार्यान्वित की जा रही है। वर्ष 1987-88 के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की 2.36 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता संस्वीकृत की गयी।

सभी राज्यों संघ शासित क्षेत्रों में IX—XII कक्षाओं की लड़कियों से वसूल किए गए शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति

5.11.1 भारत के राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त अधिवेशन में अपने भाषण में 17 जनवरी, 1985 को घोषणा की थी कि देश भर में XII वीं कक्षा तक की लड़कियों की शिक्षा निःशुल्क कर दी जाएगी। इसके अनुसरण में, राजकीय/सरकारी सहायता प्राप्त/राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के लिए स्थानीय निकाय के स्कूलों में शिक्षा के माध्यमिक/सीनियर माध्यमिक स्तर पर लड़कियों से वसूल किए गए शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति करने के लिए एक योजना बनाई गई थी। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1982-83 को कट-आफ वर्ष के रूप में लिया गया।

5.11.2 यह योजना 1.4.1985 से प्रभावी हुई थी और यह सातवीं पंचवर्षीय योजना की समूची अवधि के लिए चालू रहेगी।

युद्ध के दौरान मारे गए अथवा अपंग हुए सशस्त्र सेना अधिकारियों व कार्मिकों के बच्चों के लिए शैक्षिक सुविधाएं।

5.12.1 वर्ष 1962 में भारत-चीन व 1965 व 1971 में भारत-पाक युद्धों के दौरान मारे गए अथवा स्थाई रूप से अपंग हुए सुरक्षा कार्मिकों तथा अर्ध सेना बलों के कार्मिकों तथा अर्ध सेना बलों के कार्मिकों के बच्चों के लिए केन्द्र सरकार तथा अधिकांश राज्य सरकारों व केन्द्र शासित प्रशासनों ने शैक्षिक सुविधाएं देना जारी रखा।

5.12.2 ये सुविधाएं श्रीलंका कार्रवाई के दौरान मारे गए/अपंग हुए भारतीय शांति सेना बलों/के. आ .पु.ब. के कर्मचारियों के लिए तथा सियाचिन क्षेत्र में मेघदूत आपरेशन कार्रवाई में मारे गए अथवा अपंग हुए सशस्त्र सेना कार्मिकों के बच्चों के लिए भी बढ़ा दी गई हैं।

5.12.3 वर्ष 1987-88 में 16 विद्यार्थियों द्वारा इन सुविधाओं का उपयोग किया गया।

योग की प्रोन्नति

5.13.1 शारीरिक स्वस्थता को बढ़ाने में योग की सम्भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, देश में शारीरिक शिक्षा के विकास के लिए मंत्रालय के समूचे कार्यक्रम के भाग के रूप में, योग की प्रोन्नति के लिए एक योजना द्वितीय पंचवर्षीय योजना से कार्यान्वित कर रहा है। यह योजना रख-रखाव के लिए अखिल भारतीय स्वरूप की योग संस्थाओं को वित्तीय सहायता के साथ-साथ चिकित्सीय पक्षों के अलावा योग के विभिन्न पक्षों में मूल अनुसंधान और/अथवा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रोन्नति पर विकासात्मक व्यय की व्यवस्था करती है। योग संस्थाओं को योग चिकित्सीय पक्षों की प्रोन्नति के लिए वित्तीय सहायता, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दी जा रही है।

5.13.2 इस योजना के अन्तर्गत कैवल्य धाम श्रीमन माधव योग मन्दिर समिति, लोनावाला (पुणे) को, अनुसंधान तथा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए, अपने अनुरक्षण तथा विकासात्मक व्यय दोनों के लिए ही सहायता मिलनी जारी है।

5.13.3 केन्द्रीय विद्यालयों में प्रयोग के तौर पर 1981-82 में एक वर्ष की अवधि के लिए योग को एक अलग विषय के रूप में, शुरू किया गया था। इस प्रयोग का मूल्यांकन किया गया और केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने निर्णय लिया कि सभी केन्द्रीय विद्यालयों में नियमित आधार पर योग पढ़ाया जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्देशों को ध्यान में रखकर, बड़े पैमाने पर स्कूलों में योग शिक्षा आरम्भ करने का प्रस्ताव है। तदनुसार, यह निर्णय किया गया है कि वर्ष 1988-89 से स्कूलों तथा प्रशिक्षण संस्थानों की सहायता के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना शुरू की जाए।

शिक्षा में संस्कृति/कला/मूल्यों को सुदृढ़ करने के लिए एजेंसियों को सहायता तथा नवीन कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने वाली शैक्षिक संस्थाओं को सहायता।

5.14.1 शिक्षा के प्रबंध में विचारणीय बात यह है कि इसमें गैर-सरकारी एजेंसियों तथा स्वैच्छिक प्रयासों सहित लोगों की सहभागिता को महत्व दिया जाए जिससे शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में नवीन विचारों तथा व्यवहारों को अधिक बल मिले।

5.14.2 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में यह भी कहा गया है कि भारत की सांस्कृतिक सम्पदा के बारे में शिक्षा को सुदृढ़ बनाना तथा कला शिक्षा जैसे सृजनात्मक क्रियाकलापों पर बल देना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए सांस्कृतिक कला/मूल्यों को सुदृढ़ बनाने के लिए एजेंसियों को सहायता के लिए एक केन्द्रीय योजना, 1987 में तैयार की गई थी।

योजना के विशिष्ट उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- शैक्षिक निवेश तथा प्रक्रिया में सांस्कृतिक निवेश को सुदृढ़ बनाना,
- स्कूल प्रणाली में मूल्य शिक्षा को सुदृढ़ बनाना,
- स्कूल स्तर पर पायनियर और नवीन कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना।

निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए सहायता प्रदान की जाती है:–

- अध्ययन सामग्री/शिक्षण/अध्ययन सहायता सामग्री विकसित करना,
- शिक्षक प्रशिक्षण,
- नए परिवर्तन और प्रयोगों को बढ़ावा देने के लिए बैठकें, सम्मेलन सेमिनार,
- राष्ट्रीय महत्व की नवीन तथा प्रयोगात्मक परियोजनाएं,
- शिक्षा को संस्कृति/कला/मूल्य शिक्षा क्रिया-कलापों के साथ जोड़ने वाले क्रियाकलाप/कार्यक्रम।
- नवीन कार्यक्रमों के लिए स्कूलों में अवस्थापना का विकास।

5.14.3 वर्ष के दौरान, योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित संगठनों को 9.28 लाख रु. की राशि मुक्त की गई थी:–

(क) रामकृष्णन नैतिक तथा आध्यात्मिक शिक्षा संस्थान, मैसूर को नैतिक तथा आध्यात्मिक शिक्षा शिक्षण के लिए हाई स्कूल शिक्षकों को सेवारत प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए दिया गया।

(ख) एक समेकित शिक्षा तथा रहन-सहन प्रशिक्षण, शारीरिक शिक्षा तथा दोपहर को निशुल्क पौष्टिक आहार देने, निशुल्कः पुस्तकें तथा काफी संख्या में अ. जाति/अ.ज. जाति के छात्रों को निशुल्क वर्दियां प्रदान करने के लिए ओल्कोट मेमोरियल स्कूल, मद्रास को सहायता।

(ग) छात्रों, विशेषकर गर्ल गाईडों, झुग्गी झोपड़ी से युवा आदि के साथ कार्यशाला आयोजित करने तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला तथा महिलाओं पर वीडियो फिल्म तैयार करने के लिए अल्लरिपु, नई दिल्ली की सहायता।

(घ) शिक्षा तथा कठपुतली में थिएटर के उपयोग के लिए कोरस रिपेरेटरी थिएटर, इम्फाल की सहायता।

(ङ) ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों तथा जरूरतमंद महिलाओं तथा बच्चों के आम कल्याण के लिए धर्मार्थ क्रियाकलापों के लिए कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक न्यास, इन्दौर को सहायता।

(च) देश के युवाओं में, परम्परागत भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सिपकमैसी, नई दिल्ली को सहायता, जिसका मुख्य माध्यम शास्त्रीय भारतीय संगीत तथा गायन है।

(छ) भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं में स्कूली बच्चों के लिए अनुपूरक शैक्षिक सामग्री की एक श्रृंखला तैयार करने के लिए सांस्कृति संसाधन तथा प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली की सहायता।

(ज) स्थानीय भाषा में शिक्षण सामग्री तथा शिक्षण सहायता का विकास करने के लिए स्कूलों में शैक्षिक निवेश तथा प्रक्रिया में सांस्कृतिक निवेशों को सुदृढ़ बनाने के लिए स्कूल शिक्षा निदेशक, नागालैंड की सहायता।

राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना (एन.पी.ई.पी.)

5.15.1 बढ़ती जनसंख्या की समस्या से निपटने के लिए शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा की परियोजना अप्रैल 1980 से शुरू

की है। परियोजना का पहला चक्र (1980-85) में सफलतापूर्वक पूरा किया। इसका दूसरा चक्र पहली जनवरी, 1986 से प्रारम्भ किया गया। 26 राज्यों तथा संघशासित प्रशासनों में कार्यान्वित की जा रही परियोजना ने दूसरे चक्र का तीसरा वर्ष पूरा कर लिया है। इस परियोजना को संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या निधि तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय जो जनसंख्या शिक्षा का मुख्य मंत्रालय है, के सहयोग से विकसित किया जा रहा है।

5.15.2. कार्यक्रम के मुख्य लक्ष्य इस प्रकार हैं :–

(i) व्यक्तिगत परिवार, सोसाइटी, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तरों में जनसंख्या वृद्धि तथा सामाजिक-आर्थिक विकास की प्रक्रिया के बीच अन्तः सम्पर्क में छात्रों को प्रेरित करना;

(ii) बच्चों तथा शिक्षकों को देश में जनसंख्या की स्थिति के बारे में बताना तथा इस समस्या को दूर करने के लिए भारत सरकार के लक्ष्य तथा प्रयास,

(iii) राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरों में विश्वविद्यालय तथा अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम सहित जनसंख्या शिक्षा को औपचारिक शिक्षा प्रणाली के रूप में स्थापित करना,

(iv) जनसंख्या के मामलों में व्यापक रूप से समुदाय को शामिल करने के साथ-साथ शिक्षकों तथा छात्रों में वांछनीय प्रतिक्रिया तथा बर्ताव विकसित करना ताकि वे अपने परिवार के बारे में तर्कसंगत निर्णय ले सकें और जीवन की कोटि के बारे में सोच सकें, जैसा वे जीना चाहते है।

5.15.3 सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस परियोजना के कार्यक्षेत्र को +2 स्तर पर (कक्षा x1 और x11) छात्रों तथा शिक्षकों को शामिल करने के लिए बढ़ाया जाएगा चूंकि इस समय छात्रों का प्रजनक आयु वर्ग में प्रवेश हो जाने के कारण इसे बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ग माना गया है। इस परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए राज्यो द्वारा अपेक्षित वित्तीय तथा अन्य अपेक्षाएं रा.शै.अ.प्र. परिषद् के माध्यम से, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी। रा.शै.अ.प्र. परिषद् तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

5.15.4 राज्यों तथा संघ शासित प्रशासनों द्वारा किए जा रहे परियोजना कार्यकलापों में जमा दो-स्तर, अनौपचारिक शिक्षा क्षेत्र तथा विभिन्न लक्षित वर्गों के प्रशिक्षण, शिक्षकों की अवस्थापना तथा अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के लिए शिक्षक परियोजना के विभिन्न घटकों का मूल्यांकन तथा सह पाठ्यचर्या कार्यकलाप सामग्री विकास पर बल दिया गया है। पाठ्यपुस्तकों में जनसंख्या शिक्षा तत्वों के समेकन के संबंध में जनसंख्या शिक्षा सैलों के प्रयासों को संशोधित किया गया जिससे अधिकांश राज्यों में पाठ्यपुस्तकों में संशोधन प्रारम्भ करने में विलम्ब हुआ।

5.15.5 वर्ष 1987-88 के अन्त तक अधिक से अधिक 18 राज्यों/संघ शासित प्रशासनों ने जमा दो स्तर के लिए जनसंख्या शिक्षा में पाठ्यचर्या विकास के कार्यकलाप को पूरा किया। इन दस्तावेजों से जनसंख्या शिक्षा के तत्वों को पाठयचर्या और पाठयपुस्तकों में समेकित करने में सहायता मिलेगी जो कि रा.शि. नीति, 1986 के कार्यान्वयन के आधार पर संशोधित किया जा रहा है। सोलह राज्यों/संघ शासित प्रशासनों ने जनसंख्या शिक्षा तत्वों को पाठयक्रम में शामिल किया है। पंद्रह राज्यों तथा संघ शासित प्रशासनों ने अनौपचारिक क्षेत्र के लिए जनसंख्या शिक्षा में पाठ्यचर्या विकसित की है और इनमें से आठ राज्य इन तत्वों को, चल रही पाठ्यचर्या में समेकित कर पाए हैं। बीस राज्यों ने प्रारम्भिक शिक्षक प्रशिक्षण के लिए पाठ्यचर्या विकसित की है और उनमें से चौदह राज्यों ने जनसंख्या शिक्षा के तत्वों को चल रही पाठ्यचर्या में शामिल किया है। पिछले वर्ष की 367 की संख्या के मुकाबले में चालू वर्ष के दौरान जनसंख्या शिक्षा में शैक्षिक तथा प्रशिक्षण सामग्री के 435 शीर्षक निकाले गए हैं। राज्यों तथा संघ शासित प्रशासनों ने अनौपचारिक शिक्षा क्षेत्र के लिए 21 शीर्षक प्रकाशित किए। चौदह राज्यों/संघ शासित प्रशासनों में विभिन्न स्तरों पर 41 अनुपूरक अध्ययन सामग्री निकाली और तेरह राज्यों/संघ शासित प्रशासनों ने समाचारों के नियमित अंक प्रकाशित किए। अब तक आकाशवाणी में 403 कार्यक्रमों को प्रसारित किया गया है। चालू वर्ष के दौरान, जनसंख्या शिक्षा पर सोलह कार्यक्रमों को प्रसारित किया गया। अठारह राज्यों/संघ शासित प्रशासनों ने पोस्टर चार्ट, फिलम चार्ट आदि जैसी गैर-प्रक्षेपित सहायक सामग्री को विकसित किया है और नौ राज्यों ने जनसंख्या शिक्षा में श्रव्य दृश्य सामग्री विकसित की है। वर्ष के दौरान राज्यों/संघ शासित प्रशासनों ने 1,04,971 शिक्षकों, 1761 प्रमुख तथा संसाधन व्यक्तियों तथा अनौपचारिक शिक्षा क्षेत्र के 9595 शिक्षकों को अवस्थापना प्रदान की। रा.शि. नीति के अनुसार आयोजित जन-शिक्षक अवस्थापना कार्यक्रम के अन्तर्गत मई-अगस्त, 1988 के दौरान

लगभग 5,00,000 शिक्षकों को अवस्थापना प्रदान की गई। पन्द्रह राज्यों/संघ शासित प्रशासनों ने विभिन्न प्रकार के सह पाठ्यचर्या कार्यक्रम आयोजित किए जैसे निबंध प्रतियोगिता, चित्रकारी प्रतियोगिता, प्रश्न प्रतियोगिता तथा वाद-विवाद प्रतियोगिता आदि। ग्राम अपनाने कार्यक्रम के अन्तर्गत 17 राज्यों/संघ शासित प्रशासनों ने 137 गावों को चुना है जिसमें जनसंख्या शिक्षा कार्यकलाप आयोजित किए जा रहे हैं।

स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम

5.16.1 इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा रा.शै.अ. तथा प्र. परिषद/राज्य सरकारों आदि के परामर्श से किया जा रहा है।

5.16.2 वर्ष 1988-89 के दौरान 5 भारतीय छात्रों के एक दल ने इंडो-यू.एस. छात्र विनिमय कार्यक्रम के अन्तर्गत संयुक्त राज्य अमरीका का दौरा किया और पारस्परिक आधार पर 10 अमरीकी छात्रों के एक दल ने भारत का दौरा किया।

स्कूल पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा

5.17.1 भारत सरकार ने वर्ष 1981 से राष्ट्रीय एकता के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए स्कूल पाठ्यपुस्तकों के मूल्यांकन का एक कार्यक्रम शुरू किया है। यह राज्य सरकारों द्वारा विकेंद्रीकृत आधार पर रा.शै.अ. प्र. परिषद द्वारा तैयार की गई मार्गदर्शी रूपरेखाओं पर कार्यान्वित किया जाएगा। प्रारंभ में शुरूआत के तौर पर यह समीक्षा इतिहास और भाषाओं की पाठ्यपुस्तकों तक ही सीमित रखी गयी थी। छात्रों में राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देने और अस्पृश्यता, वर्ग भेद, प्रादेशिकता, जातिवाद और साम्प्रदायिकता आदि को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में भड़काने वाले तत्वों को पहचानने तथा उनको दूर करने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। लगभग सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में कार्यक्रम का प्रथम चरण पूरा किया जा चुका है।

5.17.2 कार्यक्रम के द्वितीय चरण में राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में भूगोल, नागरिक शास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थ-शास्त्र इत्यादि की स्कूली पाठ्यपुस्तकों का मूल्यांकन कार्यक्रम प्रारंभ करने का अनुरोध किया गया है। अधिकांश राज्यों ने यह सूचित किया है कि नई शिक्षा नीति, 1986 के अनुसार पाठ्यक्रम में संभावित परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए नई पाठ्यपुस्तकें और शिक्षण सामग्री अभी विकसित की जानी है और इसीलिए कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। तथापि, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, मिजोरम जैसे कुछ राज्यों और संघशासित क्षेत्र दिल्ली ने पहले ही यह कार्य समाप्त कर लिया है। हरियाणा ने भी आठवीं कक्षा तक की पाठ्यपुस्तकों के मूल्यांकन का कार्य प्रारंभ किया है।

5.17.3 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से पाठ्यपुस्तकों की तैयारी और विकास के अंग के रूप में पाठ्यपुस्तकों के सतत् मूल्यांकन के लिए एक अन्तः स्थापित प्रणाली बनाने का अनुरोध किया गया है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्र. परिषद ने भी आगे प्रतिवर्ष नमूने के आधार पर राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की पाठ्यपुस्तकों के मूल्यांकन/पुनरीक्षण का एक कार्यक्रम आरम्भ किया ताकि राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधक सामग्री की पहचान की जा सके और राष्ट्रीय एकता के आदर्शों को प्रोन्नत करने वाली सामग्री को विशेष स्थान दिया जा सके। परिषद राज्यों की चुनिन्दा पाठ्यपुस्तक लेखकों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम का आयोजन भी कर रहा है। इस समय भारत सरकार एक संचालन समिति के गठन पर विचार कर रही है जिससे राज्यों में समीक्षा के कार्य को प्रणालीबद्ध तरीके से जारी रखने की सुनिश्चित व्यवस्था की जा सके।

शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार

5.18.1 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कारों की योजना शिक्षकों के सम्मान को बढ़ाने तथा स्कूलों में प्रशंसनीय सेवाओं को सार्वजनिक सम्मान देने के लक्ष्य से वर्ष 1958-59 में आरम्भ हुई थी। वर्ष 1967-68 में इस योजना का कार्यक्षेत्र परम्परागत आधार पर चलने वाला संस्कृत पाठशालाओं, तोल्स आदि के शिक्षकों को शामिल करके, विस्तृत किया गया था। वर्ष 1978 में इस योजना को और विस्तृत किया गया ताकि परम्परागत आधार पर चलने वाले मदरसा के अरबी/फारसी शिक्षकों को भी शामिल किया जा सके। राष्ट्रीय शिक्षक आयोग से प्राप्त सिफारिशों के आधार पर, शिक्षकों के लिए पुरस्कार राशि वर्ष 1987-88 से प्रति पुरस्कार 2,500 रुपये से बढ़ा करके 5,000 रुपये प्रति पुरस्कार कर दी गई थी। इसके साथ, इस योजना के अन्तर्गत शिक्षकों को दिए जाने वाले पुरस्कारों की संख्या वर्ष 1988-89 से 186 से 300 तक बढ़ा दी गई है। कुल 186 पुरस्कारों में से, 163 शिक्षक वर्ष

1987 के दौरान राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए चुने गए थे। 5 सितम्बर, 1988 को एक विशेष समारोह में भारत के राष्ट्रपति द्वारा इन शिक्षकों को पुरस्कार दिए गए थे। वर्ष 1988 के लिए, अब तक कुल 200 शिक्षक चुने गए हैं। इनमें आन्ध्र प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, हरियाणा, उड़ीसा, पंजाब, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह, चण्डीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दिल्ली, पाण्डिचेरी, के राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तथा केन्द्रीय विद्यालयों के 124 प्राथमिक शिक्षक तथा 76 माध्यमिक शिक्षक शामिल हैं। शेष राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में चयन हो रहा है। यह योजना वर्ष 1989-90 में भी जारी रखने का प्रस्ताव है।

राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान

5.18.2 राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान की स्थापना पूर्व अक्षय निधि अधिनियम 1890 के अन्तर्गत 1962 में की गयी थी। इस प्रतिष्ठान का मुख्य उद्देश्य उन शिक्षकों तथा उनके आश्रितों को सहायता प्रदान करना है जो दीन परिस्थितियों में हैं। प्रतिष्ठान की निधियों का समेकन संघ, राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों और केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा दिए गए अंशदानों तथा राज्यों/संघ शासित प्रदेशों/केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा एकत्रित राशि द्वारा किया जाता है। प्रतिष्ठान के धन संग्रह को मियादी बचतों में लगा दिया गया है और उससे प्राप्त ब्याज को निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए वित्तीय सहायता देने हेतु उपयोग में लाया जाता है:–

- शिक्षक सदन के निर्माण कार्य
- विख्यात शिक्षकों जिन्होंने सराहनीय सेवाएं प्रदान की हैं, को वेतन सहित छुट्टी प्रदान करना,
- स्कूल शिक्षकों के बच्चों की व्यावसायिक शिक्षा के लिए सहायता देना
- गंभीर बीमारियों से ग्रस्त शिक्षकों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति
- गंभीर दुर्घटना के मामले में निःशुल्क सहायता।
- शिक्षकों की शैक्षिक गतिविधियों के लिए आर्थिक सहायता।
- आजादी की 40वीं वर्षगांठ और जवाहरलाल नेहरू जन्म शताब्दी समारोह के संबंध में शिक्षकों के भ्रमण दौरे।

5.18.3 उपरोक्त के अलावा, प्रतिष्ठान किसी मान्यता प्राप्त प्राथमिक, मिडिल और उच्चतर माध्यमिक स्कूल में कार्यरत, 30 वर्ष से अधिक की दोष रहित, प्रशंसनीय सेवा वाले तीन अध्यापकों को प्रोफेसर डी.सी. शर्मा मेमोरियल पुरस्कार प्रदान करता है।

5.18.4 वर्ष के दौरान प्रतिष्ठान ने निम्नलिखित वित्तीय सहायता प्रदान की है:–

- केन्द्रीय विद्यालय, सैक्टर-IV, आर.के. पुरम, नई दिल्ली में कार्यरत शिक्षक की मृत्यु के उपरांत मृतक की पत्नी को 10,000/- रु. की राशि दी गयी।
- उड़ीसा राज्य के छः शिक्षकों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में 60,000/- रुपए (प्रत्येक को 10,000/-रु.) की राशि दी गयी।
- उड़ीसा राज्य से 43 लब्धप्रतिष्ठ शिक्षकों को 84,350/- रुपए की राशि सवेतन छुट्टी के लिए प्रदान की गयी।
- निम्नलिखित मामलों में शिक्षक सदनों के निर्माण कार्य के लिए वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई:–
- अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक फैडरेशन को जनकपुरी, नई दिल्ली में शिक्षक भवन को पूरा करने के लिए 6 लाख रुपए।
- पुणे में शिक्षक भवन के निर्माण कार्य के लिए 20 लाख रुपए।
- मध्य प्रदेश में सांची, खुजराहो, शिवपुरी, माण्डव और भाराघाट में पांच शिक्षक भवनों के निर्माण कार्य के लिए 50 लाख रुपए।
- आजादी की 40वीं वर्ष गांठ तथा जवाहरलाल नेहरू जन्म शताब्दी समारोहों के उपलक्ष में शिक्षकों के भ्रमण दौरे के लिए वित्तीय सहायता के लिए विभिन्न राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों से प्राप्त प्रस्तावों के समर्थन में।
- वर्ष 1988 के लिए प्रोफेसर डी.सी. शर्मा मेमोरियल पुरस्कार निम्नलिखित तीन शिक्षकों को दिया गया:–

□ श्रीमती कमला राधाकृष्णन,
मुख्य अध्यापिका,
राजकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल,
एग्मोर, मद्रास।

□ श्रीमती जाहिदा अहमद,
सहायक शिक्षक,
राजकीय बालिका उच्च स्कूल,
बरहामपुर।

नवोदय विद्यालय
चुने गए छात्रों का संयोजन (कुल)

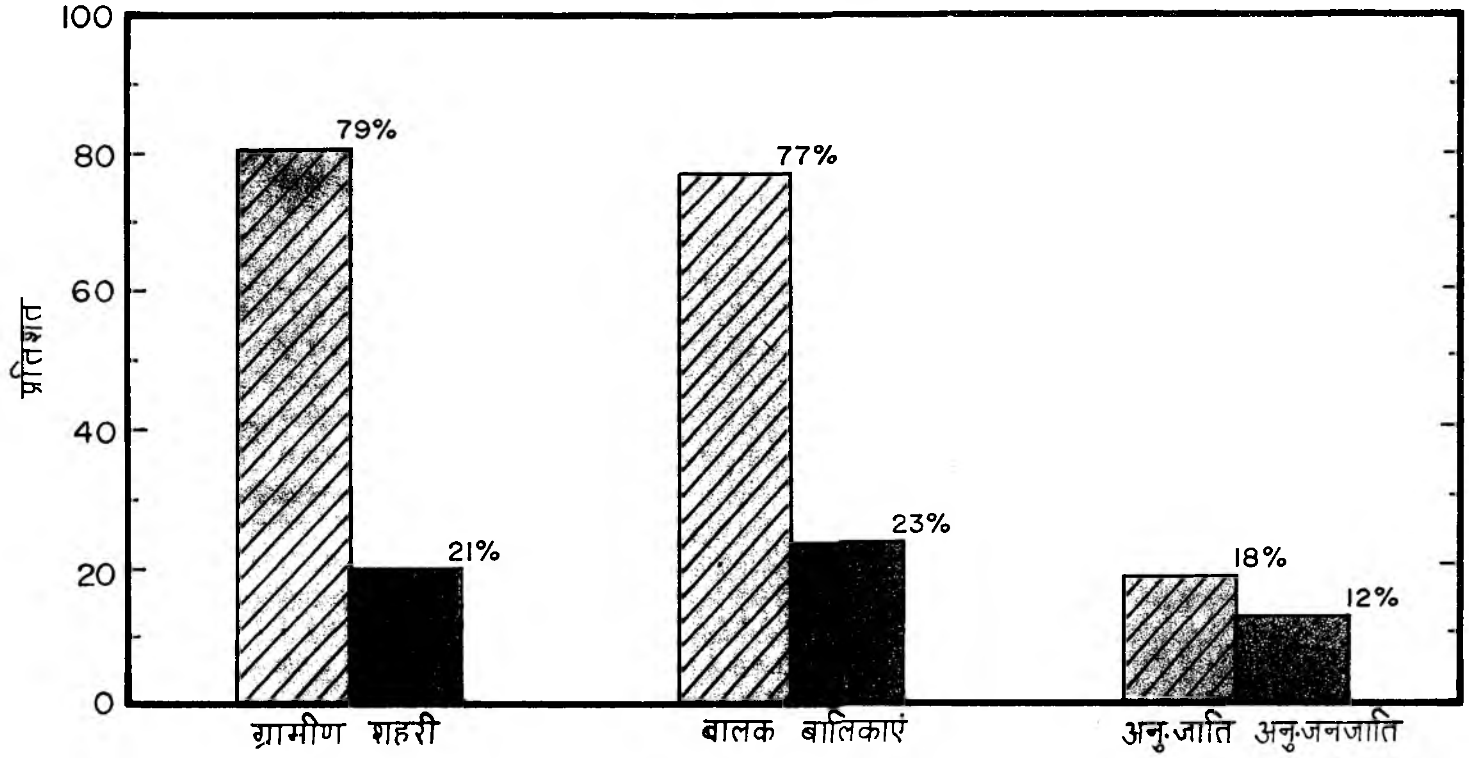

माता-पिता की आर्थिक स्थिति (पहले दो वर्ष)

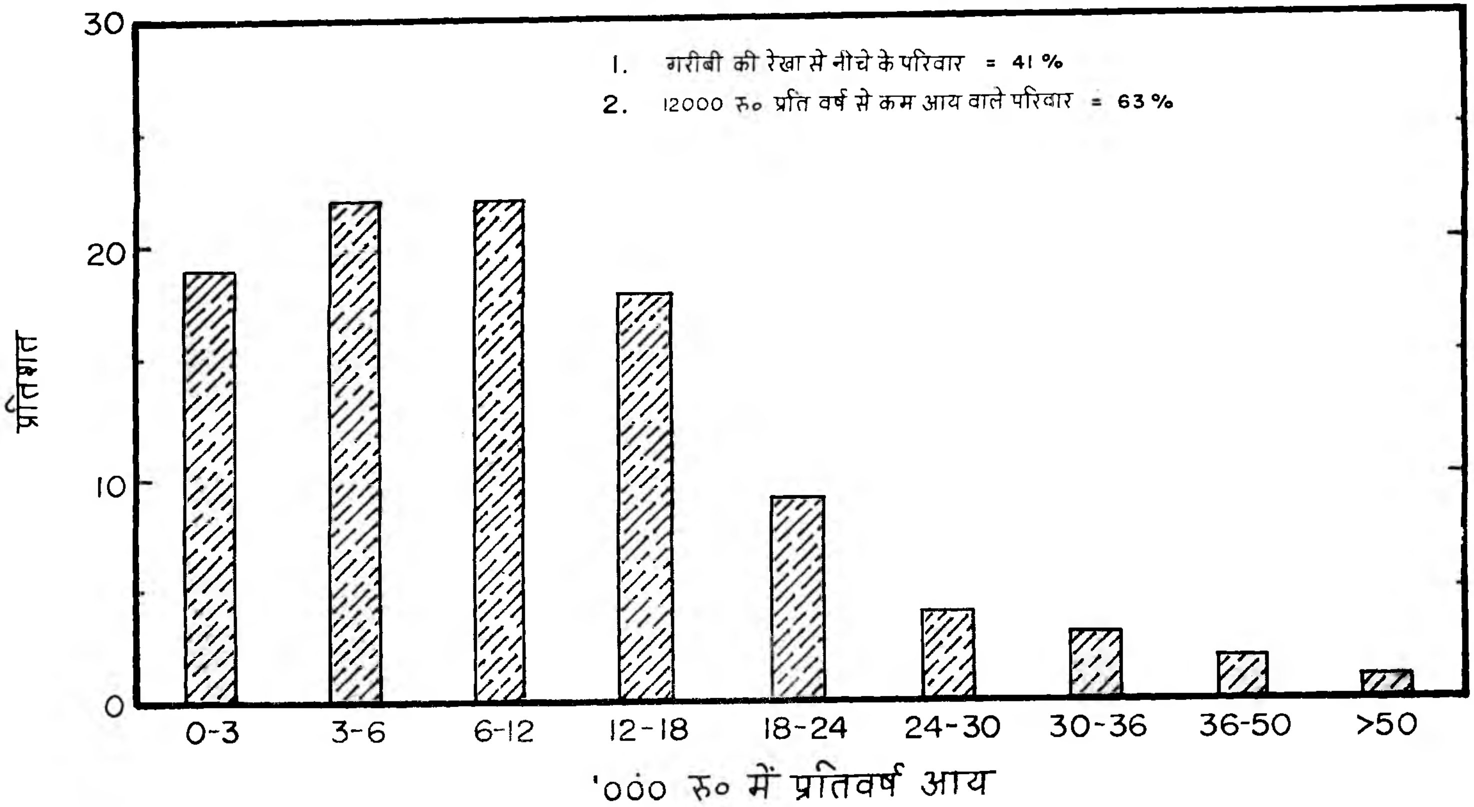

- श्री जवाहरलाल श्रीवास्तव,
  हैडमास्टर,
  राजकीय प्राथमिक स्कूल,
  जवाहर नगर, ग्वालियर।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

5.19.1 सरकार द्वारा 1962 में केन्द्रीय विद्यालयों की योजना का अनुमोदन द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिश पर किया गया ताकि रक्षा कार्मिकों सहित केन्द्रीय सरकार के उन स्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके, जिनका स्थानांतरण बार-बार होता रहता था। इस योजना का दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना था। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पूरे भारत में केन्द्रीय विद्यालयों का एक समान झंडा, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों, शिक्षण माध्यम, बच्चों की वर्दी का रंग भी एक जैसा ही है। इस समय केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अधीन 729 केन्द्रीय विद्यालय कार्यरत हैं जबकि इसके मुकाबले में 30.4.1988 को 690 विद्यालय थे। ये विद्यालय राष्ट्रीय स्तर पर केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय है। प्रशासनिक सुविधा के लिए केन्द्रीय विद्यालय संगठन को 15 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है।

5.19.2 केन्द्रीय विद्यालय शिक्षा की कोटि में सुधार के लिए सम्मिलित प्रयास कर रहे है। 1988 में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परीक्षा में केन्द्रीय अखिल भारतीय सीनियर माध्यमिक शिक्षा (ए.आई.एस.एस.ई.) एवं ए.आई.एस.एस.सी.ई. में केन्द्रीय विद्यालयों के परिणाम क्रमश: 9% और 16% ऊँचे थे। लगभग 15% छात्रों ने 75% से अधिक अंक प्राप्त किए तथा लगभग 40% छात्रों ने 60 से 74 प्रतिशत के बीच अंक प्राप्त किए। इस प्रकार 55% छात्रों ने प्रथम श्रेणी के अंक प्राप्त किए। इस वर्ष, केन्द्रीय विद्यालय के छात्रों ने हिंदी इलेक्टिव, हिंदी कोर, वाणिज्य, गणित, रसायन विज्ञान तथा जीव विज्ञान में अधिकतम अंक प्राप्त किए।

5.19.3 केन्द्रीय विद्यालय के छात्र राष्ट्रीय कैडेट कोर, स्काउट और गाइडस, सामूहिक गायन, लम्बी पहाड़ी यात्रा और पर्वतारोहण खेलों आदि में भाग लेते हैं। प्रत्येक वर्ष लगभग 10,000 छात्रों को पर्वतारोहण का प्रशिक्षण दिया जाता है और बड़ी संख्या में छात्रों को लम्बी पहाड़ी यात्रा (ट्रैकिंग) पर भेजा जाता है। केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने 11 से 20 अक्तूबर, 1988 तक दिल्ली में अपने राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जिसमें सभी 15 क्षेत्रों के लगभग 3500 छात्रों ने भाग लिया। इससे पहले मई-जून, 1988 के दौरान ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविरों में 9 खेलों का आयोजन किया गया था। लगभग 350 चुने हुए छात्रों को गहन प्रशिक्षण दिया गया। नवम्बर और दिसम्बर, 1988 के दौरान केन्द्रीय विद्यालय संगठन की राष्ट्रीय टीमों ने फुटबाल, हॉकी, वालीबाल, बैडमिन्टन, टेबल टेनिस, बास्केट-बाल, क्रिकेट और एथलेटिक्स की एस.जी.एफआई. प्रतिस्पर्द्धाओं में भाग लिया। एस.जी.एफ.आई. प्रतिस्पर्द्धाओं में उनके भाग लेने से पहले इन टीमों के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए गए थे। 28 से 31 दिसम्बर, 1988 तक बम्बई में केन्द्रीय विद्यालय संगठन के स्काऊटों और गाइडों की राज्य रैली का आयोजन किया गया था जिसमें लगभग 1200 स्काउटों और गाइडों ने भाग लिया।

5.19.4 नियमानुसार, प्रत्येक केन्द्रीय विद्यालय में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबंधित कर्मचारियों के बच्चों के लिए क्रमश: 15 और साढ़े सात प्रतिशत नए दाखिले आरक्षित होते हैं। प्रत्येक केन्द्रीय विद्यालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को इतने प्रतिशत तक दाखिला देने के प्रयास किए गए, चाहे इसके लिए अर्हक स्तरों पर छूट भी देनी पड़ी हो। आरक्षित सीटों पर अ.जा./अ.ज.जा. के उम्मीदवारों को शत-प्रतिशत दाखिला देने का लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से, दाखिले के समय मुख्य-मुख्य राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचार पत्रों के माध्यम से केन्द्रीय विद्यालयों में अ.जा./अ.ज.जा. में उम्मीदवारों के दाखिले के लिए विज्ञापन देने का निर्णय किया गया है जिसमें उनके लिए आरक्षित सीटों का प्रतिशत भी दर्शाया गया हो।

5.19.5 संगठन सम्मेलन और सेवाकालीन शिक्षण पाठ्यक्रमों के माध्यम से अपने शिक्षण और गैर शिक्षण स्टाफ की दक्षता में सुधार करने के लिए लगातार कार्यक्रम आयोजित करता रहता है। वर्ष 1988-89 के दौरान स्टाफ के विभिन्न वर्गों के लिए 111 सेवाकालीन शिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। इनमें से एक उन उप प्रधानाचार्यों और पी.जी.टी. शिक्षकों के लिए प्रवेश पाठ्यक्रम था जो प्रधानाचार्य के रूप में चुने गए थे। यह पाठ्यक्रम सहभागियों द्वारा उनके सम्बन्धित

विद्यालयों में प्रधानाचार्य के रूप में अपना कार्यभार ग्रहण से पूर्व 25 जनवरी, 1988 से 23 अप्रैल, 1988 तक आयोजित किया गया था। चार शिक्षकों को जनवरी, 1989 से अप्रैल, 1989 तक ब्रिटिश काउंसिल के अंग्रेजी भाषा शिक्षण परियोजना में भाग लेने के लिए यू.के. भेजा गया है। इस संबंध में सभी खर्चे ब्रिटिश काउंसिल द्वारा वहन किए जाएंगे।

5.19.6 सभी केन्द्रीय विद्यालयों के लिए शिक्षकों के पदों का विज्ञापन अखिल भारतीय आधार पर किया जाता है और देश के सभी भागों में शिक्षकों की सेवा शर्तें एक समान है। वरिष्ठता सूचियां भी तैयार की जाती हैं और पदोन्नतियां अखिल भारतीय स्तर पर प्रभावित होतीं हैं। केन्द्रीय विद्यालयों के लिए पी.जी.टी. शिक्षकों, उप प्रधानाचार्यों, प्रधानाचार्यों तथा अन्य उच्च पद, केन्द्रीय आधार पर भरे जाते हैं। जहां तक टी.जी.टी. शिक्षकों, पी.आर.टी. और शिक्षकों के अन्य वर्गों का सम्बन्ध है, उनकी भर्ती अखिल भारतीय आधार पर क्षेत्रीय स्तर पर की जाती है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और कश्मीर राज्य के प्रार्थियों को 5 वर्ष और असम के निवासियों को 6 वर्षों, तक की आयु में छूट, इन क्षेत्रों से शिक्षकों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए दी जाती है। इसी प्रकार महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने तथा उनको शिक्षण व्यवसाय की ओर आकर्षित करने के लिए, 1987-88 से सभी वर्गों के शिक्षण पदों में भर्ती हेतु महिला उम्मीदवारों को आयु में 10 वर्षों तक की छूट की अनुमति दी गई है।

5.19.7 केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा दिसम्बर, 1988 से केन्द्रीय विद्यालय में त्रिभाषा सूत्र का कार्यान्वयन शुरू कर दिया गया है। इस सूत्र के अंतर्गत हिंदी और अंग्रेजी, अब से I से X कक्षा तक अनिवार्य भाषाओं के रूप में पढ़ाई जाएंगी। अहिन्दी भाषी राज्यों में केन्द्रीय विद्यालयों में उस राज्य की क्षेत्रीय भाषा पढ़ाई जाएगी, जहां वे स्थित हैं। हिंदी भाषी क्षेत्रों में, अधिकांश केन्द्रीय विद्यालयों में, तीसरी भाषा के रूप में एक दक्षिण-भारतीय भाषा पढ़ाई जाएगी जबकि बाकी विद्यालयों में अन्य आधुनिक भारतीय भाषाएं पढ़ाई जाएंगी।

5.19.8 स्कूलों में कम्प्यूटर साक्षरता एवं अध्ययन की मुख्य परियोजना जिसे 1984-85 में 17 चुनिंदा केन्द्रीय विद्यालयों में शुरू किया गया था, उसे वर्ष 1988-89 में जारी रखा गया। परियोजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:–

– छात्रों को कम्प्यूटर का विस्तृत ज्ञान तथा उसके उपयोग की जानकारी प्रदान करना, और
– मनुष्य के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कम्प्यूटर के प्रयोग तथा नियंत्रण एवं सूचना एकत्रित करने के साधन के रूप में कम्प्यूटर की क्षमता से छात्रों को परिचित कराना।

30.4.1988 तक इस परियोजना के अंतर्गत केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या 309 थी।

5.19.9 संगठन द्वारा 164 केन्द्रीय विद्यालयों के लिए भवनों का निर्माण किया गया। वर्ष के दौरान 50 और भवन निर्माणधीन हैं। अब तक 72 विद्यालयों में स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण पूरा हो चुका है। 102 केन्द्रीय विद्यालयों में स्टाफ क्वार्टर निर्माणाधीन हैं।

5.19.10 केन्द्रीय विद्यालयों की अत्यधिक मांग को ध्यान में रखते हुए, 1987-90 की अवधि के दौरान प्रतिरक्षा और सिविल क्षेत्रों में प्रतिवर्ष 50 नए केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने का निर्णय किया गया हैं। हमारे नियमों और प्रस्तावों की उपयुक्तता के अनुसार परियोजना क्षेत्र में नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने का भी निर्णय किया गया है। इस निर्णय के अनुसरण में, केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने वर्ष 1988-89 के दौरान 11 परियोजना क्षेत्रों सहित 42 केन्द्रीय विद्यालय खोलने के आदेश जारी किए है।

5.19.11 वर्ष 1988-89 में अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे कर लेने पर केन्द्रीय विद्यालय इस वर्ष अपनी रजत जयन्ती मना रहे है।

केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन

5.20.1 केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन की स्थापना 1961 में एक स्वायत्तशासी संगठन के रूप में की गई थी और इसे सोसायटी पंजीकरण अधिनियम (1860) का XXI वां अधिनियम) के अंतर्गत पंजीकृत किया गया। सोसायटी का उद्देश्य 1959 में तिब्बत में चीनियों द्वारा की गई मार-काट के परिणामस्वरूप भारत आए तिब्बती शरणार्थियों के बच्चों को शिक्षा के लिए संस्थाओं को चलाना, उनका प्रबंध और उनकी मदद करना है।

5.20.2 प्रशासन 30 विद्यालय चला रहा है जिनमें से चार आवासीय विद्यालय हैं और 26 प्रातः कालीन विद्यालय है। ये विद्यालय भारत भर में फैले हैं। इन विद्यालयों का नामांकन 10,000 से अधिक है। ये

विद्यालय केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध हैं और छात्रों को अखिल भारतीय माध्यमिक विद्यालय और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परीक्षाओं के लिए तैयार करते हैं।

5.20.3 प्रशासन तिब्बती बालकों को विद्यालयोपरांत शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी सुविधाएं प्रदान करता है। केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन के विद्यालयों से प्रतिवर्ष उत्तीर्ण होने वाले छात्रों में से 15 को विद्यलय छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। भारत सरकार द्वारा प्रौद्योगिकी, औषधि, मुद्रण और फार्मेसी में तिब्बती छात्रों के लिए आठ स्थान आबंटित किए गए हैं।

5.20.4 तिब्बती बालकों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए 'प्रशासन' तिब्बती शिक्षा परिषद, परम पवित्र दलाई लामा, ब्यूरो, स्पेशल सिक्योरिटी फ्रंटियर शिक्षा और तिब्बती नेहरू स्मारक, प्रतिष्ठान जैसे अभिकरणों/संगठनों को वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रहा है। तेरह विद्यालय 'प्रशासन' से सहायक अनुदान प्राप्त कर रहे हैं।

5.20.5 केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन सेवाकालीन शिक्षा पाठ्यकम के माध्यम से शिक्षकों की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए सम्मिलित प्रयास कर रहा है। वर्ष के दौरान 'प्रशासन' ने 31 दिसम्बर, 1988 से 9 जनवरी 1989 तक 10 दिन की अवधि के लिए बाईलेक्प्पे में 'प्राथमिक शिक्षकों के लिए सेवाकालीन पाठ्यक्रम' का आयोजन किया है। केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन ने शिक्षकों को सेवाकालीन शिक्षण पाठ्यक्रम में दीक्षित करने के लिए अपना संकाय विकसित किया है।

5.20.6 प्रशासनाधीन सातों उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 'क्लास' परियोजना के अंतर्गत आते हैं और उनको कम्प्यूटर आरम्भ करवाए गए है। पाठ्येतर कार्यकलापों को प्रोत्साहित करने और छात्रों में सहयोग, सहायता समन्वय और द्वेष रहित स्पर्द्धा की भावना बढ़ाने और विकसित करने के लिए 'प्रशासन' ने स्थापना देवस को प्रतिवर्ष मिलकर मनाने का फैसला किया है। सी. एस. टी. मसूरी में 5-7 सितम्बर, 1988 तक पहली बार स्थापना दिवस मनाया गया। इस आयोजन में 'प्रशासन' के अधीन कार्यरत शिक्षकों को अपने कार्यनिष्पादन को आंकने का मौका मिला। इस आयोजन से छात्रों को अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन का सुअवसर भी प्राप्त हुआ।

5.20.7 वर्ष के दौरान सी. एस. टी. मुंडगड़ और कलिम्पोंग स्थित विद्यालयों को स्तरोन्नत कर उच्चतर माध्यमिक स्तर का बना दिया गया। राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और तिब्बती बालकों की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए सी. एस. टी. और मुंडगड़ में + 2 स्तर पर टंकण और आशुलेखन के दो व्यावसायिक पाठ्यक्रम आरम्भ किए गए हैं।

5.20.8 वर्ष के दौरान 'प्रशासन' के परीक्षा परिणाम इस प्रकार रहे :

– अखिल भारतीय माध्यमिक विद्यालय परीक्षा, 1988 74.7 प्रतिशत।

– अखिल भारतीय उच्चतम विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षा, 1988 : 84.5 प्रतिशत।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

5.21.1 केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत एक स्वायत्त शासी संगठन है। 'बोर्ड के प्रमुख कार्य हैं – संस्थाओं को संबद्ध करना; माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तरों पर परीक्षाएं अथवा अन्य ऐसी परीक्षाएं आयोजित करना जिनका आयोजन इसे सौंपा जाता हैं और पाठ्यचर्या तथा पाठ्य सामग्री तैयार करना और उसे अद्यतन बनाना।

5.21.2 के. मा. शि. बो. का मुख्यालय दिल्ली में हैं। के. मा. शि. बोर्ड का एक ग्यारह मंजिला भवन प्रीत बिहार में निर्माणाधीन है और मार्च, 1989 तक बनकर तैयार हो जाएगा। दक्षिणी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों से संबद्ध विद्यालयों के कार्यकलापों को सुकर बनाने और समन्वित करने के लिए मद्रास में 1981 में और गुवाहाटी में 1986 में 'बोर्ड' के क्षेत्रीय कार्यालय खोले गए थे। दीर्घावधिक कल्याणकारी उपाय के रूप में 'बोर्ड' ने क्षेत्रीय नए भवन से थोड़ी दूरी पर अपने लगभग 25% कर्मचारियों के लिए 109 बने बनाए फ्लैट खरीदे।

5.21.3 के. मा. शि. बो. से संबद्ध विद्यालयों की संख्या 30.11.1988 को 2,652 थी जिसमें दिल्ली, चण्डीगढ़ तथा अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह संघ क्षेत्रों के तथा अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम राज्यों के सभी राजकीय और राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालय, सभी केन्द्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सेना विद्यालय, सैनिक स्कूल, तिब्बती विद्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा संचालित विद्यालय, पब्लिक

स्कूल और देश भर के अन्य स्वतंत्र विद्यालय तथा विदेश स्थित 44 विद्यालय शामिल हैं। केवल काफी अच्छे स्तर के विद्यालयों का के. मा. शि. बो. से संबद्धन सुनिश्चित करने के लिए भूमि, भवन, योग्य स्टाफ, वेतन आदि से संबद्ध अनिवार्य नियमों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। इन अनिवार्य अपेक्षाओं पर अमल करने के कारण विद्यालयों के स्तर में सुधार हुआ है। संबद्ध विद्यालयों के आर्वाधक निरीक्षण के कार्य को तेज किया गया तथा कमियों को दूर करने के लिए निर्देश जारी किए गए। विद्यालयों को उनके मार्ग-दर्शन के लिए संबद्धन उपर्विाध भेजी हुई है।

5.21.4 वर्ष के दौरान 'बोर्ड' ने 13 परीक्षाओं का निर्विध्न और कारगर आयोजन किया है तथा उनके परिणाम अनुसूची में निर्धारित तारीखों से पहले घोषित किए हैं। 1988 की प्रमुख परीक्षाओं में शामिल हुए अभ्यार्थियों की कुल संख्या उनके उत्तीर्ण प्रतिशत के साथ नीचे दी गई है:-

	परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों की संख्या	उत्तीर्ण अध्यर्थियों का प्रतिशत
अखिल भारतीय उच्चतम विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा, मार्च, 1988	53456	83.2%
दिल्ली उच्चतम विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा, मार्च, 1988	50843	82.8%
अखिल भारतीय माध्यमिक परीक्षा, मार्च, 1988	100303	80.4%
दिल्ली माध्यमिक परीक्षा, मार्च, 1988	93262	66.7%
खुला विद्यालय परीक्षा		
नवम्बर, 1987	09075	
मई, 1988	13894	

5.21.5 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से प्रथम प्री-मेडिकल, प्री-डेंटल प्रवेश परीक्षा तथा दिल्ली प्रशासन के अनुरोध पर जे. बी. टी./एन. टी. टी. प्रवेश परीक्षा का विचाराधीन वर्ष में सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। दोनों परीक्षाओं के परिणाम समय पर घोषित किए गए।

5.21.6 के. मा. शि. बो. ने ब्रिटिश काउंशिल के सहयोग से अंग्रेजी भाषा शिक्षण परियोजना का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य "बोर्ड" से संबद्ध विद्यालयों में माध्यमिक स्तर पर अंग्रेजी पाठ्यक्रम 'ए' में भाषा पढ़ने-पढ़ाने में सुधार लाना है। यह विशद शैक्षिक परियोजना है जिसमें पाठ्यचर्या विकास, सामग्री निर्माण परीक्षा सुधार, अंग्रेजी भाषा शिक्षण आदि चार महत्वपूर्ण घटक शामिल हैं।

5.21.7 के. मा. शि. बो. ने 'नेशनल इंट्रिग्रेशन थ्रू स्कूल्स' (विद्यालयों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता) नामक एक प्रबंध (मोनोग्राफ) तैयार किया है। इस प्रबंध के माध्यम से ये दर्शाने का प्रयास किया गया है कि बालकों में राष्ट्रीय एकता के संबर्धन में विद्यालय किस प्रकार सहायक हो सकते हैं और किस प्रकार राष्ट्रीय एकता को सहज स्वभाव का एक अंग बनाया जा सकता है।

5.21.8 बोर्ड ने विद्यालयों को, विभिन्न क्षेत्रों में अभिनव परिवर्तनों की शुरूआत करके व्यवस्था में गुणवत्तात्मक परिवर्तन करने के लिए अपने संसाधन देने के वास्ते 'विद्यालय परिसरों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। इन परिसरों द्वारा निम्नलिखित प्रमुख कार्यकलाप शुरू किए गए:– शिक्षकों के व्यावसायिक विकास के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, आपसी लाभ के लिए भौतिक और शैक्षिक संसाधन जुटाना, विद्यार्थियों और स्टाफ के लिए खेल सम्मेलन आयोजित करना और राष्ट्रीय एकता बढ़ाने वाले कार्यकलापों को प्रोत्साहित करना।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसधान एवं प्रशिक्षण परिषद्

5.22.1 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना एक सितंबर, 1961 को हुई थी जो सोसाइटीज़ पंजीकरण अधिनियम XXI (1860) के अंतर्गत पंजीकृत स्वायत्त संगठन हैं। रा. शै. अ. प्र. परि. एक संसाधन संस्था है। स्कूल शिक्षा और शिक्षक शिक्षण की अपनी रीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करने तथा कार्यान्वयन के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय रा. शै. अनु. प्र. परि. के विशेषज्ञों को आंमत्रित करती है।

5.22.2 संवीक्षाधीन वर्ष के दौरान, देश में स्कूल शिक्षा और शिक्षक शिक्षण की कोटि में सुधार लाने के लिए रा. शै. अ. प्र. परि. ने व्यापक और संगठित प्रयास किए हैं और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के कार्यान्वयन में मुख्य भूमिका निभाई है। योजनावार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं।

प्रारम्भिक बाल्यकाल में देख-रेख और शिक्षा (ई. सी. ई.)

5.22.3 रा. शै. अ. प्र. परि. द्वारा प्रारम्भिक बाल्यकाल देखरेख और शिक्षा कार्यक्रमों को सुदृढ़ बनाने हेतु विभिन्न कार्यक्रम आरंभ किए गए। 3 से 8 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए शैक्षिक और मनोरंजन संबंधी सामग्री के विकास से संबंधित कार्यकलापों को चिल्ड्रन्स मीडिया लैबोरेटरी (बच्चों का जनमाध्यम अनुसंधानशाला) परियोजना के अंतर्गत जारी रखा गया। 'प्रारंभिक बाल्यकाल शिक्षा परियोजना के अंतर्गत स्कूल-पूर्व शिक्षकों और शिक्षक-शिक्षकों के प्रशिक्षण और प्रारम्भिक बाल्यकाल शिक्षा के लिए अध्ययन और खेल सामग्री के विकास हेतु प्रारंभिक, बाल्यकाल शिक्षा इकाइयों को सुदृढ़ करने हेतु 10 राज्यों को सहायता प्रदान की गई। प्रारम्भिक बाल्यकाल शिक्षा परियोजना के अंतर्गत प्रारंभिक बाल्यकाल शिक्षा और संघटित बाल विकास सेवाओं के बीच संपर्क स्थापित करने पर मुख्य बल दिया गया है। संघटित बाल विकास सेवाओं के कार्यकर्ताओं के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। बाल शिक्षा और संघटित बाल विकास सेवा के संदर्भ में विशेष रूप से बाल शिक्षा पर एक राज्य स्तर का सेमिनार कर्नाटक में आयोजित किया गया। राजस्थान द्वारा संघटित बाल विकास सेवा केंद्रों के लिए कुछ गैर मुद्रित सामग्री का विकास किया गया। उड़ीसा में लगभग 8000 आंगनवाड़ियों को रा. शै. अ. प्र. परि. द्वारा विकसित की गई चित्र पुस्तकें और अन्य नाट्य सामग्री भेजी गई। बाल शिक्षा परियोजना के अंतर्गत, संसाधन व्यक्तियों के लिए अवस्थापना पाठ्यक्रम और भाग लेने वाले राज्यों से बाल शिक्षा परियोजना के समन्वयकों की दो बैठकों का आयोजन किया गया तथा इसके अलावा शिक्षकों, शिक्षक-शिक्षकों तथा अभिभावकों के लिए शिक्षण सामग्री श्रृंखला की चार पुस्तकें प्रकाशित की गई। इनके अलावा बाल शिक्षा परियोजना में भाग लेने वाले 10 राज्यों में स्कूल-पूर्व अनुभवों के संबंध में नामांकन करने और उन्हें रोके रखने पर एक अध्ययन, अगस्त 1988 में आरंभ किया गया। बाल विकास के विकल्प तैयार करने के प्रयास के एक भाग के रूप में, उड़ीसा में जनजातीय तथा शहरी गंदी बस्तियों के क्षेत्रों में एक बाल विकास के गृह-आधारित कार्यक्रम का प्रयोग किया गया था। कक्षा IV और V के बच्चों के लिए स्वास्थ्य और पोषण संबंधी शिक्षा से संबंधित नियमित कार्यकलापों सहित स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में दो उत्सव आयोजित किए गए। दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में कार्यान्वित की जा रही बाल शिक्षा परियोजना के अंतर्गत कक्षा III के शिक्षकों के लिए खेल-खेल में पढ़ाई पद्धति और कार्रवाई पर एक अवस्थापना कार्यक्रम आयोजित किया गया था। अक्तूबर, 1988 में आकाशवाणी, कोटा के सहयोग से रा. शै. अ. प्र. परि. द्वारा रेडियो की सम्भाव्यता पर एक अध्ययन आरंभ किया गया था जिसका उद्देश्य आंगनवाड़ी तथा प्राथमिक स्कूलों में कक्षा I और II के बच्चों के अध्ययन अनुभव को बढ़ाने के माध्यम के रूप में रेडियो का प्रयोग करना था। रा. शै. अ. प्र. परि. द्वारा अपने क्षेत्र अधिकारियों के माध्यम से 31 राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में खिलौना बनाने की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। राज्य स्तर पर खिलौना प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं ने 19 से 23 दिसम्बर, 1988 तक रा. शै. अ. प्र. परि. द्वारा आयोजित खिलौना निर्माण कर राष्ट्रीय कार्यशाला एवं प्रतियोगिता में भाग लिया। इसके अलावा स्कूल पूर्व के नेत्रहीन बच्चों के लिए शिक्षा से संबंधित खिलौनों का पता लगाने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया।

शिक्षा का सर्वसुलभीकरण

5.22.4 एक दस्तावेज जिसका शीर्षक आपरेशन ब्लैक बोर्ड: प्राथमिक स्तर पर अनिवार्य सुविधाएं मानदण्ड और विशिष्टताएं को अंतिम रूप दिया गया तथा राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में व्यापक प्रसार के लिए उन्हें प्रकाशित किया गया।

5.22.5 प्राथमिक शिक्षा पाठ्यचर्या नवीनीकरण परियोजना के अंतर्गत आरंभ किए गए कार्य 'नामांकन, बनाए रखने, स्थिरता और छात्रों की उपलब्धियों' के भाग के रूप में राज्यों से एकत्रित किए गए आंकड़ों का विश्लेषण किया गया और 'प्राथमिक स्तर पर छात्रों की उपलब्धि' नामक एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई। पोषण, स्वास्थ्य शिक्षा और पर्यावरणात्मक स्वच्छता परियोजना के अंतर्गत दो अध्ययनों अर्थात् "छात्र उपलब्धि का अध्ययन" और "सामुदायिक सम्पर्क कार्यक्रम का प्रभाव" से संबंधित आंकड़ों को एकत्रित करने और संकलित करने का कार्य पूरा किया गया। मानव संसाधन विकास के लिए गहन शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत, रा. शै. अ. प्र. परि. द्वारा परियोजना के परिप्रेक्ष्य और नीतियों के बारे में राज्य स्तर पर मुख्य कार्मिकों के लिए अवस्थापना पाठ्यक्रम आयोजित

किया गया। संवीक्षाधीन वर्ष के दौरान परियोजना को छः राज्यों और एक संघ शासित क्षेत्र-महाराष्ट्र, मिजोरम, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और दादरा एवं नागर हवेली में कार्यान्वित किया गया। परियोजना का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा के सर्वसुलभी-करण के लिए समुदाय में स्कूल पूर्व, प्राथमिक, अनौपचारिक तथा प्रौढ़ शिक्षा कार्यकलापों के समाकलन को बढ़ावा देना है। परियोजना कार्यान्वयन के मुख्य घटकों में, क्षेत्र संबंधी गहन दृष्टिकोण, कार्यकलापों और संसाधन निवेशों का सामन्जस्य और विकेंद्रित आयोजना और प्रबंध में सामुदायिक सहभागिता, इसके कार्यान्वयन के सभी पहलुओं में लचीलापन तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों और जनसंख्या को प्राथमिकता देना शामिल है।

5.22.6 प्राथमिक शिक्षा की व्यापक पहुंच परि-योजना के अंतर्गत स्कूल के बाहर के बच्चों के लिए अध्ययन सामग्री के विकास (अध्ययन एपिसोडों) और अध्ययन केन्द्रों की स्थापना और प्रबंध से संबंधित कार्यकलाप जारी रखे गए। वर्ष 1988-89 में परियोजना को 17 राज्यों में कार्यान्वित किया गया। पर्यावरणात्मक अध्ययनों के चार्टों के एक सेट सहित छः माड्यूलों को मुद्रित किया गया और बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, और उत्तर प्रदेश के हिन्दी भाषी राज्यों में परियोजना के अंतर्गत सभी अध्ययन केंद्रों को भेज दिए गए। परियोजना के अंतर्गत विकसित की गई अध्ययन सामग्री को सात मुख्य स्वैच्छिक संगठनों के पास इन संगठनों द्वारा चलाए जा रहे अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों में प्रयोग के लिए भेजा गया। अध्ययन सामग्री के विकास, अध्ययन केन्द्रों के सुविधा प्रदानकर्ताओं के प्रशिक्षण, प्रश्न बैंक के विकास के लिए परियोजना में भाग लेने वाले राज्यों को परिषद द्वारा तकनीकी सहायता प्रदान की गई।

5.22.7 रा. शै. अ. प्र. परि. द्वारा केंद्र प्रायोजित अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम को सहायता देने के विभिन्न कार्यकलाप शुरू किए गए। अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के अनुकूल शैक्षिक सामग्री और उपयुक्त शिक्षण अध्ययन विकास नीतियों के विकास के कार्यों पर मुख्य बल दिया गया है। अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों में बच्चों को स्कूल में प्रवेश के समय ही उनकी उपलब्धियों के मूल्यांकन के लिए साधन और तकनीक विकसित करना भी शामिल हैं। केन्द्रों की सफलता की कहानी को प्रकाशित करने के लिए प्राथमिक स्तर पर चुनिन्दा अनौपचारिक केंद्रों का अध्ययन तथा अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के लिए विकसित पाठ्यचर्या और शैक्षिक सामग्री के विश्लेषण सहित अनुसंधान कार्य आरंभ किए। विकसित की गई शैक्षिक सामग्री में अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों की मिडल स्तर पर प्रयोग करने हेतु गणित पुस्तक-III, शै. और शिक्षा केंद्रों में प्राथमिक स्तर पर प्रयोग के लिए कक्षा III के लिए आठ कॉर्मिक पुस्तकें और शिक्षक गाईड तथा मिडल स्तर के गै. औ. शिक्षा केंद्रों में कार्य कर रहे शिक्षकों के प्रयोग के लिए गणित की कार्य पुस्तक शामिल है। परिषद ने रा. शै. अ. प्र. परि. द्वारा शामिल किए गए गै. औ. शिक्षा केंद्रों के गै. औ. शिक्षा के शिक्षकों और गै. औ. शिक्षा अधीक्षकों के लिए एक प्रशिक्षण नियम पुस्तक भी तैयार की है। शुरू किए गए अन्य कार्यक्रमों में अनौपचारिक शिक्षा अधीक्षकों के लिए प्रशिक्षण सामग्री का विकास करना, गै. औ. शिक्षा से संबंधित शिक्षण अध्ययन और प्रशिक्षण विधियों पर एक फिल्म बनाना, राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में स्वैच्छिक संगठनों और अनौपचारिक शिक्षा इकाइयों की ओर से अनौपचारिक शिक्षा के कार्यकर्ताओं के लिए अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों और अवस्थापना कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में शामिल संसाधन व्यक्तियों के लिए अवस्थापना कार्यक्रम शामिल हैं।

स्कूल स्तर पर विषयवस्तु और शिक्षा प्रक्रिया की पुनः अवस्थापना

5.22.8 रा. शै. अ. प्र. परि. द्वारा स्कूल स्तर पर विषय वस्तु शिक्षा प्रक्रिया की पुनः अवस्थापना के लिए कई समन्वित उपाय किए गए जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में परिकल्पना की गई है। इन उपायों में मुख्य बल स्कूल शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए अध्ययन के निम्नतम स्तरों के नियमों को तैयार करना, संशोधित पाठ्यचर्चा के आधार पर संस्थागत पैकेजों का विकास करना, बाल केंद्रित अध्ययन नीति कार्यकलाप आधारित शिक्षण पद्धति का विकास, अपनी व्यावसायिक दक्षता में सुधार के लिए शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कार्मिकों को प्रशिक्षण देना और परीक्षा संशोधन तथा अध्यापन-अध्ययन प्रक्रियाओं को सुधारने के लिए निरंतर और व्यापक मूल्यांकन शामिल हैं। स्कूल शिक्षक जन-अनुस्थापन कार्यक्रम के अंतर्गत 1986 से राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद तथा राज्य सरकारों के माध्यम से लगभग पांच

13-9-90

लाख स्कूल शिक्षकों के लिए अनुस्थापन कार्यक्रम किए जा रहे हैं ताकि स्कूल स्तर पर विषय वस्तु के पुनर्स्थापन की प्रक्रिया और शिक्षा की प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए सुसज्जित करने के वास्ते शिक्षकों के प्रोत्साहन और व्यावसायिक क्षमता में वृद्धि की जा सके। 1988 के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 4.6 लाख शिक्षकों को अनुस्थापित किया गया था। वर्ष 1986 और 1987 के दौरान प्राप्त अनुभवों को देखते हुए अनुस्थापन कार्यक्रम की विषय वस्तु की समीक्षा की गई थी। प्राप्त पुनर्निवेशन के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति में परिकल्पित प्रमुख बलों के प्रति जागरूकता पैदा करने के घटकों के अतिरिक्त विभिन्न पाठ्यचर्या के शिक्षण से संबंधित व्यावसायिक क्षमताओं में वृद्धि करने के लिए निर्देशित घटकों को शामिल करने के वास्ते 1988 के दौरान आयोजित अनुस्थापन कार्यक्रमों की विषय वस्तु को फिर से तैयार किया गया था। इस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्कूल शिक्षकों और माध्यमिक स्कूल शिक्षकों को सम्मिलित करके एक संशोधित प्रशिक्षण पैकेज तैयार किया गया था। अनुस्थापन/प्रशिक्षण शिविरों के संकाय/संसाधन व्यक्तियों के लिए दिशा-निर्देश भी तैयार किए गए थे। इस कार्यक्रम के लिए नई पाठ्यचर्या से सम्बद्ध कुछ नए कार्यक्रमों को शामिल करके दूरदर्शन सहयोग को भी सुदृढ़ किया गया था। 1988 के दौरान आयोजित अनुस्थापन कार्यक्रमों का मूल्यांकन तीन विश्वविद्यालयों, अर्थात् कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय और पाण्डिचेरी विश्वविद्यालय, द्वारा किया गया था और मूल्यांकन रिपोर्टों में दिए गए सुझावों के आधार पर 1989 के दौरान आयोजित किए जाने के लिए प्रस्तावित अनुस्थापन कार्यक्रमों की विषय वस्तु में और संशोधन किया गया था ताकि इसे शिक्षकों की आवश्यकताओं के लिए संगत बनाया जा सके।

5.22.9 स्कूल स्तर पर विषय वस्तु और शिक्षा की प्रक्रियाओं को पुनर्स्थापित करने के प्रयास के भाग के रूप में स्कूलों में मूल्यांकन पद्धतियों में सुधार करने के लिए उपाय किए गए थे। राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में राज्य शै. अ. प्र. परि./शिक्षा विभागों और माध्यमिक शिक्षा बोर्डों में परिचालित करने के लिए तैयार की गई एक वृहद् सतत मूल्यांकन योजना पर 22 जून से 5 जुलाई, 1988 तक आयोजित संसाधन व्यक्तियों के लिए दो सप्ताह के अखिल भारतीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में चर्चा की गई थी। शैक्षिक और गैर-शैक्षिक क्षेत्रों में छात्र की उपलब्धि के रिकार्ड रखने की कार्य विधियों सहित एक नमूना संचयी कार्ड भी तैयार किया गया है। राष्ट्रीय शै. अ. प्र. परि. ने भी माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के विभिन्न बोर्डों द्वारा आयोजित परीक्षाओं में ग्रेडिंग तथा स्केलिंग शुरू करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए और 7 से 9 सितम्बर, 1988 तथा 24 और 25 नवम्बर, 1988 को माध्यमिक शिक्षा बोर्डों के अध्यक्षों/सचिवों की दो क्षेत्रीय बैठकें आयोजित की। इन बैठकों के दौरान माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्डों द्वारा आयोजित परीक्षाओं में स्केलिंग तथा ग्रेडिंग शुरू करने से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई थी। राष्ट्रीय शै. अ. प्र. परि. ने मौखिक परीक्षाओं, खुली पुस्तक परीक्षाओं तथा परियोजना कार्य जैसी वैकल्पिक मूल्यांकन कार्य विधियों द्वारा महत्वपूर्ण व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए एक आठ दिवसीय कार्यशाला भी आयोजित की। इन के अतिरिक्त, परिषद ने विभिन्न विषय क्षेत्रों में शैक्षिक मूल्यांकन, मानदण्ड संदर्भित परीक्षाएं तैयार करने और परीक्षा विषयक लेखकों के प्रशिक्षण से संबंधित संकल्पनात्मक सामग्री के विकास के अपने कार्य जारी रखे।

5.22.10 स्कूल स्तर पर विषय वस्तु तथा शिक्षा की प्रक्रियाओं को पुनर्स्थापित करने से संबंधित कार्यों के कार्यान्वियन को सुकर बनाने के उद्देश्य से रा. शै. अ. प्र. परि. ने एक योजना तैयार की जिसके अंतर्गत विभिन्न पाठ्यचर्या क्षेत्रों में पाठ्य-पुस्तकों सहित पाठ्यचर्या के नवीकरण तथा शैक्षिक सामग्री के विकास से संबंधित कार्यकलाप शुरू करने के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी।

विज्ञान शिक्षा से संबंधित कार्यकलाप

5.22.11 स्कूलों में विज्ञान शिक्षा के सुधार की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के कार्यान्वयन से संबंधित कार्य के भाग के रूप में रा. शै. अ. प्र. परि. ने कर्नाटक और मध्य प्रदेश में वरिष्ठ/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में विज्ञान शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए सात प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए। इन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के दौरान, भाग लेने वालों ने कुछ प्रशिक्षण सामग्री तैयार की जिसका उपयोग इस योजना के अंतर्गत आयोजित किए जाने वाले उत्तरवर्ती प्रशिक्षण कार्यक्रमों में किया जा सकता है। योजना के कार्यान्वयन से संबंधित राष्ट्रीय शै. अ. प्र. परि. द्वारा शुरू किए गए अन्य कार्यकलापों में ये शामिल हैं।

योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए एक नियम पुस्तक तैयार करना, तथा उत्तर प्रदेश में उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उपयोग की जाने वाली शैक्षिक सामग्री तैयार करने के लिए एक-एक सप्ताह की कार्यशाला का आयोजन और बिहार में माध्यमिक शिक्षकों के लिए एक तीन दिवसीय अनुस्थापना कार्यक्रम शामिल हैं। परिषद ने 31 अक्तूबर और 1 नवम्बर, 1988 को राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों स्तर पर योजना के कार्यान्वयन से संबद्ध केन्द्रीय एजेंसियों के प्रतिनिधियों की एक बैठक भी आयोजित की और योजना में परिकल्पित विभिन्न कार्यों को शुरू करने के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को तकनीकी सहायता प्राप्त की।

5.22.12 परिषद ने प्राथमिक और अपर प्राथमिक स्कूलों के लिए विज्ञान किटें तैयार करने से संबंधित अपने कार्यकलाप जारी रखे। प्राथमिक विज्ञान किट के लिए किट नियम पुस्तकें और अपर प्राथमिक स्कूलों के लिए समेकित विज्ञान किट की नियम पुस्तकें मुद्रित की गई हैं। शुरू किए गए अन्य कार्यकलापों में शामिल हैं - मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में स्कूलों में शिक्षक शिक्षण विज्ञान का सर्वेक्षण; और मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के प्राथमिक एवं अपर प्राथमिक स्कूलों में "संशोधित विज्ञान शिक्षा" नामक भारत ज. ज. ग. परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों तथा प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में आयोजित विज्ञान किटों तथा उपस्कर के स्तर का सर्वेक्षण, विज्ञान किटों की मदों के निर्माण निर्धारण तथा आदान पर एक विस्तृत ब्यौरा तैयार करना और एक शिक्षक हस्तपुस्तिका तैयार करना।

5.22.13 स्कूलों में विज्ञान के शिक्षण को सुदृढ़ करने के प्रयासों के भाग के रूप में, राष्ट्रीय शै. अ. प्र. परि. ने शिक्षक गाइडें, प्रयोगशाला - पुस्तिकाएं, अनुपूरक पठन सामग्री और लोकप्रिय विज्ञान सामग्री तैयार की। राष्ट्रीय शै. अ. प्र. परि. द्वारा जम्मू और काश्मीर सरकार के सहयोग से 5 से 11 नवम्बर, 1988 को जम्मू में बच्चों के लिए सत्रहवीं राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित की गई थी।

संगणक साक्षरता उन्मुखी कार्यकलाप

5.22.14 स्कूलों में संगणक साक्षरता तथा अध्ययन परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय शै. अ. प्र. परि. और अन्य संसाधन केन्द्रों द्वारा स्कूल शिक्षकों के लिए अनेक उन्नत स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। संसाधन केन्द्रों द्वारा परियोजना में भाग लेने वाले नए स्कूलों से शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। 1988 के दौरान, परियोजना के अंतर्गत लगभग 1325 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया था। परियोजना के अंतर्गत स्थापित 53 संसाधन केन्द्रों ने परियोजना में भाग लेने वाले स्कूलों को तकनीकी सहयोग प्रदान किया। नए स्कूलों के लिए साफ्टवेयर पैकेज प्राप्त करने और परियोजना में भाग लेने वाले नए स्कूलों में उपयोग के लिए स्वदेशी साफ्टवेयर पैकेजों का चयन करने के लिए आवश्यक उपाय किए गए थे। कुल मिलाकर, नए स्कूलों को आपूर्ति के लिए लगभग 22 स्वदेशी साफ्टवेयर पैकेजों को अनुमोदित किया गया था।

व्यवसायमुखी कार्यकलाप

5.22.15 राष्ट्रीय शै. अ. प्र. परि. ने उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के व्यावसायीकरण से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों की आयोजना और कार्यान्वयन में राज्यों को आवश्यक तकनीकी सहयोग प्रदान करने के लिए अनेक कार्यकलाप शुरू किए। उन राज्यों के प्रमुख व्यक्तियों के लिए जिन्होंने उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के + 2 स्तर पर व्यावसायीकरण का कार्यक्रम पहले शुरू कर दिया है और उनके लिए भी जो व्यावसायीकरण का कार्यक्रम शुरू करने वाले हैं, व्यावसायीकरण पर नौ अनुस्थापन कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इन अनुस्थापन कार्यक्रमों के माध्यम से, दिल्ली संघ शासित क्षेत्र तथा हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश राज्यों और पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के लगभग 300 प्रमुख व्यक्तियों को उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के व्यावसायीकरण के कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं की ओर अभिमुख किया गया था। परिषद ने शिक्षा के व्यवसायीकरण के लिए कार्यक्रमों के विभिन्न पहलुओं के कार्यान्वयन के वास्ते विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों तथा वृहद् दिशा-निर्देशों के विकास के लिए न्यूनतम व्यावसायिक क्षमता आधारित पाठ्यचर्या के विकास के अपने कार्यकलाप जारी रखे। परिषद ने उद्यमशीलता में एक आदर्श पाठ्यचर्या मुद्रण प्रौद्योगिकी तथा पुस्तक जिल्दबंदी में न्यूनतम क्षमता-आधारित पाठ्यचर्या, विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में शैक्षिक सामग्री और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को लोकप्रिय बनाने के लिए फोल्डर तैयार किए।

शिक्षक शिक्षा उन्मुखी कार्यकलाप

5.22.16 शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में रा. शै. अ. प्र. प. ने संवीक्षाधीन वर्ष के दौरान तीन अनुसंधान परियोजनाएं पूरी की। इनमें शामिल हैं – भारत में शिक्षकों के जीवन स्तर का अध्ययन, विभिन्न प्रशिक्षण नीतियों की सापेक्ष प्रभावकारिता का अध्ययन और अनु. जाति/अनु. जन जाति तथा गैर अनु. जाति/अनु. जन. जाति छात्र शिक्षकों की स्व–संकल्पना, अभिवृत्ति तथा समायोजन का उनकी उपलब्धि के साथ संबंधों का अध्ययन/ रा. शै. अ. प्र. परि. ने राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करना जारी रखा और रा. शि. शि. प्र. के विभिन्न कार्यकलापों को समेकित किया। शिक्षक शिक्षा पाठ्यचर्या – एक कार्य ढांचा दस्तावेज का संशोधन एक महत्वपूर्ण कार्यकलाप था, जो शुरू किया गया था। शिक्षक शिक्षा के लिए संशोधित पाठ्यचर्या कार्य ढांचे का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति गठित की गई थी। इस समिति द्वारा तैयार किए गए प्रारूप कार्य ढांचे पर 14 और 15 नवम्बर, 1988 को आयोजित एक राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा पाठ्यचर्या सम्मेलन में चर्चा की गई थी। इस सम्मेलन में दिए गए सुझावों के आधार पर कार्य ढांचे में संशोधन किया गया है और उसे अन्तिम रूप दिया गया है। + 2 स्तर पर चार वर्षीय शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम संरचना और शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए एक संरचना तैयार करने के लिए कारवाई शुरू की गई थी।

5.22.17 परिषद ने जिला शिक्षा संस्थाओं की स्थापना के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को तकनीकी सहायता प्रदान की। इसने जिला शिक्षा संस्थानों से संबंधित परियोजना दस्तावेज को संशोधित करने का कार्य भी शुरू किया।

5.22.18 राष्ट्रीय शै अ प्र परि द्वारा संचालित चार क्षेत्रीय शिक्षा कालेजों ने बी. ए., एड., बी. ए. बी. एड डिग्रियों तथा बी. एस. सी. एड अथवा बी. एस. सी. (आनर्स/पास) बी. एड डिग्रियों, एक वर्षीय बी. एड. पाठ्यक्रम तथा एक वर्षीय एम. एड. पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए चार वर्षीय समेकित शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम जारी रखा। भुवनेश्वर और मैसूर में क्षेत्रीय शिक्षा कालेजों ने भी दो वर्षीय एम. एस. सी. एड. पाठ्यक्रम प्रदान किए। क्षेत्रीय शिक्षा कालेजों ने स्कूल शिक्षा और शिक्षक शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर अनेक विस्तार कार्यक्रम/कार्यशाला/बैठकें/सेमिनार आयोजित किए। इनके अतिरिक्त, प्रत्येक क्षेत्रीय शिक्षा कालेज ने स्कूल शिक्षा तथा शिक्षक शिक्षा से संबंधित अनुसंधान अध्ययन भी शुरू किए। क्षेत्रीय शिक्षा कालेजों द्वारा अनेक अध्येताओं को पी. एच. डी. डिग्री हेतु उनके अनुसंधान कार्य के लिए मार्ग दर्शन प्रदान किया गया था।

अनु. जातियों/अनु. जन जातियों से संबंधित कार्यकलाप

5.22.19 रा. शै. अ. प्र. परि. ने अनु. जातियों और अनु. जन जातियों की शिक्षा को प्रोन्नत करने की ओर निर्देशित अपने अनुसंधान और विकासात्मक कार्यकलाप जारी रखे। संवीक्षाधीन वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में कक्षा – V के अनु. जातियों और अनु. जन. जातियों के छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियों का एक तुलनात्मक अध्ययन पूरा किया गया था। अनु. जातियों और अनु. जन जातियों के छात्रों के लिए पूर्व-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के मूल्यांकन परक अध्ययन के अंतर्गत कार्यकलाप जारी रहे। वर्ष के दौरान 11 राज्यों (अनु. जन. जातियां, कलस्टर-I) के लिए रिपोर्ट पूरी की गई थी। कलस्टर-I (अनु. जातियों) से संबंधित प्रारूप रिपोर्ट भी तैयार की गई है। कलस्टर-II (अनु. जाति/अनु. जन जाति राज्यों) के लिए आंकड़ा-संग्रह किया जा रहा है।

5.22.20 परिषद ने जनजातीय बोलियों में प्राइमर/पाठ्यपुस्तकें तैयार करने से संबंधित अपने कार्य जारी रखे। कक्षा - I और II के लिए जनजातीय बोलियों और बिहार की पांच जनजातियों, अर्थात् सन्थाल, मुन्द्री, हो, खरिया और कुर्क के लिए देवनागरी लिपि में पाठ्यपुस्तकें तैयार करने के वास्ते नवम्बर 1988 में एक कार्यशाला आयोजित की गई थी। ये पाठ्य पुस्तकें केन्दीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर के सहयोग से तैयार की जा रही हैं। शुरू किए गए अन्य कार्यकलापों में आन्ध्र प्रदेश में गोन्ड जन जातीय बच्चों के लिए कक्षा-II के एक प्राईमर का प्रारूप और तमिलनाडु में इरूला जनजातीय बच्चों के लिए कक्षा-I का एक प्राईमर तैयार करना शामिल है। गोन्ड जनजातीय बच्चों के लिए प्राईमर गोन्डी जनजातीय बोली में तैयार किया जाता है जिसमें तेलुगु लिपि का प्रयोग किया जाता है जबकि इरूला जनजातीय बच्चों के लिए प्राईमर तमिल लिपि का इस्तेमाल करके इरूला जनजातीय बोली में तैयार किया जाता है।

शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों की शिक्षा से संबंधित कार्यकलाप

5.22.21 परिषद ने शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक समुदायों, विशेष रूप से मुसलमानों द्वारा प्रबन्धित स्कूलों में शैक्षिक स्तरों को सुधारने के उद्देश्य से शिक्षकों और प्राचार्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के वास्ते तकनीकी और वित्तीय सहयोग प्रदान करना जारी रखा। संवीक्षाधीन वर्ष के दौरान, परिषद ने शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों द्वारा प्रबन्धित स्कूलों के प्रबंधकों और प्राचार्यों के लिए मार्गदर्शीय सेवाओं से संबंधित चार 3-दिवसीय सेमिनार-एवं-कार्यशालाएं आयोजित कीं। इनके अतिरिक्त, 26 से 28 दिसम्बर, 1988 तक शैक्षिक रूप से पिछड़े समुदायों द्वारा प्रबन्धित स्कूलों में आजीविका शिक्षकों के लिए एक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित किया गया था। यह परिषद शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों, द्वारा प्रबन्धित स्कूलों के शिक्षकों के लिए आजीविका, शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी आयोजित करती रही है।

महिला-समानता के लिए शिक्षा से संबंधित कार्य

5.22.22 रा. शै. अ. प्र. परि. ने शिक्षा के माध्यम से महिलाओं को अधिकार देने के लिए अनेक कार्यक्रम और परियोजनाएं शुरू की हैं। महिला समानता के लिए शिक्षा पर आदर्श संसाधन सामग्री तैयार करने के लिए केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान के सहयोग से एक कार्यशाला आयोजित की गई थी। महिलाओं पुरुषों की समानता को प्रौन्नत करने के लिए एक स्कूल आधारित कार्यक्रम तैयार करने के लिए एक अनुसंधान परियोजना के अन्तर्गत एक अन्य कार्यशाला आयोजित की गई थी। शुरू किए गए अन्य कार्यकलापों में शामिल है महिला शिक्षा तथा विकास को संचालित करने के लिए संकेतकों तथा नीतियों की पहचान, महिला समानता की शिक्षा से संबंधित एक डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए पाठ्यक्रम रूपरेखा तैयार करना, एक छः सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए एक पाठ्यक्रम रूपरेखा तैयार करना, और अधिकार की प्रक्रिया का पता लगाने के लिए हरियाणा में महिला मण्डलों का एक अध्ययन। इनके अतिरिक्त, परिषद ने शैक्षिक कार्यक्रमों तथा पाठ्य पुस्तकों से महिला पुरुष पक्षपात का पता लगाने तथा समाप्त करने और महिला समानता की शिक्षा की दृष्टि से शैक्षिक कार्यक्रमों के निरीक्षण और मूल्यांकन की प्रक्रिया के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रमुख व्यक्तियों को अभिमुख करने के लिए चार क्षेत्रीय कार्यशालाएं और एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। परिषद ने महिला अध्ययन के लिए केन्द्रों/एककों की स्थापना करने के वास्ते राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को तकनीकी सहायता प्रदान की और आन्ध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश राज्यों से कार्मिकों के लिए जागरूकता वृद्धि कार्यक्रम आयोजित किए। इन कार्यक्रमों में भाग लेने वालों में कालेज प्रिंसिपल, स्कूल प्रिंसिपल, शैक्षिक प्रशासक तथा महिला अध्ययन के क्षेत्र में विशेषज्ञ शामिल थे।

विकलांगों की शिक्षा से संबंधित कार्यकलाप

5.22.23 रा. शै. अ. प्र. परि. ने विकलांगों के लिए समेकित शिक्षा कार्यक्रम के कार्यान्वयन से संबंधित अनेक कार्य शुरू किए। बोधात्मक तथा उत्पादक, दोनों क्षेत्रों में अध्ययन विकलांगता का पता लगाने के लिए उपकरण तैयार किए गए हैं। उन्हें अन्तिम रूप देने के लिए इन उपकरणों की जांच की जा रही है। परिषद ने विकलांग बच्चों का पता लगाने के लिए पद्धति विज्ञान से संबंधित शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए 7 कार्यक्रम आयोजित किए। इनमें मध्य प्रदेश में मुस्तोरी खण्ड में शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए तीन कार्यक्रम, मिजोरम में शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए एक कार्यक्रम और राजस्थान के चब्बरा खण्ड में शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए तीन कार्यक्रम शामिल थे।

5.22.24 परिषद ने विकलांग बच्चों की शिक्षा के वीडियो कार्यक्रमों के वास्ते विषयों का पता लगाने और संक्षिप्त विवरण तैयार करने के लिए एक कार्यशाला आयोजित की। अध्ययन विकलांगता, श्रवण-दौर्बल्य, मानसिक दुर्बलता तथा दृष्टि-दौर्बल्य से संबंधित विषयों पर वीडियो कार्यक्रमों के संक्षिप्त विवरण कार्यशाला में तैयार किए गए थे। निम्न यंत्र नियंत्रण सहित छात्रों के लिए देवनागरी लिपि के शिक्षण पर एक अन्य कार्यशाला आयोजित की गई थी। परिषद ने शैक्षिक खिलौनों तथा खेलों पर एक प्रदर्शनी एवं कार्यशाला भी आयोजित की थी। भाग लेने वालों में बाल विकास, विशेषज्ञ, पाठ्यचर्या विशेषज्ञ, सामान्य शिक्षक शामिल थे और खिलौना निर्माताओं ने कार्यशाला में भाग लिया। इनके अतिरिक्त, विकलांग बच्चों के कार्यात्मक मूल्यांकन के लिए एक दो सप्ताह का अटैचमेंट कार्यक्रम आयोजित किया गया था। मिजोरम और तमिलनाडु से आठ सहभागियों को

प्रशिक्षित किया गया था। इनके अतिरिक्त, विकलांगों के लिए समेकित शिक्षा के कार्यक्रमों वाले स्कूलों के साथ जानकारी का आदान-प्रदान करने के उद्देश्य से ''संचार-विकलांगों के लिए समान शैक्षिक अवसर'' शीर्षक से एक तिमाही समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था।

शैक्षिक प्रौद्योगिकी उन्मुख कार्यकलाप

5.22.25 राज्य शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थानों के सहयोग से केन्द्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा अनेक कार्यकलाप शुरू किए गए थे, जो शिक्षा में कोटिपरक सुधार लाने के लिए और शिक्षा तक पहुंच को सरल बनाने के लिए रेडियो और दूरदर्शन के उपयोग सहित शैक्षिक प्रौद्योगिकी की उपयोगिता की ओर निर्देशित हो।

केन्द्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान ने ई. टी. वी. कार्यक्रमों के निर्माण में देश के अन्दर क्षमताएं पैदा करने की दृष्टि से पांच प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। संवीक्षाधीन वर्ष के दौरान आयोजित कार्यक्रमों में वीडियो सम्पादन, ई. टी. वी. निर्माण तथा तकनीकी संचालन, कैमरा और ध्वनि रिकार्डिंग्स, स्टूडियो निर्माण तथा बी. सी. एन.-51 अनुरक्षण पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शामिल थे। केन्द्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान ने यूनेस्को, पेरिस द्वारा प्रायोजित एक परियोजना के भाग के रूप में शिक्षा परियोजना के लिए इनसेट पर विस्तृत मामला अध्ययन को अन्तिम रूप दिया जो एशियाई देशों में बड़े पैमाने की संचार पद्धतियों का प्रयोग करके सुदूर शिक्षा में विकास का विश्लेषण करने के लिए शुरू की गई थी।

नवोदय विद्यालयों के लिए सहायता सेवाएं

5.22.26 शैक्षिक सत्र 1989-90 के लिए नवोदय विद्यालयों में दाखिलों के लिए रा. शै. अ. प्र. प. ने चयन परीक्षाएं आयोजित की हैं। वर्ष 1989-90 में नवोदय विद्यालयों की संख्या 256 थी। चयन परीक्षाएं, 18 भाषाओं में पूरे देश भर फैले 256 जिलों में 2980 सामुदायिक विकास खंडों में 3241 केन्द्रों में आयोजित की गई। परीक्षा पुस्तिकाएं 18 भाषाओं में केंद्रीकृत तरीके से छापी गई तथा रा. शै. अ. प्र. परिषद, के क्षेत्र सलाहकार कार्यालयों के माध्यम से विभिन्न केन्द्रों को बांटी गईं। चयन परीक्षा के लिए 4,64,382 छात्रों ने आवेदन किए जिसमें 3716052 छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया। नवोदय विद्यालयों में दाखिले के लिए कुल मिलाकर 14,769 छात्रों का चयन किया गया। इनमें से 11059 (75 प्रतिशत) छात्र ग्रामीण क्षेत्रों में थे जबकि 3710 (25 प्रतिशत) छात्र शहरी क्षेत्रों में से थे। चुने गए छात्रों में से 10,001 (68 प्रतिशत) लड़के तथा 4768 (32 प्रतिशत) लड़कियां थीं। नवोदय विद्यालयों में दाखिले के लिए चुने गए 14,769 छात्रों में से 1775 (19 प्रतिशत) अनुसूचित जाति से संबंधित थे जबकि 1638 (11 प्रतिशत) अनुसूचित जन जातियों से संबंधित थे। अनुसूचित जाति से संबंधित 655 छात्रों तथा अनुसूचित जनजाति में से संबंधित 551 छात्रों को खुली प्रतियोगिता में चुना गया। चयन परीक्षाओं के अलावा परिषद, छात्रों की समाजार्थिक स्तर तथा 1986 तक स्थापित किए गए नवोदय विद्यालयों में भौतिक सुविधाओं का अध्ययन भी करती है।

शिक्षा सर्वेक्षण

5.22.27 परिषद पांचवे अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण की प्रारंभिक रिपोर्ट प्रकाशित करती है। पांचवें अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण की संदर्भ तारीख 30 सितंबर, 1986 थी। सर्वेक्षण में, तीन प्रश्नावली अर्थात् ग्राम सूचनाफार्म, शहरी सूचना फार्म तथा सूचना फार्म मुख्य थी। पहली दो प्रश्नावलियों के माध्यम से स्कूल की उपलब्धता पर सभी ग्रामों तथा शहरी क्षेत्रों से आंकड़े एकत्रित करने के साथ साथ पूर्व प्राइमरी शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा की सुविधाओं के आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। स्कूल सूचना फार्म के माध्यम से सभी स्कूलों में छात्रों, शिक्षकों, भवनों, सुविधाओं, उपलब्ध उपस्कर आदि के बारे में आंकड़े एकत्रित किए गए थे। आंकड़े पहले ब्लाक/तहसील स्तर पर एकत्रित किए गए तथा उसके पश्चात् ब्लाक सारणी से जिला स्तर सारणी तैयार की गई थी। जिला स्तर सारणी से राज्य स्तर सारणी तैयार की गई और बाद में विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रशासनों से प्राप्त राज्य सारणी पर रा. शै. अ. प्र. परिषद में अनेक तरह से राष्ट्रीय स्तर की सारणी तैयार की गई।

5.22.28 इस सर्वेक्षण आकंड़ों की शैक्षिक आयोजना विशेषकर शैक्षिक विकास के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना को तैयार करने में प्रयोग किए जाने की आशा है। इन आंकड़ों की ब्लाक स्तर पर सूक्ष्म आयोजना तथा इसके साथ ही जिला स्तर पर शैक्षिक आयोजना के लिए उपयोग किए जाने की आशा है। इसके अलावा इन आंकड़ों से राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के कार्यान्वयन के संदर्भ में प्रारम्भ की गई विभिन्न

योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन में सहायता मिलने की संभावना है जैसे कि आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण।

राष्ट्रीय प्रतिभा खोज

5.22.29 रा. शै. अ. प्र. परिषद द्वारा राष्ट्रीय प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए द्वितीय स्तर की परीक्षा 8 मई, 1988 को आयोजित की गई। प्रथम स्तर की परीक्षा राज्यों/संघ शासित प्रशासनों द्वारा आयोजित की गई। द्वितीय स्तर की परीक्षा पूरे देश में फैले 30 केन्द्रों में आयोजित की गई थी और परीक्षा में 3065 छात्रों ने भाग लिया। इन 750 छात्रों में से 70 अ. जा./ अ. ज. जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए चुना गया।

शैक्षिक मनोविज्ञान, परामर्श तथा मार्गदर्शन

5.22.30 रा. शै. अ. प्र. परिषद के शैक्षिक तथा व्यावसायिक मार्ग दर्शन के क्षेत्र में विभिन्न क्रियाकलाप आयोजिए किए। शैक्षिक व्यावसायिक आयोजना, शैक्षिक और चुनिन्दा मनोविज्ञान तथा गृह-पृष्ठ भूमि की जन जाति हाई स्कूल छात्रों में तथा शिलांग (मेघालय) के आस पास एक अध्ययन को पूरा किया गया। अनुसंधान परियोजना "व्यावसायिक बर्ताव तथा + 2 स्तर पर शैक्षिक तथा व्यावसायिक पद्धति में छात्रों का समायोजन" का कार्य तथा "दिल्ली में व्यावसायिक सीनियर सैकेन्डरी स्कूलों में स्वत: रोजगार को बढ़ावा देने" के लिए अनुसंधान परियोजना के अन्तर्गत कार्य को आलोच्य वर्ष के दौरान जारी रखा गया। परिषद ने अपना शैक्षिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन में डिप्लोमा पाठ्यक्रम जारी रखा।

5.22.31 रा. शै. अ. प्र. परिषद ने बाल केन्द्रित शिक्षा पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की। इस संगोष्ठी में 160 विख्यात शिक्षाविदों, मनोवैज्ञानिकों शैक्षिक प्रशासकों आदि ने भाग लिया। शुरू किए गए अन्य क्रियाकलापों में क्लास रूप सैटिंग, विकास में बर्ताव की संशोधित तकनीकों में प्राइमरी शिक्षकों तथा शिक्षा शिक्षकों के लिए शिक्षण मैनुअल का विकास करना तथा प्राइमरी स्कूल शिक्षा में सृजनात्मक संभावयता में एक हैंड बुक विकसित करके प्राइमरी शिक्षा शिक्षकों का विकास करना भी शामिल है।

शैक्षिक अनुसंधान

5.22.32 रा. शै. अ. प्र. परि. की शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रगामी समिति ने स्कूल शिक्षा तथा शिक्षक शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान परियोजनाओं को प्रायोजित करना जारी रखा। वर्ष 1988-89 के दौरान, 6 विभागीय तथा 5 बाहरी अनुसंधान परियोजनाओं को निधियां प्रदान की गई। ई. आर. आई. सी. द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करके 10 पी. एच. डी. शोध प्रबन्धों को प्रकाशित किया गया। आलोच्य वर्ष के दौरान 8 बाहरी तथा 27 विभागीय परियोजनाओं को पूरा किया गया। आलोच्य वर्ष के दौरान 31 बाहरी तथा 39 विभागीय अनुसंधान परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है।

5.22.33 चौथे शैक्षिक अनुसंधान सर्वेक्षण की पाण्डुलिपि तैयार कर ली गई है और प्रकाशन के लिए भेज दी गई है।

5.22.34 शैक्षिक अनुसंधान की कोटि में सुधार के प्रयास के एक भाग के रूप में परिषद ने दो सेमिनार आयोजित किए। उत्तरी क्षेत्र के लिए पहला क्षेत्रीय सेमिनार काश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर में आयोजित किया गया। दक्षिणी क्षेत्र के लिए दूसरा क्षेत्रीय सेमिनार कोयम्बतूर में आयोजित किया गया।

जनसंख्या शिक्षा

5.22.35 राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए रा. शै. अ. प्र. परिषद ने कई उपाय किए है। जनसंख्या शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 1988-89 के दौरान विभिन्न विकासात्मक और प्रशिक्षण क्रियाकलाप आयोजित किए। जनसंख्या पर पाठों के संग्रह के विकास के लिए एक कार्यशाला आयोजित की गई। बंगलौर में जनसंख्या शिक्षा (प्रश्न प्रतियोगिता) पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई।

शैक्षिक सामग्री तथा पत्रिकाओं का प्रकाशन

5.22.36 रा. शै. अ. प्र. परिषद का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रियाकलाप अनुपूरक पाठकों के लिए पाठ्य-पुस्तकों, कार्यशालाओं, शिक्षकों, गाइडों, अनुसंधान मोनोग्राफ, पत्रिकाओं आदि का आयोजन करना है। अप्रैल से दिसम्बर, 1988 के दौरान, विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत 216 प्रकाशन प्रकाशित किए गए। इनमें 160 पाठ्य पुस्तकें, 9 अनुपूरक पाठक, 3 शिक्षक गाइडें, 36 अन्य-प्रकाशन तथा पत्रिकाओं के 8 अंक शामिल हैं। परिषद ने स्कूल शिक्षा के विभिन्न स्तरों

पर छात्रों के उपयोग के लिए अंग्रेजी तथा हिन्दी में पुस्तकों की कुछ श्रृंखला प्रारम्भ की। इनमें रीडिंग टू लर्न सीरिज़, लोटस सीरीज़ तथा पढ़ें और सीखें योजना शामिल हैं। परिषद ने 6 पत्रिकाओं का प्रकाशन जारी रखा अर्थात् **भारतीय शिक्षा समीक्षा** (एक तिमाही), **भारतीय शिक्षा की पत्रिका** (हि. मासिक), **स्कूल शिक्षा** (एक तिमाही), **प्राइमरी शिक्षक** (एक तिमाही), प्राइमरी शिक्षक (हिन्दी में एक तिमाही)। रा.शै.अ.प्र. आधुनिक शिक्षा (हिन्दी में तिमाही)। रा. शै. अ. प्र. परि. ने शैक्षिक पत्रकारिता में स्रोत पुस्तक के विकास के लिए 14 से 16 जून, 1988 तक एक कार्यशाला आयोजित की। परिषद ने वर्ष 1988-89 के लिए शैक्षिक पत्रकारिता में राष्ट्रीय पुरस्कार की योजना से संबंधित क्रियाकलाप शुरू किए।

लाइब्रेरी, प्रलेखन और सूचना

5.22.37 रा. शै. अ. प्र. परिषद के लाइब्रेरी प्रलेखन और सूचना विभाग ने रा. शै. अ. प्र. परिषद के विभिन्न विभागों तथा एककों के अनुसंधान तथा विकासात्मक क्रियाकलाप जारी रखे। विभाग, रा. शै. अ. प्र. परिषद के संकाय सदस्यों की सूचना संबंधी आवश्यकताओं को ही पूरा नहीं करता बल्कि पूरे देश के अनुसंधान अध्येताओं तथा शिक्षाविदों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसके पास शिक्षा तथा मनोविज्ञान के क्षेत्र में पुस्तकों तथा आवधिकों तथा सभी स्कूल विषयों से संबंधित पाठ्यचर्या तथा संदर्भ सामग्री का एक बहुत ही अच्छा संग्रह है। विभाग ने स्कूल पुस्तकाध्यक्षों, स्कूल लाईब्रेरियों के शिक्षक प्रभारी तथा शिक्षक प्रशिक्षण कालेजों के पुस्तकाध्यक्षों के लिए सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी रखा। प्रारम्भिक स्तर पर शिक्षण प्रशिक्षण लाईब्रेरियों के विकास पर एक कार्यशाला त्रिवेन्द्रम में 12 से 16 दिसम्बर, 1988 तक आयोजित की गई और इस कार्यशाला में 38 लोगों ने भाग लिया। परिषद ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, उड़ीसा को स्कूल पुस्तकाध्यक्षों/स्कूल पुस्तकालयों के शिक्षक प्रभारियों के लिए 9 से 18 दिसम्बर, 1988 तक सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए शैक्षिक सहायता प्रदान की।

सामूहिक गान

5.22.38 रा. शै. अ. प्र. परिषद ने शिक्षकों को कला तथा सामूहिक गान की तकनीकों में प्रशिक्षित करने के लिए सामूहिक गान शिविर आयोजित किए। अप्रैल से दिसम्बर, 1988 की अवधि के दौरान राज्य/क्षेत्रीय स्तर सामूहिक गान कैम्प तथा दो राष्ट्रीय स्तर तथा एक राज्य स्तर का सामूहिक गान कैम्प आयोजित किए गए। इनके अलावा, सामूहिक गान कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय समितियां भी आयोजित की गई।

अन्तर्राष्ट्रीय संबंध

5.22.39 रा. शै. अ. प्र. परिषद ने स्कूल शिक्षा तथा शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में द्विपक्षीय सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए एक प्रमुख एजेन्सी की भूमिका में अपना कार्य जारी रखा। आलोच्य वर्ष के दौरान 13 देशों से प्रतिनिधियों तथा विशेषज्ञों ने रा. शै. अ. प्र. परिषद का दौरा किया। परिषद ने राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान महारगाया, श्रीलंका के संकाय सदस्यों के लिए 6 सप्ताह के दो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। इसने सोमानिया से आए चार महिला शिक्षा अधिकारियों के लिए आई. टी. ई. सी. कार्यक्रम के अन्तर्गत गैर-औपचारिक शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर 6 महीने का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया। परिषद ने बंगलादेश से आए 12 सदस्यों के लिए 10 दिनों के लिए फैलोशिप प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जिन्होंने अध्ययन के न्यूनतम स्तरों पर आधारित प्राइमरी शिक्षा पाठ्यचर्चा के नवीकरण की प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए भारत का दौरा किया। परिषद ने तीन यूनेस्कों द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं/अध्ययनों/कार्यक्रमों को आयोजित किया तथा विकास के लिए शैक्षिक नवीनता के एशिया तथा पैसिफीक कार्यक्रम के सह केन्द्र तथा शैक्षिक नवीनता के लिए राष्ट्रीय विकास दल के सचिवालय के रूप में प्रमुख भूमिका अदा की। वर्ष के दौरान परिषद द्वारा यूनेस्को प्रायोजित परियोजनाओं/अध्ययन कार्यक्रमों में विकसित देशों सें जैव-तकनीकी (शि.क्ष.प. वी. परियोजना, प्राइमरी स्कूलों में [illegible] शिक्षण में राष्ट्रीय कार्यशाला तथा तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा के तरीकों फार्म तथा स्वरूप में सुधार के लिए एक राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यशाला भी शामिल है। परिषद ने 29 जून, 1988 को राष्ट्रीय विकास दल की आम सभा आयोजित की। आलोच्य वर्ष के दौरान रा. शै. अ. प्र. परिषद के 15 संकाय सदस्यों ने यूनेस्कों तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों जैसे कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान संस्थान, ज्ञापन द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया।

क्षेत्र सेवाएं

5.22.40 रा. शै. अ. प्र. परिषद के 17 क्षेत्र अधिकारियों ने राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में अपने क्षेत्राधिकार में सम्पर्क कार्य करना जारी रखा। रा. शै. अ. प्र. परिषद के क्षेत्रीय अधिकारियों ने नवोदय विद्यालय की स्थापना तथा नवोदय विद्यालय में दाखिले के लिए चयन परीक्षा आयोजित करने में प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने स्कूल शिक्षा के जन अवस्थापना कार्यक्रम के अन्तर्गत अवस्थापना कैम्प आयोजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रत्येक क्षेत्र अधिकारी ने स्कूल शिक्षा तथा शिक्षक शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर शिक्षकों तथा शिक्षक शिक्षकों के लिए कुछ अवस्थापना/प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए तथा राज्य स्तर की खिलौना निर्माण प्रतियोगिता का आयोजन किया।

बाल भवन सोसायटी, भारत

5.23.1 बाल भवन सोसायटी, भारत की शुरूआत 1955 में विद्यालयोपरांत गतिविधि के रूप में बच्चों को रचनात्मक कलाओं, विज्ञान, प्रदर्शन कलाओं, संग्रहालय तकनीकों, छायांकन, खगोलशास्त्र, पर्यावरण, शारीरिक शिक्षा आदि विभिन्न क्षेत्रों में अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।

5.23.2 वर्ष के दौरान राज्यों को अपने बाल भवन आरंभ करने में मदद करने के लिए जम्मू, अरुणाचल प्रदेश और लेह के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ किए गए। बाल भवन ने, अमेरली में खगोलशास्त्र और कम लागत के तारामण्डल पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। विंध्याचल और रामगुदम, एन. टी. पी. सी. (राष्ट्रीय तापीयविद्युत निगम) के दो घटकों, में बाल भवन खोले गए। पणजी, गोआ में जवाहर बाल भवन गोआ के सहयोग से 200 शिक्षकों के लिए राज्य स्तर पर एक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया।

5.23.3 गंदी बस्तियों और देहातों के बच्चों ने बाल भवन कार्यकलापों में हिस्सा लिया। संपूर्ण वर्ष के दौरान सप्ताह में दो बार भूले-बिसरे बच्चों को लाकर नहलाया गया, उन्हें कपड़े पहनाए गए, भोजन कराया गया और उन्हें उनकी पंसद के कार्यकलापों में शामिल किया गया।

5.23.4 विकलांग बच्चों को बाल भवन और बाल भवन केन्द्रों में लाने के लिए एक मिनी बस 'टेल्को' से श्रीमती एवं श्री मूलगांवकर के माध्यम से निःशुल्क प्राप्त की गयी।

5.23.5 इसके अतिरिक्त, बाल भवन ने व्यापार मेला प्राधिकरण के साथ सहयोगात्मक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और बच्चों के कार्य की एक प्रदर्शनी इम्फाल, मणिपुर और लेह (लद्दाख) में आयोजित की। इस नए प्रयोग को हजारों अभिभावकों, बच्चों और अधिकारियों ने देखा। बच्चों के बाल भवन पर एक दृश्य श्रव्य कार्यक्रम दिखाया गया और तदनंतर उन्होंने सृजनात्मक कलाओं, सज्जात्मक कार्य और एयरो-माडलिंग में हिस्सा लिया।

5.23.6 वर्ष के दौरान के अन्य प्रमुख आयोजन में काश्मीर की घाटी और कोडइकनाल, तमिलनाडु में सेना की मदद से व्यावसायिक ट्रेकों का आयोजन था। रा. शै. अ. प्र. परिषद के सहयोग से पर्यावरण पर एक बाल कार्यशाला आयोजित की गई।

5.23.7 एयरो क्लब के बच्चों ने "बच्चों की वैज्ञानिक कृतियां" नामक प्रदर्शनी में भाग लिया। बच्चों ने आई. एन. एस. विक्रांत (जहाज) एवं पनडुब्बियों का प्रदर्शन भी किया।

5.23.8 प्रदर्शन कलाओं, सृजनात्मक कलाओं, खेल और दैनिक जीवन में विज्ञान विषयों पर चार राष्ट्रीय कार्यशालाएं आयोजित की गई। राज्य बाल भवन ने प्रतिभागियों को भेजा जिससे वे काफी लाभान्वित हुए।

5.23.9 बाल भवन निदेशकों का चतुर्थ अखिल भारतीय सम्मेलन 21 अप्रैल, से 24 अप्रैल, 1988 तक चला। सम्मेलन में देश के बाल भवनों को एक दूसरे की ओर अधिक निकट लाने की आवश्यकता की स्वीकार किया गया तथा उनके कार्यक्रमों की बाल भवन सोसायटी द्वारा अनुवीक्षण की परिकल्पना की गई। सम्मेलन के बाद भवन की सदस्यता को, 16-18 आयु वर्ग को भी बाल भवनों की सदस्यता में शामिल करके, बढ़ाने की सिफारिश की।

5.23.10 बाल भवन और बाल भवन केन्द्रों की सदस्यता में काफी वृद्धि हुई। देश के सभी बाल भवनों ने पर्यावरण अभियान का आयोजन किया जिसमें 1,65,000 बच्चों ने भाग लिया।

5.23.11 समाजवादी देशों के बच्चों के रंग चित्रों की

एक प्रदर्शनी के साथ साथ बुल्गारियाई बच्चों की कला कृतियों और रंगचित्रों की भी एक प्रदर्शनी आयोजित की गई। वर्ष के दौरान संख्या की दृष्टि से प्रदर्शनी आयोजन का एक कीर्तिमान स्थापित किया गया।

5.23.12 राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय महत्व के सभी कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें स्वतंत्रता सप्ताह, पर्यावरण अभियान, हरित वाहिनी, विश्व आवास दिवस, संयुक्त राष्ट्र दिवस, मानवाधिकार दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, कौमी एकता दिवस और बाल दिवस शामिल हैं। बाल भवन सोसायटी व बोर्ड ने राष्ट्रीय बाल संग्रहालय को प्रथम प्रधानमंत्री की स्मृति को समर्पित करने का निश्चय किया और इसका नाम जवाहरलाल राष्ट्रीय बाल संग्रहालय रख दिया।

उच्च शिक्षा और अनुसंधान

6.1.1 उच्च शिक्षा के स्तरों का समन्वय तथा निर्धारण करना संघ-सूची का विषय है और यह केन्द्रीय सरकार का विशेष दायित्व है। यह दायित्व मुख्य रूप से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से निभाया जाता है जिसकी संस्थापना संसद के एक अधिनियम के अधीन वर्ष 1956 में की गई थी। इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय भी खुले विश्वविद्यालय और सुदूर अध्ययन प्रणाली के संबंध में ये कार्य करेगा। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार ने विशिष्ट क्षेत्रों में अनुसंधान प्रयासों की प्रौन्नति तथा समन्वय के लिए एजेन्सियों की स्थापना की है। इस समय ऐसी तीन राष्ट्रीय एजेन्सियां हैं अर्थात् भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद् और भारतीय दर्शन-शास्त्र अनुसंधान परिषद्।

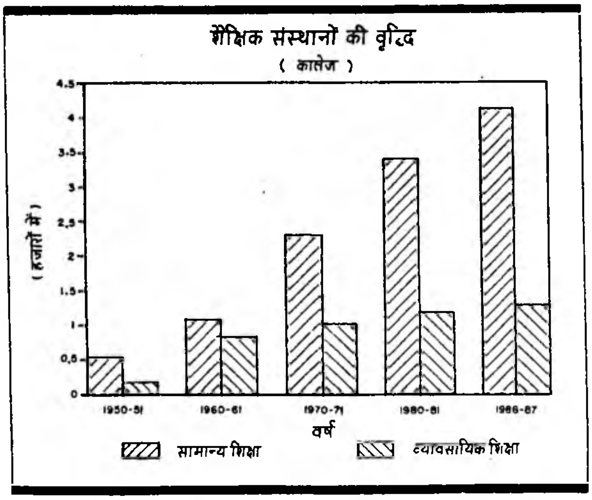

उच्च शिक्षा प्रणाली का विकास

6.2.1 वर्ष 1988-89 के आरम्भ में विश्वविद्यालयों और कालेजों में विद्यार्थियों का कुल नामांकन 38.14 लाख था। यह पिछले वर्ष के नामांकन से 1.32 लाख अधिक था। विश्वविद्यालय विभागों में नामांकन 6.37 लाख और सम्बद्ध कालेजों में 31.77 लाख था।

6.2.2 कला संकाय में नामांकन कुल नामांकन का 40.3% था। विज्ञान और वाणिज्य संकायों से यह प्रतिशतता क्रमशः 19.7 तथा 21.5 थी। प्रथम डिग्री स्तर पर नामांकन 33.57 लाख (88 प्रतिशत), स्नातकोत्तर स्तर पर 3.62 लाख (9.5 प्रतिशत), अनुसंधान स्तर पर 0.42 लाख (1.1 प्रतिशत), और डिप्लोमा और प्रमाण पत्र स्तर पर 0.53 लाख (1.4 प्रतिशत) था।

6.2.3 वर्ष के दौरान शिक्षकों की संख्या में 2.42 लाख की वृद्धि हुई। इनमें से 0.53 लाख विश्वविद्यालय विभागों/विश्वविद्यालय कालेजों और शेष सम्बद्ध कालेजों में थे। विश्वविद्यालयों में 53165 शिक्षकों में 6273 प्रोफेसर, 13079 रीडर, 31580 लेक्चरर और 2233 अनुशिक्षक–प्रदर्शनकर्ता थे। सम्बद्ध कालेजों में वरिष्ठ शिक्षकों की संख्या 24923, लेक्चररों की संख्या 155389 और अनुशिक्षकों/प्रदर्शनकर्ताओं की संख्या 8496 थी।

6.2.4 आलोच्य वर्ष के दौरान 6 राज्य विश्व-विद्यालय जिनके नाम कुवेम्पु विश्वविद्यालय (शिमोगा), कोटा खुला विश्वविद्यालय (कोटा), अजमेर विश्वविद्यालय (अजमेर), राजस्थान कृषि विश्व-विद्यालय (बीकानेर), त्रिपुरा विश्वविद्यालय (अगरतला)

और पूर्वांचल विश्वविद्यालय (जौनपुर) स्थापित किये गये।

महिलाओं में उच्च शिक्षा

6.2.5 महिला छात्रों का नामांकन पिछले वर्ष के 11.25 लाख के मुकाबले वर्ष 1988-89 के आरम्भ में 11.95 लाख था। स्नातकोत्तर स्तर पर महिलाओं का नामांकन कुल नामांकन का 32.7% था। महिला छात्रों का नामांकन केरल में सबसे अधिक (51.6%) था, उसके बाद पंजाब (46.6%), दिल्ली (44.6%), हरियाणा (39.7%) और मेघालय/नागालैंड में (39.6%) था। महिलाओं का सबसे कम नामांकन (15.9%) बिहार में था।

आयोग के कार्यक्रम और कार्यकलाप

6.2.6 वर्ष के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जिन क्षेत्रों में उत्साहपूर्वक मुख्य प्रयास किये गये, उनमें से कुछ थे : स्वायत्त कालेज, पाठ्यक्रमों की पुनर्संरचना, उच्च शिक्षा की राज्य परिषदें, मान्यता एवं मूल्यांकन परिषदें, विश्वविद्यालयों में प्रबंध के वैकल्पिक मॉडल, शिक्षकों की भर्ती के लिए राष्ट्रीय अर्हक परीक्षा, अनुसंधान एवं विकास को व्यापक आधारयुक्त बनाना, शिक्षकों का प्रशिक्षण/अनुस्थापन, कार्यदक्षता में सुधार, युवा तथा खेल और अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों/अनु. जनजातियों, विकलांगों और महिलाओं के लिए शिक्षा। विभिन्न योजनाओं के संबंध में आयोग द्वारा किये गये प्रयासों का एक संक्षिप्त विवरण आगामी पैरों में दिया गया है।

स्वायत्त कालेज

6.2.7 स्वायत्त कालेजों की योजना के लिए संशोधित मार्गदर्शी रूपरेखाओं, जिन्हें 1987 में परिचालित किया गया था, के आधार पर 76 कालेज (19 आंध्र प्रदेश में, 28 तमिलनाडु में, 25 मध्य प्रदेश में और 4 राजस्थान में), स्वायत्त स्तर प्रदान किए जाने के लिए अनुमोदित किये गये हैं। इस प्रकार नवम्बर, 1988 तक स्वायत्त कालेजों की कुल संख्या 95 हो गई। कुछ कालेजों द्वारा दिए गये प्रस्ताव विभिन्न अवस्थाओं में संबंधित विश्वविद्यालयों के विचाराधीन हैं। वे राज्य जहां से कोई सार्थक उत्तर नहीं मिला है, वे है : - बिहार, गुजरात, हरियाणा, केरल, पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम।

उच्च शिक्षा की राज्य परिषदें

6.2.8 आयोग ने उच्च शिक्षा की राज्य परिषदों की संस्थापना के लिए संशोधित मार्गदर्शी रूपरेखाओं का अनुमोदन कर दिया है जो राज्य स्तर पर उच्च शिक्षा की योजना बनाएंगी और उनमें समन्वय करेंगी। उच्च शिक्षा की राज्य परिषदें आंध्रप्रदेश में स्थापित कर ली गई हैं।

पाठ्यक्रमों की पुनर्संरचना

6.2.9 सामान्य शिक्षा में अवर-स्नातक पाठ्यक्रमों की पुनर्संरचना की योजना, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा, प्रथम, डिग्री पाठ्यक्रमों को अधिक प्रासंगिक बनाने और शिक्षा को कार्य/क्षेत्र/व्यावहारिक अनुभव और उत्पादकता के साथ जोड़ने की दृष्टि से शुरू की गई थी। 30 नवम्बर, 1988 तक बत्तीस विश्वविद्यालय इन पाठ्यक्रमों को 134 कालेजों में प्रारम्भ कर चुके हैं। पाठ्यक्रमों की पुनर्संरचना के कार्यक्रम को प्रोत्साहन देने के क्रम में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 27 पाठ्यचर्या विकास केन्द्र स्थापित किये हैं, 10 विज्ञान में और 17 मानविकी और सामाजिक विज्ञान में। ये केन्द्र, मौजूदा पाठ्यचर्या की, इसे आधुनिक बनाने और नई शिक्षण व अध्ययन सामग्रियों को तैयार एवं विकसित करने के विचार से, समीक्षा करेंगे। आयोग को अब तक 12 विषयों में नमूना पाठ्यचर्या प्राप्त हुई हैं। इन पर संबंधित विषयों में विशेषज्ञ समितियों द्वारा विचार किया जाएगा और उसके बाद विशेषज्ञ समितियों की सिफारिशों के साथ, यह विश्वविद्यालयों को भेजीं जाएंगी। इस बीच, आयोग ने 294 कालेजों को अपनी सहायता जारी रखी है जो कालेज विज्ञान सुधार का एक कार्यक्रम लागू कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त 40 विश्वविद्यालय विभागों को भी विज्ञान में विश्वविद्यालय नेतृत्व कार्यक्रम के लिए सहायता प्राप्त हो रही थी। इसी प्रकार 554 कालेज और 12 विश्वविद्यालय विभाग मानविकी और समाज विज्ञान के शिक्षण में सुधार के लिए सहायता प्राप्त कर रहे हैं।

6.2.10 आयोग, विश्वविद्यालयों और बहु-संकाय वाले कालेजों में शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा और खेलों में एक तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए सहमत हो गया है। प्रारम्भिक चरणों में प्रत्येक जिले में केवल एक कालेज ही, जहां बुनियादी न्यूनतम सुविधाएं अर्थात् ट्रेक और मैदान, जिम्नास्टिक, योग,

कन्डीशनिंग यूनिट आदि होगा, पाठ्यक्रम को लागू करने के लिए चुना जाएगा। विश्वविद्यालयों/कालेजों को सलाह दी गई कि पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए प्रस्ताव भेजें। इस पाठ्यक्रम को शुरू करने के लिए आयोग द्वारा 31 मार्च, 1988 तक 11 विश्वविद्यालयों और 22 कालेजों के प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई।

विद्यमान संस्थाओं का समेकन

6.2.11 राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उच्चतर शिक्षा के अंतर्गत विद्यमान संस्थाओं के समेकन तथा उनमें सुविधाओं के विस्तार पर मुख्य बल दिया गया। तद्नुसार, आयोग का मुख्य प्रयास विद्यमान विश्वविद्यालयों और कालेजों की अवस्थापना को मज़बूत बनाना था। वर्ष के दौरान, आयोग ने सातवीं योजना के लिए आवंटित राशि के अलावा छठी योजना तथा उससे पहले की योजनाओं में चल रही भवन-परियोजनाओं की बाकी की अपेक्षाओं के बराबर अतिरिक्त राशि विश्वविद्यालयों को आवंटित करने का निर्णय लिया। विश्वविद्यालयों से, महत्वपूर्ण कार्यों की दिशा में अर्थात् कक्षाओं, प्रयोगशाला, पुस्तकालय भवनों, छात्रावासों, कर्मचारी आवासों आदि के निर्माण के लिए इस राशि का उपयोग करने का अनुरोध किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में अप्रचलित प्रथाओं को हटाने और विश्वविद्यालयों और कालेजों में उपकरणों के समेकन पर बल दिये जाने की दृष्टि से आयोग वर्ष 1987-88 के दौरान विश्वविद्यालयों और कालेजों को, अप्रचलित प्रथाओं को हटाने और उपकरणों का समेकन करने के लिए सहायता देने के लिए सहमत हो गया।

6.2.12 कालेजों के विषय में, पिछले वर्ष, सातवीं योजना में विकास के संबंध में परिचालित मार्गदर्शी रूपरेखाओं की वर्ष 1987-88 के दौरान समीक्षा की गई और निश्चित रियायतें दी गईं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए भी आयोग ने विश्वविद्यालय द्वारा कालेजों की सम्बद्धता की शर्तों के बारे में मार्गदर्शी रूपरेखाएं, विश्वविद्यालयों और राज्य सरकारों को परिचालित कीं। जहां तक कालेज क्षेत्र को दी गई कुल सहायता का संबंध है, बुनियादी सहायता के लिए 2823 कालेजों से प्रस्ताव प्राप्त हुए, उनमें से 2683 कालेजों के प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। 2259 कालेजों ने अवर-स्नातक शिक्षा के विकास के लिए सहायता मांगी है, जिनमें से 1716 कालेजों के प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया है। इसके अतिरिक्त आयोग एकल संकाय कालेजों से प्राप्त 114 प्रस्तावों और स्नातकोत्तर संस्थाओं से प्राप्त 119 प्रस्तावों का अनुमोदन कर चुका है। सातवीं योजना में 30 जून, 1988 तक कालेजों को सहायता के लिए 114.52 करोड़ रूपये की कुल राशि का अनुमोदन किया गया।

कार्यकुशलता में सुधार

6.2.13 आयोग ने 103 विश्वविद्यालयों को संगणक सुविधाओं की स्वीकृति प्रदान की है। इसके अतिरिक्त, आयोग सातवीं योजना अवधि के दौरान 400 कालेजों को लघु संगणक देने के लिए सहमत हो गया है। शुरूआत के तौर पर 281 कालेजों का चयन किया गया है जिनमें से 186 को दिसम्बर, 1988 तक इस प्रयोजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए इन सुविधाओं का उपयोग करने के अलावा, छात्रों के रिकार्ड, खाते और प्रबंध व प्रशासन के लिए आवश्यक अन्य आंकड़ों के रख-रखाव के लिए भी उनका उपयोग किया जाएगा।

शिक्षक भर्ती प्रशिक्षण और निष्पादन मूल्यांकन

6.2.14 आयोग ने शिक्षकों की भर्ती के लिए अर्हक परीक्षा आयोजित करने हेतु कार्यविधियां तैयार करने के लिए इसके द्वारा नियुक्त समिति की सिफारिशों पर विचार किया और निर्णय किया कि समस्याओं की पेचीदगियों को दृष्टि में रखते हुए वर्ष 1988-89 के दौरान अर्हक परीक्षा के आधार पर लेक्चररों की नियुक्ति पर बल न दिया जाए और इस बीच वर्ष 1989-90 से इस योजना को समय पर लागू करने के लिए कार्यविधियां तैयार कर ली जाएं। कालेजों और विश्वविद्यालयों के नए भर्ती होने वाले लेक्चररों के प्रशिक्षण के लिए एक शैक्षिक प्रशिक्षण योजना तैयार की गई है। कार्यक्रम की विषय-वस्तु लचीली होगी ताकि विश्वविद्यालय अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप इनमें सुधार कर सकें। कार्यक्रम की प्रकृति बहु-विषयक होगी। शैक्षिक स्टाफ कालेजों की स्थापना के लिए 41 विश्वविद्यालयों को 3.47 करोड़ रूपये की अनुदान राशि स्वीकृत की गई और नवम्बर, 1988 तक इन स्टाफ कालेजों में से 38 ने कार्य करना शुरू कर दिया था। 45 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किये गये थे और करीब 2500 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया था। उम्मीद है कि निर्धारित सभी 48 शैक्षिक स्टाफ कालेज वर्ष 1988-89 के दौरान कार्य करने योग्य हो जाएंगे। शिक्षकों के कार्यनिष्पादन की प्रणाली तथा

उनके लिए व्यावसायिक नीति संहिता तैयार करने के लिए नियुक्त कार्यदल ने शिक्षकों के कार्यनिष्पादन मूल्यांकन की प्रणाली शुरू करने के संबंध में अपनी रिपोर्ट पूरी कर ली है तथा उसे नवम्बर, 1988 में विश्वविद्यालयों/कालेजों तथा राज्य सरकारों को आगे कार्रवाई के लिए भेजा गया है।

अनुसंधान को सुदृढ़ बनाना

(क) विशेष सहायता कार्यक्रम

6.2.15 आयोग ने उच्च अध्ययन के 26 केन्द्रों, तथा विज्ञान, इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी में विशेष सहायता के 75 विभागों तथा उच्च अध्ययन के 15 केन्द्रों तथा मानविकी तथा समाज विज्ञान में विशेष सहायता के 58 विभागों को सहायता प्रदान करना जारी रखा। इसके अलावा, विज्ञान में 36 विभागीय अनुसंधान सहायक परियोजनाओं तथा मानविकी तथा समाज विज्ञान में ऐसी 13 परियोजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है। आयोग के विषय-पैनलों ने इन विशेष सहायता कार्यक्रमों के अंतर्गत लाने के लिए कुछ और विभागों का पता लगाया है।

(ख) "कोसीसूट" कार्यक्रम

6.2.16 विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी शिक्षा और अनुसंधान में अवस्थापना को सुदृढ़ बनाने की योजना के अंतर्गत 30 नवम्बर, 1988 तक 95 विभागों को सहायता प्रदान की गई है।

(ग) आम सुविधाएं तथा सेवाएं

6.2.17 आधुनिक कम्प्यूटर-आधारित सूचना प्रलेखन केन्द्रों को बंगलौर, बम्बई और बड़ौदा में स्थापित कर दिया गया है। इन केन्द्रों ने शिक्षकों तथा छात्रों तक सूचना पहुचान मे सुधार किया है, और उन्हें विभिन्न विषयों में अद्यतन प्रलेखन उपलब्ध कराने के साथ-साथ उन्हें आवश्यक ग्रंथ-सूची सहायता भी प्रदान की । जे.एन.यू. परिसर में अन्तरिक्ष विज्ञान केन्द्र की वि. अ. आयोग के एक स्वायत्त संस्थान के तौर पर पंजीकृत सोसाइटी के रूप में स्थापना की मई है। इसके अलावा, पूना विश्वविद्यालय में स्थापित खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी में अन्तर-विश्वविद्यालय केन्द्र को भी नवम्बर, 1988 में स्वायत्त सोसाइटी का दर्जा प्रदान किया गया।

शैक्षिक प्रौद्योगिकी और संचार

6.2.18 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षा में "देशव्यापी कक्षा" शीर्षक के अंतर्गत उच्च शिक्षा के लिए दिए गए स्लॉट का उपयोग करने और दूरदर्शन कार्यक्रम में इसके प्रसारण के लिए पहल की। सातवीं योजना के दौरान कालेजो को चरणबद्ध तौर पर रंगीन टेलीविजन सैट उपलब्ध कराने के लिए आयोग सहमत हो गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इन्सेट परियोजना के लिए एक परिप्रेक्ष्य योजना तैयार कर रहा है जिसमें उच्च शिक्षा के लिए भावी इन्सैट समय की आवश्यकता का प्रक्षेपण बनाया जाएगा। आयोग इस समय चार शैक्षिक अनुसंधान संचार केन्द्रों की सहायता कर रहा है जो पूना विश्वविद्यालय, गुजरात विश्वविद्यालय (अहमदाबाद), अंग्रेजी तथा विदेशी भाषाओं का केन्द्रीय संस्थान (हैदराबाद) और जामिया मिलिया इस्लामिया (नई दिल्ली) में स्थित हैं। रूड़की विश्वविद्यालय, उस्मानिया विश्वविद्यालय, जोधपुर विश्वविद्यालय, अन्ना विश्वविद्यालय, मद्रास सेंट जेवियर कालेज, कलकत्ता, मदुरै कामराज विश्वविद्यालय, मदुरै तथा काश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर में सात श्रव्य-दृश्य अनुसंधान केन्द्रों को कार्मिकों के प्रशिक्षण और साफ्टवेयर के उत्पादन के लिए सहायता प्रदान की जा रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कार्रवाई योजना में यथापरिकल्पित, आयोग ने आगामी तीन वर्षों में अच्छे शिक्षकों की सहायता से श्रव्य वीडियो कैसेट के रूप में 15 विषयों में "नाम ब्राडकास्ट मोड एज्यूकेशनल मेटिरियल" की एक परियोजना शुरू की है। अवर-स्नातक छात्रों के लिए मॉडल वीडियो पाठ्यक्रम सामग्री तैयार करने पर सलाह देने के लिए एक समिति गठित की गई है। इस कार्य के लिए आठ उत्पादन-केन्द्रों को चुना गया हैं। शैक्षिक कार्यक्रमों के तैयार करने को बढ़ावा देने के लिए वि अ आयोग ने इस वर्ष दो चरणों में वीडियो कार्यक्रम समारोह आयोजित किये है।

अन्य कार्यक्रम

नए पाठ्यक्रमों की शुरूआत

6.2.19 कुछ उभरते हुए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रशिक्षित जन-शक्ति की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आयोग संबंधित राष्ट्रीय एजेन्सियों के परामर्श से पाठ्यक्रमों को तैयार करने का प्रयत्न कर रहा है। विश्वविद्यालय क्षेत्र में महासागर विज्ञान तथा

प्रौद्योगिकी के विकास में परिवर्धन के लिए आयोग, महासागर विकास विभाग का सहयोग कर रहा है। इसके साथ ही आयोग ने कुछ विश्वविद्यालयों/विश्वविद्यालय समझे जाने वाले संस्थानों में पर्यावरण विज्ञान में उत्तर एम. एस. सी. पाठ्यक्रम शुरू किया है। इसी प्रकार से कलकत्ता, दिल्ली तथा पूना विश्वविद्यालयों में एम. एस. सी. इलैक्ट्रानिक्स विज्ञान कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस पाठ्यक्रम की इलैट्रानिक्स विभाग तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से संयुक्त रूप से सहायता प्रदान की जा रही है। संगणक विज्ञान तथा प्रयोग में विभिन्न जनशक्ति प्रशिक्षण कार्यक्रमों, जैसे कि संगणक प्रयोग में एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम, 3 वर्षीय मास्टर आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन कोर्स और संगणक विज्ञान में बी. टैक, और एम टैक, पाठ्यक्रम चलाने के लिए यू. जी. सी. डी. ओ. ई. संयुक्त कार्यक्रम के अंतर्गत आयोग द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों को इलैक्ट्रानिक्स विभाग सहायता प्रदान कर रहा है। भविष्य विज्ञान तथा भावी अध्ययनों में पाठ्यक्रम प्रदान किए जाने के लिए विश्वविद्यालयों का पता लगाया गया है।

प्रौढ़, सतत् तथा विस्तार शिक्षा कार्यक्रम :

6.2.20 राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के संदर्भ में आयोग ने वर्ष के दौरान विश्वविद्यालयों में प्रौढ़ तथा सतत् शिक्षा एवं विस्तार कार्यक्रमों पर नई मार्गदर्शी रूपरेखाएं तैयार कीं जिनके अंतर्गत विश्वविद्यालयों को सलाह दी गई कि वे कार्यात्मक साक्षरता के लिए जन कार्यक्रम सहित प्रौढ़ शिक्षा आयोजित करने के लिए विशेष क्षेत्र (क्षेत्रों) को अपनाएं, अपनाए जाने वाले प्रस्तावित क्षेत्र का सर्वेक्षण करने के पश्चात् सूक्ष्मस्तरीय योजनाएं तैयार करें और उन विभिन्न आवश्यकताओं/क्षेत्रों का पता लगाएं जहां शैक्षिक हस्तक्षेप अपेक्षित है और विश्वविद्यालय तंत्र के पास उपलब्ध सुविज्ञता, अवस्थापना और सुविधाओं का उपयोग करें और आयोजित कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए अन्य विकास-एजेन्सियों से संपर्क स्थापित करें तथा उनसे सहायता प्राप्त करें। नई मार्गदर्शी रूपरेखाओं का उद्देश्य सभी कार्यक्रमों को सहायता प्रदान करना और महिलाओं, अनुसूचित जातियों/जनजातियों तथा शारीरिक रूप से विकलांग लोगों पर ध्यान देने पर बल देना है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में विश्वविद्यालयों/कालेजों की कार्यात्मक साक्षरता में स्वयं को शामिल करने के अलावा उन्हें 25,000 और 30,000 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों के माध्यम से क्रमशः वर्ष 1988-89 के दौरान पांच लाख लोगों तथा वर्ष 1989-90 के दौरान 6 लाख लोगों को शामिल करने का एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया है। विश्वविद्यालयों द्वारा स्थापित किए गए जनसंख्या शिक्षा क्लबों के क्रियाकलापों के लिए सहायता प्रदान करने के अलावा, विश्वविद्यालयों को वर्ष के दौरान क्लबों की संख्या बढ़ाने की सलाह दी गई ताकि प्रारंभ से ही क्रियाकलापों को बढ़ाया जा सके। पाठ्यचर्या प्रशिक्षण तथा विस्तार कार्यक्रमों के विकास के संदर्भ में निर्दिष्ट क्षेत्रों में विश्वविद्यालयों/कालेजों को जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रमों में सहायता सेवाएं प्रदान करने के लिए यू.एन.एफ.पी.ए.-यू.जी.सी. परियोजना के अंतर्गत स्थापित कार्य दल तथा संसाधन केन्द्रों ने महत्वपूर्ण प्रगति दर्शाई है।

छात्रवृत्तियां और शिक्षावृत्तियाँ

6.2.21 आयोग विश्वविद्यालयों और कालेजों में अनुसंधान विकास के लिए विभिन्न विषयों में कनिष्ठ/वरिष्ठ अनुसंधान शिक्षावृत्तियां प्रदान करता है। इस योजना के अंतर्गत हर बार 3500 से अधिक शिक्षावृत्तियां संचालित की जाती हैं। ये छात्रवृत्तियां केवल उन्हीं अनुसंधान अध्येताओं को प्रदान की जाएंगी जिन्होंने यू.जी.सी., सी.एस.आई.आर., जी.ए.टी.ई.ए. आई.सी.टी.ई. आदि द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की है। जे.एन.यू. तथा भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर द्वारा कुछ चुनिन्दा विषयों में आयोजित अखिल भारतीय स्तर की परीक्षाओं को इस प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय परीक्षाओं के समकक्ष माना गया है।

6.2.22 उन श्रेष्ठ शिक्षकों को एक निर्दिष्ट अवधि के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती है जो अपना पूरा समय अनुसंधान और लेखन को समर्पित करते हैं। अनुसंधान वैज्ञानिकों की योजना के अंतर्गत प्राध्यापकों, रीडरों और प्रोफेसरों के 200 पदों का सृजन इस उद्देश्य से किया गया ताकि उन व्यक्तियों को अवसर प्रदान किये जा सकें जो अनुसंधान को एक कैरियर के रूप में अपनाना चाहते हैं। इस योजना के अंतर्गत सीधे आयोग द्वारा चुनाव किया जाता है। इस समय 180 से अधिक अनुसंधान वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं।

अल्पसंख्यक समुदायों के कमजोर वर्गों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षण

6.2.23 आयोग ने अल्पसंख्यक समुदाय के कमजोर

वर्गों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु कक्षाओं के लिए 14 विश्वविद्यालय और 39 कालेजों को सहायता देना जारी रखा।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए सुविधाएं

6.224 विश्वविद्यालय के पास उलपब्ध कुल ऐसी शिक्षावृत्तियों में से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कनिष्ठ अनुसंधान शिक्षावृत्तियों के अतिरिक्त आयोग प्रति वर्ष सीधे ही केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए 50 शिक्षावृत्तियां प्रदान करता है। इसी प्रकार आयोग ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए 40 अनुसंधान सहशिक्षावृत्तियां भी आरक्षित की हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबद्ध कालेजों के शिक्षकों को एम.फिल./पी.एच.डी. करके अपनी अर्हतायें बढ़ाने के अवसर प्रदान करने हेतु इन शिक्षकों को प्रति वर्ष 50 प्राध्यापक शिक्षावृत्तियां प्रदान की जाती हैं।

महिलाओं की शिक्षा:

6.225 आयोग महिलाओं की शिक्षा में अनुसंधान तथा अवर-स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तरों पर पाठ्यचर्या के विकास तथा संबंधित विस्तार क्रियकलापों की सुव्यवस्थित परियोजनाओं को चलाने के लिए विश्वविद्यालयों को सहायता प्रदान कर रहा है। आयग ने समाज विज्ञान तथा इंजीनियरी और प्रौद्यगिकी सहित महिलाओं के लिए विज्ञान तथा मानवेकी में अंशकालिक सह-अनुसंधान के लिए 40 पदों का सृजन किया है। महिला शिक्षा से संबंधित विषयों में 28 अनुसंधान परियोजनाओं को नवम्बर, 1988 तक सहायता के लिए अनुमोदित किया गया। महिला शिक्षा संबंधी स्थाई समिति ने विभिन्न प्रस्तावों की जांच करने के पश्चात महिलाओं की शिक्षा के लिए कुछ चुनिन्दा विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में केंद्रों/सैलं का गठन करने के लिए सहायता देने की सिफारिश की

सूचना तथा लाइब्रेरी नेटवर्क की स्थापना:

6.226 आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान संगणक तथ संचार प्रौद्योगिकी के प्रयोग के साथ आयोग ने देश में लाइब्रेरियों तथा सूचना केन्द्रों के आधुनिकीकरण की एक परियोजना तैयार करने में पहल की। इस नेटवर्क में उच्च अध्ययन के सभी संस्थानों को शामिल किया जाएगा और यह सूचना-स्थानांतरण तथा पहुंच की क्षमता में सुधार करेगा। जिससे छात्रवृत्ति, अध्ययन, अनुसंधान तथा शैक्षिक मामलों में सहायता मिलेगी।

द्विपक्षीय आदान-प्रदान कार्यक्रम

6.2.27 आयोग ने समय-समय पर सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत उसे सौंपी गई विभिन्न मदों के कार्यान्वयन को जारी रखा। इन कार्यक्रमों में शिक्षकों का आदान-प्रदान, उच्च शिक्षा संस्थाओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों का विकास, संयुक्त सेमिनार, छात्रवृत्तियां तथा शिक्षावृत्तियां और भारतीय विश्वविद्यालयों में विदेशी भाषा के शिक्षकों का सौंपना शामिल है। वर्ष 1987-88 के दौरान इन कार्यक्रमों के अंतर्गत 75 भारतीय शिक्षकों ने विदेशों का दौरा किया और 70 विदेशी अध्येताओं ने भारत का दौरा किया।

केन्द्रीय विश्वविद्यालय

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय

6.3.1 अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़, देश में उच्च अध्ययन का प्रमुख संस्थान है जिसमें किसी जाति अथवा धर्म के भेदभाव के बिना सभी छात्रों को दाखिला प्रदान किया जाता है। विश्वविद्यालय को अपना अखिल-भारतीय स्वरूप बनाये रखने के लिए विश्वविद्यालय ने अपने क्षेत्रीय केन्द्रों अर्थात् बंबई, कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद, कोचीन, श्रीनगर तथा नई दिल्ली में दाखिले के लिए आवेदन प्राप्त करने की नई प्रणाली शुरू की है।

6.3.2 विश्वविद्यालय अपने आवासीय स्वरूप के लिए प्रसिद्ध है। इसमें 55 होस्टल वाले 13 आवासीय हाल हैं। इसमें छात्रों की कुल संख्या 19,041 (विश्वविद्यालय में नामांकन 12,697 स्कूलों में 6344) है तथा आवासीय हाल में रहने वाले छात्रों की संख्या 7,928 है। विश्वविद्यालय ने इस वर्ष 5,498 नए छात्रों को दाखिल किया।

6.3.3 विश्वविद्यालय अधिनियम के खंड 5 (9) (क) के उपबंधों के अंतर्गत इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी संकाय में अध्ययन के छः नए विभाग तथा पांच नए केन्द्र खोले गये। गणित तथा भौतिकी के विभागों को वि.अ. आयोग द्वारा विशेष सहायता के लिए मान्यता

प्रदान की गई है। आलोच्य वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय ने विभिन्न विषयों में कई नए पाठ्यक्रम प्रारंभ किये। कई पाठ्यक्रमों को अद्यतन बनाया गया तथा संशोधित किया गया।

6.3.4 विज्ञान संकाय के अनुसंधान पुनर्मूल्यांकन तथा भू-इंजीनियरी के लिए रिमोट सैन्सिग प्रायोगिक केन्द्र ने रिमोट सैन्सिंग में एम. फिल डिग्री कार्यक्रम प्रारंभ किया है। संगणक केन्द्र संतोषजनक कम्पयूटिंग कार्यक्रम परामर्श तथा शिक्षकों, अनुसंधान अध्येताओं तथा छात्रों के लिए कार्यक्रम लाइब्रेरी सुविधाएं प्रदान कर रहा है। केन्द्र दाखिला-प्रक्रियाओं तथा परीक्षा-परिणामों को तैयार करने में भी मदद करता है।

6.3.5 नए इलैक्ट्रानिक्स इंजीनियरी विभाग में इलैक्ट्रानिक्स और संचार प्रयोगशालाएं शामिल हैं। इसने रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को इंटेग्रेटेड सर्किट फैब्रीकेशन के क्षेत्र में प्रमुख अनुसंधान परियोजना को पूरा किया।

6.3.6 चिकित्सा संकाय सबसे बड़ा संकाय है जिसमें 18 अध्ययन विभाग हैं। विश्वविद्यालय राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के सहयोग से अपने मैडिकल कालेज में प्रारम्भिक कैंसर निदान केन्द्र प्रारंभ करने के प्रयास कर रहा है। भारत सरकार द्वारा 12 लाख रू० की लागत का एक कोबाल्ट यूनिट अनुमोदित किया गया है। मैडिकल कालेज में पेस-मेकर इंपलांटेशन शुरू किया गया है।

6.3.7 विश्वविद्यालय के महिला कालेज में, एक महिला अध्ययन केन्द्र स्थापित करने की योजना पेश की गई है जो कि वि.अ. आयोग के विचाराधीन है।

6.3.8 विश्वविद्यालय के अन्तर-विषयक जैव तकनीकी एकक ने एक रेडियो-आइसोटोप प्रयोगशाला स्थापित की है।

6.3.9 जुलाई, 1987 में स्थापित शैक्षिक स्टाफ कालेज ने पिछले पांच वर्षों के दौरान भर्ती किए गए शिक्षकों के लिए 8 शैक्षिक स्टाफ अनुस्थापन कार्यक्रम आयोजित किये। इस कालेज को कुछ चुनिन्दा विषयों में वरिष्ठ शिक्षकों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों को आयोजित करने के लिए वि.अ. आयोग द्वारा क्षेत्रीय केन्द्र के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।

6.3.10 विश्वविद्यालय का, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद्, नई दिल्ली के सहयोग से, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जन्म शताब्दी समारोह मनाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने का प्रस्ताव है।

6.3.11 विश्वविद्यालय की फुटबाल टीम ने उत्तरी क्षेत्र तथा अखिल-भारतीय अंतर-विश्वविद्यालय फुटबाल चैम्पियनशिप जीती। इसने अखिल भारतीय ड्रामा समारोह की "शरद उत्सव" ट्राफी भी जीती।

6.3.12 सर सैयद स्मारक सोसाइटी, इस्लामाबाद (पाकिस्तान) के 17 सदस्यों वाले एक प्रतिनिधिमंडल ने 15.3.1988 से 26.3.1988 तक भारत का दौरा किया तथा 18 मार्च, से 23 मार्च, 1988 तक विश्वविद्यालय का दौरा किया।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय :

6.3.13 इटली तथा जापानी भाषाओं में चालू शैक्षिक सत्र से प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया जो जुलाई, 1988 में प्रारंभ हुआ। अनुसंधान छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए प्रतियोगी परीक्षा शुरू की गई।

6.3.14 कैंसर में अनुसंधान के लिए अवस्थापना सहायता तथा मैडिकल साइंस संस्थान में शिक्षण और रोगी देख-भाल में सुधार संबंधी सुविधाओं के लिए विश्वविद्यालय के प्रस्ताव को वि.अ. आयोग द्वारा कोसीसूट कार्यक्रम के अंतर्गत अनुमोदित किया गया है। वि.अ. आयोग द्वारा विशेष सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत इलैक्ट्रीकल इंजीनियरी विभाग को 45.20 लाख रू० की राशि संस्वीकृत की गई है। शैक्षिक स्टाफ कालेज ने विश्वविद्यालय तथा पड़ोस के संस्थानों के शिक्षकों के लिए तीन अनुस्थापन पाठ्यक्रम आयोजित किये। भारतीय विश्वविद्यालय संघ की 5-7 दिसम्बर, 1988 को हुई 63वीं वार्षिक बैठक की मेज़बानी बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय ने की। विश्वविद्यालय ने वर्ष के दौरान 10 राष्ट्रीय तथा 2 अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किये तथा पूर्वी क्षेत्र अंतर-विश्वविद्यालय हाकी टूर्नामेंट की मेज़बानी की।

6.3.15 विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी संस्थान के अंतर्गत औद्योगिक परामर्शी केन्द्र के माध्यम से परामर्शी सेवाएं प्रदान कर रहा है। समेकित ग्रामीण विकास केन्द्र, प्रौढ़ तथा सतत शिक्षा केन्द्र तथा आई.सी.एम.आर. द्वारा वित्त-पोषित "ओरफीक" परियोजनाओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों से निरक्षरता, अस्वस्थता तथा गरीबी दूर करने के लिए ग्रामीणोन्मुख विस्तार सेवा कार्यक्रम को पर्याप्त सहायता प्रदान की

जा रही है। खेतीबाड़ी के लिए कृषि फसलों के बीजों की कुछ नई किस्में भी प्रदान की गई।

6.3.16 विश्वविद्यालय ने बहु-विषयक अनुसंधान विकसित करने के लिए कई क्षेत्रों का पता लगाया। इनमें अंतरिक्ष-विज्ञान, जन-शक्ति-विकास, विज्ञान-संग्रहाल्य, ऊर्जा इंजीनियरी आदि शामिल हैं। अधिक-चालकता के क्षेत्र में भौतिक विभाग में ग्रुप को सौंपे गए कार्य की वि.अ.आ. द्वारा प्रशंसा की गई है।

6.3.17 विभिन्न संकायों के कुछ अध्येताओं की अनुसंधान/छात्रवृत्ति के उनके अपने-अपने क्षेत्रों में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मान-पत्र/पुरस्कार प्रदान किये गये। प्रो० श्री कान्त लेले को वर्ष 1987 के लिए विज्ञान इंजीनियरी में शान्ति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए चुना गया था। मराठी विभाग के प्रो० डब्ल्यू.ठ. लेले को पुणे विश्वविद्यालय द्वारा ज्ञानदेव पुरस्कार प्रदान किया गया था। प्रो० बी.सी. कटिया की वर्ष 1989 में होने वाले विश्व तन्त्रिका-विज्ञान संघ के कार्यकारी सदस्य के रूप में चुना गया है। प्रो० वी.वी.पी. कुटुम्बा राव ने राष्ट्रीय धातुकर्मी दिवस पुरस्कार 1988 जीता।

6.3.18 विश्वविद्यालय ने डॉ० सर्वपल्ली राधा कृष्णन, पं० जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और सर सी.वी. रमन की जन्म शताब्दियां मनाने के लिए महत्वाकांक्षी कार्यक्रम तैयार किये। पूरे वर्ष शताब्दी समारोह मनाने के कार्यक्रमों में स्मारक व्याख्यान, सेमिनार, प्रदर्शीनियां और सांस्कृतिक सांध्य गोष्ठियां आदि शामिल हैं।

दिल्ली विश्वविद्यालय

6.3.19 शैक्षिक वर्ष 1988-89 के दौरान विश्वविद्यालय के विभिन्न नियमित और अन्य पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या 65,088 थी। इससे विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की कुल संख्या 1,59,636 हो गई जिसमें से 12,177 नान-कालजिएट महिला शिक्षा बोर्ड, 13,842 एक्सटर्नल कैंडीडेट सैल में पंजीकृत और 33,556 पत्राचार पाठ्यक्रम और सतत शिक्षा विद्यालय के विद्यार्थी थे। विभिन्न पी.एच.डी. और एम.फिल. पाठ्यक्रमों के लिए पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः 2,456 और 650 थी।

6.3.20 वर्ष के दौरान प्रवेश पाने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों की सख्या 4,190 थी।

6.3.21 वर्ष के दौरान शिक्षकों की संख्या 737 थी जिसमें से 260 प्रोफेसर 315 रीडर, 145 प्राध्यापक और 17 रिसर्च एसोसिएट थे।

6.3.22 वर्ष के दौरान निम्नलिखित नए पाठ्यक्रम आरम्भ किये गये :

i) एम.बी.ए. (सार्वजनिक प्रणाली प्रबंध)
ii) एक वर्षीय स्पेनिश भाषा गहन पाठ्यक्रम।
iii) बी.ए. (आनर्स) अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान।
iv) संगणक विज्ञान में एम. टैक. पाठ्यक्रम।
v) प्लांट मोलोक्युलर बायोलॉजी में एम.एस.सी.।

6.3.23 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय ने भारत और विदेशों के अनेक लब्ध प्रतिष्ठित विद्वानों के व्याख्यान आयोजित किए। भौतिक विज्ञान और खगोल भौतिकी विभाग के डॉ० मदन मोहन बजाज को अंतर्राष्ट्रीय पोषण महाविद्यालय अध्येतावृत्ति से सम्मानित किया गया।

6.3.24 वनस्पति विज्ञान विभाग के एक पी.एच.डी. छात्र श्री दीनबन्धु साहू ने सातवें भारतीय दक्षिणी-ध्रुव अभियान में प्रथम भारतीय छात्र के रूप में भाग लिया।

6.3.25 संस्कृत विभाग के प्रो० सत्यव्रत को उत्तर प्रदेश संस्कृत अकादमी द्वारा संस्कृत साहित्य में उनके (रचनात्मक और आलोचनात्मक) योगदान के लिए 25,000/- रु० की राशि के पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

6.3.26 भौतिक विज्ञान और खगोल भौतिकी विभाग के श्री विजय राज सिंह को अंतर्राष्ट्रीय पेन प्रतिष्ठान, संयुक्त राज्य अमरीका की सदस्यता से सम्मानित किया गया है।

6.3.27 इतिहास विभाग के प्रो० पी०एस० गुप्ता को रॉयल हिस्टारिकल सोसाइटी, यू.के. का फैलो चुना गया है।

6.3.28 कुलपति प्रो० मूनीस रज़ा ने अगस्त 1988 में सिडनी, आस्ट्रेलिया में आयोजित 26वीं अंतर्राष्ट्रीय भौगोलिक कांग्रेस में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया।

6.3.29 विश्वविद्यालय ने वर्ष 1988-89 में क्रास

कंट्री (पुरुष और महिला), टेबल टेनिस (पुरुष और महिला), क्रिकेट (पुरुष) (उत्तर क्षेत्र) और खो-खो (पुरुष) (उत्तर-पूर्वी क्षेत्र) आदि सात खेलों में अखिल-भारतीय चैम्पियनशिप जीती। विश्वविद्यालय ने अखिल भारतीय अंतर-विश्वविद्यालय चैम्पियनशिप में पांच खेलों में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। श्री धर्मेंद्र सिन्हा ने "हाई जम्प" में एक नया अंतर-विश्व-विद्यालय कीर्तिमान स्थापित किया।

हैदराबाद विश्वविद्यालय

6.3.30 विश्वविद्यालय ने अपना शैक्षिक वर्ष 1988-89 1 जुलाई, 1988 से आरम्भ किया। इससे पूर्व विश्वविद्यालय ने विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए हैदराबाद से बाहर 6 केन्द्रों पर प्रवेश परीक्षाएं आयोजित की थीं। आलोच्य वर्ष के दौरान, पूरे देश में चयन के बाद 758 नए छात्रों को दाखिल किया गया था। मुख्य रूप से अनु.ज./अनु.जनजाति के छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, एक विशेष प्रवेश परीक्षा विज्ञापन जारी किया गया था। न्यूनतम पात्रता मापदण्ड में छूट दी गई थी ताकि वे प्रवेश परीक्षा में बैठ सकें। विश्वविद्यालय में अगस्त, 1988 तक 1504 में से 179 अनु.जाति, 27 अनु.ज. जाति और 24 शारीरिक रूप से विकलांग छात्र दाखिल थे। महिला छात्रों का दाखिला 568 अर्थात 37.20 प्रतिशत है।

6.3.31 31.3.1988 की स्थिति के अनुसार, विश्वविद्यालय में 51 प्रोफेसर, 61 रीडर तथा 50 लेक्चरार थे। गैर-शिक्षण स्टाफ की संख्या 887 है जिसमें "क", "ख", "ग" और "घ" अधिकारी शामिल है।

6.3.32 वर्ष के दौरान, विश्वविद्यालय का अध्यापन कार्य बिना किसी व्यवधान के जारी रहा। छात्रों को वित्तीय सहायता योग्यता छात्रवृत्तियों के रूप में दी जाती रही। एम.फिल. और पी.एच.डी. के 40 छात्र जिन्होंने वि.अनु.आ./सी.एस.आई.आर. द्वारा संचालित एन.ई.टी. उत्तीर्ण कर लिया था, उन्हें "किसी निर्दिष्ट समय के आधार" के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से शिक्षावृत्तियां मिल रही थीं। इसके अतिरिक्त, कुछ छात्रों ने भारत सरकार और आंध्र प्रदेश की विभिन्न एजेन्सियों से अनु.जा., अनु.ज.जा., शा. वि., जैसी विशेष श्रेणियों के अंतर्गत छात्रवृत्तियां तथा वि.अनु.आ./आई.सी.पी.आर. से राष्ट्रीय/राज्य योग्यता, एल.बी.सी., ई.पी.पी. छात्रवृत्तियां प्राप्त कीं। विश्वविद्यालय ने 767 छात्रों को छात्रावास सुविधाएं उपलब्ध कराईं। इसमें 136 अनु.जा., 18 अनु.ज.जा., तथा 16 शारीरिक रूप से विकलांग छात्र शामिल हैं। 201 महिला छात्रों को छात्रावासों के स्थान उपलब्ध कराया गया था।

6.3.33 वि.अनु.आ., सी.एस.आई.आर., आई.सी.एम.आर., डी.एस.टी., डी.ए.ई., आई.सी.ए.आर. आदि द्वारा वित्त-पोषित अनुसंधान परियोजनाओं की कुल संख्या 72 थी।

6.3.34 आलोच्य वर्ष के दौरान, सामाजिक विज्ञान स्कूल, इन्दिरा गांधी स्मारक पुस्तकालय, प्रशासनिक खण्ड-II फेज और शापिंग आरकेड के भवन पूरे कर दिये गये थे और उन्होंने अपना काम करना आरम्भ कर दिया था। सरोजिनी नायडू निष्पादन कला, ललित कला और संप्रेषण स्कूल ने पेन्टिंग, नृत्य, थियेटर-कलाओं और संप्रेषण में एम.ए.पाठ्यक्रम सहित वि.अनु.आ. की सहायता से इस शैक्षिक वर्ष में कार्य करना आरंभ किया। शैक्षिक स्टाफ कालेज इस वर्ष आरम्भ हुआ। यह दो अनुस्थापन पाठ्यक्रम जिसमें से एक मार्च, 1988 में तथा दूसरा जुलाई-अगस्त 1988 में आयोजित कर सका। वि.अनु.आ. ने एक नए महिला छात्रावास के लिए भी लगभग 53.00 लाख रु० संस्वीकृत किये जिस पर निर्माण-कार्य आरम्भ हो गया है।

6.3.35 कार्यकारी परिषद् की वर्ष के दौरान छः बार बैठक हुई। कोर्ट की वार्षिक बैठक 3 दिसम्बर, 1988 को हुई और विश्वविद्यालय के कार्यकरण पर वार्षिक रिपोर्ट और वर्ष 1987-88 के वार्षिक परीक्षित लेखे प्रस्तुत किये गये थे और अनुमोदित किये गये थे। शैक्षिक परिषद् की बैठक वर्ष के दौरान दो बार मार्च और अक्तूबर, 1988 में हुई।

6.3.36 प्रो० बी.एच. कृष्णामूर्ति जिन्हें 11.6.1986 से कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया था, आलोच्य वर्ष के दौरान इसी पद पर बने रहे। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदयातुल्ला 10.4.1986 से विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं। विश्वविद्यालय ने अपने पर्याप्त मात्रा में सेमिनारों का क्रम जारी रखा। विश्वविद्यालय के पांच शिक्षकों को विभिन्न पुरस्कार मिले।

6.3.37 विश्वविद्यालय के वर्ष 1987-88 के वार्षिक लेखे 7.12.1988 को संसद के सम्मुख रखे गये। विश्वविद्यालय को योजनागत तथा योजनेत्तर योजनाओं के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से

नियमित अनुदान के जरिए वित्तीय सहायता मिल रही हैं।

इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय

6.3.38 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय ने 20 दिसम्बर, 1985 से कार्य करना आरंभ किया। विश्वविद्यालय के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं: उच्च शिक्षा को जनसंख्या के बड़े भागों, विशेषकर सुविधाहीन वर्गों की पहुँच में लाना; सतत शिक्षा के कार्यक्रम आयोजित करना; ज्ञान और कौशलों को स्तरोन्नत करना; और महिलाओं, पिछड़े क्षेत्रों, पर्वतीय क्षेत्रों आदि में रहने वाले लोगों जैसे विशिष्ट लक्षित वर्गों के लिए उच्चतर शिक्षा के विशेष कार्यक्रम आरंभ करना।

शैक्षिक कार्यक्रम

6.3.39 विश्वविद्यालय ने जनवरी, 1987 में दो डिप्लोमा कार्यक्रम आरंभ किए। वर्ष 1988-89 के दौरान इन दोनों कार्यक्रमों में नए दाखिले किए गए थे। इसके अतिरिक्त प्रबंध (माडयूल-II) और सृजनात्मक लेखन में नए डिप्लोमा पाठ्यक्रम आरंभ किए गए। अवर-स्नातक कार्यक्रमों (बी०ए० और बी०काम०) के प्रथम बैच में दाखिले अगस्त, 1988 में किए गए थे। इन कार्यक्रम के लिए नामांकन में शामिल थे: उत्तर-माध्यमिक धारा तथा विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किए गए प्रारंभिक पाठ्यक्रम से वे सफल उम्मीदवार जिनके पास कोई औपचारिक अर्हता नहीं है, से सीधे प्रवेश। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय ने वर्ष के दौरान ग्रामीण विकास तथा खाद्य और पोषाहार में प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम आरंभ किए।

6.3.40 विश्वविद्यालय का, वर्ष 1989 के प्रारंभ में लाइब्रेरी और सूचना विज्ञान में ब्रैचलर डिग्री पाठ्यक्रम तथा प्रबंध डिप्लोमा का माडयूल-III आरंभ करने का विचार है। विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यक्रमों में कुल नामांकन के मार्च, 1989 तक 40,000 तक पहुँच जाने की संभावना है। वर्ष 1989-90 के दौरान आरंभ किए जाने वाले प्रस्तावित शैक्षिक कार्यक्रमों में प्रबंध माडयूल-IV, ग्रामीण विकास खाद्य तथा पोषाहार, बाल देख-भाल और शिक्षा, हिन्दी तथा उच्च शिक्षा में सृजनात्मक लेखन में डिप्लोमा पाठ्यक्रम और जल संसाधन प्रबंध तथा ऊर्जा संरक्षण तथा प्रबंध में प्रमाण-पत्र कार्यक्रम शामिल हैं। इन पाठ्यक्रमों को आरंभ करने का प्रारंभिक कार्य प्रगति पर है।

परिसर विकास

6.3.41 स्थायी परिसर के डिज़ाइन और निर्माण के लिए वास्तुकारों का चयन कर लिया गया है। आरंभ से विश्वविद्यालय ने परिसर में अपने कार्यालयों हेतु कुछ अर्ध स्थाई संरचनाओं के निर्माण का निर्णय लिया है। लगभग 60,000 वर्ग फुट आवास के निर्माण का ठेका, भारत सरकार के एक उपक्रम, हिन्दुस्तान प्री०-फेब०लि० को दे दिया गया है। इस बीच विश्वविद्यालय दिल्ली में कई किराए के परिसरों में कार्य कर रहा है।

उपकरण तथा अन्य सुविधाएं

6.3.42 विश्वविद्यालय की एक प्रमुख अवस्थापना संबंधी आवश्यकता मुद्रण तथा इलेक्ट्रानिक साधनों के लिए सामग्री तैयार करने के लिए उत्पादन सुविधा है। फिलहाल मुद्रित सामग्री पर बहुत भरोसा है। लेकिन विश्वविद्यालय इलेक्ट्रानिक साधनों के लिए सामग्री निर्मित करने के लिए भी सुविधाएं साथ-साथ विकसित कर रहा है। श्रव्य/दृश्य कार्यक्रमों के निर्माण के लिए एक स्टूडियो, भारत सरकार के उपक्रम जी०सी०ई० एल० से उपकरण खरीद का स्थापित किया जा रहा हैं। भारत सरकार और यू०के० के बीच हस्तारक्षित सहायता के एक कार्यक्रम के अंतर्गत विश्वविद्यालय को अपना एक निर्माण स्टूडियो स्थापित किए जाने के लिए पर्याप्त उपकरण तथा अन्य सामग्री उपलब्ध कराई गई है। ब्रिटेन से कुल सहायता (इलेक्ट्रानिक्स उपकरण, संगणक, परामर्श तथा प्रशिक्षण) 8 करोड़ रुपये तक की प्राप्त होने की संभावना है।

जापान सरकार भी विश्वविद्यालय के स्टूडियो तथा निर्माण सुविधाओं के लिए जापानी उपकरण के क्रय के लिए 611 मिलियन येन (7.50 करोड़ रुपये) की सहायता देने के लिए सहमत हो गयी है। अक्तूबर, 1988 में हस्ताक्षरित करार में वर्ष 1988-89 के दौरान इस उपकरण की सप्लाई की व्यवस्था है।

वितरण प्रणाली

6.3.43 विश्वविद्यालय की वितरण प्रणाली में प्रभावी छात्र सहायता सेवाएं शामिल हैं जिसके क्षेत्रीय केन्द्र तथा अध्ययन केन्द्र अभिन्न घटक हैं। अध्ययन केन्द्रों पर अंशकालिक शिक्षक तथा गाइड छात्रों को परामर्श, सलाह और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। वे सभी पाठ्यक्रमों के लिए सारी सामग्री एकत्र करते हैं

और दृश्य/श्रव्य कार्यक्रमों के लिए देखने/सुनने की सुविधाएं उपलब्ध कराते है। मार्च, 1989 तक विश्वविद्यालय की ऐसे 125 अध्ययन केन्द्र स्थापित करने की योजना हैं जिसमें से 107 को दिसम्बर, 1988 तक स्थापित कर दिया गया है।

6.3.44 इस समय बारह क्षेत्रीय केन्द्र विद्यमान अध्ययन केन्द्रों का पर्यवेक्षण तथा समन्वय करते हैं। अध्ययन केन्द्रों की संख्या में वृद्धि के साथ-साथ और क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित किए जाएंगे।

6.3.45 वर्ष 1988-89 के दौरान विश्वविद्यालय को 10 करोड़ रु० का अनुदान संस्वीकृत किया गया था।

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय

6.3.46 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्व विद्यालय के विभिन्न स्कूलों में विभिन्न अध्ययन पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए पूरे देश में 24 केन्द्रों में संचालित जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा को, विभिन्न विज्ञान विषयों में एम०फिल०/एम०टेक०/पी०एच०डी० कार्यक्रमों में अध्ययन कर रहे छात्रों को जूनियर अनुसंधान शिक्षावृत्तियां प्रदान करने के लिए आयोग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शैक्षिक परीक्षा के बराबर मान्यता प्रदान की। इस मान्यता के परिणामस्वरूप, विश्वविद्यालय के विभिन्न स्कूलों में ऊपर उल्लिखित कार्यक्रमों में विश्वविद्यालय द्वारा संचालित अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा में अपनी पारस्परिक योग्यता के आधार पर प्रवेश लेने वाले छात्र वि०अनु०आ० जूनियर अनुसंधान शिक्षावृत्तियाँ प्रदान किए जाने के लिए इस प्रयोजनार्थ आयोग द्वारा संचालित परीक्षा उत्तीर्ण किए बगैर स्वत: ही पात्र हो जाएंगे।

6.3.47 अध्ययन के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रमों को पुन: तैयार किया गया तथा उन्हें अद्यतन बनाया गया। संगणक तथा पद्धति विज्ञान स्कूल में एक माइक्रो-वैक्स-II संगणक पद्धति स्थापित की गई। विभिन्न स्कूलों के संकाय सदस्यों द्वारा पैतीस अनुसंधान परियोजनाएं पूरी हो गई जबकि 69 परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर था। ये परियोजनाएं विभिन्न राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा प्रायोजित की गई थीं, जिनमें सरकारी विभाग भी शामिल हैं। विश्वविद्यालय के विभिन्न केन्द्रों द्वारा लगभग एक दर्जन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार/विचार-गोष्ठियां आयाजित की गई। वर्ष के दौरान "समकालीन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में प्रमुख मुद्दे" नामक विषय पर तीस विस्तार लेक्चर आयोजित किए गए। भारत की स्वतंत्रता की 40वीं वर्षगाँठ के अवसर पर भी सार्वजनिक लेक्चर आयोजित किए गए।

6.3.48 ऐतिहासिक अध्ययनों का केन्द्र वि०अनु० आ० के विशेष सहायता के कार्यक्रम के अंतर्गत अनुमोदित किया गया।

6.3.49 तिरसठ हजार प्रेस कतरनें, 11,831 पुस्तकें तथा 100 सीटों की बैठने की क्षमता वाला एक नया वाचनालय लाइब्रेरी में शामिल किए गए थे। प्रौढ़ शिक्षा एकक ने कारीगरों, विशेष रूप से दिल्ली के कुम्हारों की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों का अध्ययन आरंभ किया। इसने ज०ने० विश्वविद्यालय परिसर में तथा उसके आस-पास लगभग 55 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र स्थापित किए। परिसर में छात्रों को चिकित्सा सहायता तथा परामर्श उपलब्ध कराने के अतिरिक्त, स्वास्थ्य केन्द्र ने स्वास्थ्य देखभाल के कई निवारक कार्यक्रम आरंभ किए।

6.3.50 निर्माण कार्यक्रमों ने प्रगति को बराबर बनाए रखा। लाइब्रेरी टावर ब्लाक पूरा हो गया है इसी प्रकार ट्रांजिट आवास के 25 यूनिट तथा टाइप-I क्वार्टरों (फेज-II) के 36 यूनिट के०लो०नि० विभाग द्वारा पूरे किए गए तथा अधिकार में ले लिए गए। समाज विज्ञान स्कूल का अतिरिक्त फलोर भी अधिकार में ले लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन स्कूल के संबंध में निर्माण कार्य, सामाजिक-विज्ञान स्कूल के विस्तार खण्ड, पर्यावरणीय विज्ञान स्कूल तथा भाषाओं के स्कूल ने सारणी के अनुसार प्रगति बनाए रखी। संकाय क्लब का निर्माण कार्य तथा गेस्ट हाउस, सामुदायिक केन्द्र, छात्र क्लब तथा कर्मचारियों का क्लब प्रगति के उन्नत चरण में है।

6.3.51 विश्वविद्यालय ने 1989 में पं० जवाहरलाल नेहरू का शताब्दी समारोह आयोजित करने के लिए एक समिति गठित की। कार्यक्रम में सांस्कृतिक और खेल-कूद क्रियाकलापों, प्रदर्शनियां, विस्तार लेक्चर आदि का आयोजन शामिल है।

उत्तर-पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय

6.3.52 उत्तर-पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय के नागालैण्ड, मिजोरम और मेघालय में तीन परिसर हैं, जिनका मुख्यालय शिलांग में है। फिलहाल शिलांग

परिसर में 18 स्नातकोत्तर विभाग हैं, इसके अतिरिक्त कोहिमा परिसर में 4 शैक्षिक विभाग तथा आइजौल परिसर में 5 हैं। आज तक 8 केन्द्र स्थापित हो गए हैं। विश्वविद्यालय के 2 कालेज अर्थात् पछुंगा विश्वविद्यालय कालेज तथा कृषि विज्ञान और ग्रामीण विकास स्कूल क्रमशः मिजोरम और नागालैण्ड में स्थित हैं।

6.3.53 विश्वविद्यालयों के उद्देश्यों के अनुरूप ही उत्तर-पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय तीन राज्यों, मेघालय, नागालैण्ड तथा मिजोरम में रहने वाले लोगों विशेषकर युवाओं की सामाजिक तथा शैक्षिक श्रेष्ठता निखारने में लगा हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में शिलांग में विश्वविद्यालय के स्थायी परिसर का निर्माण करने तथा विकसित करने पर प्रयास केन्द्रित कर रहे हैं। 200 सीटों वाला छात्रवास, 50 स्टाफ क्वार्टस, उत्तर-पूर्वी परिषद् द्वारा प्रायोजित 200 सीट वाला एक और छात्रावास सेमिनार परिसर तथा गेस्ट हाउस का निर्माण पूरा कर लिया गया है। शिलांग स्थित उ०पू०प०वि० परिसर तक एम०एस०ई०बी०टर्मिनल के लिए 33 के०वि०लाइन की व्यवस्था 1987 में पूरी हो गई थी। बिजली तथा पानी की आपूर्ति स्थायी परिसर को अब कर दी गई हैं। 150 स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण 800 सीट वाला छात्रावास भवन भौतिक विज्ञानों तथा जीवन विज्ञानों के स्कूलों के लिए लेक्चर काम्पलेक्स, यू०एस०आई०सी०, आर०एस०आई०सी० तथा कार्यशाला के लिए भवनों का निर्माण प्रगति पर है। उत्तर पूर्वी परिषद द्वारा प्रायोजित मिजोरम परिसर स्थित 100 सीट वाला छात्रावास भी प्रगति पर है।

6.3.54 शैक्षिक काम्प्लेक्स के आस-पास रिंग रोड तथा एक फुटबाल ग्राउंड (खेलकूद काम्पलेक्स) का निर्माण मार्च, 1989 में पूरा हो जाने की संभावना है।

6.3.55 वर्ष 1987 और 1988 के दौरान 17 सेमिनार और सम्मेलन आयोजित किए गए थे जिसमें मिजोरम परिसर, आइजौल शामिल है।

6.3.56 8 सितम्बर, 1988 के शिलांग में हुए एक विशेष दीक्षान्त समारोह में, विश्वविद्यालय ने कृपा और अनुकम्पा की एक मानवीय प्रतीक, मदर टैरेसा, को डॉक्टर आफ लिटरेचर (आनोरिस कौजा) की डिग्री प्रदान की गई।

पांडिचेरी विश्वविद्यालय

6.3.57 पांडिचेरी विश्वविद्यालय की स्थापना 16 अक्तूबर, 1985 में हुई और तब से यह तीव्र गति से प्रगति करता रहा हैं। आलोच्य वर्ष के दौरान निम्नलिखित स्कूलों/विभागों की स्थापना की गई:

(1) सलीम अली परिस्थिति-विज्ञान स्कूल
(2) फ्रांसीसी भाषा-विज्ञान और इतिहास विभाग
(3) अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन स्कूल
(4) शैक्षिणिक स्टाफ कालेज

6.3.58 पांडिचेरी विश्वविद्यालय ने 1.6.1987 जिपमेर के भौतिकी, रसायनिकी और जैव-विज्ञान के नान-मेडिकल विभागों का अधिग्रहण किया।

6.3.59 पांडिचेरी विश्वविद्यालय के अधीन अब दो स्कूल, एक संस्थान, एक शैक्षणिक स्टाफ कालेज और ग्यारह विभाग हैं।

6.3.60 वर्ष के दौरान निम्नलिखित नए पाठ्यक्रम शुरू किए गए:

(1) एम०ए०	(अंग्रेजी और तुलनात्मक साहित्य)
(2) एम०एस०	(विकास अर्थशास्त्र)
(3) एम०ए०	(व्यावहारिक तमिल)
(4) एम०काम०	(व्यापारिक-वित्त)
(5) एम०एस०सी०	(व्यावहारिक गणित)
(6) एम०फिल०	(इतिहास)
(7) एम०फिल०	(फ्रांसीसी)

(8) फ्रांसीसी भाषा में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम (सायं)
(9) संगणकों के क्षेत्र में प्रमाण-पत्र-पाठ्यक्रम (कोस्टीड मद्रास के सहयोग से)
(10) बी०एस०सी० शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य और खेलकूद में (जुलाई, 1989 से आरंभ होगा)

6.3.61 कुल मिलाकर 7 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम और 10 एम०फिल० पाठ्यक्रम आरंभ किए जा रहे हैं। तमिल, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, इतिहास, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, परिस्थिति विज्ञान, भौतिकी, रसायन शास्त्र और जैव-विज्ञान विषयों में पी०एच०डी० कार्यक्रमों के लिए पहली बार नामांकन किया गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पांडिचेरी विश्वविद्यालय में एक अंग्रेजी भाषा प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना को स्वीकृति दे दी है।

6.3.62 पांडिचेरी विश्वविद्यालय के अधीन अब 14 सम्बद्ध कालेज हैं जिनमें से 8 कालेज पांडिचेरी में हैं, 2 कराईकल में, एक माहे में, एक यनम में और 2 पोर्टब्लेयर में हैं।

6.3.63 उपर्युक्त सम्बद्ध कालेजों में 5677 विद्यार्थी हैं जिनमें 439 विद्यार्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हैं और 2272 महिला विद्यार्थी हैं। आलोच्य वर्ष के दौरान, इन कालेजों ने 37 अवर स्नातक पाठ्यक्रम, 34 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम, 10 स्नातकोत्तर डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम, एक एम० फिल० पाठ्यक्रम और एक विषय में पी०एच०डी० कार्यक्रम आरंभ किए।

6.3.64 शैक्षिक वर्ष 1987-88 के दौरान, विश्वविद्यालय में दाखिला लेने वाले नए छात्रों की कुल संख्या 404 थी, जिनमें 35 विद्यार्थी अनुसूचित जाति के थे, 3 अनुसूचित जनजाति के थे और 95 महिला विद्यार्थी थे। शैक्षिक वर्ष 1987-88 के दौरान जिन छात्रों का नामांकन किया गया था, उनकी कुल संख्या 430 थी। 1987-88 में, पी०एच०डी० कार्यक्रम में 38 छात्रों को दाखिला दिया गया।

6.3.65 31.3.88 तक इस विश्वविद्यालय में 18 प्रोफेसर, 25 रीडर, 38 प्राध्यापक और 3 निर्देशक थे।

6.3.66 31.3.88 तक विश्वविद्यालय में 23 ग्रुप "ए" अधिकारी, 7 ग्रुप "बी", 126 ग्रुप "सी" और 91 ग्रुप "डी" कर्मचारी थे।

6.3.67 आलोच्य वर्ष के दौरान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने, प्रशासनिक परिसर, शैक्षिक भवनों, छात्रावासों, पुस्तकालय भवनों, स्टाफ-क्वार्टर, खेल स्टेडियम और परिसर विकास के निर्माण के लिए 267.67 लाख रुपये की राशि रिलीज की।

विश्व भारती

6.3.68 शैक्षिक वर्ष 1987-88 के दौरान विश्व-विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या 4515 थी तथा शिक्षकों की कुल संख्या 458 थी जिनमें 63 प्रोफेसर और 148 रीडर थे।

6.3.69 प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी द्वारा "गणित सदन (संगणक केन्द्र)" का उद्घाटन विश्वविद्यालय के शैक्षिक कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए एक और मील पत्थर था। शैक्षिक स्टाफ कालेज का गठन करने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।

6.3.70 विश्वविद्यालय ने, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, डी०एस०टी० आई०सी०ए०आर० और आई०सी०एच०आर० संस्थाओं के सहयोग से राष्ट्रीय सेमिनार और कार्यशालाएं आयोजित कीं। इन कार्यकलापों से, संकाय सदस्यों और देश के विभिन्न भागों के छात्रों के बीच तालमेल को बढ़ावा मिलता है। कई व्यक्तिगत और विभागीय परियोजनाएं आरंभ की गई। नई आरंभ की गई परियोजनाओं में से एक परियोजना, विश्व विकास आर्थिक अनुसंधान संस्थान भी है जो संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय की एक अनुसंधान संस्था है जो कि पूर्वी भारत, विशेषकर बंगाल क्षेत्र की ग्रामीण निर्धनता, सामाजिक परिवर्तन और सार्वजनिक नीति का अध्ययन करती हैं।

6.3.71 हिन्दी भवन के स्वर्णजयन्ती समारोह का उद्घाटन प्रधानमंत्री, श्री राजीव गांधी ने 16 जनवरी, 1988 को किया। हिन्दी भाषा और साहित्य के क्षेत्र में अनुसंधान के मामले में इसका योगदान सर्वव्यापक है। इस कार्यक्रम की मुख्य सफलता टैगोर की कुछ कृतियों का हिन्दी में प्रकाशन था

6.3.72 रवीन्द्र रचनावली के लोकप्रिय संस्करण के चार संग्रहों को प्रकाशित किया गया जिनका पाठकों ने व्यापक रूप से स्वागत किया। विदेशों में भी लोगों में इसके प्रति रुचि देखी गई। पश्चिमी जगत में टैगोर के चित्रों के प्रति भी गहरी रुचि दृष्टिगोचर हुई।

6.3.73 टैगोर की स्मृति से सम्बद्ध पुराने भवनों के जीर्णोद्धार का काम प्रगति पर है।

6.3.74 उड़ीसा, त्रिपुरा और बिहार के साथ सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान-प्रदान तथा सहयोग बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ।

6.3.75 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता केन्द्र ने कार्य करना आरंभ कर दिया हैं। इस केन्द्र का शैक्षिक कार्यक्रम, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल प्रो० नूरूल हसन के "भारत में धर्मनिरपेक्षवाद" विषय पर भाषण से आरंभ हुआ।

नए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना

जामिया मिलिया इस्लामिया

6.3.76 सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थानों के बायकाट के लिए गांधी जी के आह्वान के अनुसरण में खिलाफत और असहयोग आन्दोलन के दौरान 1920 में अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना की गई थी और जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के खण्ड 3 के अंतर्गत 1962 में विश्वविद्यालय समझे जाने वाला संस्थान घोषित किया

गया। पिछले कुछ वर्षों के दौरान जामिया के शैक्षिक समुदाय, इसके प्राधिकारियों तथा आम समाज की माँग थी कि इस संस्थान के ऐतिहासिक स्वरूप और राष्ट्र के प्रति इसकी सेवाओं को देखते हुए, जामिया को संसद के अधिनियम द्वारा पूर्ण विश्वविद्यालय का स्तर प्रदान किया जाना चाहिए ताकि यह उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विकसित होने और उत्कृष्टता प्राप्त करने में सक्षम हो सके- सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जामिया मिलिया इस्लामिया के कुलपति और कुछ प्रख्यात शिक्षाविदों जिनमें मुस्लिम विद्वान भी शामिल थे, के परामर्श से इस विषय पर गंभीरता से विचार किया है। जामिया की एक राष्ट्रीय संस्था के रूप में उत्पत्ति, स्वतंत्रता संग्राम में इसके योगदान, इसके इतिहास और निस्वार्थ सेवा और इसके धर्मनिरपेक्षीय स्वरूप पर विचार करके सरकार ने यह निर्णय किया कि जामिया को, अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के अभिशासन की सामान्य पद्धति के अनुसार संसदीय अधिनियम द्वारा एक पूर्ण विश्वविद्यालय में परिवर्तित किया जाए। वर्ष 1988 के संसद के मानसून सत्र के दौरान आवश्यक कानून पेश किया गया और पास किया गया। जामिया मिलिया इस्लामिया अधिनियम 1988, 26 दिसम्बर, 1988 से लागू हुआ।

6.3.77 जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय अपने विश्वविद्यालय क्षेत्र के व्यय को वहन करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से आवर्ती और अनावर्ती अनुदान प्राप्त कर रहा है। इसे अपने गैर विश्वविद्यालय क्षेत्र के लिए अनुदान शिक्षा विभाग से सीधे ही स्वीकृत किए गए।

6.3.78 गैर विश्वविद्यालय क्षेत्र के अंतर्गत जामिया अपना उच्चतर माध्यमिक स्कूल, मिडिल स्कूल, नर्सरी स्कूल तथा पालिटेक्निक चल रहा है। शैक्षिक वर्ष 1988-89 के दौरान स्कूलों और पालिटेक्निक में क्रमश: 2628 और 300 छात्र दाखिल थे।

6.3.79 जामिया मिलिया इस्लामिया को जामिया पालिटेक्निक के लिए भवन निर्माण, स्कूल परिसर के विकास और उच्चतर माध्यमिक स्कूल में इंजीनियरी शाखा के लिए उपर्युक्त ढाँचा प्रदान करने के लिए अनुदान संस्वीकृत किए गए हैं।

6.3.80 26 दिसम्बर, 1988 से जामिया मिलिया इस्लामिया अधिनियम, 1988 के लागू होने से वर्ष 1989-90 के लिए, जामिया के स्कूल क्षेत्र के लिए अनुदान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रदान किया जाएगा, जैसे कि अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को दिया जाता है।

नए प्रस्तावित विश्वविद्यालय

6.3.81 सरकार ने असम में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक को 1989 के आरंभ में संसद में पेश किए जाने की आशा है।

6.3.82 नागालैण्ड में लुमानी में एक नया विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। विश्वविद्यालय के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है और विधेयक को संसद में, 1989 के आरंभ में पेश किए जाने की आशा है।

विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्थाएं

6.3.83 दो संस्थाओं अर्थात् केन्द्रीय तिब्बती उच्च शिक्षा संस्थान, सारनाथ (वाराणसी) और महिलाओं की उच्च शिक्षा और गृह विज्ञान के लिए श्री अविनाशीलिंगम संस्थान, कोयम्बतूर को आलोच्य वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के खण्ड 3 के अंतर्गत विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्थाएं घोषित किया गया और इस प्रकार विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्थाओं की संख्या 24 हो गई है।

विशिष्ट अनुसंधान संगठन

भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला

6.4.1 भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला की स्थापना 1965 में एक आवासीय केन्द्र के रूप में की गई थी ताकि विद्वानों को मानविकी, भारतीय संस्कृति, तुलनात्मक धर्म, सामाजिक विज्ञान तथा प्राकृतिक-विज्ञान के चुने हुए विषयों में शैक्षणिक अनुसंधान के अनुकूल वातावरण प्रदान किया जा सके। संस्थान का उद्देश्य मूलभूत विषयों और जीवन तथा चिन्तन की समस्याओं पर निष्पक्ष और रचनात्मक खोज करना है। यह विस्तृत पुस्तकालय और प्रलेखन सुविधा के अतिरिक्त, उच्च परामर्शी और सहयोग के लिए सुविधाएं प्रदान करता है।

6.4.2 वर्ष 1988-89 में इस संस्थान में दाखिल 27 अध्येता, विभिन्न विषयो पर अनुसंधान कार्य कर रहे हैं। कुछ अन्य अध्येताओं द्वारा निकट भविष्य में दाखिला लिए जाने की उम्मीद है।

6.4.3 आलोच्य अवधि के दौरान संस्थान ने निम्नलिखित विषयों पर तीन विचार संगोष्ठियां आयोजित कीं जिनमें देश के सभी भागों से प्रख्यात शिक्षा-शास्त्रियों ने भाग लिया :–

i) स्वतंत्रता के पश्चात भारत में कला और जीवन

ii) महाभारत के नैतिक धर्मसंकट पर संभाषण

iii) आत्म छवि, पहचान और राष्ट्रीयता

इन विचार संगोष्ठियों की कार्यवाही को संक्षिप्त खण्डों के रूप में प्रकाशित किया जाएगा।

6.4.4 संस्थान की शैक्षिक गतिविधियों की उल्लेखनीय विशेषता, अध्येताओं की साप्ताहिक सामूहिक वाद-विवाद बैठकें हैं और इससे विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे अध्येताओं के मध्य परस्पर तालमेल स्थापित करना है। इन सामूहिक वाद-विवाद बैठकों में प्रस्तुत किए गए कागजों को "प्रासंगिक पत्र" नामक एक नई श्रृंखला के अंतर्गत प्रकाशित किया जा रहा है जो कि पुस्तिका के रूप में हैं। आलोच्य वर्ष के दौरान इस संस्थान ने कई प्रकाशन निकाले और तीन प्रकाशन अभी मुद्रणाधीन हैं।

भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद

6.5.1 इतिहास के वैज्ञानिक लेखन के उद्देश्य को बढ़ावा देने, ऐतिहासिक अनुसंधान कार्यक्रम प्रायोजित करने तथा देश की राष्ट्रीय और सांस्कृतिक विरासत के सम्यक बोध के लिए 1972 में भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद् की स्थापना की गई थी।

6.5.2 वर्ष 1988-89 के दौरान, दो प्रख्यात इतिहासकारों को राष्ट्रीय शिक्षावृत्तियां प्रदान की गई। इस परिषद ने 28 अनुसंधान परियोजनाएं तथा 98 शिक्षावृत्ति अनुदान और विद्वानों को 108 अध्ययन यात्रा अनुदान प्रदान किए। 82 अनुसंधान विनिबन्धों, मोनोग्राफ और पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशनार्थ आर्थिक सहायता की स्वीकृति दी जा चुकी है। इतिहासकारों के 57 व्यावसायिक संगठनों जैसे भारतीय इतिहास कांग्रेस, दक्षिण भारतीय इतिहास कांग्रेस, पंजाब इतिहास कांग्रेस, उड़ीसा इतिहास कांग्रेस, भारतीय मुद्राशास्त्रीय संस्था आदि को अनुदान संस्वीकृत किया गया है ताकि वे सेमिनारों/संगोष्ठियों आदि का आयोजन कर सकें।

6.5.3 इस परिषद ने इतिहासकारों को विदेशों में आयोजित निम्नलिखित सेमिनारों/सम्मेलनों में भाग लेने के लिए नामित किया : ब्राइटन में 18वां विश्व दर्शनशास्त्र सम्मेलन, बुडापेस्ट में भारतीय राष्ट्रवाद और नेहरू पर गोलमेज सम्मेलन, मास्को में आयोजित "संघर्षरत किसान" और ढाका में आयोजित प्रथम सार्क इतिहास सम्मेलन। इस परिषद ने "भारत में नए पुरातत्व विज्ञान" विषय पर एक सेमिनार आयोजित किया जिसमें चार विदेशी और 20 भारतीय विद्वानों ने भाग लिया। सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत दो अफगानी, दो पुर्तगाली और जर्मन जनवादी गणराज्य के दो विद्वानों को, भारत में अनुसंधान करने के लिए आमंत्रित किया गया।

6.5.4 इसके प्रकाशन कार्यक्रम के अंतर्गत परिषद ने टी०वी० महालिगम द्वारा लिखित "ए" टोपोग्राफिकल लिस्ट आफ इनस्क्रिप्शन इन तमिलनाडु और केरल" खण्ड 11 तथा रघुबीर सिन्हा द्वारा रचित "जोधपुर राज्य की ख्याति" (हिन्दी में), फारसी में शंभुप्रसाद देसाई द्वारा लिखित "तारीख ए सोराथ", ए०आर० देसाई द्वारा सम्पादित "भारत में मजदूर आंदोलन-1918-1920 दस्तावेज", अमलेन्दु गुहा द्वारा "प्लांटर राज टू स्वराज" (द्वितीय संस्करण) नामक पाँच पुस्तकों का प्रकाशन किया। अंग्रेजी फारसी, हिन्दी और तमिल में बाईस पुस्तकें प्रैस को भेजी गई हैं। इसके अलावा 30 से अधिक मोनोग्राफों तथा शोधपत्रों का प्रकाशन परिषद के प्रकाशन के लिए आर्थिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत किया।

6.5.5 भारत की स्वतंत्रता की 40वीं वर्षगाँठ और पंडित जवाहर लान नेहरू की जन्म शताब्दी समारोहों के भाग के रूप में भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद ने पांडिचेरी, हैदराबाद, श्रीनगर, कलकत्ता और दिल्ली में राष्ट्रीय आन्दोलन पर पाँच कार्यशालाओं का आयोजन किया।

भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद

6.6.1 भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद की स्थापना मुख्यत: दर्शन शास्त्र में अनुसंधान की प्रगति की समीक्षा करने, दर्शनशास्त्र में अनुसंधान की परियोजनाओं को प्रायोजित करने अथवा उनको सहायता ने और दर्शनशास्त्र और सम्बद्ध विषयों में अनुसंधान के संवर्धन के लिए अपेक्षित अन्य अनिवार्य उपाय करने के लिए की गई है।

6.6.2 वर्ष 1988 के दौरान परिषद ने पिछले वर्षों में पुरस्कृत अन्य शिक्षावृत्तियों को जारी रखने के अलावा दो वरिष्ठ शिक्षावृत्तियाँ, इक्कीस सामान्य शिक्षा-वृत्तियाँ, चार आवासीय शिक्षावृत्तियाँ तथा एक अल्पकालीन शिक्षावृत्ति भी प्रदान की।

6.6.3 भारतीय दार्शनिक परंपरा को फिर से सशक्त करने की अपनी परियोजना के अंतर्गत परिषद ने लखनऊ में अपने शैक्षिक केन्द्र में फारसी, अरबी और इस्लामी दर्शन सिद्धांतों के उलेमा और आधुनिक विश्वविद्यालय प्रशिक्षित अध्येयताओं के बीच एक वार्ता एवं सेमिनार का आयोजन किया। इस संबंध में परिषद द्वारा बंगलौर में एक शरद स्कूल तथा धर्मशाला में एक ग्रीष्म स्कूल का आयोजन किया गया।

6.6.4 परिषद ने युवा अध्येताओं में प्रतिभा का प्रसार करने के लिए "दर्शन संस्कृति और मूल्य" विषय पर एक अखिल भारतीय निबंध प्रतियोगिता आयोजित की। इसी विषय पर नवम्बर, 1988 में दिल्ली विश्वविद्यालय में एक सेमिनार भी आयोजित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, सेमिनारों आदि में भाग लेने के लिए सात अध्येताओं को परिषद ने यात्रा अनुदान दिए। अपने वार्षिक व्याख्यानों के कार्यक्रम के अंतर्गत जनवरी से मार्च, 1989 तक भारत में लगभग एक दर्जन विश्वविद्यालयों में परिषद यू०के० से ग्रीक दर्शन में एक प्रख्यात अध्येता प्रोफेसर रिचर्ड सोराबजी द्वारा व्याख्यानों की एक श्रृंखला का आयोजन कर रही हैं।

6.6.5 परिषद ने पाँच पुस्तकों तथा भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद की पत्रिका के तीन अंकों का प्रकाशन किया।

भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद

6.7.1 देश में सामाजिक विज्ञान अनुसधान को प्रौन्नत एवं समन्वित करने के लिए भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद की स्थापना वर्ष 1969 में की गई थी।

6.7.2 परिषद ने सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में अनुसंधान कर रहे अखिल भारतीय स्तर की अनुसंधान संस्थाओं और अपने छः क्षेत्रीय केन्द्रों को भी सहायता देना जारी रखा। आलोच्य वर्ष के दौरान दो नए अनुसंधान संस्थानों अर्थात् गुजरात इन्स्टीच्यूट आफ एरिया प्लानिंग, अहमदाबाद तथा इन्स्टीच्यूट फार इन्डुडियल डवलपमेंट (अस्थाई तौर पर नई दिल्ली में स्थापित) को समाज विज्ञान में संस्थानों को वित्तीय सहायता की इसकी योजना के अंतर्गत लाया गया जिससे ऐसी संस्थाओं कीं कुल संख्या 24 हो गई। सेमिनार, सम्मेलन, कार्यशालाएं और संगोष्ठियाँ आयोजित करने के लिए इकसठ संस्थाओं, व्यावसायिक समाज विज्ञान संगठनों, विश्वविद्यालयों को अनुदान दिए गए।

6.7.3 79 अनुसंधान परियोजनाओं को अनुदान संस्वीकृत किए गए। पहले से अनुमोदित 55 परियोजनाओं के संबंध में परिषद ने पूरी रिपोर्ट प्राप्त कीं। महिलाओं के अध्ययन पर अनुसंधान, सबके लिए स्वास्थ्य, सामाजिक विज्ञान में सिद्धांत परक और प्रणालीविज्ञान परक मुद्दे भारत में सामाजिक विधान पर विश्वकोश तैयार करने आदि जैसे विषयों पर कई प्रायोजित अनुसंधान कार्यक्रम प्रगति पर हैं।

6.7.4 परिषद ने सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में एक राष्ट्रीय शिक्षावृत्ति 15 वरिष्ठ अनुसंधान शिक्षावृत्तियाँ, सात सामान्य शिक्षावृत्तियाँ, एक प्रतिष्ठान दिवस शिक्षावृत्ति, 31 नियमित डाक्टरोल शिक्षावृत्तियां और 12 आकस्मिक अनुदान प्रदान किए और अनुसंधान प्रणाली विज्ञान में सात प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/कार्यशालाएं आयोजित कीं।

6.7.5 राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान प्रलेखन केन्द्र ने 180 शोध निबंधों और 165 अनुसंधान रिपोर्टों सहित 1500 प्रकाशन प्राप्त किए। 110 पी०एच०डी० अध्येताओं को अपने शोध कार्य हेतु सामग्री संचित करने के लिए पुस्तकालयों के दौरे करने हेतु अध्ययन अनुदान दिए गए। 24 ग्रन्थ विज्ञानीय और प्रलेखन परियोजनाओं के लिए भी वित्तीय सहायता दी गई। आंकड़ा अभिलेखों में 4 आंकड़ा सैट प्राप्त किए गए जिनकी पुनः प्रयोग की क्षमता है। 37 अध्येताओं को आंकड़ा संसाधन में मदद दी गई।

6.7.6 प्रकाशन अनुदान की योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए 65 शोध निबंधों और 16 अनुसंधान रिपोर्टों को अनुमोदित किया गया। वर्ष के दौरान विभिन्न विषयों पर पत्रों के तीस अंक निकाले गए। प्रकाशन अनुदान योजना के अंतर्गत तीस पुस्तकें प्रकाशित की गईं। अनुलिपिय अनुसंधान संसूचना श्रृंखला के अन्तर्गत चौबीस प्रकाशनों को प्रकाशित किया गया। भारत के समाज-वैज्ञानिकों के राष्ट्रीय

रजिस्टर के संकलन के लिए 2 हजार चार सौ अध्येताओं ने अपेक्षित सूचना भेजी जिसमें से 1800 प्रपत्रों का संसाधन किया गया।

6.7.7 प्रोफेसर वाई०के० अलग, सदस्य योजना आयोग की अध्यक्षता में देश के प्रमुख सात सामाजिक वैज्ञानिकों का एक दल ''आयोजना तथा आर्थिक विकास'' विषय पर सेमिनार मे भाग लेने हेतु सोवियत संघ गया। परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर एस० चक्रवर्ती की अध्यक्षता में समाज वैज्ञानिकों का एक आठ सदस्यीय शिष्टमण्डल समाज विज्ञान में इंडो-सोवियत संयुक्त आयोग की बैठक में भाग लेने के लिए सोवियत संघ गया। परिषद द्वारा आयोजित ग्रामीण विकास पर एक संयुक्त सेमिनार में भारत और चीन प्रत्येक से आठ-आठ अध्येताओं ने भाग लिया। इंडो-डच वैकल्पिक विकास संबंधी कार्यक्रम के लिए संयुक्त समिति ने कार्यक्रम के विभिन्न कार्यकलापों की समीक्षा की और इस कार्यक्रम के तीसरे चरण के लिए अनुसंधान प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के अंतर्गत दो चीनी अध्येताओं, एक डच अध्येता और दो फ्रांसीसी अध्येताओं के दौरे को परिषद ने प्रायोजित किया। परिषद ने छः भारतीय अध्येताओं को फ्रांस, 8 भारतीय अध्येताओं को नीदरलैंड तथा तीन भारतीय अध्येताओं को चीन के दौरे हेतु प्रायोजित किया।

अखिल भारतीय उच्च अध्ययन संस्थानों के लिए अनुदान योजना

6.8.0 इस योजना का उद्देश्य कुछ स्वैच्छिक संगठनों को सहायता देना है जो अखिल भारतीय स्तर पर कार्य कर रहे हैं और विश्वविद्यालय शिक्षा की परंपरागत पद्धति से हटकर शिक्षा के कार्यक्रम प्रदान कर रहे हैं जो विशेष रूप से ग्रामीण समुदायों की रुचि के हैं अथवा नवीन स्वरूप के हैं। वर्ष 1988-89 के दौरान निम्नलिखित संस्थाओं को इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की गई हैं:

- श्री अरबिन्दो अंतराष्ट्रीय शिक्षा केन्द्र, पांडिचेरी
- लोक भारती, सनोसरा
- श्री अरबिन्दो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान संस्थान, आरोविल।

द्विपक्षीय/विदेशी सहयोग

शास्त्री भारत-कनाडा संस्थान

6.9.1 शास्त्री भारत कनाडा संस्थान, कनाडा में संस्थापित एक स्वायत्त स्वैच्छिक संगठन है जिसने भारत सरकार के साथ एक सद्भावना ज्ञापन के अनुसरण में नवम्बर, 1968 में भारत में अपने कार्यकलाप शुरू किए। संस्थान का उद्देश्य अध्येताओं तथा छात्रों के बीच एक दूसरे देश के ज्ञान की प्रगति और सूझबूझ को प्रोत्साहित करने तथा सहायता देने के प्रयोजन के लिए कार्य करना है। भारत सरकार द्वारा इसके कार्यकलापों के संचालन के लिए अनुदान नई दिल्ली स्थित इसके शाखा कार्यालय को प्रदान किए जाते हैं।

6.9.2 वर्ष 1988-89 के दौरान संस्थान ने कनाडा के ग्यारह अध्येताओं को मानविकी में अनुसंधान शुरू करने और भारतीय भाषाएं सीखने के लिए तथा निष्पादन कलाओं के क्षेत्र में शिक्षावृत्तियाँ प्रदान कीं। विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत कनाडा का दौरा करने के लिए छः भारतीय अध्येताओं को भी संस्थान ने प्रायोजित किया।

भारतीय विश्वविद्यालयों आदि का दौरा करने वाले विदेशी अध्येताओं की अनुसंधान परियोजनाएं

6.9.3 भारत में अनुसंधान कार्य शुरू करने के लिए दौरा करने वाले विदेशी अध्येताओं के लिए प्रस्ताव विदेशी एजेंसियों अर्थात अमेरिकन इन्स्टीच्यूट, भारत में यूनाइटेड स्टेट्स एज्यूकेशनल फाउंडेशन, कैलीफोर्निया विश्वविद्यालय भारत में बारकले व्यावसायिक अध्ययन कार्यक्रम द्वारा प्रायोजित किए जाते हैं। इसके अलावा विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों, भारतीय संस्थाओं और भारतीय विश्वविद्यालय प्रणाली में सम्बद्ध अलग-अलग अध्येताओं से भी प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। वर्ष के दौरान ऐसे 182 प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया और 21 प्रस्तावों को रद्द कर दिया गया।

अन्य कार्यकलाप

विश्वविद्यालय और कालेजों के शिक्षकों के वेतनमानों में संशोधन की योजना।

6.10.1 विश्वविद्यालय और कालेजों के शिक्षकों के वेतनमानों में संशोधन की योजना की घोषणा 17 जून, 1987 को की गई। शिक्षकों/शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ आगे चर्चा के अनुसरण में इस

योजना में कुछ संशोधन/स्पष्टीकरण किए गए। संशाधित योजना को राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा 22 जुलाई, 1988 को संसूचित किया गया था।

6.10.2 इस संशोधित योजना में मुख्य संशोधन यह किया गया कि रीडरों के दो ग्रेडों को मिलाया गया है, लेक्चररों के लिए प्रवरण ग्रेड बनाया गया है जो कि रीडरों के संशोधित ग्रेड के बराबर हैं तथा कुलपति के लिए 7600/-रु० का नियत वेतन रखा गया है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि लेक्चररों की भर्ती के लिए अर्हक परीक्षा एजेंसियों के जरिए विभिन्न राज्यों/विश्वविद्यालयों द्वारा अनुसरण किए जा रहे शिक्षा के माध्यम की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आयोजित की जाएगी। इसी प्रकार स्नातकोत्तर अध्ययन की तत्काल समाप्ति के बाद अनुसंधान कार्यक्रमों में दाखिले को प्रोत्साहित करने के लिए अग्रिम वेतनवृद्धियों के लिए प्रावधान किया गया। तदनुसार जो उम्मीदवार एम०फिल० अथवा पी०एच०डी० डिग्रियों के लिए पात्र होंगे उन्हें उनकी भर्ती के समय क्रमश: एक और तीन अग्रिम वेतनवृद्धियाँ दी जाएंगी। पदोन्नति के प्रयोजन के लिए वे सेवा के तद्नुरूपी वर्षों के लाभ के हकदार होंगे। वर्तमान लेक्चररों और भविष्य में भर्ती किए गए वे लेक्चरर जिन्होंने अनुसंधान डिग्रियां नहीं ली हैं वे भी अनुसंधान डिग्रियां प्राप्त करने के बाद सेवारत लाभ के लिए पात्र होंगे। रीडर के पद के लिए प्रौन्नति और प्रवरण ग्रेड में तैनाती एक समिति द्वारा चयन प्रक्रिया द्वारा की जाएगी जिसका गठन विश्वविद्यालय द्वारा रीडरों की नियुक्ति के लिए किया गया है। दोनों मामलों में सतत शिक्षा कार्यक्रमों में सहभागिता और इसके साथ-साथ अच्छे निष्पादन संबंधी मूल्यांकन रिपोर्ट वृत्तिका में प्रगति के क्रम में अनिवार्य घटक हैं। लेक्चररों के सीनियर स्केल और सलेक्शन ग्रेड में नियुक्ति के साथ-साथ रीडरों के पदों पर प्रौन्नति के लिए संबंधित उम्मीदवारों द्वारा धारित पदों को स्तरोन्नत करके अपेक्षित संख्या में पदों का सृजन किया जाएगा।

पुस्तकाध्यक्षों और शारीरिक शिक्षा कार्मिकों के वेतनमानों का संशोधन

6.10.3 विश्वविद्यालय तथा कालेजों में पुस्तकाध्यक्षों तथा शारीरिक शिक्षा कार्मिकों के वेतनमानों में भी संशोधन किया गया है। उनके लिए भी, विश्वविद्यालयों तथा कालेज शिक्षकों के लिए अनुमोदित संशोधन वेतनमान के समान वेतनमान हैं। पुस्तकाध्यक्षों तथा शारीरिक शिक्षा कार्मिकों के संशोधित वेतनमानों के ब्यौरे पदनाम सहित निम्नलिखित हैं:-

पदनाम	**संशोधित वेतनमान**
(क) विश्वविद्यालय	
1. सहायक पुस्तकाध्यक्ष/ प्रलेखन अधिकारी शारीरिक शिक्षा के सहायक निदेशक	2200-75-2800-100-4000
2. सहायक पुस्तकाध्यक्ष/ प्रलेखन अधिकारी (वरिष्ठ वेतनमान) शारीरिक शिक्षा के सहायक निदेशक (वरिष्ठ वेतनमान)	3000-100-3500-125-5000
3. सहायक पुस्तकाध्यक्ष/ प्रलेखन अधिकारी (प्रवारण ग्रेड) शारीरिक शिक्षा के सहायक निदेशक (प्रवारण ग्रेड)	3700-125-4950-150-5700

4.	उप-पुस्तकाध्यक्ष शारीरिक शिक्षा के उप-निदेशक	3700-125-4950-150-5700
5.	पुस्तकाध्यक्ष शारीरिक शिक्षा के निदेशक	4500-150-5700-200-7300

	पदनाम	**संशोधित वेतनमान**
ख.	कालेज	
1.	कालेज पुस्तकाध्यक्ष शारीरिक शिक्षा के निदेशक	2200-75-2800-100-4000
2.	कालेज पुस्तकाध्यक्ष (वरिष्ठ वेतनमान) शारीरिक शिक्षा के निदेशक (वरिष्ठ वेतनमान)	3000-100-3500-200-5000
3.	कालेज पुस्तकाध्यक्ष (प्रवरण ग्रेड) शारीरिक शिक्षा के निदेशक (प्रवरण ग्रेड)	3700-125-4950-150-5700

विश्वविद्यालय शिक्षकों के लिए पुस्तकाध्यक्षों और शारीरिक शिक्षा कार्मिक को भी वृत्तिका में प्रगति योजना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा।

इस योजना का कार्यान्वयन

6.10.4 अधिकांश राज्यों ने इस योजना को स्वीकार करने की सूचना दे दी है। कुछ राज्यों ने अपने-अपने राज्यों के विश्वविद्यालयों और कालेजों में शिक्षकों, पुस्तकाध्यक्षों और शारीरिक शिक्षा कार्मिकों के संशोधित वेतनमानों के आदेश भी जारी कर दिए हैं। जिन राज्य सरकारों ने इस योजना को कार्यान्वित करने का निर्णय कर लिया है वे हैं : आन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। कुछ शेष राज्य सरकारें इस योजना पर विचार करने के लिए शिक्षा विभाग से अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण माँग रही हैं।

डा० जाकिर हुसैन स्मारक कालेज न्यास

6.11.1 डा० जाकिर हुसैन स्मारक कालेज न्यास की स्थापना 1973 में, डा० जाकिर हुसैन कालेज (पहले दिल्ली कालेज) के प्रबंध और रखरखाव का उत्तरदायित्व लेने के लिए की गई थी। कालेज जो दिल्ली विश्वविद्यालय का संघटक है, का रखरखाव व्यय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और न्यास द्वारा 95:5 के अनुपात में किया जाता है। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के लिए आयोग द्वारा निर्धारित सहायता की पद्धति के अनुसार विकास व्यय के रूप में कालेज के अनुदान संस्वीकृत करता है। इस प्रकार के विकास संबंधी व्यय के लिए बराबर का योगदान न्यास द्वारा वहन किया जाना अपेक्षित है। चूँकि न्यास के पास अपना कोई स्रोत नहीं है अतः उपर्युक्त व्यय वहन करने के लिए सरकार द्वारा अनुदान प्रदान किए जाते हैं। इन अनुदानों में न्यास का प्रशासनिक व्यय भी शामिल है।

6.11.2 न्यास द्वारा निर्णित प्रमुख कार्यक्रमों में से एक कालेज के वर्तमान परिसर को मिन्टो रोड क्षेत्र में स्थानान्तरित करना था। नए स्थान पर निर्माण कार्य के लिए अनुमोदित पाँच ब्लाकों में से 1986 में साइंस ब्लाक का कार्य पूरा हो गया तत्पश्चात् लेक्चर आरंभ हुआ। प्रशासनिक ब्लाक, लड़के और लड़कियों के लिए

कामन रूम और कैंटीन की इमारतों को क्रमश: दिसम्बर 1987 और जनवरी, 1988 में शुरू किया गया। कला और वाणिज्य खण्डों का निर्माण कार्य भी समापन पर है। पुस्कालय के विशाल ढाँचे के निर्माण का कार्य शीघ्र शुरू किया जाने वाला है। छात्रों और शिक्षकों के छात्रावास, प्राक्कलन, प्रिंसिपल और उप प्रिंसिपल और अन्य अनिवार्य स्टाफ के लिए रहने के क्वार्टर, व्यायामशाला और वनस्पति संग्रहालय के लिए योजना और प्राक्लन की डी०डी०ए० और विअ०आ० से स्पर्ष्टकरण की प्रतीक्षा है।

राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोफेसरशिप की योजना

6.12.0 राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोफेसरशिप की योजना 1949 में प्रतिष्ठित शिक्षाविदों तथा अध्येताओं को उनके अपने-अपने क्षेत्र में ज्ञान के योगदान को स्वीकारते हुए, सम्मानित करते हुए शुरू की गई थी। 1949 से 1965 के बीच 9 प्रतिष्ठित अध्येताओं को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। योजना को 1982 में एक विख्यात परीक्षा विज्ञानी डा० सलीम अली और प्रो०टी०एम०पी० महादेवन, दर्शनशास्त्र के एक प्रतिष्ठित प्रो० की नियुक्ति के साथ फिर से चालू किया गया था। इस समय चार राष्ट्रीय प्रोफेसर है। वे हैं: डा० वी०के०आर०वी० राव, अर्थशास्त्री; डा० (न्यायमूर्त) डी०डी० बसु; संविधान विशेषज्ञ, डा० सी०आर० राव, गणितज्ञ और डा० ए० एप्पोदोराई (राजनीतिक विज्ञानी)

भारतीय विश्वविद्यालय संघ

6.13.1 भारतीय विश्वविद्यालयों का संघ एक स्वैच्छिक संगठन है। विश्वविद्यालय इसके सदस्य हैं, और समान हित के मामलों पर विचारों का आदान-प्रदान करने तथा उन पर चर्चा करने के लिए एक साथ इकट्ठा होने के लिए विश्वविद्यालयों, प्रशासनों तथा शिक्षाविदों को यह एक मंच प्रदान करता है। संघ, उच्च शिक्षा में सूचना ब्यूरो के रूप में कार्य करता है और उच्च शिक्षा पर लाभप्रद प्रकाशन, शोध-पत्र, पुस्तकें और पत्र-पत्रिकाएं प्रकाशित करता है।

6.13.2 संघ का पर्याप्त रूप से वित्त पोषण सदस्य विश्वविद्यालयों द्वारा दिए गए वार्षिक चन्दे से होता है। सरकार उच्च शिक्षा के महत्वपूर्ण मामलों में अनुसंधन/अध्ययनों के लिए संघ को अनुदान प्रदान करती है। सरकार की सहायता से स्थापित अनुसंधान सैल द्वारा आरंभ किए गए कार्यकलापों सहित इसके अनुरक्षण व्यय के एक भाग को वहन करने के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अनुसंधान सैल ने दूरस्थ शिक्षा की अर्थ-व्यवस्था, विश्वविद्यालय क्षेत्र में विज्ञान तथा प्रौद्योगिक का सर्वेक्षण, जन-शक्ति विश्वविद्यालय उद्योग अन्त: क्रिया, भारत में स्नातक बेरोजगारी और विश्वविद्यालय क्षेत्र में योजनेत्तर व्यय का वित्त पोषण संबंधी विषयों पर अध्ययन आरंभ किया है। परीक्षा-सुधार के क्षेत्र में प्रश्न बैंक पर अध्ययन प्रारंभ किए गए हैं। प्रश्न बैंक पर बहुत सी पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं। वर्तमान में (क) विश्वविद्यालय उद्योग अन्त: क्रिया, (ख) सुदूर शिक्षा और (ग) प्रश्न बैंक पर अनुसंधान अध्ययन प्रगति पर है।

पंजाब विश्वविद्यालय

6.14.0 पंजाब राज्य के पुनर्गठन के साथ पंजाब विश्वविद्यालय को पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत अंतर राज्य निगमित निकाय घोषित किया गया था। विश्वविद्यालय का अनुरक्षण व्यय इस समय पंजाब सरकार तथा चण्डीगढ़ के संघ शासित क्षेत्र प्रशासन द्वारा 40:60 के अनुपात में बांटा जा रहा है। विश्वविद्यालय का विकास संबंधी व्यय मुख्य रूप से वि०अनु०आ० द्वारा संस्वीकृत किए गए अनुदानों में से वहन किया जा रहा है जो आयोग की मार्गदर्शी रूपरेखाओं के अनुसार विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए अनुदान प्रदान करता है। तथापि, विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संस्वीकृत किए गए विकास अनुदानों के लिए बराबर के हिस्से उपलब्ध कराने हैं और कई परियोजनाएं और कार्यक्रम जो वि०आ०आ० की योजनाओं में शामिल नहीं हुए है उनका भी वित्त पोषण करना है। इन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार विश्वविद्यालय को वार्षिक ऋण संस्वीकृत कर रही है। वर्ष 1988-89 के दौरान विश्वविद्यालय को अपने विकास कार्यक्रमों के लिए 50 लाख रुपए संस्वीकृत किए गए हैं।

नौकरियों से डिग्रियों को अलग करना—राष्ट्रीय परीक्षण सेवा की स्थापना

6.15.1 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में राष्ट्रीय परीक्षण सेवा की स्थापना की परिकल्पना की गई है जिससे कि उन नौकरियों में भर्ती के लिए विश्वविद्यालय डिग्री को अलग करने की प्रक्रिया को आसानी से लागू किया जा सके जिनके लिए

विश्वविद्यालय डिग्री का एक आवश्यक योग्यता होना जरूरी न हो।

6.15.2 जब राष्ट्रीय परीक्षण सेवा की स्थापना की जाएगी तो यह स्वैच्छिक आधार पर परीक्षाएं आयोजित करेगी ताकि उन विशिष्ट (क) नौकरियों के लिए उम्मीदवारों की उपयुक्तता को निर्धारित और प्रमाणित किया जा सके जिनके लिए डिप्लोमा अथवा डिग्री की योग्यता की जरूरत नहीं होती (ख) जो उम्मीदवार स्वेच्छा से परीक्षाएं देना चाहेंगे उनके लिए परीक्षण उपलब्ध कराना (और जो विशिष्ट नौकरियों/सेवाओं के लिए अर्हक और प्रमाणित कर दिए जाएंगे वे किसी अन्य योग्यता पर जोर दिए बिना ही ऐसी नौकरियों/सेवाओं पर नियुक्ति के लिए पात्र होंगे); (ग) विस्तृत नौकरी विवेचन, नौकरी विश्लेषण आदि के आधार पर परीक्षणों की एक श्रृंखला तैयार करेगी ताकि निर्धारित नौकरियों के प्रयोजनार्थ आवश्यक अभिरूचि, दक्षता कौशलों, ज्ञान की अपेक्षाओं का पता लगाया जा सके और (घ) परीक्षण विकास, परीक्षण प्रशासन परीक्षा में अंक प्राप्त करना, कम्प्यूटर प्रणाली के अनुप्रयोग और आप्शनल मार्करीडर आदि में राष्ट्रीय स्तर पर यह सुसज्जित संसाधन केन्द्र के रूप में कार्य करेगी।

6.15.3 उक्त लक्ष्यों के साथ सरकार ने सिद्धांत रूप में, राष्ट्रीय परीक्षण सेवा की स्थापना के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। राष्ट्रीय परीक्षण सेवा की स्थापना सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में की जा रही हैं। संगम ज्ञापन और नियमों की अंतिम रूप दे दिया गया है। आम परिषद और शासी निकाय के गठन और अध्यक्ष तथा निदेशक की नियुक्ति की अंतिम रूप दिया जाने वाला है। जैसे ही इन ब्यौरों को अंतिम रूप दे दिया जाएगा, रा०पं०सं० को पंजीकृत कर दिया जाएगा। वित्तीय वर्ष 1989-90 के शुरू हाने से पूर्व यह चालू हो जाएगी।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विशेष सैल

6.16.1 यह सैल कालेज और विश्वविद्यालयों में प्रवेश और नियुक्ति में आरक्षण के संबंध में नीति की समीक्षा करने के लिए उत्तरदायी है। यह सैल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयोग और संसद को आरक्षण के संबंध में सूचना देने के लिए संपर्क एकक के रूप में कार्य करता है। सैल ने कालेज तथा विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति शिक्षकों/छात्रों/कर्मचारियों से प्राप्त अभ्यावेदनों की जाँच की तथा जहाँ कहीं आवश्यक था उन्हें संबंधित प्राधिकारियों के साथ उठाया गया।

6.16.2 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण संबंधी संसदीय समिति ने वि०अनु०आयोग और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अनु०ज/जन जाति के कर्मचारियों के लिए आरक्षण एवं उनके रोजगार के लिए तथा अनु०जा०/अनु०ज०जा० के छात्रों को प्रवेश और अन्य सुविधाएं प्रदान किए जाने की जाँच की और वर्ष 1988 में संसद के समक्ष अपनी 38वीं रिपोर्ट पेश की। सैल ने वि०अनु०आयोग, केन्द्रीय विद्यालयों आदि के साथ परामर्श से संसदीय समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर की गई कार्रवाई का विवरण लोकसभा सचिवालय को प्रस्तुत किया।

ग्रामीण संस्थाएं

16.17.0 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में शिक्षा के बारे में गाँधी जी के विचारों के आधार पर ग्रामीण संस्थाओं/विश्वविद्यालयों की स्थापना की परिकल्पना की गई है। ग्रामीण संस्थाओं के विकास के सुसमन्वित कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए एक स्वायत्त पंजीकृत निकाय के रूप में एक केन्द्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद की स्थापना करने का प्रस्ताव है जो सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वित्त पोषित होगी। ग्रामीण संस्थाओं के माध्यम से नई शिक्षा पद्धति सामाजिक रूप से लाभप्रद उत्पाद कार्य और शैक्षिक कार्यकलापों के बीच सहसंबंध की संकल्पना पर आधारित होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तन के लिए ग्रामीण संस्थाएं विस्तार कार्यकलापों को अपनाएंगी। प्रस्तावित केन्द्रीय परिषद गाँधी जी की बुनियादी शिक्षा में संलग्न उन ग्रामीण संस्थानों और अन्य एजेंसियों का पता लगाएंगी जिनकी विकास की क्षमता है और जो मुख्यत: ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ही हैं। परन्तु वर्षों से जिन्हें पर्याप्त सहायता और प्रोत्साहन नहीं मिला। अगले कुछ वर्षों में नए संस्थान खोलने की बजाय विद्यमान कार्यशील कार्यक्रमों और संस्थानों के समेकन विस्तार और उन्हें सहायता देने पर मुख्य बल दिया जाएगा।

राष्ट्रीय उच्च शिक्षा परिषद

6.18.0 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में उच्च शिक्षा नीति के समन्वय के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक शीर्ष

निकाय स्थापित करने की परिकल्पना की गई है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ नीति के बेहतर समन्वय और उसमें निरंतर तादात्म्य बनाए रखने के लिए कृषि, चिकित्सा, तकनीकी और कानूनी क्षेत्र शामिल होंगे। संबधित विभागों और एजेंसियों से विस्तार से विचार-विमर्श करने के पश्चात् राष्ट्रीय उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना करने से संबंधित प्रारूप प्रस्ताव तैयार कर लिए गए हैं। इन प्रस्तावों को टिप्पणियों/सहमति के लिए संबंधित मंत्रालयों और विभागों को भेजा गया था। उनमें से कुछ ने इन प्रस्तावों पर शंकाएं व्यक्त की हैं। इन बातों को दृष्टिगत रखते हुए पूरे प्रस्ताव की समीक्षा की जा रही है।

तकनीकी शिक्षा

7.1.1 तकनीकी शिक्षा मानव संसाधन विकास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटकों में से एक हैं जिसमें उत्पादों तथा सेवाओं का महत्व बढ़ाने, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान देने और लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने की अधिक सम्भावना दिखाई देती है। इस क्षेत्र के महत्व को पहचानते हुये क्रमिक पंचवर्षीय योजनाओं में तकनीकी शिक्षा के विकास पर अधिक बल दिया गया।

7.1.2 पिछले चार दशकों के दौरान, देश में तकनीकी शिक्षा सुविधाओं का असाधारण विस्तार हुआ है जैसा कि आगे दिए गए ग्राफों से स्पष्ट हो जाता है तथापि इसके कार्यक्षेत्र को बढ़ाने तथा विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों तक इसकी पहुंच बढ़ाने एवं इसकी उत्पादकता में और सुधार करने के लिए तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में अभी और बहुत कुछ प्राप्त करना बाकी है। इसके अतिरिक्त सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सदी बदलने के साथ-साथ परिवर्तनशील परिस्थितियों पर विचार करने की आवश्यकता है ताकि तकनीकी शिक्षा प्रणाली अपनी भूमिका और अधिक प्रासंगिक रूप से तथा उद्देश्यपूर्ण ढंग से निभा सके। इन्हीं विचारों पर आधारित राष्ट्रीय शिक्षा नीति और कार्रवाई योजना में, तकनीकी शिक्षा प्रणाली में और सुधार करने के लिए अनेक नये उपायों का यथोचित उल्लेख किया गया है। इनमें आधुनिकीकरण तथा अप्रचलित सामग्री को हटाना, संस्थागत-उद्योग में परस्पर तालमेल को प्रौन्नत करना, पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों की पुन: संरचना करना, उद्यमता विकास, महिलाओं की तकनीकी शिक्षा को प्रौन्नत करना, तकनीकी शिक्षा को विकास क्षेत्रों के साथ जोड़ना और ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का अनु-प्रयोग शामिल है।

7.1.3 आलोच्य वर्ष के दौरान तकनीकी शिक्षा क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण कार्य किये गये। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आधारित कई कार्यक्रमों और योजनाओं के कार्यान्वयन के क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति हुई। सांविधिक अधिकार प्राप्त अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने उसे सौंपे गये कार्यों को पूरा करने के लिए अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। सांविधिक अधिकार प्राप्त अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की पहली बैठक 6 जुलाई, 1988 को हुई। पाठ्यक्रमों और संस्थाओं के लिए नियम, मापदण्ड और स्तर, शुल्क, प्रवेश-दिशानिर्देश, संस्थाओं और पाठ्यक्रम के निष्पादन-मूल्यांकन के लिए प्रत्यायन का विवरण, राज्य-निदेशालयों के लिए माडल, और राज्यों तथा केन्द्रीय संस्थाओं की परिप्रेक्ष्य योजनाओं और कार्रवाई योजनाओं को सूत्रबद्ध किया गया। नई संस्थाओं/पाठ्यक्रमों को शुरू करने के लिए कई प्रस्तावों की जांच की गई और उसमें से 70 को स्वीकार किया गया।

7.2.0 इस वर्ष के दौरान, तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों तथा उनकी प्रगति का संक्षिप्त सारांश नीचे दिया गया है :—

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान

7.2.1 अवर-स्नातक स्तर पर इंजीनियरी तथा प्रयुक्त विज्ञान में शिक्षा तथा प्रशिक्षण के प्रमुख केन्द्रों के रूप में और स्नातकोत्तर अध्ययन तथा अनुसंधान के लिए पर्याप्त सुविधायें प्रदान करने के लिए खड़गपुर, बम्बई, मद्रास, कानपुर तथा दिल्ली में पांच भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किये गये थे। ये राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं।

7.2.2 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री (बी.टेक.) प्राप्त करने के लिए चार वर्षीय अवर-स्नातक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। वे भौतिकी, रसायन शास्त्र तथा गणित में पांच वर्ष की अवधि के समेकित मास्टर डिग्री पाठ्यक्रम विभिन्न विशेषज्ञताओं में डेढ़ वर्ष के एम. टेक. डिग्री पाठ्यक्रम और चुनिन्दा क्षेत्रों में एक वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त ये संस्थान इंजीनियरी, विज्ञान, मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में पी.एच.डी. कार्यक्रम प्रदान करते हैं। विशेषज्ञता के ज्ञात क्षेत्रों में प्रत्येक संस्थान में प्रशिक्षण तथा अनुसंधान के उन्नत केन्द्र भी है।

7.2.3 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों ने प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के मामले में बड़े योगदान दिये हैं। अनेक उद्योगों को या तो प्रायोजन द्वारा अथवा अपनी ओर से इन संस्थानों द्वारा किये गये अनुसंधान कार्य से लाभ पहुंचा है। इन वर्षों में उन्होंने पेटेन्ट को विकसित करने और उद्योग द्वारा उनका उपयोग करने में भी सफलता प्राप्त की है। प्रायोजित अनुसंधान परियोजनाओं और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों तथा उनके संकाय द्वारा शुरू किये परामर्शी कार्य द्वारा संस्थानों को प्रत्येक वर्ष पर्याप्त राजस्व प्राप्त होता है।

7.2.4 देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों द्वारा दिया गया अन्य महत्वपूर्ण योगदान अन्य इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी संस्थानों के लाभ के लिए पाठ्यचर्याओं आदि के विकास में उनके द्वारा दी गई सहायता है।

7.2.5 इन संस्थाओं को अपने स्नातकों पर नाज़ है—क्योंकि पास होकर निकलने पर वे उच्च स्तरीय क्षमता, मूल्यों और परिपक्वता का परिचय देते हैं। सर्वाधिक होनहार छात्रों का चयन तथा प्रशिक्षण की अति उच्च कोटि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पद्धति की शक्तियां हैं जो कि उत्कृष्टता के लक्ष्य से प्रतिबद्ध है। आलोच्य वर्ष के दौरान, इन संस्थानों ने अप्रचलित उपस्करों के प्रतिस्थापन तथा प्रयोगशालाओं को आधुनिक बनाने की प्रक्रिया को इस प्रयोजन के लिए प्रदान की गई निधियों की सहायता से जारी रखा।

7.2.6 इन संस्थानों ने क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों को संस्थागत नेटवर्क योजना के अंतर्गत उनकी प्रयोगशालाओं तथा संकाय के विकास में सहायता करना भी जारी रखा।

7.2.7 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के छात्रों के प्रवेश को सुधारने के लिए 10 महीने की अवधि का एक विशेष तैयारी पाठ्यक्रम जारी रखा गया। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उन छात्रों को, जो भारतीय प्रौद्योगिक संस्थानों में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं परन्तु एक न्यूनतम अंक प्रतिशतता प्राप्त कर लेते हैं इस तैयारी पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाता है। तैयारी पाठ्यक्रम की समाप्ति पर, इन छात्रों को एक अर्हक परीक्षा देनी होती है जिसके आधार पर पुनः संयुक्त प्रवेश परीक्षा में बैठे बिना बी.टेक. कार्यक्रम में प्रवेश प्रदान कर दिया जाता है। इससे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में अनु. जाति/अनु. जनजाति के छात्रों के प्रवेश की स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ है। अनु. जाति/अनु. जन जाति के छात्रों को इन संस्थानों से निःशुल्क भोजन के अतिरिक्त जेब खर्च, ऋण तथा विवेकाधीन अनुदानों के रूप में वित्तीय सहायता भी प्राप्त होती रही।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान	दाखिला अवर स्नातक/स्नातकोत्तर+ अनुसंधान	छात्र-संख्या अवर-स्नातक/स्नातकोत्तर+ अनुसंधान	उत्तीर्ण अवर-स्नातक/स्नातकोत्तर+ अनुसंधान
दिल्ली	277/799	1054/1654	209/439
मद्रास	267/493	1067/1281	247/481
कानपुर	268/295	1070/893	220/261
बम्बई	326/606	1249/1364	268/404
खड़गपुर	364/504	1477/1094	378/442

7.2.8 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में दिए गये दिशानिर्देशों को कार्यान्वित करने के लिए प्रत्येक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने, अपनी-अपनी कार्रवाई योजना तैयार की है। जैसा कि योजना आयोग ने इच्छा प्रकट की है, इन संस्थानों ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विशिष्ट क्षेत्रें के विकास के लिए दृष्टिकोण दस्तावेज़ भी तैयार किए हैं। आगे विकास में अवस्थापना सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने पर बल दिया जाएगा जिनमें अतिरिक्त छात्रावासों और कर्मचारियों के क्वार्टरों के निर्माण, प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण, उभरते हुये महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नए पाठ्यक्रमों का आरम्भ, अप्रचलित उपस्कर को हटाना, गुणवत्ता सुधार, कर्मचारियों और संकाय विकास आदि के लिए नये कार्यक्रमों को शुरू करना भी शामिल हैं।

7.2.9 उच्च अधिकार प्राप्त समीक्षा समिति, जिसने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के कार्यचालन और कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन किया था, ने अपनी रिपोर्ट, फरवरी 1987 में प्रस्तुत कर दी थी। यथेष्ट विचार और संवीक्षा करने के पश्चात् बहुत सी सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में भेजा गया है। अन्य सिफारिशों पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान परिषद् और अधिकृत समिति द्वारा विचार किया जा रहा है। सिफारिशों के कार्यान्वयन की मानीटरिंग भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान परिषद् द्वारा की जायेगी।

1988-89 में पांच भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के लिए बजट प्रावधान 91 करोड़ रुपये था।

7.2.10 'असम समझौता' के अंतर्गत, सरकार असम में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने के लिए सहमत हो गई थी। यह संस्थान देश में छठा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान होगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए स्थान नौगांव जिले में मिसा में चुना गया है। इस संस्थान का विस्तार केन्द्र गुवाहटी में होगा। राज्य सरकार द्वारा दोनों स्थानों पर भूमि-अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू हो गई है। विशेषज्ञ परियोजना टीम ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की है। जिसे अब अन्तिम रूप दिया जा रहा है। 1989-89 में इस योजना के लिए बजट प्रावधान 400 लाख रुपये था।

भारतीय प्रबन्ध संस्थान :

7.3.1 प्रबन्ध के क्षेत्र में कार्मिकों के प्रशिक्षण हेतु सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तथा इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में अनुसंधान आयोजित करने और ज्ञान-वृद्धि में योगदान करने के लिए कलकत्ता, अहमदाबाद, बंगलौर और लखनऊ में क्रमशः 1961, 1962, 1972 और 1984 में यह चार भारतीय प्रबन्ध संस्थान स्थापित किये गये। ये संस्थान प्रबन्ध में स्नातकोत्तर तथा फैलोशिप कार्यक्रम आयोजित करते हैं और इसके साथ-साथ उद्योगों में प्रबन्धकों के लिए कार्यपालक विकास कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं। वे कार्मिकों के लिए सेवाकालीन कार्यक्रम भी संचालित करते है। वर्ष के दौरान, संस्थानों ने अनेक व्यवस्थापन कार्यक्रम संचालित किये और बड़ी संख्या में परामर्श परियोजनाएं भी प्रारम्भ कीं।

7.3.2 लखनऊ में नये संस्थान ने अपना पहला शैक्षिक सत्र जुलाई, 1985 में शुरू किया। यह विकास के चरण में हैं। संस्थान ने अपने स्थायी स्थल का कब्जा ले लिया है जहां सिविल निर्माण-कार्य को रहा है।

राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान (रा. औ. ई. प. स.)

7.4.0 राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, बम्बई की स्थापना औद्योगिक इंजीनियरी तथा संबद्ध क्षेत्रों में प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं प्रदान करने हेतु संयुक्त-राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से एक स्वायत्त निकाय के रूप में 1963 में की गई थी। संस्थान औद्योगिक इंजीनियरी में स्नातकोत्तर कार्यक्रम, एम. टेक के समकक्ष औद्योगिक इंजीनियरी में (अनुसंधान द्वारा) स्नातकोत्तर डिप्लोमा और पी.एच-डी. के समकक्ष औद्योगिक इंजननियरी में फैलोशिप कार्यक्रम प्रदान करता है। यह औद्योगिक इंजीनियरी तथा प्रबन्ध तकनीकों के क्षेत्रों में विविध अल्पकालीन कार्यपालक विकास कार्यक्रम आयोजित करता है। संस्थान, संचालन अनुसंधान, सूचना पद्धतियों, कार्य पद्धति डिज़ाइन संगणक और उनके प्रयोग, औद्योगिक सम्बंध, कार्य-मूल्यांकन, आपद-विश्लेषण और प्रबन्ध से संबंधित अन्य क्षेत्रों में अनुसंधान तथा परामर्शदात्री सेवाएं सक्रिय रूप से प्रदान करने में लगा हुआ है। संस्थान ने हैदराबाद के और उसके आस-पास उद्योगों और संगठनों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, हैदराबाद में एक विस्तार केन्द्र की स्थापना की है।

राष्ट्रीय ढलाई और गढ़ाई प्रौद्योगिकी संस्थान

7.5.1 रांची स्थित यह संस्थान ढलाई तथा गढ़ाई प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण तथा अनुसंधान के लिए एक शिखर संस्था के रूप में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम-यूनेस्को के सहयोग से वर्ष 1966 के दौरान स्थापित किया गया था। यह भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित एक स्वायत्त संस्था है। संस्थान के उद्देश्य हैं :—

- उच्च डिप्लोमा पाठ्यक्रमों, पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों, एम. टेक. पाठ्यक्रमों के जरिए प्रशिक्षण प्रदान करना और उद्योग द्वारा अपेक्षित यूनिट-आधारित कार्यक्रम संचालित रना।
- गढ़ाई और ढलाई प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त अनुसंधान में मार्गदर्शन करना तथा संचालन करना, और

तकनीकी शिक्षा की प्रगति

इंजीनियरी और तकनीकी कालेज (डिग्री और उससे उच्च स्तर)					
संस्थाओं की संख्या	33	78	107	120	225
नामांकन (हजारों में)	17	48	93	130	182
इंजीनियरी और प्रौद्योगिकीय कालेज (डिग्री स्तर से कम)					
संस्थाओं की संख्या	78	130	631	885	1075
नामांकन (हजारों में)	38	84	133	331	303*

* 1983-84 से सम्बन्धित

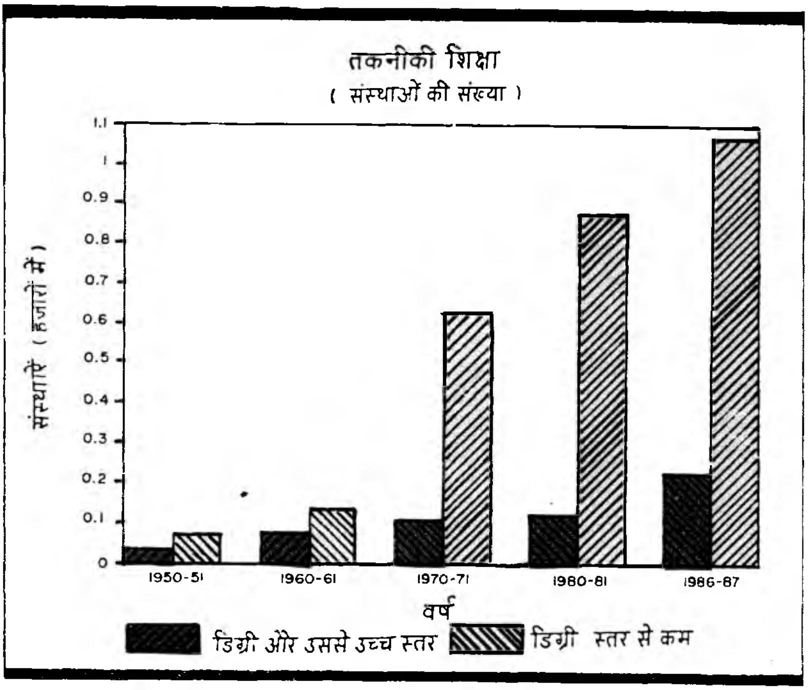

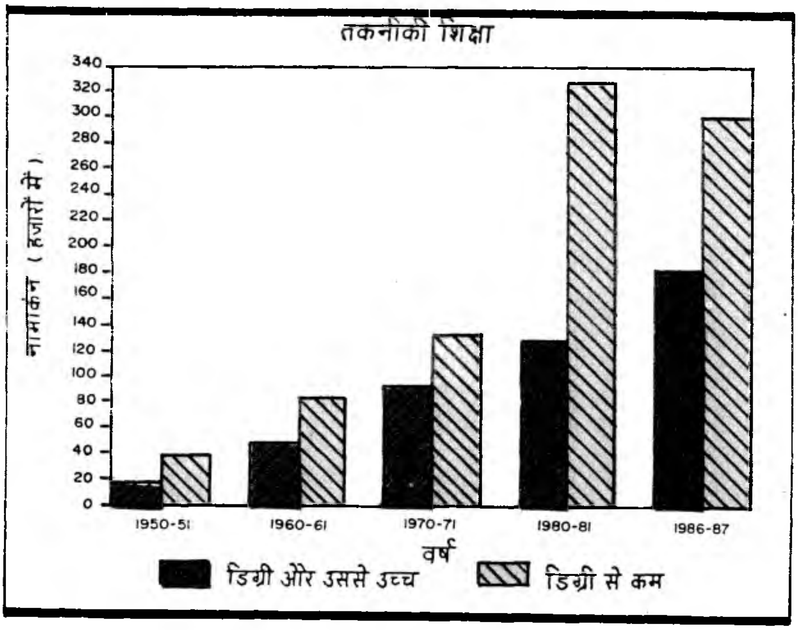

– ढलाई, गढ़ाई और सम्बद्ध उद्योगों को परामर्शी परीक्षण, प्रलेखन और सूचना-सेवाएं प्रदान करना।

7.5.2 संस्थान ने ढलाई तथा गढ़ाई प्रौद्योगिकी में अपना 15वां उच्च डिप्लोमा पाठ्यक्रम सितम्बर, 1987 में आरम्भ किया था जिसमें कुल 54 छात्र थे। एम. टेक. का तीसरा बैच अगस्त 1987 में आरम्भ किया गया था, जिसमें कुल 13 छात्र थे। वर्ष 1987-88 के दौरान, संस्थान ने 9 पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित किए जिसमें 72 प्रायोजित प्रत्याशियों ने भाग लिया। संकाय सदस्यों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों/संगोष्ठियों /सम्मेलनों में भाग लिया और उन्होंने 16 तकनीकी पेपर प्रस्तुत किये ओर प्रकाशित किये। संस्थान ने कई एजेन्सियों के साथ तालमेल स्थापित किया तथा अनुसंधान एवं परामर्शी परियोजनाएं भी बड़ी मात्रा में आरम्भ कीं।

7.5.3 संस्थान ने होरीज़न – 3,32 बिट विभिन्न परिधियों के साथ 2 आर. ए. एम. पद्धति सहित एक संगणक केन्द्र की भी स्थापना की। नवीनतर पद्धतियों के निकट भविष्य में प्राप्त कर लिए जाने की सम्भावना है। वर्ष 1988-89 के दौरान संस्थान का बजट-प्रावधान 180.00 लाख रुपये था।

आयोजना तथा वास्तुकला स्कूल।

7.6.1 नई दिल्ली स्थित इस स्कूल की स्थापना 1955 में मानव बस्तियों और पर्यावरण से संबंधित क्षेत्रों में प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक अग्रगामी संस्था के रूप में की गई थी। यह एक स्वायत्त संस्था है और भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित है। इस स्कूल को वर्ष 1979 में "समझा जाने वाला विश्वविद्यालय" का दर्जा दिया गया था ताकि यह अपने शैक्षिक कार्यक्रमों के क्षेत्रों को विस्तृत कर सके, अनुसंधान तथा विस्तार कार्यक्रमों को और अधिक बढ़ावा दे सके और अपनी ही अवर-स्नातक, स्नातकोत्तर तथा डाक्टोरल उपाधियां प्रदान कर सकें।

7.6.2 यह स्कूल वास्तुकला में स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम आयोजित करता है जिसमें दो पारियों में वार्षिक संस्वीकृत प्रवेश क्षमता 68 है। यह स्कूल आयोजना (शहरी तथा क्षेत्रीय आयोजना, परिवहन आयोजना और आवास में विशिष्टता के साथ), वास्तुकला (शहरी डिज़ाइन तथा वास्तुशिल्पीय-संरक्षण-में विशिष्टताओं के साथ), भवन इंजीनियरी और प्रबन्ध तथा भूदृश्य वास्तुकला में निष्पात डिग्री पाठ्यक्रम भी संचालित करता है। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की कुल प्रवेश क्षमता 110 है। संस्थान पी. एच. डी. कार्यक्रम भी संचालित करता है जिसकी प्रवेश क्षमता 10 है। अन्तर-विषय अनुसंधान तथा विस्तार कायक्रमों को बढ़ावा देने तथा उन्हें समन्वित करने के उद्देश्य से, स्कूल ने पहले से ही अध्यापन विभागों के संसाधन केन्द्र के रूप में कार्य कर रहे विद्यमान ग्रामीण विकास और पर्यावरणीय अध्ययनों के केन्द्रों के अतिरिक्त एक संरक्षण अध्ययन केन्द्र तथा विश्लेषण और पद्धति अध्ययन केन्द्र की स्थापना की है। विश्लेषण और पद्धति अध्ययन केन्द्र में, संगणक सहायतायुक्त डिज़ाइन के लिए उन्नत सुविधाओं के साथ एक अपोलो डी. एन. 560 संगणक स्थापित किया गया है।

7.6.3 आलोच्य वर्ष के दौरान, स्कूल के महारानी बाग परिसर में एक छात्रावास, एक अतिथि-गृह और 71 कर्मचारियों के क्वार्टरों का स्थानीय निर्माण कार्य आरम्भ किया गया। इस स्कूल ने कई अध्ययन गोष्ठियां, कार्यशालाएं और अल्पकालीन पाठ्यक्रमों का आयोजन किया और बहुत सी अनुसंधान और परामर्शदात्री परियोजनाएं भी आरम्भ कीं।

तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाए

7.7.0 पोलिटेक्निक शिक्षकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण देने तथा पालिटेक्निक शिक्षा के समग्र सुधार के लिए कई कार्यकलाप आरम्भ करने के लिए भी सातवें दशक के मध्य में चार तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएं भोपाल, कलकत्ता, चण्डीगढ़ और मद्रास में आयोजित की गई थी। ये संस्थाएं शिक्षकों को पाठ्यचर्या विकास और संबद्ध कार्यकलापों से अवगत कराने के लिए अल्पकालिक प्रशिक्षण देने के अतिरिक्त पालिटेक्निकों के डिग्री और डिप्लोमाधारी शिक्षकों को 12 माह/18 माह की अवधि के दीर्घकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करती है। मद्रास और भोपाल स्थित पालिटेक्निक अब तकनीकी अध्यापन में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रदान करने के स्तर तक पहुंच गए हैं। शिक्षक प्रशिक्षण के अतिरिक्त, ये संस्थाएं संसाधन विकास, विस्तार कार्य, परामर्शदात्री और परियोजनाएं बनाने जैसे कार्यकलाप भी आयोजित करती है। ये संस्थाएं यू. एन. डी. पी. परियोजना के अंतर्गत शैक्षिक फिल्म-निर्माण, राष्ट्रीय परीक्षण सेवाओं, शैक्षिक पैकेजों आदि को तैयार करने में गहरी रुचि ले रही हैं।

आलोच्य वर्ष के दौरान, इन संस्थाओं ने अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले कई क्षेत्रों में अपने कार्यकलापों को जारी रखा और पालिटेक्निक शिक्षा के आगे विकास के लिए महत्वपूर्ण रूप से योगदान दिया।

अंतराष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा केन्द्र

7.8.0 अंतराष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी केन्द्र की स्थापना 1986 में, देश में विद्यमान संस्थाओं के नेटवर्क के माध्यम से कार्य करने तथा एक संसाधन केन्द्र और सहयोगी अनुसंधान केन्द्र के रूप में कार्य करने के लिये की गई थी। यह अंतराष्ट्रीय केन्द्र विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान कार्यक्रमों को भी समन्वित करेगा जिसके लिए देश में थोड़े से प्रयास किये गये हैं जबकि कई संस्थाएं इस कार्यकलाप में लगी हुई हैं। यह केन्द्र विकासशील देशों की आवश्यकताओं को भी पूरा करेगा और यूनेस्कों तथा यू. एन. डी. पी. जैसी अंतराष्ट्रीय एजेन्सियों से इसे अपने कार्यक्रमों के लिए सहायता मिलने की सम्भावना हैं। यह केन्द्र एक स्वायत्त संस्था है और यह भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त-पोषित है।

गैर-विश्वविद्यालय केन्द्रों में प्रबंध शिक्षा

7.9.0 इस कार्यक्रम के अंतर्गत उन चुनिन्दा गैर-सरकारी विश्वविद्यालय केन्द्रों को सहायता प्रदान की जाती है जो अखिल भारतीय स्तर पर कार्य कर रहे हैं और प्रबन्ध अध्ययन में 2 वर्षीय पूर्णकालिक और 3 वर्षीय अंशकालिक स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रदान कर रहे हैं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के अखिल भारतीय प्रबन्ध अध्ययन बोर्ड की सिफारिशों पर सहायता प्रदान की जाती है।

क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज

7.10.1 दूसरी तथा तीसरी योजना अवधियों के दौरान प्रत्येक प्रमुख राज्य में एक-एक करके चौदह क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों की स्थापना की गई थी ताकि देश आगामी उत्तरवर्ती योजना अवधियों के दौरान प्रशिक्षित कार्मिकों के लिए बढ़ती हुई आवश्यकता को पूरा कर सके। सिल्चर (असम) स्थित पन्द्रहवें क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज ने नवम्बर, 1977 में कार्य करना आरम्भ किया तथा सोलहवां क्षे. ई. कालेज, जो हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में स्थापित किया गया था, ने जुलाई, 1986 में कार्य करना आरम्भ किया। पंजाब के जालन्धर में एक और क्षे. ई. का. स्थापित किये जाने की अनुमति दे दी गई है और आशा है कि यह 1989-90 के शैक्षिक सत्र से आगे कार्य करना आरम्भ कर देगा

7.10.2 जबकि सभी क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज (हमीरपुर के क्षे. ई. का. को छोड़कर) सिविल इंजीनियरी, यान्त्रिक इंजीनियरी, विद्युत इंजीनियरी में प्रथम डिग्री पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं, उनमें से बहुत से क्षे. ई. का. रसायन इंजीनियरी, धातुकर्मीय इंजीनियरी, इलैक्ट्रानिक्स उत्पादन इंजीनियरी, खनन इंजीनियरी, वास्तुकला तथा संगणक विज्ञान में प्रथम डिग्री पाठ्यक्रम भी प्रदान करते है। हमीरपुर स्थित क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज में इस समय सिविल तथा इलैक्ट्रिकल इंजीनियरी तथा इलैक्ट्रानिक्स में प्रथम डिग्री पाठ्यक्रम की व्यवस्था है। चौदह क्षे. ई. कालेज स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों का भी संचालन करते हैं। इनमें नौ कालेज उच्च दाब के बायलरों और अन्य सहायक उपकरणों का डिज़ाइन और निर्माण, इस्पात संयंत्रों के लिए भारी मशीनों, परिवहन इंजीनियरी, औद्योगिक तथा समुद्रीय संरचनाओं, समेकित ऊर्जा पद्धतियों आदि जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में उद्योगोन्मुख पाठ्यक्रमों का भी संचालन कर रहे हैं।

7.10.3 आलोच्य वर्ष के दौरान शैक्षिक कार्यक्रमों की विविधता एवं विस्तार, बेकार उपस्करों को बदलने सहित प्रयोगशालाओं को आधुनिक बनाने, छात्रावासों के निर्माण, छात्र-कार्यकलाप केन्द्रों के विकास, अनुसंधान कार्यों के विस्तार, संस्थान-उद्योग सहयोग तथा सतत् शिक्षा कार्यक्रमों जैसे नये कार्यकलाप शुरू करने पर बल दिया गया। इन कालेजों ने अपनी विकास-योजनाओं के कार्यान्वयन में अच्छी प्रगति की। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के साथ संस्थागत नेटवर्क की योजना के अंतर्गत इन कालेजों में एक सौ छप्पन प्रयोगशालाओं का विकास किया जा रहा है। इन संस्थाओं में से चार में प्रमुख फ्रेम कम्प्यूटर है, जबकि अन्य में मुख्यतः छात्रों के प्रशिक्षण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए माइक्रो-प्रणाली और पर्सनल कम्प्यूटर प्राप्त किये गये हैं।

7.10.4 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के कार्यान्वयन के संदर्भ में सभी क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों द्वारा अपने संस्थागत लक्ष्यों और उद्देश्यों को पुनर्भाषित करते हुए और सातवीं योजना की बकाया अवधि और आठवीं योजना अवधि को शामिल करने के लिए परिप्रेक्ष्य योजनओं को दिखाते हुए, कार्रवाई योजना संबंधी

दस्तावेज तैयार किये गये थे। आलोच्य वर्ष के दौरान, क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज प्रणाली को उपलब्ध कराये गये साधनों के सीमित होने के कारण ही इन दस्तावेजों मिें उल्लिखित कार्यकलापों की केवल शुरूआत की जा सकी।

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों और अनुसंधान कार्य का विकास

7.11.1 भारत सरकार प्रत्यक्ष रूप से, इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर शिक्षा और अनुसंधान के विकास की केन्द्रीय योजना के अंतर्गत, 15 राज्य सरकार संस्थानों और 24 गैर-सरकारी स्नातकोत्तर संस्थानों को सहायता दे रही है। सामान्य तौर पर तकनीकी शिक्षा के विकास और विशेष रूप से अनुसंधान तथा विकास और विशेष रूप से अनुसंधान तथा विकास को बढ़ावा देने के लिए इस योजना ने पर्याप्त योगदान दिया है। आलोच्य वर्ष के दौरान 7 नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम स्वीकृत किये गये।

7.11.2 अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त सभी प्रौद्योगिकी शिक्षण संस्थाओं में अनुसंधान शिक्षावृत्ति/अनुसंधान सम्बद्धता-वृत्ति और आकस्मिक अनुदान की राशियां पहली अप्रैल, 1987 से बढ़ा दी गईं।

7.11.3 फरवरी, 1988 में इंजीनियरी में स्नातक अभिरुचि जांच (जी. ए. टी. ई.) परीक्षा आयोजित की गई, जिसके आधार पर स्नाकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिये गये।

गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम

7.12.1 तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता और स्तरों में सुधार करने के उद्देश्य से गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम वर्ष 1970-71 में प्रारम्भ किया गया। इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

(i) संकाय विकास जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:-

– एम. टेक. और डाक्टोरल कार्यक्रम
– गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम केन्द्रों में अल्पकालीन पाठ्यक्रम
– भारतीय तकनीकी शिक्षा सोसाइटी के जरिए ग्रीष्म और शरद् स्कूल कार्यक्रम

(ii) पाठ्यचर्या विकास, जिसमें प्रयोगशाला विकास, शैक्षणिक सामग्री और पाठ्य-पुस्तकों आदि को तैयार करना शामिल है।

(iii) इंजीनियरी कालेजों और पॉलिटेक्निकों के शिक्षकों के लिए उद्योगों में व्यावहारिक प्रशिक्षण

गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के अधीन उपलब्धियां

* पी. ए. डी. के लिए प्रशिक्षित शिक्षक	1100
* एम. टेक. के लिए प्रशिक्षित शिक्षक	1020
* अल्पकालिक पाठ्यक्रमों में डिग्री स्तर पर प्रशिक्षित शिक्षक	12600 (770 पाठ्यक्रम)
* भारतीय तकनीकी शिक्षा सोसाइटी (आई. एस. टी. ई.) के ग्रीष्मकालीन और शीत कालीन स्कूल कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित इंजीनियरी कालेजों और पोलिटेक्निकों के शिक्षक	31890

7.12.2 एम. टेक. और डाक्टोरल कार्यक्रम 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थाओं, रूड़की विश्वविद्यालय, भारतीय विज्ञान संस्थान (बंगलौर), बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, कुछ क्षेत्रीय इंजीनियरी कॉलेजों, अन्ना विश्वविद्यालय (मद्रास), और जादवपुर विश्वविद्यालय (कलकत्ता) में कार्यान्वित किये जा रहे हैं। अल्पावधि पाठ्यक्रमों से संबंधित कार्यक्रम इंजीनियरी कालेज शिक्षकों के लिए उपरोक्त केन्द्रों के जरिए और चार तकनीकी शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थानों तथा डिप्लोमा स्तर की संस्थाओं के शिक्षकों के लिए इंजीनियरी व ग्रामीण प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद के जरिए कार्यान्वित किये जाते हैं। जबकि उद्योग में अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा आयोजित किये जाते हैं, ग्रीष्म/शरद् स्कूलों का कार्यक्रम भारतीय तकनीकी शिक्षा सोसाइटी के जरिये आयोजित किया जाता है।

7.12.3 वर्ष 1987-88 तक लगभग 1020 शिक्षक एम. टेक. के लिए और 1100 शिक्षक पी. एच. डी. के लिए प्रशिक्षित किये गये। गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम केन्द्रों में लगभग 770 अल्पकालिक पाठ्यक्रम डिग्री स्तर के शिक्षकों के लिए आयोजित किये गये जहां लगभग 12,600 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। इंजीनियरी कॉलेजों और पालिटेक्निकों के शिक्षकों के लिए भारतीय तकनीकी शिक्षा सोसाइटी द्वारा लगभग 1472 अल्पकालिक ग्रीष्म/शरद् स्कूल कार्यक्रम आयोजित

किये गये जिनमें लगभग 31,890 शिक्षक प्रशिक्षित किये गये। तकनीकी शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थान ने पालिटेक्निक शिक्षकों के लिए लगभग 1520 अल्पकालिक कार्यक्रमों के आयोजन द्वारा 31,000 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया। उद्योग में अल्पकालिक कार्यक्रम के अंतर्गत डिग्री और डिप्लोमा स्तरों पर 6,300 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया।

7.12.4 डिग्री स्तर पर पाठ्यचर्या विकास सैलों ने अब तक 250 पाठ्य-पुस्तकें, 125 मोनोग्राफ्स, 50 नियम-पुस्तिकाओं, 125 अन्य प्रकाशनों का प्रकाशन तथा लगभग 175 कार्यशालाओं औ सेमिनारों का आयोजन किया। भारतीय तकनीकी शिक्षा सोसाइटी ने भी लगभग 90 शिक्षक नियम-पुस्तिकाओं का प्रकाशन किया।

संगणकीकरण और जनशक्ति विकास

7.13.1 संगणक संबंधी जागरुकता उत्पन्न करने और इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी में विद्यमान पाठ्यक्रमों में विभिन्न संगणक कार्यक्रम आरम्भ करने के लिए भारत सरकार तकनीकी संस्थाओं के लिए संगणक सुविधाओं के अर्जन के लिए सहायता प्रदान करती रही है। यह राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी केन्द्र, बम्बई के जरिए स्वदेशी "O" "ओ" संगणकों की जांच करवा रही है। राष्ट्रीय साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी केन्द्र से प्राप्त मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर 24 प्रणालियों को अब तक स्वीकृति दी जा चुकी है। सातवीं योजना के दौरान सभी स्वीकृत इंजीनियरी कॉलेजों में कम से कम "O" स्तरीय संगणक प्रदान करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।

7.13.2 आलोच्य वर्ष के दौरान इलैक्ट्रानिकी विभाग के सहयोग से संगणक अनुप्रयोग में 1½ वर्षीय पोस्ट-पालिटेक्निक डिप्लोमा शुरू करने के लिए कुछेक और पालिटेक्निकों का चयन किया गया जिससे ऐसे पालिटेक्निकों की कुल संख्या 55 हो गई है। संगणक अनुप्रयोग में त्रिवर्षीय स्नातकोत्तर डिग्री-पाठ्यक्रम में ऐसी संस्थाओं की कुल संख्या 56 हो गयी है। संगणक विज्ञान/इंजीनियरी में अवर-स्नातक कार्यक्रम को 37 केन्द्रों में स्वीकृत किया गया है।

संस्थागत नेटवर्क योजना

7.14.1 यह योजना 1981-82 में शुरू की गई थी ताकि प्रयोगशालाओं के विकास, संकाय के विनिमय, संकाय सदस्यों के प्रशिक्षण, और अनुसंधान कार्यक्रमों में सहयोग के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों जैसे विकसित प्रौद्योगिकी संस्थानों और कम विकसित संस्थानों अर्थात् क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों और राज्य इंजीनियरी कालेजों के बीच आंतरिक सहायता कार्यक्रम का नेटवर्क विकसित किया जा सके।

7.14.2 सातवीं योजना अवधि के पहले तीन वर्षों के दौरान नेटवर्क योजना के जरिए 120 प्रयोगशालाएं विकसित की गईं और इस प्रयोजन के लिए 300 लाख रुपये की धनराशि दी गई है। वर्ष 1988-89 के दौरान 100 लाख रुपये की लागत पर 40 अन्य प्रयोगशालाएं विकसित करने का प्रस्ताव हैं।

7.14.3 इस योजना के प्रावधानों के अनुसार, 5 लाख रुपये के अनुदान द्वारा नेटवर्क की एक परियोजना स्वीकृत है, जिसमें से 50% इस विभाग द्वारा और शेष 50% सम्बद्ध संस्थान द्वारा पूरा किया जाता है।

7.14.4 वर्षों से इस योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा के बाद, योजना के संचालन में निम्नलिखित परिवर्तन लागू किए गये हैं :–

(i) उपकरणों की खरीद पर दबाव कम होगा और संकाय विनियम, संयुक्त व सहयोगात्मक अनुसंधान, पाठ्यचर्या विकास, परामर्श, संगणक समय के लिए प्रावधान, उपकरणों की मरम्मत और रख-रखाव आदि जैसी प्रभावी "आंतरिक सहायता" पर अधिक दबाव होगा। उपकरणों की खरीद के लिए अनुदान का 40% और प्रभावी आंतरिक सहायता के लिए 60% का उपयोग हो सकता है।

(ii) एक ओर शैक्षिक संस्थाओं और दूसरी ओर सी. एस. आई. आर., अनुसंधान प्रयोगशालाओं, रक्षा अनुसंधान प्रयोगशालाओं और अन्य उपभोक्ता एजेन्सियों के बीच संबंध स्थापित करते हुए योजना का कार्यक्षेत्र विकसित किया जाना है। संस्थागत नेटवर्क पर एक व्यापक आधार वाली योजना शीघ्र ही तैयार की जायेगी।

तकनीकी शिक्षा के विशिष्ट क्षेत्र

(क) प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण तथा कमजोर क्षेत्रों में औद्योगिक सुविधाओं को सुदृढ़ बनाना

7.15.1 इस योजना को छठी योजना के दौरान

आरम्भ किया गया था और सातवीं योजना के दौरान क्षेत्र और आयाम की दृष्टि से सुधार किये गये थे जिनका उद्देश्य प्रौद्योगिकी के निश्चित चुनिन्दा क्षेत्रों में जहां काफी कमियां विद्यमान हैं, प्रौद्योगिकीय अवस्थापना सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण/पाठ्यक्रमों की विविधता द्वारा दुर्बलता निवारण के लिए निर्धारित प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण क्षेत्र संस्थाओं में अवर-स्नातक स्तर पर पाठ्यक्रम प्रस्तुत करके निम्नलिखित द्वारा सुविधाओं को सुदृढ़ करना था: (I) भौतिकीय सुविधाओं में वृद्धि जैसे प्रयोगशाला उपस्कर, स्थान, निकाय और सहायक स्टाफ, (II) पाठ्यक्रमों की विविधता और (III) स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए आधार तैयार करना। प्रौद्योगिकी के वे चुनिन्दा क्षेत्र जहां कमियां विद्यमान हैं वे हैं :- कम्प्यूटर विज्ञान/ प्रौद्योगिकी इलैक्ट्रानिकी, शल्यकर्म, पदार्थ विज्ञान/ प्रौद्योगिकी, अनुरक्षण इंजीनियरी, उत्पाद विकास/ अभिकल्पना/ जैव-सम्परिवर्तन, एरगोनोमिक्स, मुद्रण प्रौद्योगिकी, प्रबन्ध-विज्ञान और व्यवसाय।

- ☐ कम्प्यूटर विज्ञान/प्रौद्योगिकी
- ☐ इलैक्ट्रानिक्स
- ☐ इन्स्ट्रूमेन्टेशन
- ☐ पदार्थ विज्ञान/प्रौद्योगिकी
- ☐ अनुरक्षण इंजीनियरी
- ☐ उत्पाद विकास/डिजाइन
- ☐ बायो कनवर्शन
- ☐ ऑर्गोनॉमिक्स
- ☐ मुद्रण प्रौद्योगिकी
- ☐ प्रबंध विज्ञान और उद्यमशीलता

7.15.2 217 परियोजनाओं को सहायता प्रदान करते हुए सातवीं योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान 2446.75 लाख रुपये दिये गये। 800.00 लाख रुपये मूल्य पर 1988-89 के दौरान 55 परियोजनाओं को सहायता देने का प्रस्ताव हैं।

(ख) नई प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में अवस्थापना का निर्माण।

7.15.3 यह योजना छठी योजना अवधि के दौरान चुनिन्दा इंजीनियरी/ प्रौद्योगिकी संस्थाओं में नई प्रौद्योगिकी के 14 निर्धारित क्षेत्रों में शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए अवस्थापना सुविधाओं के निर्माण के लिए प्रयोगात्मक आधार पर शुरू की गई थी। सातवीं योजना अवधि के दौरान योजना के क्षेत्र और आयाम को बढ़ाया गया था। योजना के मुख्य उद्देश्य हैं :-

- नई प्रौद्योगिकी के निर्धारित क्षेत्रों में आधुनिक प्रयोगशाला के संबंध में अवस्थापना का विकास।
- निर्धारित कार्यक्रमों और पाठ्यक्रमों द्वारा उच्चस्तरीय कार्य के लिए मजबूत आधार विकसित करना।
- राष्ट्रीय स्तर पर प्रौद्योगिकी के अनुवर्ती क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास के कार्यकलापों के लिए सुविधायें तथा समर्थन प्रदान करना ताकि धीरे-धीरे विकसित देशों की तुलना में प्रौद्योगिकी के अंतर को पाटा जा सके।
- जन शक्ति का विकास
- संकाय के प्रशिक्षण की सुविधायें।
- अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठानों तथा प्रयोक्ता अभिकरणों सहित अन्य संस्थानों के साथ सम्पर्क बढ़ाना।
- समर्थित संस्थानों द्वारा विकसित सुविज्ञता के क्षेत्र में सूचना का प्रसार।

अवस्थापना सृजन के लिए निर्धारित नई प्रौद्योगिकियां

- ☐ ऊर्जा विज्ञान
- ☐ परिवहन इंजीनियरी
- ☐ माइक्रो इलैक्ट्रानिक्स
- ☐ सुदूर सुग्राहिता
- ☐ वायुमंडलीय विज्ञान
- ☐ विश्वसनीयता इंजीनियरी
- ☐ पर्यावरणीय इंजीनियरी
- ☐ जल संसाधन प्रबंध
- ☐ प्रकाशीय संचार और फाइबर प्रकाश विज्ञान
- ☐ लेसर प्रौद्योगिकी
- ☐ इन्फोर्मेटिक्स
- ☐ टेलीमेटिक्स
- ☐ शिक्षा प्रौद्योगिकी
- ☐ कम्प्यूटर आधारित डिजाइन/कम्प्यूटर आधारित विनिर्माण
- ☐ माइक्रो प्रोसेसर
- ☐ रोबोटिक्स और कृत्रिम बुद्धि

तकनीकी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए सहायता

(वर्ष 1985-89 के दौरान 30 क्षेत्रों को सहायता दी गई)

क्षेत्र	परियोजनाओं की संख्या	शामिल की गई संस्थाओं की संख्या	अनुदान (लाख रू० में)
1	2	3	4
संगणक विज्ञान/इनफार्मेटिक्स/माइक्रोप्रोसेसर्स	120	50	1335
रोबोटिक्स/कृत्रिम आसूचना/सी.ए.डी.सी.ए.एम.	89	45	1503
इलेक्ट्रानिक्स/माइक्रो इलेक्ट्रानिक्स	89	35	1089
इन्स्ट्रूमेंटेशन	53	39	607
लेसर प्रौद्योगिकी/फाइबर आप्टिकस/सुदूर संवेदन	51	39	722
पदार्थ विज्ञान	34	30	397
उत्पाद विकास अनुरक्षण प्रौद्योगिकी/विश्वसनीयता	32	24	589
पर्यावरणात्मक प्रौद्योगिकी	44	18	519
जैव प्रौद्योगिकी	26	23	314
ट्रांसपोर्टेशन	25	18	257
जल संसाधन प्रबंध	23	23	179
उर्जा विज्ञान	18	16	225

7.15.4 इस योजना के अंतर्गत सहायतार्थ जिन क्षेत्रों की पहचान की गई वे हैं : ऊर्जा विज्ञान, परिवहन इंजीनियरी, माइक्रो-इलैक्ट्रानिकी, दूरस्थ संवेदन, वातावरण, विज्ञान, विश्वसनीयता विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, जल संसाधन प्रबंध, ऑप्टिकल संचार और फाइबर ऑप्टिक्स, लेसर प्रौद्योगिकी, इनफोर्मेटिक्स, टेलीमेटिक्स, शिक्षा–प्रौद्योगिकी, संगणक सहायता प्राप्त डिज़ाइन/संगणक सहायता प्राप्त निर्माण, माइक्रो-प्रोसेसर, रोबेटिक्स तथा कृत्रिम बुद्धि।

7.15.5 सातवीं योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान 206 परियोजनाओं को 2911.25 लाख रुपये जारी किये गये। 1988-89 के दौरान 125 परियोजनाओं की सहायता करने का प्रस्ताव है।

(ग) नई और/या उन्नत प्रौद्योगिकियों और विशेषज्ञता के क्षेत्रों में नये पाठ्यक्रम लगाने के कार्यक्रम।

7.15.6 यह एक नई योजना है जो वर्ष 1987-88 के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के एक भाग के रूप में शुरू की गई थी। यह योजना बदलती हुई औद्योगिक परिस्थितियों और विश्वभर के प्रौद्योगिकी विकास की गति को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। प्रौद्योगिकी के परम्परागत क्षेत्रों के साथ-साथ प्रौद्योगिकी के कई नए उभरते हुए क्षेत्र हाल ही के वर्षों में विकसित हुए हैं जो कि राष्ट्रीय आवश्यकताओं के लिए प्रासंगिक हैं, जहां उपयुक्त विशेषज्ञता के साथ जन-शक्ति का विकास किया जाना आवश्यक है। प्रौद्योगिकी के 46 नए/सुधरे हुए क्षेत्रों का पता लगाया गया है जहां इस योजना के अंतर्गत कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों को सहायता दी जायेगी।

7.15.7 वर्ष 1987-88 के दौरान केवल 37.00 लाख रुपये की लागत से दो परियोजनाओं की सहायता की गई। वर्ष 1988-89 के दौरान 12 परियोजनाओं को सहयोग देने का प्रस्ताव है।

आधुनिकीकरण और पुरानी अप्रचलित चीजों को हटाना

7.16.1 छठी योजना अवधि के दौरान, चुनिन्दा इंजीनियरी कालेजों में शत-प्रतिशत प्रत्यक्ष केन्द्रीय सहायता के आधार पर, प्रौद्योगिकीय प्रगति और पाठ्यक्रमों के परिवर्तन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आधुनिक यंत्रों और मशीनों को प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई थी।

7.16.2 सातवीं योजना अवधि के दौरान और विशेष रूप से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाये जाने के बाद में इस योजना का क्षेत्र और आयाम काफी बढ़ गया है जिसमें तकनीकी विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालयों के प्रौद्योगिकी संकाय, पालिटेक्निक सहित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों और अन्य इंजीनियरी कालेजों को सम्मिलित करना तथा मानव संसाधनों संबंधी पुरानी अप्रचलित चीजों को हटाना शामिल है। इस योजना के उद्देश्यों को निम्नानुसार पुनः परिभाषित किया गया है :

- इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संस्थानों में प्रयोगशालाओं और कार्यशालाओं में अप्रचलित मशीनों और उपकरणों को हटाना।
- प्रौद्योगिकी के तीव्र विकास के परिणाम-स्वरूप संबद्ध पाठ्यचर्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नए अतिरिक्त उपस्करों द्वारा आधुनिकीकरण
- छात्रों को आधुनिक प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला कार्य का अनुभव प्रदान करना।
- नई प्रयोगशालाओं का निर्माण।
- संगणकों का प्रावधान।
- संकाय और सहायता करने वाले स्टाफ का प्रशिक्षण और पुनर्प्रशिक्षण।

7.16.3 सातवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान सहायता प्राप्त परियोजनाओं की संख्या और प्रतिवर्ष

दिये गये (रिलीज़ किये गये) अनुदान की राशि निम्नानुसार है :–

वर्ष	सहायता प्राप्त परि-योजनाओं की संख्या	दिया गया (रिलीज़ किया गया) अनुदान (लाख रूपयों में)
1985-86	131	1500
1986-87	151	1800
1987-88	497	6000
1988-89	530	4300 (प्रस्तावित)

राष्ट्रीय तकनीकी जनशक्ति सूचना प्रणाली

7.17.1 • राष्ट्रीय तकनीकी जनशक्ति सूचना प्रणाली की योजना वर्ष 1983-84 में, सतत रूप से अद्यतन एवं लाभप्रद जनशक्ति संबंधी सूचना प्रदान करने के मुख्य उद्देश्य से शुरू की गई थी ताकि संबंधित शैक्षिक प्राधिकरण इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास क्षेत्रों का पूर्वानुमान लगा सकें और देश में तकनीकी जनशक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सुव्यवस्थित आधार पर योजनाएं तैयार कर सकें। इस प्रणाली के अंतर्गत प्रयुक्त जनशक्ति अनुसंधान संस्थान में एक लीड सेन्टर, चुने गये इंजीनियरी कालेजों/प्रौद्योगिकी संस्थाओं/प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड में 21 प्रमुख केन्द्र और मंत्रालय में जनशक्ति सैल शामिल हैं। इस योजना की वर्तमान में एक विशेष दल द्वारा समीक्षा की जा रही हैं। इस दल की सिफारिशों के आधार पर इस योजना के कार्य-क्षेत्र का विस्तार करने के लिए अगली कार्रवाई की जायेगी।

उच्च तकनीशियन पाठ्यक्रम

7.18.0 यह योजना वर्ष 1981-82 में डिप्लोमा-धारियों के लिए बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराने के मुख्य लक्ष्य से शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत उन्नत स्तर पर अध्ययन के उच्च पाठ्यक्रम उपलब्ध कराये जाते हैं, ताकि इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी की विभिन्न शाखाओं में डिप्लोमा प्राप्त तकनीशियन अपने-अपने कार्य क्षेत्रों में उच्च योग्यता प्राप्त कर सकें और व्यावसायिक रूप से प्रगति कर सकें। इन पाठ्यक्रमों में उत्तीर्ण छात्रों की, औद्योगिक क्षेत्र द्वारा बहुत प्रशंसा की गई है। इस समय यह योजना निम्नलिखित 9 संस्थानों के जरिए कार्यान्वित की जा रही है :

(1) वाई.एम.सी.ए. इंजीनियरी संस्थान, फरीदाबाद।

(2) सी.एम. कोठारी प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास।

(3) एस.बी.एम. पॉलिटेक्निक, बम्बई।

(4) इंजीनियरी और ग्रामीण प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद।

(5) कमला नेहरू महिला पॉलिटेक्निक, हैदराबाद।

(6) के.जी. इंजीनियरी संस्थान, बिशनपुर (पश्चिम बंगाल)।

(7) राजकीय पॉलिटेक्निक, खुराई (मध्य प्रदेश)।

(8) खेतान पॉलिटेक्निक, जयपुर।

(9) राजकीय पॉलिटेक्निक, पोरबन्दर।

वर्ष 1988-89 के दौरान इस योजना में 33 लाख रूपये का बजट प्रावधान था।

ग्रामीण विकास के लिए तकनीकी शिक्षा

* ग्रामीण आवश्यकताओं से संबंधित तकनीकी विकास के लिए पंद्रह ग्रामीण प्रौद्योगिक विकास केन्द्र
* ग्रामीण समुदाय को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में लगे 109 सामुदायिक पोलिटेक्निक
* चुनिन्दा सामुदायिक पॉलिटेक्निकों के माध्यम से समग्र ग्रामीण विकास के लिए प्रायोगिक पाइवर परियोजनाएं
* ग्रामीण विकास के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी के विशेष संस्थान

ग्रामीण प्रौद्योगिकी के विकास के लिए केन्द्र

7.19.0 योजना 1980-81 के दौरान शुरू की गई। विभिन्न डिप्लोमा स्तरीय संस्थानों में स्थापित किये गये 15 ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र ग्रामीण

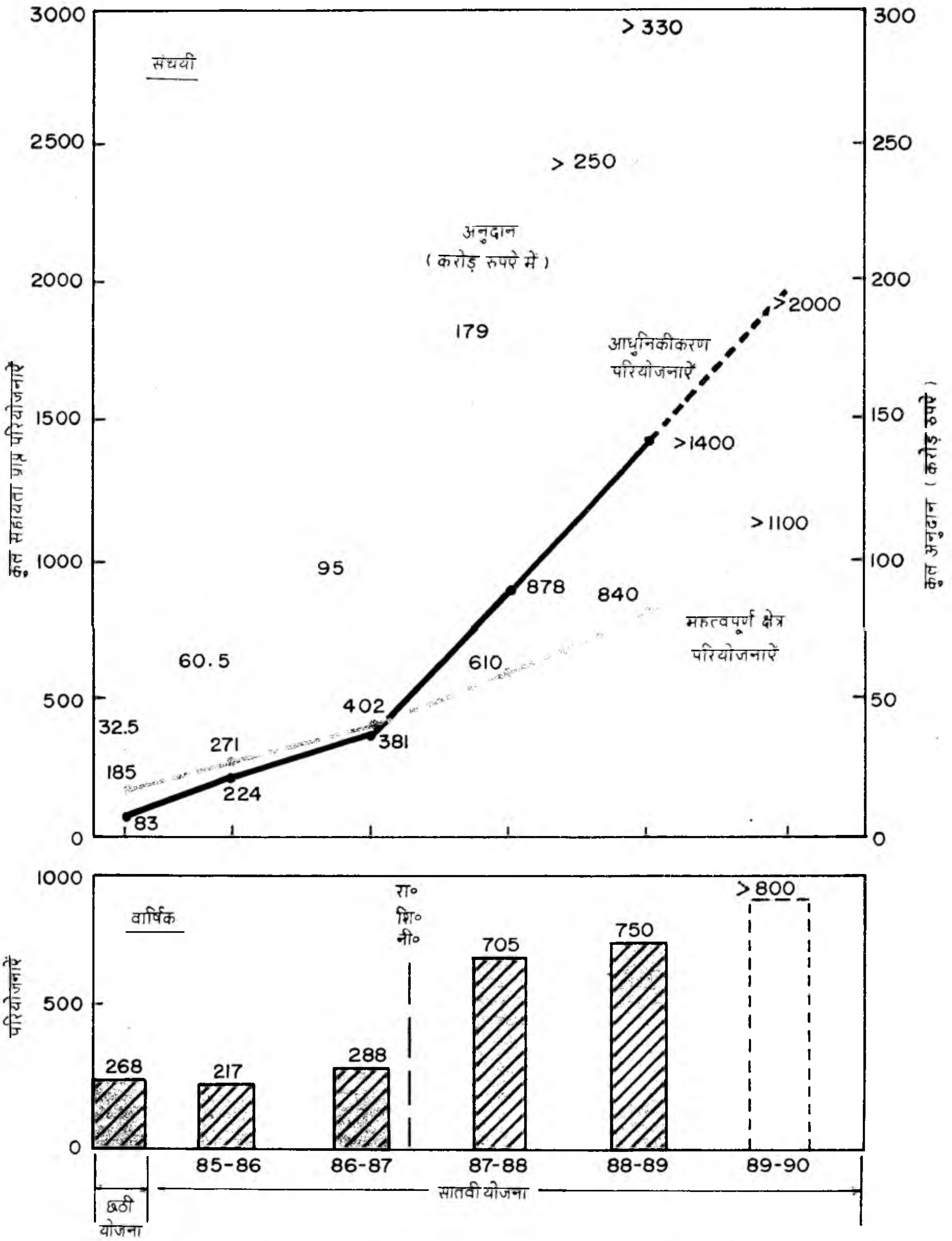

तकनीकी शिक्षा के महत्वपूर्ण क्षेत्र और आधुनिकीकरण के लिए सहायता

राज्य मंत्री (शिक्षा एवं संस्कृति), श्री ललितेश्वर प्रसाद शाही—उद्यमवृत्ति-विकास संगोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए।

पदार्थ विज्ञान और प्रौद्योगिकी केन्द्र, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली—पदार्थ अनुसंधान में तापीय विश्लेषक।

आवश्यकताओं के अनुरूप प्रौद्योगिकी को विकसित, परिवर्तित और अपनाने के लिए तेजी से कार्य कर रहे हैं।

सामुदायिक पॉलिटेक्निक

7.20.1 यह योजना वर्ष 1978-79 में केन्द्रीय क्षेत्र के अंतर्गत शुरू की गई थी, जिसमें 36 पॉलिटेक्निकों को "सामुदायिक पॉलिटेक्निक" के रूप में कार्य करने के लिए चुना गया था। इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी की विभिन्न शाखाओं में डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रदान करने के अतिरिक्त इन पॉलिटेक्निकों से अपेक्षा की जाती हैं कि यह पर्यावरण के साथ तालमेल सहित ग्रामीण क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के अंतरण को प्रोत्साहित करने के लिए केन्द्र बिन्दु के रूप में कार्य करें। इन पॉलिटेक्निकों द्वारा शुरू किये गये कार्यकलापों में ग्रामीण युवकों के लिए विभिन्न पेशों/व्यवसायों में अल्पकालिक दक्षता-प्रशिक्षण, ग्रामीण लोगों के लिए प्रौद्योगिकी और सहायक सेवाओं का प्रावधान, पहले से ही विकसित, परीक्षित, और अपनाई गई उपयुक्त प्रौद्योगिकी की संबद्ध चीजों का स्थानान्तरण, अधिष्ठापन तथा अनुरक्षण, सूचना एवं प्रसार केन्द्रों की स्थापना और ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग सहित प्रयोगात्मक मार्गदर्शक परियोजनाएं शुरू करना शामिल हैं। वर्ष 1984-85 के दौरान अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों के निकटस्थ 10 पॉलिटेक्निकों को सामुदायिक पॉलि-टेक्निक के रूप में स्वीकृति दी गई ताकि अल्पसंख्यक समुदायों के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जा सके। वर्ष 1988-89 के दौरान असम राज्य में अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में 2 और पॉलिटेक्निकों को शामिल करने के लिए इस योजना का और अधिक विस्तार किया गया। वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत कुल 109 सामुदायिक पॉलिटेक्निक हैं।

7.20.2 सामुदायिक पॉलिटेक्निकों ने दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस योजना के अंतर्गत उपलब्ध सेवाएं और सुविधाएं गांवों में ही उपलब्ध हों, विस्तार केन्द्रों की स्थापना की हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार स्थापित विस्तार केन्द्रों की कुल संख्या लगभग 236 है। इस योजना के प्रारंभ से प्रशिक्षित लोगों की संख्या 94,000 और तकनीकी सेवाओं/प्रौद्योगिकी के स्थानान्तरण के जरिए लाभान्वित गांवों की संख्या लगभग 3600 हैं। इसकी उपयोगिता के मूल्यांकन के लिए इस योजना का हाल ही में मूल्यांकन किया गया है। इस मूल्यांकन के आधार पर इस योजना को और अधिक सुदृढ़ और विस्तृत किया जा रहा है।

प्रशिक्षुता प्रशिक्षण कार्यक्रम

7.21.1 प्रशिक्षुता अधिनियम 1961 (1973 में संशोधित) के अंतर्गत इंजीनियरी स्नातक और डिप्लोमाधारियों के लिए प्रशिक्षुता कार्यक्रम का कार्यान्वयन कानपुर, कलकत्ता बम्बई और मद्रास स्थित चार प्रशिक्षुता बोर्डों के जरिए जारी रहा। उद्योग के साथ बेहतर सम्पर्क के लिए बोर्डों की राज्य स्तरीय समितियां है। प्रशिक्षुओं को दिये जा रहे भत्ते का खर्च प्रशिक्षण संस्थानों और भारत सरकार द्वारा परस्पर बांटा जाता है।

7.21.2 पिछले तीन वर्षों में, 31 अक्तूबर की स्थिति के अनुसार प्रत्येक वर्ष लगाये गये प्रशिक्षुओं की संख्या नीचे दर्शाई गई है :–

	31.10.86	31.10.87	31.10.88
कुल प्रशिक्षाणार्थी	16362	17352	21221
स्नातक प्रशिक्षाणार्थी	4658	4667	6021
डिप्लोमाधारी	11704	12685	15200
अनुसूचित जाति	242	450	547
अनुसूचित जनजाति	65	80	104
अल्पसंख्यक	767	1208	1082
विकलांग	9	2	12
महिलाएं	927	1138	1273

7.21.3 इन बोर्डों द्वारा कुछ इंजीनियरी कालेजों तथा पॉलिटेक्निकों के अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए प्रशिक्षुता प्रशिक्षण तथा आजीविका, मार्गदर्शन कार्यक्रम की कोटि सुधारने के लिए कई पर्यवेक्षी विकास कार्यक्रम आयोजित किये गये। ये बोर्ड ऐसी पत्रिकायें प्रकाशित कर रहे हैं जिनमें सूचनात्मक लेख हैं। उनमें से कुछ ने प्रशिक्षण मैनुअल भी तैयार किये हैं।

7.21.4 वर्ष 1988-89 से 10+2 के व्यावसायिक छात्रों के लिए प्रशिक्षुता प्रशिक्षण की एक नई योजना शुरू की गई।

समग्र ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग हेतु प्रयोगात्मक मार्गदर्शी परियोजनाएं

7.22.0 सातवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल यह एक नई योजना है। इस विशेष योजना का उद्देश्य इस कार्य

में शामिल चुनिन्दा सामुदायिक पोलिटेक्निकों और/अथवा अन्य विशिष्ट संस्थानों को समग्र ग्रामीण विकास हेतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के लिए प्रयोगात्मक मार्गदर्शी परियोजनाएं शुरू करने के लिए सहायता सुलभ कराना है ताकि ये ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त वर्तमान वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार और अधिक प्रांसगिक बन सकें और वैज्ञानिक दिशा में ग्रामीण विकास को बढ़ाने और सहायता करने में कुछ व्यवहार्य और परिवर्तित माडलों का विकास हो सके। इस योजना से सम्पूर्ण ग्रामीण विकास के लिए 100 गांवों की एक इकाई के रूप में परिकल्पित किया गया है। इस परियोजना का संचालन व्यावसायिक प्रबन्धकों के एक दल, जिसमें मुख्यालय में एक महाप्रबंधक, मुख्य केन्द्रों में क्षेत्रीय प्रबन्धक और गांव स्तर पर प्रबन्धक होंगे, द्वारा किया जायेगा। समन्वय-संस्थान स्रोत संस्थान का काम करेगा और परियोजना की शासी परिषद् की सहायता करेगा। इस परिषद् में ग्रामीण विकास से सभी संबंधित हित शामिल होंगे। विभिन्न सामुदायिक पालिटेक्निक और अन्य संस्थान आवश्यक वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी निवेश प्रदान करेंगे। परियोजना का उद्देश्य 5 वर्षों की अवधि के दौरान रोजगार उत्पन्न करना, उत्पादकता में सुधार लाना, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, और जीवन को अधिक मूल्यवान भरापूरा बनाने के लिए वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी और प्रबंध निवेशों के माध्यम से क्षेत्र की आय को 10 गुणा बढ़ाना हैं। यह परियोजना अनुसंधान कार्रवाई द्वारा वैध मानी जायेगी।

उपयुक्त प्रौद्योगिकी और ग्रामीण विकास के विशेष संस्थान

7.23.0 यह एक मई योजना है जिसे सातवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है। ये संस्थान उपयुक्त प्रौद्योगिकी और ग्रामीण विकास की विभिन्न शाखाओं में अनुसंधान कार्य के लिए तथा प्रमाण पत्र स्तर से लेकर स्नातकोत्तर तक के विभिन्न स्तरों के पाठ्यक्रमों के विकास और आयोजन के लिए, श्रेष्ठता केन्द्रों के रूप में कार्य करेंगे। इसके अतिरिक्त, ये संस्थान प्रौद्योगिकी और समेकित ग्रामीण विकास के स्थानान्तरण के लिए मुख्य केन्द्रों के रूप में कार्य करेंगे और ग्रामीण विकास में किसी भी रूप में लगे हुए सभी अन्य संस्थानों और संगठनों के लिए स्रोत संस्थान के रूप में भी कार्य करेंगे।

वर्ष 1988-89 के दौरान योजना के लिए बजट प्रावधान 20.00 लाख रुपया था।

एशियाई प्रौद्योगिकी संस्थान, बैंकाक

7.24.1 एशियाई प्रौद्योगिकी संस्थान, बैंकाक, एक स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय स्नातक संस्थान है जो इंजीनियरी, विज्ञान और सम्बद्ध विषयों में उच्च शिक्षा प्रदान करता है। यह 20 से अधिक देशों से लगभग 600 छात्रों को दाखिल करता है और इसके अंतर्राष्ट्रीय संकाय सदस्य हैं। यह संस्थान भारत सहित विभिन्न देशों के सदस्यों के एक अंतर्राष्ट्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा अभिशासित है। यह 9 विषयों में शैक्षिक कार्यक्रमों, एशियाई देशों से सम्बद्ध समस्याओं पर अनुसंधान और अल्पकालिक पाठ्यक्रमों सहित विशेष कार्यक्रमों, सम्मेलनों आदि का आयोजन करता है।

7.24.2 भारत सरकार एशियाई प्रौद्योगिकी संस्थान (ए. आई. टी.) को निम्नलिखित सहायता प्रदान करने के लिए सहमत हो मई है :-

- इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी के विशिष्ट क्षेत्रों में भारतीय शिक्षकों/विशेषज्ञों की प्रति-नियुक्ति और प्रतिनियुक्ति के सम्पूर्ण व्यय का वहन।
- निम्नलिखित एक या अधिक उद्देश्यों के लिए 3.00 लाख रु. तक के वार्षिक अनुदान का उपयोग :

(क) भारत से उपकरणों की खरीद
(ख) पुस्तकों की खरीद तथा भारत में प्रकाशित अकादमीय तथा तकनीकी पत्रों के चन्दे के लिए भुगतान, तथा
(ग) भारत में अकादमी संबंधी गतिविधियों पर व्यय।

1983-88 की अवधि के दौरान 42 भारतीय विशेषज्ञ ए. आई. टी., बैंकाक में प्रतिनियुक्त किये गये।

ऐजुकेशनल कन्सलटेन्ट इण्डिया लिमिटेड

7.25.1 इस मंत्रालय का एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम अर्थात् शैक्षिक परामर्शदाता भारत लि, नई दिल्ली 17 जून, 1981 को कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत स्थापित किया गया था। यह केन्द्रीय सरकार

के विभिन्न मंत्रालयों और संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक बोर्ड आफ डायरेक्टर्स की देखरेख में कार्य करता है। इसमें एक अंशकालिक गैर-सरकारी अध्यक्ष तथा एक पूर्णकालिक प्रबंध निदेशक है।

7.25.2 वर्ष 1988-89 के दौरान कम्पनी ने बैंकाक, थाईलैंड में एक इलैक्ट्रानिक डिज़ाईन प्रयोगशाला की स्थापना के लिए प्रारम्भिक कार्य की शुरुआत सहित अपनी अनेक गतिविधियों को संचालित किया। कम्पनी ने भारत और विदेशों में निम्नलिखित परियोजनाएं भी पूरी कीं :-

1 भारत में :

1. बायो-इंजीनियरिंग तथा मेडिकल इन्स्ट्रू-मेंटेशन विभाग, स्वास्थ्य विज्ञान विश्व-विद्यालय, विजयवाड़ा की स्थापना।
2. न्यू ओखला इन्डस्ट्रियल डेवलेपमेंट ऑथारिटी, नौएडा, उ. प्र. में एक तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना।
3. न्यू ओखला इन्डस्ट्रियल डेवलेपमेंट ऑथा-रिटी, उ. प्र. में स्कूलों की स्थापना के लिए ज़मीन के आवंटन हेतु शैक्षिक सोसाइटियों का मूल्यांकन।
4. भारत में पोत निर्माण उद्योग, हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम के लिए एक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना।
5. भारत में राष्ट्रीय परीक्षण सेवा (मानव संसाधन विकास मंत्रालय) की स्थापना के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना।
6. असम में मानव संसाधन विकास मंत्रालय में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना।
7. ग्रामीण संस्थानों/विश्वविद्यालयों के लिए केन्द्रीय परिषद् की तथा ग्रामीण संस्थान/विश्वविद्यालय (मानव संसाधन विकास मंत्रालय) की स्थापना।
8. महिलाओं के लिए आवासीय पॉलिटेक्निक स्थापित करने तथा लोंगोवाल इंजीनियरी व प्रौद्योगिकी संस्थान, लोंगोवाल (पंजाब), मानव संसाधन विकास मंत्रालय) की स्थापना करने से संबंधित परियोजना रिपोर्टों सहित मानव संसाधन विकास मंत्रालय, तकनीकी शिक्षा ब्यूरो की 21 परियोजनाओं का कार्यकरण।

II विदेश में

1. मोई विश्वविद्यालय, केनिया सरकार के लिए एक मास्टर प्लान तैयार करना।
2. बोत्सवाना गणराज्य, शिक्षा मंत्रालय, बोत्सवाना में माध्यमिक स्कूलों के लिए भारतीय अध्यापकों का अनुसमर्थन।
3. भारत व अफ्रीकी देशों, यूनेस्को, पेरिस के मध्य अन्तर्क्षेत्रीय तकनीकी सहयोग।
4. रियाद, सऊदी अरब के भारतीय दूतावास के द्वारा रियाद व जद्दाह में भारतीय दूतावास स्कूलों के लिए प्रिंसिपलों व उप-प्रिंसिपलों-सह-प्रशासकों की भर्ती।

7.25.3 कम्पनी ने अपने आवर्त में 30 प्रतिशत की वृद्धि की, जबकि पिछले वर्ष के वित्तीय आंकड़ों की तुलना में लाभ में 100 प्रतिशत वृद्धि हुई। जहां कम्पनी के कार्यचालन संबंधी लगभग सभी क्षेत्रों में विकास हुआ, वहां विदेशी प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या में गिरावट का रुख रहा।

7.25.4 1987-88 के दौरान कम्पनी ने टूट-फूट व्यय के बाद 38.66 लाख रु. का लाभ अर्जित किया। कम्पनी ने 10 प्रतिशत के एक अप्रयुक्त लाभांश के भुगतान की घोषणा की जो 10 रु. प्रति शेयर था।

शैक्षिक अर्हता मूल्यांकन बोर्ड

7.26.1 यह मूल्यांकन बोर्ड के केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत पदों और सेवाओं में भर्ती के लिए शैक्षिक और व्यावसायिक अर्हताओं को मान्यता प्रदान करने के प्रयोजनार्थ भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। तकनीकी शिक्षा ब्यूरो इस बोर्ड के सचिवालय का कार्य करता है और अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग इस बोर्ड के अध्यक्ष हैं।

7.26.2 वर्ष के दौरान सात शैक्षिक अर्हताओं (छः भारतीय और एक विदेशी) को मान्यता प्रदान की गई। सोवियत संघ के साथ अर्हताओं की समकक्षता के एक प्रोटोकोल पर भी हस्ताक्षर किये गये।

आंशिक वित्तीय सहायता

7.27.1 तकनीकी शिक्षा ब्यूरो विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्रों के शिक्षकों तथा वैज्ञानिकों को हवाई-किराए की आंशिक प्रतिपूर्ति के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की "आंशिक वित्तीय सहायता योजना" का प्रबंध करता है।

7.27.2. इस वर्ष के दौरान, 10 व्यक्तियों को जिन्होंने विदेशों में सम्मेलनों/अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी।

महिलाओं के लिए आवासीय पॉलिटेक्निक

7.28.0 महिलाओं के लाभ के लिए तकनीकी शिक्षा के उपयुक्त औपचारिक व अनौपचारिक कार्यक्रम उपलब्ध कराने के लिए महिलाओं के लिए आवासीय पॉलिटेक्निक स्थापित करने की योजना को मंजूरी दी गई। ये पोलिटेक्निक स्वरूप में स्वायत्त होंगे तथा अपने पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों के डिजाइन, विकास, क्रियान्वयन व पुनरीक्षण में स्वतंत्र होंगे तथा संबंधित राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा अनुमोदित अपने स्वयं के डिप्लोमा व प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे। वे स्वरूप में पूर्णतः आवासीय होंगे तथा रोजगार के लिए उच्च सम्भावनाओं सहित प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में पाठ्यक्रम प्रदान करेंगे।

विद्यमान संस्थानों का सुदृढ़ीकरण तथा गैर-निगमित तथा असंगठित क्षेत्रों के लिए नए संस्थानों की स्थापना

7.29.0 इस योजना का उद्देश्य असंगठित तथा गैर-निगमित क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, जो लगभग 90% कृत्य बल (वर्किंग फोर्स) को काम देते हैं, डिप्लोमा स्तर के कुछ चुने हुये संस्थानों में उद्यमशीलता व प्रबन्ध विकास केन्द्र (सी.इ.एम.डी.ई.वी.) तथा उद्यमशीलता विकास केन्द्र (सी.ई.डी.) स्थापित करना था। आरम्भ में भोपाल, कलकत्ता, चण्डीगढ़ तथा मद्रास में तकनीकी शिक्षक-शिक्षा संस्थानों में चार सी.ई.एम.डी.ई.वी. स्थापित करने का प्रस्ताव है, जो देश में तकनीशियन शिक्षा प्रणाली के लिए संसाधन संस्थान हैं।

तकनीकी शिक्षा में पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों की पुनर्संरचना

7.30.0 राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के एक भाग के रूप में 1987-88 के दौरान शुरू की गई इस नई योजना में डिप्लोमा, डिग्री तथा स्नातकोत्तर स्तरों पर पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों की पुनर्संरचना के लिए प्रावधान है। 1987-88 के दौरान यह योजना चार संस्थानों में कार्यान्वित की गई थी– डिग्री तथा डिप्लोमा स्तरों पर प्रत्येक में दो-दो संस्थानों में तथा इस उद्देश्य के लिए 10.00 लाख रु. का एक योजना परिव्यय दिया गया (रिलीज किया गया) था।

पाठ्यचर्या विकास :

7.31.1 यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के एक भाग के रूप में 1987-88 के दौरान निम्नलिखित विस्तृत उद्देश्यों के साथ प्रारम्भ हुई :

– प्रयोक्ता एजेन्सियों की मांग पूरी करने के लिए पाठ्यचर्या अद्यतन बनाना
– डिग्री तथा डिप्लोमा दोनों स्तरों पर बहु-केन्द्र प्रविष्टि तथा क्रेडिट प्रणाली के लिए पाठ्यचर्या विकास।
– दूरस्थ शिक्षा पैकेज तथा अध्ययन/शिक्षण मैनुअलों सहित बहु-माध्यम पैकेज तैयार करना।
– प्रयोगशाला तथा कक्षा में प्रयोग के लिए ट्रान्सपेरेंसीज़, स्लाइडें तथा वीडियो फिल्में तैयार करना।
– राज्यों में संस्थानों की आवश्यकताओं का आकलन, पाठ्यचर्या विकास सैलों को पुनर्निवेश उपलब्ध कराना तथा पा. वि. सैलों व संस्थानों के बीच सम्पर्क स्थापित करना।

7.31.2 1987-88 के दौरान, 5 आई.आई.टी., आई.आई.एस. बंगलौर तथा रुड़की विश्वविद्यालय में चल रहे सात विद्यमान पाठ्यचर्या विकास केन्द्रों को, अनेक नई गतिविधियां शुरू करने तथा चल रहे कार्यक्रमों के समेकन को सुसाध्य बनाने के लिए सुदृढ़ किया गया। योजना में संसाधन विकास केन्द्रों, अध्ययन संसाधन केन्द्रों तथा राज्यस्तरीय पाठ्यचर्या विकास सैलों की स्थापना की परिकल्पना की गई है।

उद्योग-संस्थान अन्तःक्रिया

7.32.1 "उद्योग-संस्थान अन्तः क्रिया" की योजना अक्तूबर, 1988 में मंजूर की गई। योजना में निम्नलिखित की कल्पना की गई है :–

(क) इंजीनियरी कालेजों तथा उद्योगों के मध्य अंतः क्रियाएं।

(ख) पोलिटेक्निकों तथा उद्योगों के मध्य अन्तः क्रियाएं।

(ग) आई.आई.टी., दिल्ली में एक "औद्योगिक प्रतिष्ठान" की स्थापना।

7.32.2 1988-89 के दौरान ऐसी आशा है कि योजना 18 इंजीनियरी कालेजों तथा 10 पोलिटेक्निकों में शुरू की जायेगी। कालेज स्तर पर, यह परिकल्पना है कि प्रत्येक कालेज तथा एक औद्योगिक प्रतिष्ठान के मध्य कम से कम दो संयुक्त अनुसंधान परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। संस्थानों तथा उद्योगों के बीच संकाय आदान-प्रदान भी होगा।

7.32.3. आई.आई.टी. दिल्ली में स्थापित किया जाने वाला प्रस्ताविक औद्योगिक प्रतिष्ठान संस्थान की अनुसंधान तथा परामर्श क्षमताओं के विपणन, उद्योग तथा अन्य संगठनों द्वारा प्रायोजित वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकीय समस्याओं के समाधान, प्रोटोटाइप विकास तथा औद्योगिक पाइलट प्लांट की प्रावस्थाओं के जरिए अनुसंधान परिणामों के व्यासायिकरण, उद्योगों के साथ संयुक्त रूप से सहकारी अनुसंधान कार्यक्रमों को सम्भालने, प्रौद्योगिकी सूचना के प्रसार तथा उद्योगों को सामान्य प्रौद्योगिकी समर्थन प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

सतत् शिक्षा

7.33.1 "सतत् शिक्षा" योजना, कार्य कर रहे व्यवसायियों की इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में पाठ्यक्रम सामग्री तैयार करने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फरवरी, 1988 में शुरू की गई।

योजना के व्यापक रूप से दो पहलू हैं:

(i) उद्योग व अन्य प्रयोक्ता एजेन्सियों के परामर्श से पहचाने गए चुनिन्दा विषयों पर पाठ्य सामग्री तैयार करना।

(ii) सतत शिक्षा आवश्यकताओं का सर्वेक्षण करना जिनके आधार पर भविष्य में पाठ्य सामग्री तैयार की जानी है।

7.33.2 दस संगठनों अर्थात् दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, बम्बई तथा मद्रास स्थित पांच आई.आई.टी., चण्डीगढ़, कलकत्ता, मद्रास तथा भोपाल स्थित चार टी.टी.टी.आई. और भारतीय तकनीकी शिक्षा सोसाइटी द्वारा तैयार की जा रही सामग्री का समन्वय करना यह एक तीसरा तत्व है।

तकनीकी शिक्षा की विशिष्टिताएं

- अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम पारित हुआ और व्यय किया गया
- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के अपने ओर प्रायोजित अनुसंधानों के फलस्वरूप पेटेंटों का विकास और उद्योगों द्वारा उनका उपयोग
- अन्य इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी संस्थानों के साथ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों का निकटतम सम्पर्क
- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रवेश में सुधार के लिए विशेष प्रारंभिक पाठ्यक्रमों का संचालन
- गुवाहाटी में एक विस्तार केन्द्र सहित नौगांव के मीसा में (असम समझौते के अधीन) छठे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के स्थान के बारे में निर्णय
- जालंधर में क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज की स्वीकृति (शिक्षा-सत्र 1989-90 से कार्य प्रारंभ)
- गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के माध्यम से डाक्टरल स्नातकोत्तर, स्नातक आदि स्तरों पर शिक्षकों के सामूहिक प्रशिक्षण पर सतत बल
- महत्वपूर्ण और नई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सार्थक निवेश
- राष्ट्रीय तकनीकी जनशक्ति सूचना प्रणाली का पुनरावलोकन
- ग्रामीण विकास के लिए तकनीकी शिक्षा में उपयोग पर बल
- इंजीनियरी स्नातकों और डिप्लोमाधारियों के लिए सामूहिक प्रशिक्षुता प्रशिक्षिण + दो के व्यावसायिक विषयो के छात्रों के लिए प्रशिक्षुता प्रशिक्षण लागू करना
- आवासी पोलिटेक्निकों के माध्यम से महिलाओं के लिए औपचारिक और अनौपचारिक तकनीकी शिक्षा।

7.33.3 आशा है कि 1988-89 के अंत तक 137 पाठ्य-सामग्रियां तैयार हो जाएंगी।

नए संस्थानों की स्थापना तथा नए पाठ्यक्रमों/ कार्यक्रमों की शुरूआत

7.34.0 आलोच्य वर्ष के दौरान, भारत के विभिन्न

भागों में 15 नए पोलिटेक्निकों की स्थापना तथा विभिन्न संस्थानों में 55 नए पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों की शुरूआत को मंजूरी दी गई।

7.35.0 संक्षेप में, आलोच्य वर्ष के दौरान तकनीकी शिक्षा ने उल्लेखनीय प्रगति की। जहां तकनीकी शिक्षा का विस्तार तथा उसकी पहुंच बढ़ाने के लिए अनेक नई पहलें की गई हैं, वहां नई शिक्षा नीति में उल्लिखित निदेशों/लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुये, चल रहे कार्यक्रमों/योजनाओं को नया रूप तथा नई दिशा प्रदान की गई। कुल मिलाकर विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के लिए निर्धारित आवंटनों का अधिकतम उपयोग किया गया।

प्रौढ़ शिक्षा

(राष्ट्रीय साक्षरता मिशन)

8.1.0 समाज के वंचित वर्गों तथा देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लाभ के लिए वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिक अनुसंधान की उपलब्धियों का प्रयोग करने के उद्देश्य से साक्षरता की उन्नति को छः राष्ट्रीय मिशनों में से एक निर्धारित किया गया है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन (रा.सा.मि.) का उद्देश्य 15-35 आयु वर्ग में 8 करोड़ प्रौढ़ शिक्षार्थियों को—3 करोड़ को 1990 तक और अतिरिक्त 5 करोड़ को 1995 तक शिक्षित करना है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मिशन द्वारा विभिन्न उपाय अपनाने का प्रस्ताव है। यह चल रहे प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों का विकल्प नहीं है बल्कि इसका उद्देश्य नया संस्थागत ढांचा उपलब्ध कराकर और विद्यमान अवस्थापना का बेहतर सदुपयोग सुनिश्चित करके पहले के कार्यक्रमों की कुछ कमियों और बाधाओं को दूर करने के लिए दृढ़ प्रयास करना है। प्रधानमंत्री ने 5 मई, 1988 को राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में व्यापक जन सहयोग के लिए एक राष्ट्रीय अभियान प्रारम्भ किया था। साथ ही, सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने राज्य स्तर पर इसी प्रकार के अभियान प्रारम्भ किए। ऐसी सूचना है कि चौबीस राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजना

8.2.1 यह एक केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसके अन्तर्गत सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को अनुमोदित वित्तीय पद्धति के अनुसार शत-प्रतिशत आधार पर निधियां प्रदान की जाती हैं। ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजनाओं को निधियां प्रदान करने की पद्धति की समीक्षा की गई है और इसमें संशोधन किया गया है और नई पद्धति 1.4.88 से लागू है। संशोधित पद्धति में पर्यवेक्षण अवधि कम कर दी गई है। इस योजना का उद्देश्य 300 केन्द्रों तक की परियोजनाएं स्थापित करने का है, जिनमें प्रत्येक जिले में एक या दो निकटवर्ती विकास खण्ड तथा कुछ राज्यों के पहाड़ी क्षेत्र में 100 केन्द्र तक शामिल होंगे। 1988-89 के दौरान देश के लगभग सभी जिलों को शामिल करने वाली 513 परियोजनायें जारी रहीं। सितम्बर, 1988 के अंत तक 1,32,291 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों में ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता योजना के अंतर्गत कुल मिलाकर 39.40 लाख प्रौढ़ निरक्षर लोगों को दाखिल किया गया। इनमें से, महिलाएं 57.50% हैं और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्य क्रमशः 25.63% और 13.8% हैं।

8.2.2 ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजना के अन्तर्गत संस्वीकृत प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों के अलावा, राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों ने भी सितम्बर, 1988 के अंत तक राज्य प्रौढ़ शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत 109218 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र खोले हैं जिनमें 32.87 लाख शिक्षार्थी हैं।

स्वैच्छिक एजेंसियां

8.3.1 प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही स्वैच्छिक एजेंसियों को यह मंत्रालय वित्तीय सहायता प्रदान करता हैं जिसके अंतर्गत पंजीकृत सोसाइटियां, जनशिक्षण निलयम, संसाधन विकास, प्रकाशन, सेमिनार आयोजन इत्यादि के माध्यम से कार्यात्मक साक्षरता, उत्तर साक्षरता परियोजनाओं के लिए अनुदान प्राप्त करने की पात्र होती हैं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में

परिकल्पित नीतियों के अनुसरण में विभिन्न नियमों को सरल बनाकर योजना को उदार और कारगर बनाया गया है। क्षेत्र विकास की अवधारणा, संशोधित योजनाओं में शामिल की गई है जिससे स्वैच्छिक एजेंन्सियां एक निश्चित समय में और पूर्ण तथा सटे हुये क्षेत्र में कार्यात्मक साक्षरता परियोजनायें प्रारम्भ कर सकेंगी।

8.3.2 चालू वर्ष में नवम्बर, 1988 तक 11,415 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों और 964 जन शिक्षण निलयमों को चलाने के लिए लगभग 200 स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता दी गई जिसमें 7.42 करोड़ रुपये खर्च हुये।

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों में छात्र सहयोग

8.4.1 15-35 आयु वर्ग में साक्षरता संबंधी कार्यों में विश्वविद्यालयों तथा कालेजों के छात्रों और शिक्षकों के सहयोग को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध प्रौढ़ तथा सतत शिक्षा निदेशालय के माध्यम से प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र स्थापित करने के लिए 92 विश्वविद्यालयों और कालेजों को वित्तीय सहायता देना जारी रखा।

8.4.2 इसके अतिरिक्त सरकार ने स्वैच्छिक आधार पर कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए पहली मई, 1986 को एक कार्यक्रम आरंभ किया जिसमें विश्वविद्यालयों और कालेजो के लगभग 2 लाख राष्ट्रीय सेवा योजना के और 1 लाख गैर-राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्र शामिल हुये। राज्य संसाधन केन्द्रों द्वारा छात्रों को निःशुल्क साक्षरता किटें प्रदान की गईं। यह कार्यक्रम स्वैच्छिक प्रयत्न के रूप में पूर्णरूपेण छात्रों द्वारा कार्यान्वित किया जाना है। कार्यात्मक साक्षरता के व्यापक कार्यक्रम (एम.पी.एफ.एल.) में 3.50 लाख राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्रों, 1.50 लाख अन्य छात्रों तथा 0.75 लाख एन.सी.सी. कैडेटों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया।

राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में प्रशासनिक ढाँचे को सुदृढ़ करना

8.5.0 प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, योजना के अन्तर्गत अनुमोदित वित्तीय पद्धति के अनुसार राज्य और जिला दोनों स्तरों पर आवश्यक प्रशासनिक ढांचे को जारी रखने/सृजित करने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सन् 1987 में इस योजना में संशोधन किया गया है और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कार्यक्रम के उचित कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण और मानीटरिंग के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को राज्य और जिला, दोनों स्तरों पर अतिरिक्त कर्मचारी मंजूर किये गये। वर्तमान में 26 राज्य/संघ शासित क्षेत्र वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हैं। योजना का मुख्य उद्देश्य बुद्धिमान, ज्ञानी और सक्षम लोगों का एक कैडर बनाना है जिनमें प्रौढ़ शिक्षा के प्रति उचित बोध और प्रतिबद्धता हो।

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का मूल्यांकन

8.6.0 प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए इसका बाह्य मूल्यांकन एक महत्वपूर्ण निवेश है। देश के 12 राज्यों में कार्यक्रम की समीक्षा और मूल्यांकन करने के लिए सोलह विख्यात समाज विज्ञान अनुसंधान संस्थानों की पहचान की गई है, बाद में इन्हें और राज्यों में बढ़ाया जाएगा। अब तक इस प्रयोजनार्थ 6 मूल्यांकन एजेंसियों को वित्तीय सहायता दी गई है।

राज्य संसाधन केन्द्रों के माध्यम से शैक्षिक तथा तकनीकी सहायता प्रदान करना

8.7.1 कुल मिलाकर 13 राज्य संसाधन केन्द्र है जिनका वित्त पोषण शिक्षा विभाग द्वारा किया जाता है और वे बुनियादी, उत्तर साक्षरता और सतत शिक्षा के लिए सामग्री का निर्माण करके और प्रशिक्षण प्रदान करके प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को आवश्यक शैक्षिक और तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त 2 राज्य संसाधन केन्द्र राज्य सरकारों द्वारा तथा 3 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा चलाये जा रहे हैं। इसके अलावा मणिपुर, त्रिपुरा, अरूणाचल प्रदेश और सिक्किम के लिए 4 अनुसंधान सैल स्वीकृत किये गये जिनमें से मणिपुर और अरूणाचल प्रदेश में 2 सैल औपचारिक रूप से स्थापित किये जा चुके है। राज्य संसाधन केन्द्र स्वायत्त निकाय हैं जिनका प्रबंध उनके प्रबंध बोर्ड द्वारा किया जाता है। उपरोक्त 13 राज्य संसाधन केन्द्रों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा 80% अनुदान, राज्य सरकार द्वारा 15% और स्वैच्छिक एजेंसियों द्वारा 5% अनुदान के साथ वित्त पोषण पद्धति निर्धारित की गई है। राज्य संसाधन केन्द्रों ने कार्यात्मक साक्षरता जन कार्यक्रम के अन्तर्गत किट सामग्री के निर्माण तथा मास्टर प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण का अतिरिक्त उत्तरदायित्व भी लिया है। उन्होंने प्रौढ़

MASS CAMPAIGN
FOR
NATIONAL LITERACY
MISSION
LAUNCHING
MAY 5, 1988

1988

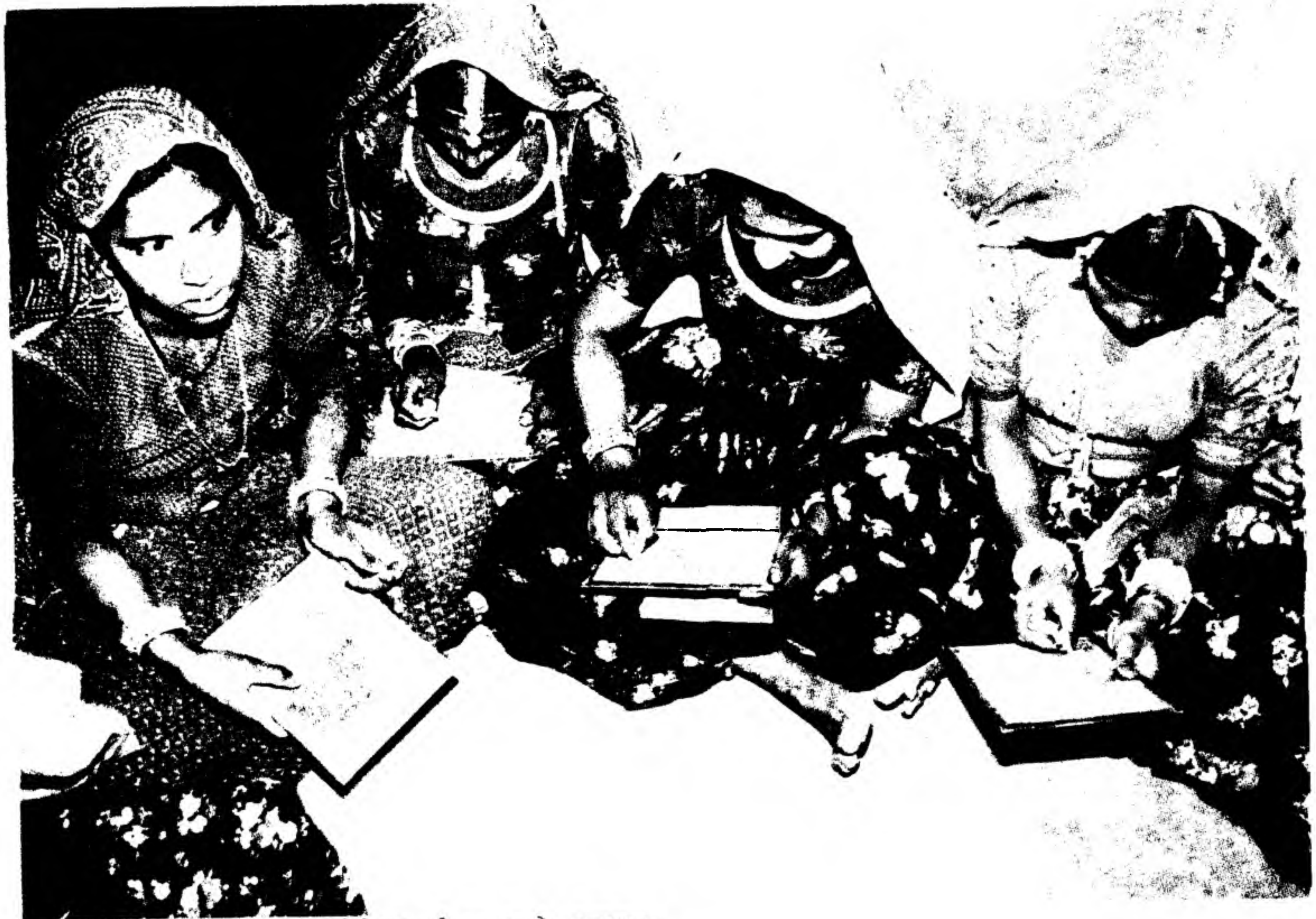

इंदिरा गांधी प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र, खानाखेड़ी ग्राम, श्रीनगर, अजमेर, राजस्थान।

नानु बाज़ार डोंगा आदिवासी प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र, मोहम्मद बाजार ब्लाक, जिला बीरभूम, पश्चिम बंगाल।

शिक्षा कार्यक्रम के लिए आवश्यक प्रचार माध्यम सहायता प्रदान करने के लिए सॉफ्टवेयर का विकास कार्य भी शुरू किया है।

8.7.2 एक विशेषज्ञ द्वारा सभी राज्य संसाधन केन्द्रों के कार्यकरण की समीक्षा की गई है और उपचारात्मक कदम उठाये जा रहे हैं। और अधिक विकेन्द्रीकरण के उपाय के रूप में तथा प्रारम्भिक स्तर पर संसाधन सहायता सुदृढ़ करने के लिए 110 जिला संसाधन इकाइयों के लिए संस्वीकृति दी गई है।

कार्यात्मक साक्षरता के लिए जन कार्यक्रम (एम.पी.एफ.एल.)

8.8.0 राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की एक मुख्य नीति जन-आन्दोलन चलाना है ताकि साक्षरता को लोगों का मिशन बनाया जा सके और इस मिशन के लिए सभी एजेन्सियों का उपयोग किया जा सके। कार्यात्मक साक्षरता जन कार्यक्रम में पहले ही संलग्न किये गये विश्वविद्यालय और कालेज छात्रों के अलावा, इस कार्यक्रम के आधार को विस्तृत करने के लिए इस वर्ष शुरूआत की गई है। अब तक उठाये गये महत्वपूर्ण कदम इस प्रकार है:–

(i) केन्द्रीय नियोक्ताओं और मजदूर संघों का एक सम्मेलन 7.7.1988 को हुआ ताकि उनकी सहभागिता की पद्धतियों पर विचार कर अंतिम रूप दिया जा सके। ये संगठन अपने फेडरेशन/संघ के साथ इस बात पर विचार कर रहे है कि किस प्रकार ये संगठन साक्षरता कार्यक्रमों में सहायता दे सकते हैं।

(ii) रेलवे बोर्ड ने 9 रेलवे जोनों के विभिन्न स्थानों पर खोले जाने वाले 425 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों के माध्यम से अपने कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी ली। साक्षरता किटों और प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण को आयोजित करने के प्रावधान के लिए निधियां शिक्षा विभाग द्वारा दी गई और शेष रेलवे द्वारा दी गईं। क्षेत्रीय रेलवे द्वारा विस्तृत कार्य योजनायें तैयार की गईं।

(iii) सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के गृह सचिवों और पुलिस महानिरीक्षकों (जेल) से, बंदियों (विचाराधीन तथा आजीवन कारावास से दण्डित दोनों), जो कि प्रौढ़ (15-35 आयु वर्ग के) हों, के लिए कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम आयोजित करने का अनुरोध किया गया है। केन्द्रीय गृह मंत्री ने इस संबंध में सभी मुख्य सचिवों को लिखा।

(iv) गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद ने मई-जून, 1988 में एक साक्षरता अभियान आरम्भ किया, जिसमें 2,60,000 स्वयंसेवी छात्र थे और यह अभियान 1,45,000 लोगों के लिए था।

(v) महानगर दिल्ली, में साक्षरता मिशन में स्कूल के छात्रों को शामिल करने के लिए शुरूआत की गई। 8 सितम्बर, 1988 को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर सात हजार स्कूली छात्रों ने निरक्षरता समाप्त करने की राजघाट पर शपथ ली। इन्दिरा गांधी स्टेडियम में राष्ट्रीय स्तर पर एक समारोह आयोजित किया गया जिसमें 10,000 छात्रों ने भाग लिया। तब से दिल्ली के 78 स्कूलों ने स्वयं को इस कार्यक्रम में शामिल किया।

उत्तर साक्षरता और सतत् शिक्षा:

8.9.0 फरवरी, 1988 में, सरकार ने, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्रलेख में उल्लिखित, देश भर में एक चरणबद्ध रूप में जन-शिक्षण निलयमों की स्थापना का निर्णय किया। यह उत्तर-साक्षरता और सतत शिक्षा का स्थायी आधार पर एक संस्थागत ढांचा है। इस प्रकार का ढांचा प्रदान करने का मुख्य लक्ष्य, साक्षरता कौशल का अनुरक्षण सुनिश्चित करना, प्रारम्भिक साक्षरता से आगे अपने अध्ययन को जारी रखने के लिए शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने हेतु सुविधाओं का प्रावधान करना और उन्हें अपने रहन-सहन में सुधार के लिए अपनी शिक्षा के अनुप्रयोग के पर्याप्त अवसर प्रदान करना है। ये जन-शिक्षण निलयम सांस्कृतिक ओजस्व और सृजनात्मकता को पुनः स्थापित करेंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में उनको काम में लगायेंगे एवं एक शिक्षित समाज के निर्माण में सहायक होंगे। अब तक सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में 10,065 जन शिक्षण निलयमों को संस्वीकृत किया गया है। इनको स्थापित करने की कार्रवाई चल रही है। ऐसी आशा है कि चालू वर्ष के दौरान, 4300 और जन शिक्षण निलयमों को संस्वीकृत किया जाएगा।

प्रौद्योगिकी प्रदर्शन

8.10.1 प्रौद्योगिकी प्रदर्शन की प्रक्रिया में साक्षरता

कार्यक्रम की प्रगति ओर गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय अनुसंधान की उपलब्धियों के अनुप्रयोग की अपेक्षा की गई हैं। तकनीकी शैक्षणिक निवेशों के विकास, अन्तरण और अनुप्रयोग के लिए 40 जिलों को चुना गया है। इनमें से 20 को इन जिलों में उपलब्ध अवस्थापना के संदर्भ में कम साधन प्रदान किये गये है और शेष 20 को पर्याप्त साधन प्रदान किये गये हैं।

8.10.2 विभिन्न तकनीकी शैक्षणिक निवेशों के विकास और अनुप्रयोग के लिए जो कदम उठाये गये हैं, वे निम्नलिखित है:—

* गैर-परम्परागत ऊर्जा विभाग ने, 5 जिलों के बिजली-रहित ग्रामों में सौरशक्ति पैक्स के अधिष्ठापन की एक मुख्य परियोजना शुरू कर दी है। अब तक अलीगढ़, बीकानेर और उस्मानाबाद जिलों में, 93 सौर-शक्ति पैक्स अधिष्ठित किये गये हैं।
* भारतीय पैट्रो-केमिकल लि. (आई.पी.सी.एल.) ने उन्नत प्लास्टिक ब्लैक बोर्डों का निर्माण किया है। इस तरह के 1000 आदर्श ब्लैकबोर्डों का गुजरात और महाराष्ट्र में क्षेत्रपरीक्षण किया जा रहा है।
* केन्द्रीय इलैक्ट्रानिक लिमिटेड (सी.ई.एल.) ने राजस्थान और कर्नाटक में अपने टी.वी. प्रक्षेपण का क्षेत्र-परीक्षण किया और उसके संतोषजनक परिणाम निकले।
* सामान्यतः राष्ट्रीय साक्षरता मिशन और विशेषतया प्रौद्योगिकी प्रदर्शन प्रक्रिया के निमित विज्ञान और प्रौद्योगिकी निवेशों हेतु आर. एण्ड डी. के लिए सलाह देने हेतु प्रौद्योगिकी प्रदर्शन संबंधी एक पैनल गठित किया गया।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण :

8.11.0 जून, 1988 में एक राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण की स्थापना एक संकल्प द्वारा की गई। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) का एक स्वतंत्र और स्वायत्त खंड है और इस के कार्यक्षेत्र में कार्यकारी और वित्तीय शक्तियां निहित हैं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में परिकल्पित सभी कार्यों के निष्पादन और कार्यान्वयन के लिए यह प्राधिकरण एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण की एक समिति और एक कार्यकारिणी समिति है जिन्हें जून, 1988 में जारी की गई एक अधिसूचना द्वारा गठित किया गया है। समिति और कार्यकारिणी समिति की कई बैठकें हो चुकी हैं और इन बैठकों में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन से संबंधित कई महत्वपूर्ण विषयों पर विचार किया गया, जो ये हैं:—

(i) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की विवेचनात्मक समीक्षा।
(ii) माध्यमिक और उच्चतर साध्यमिक स्तर के स्कूल-छात्रों को शामिल करते हुये इसके लिए सामूहिक रूप से प्रेरित करना।
(iii) राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान की स्थापना।
(iv) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों का प्रत्यायोजन।
(v) प्रौद्योगिकी प्रदर्शन प्रक्रिया।
(vi) दूरदर्शन-वीडियो कैसेट प्लेयर द्वारा साक्षरता प्रदान करना।
(vii) साक्षरता जत्थों या साक्षरता कारवां का आयोजन।

पोस्ट आफिस बाक्स नं. 9999:—

8.12.0 केन्द्रीय और राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों को डाक विभाग द्वारा एक सामूहिक पोस्ट बाक्स नं. 9999 आर्वटित किया गया है। कोई भी प्रौढ़ निरक्षर जो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कार्यक्रम की सुविधाएं और सेवाएं प्राप्त करना चाहता है, या कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की सफलता के लिए किसी भी प्रकार का योगदान देना चाहता है, वह इस पोस्ट-बाक्स को लिख सकता है और उसे सकारात्मक उत्तर प्राप्त होगा। इस पोस्ट-बाक्स को राष्ट्रीय स्तर पर पहले ही क्रियाशील बनाया गया है और इसे राज्य और जिला स्तर पर भी याथासमय क्रियाशील बनाने की कार्रवाई चल रही है।

श्रमिक विद्यापीठ

8.13.1 देश भर में विभिन्न औद्योगिक केन्द्रों में इस समय 36 श्रमिक विद्यापीठ कार्य कर रहे हैं जो कि रोजगार प्राप्त कार्मिकों, स्व-रोजगार प्राप्त व्यक्तियों, भावी कार्मिकों और औद्योगिक कार्मिकों के पारिवारिक सदस्यों के लिए अनौपचारिक, सतत शिक्षा और बहु संयोजक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने के लिए

संस्थागत ढांचे का प्रतिनिधित्व करते हैं ताकि बेरोजगार लोगों को रोजगार के अवसर सुलभ हों और रोजगार प्राप्त कार्मिकों के लिए अर्जन-क्षमता में वृद्धि हो। श्रमिक विद्यापीठ उन लोगों के लिए एकमात्र संस्थाएं हैं जिनकी शैक्षिक अर्हताएं बहुत कम हैं और जिनकी आय कम है और वे किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या इंजीनियरी संस्थान में प्रवेश प्राप्त नहीं कर सकते। पहले श्रमिक विद्यापीठ की स्थापना 1967 में बम्बई में की गई। इस समय कार्यरत 36 श्रमिक विद्यापीठों में से, केवल एक का संचालन, दिल्ली में केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जा रहा है। तीन श्रमिक विद्यापीठों का संचालन विश्वविद्यालयों द्वारा, 23 श्रमिक विद्यापीठों का संचालन स्वायत्त संगठनों द्वारा और शेष नौ का राज्य सरकारों द्वारा संचालन किया जा रहा है।

8.13.2 प्रत्येक विद्यापीठ का कार्य-प्रबन्ध, एक प्रबन्ध बोर्ड द्वारा किया जाता है जिसका अध्यक्ष एक मानद अध्यक्ष होता है। इस बोर्ड के सदस्य वे लोग हैं जो कामगारों और नियोजकों के हितों का तथा, प्रौढ़ों की एक विशेष इकाई के रूप में, कामगारों की शिक्षा और प्रशिक्षण में रूचि प्रदर्शित करने वाली शैक्षिक, सामाजिक और विकास एजेन्सियों और व्यक्तियों के हितों का प्रतिनिधित्व करते है। प्रत्येक श्रमिक विद्यापीठ में व्यावसायिक स्टाफ का एक केन्द्र होता हैं जो कि एक निदेशक के नियंत्रणाधीन होता है जिसे दो या तीन पूर्णकालिक कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा सहायता दी जाती है। विभिन्न पाठ्यक्रमों को आयोजित करने के लिए प्रत्येक श्रमिक विद्यापीठ, विशिष्ट क्षेत्रों के लिए अनुकूल पाठ्यक्रमों को अंशकालिक आधार पर आयोजित करने या विभिन्न दक्षताएं प्रदान करने के लिए, स्थानीय योग्य और अनुभवी संसाधन व्यक्तियों की सेवाएं प्राप्त करता है। इन प्रशिक्षकों को, उनके द्वारा दिए गए प्रत्येक व्याख्यान के लिए मानदेय दिया जाता है।

8.13.3 कार्यक्रम तैयार करने से पूर्व सभी श्रमिक विद्यापीठों में कार्यकलापों के प्रचालन के लिए एक सामाजिक-आर्थिक रूपरेखा और कार्य योजना तैयार की गई है। सम्बद्ध औद्योगिक आवाह क्षेत्रों की सामाजिक-आर्थिक रूपरेखा ऐसे मानदण्ड प्रदान करती है जिनके अन्तर्गत श्रमिक विद्यापीठ अपने कार्यक्रमों का प्रचालन करेंगे। इन रूपरेखाओं ने शहरी परिवेश की जनशक्ति आवश्यकताओं और औद्योगिक कार्मिका की अर्जन-क्षमता और संसाधनों (अंतर्निहित और अप्रयुक्त), जिन्हें कि काम में लाया जा सकता है, में वृद्धि करने से संबंधित विशेष आवश्यकताओं की, श्रमिक विद्यापीठों को पूरी जानकारी देने में सहायता की है।

8.13.4 ये कार्यक्रम, पाठ्यक्रम कार्यकलापों और अनुवर्ती सेवाओं के रूप में प्रदान किये जाते है, जिनमें से सभी कार्यक्रम प्रौढ़ शिक्षा कार्यकर्ताओं, संगठित और असंगठित क्षेत्र में निरक्षर, अर्धशिक्षित, कुशल, अर्धकुशल, अकुशल, स्त्री और पुरूषों के लिए विशेष सेवाएं प्रदान करते हैं। कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए श्रमिक विद्यापीठ विभिन्न स्थानीय एजेंसियों, ट्रेड-यूनियनों, औद्योगिक संस्थाओं, कल्याण-केन्द्रों, विकास एजेन्सियों और वित्तीय सहायता एजेन्सियों से सहयोग/सहायता प्राप्त करते हैं। यह प्रक्रिया अन्य एजेंसियों के पास उपलब्ध संसाधनों के उपयोग जैसे परिसर के प्रयोग, प्रशिक्षकों की सेवाओं, औजारों और उपस्करों के प्रयोग और कार्य के निरीक्षण और प्रबन्ध के बंटवारे, जो कि अन्यथा बहुत मंहगा पड़ेगा, के रूप में सहायता करती है।

8.13.5 मंत्रालय में, श्रमिक विद्यापीठों के निष्पादन का विषयानुसार विवेचनात्मक अध्ययन करने के लिए एक टीम गठित की गई है। श्रमिक विद्यापीठों के निदेशकों और कार्यक्रम अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण चक्र का गठन किया गया है। प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, नई दिल्ली में अभी तक, श्रमिक विद्यापीठ के निदेशकों और कार्यक्रम अधिकारियों के लिए, श्रमिक विद्यापीठों में प्रशिक्षण कक्षाएं आयोजित करने के लिए, उपागम के पुनर्अभिविन्यास हेतु तीन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं। उन्नत निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए त्वरित निवेशन प्रदान करने की प्रणाली विकसित की गई है। प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, दिल्ली ने श्रमिक विद्यापीठों द्वारा, अपने चल रहे कार्यक्रमों के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए विशिष्ट प्रपत्र निर्धारित किये हैं।

8.13.6 श्रमिक विद्यापीठों को वित्तीय सहायता देने की योजना के अंतर्गत, कार्यक्रमों को चलाने और स्टाफ कर्मचारियों के वेतन से संबंधित व्यय को वहन करने के लिए प्रारम्भिक राशि (3.5 लाख रूपये) प्रदान की गई है। सभी श्रमिक विद्यापीठों को अपने कार्यक्रमों को विस्तृत और सुदृढ़ करने के लिए और अपने संसाधनों को विकसित करने के लिए कहा गया है। श्रमिक विद्यापीठों के लिए वित्तीय सहायता पद्धति पर पुनर्विचार किया

गया है और मामला अनुमोदन के लिए व्यय वित्त समिति के समक्ष रखा गया है।

8.13.7 इस समय उस समेकित प्रभाव का अनुमान लगाने के लिए एक आंकड़ा आधार तैयार करने पर बल दिया जा रहा है जो प्रत्येक श्रमिक विद्यापीठ का अपने अनुयायियों के रहन-सहन की परिस्थितियों को सुधारने में पड़ा है। ऐसा करते समय श्रमिक विद्यापीठ अपने भूतपूर्व शिक्षार्थियों की वर्तमान स्थिति के बारे में अनुवर्ती कार्रवाई करेंगे ताकि यह जाना जा सके कि जो प्रशिक्षण उन्होंने श्रमिक विद्यापीठ में लिया था उससे उनकी आय बढ़ाने में कहां तक सहायता मिली है।

8.13.8 1987-88 के दौरान श्रमिक विद्यापीठ में 5862 कार्यक्रम चलाये गये जिनमें से 3467 व्यावसायिक पाठ्यक्रम थे तथा 2395 अन्य कार्यक्रम थे। इन पाठ्यक्रमों तथा कार्यक्रमों से लाभान्वित व्यक्तियों का अलग-अलग ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

(i) व्यावसायिक पाठ्यक्रमों तथा अन्य गतिविधियों से लाभान्वित कुल व्यक्तियों की संख्या = 2,30,156
- पुरुष = 88,272 (33.35%)
- महिलाएं = 1,41,884 (61.65%)

(ii) व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में कुल लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या = 67,785
- पुरुष = 22,935 (33.83%)
- महिलाएं = 44,850 (66.17%)

जोड़ : = 2,30,156

(iii) व्यावसायिक पाठ्यक्रमों से भिन्न अन्य गतिविधियों में लाभान्वित व्यक्तियों की कुल संख्या = 1,62,371
- पुरुष = 65,924 (40.60%)
- महिलाएं = 96,447 (59.40%)

उपयुक्त मद 2 का अलग-अलग ब्यौरा

I. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सहभागिता

अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति	अन्य
13,809 (20.37%)	2,513 (3.71%)	51,463 (75.92%)

II साक्षरता स्तर

कुछ शिक्षा सहित	निरक्षर
55,485 (81.85%)	12,300 (18.15%)

III आयु वर्ग

15 वर्ष से नीचे	15-35 वर्ष	35 वर्ष से ऊपर
2,951 (4.35%)	60,798 (89.70%)	4,036 (5.95%)

IV आय संबंधी पृष्ठभूमि

500/- रु. प्रतिमाह से नीचे	500-1500 रु. प्रतिमाह	1500/- रु. प्रतिमाह
44,571 (65.75%)	20,666 (30.49%)	2,548 (3.76%)

V व्यावसायिक व्यवस्था

औद्योगिक तथा श्रमजीवी	स्व. रोजगार प्राप्त	भावी कामगार
9,060 (13.37%)	15,069 (22.23%)	43,656 (64.40%)

अंतर्राष्ट्रीय और यूनेस्को मामले

8.14.1 सभी के लिए एशिया प्रशान्त महासागर शिक्षा कार्यक्रम, (स.ए.प्र.म.शि.का.) फरवरी 1987 में शुरू किया गया जिसका उद्देश्य निरक्षरता उन्मूलन, प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना तथा एशिया तथा प्रशान्त महासागर क्षेत्र में सतत शिक्षा के लिए अवस्थापना को सुदृढ़ करना है। स.ए.प्र.म.शि.का. संबंधी एक राष्ट्रीय समन्वय समिति इस देश में आरम्भ की गई गतिविधियों का मूल्यांकन करने के लिए गठित की गई है ताकि नये कार्यक्रम बनाये जा सकें तथा इसके कार्यान्वयन के लिए कार्यनीतियां भी तैयार की जा सकें।

8.14.2 संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भी 1990 को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष के रूप में घोषित किया है। स.ए.प्र.म.शि.का. संबंधी समन्वय समिति अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष मनाने के लिए नीतियां तैयार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष संबंधी समन्वय समिति के रूप में भी कार्य करेगी। इस वर्ष के दौरान अब तक समिति की दो बार बैठकें हो चुकी हैं। यूनेस्को के महानिदेशक ने भी दिसम्बर, 1988 में भारत में अपने दौरे के दौरान इस समिति के सदस्यों को संबोधित किया था।

8.14.3 प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय के एक प्रतिनिधि ने थाईलैंड तथा चीन में 1-23 अगस्त, 1988 को हुई प्रशिक्षण सामग्री के विकास संबंधी क्षेत्रीय कार्यशाला में भाग लिया था।

8.14.4 अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष संबंधी कार्यदल की एक बैठक 10-14 अक्तूबर, 1988 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। इसमें अफगानिस्तान, बंगलादेश, इण्डोनेशिया, भारत, ईरान, नेपाल तथा पाकिस्तान के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यदल की अध्यक्षता (भारत के प्रतिनिधि) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण के महानिदेशक ने की।

8.14.5 यूनेस्को ने 14-18 नवम्बर, 1988 तक बैंकाक में स.ए.प्र.म.शि.का. की क्षेत्रीय समन्वय समिति की बैठक का भी आयोजन किया जिसमें राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, नई दिल्ली के महानिदेशक ने भाग लिया।

8.14.6 2-11 नवम्बर, 1988 तक सिडनी, आस्ट्रेलिया में हुये प्रौढ़ शिक्षा में सरकार की भूमिका संबंधी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय के निदेशक को भेजा गया।

प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय

8.15.1 प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय शीर्ष संसधन केन्द्र है। इसने व्यावसायिक संसाधन सहायता तथ सभी स्तरों पर कार्यक्रम के उन्नत प्रबंध के लिए तंत्र तैयार करने के कई उपाय शुरू किये हैं।

8.15.2 तीव्र साक्षरता अध्ययन पद्धतियों को शुरू करने के प्रयास इस वर्ष के दौरान भी जारी रहे। वर्ष के दौरान देश के विभिन्न भागों में तीव्र साक्षरता के क्षेत्र तथ सम्भावनाओं का अध्ययन करने के लिए तीन कार्यशालाएं आयोजित की गई। कार्यशालाओं की सिफारिशों के आधार पर तीव्र साक्षरता अध्ययन पद्धतियों पर मार्ग-निर्देशिकाएं तैयार करने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई शुरू की गई है। इस प्रयास का उद्देश्य कार्यक्षमता तथा जागरूकता के तत्वों को गंवाये बिना अध्ययन की समग्र अवधि को कम करना, अध्ययन की गति को तेज करना तथा कम समय में उच्च-प्रसार को प्राप्त करना है।

8.15.3 सम्पूर्ण प्रोत्साहन प्रयास में साक्षरता के निर्धारित स्तरों तथा संख्या को प्राप्त करने पर बल दिया जाना है, न कि अधिक प्रसार पर। अध्ययन परिणाम के मूल्यांकन के विभिन्न मानदण्डों एवं सीमाओं पर एक कार्यशाला भी आयोजित की गई।

8.15.4 बोलचाल की भाषाओं में साक्षरता प्रदान करने के लिए, उन भाषाओं की पहचान के लिए एक कार्यशाला आयोजित की गई जिनपर पठन-पाठन सामग्री तैयार की जानी है

8.15.5 अब तक निम्नलिखित बोलचाल की भाषाओं में पठन-पाठन सामग्रियां तैयार की गई हैं :—

हाल्बी	मध्य प्रदेश
भीली	मध्य प्रदेश
नागपुरिया	बिहार
ब्रज	उत्तर प्रदेश
ढुंढाड़ी	राजस्थान
मारवाड़ी	राजस्थान
हाड़ोती	राजस्थान
डोगरी	हिमाचल प्रदेश
चमियाली	हिमाचल प्रदेश
किन्नोरी	हिमाचल प्रदेश

8.15.6 जैसा कि एम. आई. एस. और मूल्यांकन पर कार्यदल द्वारा सिफारिश की गई थी, मानीटरिंग और मूल्यांकन की मौजूदा प्रणाली की समीक्षा की गई है। नए एम. आई. एस. के प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एन. आई. आई. टी.) के सहयोग से एक सम्भाव्यता अध्ययन चलाया गया था। पूर्व-जांच के बाद एम. आई. एस. प्रपत्र तैयार कर लिया गया है और उसे अन्तिम रूप दिया जा चुका है। प्रपत्रों का भौतिक और संगणीकृत दोनों प्रकार का संकलन किया जा सकेगा। 40 टी. डी. जिलों में इस प्रयोजन के लिए स्थापित किये जाने वाले कम्प्यूटरों के प्रयोग के जरिए डी.ए.ई.ओ. के कार्यालयों में सूचना संकलित की जाएगी।

8.15.7 निदेशालय ने राज्य संसाधन केन्द्रों के कार्यकलापों को मानीटर करना और इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन से संबंधित सूचना का प्रसार करना जारी रखा।

8.15.8 आलोच्य वर्ष के दौरान 9 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये थे जिनमें 6 कार्यक्रम डी. ए. ई. ओ. के लिए, 2 एम. पी. एफ. एल. के तहत एन. एस. एस. और गैर एन. एस. एस. के प्रशिक्षणार्थियों के लिए और एक डी. ए. ई. तथा एस. आर. सी. निदेशकों के लिए हैं। इन कार्यक्रमों में जिस मूल विषय पर चर्चा की गई वह था, प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को कैसे संचालित किया जाये।

8.15.9 चूंकि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्रलेख में प्रचार मीडिया सहायता से प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम पर बल दिया गया है, इसलिए मीडिया एजेन्सियां जैसे आकाशवाणी, दूरदर्शन, दृश्य-श्रव्य प्रचार निदेशालय, गीत एवं नाटक प्रभाग आदि का, जनता के बीच उत्प्रेरणा और सही परिप्रेक्ष्य विकसित करने की दृष्टि से प्रौढ़ शिक्षा पर अधिक कार्यक्रमों का प्रसारण करने के लिए उपयोग किया जा रहा है ताकि वह सहायता कर सके और उसमें भाग ले सके।

8.15.10 निदेशालय को आलोच्य वर्ष के दौरान प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में 42 नए शोध प्रस्ताव प्राप्त हुए। एक शोध रिपोर्ट प्राप्त हुई और तीन सारांश रिपोर्टें तैयार की गई तथा सभी को सूचना प्रसारित की गई। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं पर आठ शोध अध्ययन शुरू करने के लिए विभिन्न वैयक्तियों और संगठनों को 5, 33, 252/- रुपये कुल अनुदान स्वीकृत किया गया।

8.15.11 जनसंख्या शिक्षा पर 1986 में शुरू की गई यू. एन. एफ. पी. ए. से सहायता प्राप्त परियोजना इस वर्ष के दौरान भी जारी रही। इस परियोजना के अंतर्गत, वर्ष के दौरान की गई प्रगति की समीक्षा के लिए निदेशालय ने दो प्रगतिशील परियोजना रिपोर्ट संबंधी बैठकें आयोजित कीं।

8.15.12 लड़कियों और महिलाओं की अनौपचारिक शिक्षा की यूनीसेफ से सहायता प्राप्त परियोजना के अंतर्गत वर्ष के दौरान शुरू किये गये कार्यकलाप निम्नलिखित थे :

- 8 वीडियो मॉड्यूल (संख्या 16-20) प्रवेशिका 'खिलती कलियां' तैयार करना जो यूनीसेफ से सहायता प्राप्त परियोजना "महिलाओं और लड़कियों के लिए अनौपचारिक शिक्षा" के तहत पहले तैयार की गई थी।
- राज्य संसाधन केन्द्र जम्मू और कश्मीर द्वारा जन शिक्षण निलयमों और महिलाओं के लिए प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों को सहायता के लिए उर्दू की पन्द्रह पाण्डुलिपियों में से प्रत्येक की 40,000 प्रतियों का अनुलिपिकरण। ये पाण्डुलिपियां स्वास्थ्य-समस्याओं और महिलाओं, बच्चों व लड़कियों की पोषण आवश्यकताओं तथा सुरक्षित पेयजल आदि से संबंध रखती हैं।

8.15.13 आलोच्य वर्ष के दौरान निदेशालय ने प्रधानमंत्री द्वारा 5.5.1988 को राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के जन अभियान को प्रारम्भ करने के अवसर पर और 8.9.1988 को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस समारोह के अवसर पर भी काफी तादाद में प्रकाशन निकाले।

8.15.14 प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय की द्विभाषी मासिक पत्रिका न्यूज़लेटर (अब अगस्त 1988 के अंक से "साक्षरता मिशन" के नाम से ज्ञात) को हर महीने नियमित रूप से प्रकाशित करना जारी रखा गया।

8.15.15 देश भर के सृजनात्मक कलाकारों को प्रौढ़ साक्षरता में दृश्य-उत्प्रेरक सामग्री तैयार करने में प्रेरणा और प्रोत्साहन देने के मुख्य प्रयोजन सहित छठी राष्ट्रीय पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित की गई। चयनित पोस्टरों को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष 1990 में आयोजित होने वाली प्रतिस्पर्धा में भाग लेने के लिए यूनेस्को, पेरिस भेजा जाएगा।

प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय ने विदेशी उच्चाधिकारियों की अगवानी की और उनके लिए निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किये गये :-

- मालावी से तीन प्रौढ़ों के लिए संयोजन प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- मालदीव से स्कूल से बाहर जनसंख्या शिक्षा के एक प्रौढ़ शिक्षक का स्थापन प्रशिक्षण।
- प्रौढ़ शिक्षा और जनसंख्या शिक्षा में सोमालिया से तीन महिला प्रौढ़ शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम
- यूनीसेफ कार्यक्रम 1984-88 के तहत अंतराष्ट्रीय पर्यावरणीय शिक्षा कार्यक्रम के मूल्यांकन के संबंध में अवकाश प्राप्त प्रोफेसर हॉन क्रोक्केट स्मिथ प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय में आए।
- यूनीसेफ मुख्यालय न्यूयार्क के कार्यक्रम निदेशक श्री न्यी-न्यी 28 अक्तूबर, से 3 नवम्बर, 1988 तक भारत की यात्रा पर आए।

संघ राज्य क्षेत्रों में शिक्षा

9.0.0 संघ राज्य क्षेत्रों में शिक्षा, केन्द्रीय सरकार का एक विशेष दायित्व रहा है। प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र में इस वर्ष के दौरान किए गए शैक्षिक कार्यकलापों का विवरण इस अध्याय में दिया गया है।

अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह

9.1.1 इस संघ राज्य क्षेत्र में, शिक्षा निदेशालय के प्रधान शिक्षा निदेशक हैं, जिनकी सहायता सहायक निदेशक तथा अन्य अधिकारी करते हैं।

9.1.2 इस वर्ष के दौरान 4 मिडिल स्कूलों का दर्ज़ा बढ़ाकर सीनियर स्कूल तथा 3 माध्यमिक स्कूलों का दर्ज़ा बढ़ाकर सीनियर माध्यमिक स्कूल कर दिया गया। संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को 4 नए प्राइमरी स्कूल खोलने तथा 5 प्राइमरी स्कूलों को मिडिल स्तर का स्कूल बनाने का भी प्रस्ताव है।

प्रोत्साहन योजनाएं

9.1.3 संघ राज्य क्षेत्रों में शिक्षा की प्रौन्नति के लिए संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं को चला रहा है। छात्रों को मध्याह्न भोजन, वर्दियाँ, यात्रा रियायतों, रियायतों, पाठ्य पुस्तकों इत्यादि के रूप में वित्तीय रियायतें दी गईं।

9.1.4 प्रारंभिक तथा माध्यमिक स्तर पर शिक्षकों कीं अतिरिक्त जरूरत को पूरा करने के लिए 4 प्रधानाधयापकों, 40 प्राइमरी स्कूल शिक्षकों, 60 प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों और 30 स्नातकोत्तर शिक्षकों के पदों का सृजन किया गया।

छात्रवृत्ति दरों में सुधार

9.1.5 संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन अंडमान निकोबार द्वीपसमूह से बाहर अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं चला रहा है। इस छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत विभिन्न पाठ्यक्रमों को जारी रखने के लिए जैसे कि बी०ए०, एम०ए० मेडिसिन में डिग्री/इंजीनियरी/मछली उद्योग, वनविद्या/पुस्तकालय/बी०एड०/पी०एच०डी० और विभिन्न प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों के लिए छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं। छात्रवृत्ति की दरें पिछली बार 1983-84 के दौरान संशोधित की गईं थीं। संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने इन दरों में सुधार करने का प्रस्ताव मंत्रालय के समक्ष रखा है। मंत्रालय ने अण्डमान निकोबार द्वीप समूह के छात्रों को उपर्युक्त पाठ्यक्रम अध्ययनों को जारी रखने के लिए उन्हें मिल रही वर्तमान छात्रवृत्ति को पर्याप्त रूप से बढ़ा दिया हैं, इससे छात्रों की बड़ी संख्या को लाभ होगा।

प्रशिक्षण संस्थान

9.1.6 शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत, बी०एड० और जे०बी०टी० पाठ्यक्रम चलाए गए। बी०एड० तथा जे०बी०टी० में नामित छात्रों की संख्या क्रमशः 80 और 128 थी

चण्डीगढ़

9.2.1 संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ में 332 स्कूल हैं जिनमें पूर्व–प्राथमिक से लेकर सीनियर माध्यमिक स्तर तक के बच्चे होते हैं। ये स्कूल प्रारंभिक स्तर पर लगभग एक लाख छात्रों तथा माध्यमिक स्तर पर लगभग 24,000 छात्रों की शैक्षिक जरूरतों को पूरा करते हैं।

छात्रवृत्तियाँ

9.2.2 अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों को विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन/छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं। आलोच्य अवधि के दौरान दिए गए प्रोत्साहनों का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित हैं :

(लाख रुपयों में)

	योजनागत	योजनेत्तर
उपस्थिति छात्रवृत्तियाँ	0.90	3.50
अनु०जा०/अनुजन०जा० छात्रवृत्तियां	1.25	5.50
प्रतिभा खोज छात्रवृत्तियाँ	0.50	-
पाठ्यपुस्तकें	1.69	3.50
वर्दी तथा लेखन सामग्री	4.50	11.20
अतिरिक्त शिक्षण	1.20	1.70

प्रारंभिक शिक्षा

9.2.3 संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा को बढ़ावा दे रहा है। 1988-89 के दौरान दो नए स्कूल खोले गए तथा 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के नामांकन 5500 से भी अधिक हो जाने के कारण 4 स्कूलों का स्तर बढ़ा दिया गया।

अनौपचारिक शिक्षा

9.2.4 संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा इस समय 100 केन्द्र चलाए जा रहे हैं जिनमें लगभग 2300 बच्चों का नामांकन है। ये केन्द्र स्कूल छोड़ने वाले बच्चों के लिए नर्सरी के रूप में कार्य करते हैं। समाज के इस वर्ग के कल्याण के लिए दस अध्ययन कक्ष भी चलाए जा रहे हैं।

व्यावसायिक शिक्षा

9.2.5 इस संघ शासित क्षेत्र के 9 सीनियर माध्यमिक स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं जहाँ, आशुलिपि और सचिवालय कार्य, पोशाक प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रोनिकी, ड्रैस डिजाईन आदि की शिक्षा दी जा रही है। संघ शासित प्रशासन ने अपने स्कूलों में सामान्य बीमा का शिक्षण भी शुरू कर दिया है ।

प्रौढ़ शिक्षा

9.2.6 विभिन्न प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों जैसे कि ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम तथा राज्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों में 6700 अध्येताओं को शामिल किया गया है। पन्द्रह जन शिक्षा निलयम खोले गए हैं। महिला साक्षरता गृह का 8.9.1988 को उद्घाटन किया गया। इस भवन का निर्माण महिला साक्षरता की प्रौन्नति के लिए भारत सरकार से प्राप्त पुरस्कार राशि से किया गया।

खेल

9.2.7 चण्डीगढ़ के स्कूलों में खेलकूद एक नियमित प्रमुख क्रिया है। खेलों में भागीदारीता को बढ़ावा देने के लिए संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन नियमित रूप से टूर्नामेंट्स तथा प्रतियोगिताएं आयोजित करता है। संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय स्कूल खेल, जवाहरलाल नेहरू जूनियर हाकी टूर्नामेंट तथा सुब्रतो मुखर्जी फुटबाल टूर्नामेंट आदि में भाग लिया।

राज्य शिक्षा संस्थान

9.2.8 संस्थान सेवाकालीन पाठ्यक्रमों और अनुस्थापन तथा अनुसंधान कार्यक्रमों के माध्यम से स्कूल शिक्षा में गुणवत्ता संबंधी सुधार लाने में सहायक हुआ है। स्कूल शिक्षा में अध्यापकों के लिए सेवाकालीन पाठ्यक्रम आयोजित करने के वास्ते एक क्षेत्रीय अंग्रेजी संस्थान की स्थापना की गई है ताकि अंग्रेजी शिक्षण में गुणवत्तात्मक सुधार लाया जा सके। वर्ष के दौरान चालीस अध्यापकों को अनुस्थापन प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

उच्चतर शिक्षा

9.2.9 उच्चतर शिक्षा में प्रशासन कला, विज्ञान तथा वाणिज्य विषयों में डिग्री स्तर तक शिक्षा प्रदान की जाती है। कालेज में लड़कियों को संगीत में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रदान किया जाता है। व्यावसायिक पक्ष में दो कालेज हैं—एक राजकीय शिक्षा कालेज और दूसरा राजकीय गृह-विज्ञान कालेज।

9.2.10 इसमें से प्रथम कालेज स्नातकों को शिक्षा स्नातक की डिग्री के लिए प्रशिक्षित करता है और बाद वाला गृह-विज्ञान में डिग्री स्तर तक एवं गृह-विज्ञान के विभिन्न विषयों में स्नातकोत्तर स्तर पर शिक्षा प्रदान करता है।

9.2.11 इसके अतिरिक्त यहाँ सात निजी रूप से

अनुदान/सहायता प्राप्त कालेज हैं। इन निजी रूप से प्रबंधित सहायता प्राप्त कालेजों को प्रशासन राजस्व व्यय की 95% सहायता-अनुदान प्रदान करता है।

दादरा तथा नगर हवेली

9.3.1 इस संघ राज्य में 161 प्राइमरी तथा 8 माध्यमिक एवं सीनियर माध्यमिक स्कूल हैं जो कि लगभग 18,000 छात्रों की प्राइमरी स्तर पर तथा लगभग 3500 छात्रों की माध्यमिक/सीनियर माध्यमिक स्तर पर शैक्षिक आवश्यकता को पूरा करते हैं।

अनु०जा०/अनु०जन०जा० के लिए प्रोत्साहन योजना

9.3.2 संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अनु०जा०/अनु०जन०जा० के छात्रों को, नि:शुल्क शिक्षा, शिक्षण-सहायक-उपस्कर, मध्याह्न भोजन, वर्दी तथा पुस्तकें आदि प्रदान करने जैसी विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं चलाकर पढ़ाई की ओर आकर्षित कर रहा है।

प्रौढ़ शिक्षा

9.3.3 संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत 100 केन्द्र तथा राज्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत 50 केन्द्र क्रमश: 3000/1500 अध्येताओं को शामिल करते हुए चला रहा है।

शारीरिक शिक्षा/खेल

9.3.4 भारत स्काउट तथा गाइड्स कार्यक्रम आयोजित किए गए। वर्ष के दौरान लगभग 300 छात्रों ने राष्ट्रीय कैडेट कोर में भाग लिया। एक अध्यापक ने भारत के राष्ट्रपति से राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया।

विविध

9.3.5 इस संघ राज्य राज्य क्षेत्र में संगणक साक्षरता अध्ययन शुरू किया गया और इसे चार स्कूलों तक बढ़ाया गया तथा इस परियोजना में और अधिक नामित किया गया। कबीले के लोगों को अध्ययन के प्रति आकर्षित करने तथा कबीली उप-भाषा को प्रौन्नत करने के लिए "देवरावरेली" तथा "दंगरवर्ली" नामक दो भाषाओं में द्विविभाषी पाठ्यपुस्तकें तैयार करने के लिए परियोजना शुरू की गई। (चार स्कूलों में)

दमन और दीव

संघ राज्य क्षेत्र में शैक्षिक सुविधाएं

9.4.1 पूर्व संघ राज्य क्षेत्र गोवा, दमन और दीव से अलग होने के बाद 30 मई, 1987 को संघ राज्य क्षेत्र दमन और दीव अस्तित्व में आया। इस संघ राज्य क्षेत्र में पश्चिमी तटों पर स्थित दमन और दीव जैसे दो जिलों को समाविष्ट किया गया। एक किलोमीटर के अन्दर-अन्दर की दूरी के छात्रों को शिक्षा प्रदान की जाती है। वर्ष 1988-89 के दौरान संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने दोनों जिलों में दो-दो स्कूलों सहित चार नए प्राइमरी स्कूल खोलने का निर्णय किया है। इसके साथ ही वर्ष के दौरान चार स्कूलों का दर्जा बढ़ाया गया है।

स्कूल शिक्षकों के लिए व्यापक अनुस्थापन

9.4.2 इस कार्यक्रम के अंतर्गत 147 प्राइमरी स्कूल शिक्षकों तथा 84 माध्यमिक शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। राज्य शिक्षा संस्थान, गोवा और शिक्षा विभाग दमन द्वारा 5 शिविर आयोजित किये गये। इस शैक्षिक वर्ष के दौरान संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का 4 और अनुस्थापन शिविर आयोजित करने का प्रस्ताव है जिसमें 100 प्राइमरी/माध्यमिक शिक्षकों को शामिल किया जाएगा

नवोदय विद्यालय

9.4.3 केन्द्रीय सरकार द्वारा दमन और दीव दोनों के लिए एक-एक नवोदय विद्यालय की संस्वीकृति दी गई है। 100 छात्रों का एक नवोदय विद्यालय पहले ही कार्य करना शुरू कर चुका है। शिक्षक तथा सचिवालयी स्टाफ की नियुक्ति हो चुकी है। दो विद्यालयों के लिए नए भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

व्यवसायिक शिक्षा

9.4.4 ग्रामीण क्षेत्रों के तीन स्कूलों में संघीय क्षेत्र प्रशासन ने टंकण तथा टेलरिंग की कक्षाएं शुरू कर दी हैं जिसमें पिछड़े वर्ग के 100 छात्र लाभ उठा रहे हैं।

तकनीकी शिक्षा

9.4.5 इस संघ राज्य क्षेत्र में दो तकनीकी हाई स्कूल तथा दो आई०टी०आई० चलाए जा रहे हैं। भारत सरकार ने शीघ्र ही एक राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज को शुरू करने का अनुमोदन दे दिया है।

प्रौढ़ शिक्षा

9.4.6 राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम योजना के अंतर्गत इस समय संघीय प्रशासन 36 केन्द्र चला रहा है। दमन जिले में एक जन शिक्षण निलयम स्थापित किया गया।

छात्रवृत्ति योजना

9.4.7 संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अनु०जा०/अनु०जन०जाति के छात्रों के लिए कन्या शिक्षा, विकास, पुस्तक अनुदान, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति, विकलांग बच्चों को वजीफा, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति जैसी सभी छात्रवृत्तियाँ/वजीफा योजनाएं चला रहा है।

जन जाति उप-योजना

9.4.8 इस योजना के अंतर्गत संघ राज्य प्रशासन अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पाठ्यपुस्तकें, वर्दी और लेखन सामग्री आदि प्रदान करता है। स्कूलों में उपस्थिति को बढ़ाने के लिए प्रत्येक जनजाति महिला छात्रा के लिए 25/- रु० की राशि भी प्रदान की जाती है।

दिल्ली

9.5.1 दिल्ली प्रशासन द्वारा अनु०जा०/अनु०जन० जाति के छात्रों की सहायता पर विशेष बल दिया गया है। अनु०जाति/अनु०जन०जाति के छात्रों के शैक्षिक सुधार के लिए उनको बहुत सी छात्रावृत्तियाँ प्रदान की जाती है तथा अनु०जा०/अनु०जन जाति के छात्रों के लिए उपचारी शिक्षण तथा कोचिंग सुविधाएं बढ़ाई गई हैं।

शैक्षिक सुविधाएं

9.5.2 वर्ष 1988-89 के दौरान दिल्ली में स्कूलों की संख्या निम्नलिखित है :

	राजकीय स्कूल	सहायता प्राप्त स्कूल	बिना सहायता प्राप्त स्कूल	दि०न०नि० के स्कूल	केन्द्रीय विद्यालय	कुल
अपर प्राइमरी स्कूल	223	30	126	10	-	389
माध्यमिक स्कूल	169	37	71	-	-	277
सीनियर माध्यमिक स्कूल	453	138	104	5	29	729

9.5.3 शैक्षिक वर्ष 1988-89 के दौरान दिल्ली प्रशासन ने 9 मिडिल स्कूल खोले। 6 मिडिल स्कूलों का दर्जा बढ़ा कर माध्यमिक स्कूलों का कर दिया गया तथा 15 माध्यमिक स्कूलों को सीनियर माध्यमिक स्कूलों में बदल दिया गया। वर्ष के दौरान 3 मिडिल स्कूलों, 2 माध्यमिक स्कूलों तथा तीन सीनियर माध्यमिक स्कूलों का भी द्विभाजन किया गया।

9.5.4 गाँवों में लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से गाँवों में रहने वाली तथा राजकीय कन्या स्कूलों में पढ़ने वाली लगभग 4000 छात्राओं को कार्य दिवस पर प्रतिदिन घर से स्कूल तथा स्कूल से वापस घर लाने ले जाने की व्यवस्था की गई हैं। वर्ष 1988-89 के दौरान शिक्षा निदेशालय ने दिल्ली के गाँवों की लड़कियों की इस यात्रा भत्ते की योजना पर 7 लाख रुपये की बजट व्यवस्था की है।

प्रौढ़ शिक्षा

9.5.5 दिल्ली प्रशासन का शिक्षा विभाग ऐसे प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए जो कि अपने घरेलू सामाजिक और आर्थिक कारणों की वजह से नियमित शिक्षा पूरी नहीं कर पाते, उनको लाभान्वित करने की दृष्टि से इस समय 12 सायंकालीन प्रौढ़ स्कूल चला रहा है। इन स्कूलों में इस समय 6000 प्रौढ़ अध्येताओं का नामांकन किया गया है।

अनौपचारिक शिक्षा

9.5.6 शिक्षा विभाग उन बच्चों जो औपचारिक शिक्षा सुविधाएं प्राप्त कराने में असमर्थ है, के लिए 74 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों को चला रहा है। पिछले 5 वर्षों के दौरान इन केन्द्रों में 10,234 छात्रों ने लाभ उठाया है।

राज्य शिक्षा संस्थान

9.5.7 संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के राज्य शिक्षा संस्थान का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है। यह विशेष विषय के शिक्षकों के लाभ के लिए सेमिनार तथा पाठ्यक्रमों को आयोजित करता है। संस्थान 30,000 अध्यापकों के अनुस्थापन का कार्य भी देखता है। इसके पास प्राइमरी शिक्षक शिक्षा मूल्यांकन के लिए यूनेस्को सहायक परियोजना भी हैं। राज्य शिक्षा संस्थान द्वारा ''दिल्ली शिक्षा'' नामक शिक्षा की एक त्रैमासिक पत्रिका प्रकाशित की जाती है।

खेल-कूद कार्यकलाप

9.5.8 दिल्ली प्रशासन के पास ''छत्रसाल स्टेडियम'' नामक एक स्टेडियम भी है जो शिक्षा विभाग के व्यायाम तथा खेल-कूद कार्यकलापों की जरूरतों को पूरा करता है। प्रशासन के पास 10 तरण ताल भी हैं। खेल विभाग कोचिंग कैम्पस आयोजित करता है तथा लड़के-लड़कियों को राष्ट्रीय कैम्पों के लिए तैयार करता है।

विज्ञान शिक्षा

9.5.9 दिल्ली प्रशासन (शिक्षा निदेशालय) की विज्ञान शाखा वैज्ञानिक रुचि को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय प्रतिभा खोज तथा अन्य विज्ञान कार्यकलापो को भी चलाता है। यह दिल्ली में सभी जगह कार्यशालाएं, अध्ययन सर्किल, बैठकें तथा छात्र अध्ययन शिविर भी आयोजित करता है।

पत्राचार विद्यालय

9.5.10 दिल्ली प्रशासन छात्रों की शिक्षा के लिए एक पत्राचार विद्यालय भी चलाता है और माध्यमिक स्कूल परीक्षा तथा सीनियर माध्यमिक स्कूल परीक्षा में बैठने के लिए उनका मार्गदर्शन भी करता है। पूरे वर्ष विशेष तौर से छुट्टियों के दौरान माध्यमिक तथा सीनियर स्तर पर विज्ञान विषयों के छात्रों के लिए प्रयोगशाला सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं। पत्राचार विद्यालय 22,000 छात्रों की शैक्षिक जरूरतें पूरी करता है।

9.5.11 भाषाओं तथा साहित्य को प्रोत्साहन देने के लिए, दिल्ली प्रशासन, पंजाबी, हिंदी, संस्कृत तथा उर्दू अकादमियों को सहायता देने के अलावा, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली, नगर पालिका, दिल्ली छावनी बोर्ड, साहित्य कला परिषद् तथा सांस्कृतिक संगठनों को सहायता अनुदान भी देता है। इन अकादमियों की स्थापना संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में पंजाबी, उर्दू और संस्कृत भाषाओं की प्रौन्नति तथा विकास के लिए की गई।

लक्षद्वीप

9.6.1 लक्षद्वीप संघ क्षेत्र एक केन्द्र प्रशासित क्षेत्र है, प्रशासन विभाग का प्रशासक ही इसका प्रमुख है। शिक्षा विभाग के लिए शिक्षा निदेशक ही नियंत्रक अधिकारी है और जिनकी सहायता विभिन्न शिक्षा अधिकारी और अन्य कर्मचारी करते हैं। लक्षद्वीप में दस बसे हुए द्वीप शामिल है।

शैक्षिक सुविधाएं

9.6.2 इस संघ राज्य क्षेत्र में 54 शैक्षिक संस्थान शामिल हैं जिनका ब्यौरा निम्नलिखित है :

1. जूनियर कालेज	2
2. हाई स्कूल	9
3. सीनियर बेसिक स्कूल	4
4. जूनियर बेसिक स्कूल	19
5. नर्सरी स्कूल	9
6. बालवाड़ी (लस्सवा बोर्ड के अन्तर्गत)	11
जोड़	54

9.6.3 बित्रा को छोड़कर 9 द्वीपों में नर्सरी स्कूल कार्य कर रहे है। वर्ष 1988-89 के दौरान छात्रों की संख्या 14,523 थी। सभी स्कूलों में शिक्षण और खेलों के लिए आवश्यक उपस्कर उपलब्ध कराए गए। यहाँ चार होस्टल हैं, दो लड़कों और दो लड़कियों के लिए हैं। प्रवेश पाने के इच्छुक सभी छात्रों को स्थान प्राप्त करने की सुविधा दी जाती है। मिनीकाय में एक नवोदय विद्यालय ने कार्य करना शुरू कर दिया है।

प्रौढ़ शिक्षा

9.6.4 संघ राज्य क्षेत्र ने विभिन्न प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चला रखे हैं। मई, 1988 में इसी संघ क्षेत्र में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन अभियान का उद्घाटन किया गया। निरक्षरता उन्मूलन के कार्य को गति देने के लिए साक्षरता मिशन प्राधिकरण की स्थापना की गई है और विभिन्न द्वीपों को तीन अभिकरणों, अर्थात् शिक्षा विभाग, नवयुवक केन्द्र और लस्सवा (एल० एस०

एस० डब्ल्यू० ए०) बोर्ड में विभाजित कर दिया गया है।

खेल

9.6.5 संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने क्षेत्र में खेल और शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। वर्ष के दौरान संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने खिलाड़ी लड़कों और तैराकी के प्रशिक्षकों के रिक्त पदों को भर दिया है। 4 एन०सी०सी० जूनियर डिवीजन कैडिटों को कोचीन में गणतंत्र दिवस परेड के चयन और तैयारी शिविरों में नियुक्त किया गया। संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के छात्रों ने भी बंगलौर के राष्ट्रीय खेल प्रतिभा (एथेलेटिक) में भाग लिया।

छात्रवृत्ति दरों का संशोधन

9.6.6 संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन, मैट्रिक, मैट्रिकोत्तर, स्नातक, विभिन्न विषयों में स्नातकोत्तर अध्ययन को जारी रखने के लिए छात्रवृत्तियों की योजना को कार्यान्वित कर रहे है। छात्रवृत्ति की दरें काफी बढ़ा दी गई हैं और इससे काफी अधिक संख्या में छात्रों को लाभ पहुँचा है।

शिक्षा का व्यावसायीकरण

9.6.7 शैक्षिक सुधार के लिए संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों में नीपा ने एक अध्ययन शुरू किया है जिसमें उन क्षेत्रों में व्यावसायिक शिक्षा के महत्व पर बल दिया गया है। संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन ने माध्यमिक स्कूलों में मछली पालन, प्रौद्योगिकी और नारियल रेशा संसाधन पर आधारित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की शुरूआत के लिए विभिन्न पदों के सृजन के लिए मंत्रालय को कहा है। तदनुसार शिक्षा विभाग ने निम्नलिखित पदों के सृजन के लिए अनुमोदन दे दिया है।

पद का नाम	पदों की संख्या
मैकेनिकल प्रशिक्षक	4
नौका चालक	4
मछेरे एवं जीवन रक्षक	4
नारियल रेशा शिल्प प्रशिक्षक	4
मछली पालन प्रशिक्षक	4

9.6.8 संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के स्कूलों से कक्षा 8वीं से व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के लिए केरल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से स्वीकृति और मान्यता प्राप्त करना आवश्यक होगा क्योंकि यह स्कूल केरल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध है। इसे स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम

9.6.9 शिक्षा विभाग के अधिकारियों और मुख्य अध्यापकों तथा अभिभावक शिक्षक संघ के सदस्यों के लिए कवेरती में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में नीपा के प्रसिद्ध शिक्षाविदों और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय के अध्यापकों ने भाग लिया। कुल मिलाकर इस कार्यक्रम में 52 व्यक्तियों ने भाग लिया। जन अनुस्थापन की राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत नई शिक्षा नीति, 1986 के अनुरूप अध्यापकों के लिए एक अनुस्थापन पाठ्यक्रम चलाया गया जिसमें 80 अध्यापकों ने भाग लिया। विज्ञान किटों के प्रयोग से संबंधित एक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया गया जिसमें 20 अध्यापकों ने भाग लिया। सी०सी०आर०टी०, नई दिल्ली द्वारा आयोजित 6 सप्ताह के एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में विभिन्न द्वीपों के 6 अध्यापकों ने भाग लिया।

शैक्षिक प्रणाली को सुदृढ़ करना

9.6.10 शिक्षा प्रणाली के और अधिक सुधार के लिए नीपा द्वारा सुझाए गए उपायों की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों ने व्यावसायिक शिक्षा, सामान्य प्रशासनिक स्थापना, अकादमिक स्थापना, माध्यमिक शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा आदि के लिए पदों का प्रस्ताव रखा है। शिक्षा विभाग ने व्यावसायिक शिक्षा के लिए 20 पदों और सामान्य प्रशिक्षण, अकादमिक स्थापना और प्रक्योरमेंट सेल आदि के लिए 24 पदों के सृजन की अनुमति प्रदान की है।

सह–पाठ्यचर्या कार्यकलाप

9.6.11 शिक्षक दिवस बहुत उत्साह के साथ मनाया गया। संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों में बाल दिवस भी धूमधाम से मनाया गया जिसमें जन-साधारण बैठक का आयोजन और रंगारंग कार्यक्रम जैसे कि लेख प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, रेखाचित्र और अन्य सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजना किया गया। नौका दौड़ और तैराकी प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई।

पांडिचेरी

9.7.0 वर्ष के दौरान पांडिचेरी संघ शासित क्षेत्र प्रशासन की विभिन्न योजनाओं और शैक्षिक कार्यकलापों को बढ़ाने में लगे रहे। वर्ष के दौरान हाथ में लिए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य इस प्रकार हैं :—

प्राथमिक शिक्षा

9.7.1 छठी योजना के दौरान प्रार्थमिक शिक्षा के क्षेत्र में काफी अधिक विस्तार हुआ जिसके फलस्वरूप लगभग शत-प्रतिशत नामांकन प्राप्त हुआ। सातवीं योजना के दौरान स्कूलों को लाइब्रेरी, वैज्ञानिक उपस्करों, फर्नीचर, भवन, श्रव्य-दृश्य सहायक सामग्री और अन्य आधारभूत सुविधाओं द्वारा मजबूत बनाकर शैक्षिक पद्धति के गुणवत्ता संबंधी पहलू को मजबूत किया गया। इन स्कूलों के लिए भूमि अभिग्रहण और भवन-निर्माण के साथ-साथ फर्नीचर की सप्लाई और इन कार्यों के कार्यान्वयन आदि के पिछले सारे अवरुद्ध कार्यों को शीघ्र पूरा करने का प्रस्ताव है। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापकों की नियुक्ति के पिछले आदेशों को भी निपटाने का प्रस्ताव है। इस योजना का उद्देश्य सभी एकल शिक्षक स्कूलों को द्वि-शिक्षक/बहु शिक्षक स्कूलों में परिवर्तित करना है।

9.7.2 1988-89 के दौरान प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत 1 प्रार्थमिक स्कूल, 1 मिडिल स्कूल, 34 अतिरिक्त कक्षाएं, 15 आगामी उच्चतर स्तर के स्कूल भी खोले गए। पाठ्यपुस्तकों, लेखन सामग्री और वर्दी के निःशुल्क वितरण के उद्देश्य के अंतर्गत 57,300 गरीब बच्चों को शामिल किया गया।

विज्ञान शिक्षा

9.7.3 बच्चों में वैज्ञानिक उत्सुकता को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक मिडिल स्कूल में विज्ञान कार्नर स्थापित करने तथा सीनियर माध्यमिक स्कूलों में प्रयोगशालाओं को मजबूत करने का प्रस्ताव है। इसी प्रकार बच्चों को इंसैट सुविधा से लाभ उठाने के योग्य बनाने के लिए शेष सभी मिडिल/माध्यमिक/सीनियर माध्यमिक स्कूलों में श्रव्य-दृश्य शिक्षा के अंतर्गत टी०वी० सेट उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है जो कि पांडिचेरी में टी०वी केन्द्र स्थापित होने के बाद होगा।

व्यावसायिक शिक्षा

9.7.4 योग्य अध्यापकों की नियुक्ति तथा यंत्र एवं कच्चे माल की आपूर्ति द्वारा मिडिल तथा हाई स्कूलों में माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायिकरण और व्यावसायिक कार्यों को आगे बढ़ावा देने का भी प्रस्ताव हैं। संघ राज्य क्षेत्र के प्रत्येक सीनियर माध्यमिक स्कूल में कम से कम एक व्यावसायिक कार्य आरंभ करने का प्रस्ताव है।

माध्यमिक शिक्षा

9.7.5 वर्ष 1988-89 के दौरान, 9 मिडिल स्कूलों की उच्च स्कूलों में स्तरोन्नति की गई और 2 अगले उच्च स्तरों के स्कूल खोले गये। विद्यमान सीनियर माध्यमिक स्कूल में अतिरिक्त पाठ्यक्रमों/व्यावसायिक पाठ्यक्रम यथा प्रस्तावित खोले गए। तीन हाई स्कूलों की सीनियर माध्यमिक स्कूलों के रूप में स्तरोन्नति भी की गई।

शिक्षक शिक्षा

9.7.6 प्रत्येक वर्ष विभिन्न श्रेणियों के 500 शिक्षकों को, विभिन्न विषयों में सेवाकालीन अनुस्थापन प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

विश्वविद्यालय शिक्षा

9.7.7 विश्वविद्यालय शिक्षा के अंतर्गत इस संघ-राज्य क्षेत्र के उन छात्रों जो उच्च शिक्षा की अभिलाषा रखते हैं। परंतु जिन्हें पड़ौसी राज्यों के कालेजों में आरक्षित कुछ सीटों पर निर्भर रहना पड़ता हैं, की सहायता करने के लिए छः डिग्री कालेजों में नए पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। जो उच्च शिक्षा की अभिलाषा रखते हैं, परन्तु कुछ आरक्षित सीटों के लिए उन पर निर्भर हैं, को पड़ौसी राज्यों में सीट आरक्षण के आधार पर सीट उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। वर्ष 1988-89 के दौरान विद्यमान कालेजों में कला तथा विज्ञान में उत्तर स्नातक पाठ्यक्रमों को शुरू किया गया तथा एल०एल०एम० में एक और शाखा आरंभ की गई।

तकनीकी शिक्षा

9.7.8 वर्ष 1988-89 के दौरान तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत पांडिचेरी इंजीनियरिंग कालेज में डी०सी०ए० पाठ्यक्रम आरंभ किया गया। नए पाठ्यक्रम इस प्रकार हैं: (1) ओटोमोबाइल इंजीनियरिंग में रेफ्रिजिएशन और एयर कन्डीशनिंग (2) इलैक्ट्रोनिक इंजीनियरिंग में टी०वी० इंजनियरिंग (3) सिविल इंजीनियरिंग में

बिल्डिंग टेक्नोलोजी (4) फैब्रीकेशन तथा डिजाईनिंग (5) कम्प्यूटर एप्लीकेशन में पोस्ट डिप्लोमा कोर्स और (6) लैटर प्रैस प्रिंटिंग भी शुरू की गई।

महिला पालिटेक्निक

9.7.9 इस संघ राज्य क्षेत्र के व्यक्तियों की बहुत पहले सोची गई आवश्यकता की पूर्ति के लिए पाण्डिचेरी में एक महिला पॉलिटेक्निक तथा कराईकल में लड़के तथा लड़कियों के लिए एक पॉलिटेक्निक की स्थापना की गई। संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने मेह में एक जूनियर टेक्निकल स्कूल के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए भी कदम उठाए हैं।

प्रौढ़ शिक्षा

9.7.10 पांडिचेरी संघ राज्य प्रशासन में राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए शिक्षा विभाग एक प्रमुख विभाग है। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अधीन कार्यरत पर्यवेक्षकों तथा एनिमेटर्स के लिए प्रत्येक वर्ष प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत दो प्रशिक्षण कार्यक्रम नियमित रूप से संचालित किए जाते हैं। वर्ष 1988-89 के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत 1500 निरक्षरों को शामिल किया जाएगा।

शारीरिक शिक्षा

9.7.11 वर्ष 1988-89 के दौरान शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत सभी शारीरिक शिक्षा योजनाएं जारी रखी जा रही हैं। उत्कृष्ट खिलाड़ियों, एन०सी०सी० कैडटों, स्काउट और गाइड को छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं। खेल-कूद परिसर का निर्माण जारी है।

अन्य कार्यक्रम तथा सह-पाठ्यचर्या कार्यकलाप

9.7.12 बाल भवनों तथा समुदाय स्तर के लघु बाल भवनों को सुदृढ़ बनाया गया। विभिन्न स्कूलों में फिल्म-शो, वीडियो कार्यक्रमों जैसे कार्यकलाप आयोजित किए गए। पिछली योजना अवधि के दौरान प्राप्त प्रगति के वेग को बनाए रखने का जब प्रयास किया जा रहा था, संघीय प्रशासन ने पहले से प्राप्त उपलब्धियों को मजबूत बनाने तथा आगामी वर्षों के दौरान इसके स्वरूप में सुधार लाने के प्रयास किए।

छात्रवृत्तियाँ

10.0.0 शिक्षा विभाग भारतीय छात्रों के लिए आगे पढ़ाई के वास्ते छात्रवृत्तियों के अनेक कार्यक्रमों का संचालन करता है, इनमें अन्य सरकारों द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्तियां भी शामिल हैं। विभाग द्विपक्षीय आधार पर अथवा अन्यथा अन्य देशों के राष्ट्रिकों को भी छात्रवृत्तियां प्रदान करता है। महत्वपूर्ण योजनाओं का उल्लेख नीचे किया गया है :-

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना

10.1.0 इस योजना के अंतर्गत, जिसे राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है, छात्रवृत्तियां योग्यता एवं आय के आधार पर उत्तर-मैट्रिक स्तर की पढ़ाई के लिए दी जाती हैं। वर्ष 1988-89 के दौरान, 33,000 छात्रवृत्तियां प्रदान की गईं। छात्रवृत्तियों की दरें अध्ययन पाठ्यक्रम के आधार पर दिवा छात्रों के लिए 60/- रुपये से 120/- रुपये मासिक तक और छात्रावासों में रहने वालों के लिए 100/- रुपये से 170/- रुपये मासिक तक की हैं। 1.4.1988 से, आय संबंधी अधिकतम सीमा सभी अनुमत्य छूटों को प्रदान करने के बाद, 6000/- रुपये से बढ़ाकर 25,000/- रुपये वार्षिक कर दी गई है।

राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति योजना

10.2.0 इस योजना के अंतर्गत, वर्ष 1988-89 में 20,000 छात्रवृत्तियां जरूरतमंद छात्रों को अपना अध्ययन पूरा करने के लिए प्रदान की गईं। ये छात्रवृत्तियां उत्तर-मैट्रिक अध्ययन के लिए योग्यता एवं आय के आधार पर प्रदान की जाती हैं। यह योजना राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही हैं। अध्ययन पाठ्यक्रम के आधार पर ऋण की राशि 720/- रु० से 1720/- रु० वार्षिक तक होती है। 1.4.1988 से, आय संबंधी अधिकतम सीमा, सभी अनुमत्य छूटें प्रदान करने के बाद, 6000/- रु० से बढ़ाकर 25,000/- रु० वार्षिक कर दी गई है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के छात्रों की योग्यता में वृद्धि के लिए योजना

10.3.1 यह योजना वर्ष 1987-88 में शुरू की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के छात्रों को सुधारात्मक और विशेष दोनों तरीकों से अतिरिक्त कोचिंग प्रदान करके उनकी योग्यता में वृद्धि करना है जिससे स्कूल-विषयों में उनकी शैक्षिक कमियां दूर हो सकें और उन व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में, जिनमें प्रवेश, प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर होता है, उनका प्रवेश सुसाध्य हो सकें। इस योजना के अंतर्गत जिन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के छात्रों का चयन किया जाता है, उन्हें अच्छे आवासीय स्कूलों में रखा जाता है ताकि वे बेहतर क्वालिटी की शिक्षा प्राप्त कर सकें, अपने अन्दर आत्म-विश्वास ला सकें और ऐसी स्थिति में हो सकें कि सही शैक्षिक तैयारी से अन्य छात्रों के साथ तालमेल कर पायें। यह योजना राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों के माध्यम से संचालित की जा रही है।

10.3.2 इस योजना का आरम्भ 50 स्कूलों में 1000 छात्रों (670 अनुसूचित जाति के और 330 अनुसूचित जन-जाति के) के लिए किया गया। विभिन्न राज्यों में स्कूलों का आवंटन वहां के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति समुदायों की निरक्षर जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। सुधारात्मक कोचिंग नवीं

कक्षा-स्तर से आरम्भ की जायेगी और तब तक जारी रहेगी जब तक कि छात्र बारहवीं कक्षा पास न कर ले। सुधारात्मक कोचिंग इन छात्रों को कक्षा नवीं से बारहवीं तक चार वर्ष की अवधि के लिए दी जायेगी जबकि विशेष कोचिंग केवल ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षाओं में ही प्रदान की जायेगी। इस योजना के अंतर्गत, कोई आय-सीमा निर्धारित नहीं है।

मान्यता प्राप्त आवासीय माध्यमिक स्कूलों में भारत सरकार की छात्रवृत्ति योजना

10.4.0 इस योजना का उद्देश्य प्रतिभाशाली परन्तु निर्धन छात्रों (11-12 वर्ष की आयु वर्ग के) को अच्छे आवासीय स्कूलों में पढ़ने के लिए शैक्षणिक सुविधायें प्रदान करना है। वर्ष 1988-89 के दौरान उन छात्रों को जिनके अभिभावकों की आय 25,000/- रुपये प्रतिवर्ष से अधिक नहीं थी, योग्यता एवं आय के आधार पर पांच सौ छात्रवृत्तियां प्रदान की गईं। इनमें से पचास प्रतिशत छात्रवृत्तियां अखिल भारतीय योग्यता के आधार पर प्रदान की गईं और शेष 50% राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को उनकी जनसंख्या के आधार पर आवंटित की गई। इसमें भी शर्त यह थी कि वे निर्धारित न्यूनतम मानकों को पूरा करते हों। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को क्रमशः 15 प्रतिशत और 7½ प्रतिशत छात्रवृत्तियां प्रदान की गई। ये छात्रवृत्तियां माध्यमिक स्कूली शिक्षा की पूरी अवधि के लिए होती हैं, इसमें मान्यता प्राप्त आवासीय स्कूलों में शिक्षा का + 2 स्तर भी शामिल है। सरकार द्वारा निर्धारित दरों/सीमा तक जेब खर्च, वर्दी, वस्त्र भत्ता तथा भ्रमण व्यय के अलावा छात्र शिक्षा शुल्क, आवासीय व्यय, पुस्तकों और लेखन सामग्री की लागत की पूरी राशि के हकदार होते हैं। छात्रों और उनके अनुरक्षकों को भी इस प्रयोजन के लिए निर्धारित दरों पर यात्रा अनुदान भी अनुमत्य हैं।

1988-89 में हिन्दी में उत्तर-मैट्रिक अध्ययन के लिए अहिन्दी भाषी राज्यों के छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां

10.5.0 यह योजना 1955-56 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य अहिन्दी भाषी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में हिन्दी के अध्ययन को प्रोत्साहन करना और उनकी सरकारों को शिक्षण तथा अन्य पदों के लिए, जहां हिन्दी का ज्ञान अनिवार्य है, उपयुक्त कार्मिक उपलब्ध कराना है। 1988-89 के दौरान विभिन्न अहिन्दी भाषी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को दो हजार पांच सौ छात्रवृत्तियां आवंटित की गई थीं। छात्रवृत्तियों की दरें, अध्ययन के पाठ्यक्रम तथा राज्य/संघ शासित क्षेत्र, जिसमें हिन्दी का अध्ययन किया जा रहा है, पर निर्भर करती हैं और 50/- रु० से 125/- रु० मासिक तक होती है। इस योजना का केन्द्रीय हिन्दी संस्थान आगरा से मूल्यांकन करवाया गया है। समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ छात्रवृत्तियों की दरों की संख्या में वृद्धि का सुझाव दिया है। सिफारिशों की जांच की जा रही है।

संस्कृत के अलावा अरबी और फारसी जैसी श्रेण्य (क्लासिकल) भाषाओं के अध्ययन में लगी पारम्परिक संस्थाओं के छात्रों को अनुसंधान छात्रवृत्तियां।

10.6.0 इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष बीस छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। वर्ष 1988-89 में 20 छात्रों को इस छात्रवृत्ति के लिए चुना गया।

ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों के लिए माध्यमिक स्तर पर राष्ट्रीय छात्रवृत्तियां

10.7.0 प्रति वर्ष 38,000 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती है। 1988-89 के लिए आवंटित 38,000 छात्रवृत्तियों का अलग-अलग ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

		छात्रवृत्तियों की कुल संख्या
—सामान्य वर्ग	प्रत्येक सामुदायिक विकास खण्ड के लिए तीन छात्रवृत्तियां	15,000
—भूमिहीन श्रमिकों के बच्चे	प्रत्येक सामुदायिक विकास खण्ड के लिए दो छात्रवृत्तियां	10,000
—अनुसूचित जाति के बच्चे	प्रत्येक सामुदायिक विकास खण्ड के लिए दो छात्रवृत्तियां और प्रत्येक ऐसे सामुदायिक विकास खण्ड के लिए अतिरिक्त छात्रवृत्ति जिसमें अनुसूचित जाति की जनसंख्या 20% या इससे अधिक हो।	11,500
—अनुसूचित जन-जाति के बच्चे	प्रत्येक जनजातीय सामुदायिक विकास खण्ड के लिए तीन छात्रवृत्तियां	1,500
		38,000

यह योजना राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है।

सामान्य सांस्कृतिक छात्रवृत्ति योजना

10.8.1 सद्भावना और मैत्रीपूर्ण संबंध बढ़ाने के लिए चुनिन्दा अफ्रीकी, एशियाई और अन्य विकासशील देशों के राष्ट्रिकों को भारत में अवर-स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के अध्ययन के लिए प्रति वर्ष 180 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं, विशेषकर उन पाठ्यक्रमों में जिनके लिए उनके अपने देशों में सुविधाओं का आभाव है। छात्रों को उनकी अपनी सरकारों की सिफारिशों के आधार पर छात्रवृत्तियां दी जाती हैं।

10.8.2 अवर स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए छात्रवृत्ति की राशि 750/- रु० प्रतिमाह और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 900/- रु० प्रतिमाह हैं। इसके अतिरिक्त छात्रों को चिकित्सा और अध्ययन दौरों, का खर्च दिया जाता है। पाठ्यक्रमों पर निर्भर करते हुये उन्हें क्रमशः 1500 रुपये से 2500 रुपये तक का वार्षिक आकस्मिक भत्ता भी दिया जाता है।

बंगलादेश के राष्ट्रिकों के लिए छात्रवृत्तियां/शिक्षावृत्तियां

10.9.1 इस योजना के अंतर्गत, भारत में उच्च अध्ययन के लिए बंगलादेश के राष्ट्रिकों को प्रति वर्ष छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। इनमें संस्कृत और पालि के अध्ययन के लिए 10 छात्रवृत्तियां शामिल हैं। छात्रवृत्तियों के लिए चयन ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग के परामर्श से बंगला देश सरकार द्वारा किया जाता है।

10.9.2 इस छात्रवृत्ति की राशि अवर-स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए 750/- रु० प्रतिमाह और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 900/- रु० प्रति माह हैं। इसके अतिरिक्त छात्रों को वार्षिक आकस्मिक भत्ते के रूप मे 1500 से 2500 रु० तक दिये जाते हैं। चिकित्सा और अध्ययन दौरों पर होने वाले व्यय की भी प्रतिपूर्ति की जाती है। इस छात्रवृत्ति में (ढाका से कलकत्ता तक की) हवाई यात्रा, और (कलकत्ता से भारत में अध्ययन स्थान तक का) प्रथम श्रेणी का रेल किराया तथा अध्ययन पूरा करने के बाद वापसी घर जाने के लिए यात्रा का किराया भी दिया जाता है। यह योजना विदेश मंत्रालय द्वारा वित्त-पोषित है।

श्रीलंका, मालदीव, अंगोला और मारीशस के राष्ट्रिकों के लिए छात्रवृत्तियां

10.10.1 1988-89 के शैक्षिक सत्र से विदेश मंत्रालय की सिफारिशों पर भारत में उच्च अध्ययन के लिए श्रीलंका, मालदीव और अंगोला के राष्ट्रिकों के लिए छात्र-वृत्तियों की संख्या में वृद्धि की गई है। 1988-89 के दौरान इन देशों को प्रदान की गई छात्रवृत्तियों की संख्या इस प्रकार है :-

श्री लंका	50	
अंगोला	40	
मालदीव	20	(सामान्य सांस्कृतिक छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत दी गई 4 सहित)
मारीशस	40	(जी सी एस एस के अन्तर्गत 10+30 अतिरिक्त)

10.10.2 इन छात्रवृत्तियों के नियम व शर्तें वैसी ही हैं जैसी सामान्य सांस्कृतिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत हैं। ये छात्रवृत्तियां विदेश मंत्रालय के बजट से दी जाती हैं।

विदेशों में अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियां

10.11.1 विदेशों में अध्ययन के लिए 1988-89 में छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए 50 भारतीय छात्रों का चयन किया गया है। ये छात्रवृत्तियां मुद्रण प्रौद्योगिकी में स्नातक अध्ययन के लिए, नौसेना वास्तुकला और कागज प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए और मानविकी, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में डॉक्टरल तथा पोस्ट-डॉक्टरल अध्ययन के लिए प्रदान की जाती हैं। इन छात्रवृत्तियों के लिए केवल वही छात्र पात्र हैं, जिनके अभिभावकों की पूर्व-संशोधित वेतनमानों को ध्यान रखने के बाद सभी स्त्रोतों से आय सामान्य मानक छूटों के बाद 1000 रुपये प्रतिमाह अथवा इससे कम है।

10.11.2 राष्ट्रीय/विदेशी छात्रवृत्ति प्रभाग के प्रबन्ध और प्रशासनिक कार्यों के लिए कम्प्यूटर का उपयोग पहली बार 1987-88 में शुरू किया गया और 1988-89 में जारी रहा।

सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत विदेशी सरकारों द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्तियां/शिक्षावृत्तियां

10.12.0 शिक्षा विभाग के अंतर्गत विदेश छात्रवृत्ति प्रभाग अनेक ऐसे कार्यक्रम चलाता है जिनके अंतर्गत

भारतीय छात्रों/नागरिकों को विदेशों में उच्च अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। ये छात्रवृत्तियां विभिन्न विदेशी सरकारों व एजेन्सियों द्वारा हर वर्ष उपलब्ध की जाती हैं। इस मंत्रालय द्वारा 30.11.88 तक इन छात्रवृत्तियों का देशवार वास्तविक उपयोग इस प्रकार किया है: नार्वे-6, पोलैंड-1, जी.डी. आर.-5, मंगोलिया-1, बुलगारिया-4, यूगोस्लाविया-1, फ्रांस-2, एफ.आर.जी.-8, आयरलैंड-8, जापान-9, डेनमार्क-3, टर्की-3, यू.एस.ए.-3, यू.एस.एस.आर.-18, थाइलैंड-4, स्पेन-4, आस्ट्रिया-1. चेकोस्लोवाकिया-2, नीदरलैंड-3, इटली-28, आस्ट्रेलिया-5, ट्रिनीडाड-1, न्यूजीलैंड-1, बेल्जियम-2, ग्रीक-2

विदेश व राष्ट्रमंडलीय छात्रवृत्तियां (एफ.सी.ओ. तथा पुरस्कार योजना, यू.के.

10.13.0 इस योजना के अंतर्गत यू.के. में 9 छात्रों को विदेश भेजा गया।

यू.के./कनाडा सरकार द्वारा प्रदान की गई राष्ट्रमंडलीय छात्रवृत्तियां व शिक्षावृत्तियां

10.14.0 इस योजना के अंतर्गत, 60 छात्रों को विदेश भेजा गया।

विज्ञान अनुसंधान छात्रवृत्तियां

10.15.0 वर्ष 1988-89 के दौरान इस योजना के अंतर्गत कोई छात्र विदेश नहीं भेजा गया।

तकनीकी सहयोग प्रशिक्षण कार्यक्रम

10.16.0 इस योजना के अंतर्गत इस मंत्रालय ने 7 छात्रों को विदेश भेजा।

राष्ट्रमण्डलीय शिक्षा सहयोग कार्यक्रम

10.17.0 इस कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित 3 वरिष्ठ शिक्षाशास्त्रियों को 1988-89 के दौरान विजिटरशिप के लिए चुना गया:-

1. डॉ० लेन कूपर टेलर (कनाडा)
2. श्री जोसेफ केथेम्बा म्वाले (मालवी)
3. श्री अकीकी बोम्बेरा मुजाजु (यूगांडा)

ब्रिटिश काउंसिल विजिटरशिप कार्यक्रम

10.18.0 इस कार्यक्रम के अंतर्गत 150 से अधिक, वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों तथा चिकित्सा विशेषज्ञों ने अपनी-अपनी विशेषज्ञताओं के क्षेत्र में हुये महत्वपूर्ण विकास की जानकारी के आदान-प्रदान का लाभ उठाया।

भारत में अध्ययन/प्रशिक्षण के लिए विदेशी छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां

10.19.0 आलोच्य वर्ष के दौरान, भारत द्वारा द्विपक्षीय सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के अंतर्गत भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में अध्ययन के लिए विभिन्न देशों को 300 से भी अधिक छात्रवृत्तियों की पेशकश की गई। ये देश हैं:

सेनेगेल, फ्रांस, जर्मन संघीय गणराज्य, यू.एस.एस.आर., फिलीपाइन्स, बेल्जियम, मेक्सिको, अफगानिस्तान, ग्रीस, सोमालिया, इटली, यूगोस्लाविया, सीरिया, यमन-लोकतांत्रिक गणराज्य, हंगरी, वियतनाम, बुल्गारिया, ट्यूनिशिया, पुर्तगाल, मलेशिया, श्रीलंका, बहरीन, बर्मा, ईरान, केनिया, कोरिया जनवादी लोकतान्त्रिक गणराज्य, मारीशस, जापान, अल्जीरिया, आस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात, सुडान, इथोपिया, जोर्डन। इस प्रस्ताव के अंतर्गत हमें 260 नामांकन प्राप्त हुये तथा हमने 185 छात्रों के लिए स्थान का प्रबंध किया। जनवरी, 1989 तक 110 छात्र भारत की विभिन्न संस्थाओं में आ गये हैं।

भारत में अध्ययन के लिए राष्ट्रमंडलीय छात्रवृत्ति/शिक्षावृत्ति योजना

10.20.0 इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा राष्ट्रमंडलीय देशों को उनके राष्ट्रिकों के लिए भारत में स्नातकोत्तर–अनुसंधान अध्ययनों के लिए 75 छात्रवृत्तियों की पेशकश की गई। इस प्रस्ताव के अंतर्गत हमें 70 नामांकन प्राप्त हुये तथा जनवरी, 1989 तक 20 छात्र अपनी संस्थाओं में आ गये हैं।

डॉ० अमिलकर काब्रल छात्रवृत्ति

10.21.0 इस कार्यक्रम के अंतर्गत एक अफ्रीकी छात्र के लिए एक छात्रवृत्ति की पेशकश की गई है।

डॉ० एन्यूरिन बेवन स्मारक शिक्षावृत्ति

10.22.0 इस कार्यक्रम के अंतर्गत यू.के. के राष्ट्रिकों

के लिए एक से दो तक की शिक्षावृत्तियों की पेशकश की गई है।

कोलंबो योजना की तकनीकी सहयोग योजना

10.23.0 कोलंबो योजना की तकनीकी सहयोग योजना के अंतर्गत कोलंबो योजना देशों से आने वाले छात्रों को स्थान देने के लिए सहायता दी जाती है जिनके नाम हैं: अफगानिस्तान, भूटान, ईरान, इण्डोनेशिया, मलेशिया, मालदीव, नेपाल, फिलीपीन्स, श्रीलंका। इस योजना के अंतर्गत हमें वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) जो इस कार्यक्रम के लिए मुख्य मंत्रालय है, से लगभग 100 छात्रों के नामांकन प्राप्त होते हैं। उन छात्रों को जिन्हें भारतीय संस्थाओं में स्थान मिल जाता हैं, छात्रवृत्ति भी दी जाती है। आलोच्य वर्ष के दौरान, इस कार्यक्रम के अंतर्गत 75 छात्रों को छात्रवृत्तियां दी गईं।

राष्ट्रमण्डलीय शिक्षा सहयोग योजना–शिल्प-अनुदेशकों का प्रशिक्षण

10.24.0 इस योजना के अंतर्गत, रोजगार व प्रशिक्षण महानिदेशालय को नियंत्रणाधीन विभिन्न संस्थाओं में विभिन्न प्रकार के शिल्पों के शिल्प अनुदेशकों के प्रशिक्षण के लिए, एशिया, अफ्रीका, और लेटिन अमेरिका के राष्ट्रमण्डलीय देशों के 10 राष्ट्रिकों के लिए विशेष छात्रवृत्तियां देने की पेशकश की गई है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जनवरी, 1989 तक दो छात्रवृत्तियों का उपयोग किया गया

दादू नायकर पुरस्कार

10.25.0 वर्ष 1988-89 से शुरू किये गये इस कार्यक्रम के अंतर्गत एक छात्रवृत्ति भारत में अध्ययन के लिए भारतीय मूल के एक सुयोग्य दक्षिण अफ्रीकी छात्र को दी गईं।

पुस्तक संवर्धन और कापीराईट

11.0.0 शिक्षा के क्षेत्र में पुस्तकों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। देश में शैक्षिक सुविधाओं के विस्तार से पुस्तकों की मात्रा के साथ-साथ विभिन्न विषयों की पुस्तकों की मांग भी अधिक बढ़ गई है। शिक्षा विभाग के पुस्तक संवर्धन प्रभाग की, उचित दामों में अच्छी कोटि की पुस्तकें तैयार करने, स्वदेशी लेखकों को बढ़ावा देने, लोगों में पढ़ने की आदत पैदा करने तथा भारतीय पुस्तक उद्योग की समस्याओं का समाधान करने के लिए कई योजनाएं हैं। इस सम्बन्ध में शुरू किये गए कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का संक्षिप्त ब्यौरा निम्नलिखित पैरा में दिया गया है:

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास :

11.1.1 राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की वर्ष 1957 में एक स्वायत्त संगठन के रूप में स्थापना इस उद्देश्य के साथ की गयी थी कि वह उचित दामों में अच्छी अध्ययन सामग्री तैयार करे तथा उसके उत्पादन को बढ़ावा दे, लोगों में पुस्तकों के प्रति रूचि पैदा करे। इन उद्देश्यों के अनुसरण में, न्यास एक सुपरिभाषित श्रृंखलाओं में अंग्रेजी के साथ भारतीय भाषाओं में पुस्तकें तैयार करता रहा है। न्यास राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय स्तरों पर पुस्तक मेले आयोजित करता है तथा पुस्तक लेखन के विभिन्न पहलुओं पर सेमिनार तथा संगोष्ठियां आयोजित करता है। इसके अलावा यह पुस्तकों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारतीय प्रकाशन उद्योग की ओर से विदेशों में आयोजित पुस्तक प्रदर्शनियों में भी भाग लेता है। न्यास के बंगलौर तथा बम्बई स्थित दो क्षेत्रीय कार्यालय है तथा अमृतसर, बंगलौर, बम्बई, कलकत्ता, हैदराबाद, मैसूर, शांति निकेतन तथा नई दिल्ली में आठ पुस्तक केन्द्र है।

प्रकाशन कार्यक्रम :

11.1.2 कुछ महत्वपूर्ण विषय जिनमें न्यास पुस्तकें प्रकाशित करता है वे हैं : भारत – लोगों की भूमि, राष्ट्रीय जीवनियां, युवा भारत, लोकप्रिय विज्ञान, आज का विश्व, आदान-प्रदान और नेहरू बाल पुस्तकालय। इन सतत् योजनाओं के अलावा न्यास ने स्कूल पुस्तकालय कार्यक्रमों, नौसिखियों तथा स्कूल बीच में छोड़ जाने वालों की शिक्षा को जारी रखने के लिए पाठ्य सामग्री और प्राचीन साहित्य के प्रकाशन आदि के लिए पुस्तकों के प्रकाशन के लिए नई योजनाएं शुरू की हैं।

प्रकाशन (सतत् योजनाएं)

11.1.3 पिछले वर्षों के दौरान विभिन्न श्रृंखलाओं और भाषाओं में पुस्तकों तथा आने वाले वर्षों के दौरान सम्भावित मांग के आधार पर न्यास ने अब अपनी सतत् योजनाओं में वर्ष 1988-89 से एक आवश्यकता पर आधारित भाषावार प्रकाशन कार्यक्रम आरंभ किया है। उक्त प्रकाशन कार्यक्रम को तैयार करने के फलस्वरूप एक निर्धारित प्रकाशन समय-सारिणी तैयार की गई है और आशा है कि आने वाले महीनों के दौरान पिछले वर्षों में प्रकाशित और मुद्रित पुस्तकों के मुकाबले कहीं बेहतर संख्या में पुस्तकें प्रकाशित की जाएंगी। अप्रैल और अक्तूबर, 1988 के बीच न्यास ने 102 पुस्तकें प्रकाशित कीं जिनमें से 29 मूल पुस्तकें और 73 पुनः मुद्रित हैं।

11.1.4 चूंकि बड़ी मात्रा में पाण्डुलिपियां प्रैस में हैं और पुस्तकों का प्रकाशन कार्यक्रम के अनुसार एक योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है।अतः यह आशा

31-12-88 की स्थिति

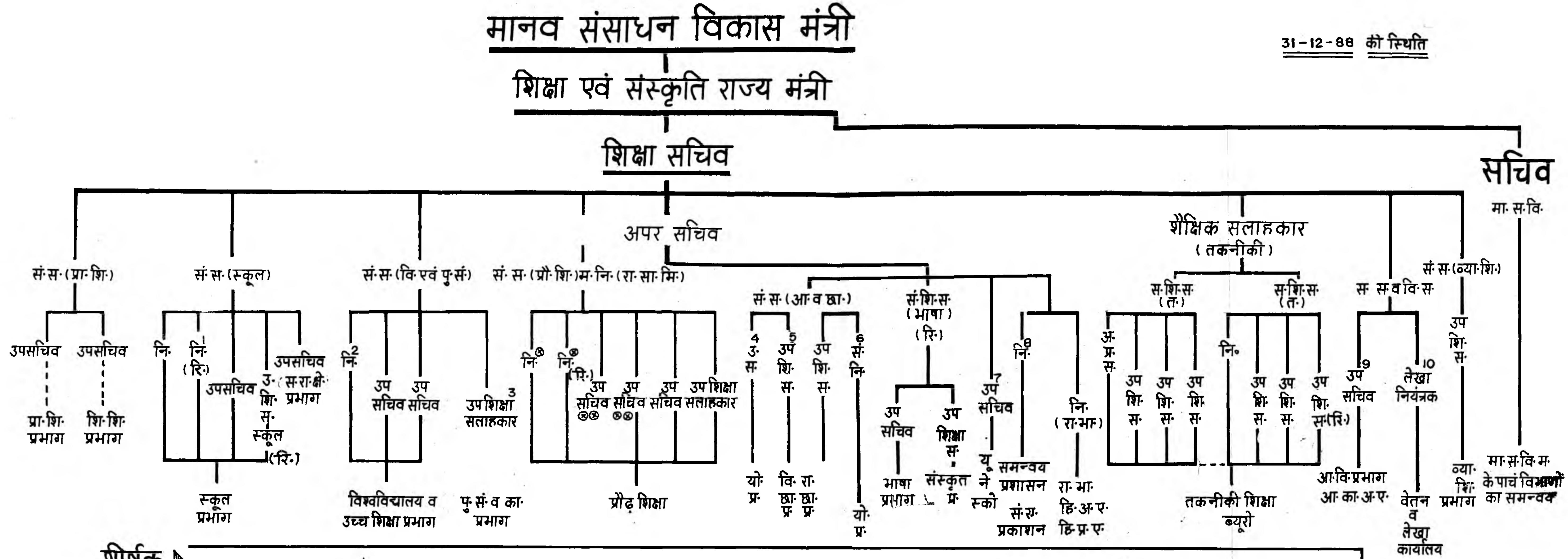

शीर्षक

प्रौ· शि·	प्रौढ़ शिक्षा
अ· प्र· स·	अपर प्रशिक्षुता सलाहकार
प्र·	प्रशासन
पु· सं·	पुस्तक संवर्द्धन
ले· नि·	लेखा नियंत्रक
स·	समन्वय
नि·	निदेशक
प्र·	प्रभाग
प्रा· शि·	प्रारम्भिक शिक्षा
वि· छा·	विदेश छात्रवृत्ति
वि· स·	वित्त सलाहकार
हि· अ· ए·	हिन्दी अनुवाद एकक
आ· वि· प्र·	आन्तरिक वित्त प्रभाग
आ· का· अ· ए·	आन्तरिक कार्य अध्ययन एकक
स· स·	संयुक्त सचिव
सं· शि· स·	संयुक्त शिक्षा सलाहकार
हि· प्र· ए·	हिन्दी प्रकाशन एकक
सं· ए·	संसद एकक

भा·	भाषा
रा· छा·	राष्ट्रीय छात्रवृत्ति
रा· सा· मि·	राष्ट्रीय साक्षरता मिशन
रा· भा·	राजभाषा
वे· ए· ले· का·	वेतन एवं लेखा कार्यालय
यो· एवं छा·	योजना एवं छात्रवृत्ति
यो·	योजना
स्कूल	स्कूल
शि· शि·	शिक्षक शिक्षा
त·	तकनीकी
वि·	विश्वविद्यालय
स· रा· क्षे· प्र·	संघ राज्य क्षेत्र प्रभाग
व्या· शि·	व्यावसायिक शिक्षा
रि·	रिक्त
⊗	पदेन अपर महानिदेशक राष्ट्रीय साक्षरता मिशन
⊗⊗	पदेन निदेशक राष्ट्रीय साक्षरता मिशन
प्र·	प्रकाशन एकक

1. पद उपसचिव के रूप में प्रयुक्त है
2. – वही –
3. – वही –
4. पद निदेशक के रूप में प्रयुक्त है
5. पद उपसचिव के रूप में प्रयुक्त है
6. – वही –
7. पद निदेशक के रूप में प्रयुक्त है
8. पद उपसचिव के रूप में प्रयुक्त है
9. पद निदेशक के रूप में प्रयुक्त है
10. पद उप लेखा नियंत्रक के रूप में प्रयुक्त है

की जाती है कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान न्यास कई और पुस्तकें प्रकाशित करेगा।

महत्वपूर्ण (कोर) पुस्तक परियोजना और सहायता प्राप्त योजना

11.1.5 स्वदेशी लेखकों को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय के पास भारतीय लेखकों द्वारा लिखी गई विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों के प्रकाशन के लिए सहायता देने की एक योजना है जिसका उद्देश्य छात्रों को उचित दामों में पुस्तकें उपलब्ध कराना है। यह योजना राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के माध्यम से वर्ष 1970 से कार्यान्वित की जा रही है। आलोच्य वर्ष के दौरान, न्यास ने सहायता प्राप्त पुस्तकों के प्रकाशन के लिए योजना के नियमों को संशोधित किया है ताकि निजी प्रकाशकों को अधिकाधिक भाग लेने के लिए आकर्षित किया जा सके, जिनके लिए मुख्य तौर से यह योजना बनाई गई है। पद्धतियों को सफल बनाने के अलावा संशोधित नियमों में इस योजना को इसके उपयुक्त परिप्रेक्ष्य में तर्कसंगत तरीके से प्रस्तुत किया गया है।

पढ़ने की आदतों को बढ़ावा देने के लिए न्यास द्वारा उठाए गए कदम

11.1.6 चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, न्यास अपने पुस्तक संवर्धन कार्यकलापों को बढ़वा दे रहा है। अब से मार्च, 1989 तक, पांच मुख्य पुस्तक मेले/उत्सव दिल्ली, लखनऊ, बम्बई, बड़ौदा और कोयम्बटूर में आयोजित किए गए/जा रहे हैं।

11.1.7 इसके अलावा, फरवरी, 1989 के प्रथम सप्ताह में अन्य कार्यकलापों के अतिरिक्त देश भर में एक साथ विश्वविद्यालयी शहरों में 40 प्रदर्शनियां आयोजित करते हुए एक राष्ट्रीय पुस्तक सप्ताह का आयोजन किया जाएगा।

11.1.8 भारत में सोवियत महोत्सव के भाग के रूप में न्यास ने मार्च, अप्रैल और मई 1988 में हैदराबाद, मद्रास और बंगलौर में सोवियत पुस्तक प्रदर्शनियां आयोजित कीं।

विदेशी मूल की विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों को कम कीमत पर प्रकाशित करना।

11.2.0 शिक्षा विभाग ब्रिटेन, अमेरिका, रूस तथा जर्मन की सरकारों के सहयोग से चार द्विपक्षीय कार्यक्रमों को चला रहा है ताकि विदेशी मूल की अच्छे स्तर की पुस्तकों को भारतीय विश्वविद्यालयों के छात्रों को कम कीमत के संस्करणों में उपलब्ध कराया जा सके। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत पुस्तकों के नवीन संस्करणों को शामिल करने पर विचार किया जाता है और इनका विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा इस दृष्टिकोण से मूल्यांकन किया जाता है कि यह भारतीय छात्रों के लिए उपयुक्त हैं तथा इसके बराबर के स्तर की भारतीय पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं। तत्पश्चात् अंग्रेजी तथा भारतीय भाषाओं में उपयुक्त पुस्तकों के प्रकाशन की सिफारिश की जाती है। वर्ष 1987-88 के अंत तक लगभग 763 ब्रिटिश, 1630 अमेरिकी, 600 सोवियत और 9 जर्मन पुस्तकें इन कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रकाशित की जा चुकी हैं। चालू वर्ष के दौरान 25 अमेरिकी और 33 सोवियत पुस्तकों के प्रकाशन की सिफारिश की गई है।

भारत सोवियत साहित्य परियोजना :

11.3.0 दोनों देशों की समकालीन रचनात्मक कृतियों के प्रकाशन के लिए गठित भारत-सोवियत समिति ने भारत तथा सोवियत रूस की 20वीं शताब्दी के साहित्य के अनुवाद को लगभग 20खण्डों में प्रकाशित कराने के लिए एक परियोजना तैयार की है। प्रथम दो खण्डों का मास्को में भारत महोत्सव के दौरान विमोचन किया गया। खण्ड 3 और 4 की विषय वस्तु की संरचना को भी अन्तिम रूप दे दिया गया है। सभी 20 खण्डों का प्रकाशन वर्ष 1995 तक किए जाने की संभावना है।

पुस्तकों और प्रकाशन के लिए नई आयात-निर्यात नीति :

11.4.1 पुस्तकों और प्रकाशन के लिए नई आयात-निर्यात नीति अप्रैल, 1988 से लागू की गई और यह मार्च 1991 तक लागू रहेगी। इस नीति की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:—

(1) सामान्य खुला लाइसैंस (ओ०जी०एल०) के अंतर्गत शैक्षिक, वैज्ञानिक और तकनीकी पुस्तकें और पत्र-समाचार पत्रिकाएं और समाचार-पत्र सभी व्यक्तियों द्वारा आयात किए जा सकते हैं।

(2) शिक्षण सहायक सामग्रियों और शैक्षिक स्वरूप की माइक्रो फिल्में और माइक्रोफिशे, शैक्षिक स्वरूप की श्रव्य कैसेटों/वीडियो टेपों सहित अथवा रहित फिल्म स्ट्राइपों/स्लाइडों का आयात केवल मान्यता प्राप्त शैक्षिक,

वैज्ञानिक, तकनीकी, अनुसंधान संस्थाओं, ऐसे संस्थाओं के पुस्तकालयों, केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के विभागों, अनुसंधान और विकास कार्य में संलग्न औद्योगिक एककों, पंजीकृत चिकित्सा संस्थानों, अस्पतालों, परामर्शदाताओं, मान्यताप्राप्त चैम्बर आफ कामर्स, उत्पादकता परिषदों, प्रबंध संघों और व्यावसायिक निकायों द्वारा किया जा सकता है।

11.4.2 तथापि उन विदेशी पुस्तकों के संस्करण जिसके लिए प्राधिकृत भारतीय पुनः मुद्रित संस्करण उपलब्ध हों, के आयात की स्वीकृति नहीं दी जाएगी। भारतीय प्रकाशनों के विदेशी पुनः मुद्रण की स्वीकृति इस मंत्रालय से पूर्व लिखित अनुमति के आधार पर दी जाएगी।

पुस्तक निर्यात और संवर्धन कार्यकलाप :

11.5.1 भारत विश्व के दस प्रमुख पुस्तक प्रकाशक देशों में से एक है। विदेशों में भारतीय पुस्तकों की बिक्री तथा अनुवाद/पुनर्मुद्रण के अधिकारों को प्रोत्साहित करने और विदेशों से मुद्रण कार्य प्राप्त करने के वास्ते अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तक मेलों में भाग लेकर तथा भारतीय पुस्तकों की विशेष प्रदर्शनियां आयोजित करके, टीका सहित सूची पत्रों, विवरणिकाओं आदि के परिचालन द्वारा वाणिज्यिक प्रचार तथा बाजार का अध्ययन करके हमारी पुस्तकों के प्रचार के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

11.5.2 वर्ष 1988-89 में भारत ने काहिरा, लंदन, सोफिया, मलेशिया, बीजिंग (चीन) सिंगापुर, फैंकफर्ट, सूराबया और बाली (इंडोनेशिया) में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तक मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लिया। कैनबरा, सोफिया, बुलगारिया और ब्रिसबेन में भारतीय पुस्तकों की विशेष प्रदर्शनियां आयोजित की गईं।

11.5.3 सोवियत संघ में भारत महोत्सव समारोहों के एक भाग के रूप में, सोवियत संघ के सात शहरों : ताशकंद, फ्रुंजे, डशानबे, विल्नियस, कीव, बाकु और मास्को में सात भारतीय, पुस्तक प्रदर्शनियों आयोजित की गयीं। प्रत्येक प्रदर्शनी में विभिन्न विषयों पर 3000 पुस्तकें प्रदर्शित की गयीं। इन पुस्तक प्रदर्शनियों के दौरान एक विशेष प्रदर्शनी "भारतीय प्रकाशन का इतिहास' का भी आयोजन किया गया था।

11.5.4 अप्रैल-नवम्बर, 1988 के बीच न्यास ने विदेश में अनेक प्रदर्शनियों और पुस्तक मेलों में भाग लिया और/अथवा पुस्तक व्यवसाय की सहभागिता की व्यवस्था की। इसने भारतीय पुस्तकों के लिए संयुक्त स्टाल स्थापित किये तथा विदेशी खरीदारों को भारतीय पुस्तकों और प्रकाशनों के सभी पहलुओं के सम्बन्ध में सूचना प्रदान की।

11.5.5 अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तक मेलों/विदेशों में प्रदर्शनियों में भाग लेने के परिणामस्वरूप वर्ष 1988-89 में पत्र-पत्रिकाओं सहित पुस्तकों का निर्यात 29 करोड़ रुपये तक बढ़ जाने का अनुमान है।

राजाराम मोहनराय राष्ट्रीय शैक्षिक संसाधन केन्द्र :

11.6.1 केन्द्र की स्थापना वर्ष 1972 में इस मुख्य उद्देश्य से की गई थी कि यह विश्वविद्यालय स्तर पर स्वदेशी पुस्तकों के लेखन और प्रकाशन को बढ़ावा देगा। इसका उद्देश्य पुस्तक प्रकाशन के क्षेत्र में विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों के लेखकों और प्रकाशकों तथा अनुसन्धान कार्यकर्ताओं को सेवाएं प्रदान करना है। यह स्वदेशी पाठ्य पुस्तकों के संबंध में सभी सूचना स्पष्ट करने के लिए एक आंकड़ा बैंक के रूप में कार्य करेगा। हिन्दी और अंग्रेजी सहित सभी क्षेत्रीय भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तर की मानक पाठ्य-पुस्तकों के लिए यह केन्द्र एक संदर्भ पुस्तकालय के रूप में कार्य करता है। यह केन्द्र मौके पर मूल्यांकन की अपनी अभिनव योजना के अंतर्गत सभी विषयों पर स्वदेशी पुस्तकों का विषय विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकन कराता है तथा भारतीय विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालय पाठ्य चर्चा में शामिल करने के लिए इन मानक पुस्तकों की सिफारिश करता है। अब तक विषय विशेषज्ञों की ऐसी अस्सी पैनल बैठकें आयोजित हो चुकी हैं और 750 पुस्तकों को मानक पुस्तकें निर्धारित किया गया है जिनमें से 105 को विभिन्न विश्वविद्यालयों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में शामिल कर लिया गया है।

11.6.2 शिक्षकों और छात्रों में मानक स्वदेशी पुस्तकों के प्रकाशन और विद्यमानता के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से केन्द्र बारी-बारी से विभिन्न विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों की प्रदर्शनियां समय-समय पर आयोजित करता है। वर्ष 1988-89 के दौरान, इस केन्द्र ने चार प्रदर्शनियां भोपाल विश्वविद्यालय जीवाजी विश्व-

विद्यालय, ग्वालियर, भारतीदासन विश्वविद्यालय, तिरूचिरापल्ली (तमिलनाडु) और श्री कृष्णदेव राय विश्वविद्यालय, अनंतपुर (आन्ध्र प्रदेश) में आयोजित की हैं।

11.6.3 यह केन्द्र अन्तर्राष्ट्रीय आई०एस०बी० एन० एजेंसी, बर्लिन के मार्गदर्शन से भारत में अन्तर्राष्ट्रीय मानक पुस्तक संख्या प्रणाली को लागू करने में एक राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है। यह एजेंसी प्रकाशकों को आई०एस०बी०एन० निःशुल्क देती है। अब तक इस एजेंसी ने आई०एस०बी०एन० प्रणाली के अन्तर्गत 600 से भी अधिक भारतीय प्रकाशकों को पंजीकृत किया है।

11.6.4 यह केन्द्र पुस्तक व्यापार और विश्वविद्यालयों के लाभ हेतु कई विशिष्ट प्रकाशनों का प्रकाशन कर रहा है। हाल ही में, इसने पुस्तक उद्योग और व्यापार पर पुस्तक सूची प्रकाशित की है। दो अन्य प्रकाशन अर्थात् आई०एस०बी०एन० पुस्तकों की राष्ट्रीय सारणी को भी प्रकाशित किया गया है। इसने आगे विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों के खण्ड 3 की राष्ट्रीय सारणी का प्रकाशन किया है जिसमें 3000 से अधिक विश्वविद्यालय स्तरीय पाठ्यपुस्तकों के बारे में जानकारी निहित है।

कापीराईट

11.7.1 कापीराईट कार्यालय की स्थापना जनवरी, 1958 में कापीराईट अधिनियम, 1957 की धारा 9 के अनुसरण में की गयी थी। वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1983 के कापीराईट संशोधन अधिनियम की वर्ष 1984 के कापीराईट संशोधन अधिनियम द्वारा कापीराईट अधिनियम में संशोधन किया गया।

11.7.2 वर्ष 1988 के दौरान (30.11.88 की स्थिति के अनुसार) कापीराईट कार्यालय ने 718 कार्य पंजीकृत किए जिनमें 441 कलात्मक कार्य, 276 साहित्यिक कार्य और एक गीतों के रिकार्ड शामिल है। इसके अलावा, कापीराईट कार्यालय ने 27 कलात्मक कार्यों और एक साहित्यिक कार्य के संबंध में कापीराईट के रजिस्टर में दर्ज कापीराईट के विवरणों में परिवर्तनों को पंजीकृत किया है।

11.7.3 कापीराईट बोर्ड, जो कि एक अर्धन्यायिक निकाय है, की स्थापना प्रारंभ में सितम्बर, 1958 में की गयी। कापीराईट बोर्ड का क्षेत्राधिकार पूरे भारत में है। यह कापीराईट पंजीकरण के परिशोधन कापीराईट कार्य के संबंध में विवादों के मामले की सुनवाई करता है। लोगों तक पहुंचने में रोके गये कार्यों के लिए लाइसेंस अप्रकाशित भारतीय कार्यों में अनिवार्य लाइसेंस, अनुवादों को तैयार करने और प्रकाशित करने के लिए लाइसेंस, कुछ प्रयोजनों के लिए कार्यों के प्रकाशन के लिए लाइसेंस देता है और कापीराईट अधिनियम, 1957 के अंतर्गत दायर विविध मामलों की सुनवाई करता है। इसके बोर्ड की बैठकें देश के विभिन्न क्षेत्रों में होती है ताकि लेखकों, सृजनकर्ताओं और बौद्धिक सम्पत्ति के मालिकों को उनके निवास अथवा व्यावसायिक स्थल के समीप न्याय की सुविधाएं मिल सकें। वर्ष 1988 के दौरान (30.11.1988 तक) बोर्ड ने 7 बैठकें आयोजित कीं और 201 मामलों पर सुनवाई की तथा 15 मामलों का फैसला किया और 23 चूककर्ताओं के मामलों को निरस्त कर दिया।

11.7.4 भारत कापीराईट संबंधी दो अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय अर्थात् साहित्यिक और कलात्मक कार्यों के संरक्षण के लिए वर्न अभिसमय और यूनिवर्सल कापीराईट अभिसमय का सदस्य है। इन दोनों अभिसमयों को जुलाई, 1971 में पेरिस में संशोधित किया गया था, ताकि इनमें विकासशील देशों को दी जाने वाली विशेष रियायतों को शामिल किया जा सके और वे शैक्षिक प्रयोजनों के लिए विदेशी मूल की पुस्तकों के पुनः प्रकाशन/अनुवाद के लिए अनिवार्य लाइसेंस जारी कर सकें, यदि कुछ शर्तों के अंतर्गत स्वतंत्रतापूर्वक आपसी बातचीत के माध्यम से इन अधिकारों को प्राप्त नहीं किया जा सका है। भारत ने दोनों अभिसमय स्वीकार कर लिये हैं।

विदेशी प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण सुविधाएं :

11.7.5 विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठन शिक्षा वृत्ति कार्यक्रम के अंतर्गत श्री एम०डी० सोमा वीरा ने कापीराईट के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए नवम्बर, 1988 में भारत का दौरा किया।

भारतीय प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण सुविधाएं :

11.7.6 श्री एस०ए० पद्मनाभन, विशेष अधिकारी (पुस्तक आयात) और मंत्रालय में कापीराईट के उप-रजिस्ट्रार ने जून, 1988 में स्विटजरलैंड में 1988 के लिए वाइपो शिक्षावृत्ति कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशासन कापीराईट और समीपवर्ती अधिकार संबंधी एक

विशिष्ट पाठ्यक्रम में भाग लिया।

वर्ष 1988 के लिए वाइपो शिक्षावृत्ति कार्यक्रम के अंतर्गत श्री एन०डी० ग्रोवर, डेस्क अधिकारी ने कापीराईट और समीपवर्ती अधिकार संबंधी एक सामान्य प्रारंभिक पाठ्यक्रम में 29 अगस्त से 13 सितम्बर, 1988 तक हंगरी में भाग लिया तथा जेनेवा, स्विटजरलैंड में 14 से 16 सितम्बर, 1988 तक बौद्धिक संपत्ति के नियम की उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के प्रभाव पर वाइपो विश्वव्यापी मंच में भाग लिया।

भाषाओं की प्रौन्नति

12.0.0 शिक्षा के लिए भाषाओं का बहुत महत्व है। अतः राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भाषाओं के विकास को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। यही कारण हैं कि एक ओर संस्कृत और उर्दू सहित संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित 14 भाषाओं तथा दूसरी और अंग्रेजी और विदेशी भाषाओं की प्रोन्नति और विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया गया। इस दायित्व के निर्वाह के लिए विभाग की सहायता के लिए अनेक स्वायत्त संगठन और अधीनस्थ कार्यालय हैं अर्थात केन्द्रीय हिंदी शिक्षण मंडल, आगरा, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली तथा इसके 8 विद्यापीठ केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर तथा इसके 4 क्षेत्रीय केन्द्र और 2 उर्दू प्रशिक्षण और अनुसंधान केन्द्र; केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, नई दिल्ली, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, नई दिल्ली तथा तरक्की-ए-उर्दू ब्यूरो, नई दिल्ली। आलोच्य वर्ष के दौरान विभाग द्वारा अपने पहले से चल रहे कार्यक्रमों और योजनाओं को जारी रखा गया। वर्ष 1988-89 के दौरान भाषाओं की प्रौन्नति और विकास के सम्बन्ध में किए गए महत्वपूर्ण कार्यकलाप निम्नलिखित हैं :—

हिंदी की प्रौन्नति और विकास

12.1.0 दूसरी पंचवर्षीय योजना से ही अहिंदी भाषी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के अपर-प्राथमिक से लेकर उच्चतर-माध्यमिक स्कूलों में हिंदी शिक्षकों की नियुक्ति के लिए केंद्रीय सहायता उपलब्ध की जा रही हैं। इस योजना के अंतर्गत शत-प्रतिशत सहायता दी जाती है। अब तक चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान अहिंदी भाषी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लगभग 7,000 हिंदी शिक्षकों को नियुक्त किया जा चुका है। इसी प्रकार की एक अन्य योजना है जिसके अंतर्गत अहिंदी भाषी राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों को हिंदी शिक्षक प्रशिक्षण कालेजों की स्थापना के लिए शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जाती है। इसी प्रयोजन के लिए यह सहायता स्वैच्छिक संगठनों को भी उपलब्ध है। अब तक इस योजना के अंतर्गत 29 कालेज लाभान्वित हो चुके हैं जिनमें से 19 कालेज राज्य सरकारों द्वारा और 10 स्वैच्छिक संगठनों द्वारा चलाए जा रहे हैं। इन कालेजों में वार्षिक प्रवेश क्षमता लगभग 1000 प्रशिक्षणार्थी हैं।

12.1.1 भाषा अध्ययन और भाषा विश्लेषण के लिए शब्द-कोशों को बहुत महत्वपूर्ण पाया गया है। अतः शब्दकोश प्रयोजनाओं को समुचित महत्व दिया गया है। इन प्रयोजनाओं के अंतर्गत केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय द्वारा 13 हिंदी आधारित और 13 क्षेत्रीय भाषा आधारित शब्द-कोश संकलित किए जा रहे हैं। अब तक हिंदी-गुजराती, हिन्दी-सिंधी, हिंदी-उर्दू, हिंदी-मराठी, हिंदी-असमी, हिंदी-तमिल, हिंदी-तेलुगु, हिंदी-मलयालम, हिंदी-उड़िया शब्दकोश प्रकाशित किए जा चुके हैं। केन्द्रीय हिंदी निदेशालय ने 5 त्रि-भाषा शब्दकोश भी प्रकाशित किए हैं और हिंदी पर आधारित 12 और क्षेत्रीय भाषाओं पर आधारित 12 त्रि-भाषा कोशों का संकलन कार्य चल रहा है। निदेशालय द्वारा एक बहु-भाषा कोश भी प्रकाशित किया गया है। एक तत्सम शब्दकोश जिसमें 2000 हिन्दी शब्दों के तत्सम शब्द 13 क्षेत्रीय भाषाओं में दिए गए हैं प्रकाशित किया जा चुका है। सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों के अंतर्गत हिंदी-चीनी, हिंदी-अरबी, हिंदी-फ्रेंच और हिंदी-स्पेनिश शब्दकोश भी प्रकाशित किए जा चुके है।

12.1.2 मूल विज्ञानों, अनुप्रयुक्त विज्ञानों समाज-विज्ञानों और मानविकी से सम्बन्धित 27 विषयों के वैज्ञानिक और तकनीकी लगभग 5 लाख शब्दों को समन्वित और विषयवार शब्द संग्रहों के रूप में प्रकाशित किया जा चुका है। कम्प्यूटर विज्ञान, मुद्रण प्रौद्योगिकी और आधुनिक वास्तु-कला जैसे उन्नत और विशिष्ट क्षेत्रों की शब्दावली के मूल्यांकन का कार्य चल रहा है। केन्द्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा अंग्रेजी पत्रिका "यूनेस्को कूरियर" का हिंदी रूपान्तर, "यूनेस्को दूत" शीर्षक से प्रकाशित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त निदेशालय एक त्रैमासिक पत्रिका "भाषा" और एक वार्षिक पत्रिका "वार्षिकी" का प्रकाशन भी कर रहा है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग भी इसी प्रकार "विज्ञान गरिमा सिन्धु" नाम से एक विज्ञान पत्रिका का प्रकाशन कर रहा है। सामाजिक विज्ञानों के लिए इसी प्रकार "विज्ञान गरिमा सिंधु" नाम की एक ओर पत्रिका इस वर्ष से प्रकाशित करने की योजना बनाई गई हैं।

12.1.3 विश्वविद्यालय स्तर पर अंग्रेजी के स्थान पर शिक्षा माध्यम के रूप में हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं को अपनाने से संबंधित नीति-निर्देश का अनुसरण करते हुए विभिन्न विषयों में विश्वविद्यालय स्तरीय पाठ्य-पुस्तकों के निर्माण की एक योजना बनाई गई थी। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य को 100 लाख रुपये तक केन्द्रीय सहायता उपलब्ध है। यह सहायता इस योजना में भाग लेने के लिए 15 राज्यों और 4 विश्वविद्यालयों को उपलब्ध की गई ताकि वे उच्च-शिक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं को अपना सकें। इस योजना के अंतर्गत कुल 8300 पुस्तकें प्रकाशित/पुन:प्रकाशित की जा चुकी हैं। यह पुस्तकें हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में हैं और इनमें से 280 पुस्तकें इस योजना की मुख्य एजेंसी अर्थात वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा प्रकाशित की गई हैं।

12.1.4 हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं की प्रौन्नति और प्रचार के लिए प्रकाशन निकालने हेतु स्वैच्छिक संगठनों, संस्थाओं, न्यासों तथा व्यक्तियों को वित्तीय सहायता दी जा रही है। यह सहायता सरकार द्वारा स्वीकृत कुल लागत अनुमानों के 80% तक दी जाती हैं। सुदूर शिक्षा के महत्व को स्वीकार करते हुए केन्द्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा अंग्रेजी, तमिल, बंगला और मलयालम के माध्यम से हिंदी शिक्षण के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। चालू वर्ष के दौरान इन पाठ्यक्रमों में लगभग 15 हजार छात्र प्रशिक्षण पा रहे हैं।

12.1.5 केन्द्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा अहिंदी भाषिओं के अध्ययन दौरे हिंदी भाषी क्षेत्रों में आयोजित किए गए। इसके अतिरिक्त अहिंदी भाषी क्षेत्रों के शोध कर्त्ताओं को यात्रा अनुदान भी दिए गए। इसी प्रकार विद्वानों की व्याख्यान यात्राओं का भी आयोजन किया गया। हिंदी के मूल लेखन को प्रोत्साहन देने के लिए अहिंदी भाषी क्षेत्रों में नव-हिंदी लेखकों के लिए 8 लेखक कार्यशालाएं भी आयोजित की गईं। इसके अतिरिक्त अहिंदी भाषी क्षेत्रों में भारतीय साहित्य के विभिन्न पहलुओं पर परिचर्चाओं के लिए संगोष्ठियां भी आयोजित की गईं।

12.1.6 वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा विश्वविद्यालय/कालेज स्तर के शिक्षकों के लिए कार्यशालाएं आयोजित की गई ताकि उन्हें आयोग द्वारा बनाई गई शब्दावलियों के माध्यम से शिक्षण में हिंदी के प्रयोग के संबंध में मार्गदर्शन दिया जा सके।

12.1.7 अहिंदी भाषी राज्यों के हिंदी शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से केन्द्रीय हिंदी संस्थान द्वारा अनेक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में निष्णात और पारंगत प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम शामिल हैं। संस्थान द्वारा जन-जातीय क्षेत्रों के हिंदी शिक्षकों के लिए विस्तार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। संस्थान विदेशियों को हिंदी पढ़ाने के लिए एक सम्पूर्ण शैक्षिक पाठ्यक्रम भी चला रहा है। चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा इन विदेशी छात्रों को 50 छात्रवृत्तियां प्रदान की गईं।

12.1.8 प्रधान मंत्री जी द्वारा 13.2.1989 को केन्द्रीय हिन्दी संस्थान की रजत जयन्ती समारोह का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने हिन्दी की उल्लेखनीय सेवाओं के लिए निम्नलिखित पुरस्कार प्रदान किये।

(क) हिन्दी प्रचार तथा शिक्षण प्रशिक्षण

(1) श्री मो० सत्यनारायण
(2) श्री गो०पे० नेने
(3) श्री गिरिराज किशोर
(4) श्री शंकर राव लौंढे
(5) श्रीमती मुतुबाई माने
(6) श्री रजनीकांत चक्रवर्ती
(7) श्री एम०के० वेलायुधन नायर

(8) श्री शा. रा. शारंगपाणि

(9) श्री दत्तात्रेय मिश्र

(10) श्री नरसिंह नन्द शर्मा

(11) श्री एच० गोकुलानन्द शर्मा

(12) श्री नरेन्द्र अंजारिया

(ख) (1) श्री धर्मवीर भारती — हिन्दी पत्रकारिता और

(2) श्री बालशौरि रड्डी — रचनात्मक साहित्य

(3) श्री के०जी० बाल कृष्ण पिल्लै

(ग) (1) श्री राम चरण मेहरोत्रा — हिन्दी में वैज्ञानिक

(2) डा० ब्रज मोहन — साहित्य तथा उपकरण

(3) डा० ओम विकास — आदि का विकास

(4) श्री गुणाकर मुले

(घ) (1) डा० प्रभाकर माचवे — हिन्दी की प्रोन्नति

(2) डा० ब्रजेश्वर वर्मा — और विकास आदि

(3) डा० हरदेव बाहरी

(4) डा० एन० नागप्पा

(5) प्रो० रामसिंह तोमर

12.1.9 एक अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के परामर्श से विचार किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त टिप्पणियां सम्प्रति एक उच्च स्तरीय समिति के विचाराधीन है।

12.1.10 हिंदी की प्रौन्नति विकास और प्रचार में कार्यरत स्वैच्छिक संस्थाओं को प्रोत्साहन देने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा उन्हें उनके स्वीकृत अनुमानों के 75% तक वित्तीय सहायता दी जा रही है। लगभग 170 संगठन इस सहायता से लाभान्वित हो रहे हैं। दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा और अखिल भारतीय संस्था संघ को शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता दी जा रही है।

ख. आधुनिक भारतीय भाषाओं की प्रौन्नति और विकास

12.2.1 त्रिभाषा सूत्र को कार्यान्वित करने के लिए शिक्षकों के आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षण और विकास की ध्यान रखते हुये, केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान अपने चार क्षेत्रीय भाषा केंद्रों और दो उर्दू प्रशिक्षण अनुसंधान केन्द्रों में विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के स्कूली शिक्षकों के लिए एक शैक्षिक वर्ष के पाठ्यक्रम चला रहा है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित तीन सौ सत्तानवे शिक्षक-प्रशिक्षुओं को 13 भाषाओं में दाखिला दिया गया था। इसके अलावा 110 पत्राचार पाठ्यक्रमों द्वारा तमिल और बंगला में प्रयोगात्मक आधार पर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। भाषा में दक्षता के मूल्यांकन के लिए भाषाओं में योग्यता परीक्षा को विकसित करने के लिए, संस्थान ने सात भाषाओं के परीक्षा पाठों को भी तैयार कर लिया है जबकि अन्य सात भाषाओं के परीक्षा पाठों को तैयार किया जा रहा है।

12.2.2 जनजातीय भाषाओं में तथा उन पर कई पुस्तकें प्रकाशित किए जाने के अलावा, संस्थान द्वारा कई जनजातीय और सीमावर्ती भाषाओं में व्याकरणों, शब्दकोशों और प्रवेशिकाओं का प्रकाशन किया गया है। दक्षिण भारत में उर्दू प्रौन्नति के कार्यकलापों को तेजी से आगे बढ़ाने हेतु ब्यूरो ने हैदराबाद में शाखा कार्यालय की स्थापना की है। उर्दू में सुलेखन कला के परिरक्षण और विकास के लिए, उर्दू प्रौन्नति ब्यूरो द्वारा देश में 36 सुलेखन प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की गई है जिनमें से 6 केन्द्र केवल महिलाओं के लिए हैं। इन केन्द्रों से अब तक लगभग 1000 छात्र लाभान्वित हुये हैं। ब्यूरो द्वारा उर्दू में बहुत से प्रकाशन भी निकाले गये हैं तथा इसके अलावा उर्दू में तकनीकी शब्दों की एक शब्दावली भी प्रकाशित की गई है। उर्दू प्रौन्नति ब्यूरो द्वारा "फिकरो तहकीक" नामक उर्दू में शोध पत्रिका का भी प्रकाशन किया जा रहा है।

12.2.3 आधुनिक भारतीय भाषाओं की प्रौन्नति और प्रचार को दृष्टिगत रखते हुए प्रकाशनों को निकालने के लिए स्वैच्छिक संगठनों और व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इसी प्रकार, आधुनिक भारतीय भाषाओं की प्रौन्नति के कार्य में लगे हुये स्वैच्छिक संगठनों को केंद्रीय सहायता मिलती है। योजना के अंतर्गत सहायता का स्वरूप हिन्दी के लिए दी जाने वाली सहायता के स्वरूप की तरह है।

12.2.4 सिंधी की प्रौन्नति और विकास के लिए केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय द्वारा योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं जिसमें सिंधी की प्रौन्नति और प्रचार में लगे स्वैच्छिक संगठनों को प्रकाशन सहायता तथा वित्तीय सहायता और सिंधी अध्येताओं को पुरस्कार प्रदान करना शामिल है।

अंग्रेजी की निपुणता में सुधार

12.3.1 देश में अंग्रेजी के अध्ययन/अध्यापन के स्तरों में पर्याप्त सुधार लाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा

प्रत्येक राज्य में अंग्रेजी भाषा के लिए कम से कम एक जिला केन्द्र की स्थापना के लिए, केन्द्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान के माध्यम से सहायता प्रदान की जा रही है। अब तक 22 केन्द्र स्थापित किये जा चुके है। सरकार केन्द्रीय और विदेशी भाषा संस्थान के माध्यम से विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय अंग्रेजी संस्थाओं और अंग्रेजी भाषा शिक्षण संस्थाओं को सुदृढ़ करने हेतु सहायता प्रदान कर रही है।

12.3.2 सरकार द्वारा सी.आई.ई.एफ.एल. के साथ सहयोग से क्षेत्रीय अंग्रेजी भाषा संस्थान को एक योजना सौंपी गई है जिसके अंतर्गत Xवीं कक्षा के बाद के छात्रों तथा भारत में उच्च अध्ययन हेतु आए विदेशी छात्रों की अंग्रेजी दक्षता के स्तर के मूल्यांकन के लिए परीक्षाएं तैयार की जाएंगी। "टी.ई.पी.-10" और "टी.ई.पी.-12" नामक अंग्रेजी दक्षता का मूल्यांकन करने वाली ये परीक्षाएं तैयार होने वाली है।

संस्कृत और अन्य श्रेण्य भाषाओं की प्रौन्नति

12.4.1 राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में और हमारी सांस्कृतिक धरोहर के समझने तथा उसके परिरक्षण में संस्कृत के महत्व को मान्यता देते हुये, सरकार द्वारा संस्कृत शिक्षण और अध्ययन के विकास और प्रौन्नति हेतु कई कार्यक्रम आरम्भ किये गये है। दो अन्य श्रेण्य भाषाओं अरबी और फारसी के प्रचार और विकास के लिए भी कार्यक्रम जारी हैं। 1988-89 के दौरान संस्कृत भाषा (पालि और प्राकृत सहित) साहित्य और अध्ययन की प्रौन्नति हेतु शुरू किये गये कुछ मुख्य कार्यक्रम निम्नलिखित हैं :-

संस्कृत के प्रचार और विकास में लगी स्वैच्छिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना

12.4.2 इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत संस्कृत संगठनों/संस्थाओं को शिक्षकों के वेतन, छात्रों को छात्रवृत्ति देने, भवन, फर्नीचर, पुस्तकालय आदि के निर्माण और मरम्मत के लिए आवर्ती और अनावर्ती अनुदान प्रदान किये जाते हैं। उपरोक्त प्रत्येक मद पर अनुमोदित व्यय का पिचहत्तर प्रतिशत मंत्रालय द्वारा अनुदान के रूप में दिया जाता है और उन वैदिक संस्थाओं को जहां मौखिक वैदिक परम्पराओं का संरक्षण किया जा रहा है, कुल अनुमोदित व्यय का 95% सरकारी अनुदान के रूप में दिया जाता है। इस वर्ष के दौरान लगभग 700 संस्कृत संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

आदर्श संस्कृति महाविद्यालय/शोध संस्थाएं

12.4.3 स्वैच्छिक संगठनों में से कुछ संस्थाओं में भावी विकास की क्षमता है और वे स्नातकोत्तर शिक्षा प्रदान कर रही हैं, उनको 95% आवर्ती और 75% अनावर्ती व्यय की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अभी तक 12 स्नातकोत्तर शिक्षण संस्थाओं और 2 स्नातकोत्तर अनुसंधान संस्थाओं को इस योजना के अंतर्गत लाया गया है। इनमें से तीन उत्तर प्रदेश में, एक केरल में, तीन बिहार में, दो हरियाणा में, दो महाराष्ट्र में तथा 3 तमिलनाडु में है।

राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान

12.4.4 अनुसंधान, प्रकाशन, पाण्डुलिपियों के संग्रह और उनके संरक्षण तथा प्रशिक्षण संबंधी कार्यकलापों के आयोजन सहित संस्कृत के संरक्षण और प्रसार के लिए मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त शासी संगठन के रूप में इस संस्थान का गठन किया गया है। सन् 1970 से अब तक इसने सात राज्यों में तिरूपति, दिल्ली, जम्मू, इलाहाबाद, पुरी, गुरूवायुर, जयपुर और लखनऊ स्थित 8 केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठों की स्थापना की है। इसके अलावा, इसने परीक्षा के प्रयोजनार्थ अपने से लगभग 39 प्राइवेट संस्थाओं को सम्बद्ध किया है। यह प्रथमा से विद्यावारिधि तक परीक्षा आयोजित करता है और प्रमाण-पत्र तथा डिग्रियां प्रदान करता है। यह स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर तक अध्यापक-प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। इस समय संस्थान के विद्यापीठों में 2000 छात्र दाखिल हैं जिनमें से 1200 छात्रों को उनके अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियां दी जाती हैं और लगभग 700 छात्रों को छात्रावास संबंधी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्थाएं

12.4.5 दिल्ली तथा तिरूपति स्थित दो विद्यापीठों को 16 नवम्बर, 1987 को विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्थाओं के रूप में घोषित किया गया है।

12.4.6 इन विद्यापीठों ने प्रशिक्षण देने के अलावा अनेक अनुसंधान विकास तथा विस्तार संबंधी क्रियाकलापों को भी आरम्भ किया है। उन पर नीचे चर्चा की गई है :-

इलाहाबाद विद्यापीठ : जो पाण्डुलिपियों के संग्रह और उनके परिरक्षण में एक विशिष्ट संस्था है, ने अब तक

लगभग 50000 पांडुलिपियां एकत्र की है और अनेक महत्वपूर्ण कृतियां प्रकाशित की हैं। इसने कश्मीर शैववाद से संबंधित कश्मीर विश्वविद्यालय से पाण्डुलिपियों की माइक्रो फिल्म तैयार करने की योजना बनाई है। यह कार्य चल रहा है।

तिरूपति विद्यापीठ : निम्नलिखित परियोजनाओं पर कार्य कर रहा है :–

अगम कोष : बैरवानस अगम कोष मुद्रण के लिए लिया गया है। पन्कारत्रा तथा शैववाद कोष इसके बाद होंगे।

वेदों की टेप रिकार्डिंग : विभिन्न शाखाओं का वैदिक गायन 1200 घंटे तक रिकार्ड किया गया। आगे का कार्य तिरूपति तिरूमाला देवस्थानम् की सहायता से प्रगति पर है।

मौखिक शास्त्रीय परम्पराओं की टेप रिकार्डिंग : मीमांसा परम्परा की टेप रिकार्डिंग पूरी हो गई तथा न्याय परम्परा की रिकार्डिंग शुरू हो गई है।

जम्मू विद्यापीठ : इस विद्यापीठ की कश्मीर शैव दर्शन में विशेषज्ञता है तथा कश्मीर शैव दर्शन की पाण्डुलिपि पूरी की गई। पुनरीक्षण जारी है। इस परम्परा की पाण्डुलिपियों के संकलन के लिए श्रीनगर में एक केन्द्र खोला जा रहा है।

दिल्ली विद्यापीठ : सांख्य व योग पर एक संदर्भ कोष तैयार करने में विशेषज्ञ है जिसकी पाण्डुलिपि पूरी हो गई है। कमेन्ट्री के साथ-2 सबारा भाष्य का मुद्रण प्रगति पर है।

12.4.7 **मुख्यालय का कार्यालय** : मीमांसा पर टीका सहित श्लोक वर्तिका। संस्कृत में विद्यार्थियों के लिए वेदों ने चुने गये स्रोत सूत्रों का एक अध्ययन प्रगति पर है। कुल मिलाकर विभिन्न विद्यापीठों तथा संस्थान के मुख्यालय के कार्यालय से 155 प्रकाशन निकाले गये हैं। मुख्यालय कार्यालय द्वारा संस्कृत साहित्य के छात्रों के लिए, लिए गए संक्षिप्त खण्ड पूरे हो गये है। वर्ष के दौरान मीमांसा व शैववाद पर सेमिनार क्रमशः तिरूपति व श्रीनगर में आयोजित किये गये।

12.4.8 वर्ष 1988 के दौरान, लगभग 154 विद्यार्थियों को विभिन्न विद्यापीठों के विद्यावारिधि पाठ्यक्रम के लिए पंजीकृत किया गया तथा लगभग 24 विद्यार्थियों को विद्यावारिधि की डिग्री प्रदान की गई।

छात्रवृत्तियां

12.4.9 राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से, दो छात्रवृत्ति कार्यक्रम चला रहा है।

संस्कृत पाठशालाओं के छात्रों के लिए अनुसन्धान छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत अनुसंधान अध्येताओं को दो वर्ष की अवधि के लिए 300 रु० मासिक भत्ता दिया गया है। इसके अलावा प्रत्येक विद्यार्थी को 500 रु० वार्षिक दर से एक आकस्मिक अनुदान भी दिया गया है।

उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्ति के अंतर्गत वे विद्यार्थी, जिन्होंने आधुनिक धारा में एम.ए./आचार्य, पी.एच.डी. स्तरों तथा संस्कृत एक विषय के रूप में पढ़ी है, को क्रमशः 100 रु० प्रति माह तथा 300 रु० प्रतिमाह की दर से छात्रावृत्ति दी गई।

संस्कृत शब्दकोष परियोजना, दि दक्कन कालेज, पुणे

12.4.10 दक्कन कालेज, पुणे को ऐतिहासिक सिद्धान्तों पर एक शब्दकोष तैयार करने के लिए सहायता उपलब्ध कराई जा रही है यह अनुसंधान अध्येताओं की प्राचीन तथा कठिन संस्कृत भाष्यों के अनुवाद में सहायता करेगा। भाग I व II खण्डों के प्रत्येक के तीन भाग, तथा खण्ड III का एक भाग प्रकाशित किये जा चुके हैं।

शास्त्रों में गहन अध्ययन प्रदान करने के लिए जान-माने वरिष्ठ संस्कृत विद्वानों की सेवाओं का प्रयोग

12.4.11 इस योजना के अंतर्गत 85 जाने-माने संस्कृत विद्वानों को स्टाफ के कनिष्ठ सदस्यों तथा आदर्श संस्कृत पाठशालाओं के वरिष्ठ छात्रों, कुछ महत्वपूर्ण स्वैच्छिक संस्कृत शिक्षण संस्थानों, अनुसंधान केन्द्रों तथा संस्कृत विश्वविद्यालयों को उच्च भाष्यों, अनुसंधान तथा प्रणाली-विज्ञान में गहन अध्ययन में मार्ग-दर्शन के लिए मान्यता दी गई है यह विद्वान 1000 रु० प्रतिमाह के मानदेय पर नियुक्त किये गये हैं

संस्कृत के अलावा अरबी व फारसी जैसी प्राचीन भाषाओं के विकास तथा प्रसार में संलग्न स्वैच्छिक संगठनों के लिए वित्तीय सहायता

12.4.12 इस योजना के अंतर्गत, अरबी व फारसी

की उन्नति के लिए कार्य कर रहे पंजीकृत स्वैच्छिक संगठनों को वेतन, छात्रवृत्ति, फर्नीचर, पुस्तकालय आदि व अन्य गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता दी गई। इस योजना के अंतर्गत लगभग 200 संस्थाओं को सहायता दी जा रही है। अरबी और फारसी ने उच्च अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए परम्परागत मदरसों व मकतबों के विद्यार्थियों को भी प्रत्येक वर्ष छात्रवृत्तियां दी गई

संस्कृत, अरबी व फारसी के विद्वानों को सम्मान-पत्र प्रदान करना

12.4.13 यह योजना जाने-माने संस्कृत, अरबी व फारसी विद्वानों को राष्ट्रपति का पुरस्कार, सम्मान प्रमाण पत्र देने पर विचार करती है। प्रत्येक वर्ष 14 विद्वानों को, 10 संस्कृत तथा अरबी व फारसी प्रत्येक में 2, पुरस्कार के लिए चुनती है तथा उनके नाम स्वतंत्रता दिवस की संध्या को घोषित किये जाते है। पुरस्कार में जीवन भर के लिए 10,000/- रु० का वार्षिक वित्तीय अनुदान है। प्रत्येक विद्वान को राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में एक सनद तथा शाल भेंट की जाती है। पिछले वर्षो के समान, इस वर्ष भी 14 विद्वानों को पुरस्कार के लिए चुना गया है।

राज्य सरकारों/केन्द्र शासित क्षेत्रों के द्वारा संस्कृत के विकास के लिए योजना

अभावग्रस्त परिस्थितियों में रह रहे संस्कृत के जाने-माने विद्वानों को वित्तीय सहायता

12.4.14 लगभग 1460 जाने माने विद्वानों को, जिनकी आय 4000/- रु० प्रति वर्ष से कम है इस योजना के अंतर्गत 4000/- रु० प्रति वर्ष तक की वित्तीय सहायता दी जा रही हैं।

संस्कृत पाठशालाओं का आधुनिकीकरण

12.4.15 संस्कृत शिक्षा की परम्परागत तथा आधुनिक प्रणाली के बीच तादात्म्य स्थापित करने के लिए भारत सरकार, राज्य सरकारों को परम्परागत संस्कृत पाठशालाओं में चुने हुये आधुनिक विषयों के शिक्षण के लिए शिक्षक नियुक्त करने लिए अनुदान दे रही है। 1988-89 के दौरान तीन राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों के एक-2 शिक्षक की नियुक्ति के लिए अनुदान जारी किए जाने की आशा है।

उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में संस्कृत शिक्षण के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना।

12.4.16 जहां राज्य सरकारें संस्कृत शिक्षण उपलब्ध कराने की स्थिति में नहीं हैं वहां उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में नियुक्त होने वाले संस्कृत शिक्षकों के वेतन के लिए भारत सरकार ने शत-प्रतिशत अनुदान देकर अंतर को पाटने के लिए कदम उठाये हैं। 1988-89 के दौरान नौ शिक्षकों की नियुक्ति के लिए तीन राज्यों द्वारा इस सुविधा से लाभ उठाने की आशा है।

उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में अध्ययनरत संस्कृत के छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां

12.4.17 उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में मेधावी छात्रों को संस्कृत अध्ययन की ओर आकर्षित करने के लिए 9वीं तथा 10वीं कक्षाओं में संस्कृत छात्रों के लिए 10/- रु० प्रति माह की दर से छात्रवृत्तियां दी गई। लगभग 3,000 छात्र इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। छात्रवृत्ति की राशि बढ़ाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

संस्कृत की उन्नति के लिए राज्य सरकारों को उनकी अपनी योजनाओं के लिए अनुदान

12.4.18 इस योजना के अंतर्गत, राज्य सरकारें संस्कृत के विकास और प्रसार के लिए शिक्षकों का वेतन बढ़ाना, वैदिक विद्वानों का सम्मान, विद्वत्त सभाओं का आयोजन, संस्कृत के लिए सांध्य कक्षायें चलाना, कालिदास समारोह मनाना जैसे कार्यक्रमों द्वारा अपने स्वयं के कार्यक्रम बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। इस योजना के अंतर्गत 1988-89 के दौरान पांच राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को सहायता दिए जाने की सम्भावना है।

संस्कृत साहित्य की रचना

12.4.19 इस योजना के अंतर्गत (i) संस्कृत साहित्य संबंधी मूल कृतियों का मुद्रण व प्रकाशन, (ii) अप्राप्य संस्कृत पुस्तकों का मुद्रण, (iii) विभिन्न संस्थाओं को नि:शुल्क वितरण के लिए लेखकों व प्रकाशकों से प्रकाशनों की खरीद (iv) संस्कृत पत्रिकाओं की गुणवत्ता व विषयवस्तु में सुधार (v) संस्कृत पाण्डुलिपियों की विस्तृत सूची को तैयार व प्रकाशित करना तथा संस्कृत पाण्डुलिपियों के आलोचनात्मक भाग का प्रकाशन, आदि के लिए सहायता दी गई है।

12.4.20 1988-89 के दौरान (दिसम्बर, 1988 के अंत तक) सरकारी सहायता से 20 प्रकाशन निकाले गये। 1988-89 के दौरान 20 और प्रकाशन निकाले जाने की आशा है।

इसके अलावा धर्मकोश मण्डल, वाई, जो प्राचीन संस्कृत साहित्य के एक धर्मकोश नामक विश्वकोश के निर्माण कार्य और प्रकाशन में लगा हुआ है, को सातवीं, पंचवर्षीय योजना की बाकी अवधि के दौरान, भारत सरकार द्वारा अनुदान की राशि दी जाएगी। अखिल भारतीय काशीराज ट्रस्ट, वाराणसी, सरकार की सहायता से सभी महापुराणों के हिन्दी अनुवाद; अंग्रेजी अनुवाद तथा आलोचनात्मक संस्करणों को निकालने के काम में लगा हुआ है।

12.4.21 लगभग 33 पत्रिकाओं को उनकी कोटि तथा विषय-वस्तु में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा 1500/- रूपये से 10,000/- रूपये प्रतिवर्ष तक का अनुदान दिया जा रहा है। सरकार ने विभिन्न संस्थाओं को निःशुल्क आवंटन के लिए व्यक्तियों तथा प्रकाशकों से लगभग 200 पुस्तकें भी खरीदी। वर्ष 1988-89 में पाण्डुलिपियों के दो सूची-पत्र आलोचनात्मक संस्करण प्रकाशित किये गये। वर्ष 1988-89 के दौरान पांच और सूची पत्र/आलोचनात्मक संस्करण प्रकाशित किये जाने की संभावना है।

12.4.22 इसके अलावा महत्वपूर्ण दुर्लभ संस्कृत पुस्तकों के फोटो आफसैट पुनर्मुद्रण का भी एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया गया है ताकि इन पुस्तकों को कम कीमत पर पाठकों को उपलब्ध कराया जा सके। वर्ष 1988-89 के दौरान, लगभग 30 पुस्तकों के पुनर्मुद्रण की आशा है।

वैदिक अध्ययन की मौखिक परम्परा का संरक्षण

12.4.23 वैदिक अध्ययन की मौखिक परम्परा के संरक्षण के एक विशेष कार्य के रूप में एक योजना वर्ष 1978 में प्रारंभ की गई थी जिसके अंतर्गत प्रत्येक स्वाध्यायी को किसी एक विशेष वेद शाखा में 12 वर्ष की आयु से कम वाले दो छात्रों को, जिसमें से एक उनका अपना बेटा अथवा सगा-संबंधी होता है, प्रशिक्षित करना होता है। वर्ष 1988-89 के दौरान, ऐसी पन्द्रह इकाइयां सहायता प्राप्त कर रही हैं। इस योजना के अंतर्गत अध्येता को 1250 रूपये प्रतिमाह का मानदेय और प्रत्येक छात्र को 175 रूपये प्रतिमाह का वजीफा दिया जाता है।

वैदिक सम्मेलन

12.4.24 उन क्षेत्रों तथा परिवारों का पता लगाने के लिए जहां आज भी वेदपाठ की मौखिक परंपरा अभी तक कायम है, यह मंत्रालय प्रत्येक वर्ष वैदिक सम्मेलन आयोजित करता है जिसके अंतर्गत पूरे देश के अध्येताओं को आमंत्रित किया जाता है। इस वर्ष वैदिक सम्मेलन जनवरी, 1989 में आयोजित किये जाने की आशा है।

अखिल-भारतीय वाक् प्रतियोगिता

12.4.25 संस्कृत अध्ययन के विभिन्न विषयों में पारम्परिक संस्कृत पाठशालाओं के छात्रों में महत्वपूर्ण प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए मंत्रालय अखिल-भारतीय वाक् प्रतियोगिताएं आयोजित करता है। इसमें भाग लेने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों से एक शिक्षक सहित आठ छात्रों के एक दल को आमंत्रित किया गया। इस वर्ष की प्रतियोगिता जनवरी/फरवरी 1989 में होनी निश्चित हुई है।

राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान

12.4.26 राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान को वैदिक अध्ययन की मौखिक परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में स्थापित किया गया है जो पारम्परिक वैदिक संस्थानों तथा अध्येताओं को बढ़ावा देने, छात्रवृत्तियां/शिक्षावृत्तियां आदि देने जैसे विभिन्न कार्यकलाप करेगा। इस प्रतिष्ठान का 19 अगस्त, 1987 को उद्घाटन किया गया। वर्ष 1988-89 के दौरान प्रतिष्ठान को संग्रह राशि के रूप में उपयोग करने के लिए 40 लाख रूपये की राशि संस्वीकृत की गई है।

12.4.27 इसके अतिरिक्त, वर्ष 1988-89 के दौरान प्रतिष्ठान को स्टाफ की नियुक्ति और वेतन संबंधी खर्चों को पूरा करने के लिए 5 लाख रूपये की राशि की संस्वीकृति दी गई। इस प्रतिष्ठान ने वैदिक गणित पर, दो कार्यशालाएं, पहली जयपुर में मार्च, 1988 में और दूसरी अक्तूबर, 1988 में अहमदाबाद में आयोजित कीं।

संस्कृत पाठशालाओं के निर्माण के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण

12.4.28 यह योजना केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठों, आदर्श संस्कृत महाविद्यालयों और अन्य पारंपरिक

संस्कृत संस्थाओं से निकलने वाले छात्रों के लिए रोजगार की संभावनाएं बढ़ाने की दृष्टि से शुरू की गई थी। यह उन छात्रों के संस्कृत के अध्ययन से जुड़े विषयों में अल्पकालीन व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध करवाती है जैसे पुरालेख शास्त्र, पाण्डुलिपि मुद्रण, धर्मविधि, संस्कृत मुद्रण और कम्पोजिंग आदि। इन पाठ्यक्रमों को चलाने के लिए पंजीकृत स्वैच्छिक संगठनों को शत-प्रतिशत अनुदान प्राप्त होता है। वर्ष 1988-89 के दौरान ऐसे करीब बारह पाठ्यक्रम शुरू होने की संभावना है।

विभिन्न सलाहकार बोर्डों/आयोगों के कार्य और कार्यकलाप

केन्द्रीय संस्कृत बोर्ड

12.4.29 केन्द्रीय संस्कृत बोर्ड भारत सरकार को विभिन्न स्तरों पर संस्कृत शिक्षा के प्रतिमानों से संबंधित देश में संस्कृत के प्रसार और विकास के संबंध में नीति के मामलों पर सलाह देता है।

संस्कृत, अरबी, फारसी के स्वैच्छिक संगठनों पर अनुदान समिति

12.4.30 संस्कृत/अरबी और फारसी संगठनों पर अनुदान समिति, जो संस्कृत/अरबी, फारसी के प्रचार और विकास के लिए कार्य कर रही, संबंधित राज्य सरकारों के जरिए विभिन्न संस्थाओं से प्राप्त आवेदनों पर विचार करती है, और संस्कृत की प्रौन्नति के लिए कार्य कर रहे स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता की योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता देने और श्रेण्य भाषाओं अर्थात् अरबी और फारसी के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता देने की सिफारिशें करती हैं। इन समितियों की पिछली बैठक क्रमश: 18/19 अगस्त, 1988 और 7 दिसम्बर, 1988 को हुई थी।

संस्कृत के वयोवृद्ध व प्रख्यात विद्वानों के चयन के लिए समितियों का गठन

12.4.31 यह समिति शास्त्र चूडामणि योजना के अंतर्गत व्याकरण, न्याय, वेदांत आदि जैसे शास्त्रीय विषयों की गहन शिक्षा प्रदान करने के लिए पार्टियों के आवेदन पत्रों की जांच करती है और उपयुक्त विद्वानों का चयन करती है। इस समिति की अन्तिम बैठक 26 सितम्बर, 1988 को हुई थी।

प्रधानमंत्री, श्री राजीव गांधी—केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल के रजत जयंती समारोह के उद्घाटन अवसर पर हिन्दी के विद्वानों को सम्मानित करते हुए—विज्ञान भवन, नई दिल्ली—13 फरवरी, 1989.

सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम

13.1.0 सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम में गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू तथा कश्मीर सीमावर्ती चार राज्यों को शामिल किया गया है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 200 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है जिसका कार्यान्वयन वर्ष 1986-87 के दौरान गृह मंत्रालय द्वारा किया गया। इसे 1987-88 में शिक्षा विभाग को हस्तान्तरित किया गया। इसका अभिप्राय यह था कि इस कार्यक्रम को शिक्षा और इससे संबद्ध मामलों तक सीमित रखा जाए, जो सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए महत्वपूर्ण अंग है। अब इस कार्यक्रम के अधीन समग्र मानव संसाधन विकास पर जोर दिया गया है। इस कार्यक्रम के अधीन राज्य शिक्षा विकास कार्यक्रमों की कमी को पूरा करने के प्रयास किये जाते हैं जिनमें वे भी शामिल हैं जो एन०आर०ई०पी०, आर०एल०ई०जी०पी०, आई०आर०डी०पी०, और मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अधीन शुरू किये जाते हैं। इस कार्यक्रम के अधीन नये स्कूल खोलने, स्कूलों का ग्रेड बढ़ाने, मौजूदा स्कूलों में कक्षाओं के लिए अतिरिक्त कमरे, प्रयोगशालाएं, शौचालय आदि बनाने, अनिवार्य सुविधाओं की व्यवस्था, पॉलिटेक्निकों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थाओं की स्थापना, प्रौढ़ शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना, युवा कार्यक्रम, सांस्कृतिक विकास कार्यकलाप आदि के लिए फंड की व्यवस्था की गई है।

13.2.0 कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए शिक्षा विभाग ने मार्गदर्शी निर्देश तैयार किए हैं और उन्हें सीमावर्ती राज्यों में परिचालित किया। उनसे इन मार्गदर्शी निर्देशों के अनुसार अपने प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया गया। शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में संस्वीकृतिदात्री समिति गठित की गई है जिसमें योजना आयोग, राज्य सरकारों और संबंधित मंत्रालयों के प्रतिनिधि हैं ताकि राज्यों के प्रस्तावों को तेजी से निपटाया जा सके।

13.3.0 संस्वीकृतिदात्री समिति की सिफारिश के अनुसार राज्य सरकारों को विभिन्न कार्यक्रमों/कार्यकलापों के लिए प्रशासनिक स्वीकृति सूचित की गई है जो 36.63 करोड़ रूपये की है और वर्ष 1987-88 के दौरान उन्हें 25 करोड़ रूपये का संपूर्ण बजट प्रावधान जारी किया गया था। वर्ष 1988-89 के दौरान 45.50 करोड़ रूपये (35.5 करोड़ रूपये के मूल प्रावधान को बढ़ाकर 45.5 करोड़ रूपये किया गया था) के मुकाबले में संस्वीकृतिदात्री समिति ने विभिन्न कार्यकलापों के लिए 6069.18 करोड़ रूपये (पीछे से चले आ रहे कार्यकलापों के लिए वचनबद्धता के अलावा) की प्रशासनिक स्वीकृति दी है और राज्य सरकारों को 31.1.89 तक 23.12 करोड़ रूपये दे दिए गए हैं।

13.4.0 राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना और प्रशासन संस्थान ने 19-21 सितम्बर, 1988 को खंड विकास योजनाओं के लिए मानदंड और मार्गदर्शी निर्देश बनाने और कार्यक्रम के अनुवीक्षण और मूल्यांकन के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया।

बीस सूत्री कार्यक्रम, 1986 और सुविधावंचित वर्गों के लिए शिक्षा की सुलभता

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की शिक्षा

14.1.1 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के संबंध में कार्य योजना में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य कमज़ोर वर्गों की शैक्षिक स्थिति में सुधार के लिए कई उपायों की संकल्पना की गई है। राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए शैक्षिक कार्यक्रमों से संबंधित मामलों पर समीक्षा करने और परामर्श देने के क्रम में एक केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (सी०ए०बी०ई०) का गठन (जिसका उल्लेख पहले किया गया है) केन्द्रीय कल्याण राज्यमंत्री श्रीमती राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी की अध्यक्षता में किया गया है। समिति की दूसरी बैठक 25 अगस्त, 1988 को हुई थी। समिति ने कमजोर वर्गों के शैक्षिक विकास के लिए मौजूदा कार्यक्रमों, योजनाओं आदि पर विचार-विमर्श किया और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन, समय पर छात्रवृत्तियों और अन्य प्रोत्साहनों के वितरण, उपचारी उपायों और विशेष कोचिंग, माइक्रो-प्लानिंग आदि के संबंध में काफी सिफारिशें की गईं।

14.1.2 उन वर्गों की विशिष्ट आवश्यकताओं पर ध्यान देकर शिक्षा संबंधी असमानता और असंगति के निराकरण पर विशेष बल दिया गया है जो मौजूदा शैक्षिक प्रावधानो और सुविधाओं का पूर्ण लाभ नहीं उठा पा रहे हैं।

14.1.3 आंध्र प्रदेश, असम, उड़ीसा, और राजस्थान में अनुमोदित 12 स्कूलों में विशेष और प्रतिकारी कोचिंग द्वारा "अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की मैरिट उन्नयन" स्कीम के अंतर्गत वर्ष के दौरान 225 छात्रों को सम्मिलित किया गया, देश भर में अनुमोदित आवासीय सैकण्डरी स्कूलों में नामांकन के लिए 113 छात्र चुने गए।

अल्पसंख्यकों की शिक्षा

14.2.0 अल्पसंख्यकों के सुधार के लिए निर्देशित प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम के अनुसार, आलोच्य वर्ष के दौरान, अल्पसंख्यकों के शैक्षिक विकास के लिए ये कार्यक्रम आगे बढ़ाए गए। कार्यक्रम का संक्षिप्त ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

(1) व्यावसायिक प्रशिक्षण

अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में दस सामुदायिक पॉलिटेक्निकों में विभिन्न कौशलों/शिल्पों में, अल्पकालीन व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से 10,000 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया।

(2) कोचिंग कक्षाएं

शैक्षिक रूप से पिछड़े, अल्पसंख्यक छात्रों की कोचिंग के लिए विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को सहायता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक योजना कार्यान्वित करता हैं। छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करने के लिए कोचिंग दी जाती है। इस समय 20 विश्वविद्यालयों और 14 कॉलेजों में कोचिंग कक्षाएं चलाई जा रही हैं।

(3) पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा

राष्ट्रीय एकता के दृष्टिकोण से स्कूल पाठ्यपुस्तकों का मूल्यांकन किया जा रहा है। इसका उल्लेख "स्कूल शिक्षा" के अंतर्गत भी किया गया है। भावनात्मक

एकता और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने की दृष्टि से स्कूलों और कॉलेजों में निर्धारित पाठ्यपुस्तकों से उस सामग्री और प्रयासों को दूर करने का लक्ष्य हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अस्पृश्यता, जातिवाद, क्षेत्रवाद और सम्प्रदायवाद को चिरस्थायी बनाते हैं। राष्ट्रीय, शैक्षिक, अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद ने विभिन्न विषयों में पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं। राज्य स्तर पर राजकीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषदों, राज्य पाठ्यपुस्तक बोर्डों/निगमों ने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना के प्रकाश में पाठ्यक्रम में संशोधन करने के लिए कदम उठाये हैं।

महिला शिक्षा

14.3.0 शैक्षिक योजनाएं बनाते समय लड़कियों/महिलाओं के लिए एक उत्तम तरीके से शिक्षा में प्रवेश प्रदान करने की आवश्यकता को ध्यान में रखा गया। इन योजनाओं का विवरण संबद्ध अध्यायों—प्रारंभिक शिक्षा, स्कूल शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा और तकनीकी शिक्षा में दिया गया है।

14.4.1 बीस सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा में प्रगति का मूल्यांकन, पूर्व निर्धारित लक्ष्यों के संदर्भ में किया जाना है। प्रारंभिक और प्रौढ शिक्षा के क्षेत्र में लक्ष्य, कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और योजना आयोग के अनुदेशों के अनुसार नामांकन के रूप में निर्धारित किए जाते हैं। अनौपचारिक शिक्षा का अनुवीक्षण अभी किया जाना हैं।

14.4.2 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और कार्य योजना के अनुरूप शिक्षा विभाग ने "धारण" के साथ-साथ योग्यता प्राप्ति पर बल देने वाली एक नई मानीटरिंग पद्धति की स्थापना का विचार किया है। इस विषय पर योजना आयोग और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में चर्चा की गई है। अन्ततः केबिनेट मंत्रिमंडलीय सचिवालय में सचिव-समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जब तक नई मानीटरिंग प्रणाली तैयार नहीं की जाती, तब तक लक्ष्य निर्धारित किए जायें और प्रारंभिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा के संदर्भ में नामांकन के रूप में मानीटरिंग की जाए।

प्रबंध, मानीटरिंग और मूल्यांकन

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (सी.ए.बी.ई.)

15.1.1 केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (सी.ए.बी.ई.) में राज्यों के शिक्षा मंत्री, प्रशासक, शिक्षाविद और विद्वान शामिल हैं। यह राष्ट्रीय स्तर के निकाय के रूप में वर्ष के दौरान कार्य करता रहा हैं और शिक्षा के क्षेत्र में प्रवृत्तियों की समीक्षा, कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का विश्लेषण और नीति विषयक विषयों पर सलाह देते हुए शिक्षा नीति के प्रबंध के लिए महत्वपूर्ण आदान-प्रदान करता रहा है।

15.1.2 बोर्ड ने, 10 समितियों के माध्यम से कार्य किया, इन समितियों को निम्नलिखित विषयों पर गहराई से विचार करने का काम सौंपा गया:–

- प्रारंभिक शिक्षा (आपरेशन ब्लैकबोर्ड सहित)
- शिक्षा का स्वरूप और प्रक्रिया (खासतौर पर स्कूल स्तर पर)।
- शिक्षकों का स्थानांतरण।
- महिला शिक्षकों के लिए आवास सुविधाएं।
- सामान्य शिक्षा प्रणाली।
- शिक्षा का व्यावसायिकरण।
- भाषा विकास और भाषा शिक्षण।
- अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और शिक्षा की दृष्टि से सुविधा विहीन अन्य वर्ग।
- शिक्षा का प्रबंध।
- **शिक्षा के लिए संसाधन।**

15.1.3 नीचे तालिका में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठकों के ब्यौरे और इसकी समितियां और उनकी मुख्य-मुख्य सिफारिशें दी गई हैं:–

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, इसकी समितियों की बैठकें और उनकी मुख्य-मुख्य सिफारिशें

क्र० सं०	केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड और इसके निकायों के ब्यौरे	बैठक की तारीखें	मुख्य-मुख्य सिफारिशें/ संपादित कार्य
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड	13 और 14 सितम्बर, 1988	– आठवीं योजना अवधि के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सभी स्कीमों का निर्धिकरण – विकेन्द्रीकृत माइक्रो-प्लानिंग – सार्थक मानीटरिंग प्रणाली तैयार करना – नैतिक शिक्षा पर बल – व्यावसायिक शिक्षा के सुप्रवाहीकरण के के लिए प्रबंध संरचना – राज्य उच्च शिक्षा परिषदों की स्थापना की आवश्यकता – शिक्षकों के नियमित और योजनाबद्ध कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन – नये कालेजों की

1	2	3	4
			स्थापना में कठिनाई – प्रत्येक गांव में शिशु देख-भाल सेवाओं के रूप में विशेष सहायक सेवाओं की व्यवस्था – जनजातियों की समृद्ध सांस्कृतिक पहचान और विरासत को बनाए रखने के लिए उनकी शिक्षा पर विशेष ध्यान – पालक माता-पिता योजना का कार्यान्वयन – शैक्षिक संस्थाओं और विशेषज्ञ अनुसंधान तथा विकास संगठनों में सहलग्नता की पुनर्स्थापना की की तत्काल आवश्यकता – तकनीकी संस्थाओं में अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन की व्यवस्था – उच्च शिक्षा के सभी क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास कार्यों का समन्वय करने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद की स्थापना।
2.	शिक्षकों के स्थानांतरण संबंधी समिति	26 अक्तूबर 1988	– मसौदा रिपोर्ट पर चर्चा की और निर्णय किया कि राज्य सरकारों के विचार आमंत्रित किये जाएं।
3.	शिक्षा प्रबंध संबंधी समिति	15 जून, 1988	– राज्य शिक्षा सलाहकार बोर्ड, जिला शिक्षा बोर्डों और ग्राम शिक्षा समितियों के लिये
			मार्गदर्शी सिद्धांतों को अंतिम रूप दिया।
4.	अनौपचारिक शिक्षा सहित प्रारंभिक शिक्षा पर केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की समिति	8.7.1988	– आठवीं योजना के दौरान आपरेशन ब्लैक बोर्ड स्कीम के लिए केन्द्रीय सहायता जारी रखने की आवश्यकता। – एन.आर.ई.पी./आर.एल.ई.जी.पी. निधियों से स्कूल भवनों के निर्माण के लिए संबंधित विभागों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई – अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के लिए शिक्षण और अध्ययन सामग्री और पाठ्य-विवरण तैयार करने के लिए प्रत्येक राज्य में संसाधन व्यक्तियों का पूल तैयार करना
5.	व्यावसायिकी-करण पर केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की समिति	29.7.1988	– ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और बालिकाओं/महिलाओं के लिए समुचित व्यावसायिक पाठ्यक्रम तैयार करने के प्रश्न पर विचार करने के लिए दो तदर्थ दलों का गठन। – स्कीम के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की गई और यह रिपोर्ट दी कि राज्यों द्वारा कोई अधिक कार्रवाई नहीं की गई: सुझाव दिया गया कि इस मामले को राज्यों के साथ दृढ़ता से उठाया जाए।
6.	अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-	25.8.1988	– शिक्षा की दृष्टि से वंचित वर्गों के विकास के लिए

1	2	3	4
	जातियों तथा शैक्षिक दृष्टि से अन्य वंचित वर्गों पर केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की समिति		विभिन्न स्कीमों की व्यापक समीक्षा की गई और महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। जिन महत्वपूर्ण मदों पर चर्चा हुई उनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के शैक्षिक विकास के लिए मुख्य-मुख्य कार्यक्रमों के अनुवीक्षण के लिए मानीटरिंग प्रोफार्म भी शामिल हैं। — सुविधाओं के स्थान निर्धारण के लिए प्रभावी माइक्रो प्लानिंग जहां अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के बच्चों की बहुतायत हो। — छात्रवृत्तियों के संवितरण के लिए तर्क संगत प्रक्रिया और जनजाति भाषाओं में प्राइमर तैयार करना — राज्यों में नोडल एजेंसियों की स्थापना।
7.	महिला शिक्षकों के लिए आवास सुविधाओं के संबंध में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की उप-समिति	21.7.1988	— समिति का कार्य क्षेत्र प्रारंभिक स्कूल शिक्षकों तक सीमित रखा गया, इसमें प्राथमिक स्कूल शिक्षकों की समस्या पर विशेष ध्यान दिया गया। — निम्नलिखित समस्याओं के साथ-साथ अन्य समस्याओं के बहुआयामी समाधान सुझाए गए: (क) ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, समूह प्रस्ताव अर्थात् मुख्य स्थान पर यानि पंचायत घर के समीप महिला कर्मचारियों के लिए सामूहिक भवनों का निर्माण। (ख) शहरी क्षेत्रों में: कामकाजी महिलाओं का हॉस्टल, अधि-मानतः कुछ अपार्टमेंट जो कम लागत के हों। (ग) शिक्षकों को स्वयं अपना मकान बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। (घ) सस्ते मकानों की व्यवस्था करने के रास्ते निकाले जाएं। (ङ) सी.ए.पी.ए.आर.टी. से संबद्ध स्वैच्छिक एजेंसियों को कुछ मकान बनाने के लिए काम में लगाया जाए।

राज्यों के शिक्षा सचिवों और निदेशकों के सम्मेलन

15.2.0 शिक्षा प्रबंध के उपाय के रूप में राज्यों के शिक्षा सचिवों और निदेशकों के भी सम्मेलन हुए। इन सम्मेलनों के ब्योरे नीचे दिए जा रहे हैं:—

शिक्षा संबंधी आंकड़े

15.3.1 शिक्षा के प्रबंध को सार्थक बनाने के लिए शिक्षा संबंधी आंकड़ों पर विशेष ध्यान दिया गया। इस "शैक्षिक सांख्यिकीय" पर स्थायी समिति की बैठक 19.12.1988 (13 वीं बैठक) को हुई। इसमें शिक्षा विभाग के सांख्यिकीय यूनिट द्वारा किए गए कार्य की प्रगति की समीक्षा की गई।

15.3.2 शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने अप्रैल, 1988 में भारत के महारजिस्ट्रार द्वारा आयोजित आंकड़ा प्रयोक्ता सम्मेलन (1981 जनगणना) में भाग लिया।

राज्य शिक्षा सचिवों/राज्य शिक्षा निदेशकों के सम्मेलन और उनकी महत्वपूर्ण सिफारिशें

क्र. सं.	भाग लेने वालों के ब्योरे	सम्मेलन की तारीख	महत्वपूर्ण निर्णय
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के शिक्षा सचिव प्रारंभिक शिक्षा के आयुक्त और निदेशक उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा।	17 और 18 जून, 1988	1. माइक्रोलेबल प्लानिंग प्रणाली लागू करना 2. उच्च प्राथमिकता आधार पर आप्रेशन ब्लैक बोर्ड स्कीम का कार्यान्वयन। 3. नवोदय विद्यालयों में शिक्षण की श्रेष्ठता को सुनिश्चित करना 4. राज्यों में शिक्षा प्रौद्योगिकी को सक्रिय बनाना। 5. कम्प्यूटर साक्षरता में शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रमों में सुधार। 6. समयबद्ध आधार पर देश के सभी भागों में त्रिभाषा सूत्र का कार्यान्वयन। 7. स्वशासी हैसियत प्रदान करने के लिए कालेजों का सावधानीपूर्वक चयन। 8. विश्वविद्यालय और कालेज शिक्षकों के लिए योजनाबद्ध कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली का प्रवर्तन।
2.	--यथोपरि--	12 सितम्बर 1988	प्रारम्भिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के सर्व सुलभीकरण के संबंध में प्रभावी मानीटरिंग प्रणाली की सिफारिश की गई।

15.3.3 शिक्षा विभाग ने उड़ीसा सरकार द्वारा आयोजित शिक्षा संबंधी सांख्यिकीय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए संसाधन कार्मिक के रूप में अपने अधिकारियों को भेजा।

15.3.4 विभाग द्वारा गठित कार्यकारी दल ने शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े राज्यों में उपयोग के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में शिक्षा संबंधी आंकड़ों के कम्प्यूटरीकरण पर केन्द्रीय योजना स्कीम की कार्य प्रणाली को अंतिम रूप दिया।

15.3.5 आलोच्य वर्ष के दौरान शिक्षा संबंधी आंकड़ों पर निम्नलिखित प्रकाशन निकाले गए:–

1. भारत में शिक्षा, 1976-77 खण्ड 3
2. भारत में शिक्षा, 1979-80 खण्ड 2
3. भारत में शिक्षा, 1982-83 खण्ड 1
4. भारत में शिक्षा, 1983-84 खण्ड 1 (प्रकाशनाधीन)
5. भारत में पत्राचार पाठ्यक्रम पर अध्ययन, 1980-81

6-12. ज़िलेवार शिक्षा संबंधी आंकड़े 1981-82: असम--खण्ड 5, प. बंगाल-खण्ड 6, पंजाब-खण्ड 7, हिमाचल प्रदेश-खण्ड 8, गोवा, दमन और दीव खण्ड-9, बिहार-खण्ड 10, तमिलनाडु खण्ड 11

13. विदेश जाने वाले भारतीय छात्र/प्रशिक्षणार्थी 1983-84
14. भारतीय विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत विदेशी छात्र, 1983-84
15. स्कूल शिक्षा पर चुनिन्दा सूचना 1985-86
16. स्कूल शिक्षा पर चुनिन्दा सूचना 1986-87
17. चुनिन्दा शिक्षा संबंधी आंकड़े 1986-87
18. भारत में अनौपचारिक शिक्षा (कालेज स्तर)

कम्प्यूटीकृत प्रबंध सूचना प्रणाली (सी.एम.आई.एस.)

15.4.1 कम्प्यूटीकृत प्रबंध सूचना प्रणाली को विकसित करने में भी प्रगति की गई।

15.4.2 इस संदर्भ में, राष्ट्रीय इन्फार्मेटिक्स केन्द्र ने आठ माइक्रो कम्प्यूटर और 16 टर्मिनलों सहित बृहत भंडारण क्षमता वाले उच्च प्रौद्योगिकी का एक कम्प्यूटर स्थापित किया।

15.4.3 सी.एम.आई.एस. के अंतर्गत कम्प्यूटीकृत परियोजनाओं की स्थिति आगे दी गई है:–

15.5.0 राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना और प्रशासन संस्थान (नीपा) स्वशासी संगठन के रूप में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। संगठन वर्ष के दौरान निम्नलिखित कार्य करता रहा:–

क्र. सं.	परियोजना का नाम	स्थिति
1.	भारतीय विश्वविद्यालयों में अध्ययन विदेशी छात्र	1984-85 पूरा किया गया
2.	विदेश जाने वाले भारतीय छात्र	1985-86 तक पूरा किया गया
3.	बजट में सम्मिलित व्यय का विश्लेषण	वर्ष 1987-88 के लिए पूरा किया गया
4.	विभाग के महत्वपूर्ण कार्यकलापों के संबंध में वार्षिक कार्य योजना और मंत्रिमंडल सचिवालय तथा प्रधानमंत्री कार्यालय को प्रस्तुत करने के लिए इसके कार्यान्वयन पर तिमाही रिपोर्टें	द्वितीय तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत की गई (1988-89)
5.	"भारत में चुनिन्दा शिक्षा संबंधी आंकड़ों" के संबंध में आंकड़ों का आधार	वर्ष 1987-88 के लिए पूरा किया गया।
6.	सातवीं पंचवर्षीय योजना के चार वर्षों के दौरान राज्य योजना आबंटन और उपलब्धियां	वर्ष 1988-89 के लिए पूरा किया गया।
7.	अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक संख्यांकन प्रणाली का विकास (एन.ई.आर.सी. की परियोजना)	नियमित रूप से सप्लाई की गई।
8.	विभाग के अधिकारियों/स्टाफ के वेतन बिलों और वेतन पर्चियों का कम्प्यूटीकरण	नियमित रूप से सप्लाई की गई
9.	भारत में शिक्षा	1984-85 और 1985-86 पर काम चल रहा है।
10.	कक्षा 1-5 और 6-7 के राज्यवार निवल नामांकन अनुपात के अनुमान के लिए अनुरूपण माडल	पूरे किए गए

- वरिष्ठ शैक्षिक प्रशासकों का प्रशिक्षण और अभिविन्यास प्रशिक्षण
- शैक्षिक आयोजना और प्रशासन की प्रगति में अनुसंधान (दो अनुसंधान अध्ययन पूरे किए गए और 11 पर अनुसंधान हो रहा है)
- राज्यों और अन्य संगठनों के लिए विस्तार सेवाएं और परामर्शी सेवाएं।
- शैक्षिक आयोजना और प्रशासन से संबंधित मामलों पर सेमिनार। कार्यशालाएं और सम्मेलन (49 प्रशिक्षण कार्यक्रम/सेमिनार/कार्यशालाएं नवम्बर 1988 के अंत तक आयोजित किए गए और 31.3.1989 तक 16 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे)।
- अन्य देशों और अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों, यूनेस्को, यू.एन.डी.पी. आई.आई.ई.पी., राष्ट्रमंडल सचिवालय आदि के लिए प्रशिक्षण और अनुसंधान सुविधाओं की व्यवस्था।
- शिक्षा के प्रबंध पर सरकार को तकनीकी सहायता की व्यवस्था (माइक्रो लेवल प्लानिंग पर मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार किए गए। स्कूल शिक्षा के संबंध में सामुदायिक सहभागिता और ग्रामीण समुदायों की भूमिका)।

अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग

भारत और यूनेस्को के बीच सहयोग

16.1.0 संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन के संस्थापक सदस्य के रूप में भारत संगठन के अनुच्छेद उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्रोन्नति की दिशा में निरंतर प्रयास करता रहा है। यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग, जिसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा यूनेस्को के संविधान के अनुच्छेद VII के अनुपालन में वर्ष 1949 में की गई थी। राष्ट्रीय स्तर पर एक सलाहकार, कार्यकारी, सूचना तथा सम्पर्क निकाय के रूप में प्रभावशाली भूमिका निभा रहा है और यूनेस्को के कार्यक्रमों तथा इसकी सक्षमता के सभी क्षेत्रों में कार्यकलापों के कार्यान्वयन के लिए एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्र के राष्ट्रीय आयोगों और यूनेस्को के क्षेत्रीय कार्यालय तथा केन्द्रों के साथ सहयोग भी कर रहा है

16.2.0 यूनेस्को के एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्र के विकास हेतु शैक्षिक नव-परिवर्तन (ए. पी. ई. आई. डी.) के प्रमुख क्षेत्रीय कार्यक्रम, जो वर्ष 1874 में शुरू हुआ था, के संस्थापक सदस्य के रूप में भारत ने ए. पी. ई. आई. डी. कार्यकलापों में सक्रिय रूप से भाग लिया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत एक राष्ट्रीय विकास दल स्थापित किया गया है जो देश में विकास के लिए शैक्षिक नव परिवर्तन के राष्ट्रीय स्तर पर पहचान करने वाले, प्रेरक तथा समन्वयक के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् क्षेत्रीय स्तर पर ए०पी०ई०आई०डी० के कार्यकलापों, क्षेत्रीय स्तर के नए अनुभवों के बारे में सूचना के प्रसार तथा देश में ए. पी. ई. आई. डी. में क्षेत्रीय सहयोग के परिणामों के देशभर में प्रचार में सहायता प्रदान करती है।

16.3.0 एक अन्य महत्वपूर्ण कार्यकलाप, जिसके लिए भारत ने यूनेस्को को अपना पूर्ण समर्थन और सहयोग दिया है, सभी के लिए एशिया–प्रशान्त शिक्षा कार्यक्रम (ए०पी०पी०ई०ए०एल०) है, जिसे यूनेस्को ने वर्ष 1987 में नई दिल्ली में आरंभ किया था। इस कार्यक्रम को और प्रोत्साहन देने तथा 2000 ई. तक निरक्षरता उन्मूलन के लिए उपाय तैयार करने की दृष्टि से ए. पी. पी. ई. ए. एल. के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष क्षेत्रीय कार्यकारी दल की बैठक 11-14 अक्तूबर, 1988 तक नई दिल्ली स्थित यूनेस्को के एशिया तथा प्रशान्त के प्रधान कार्यालय के सहयोग से आयोजित की गई, जिसमें अफगानिस्तान, बंगलादेश, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, नेपाल और पाकिस्तान के उच्च स्तरीय अधिकारियों तथा योजना-निर्माताओं ने भाग लिया। भारत ने दक्षिण एशिया में विकासशील देशों में तकनीकी सहयोग (टी. सी. डी. सी.) के लिए यूनेस्को के सक्षम क्षेत्र में कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए एक उप-क्षेत्रीय संगोष्ठी भी आयोजित की, जो नई दिल्ली में 5-9 दिसम्बर, 1988 तक चली। भारत ने बैंकाक में अगस्त, 1988 में आयोजित ए. पी. ई. आई. डी. की ग्यारहवीं क्षेत्रीय सलाहकार बैठक में और 22-27 सितम्बर, 1988 तक पेइचिंग में संपन्न एशिया तथा प्रशान्त में यूनेस्को राष्ट्रीय आयोगों के नवें क्षेत्रीय सम्मेलन में भाग लिया।

16.4.0 भारत ने यूनेस्को तथा इसके क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ, विभिन्न कार्यशालाओं तथा संगोष्ठियों में, भारतीय विशेषज्ञों और संस्थाओं द्वारा भाग लिए जाने का प्रबन्ध करके, भारतीय संस्थाओं तथा प्रयोगशालाओं में, यूनेस्को अध्येताओं को रखने का प्रबन्ध करके और यूनेस्को के सहभागिता कार्यक्रम

के अधीन परियोजनाओं का कार्यान्वयन करके, इसके कार्यकलापों के कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से सहयोग किया है। इसने यूनेस्को कूपन योजना, यूनेस्को कूरियर तथा न्यूज़लैटर के हिन्दी तथा तमिल संस्करणों के प्रकाशन को भी जारी रखा। वर्ष के दौरान किए गए कार्यकलापों का संक्षिप्त सारांश नीचे दिया गया है।

अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा समीक्षा सम्पादकीय बोर्ड का चौंतीसवां सत्र और यूनेस्को शिक्षा संस्थान, हेम्बर्ग के शासी बोर्ड का चालीसवां सत्र

16.5.0 संस्थान के शासी बोर्ड के सदस्य के रूप में, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग के भूतपूर्व विशेष सचिव, श्री किरीट जोशी ने अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा समीक्षा सम्पादकीय बोर्ड के 34वें सत्र में (2 मई, 1988 को) और हेम्बर्ग में हुए यूनेस्को शिक्षा संस्थान के सम्पादकीय बोर्ड के 40वें सत्र में (3-5 मई, 1988 को), जहां यूनेस्को की तृतीय मध्य-अवधि योजना पर भी चर्चा हुई, भाग लिया। 6-7 मई, 1988 तक हुई सलाहकार बैठक में, सदस्यों ने शिक्षा में अनुसंधान प्राथमिकताओं तथा कार्रवाई के उन विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जो यूनेस्को तृतीय मध्य-अवधि योजना के दौरान शुरू कर सकता है।

यूनेस्को,पत्तया,बैंकाक की तृतीय मध्यावधि योजना पर क्षेत्रीय परामर्श, 12-14 मई 1988

16.6.0 शिक्षा विभाग, मानव संस्थान विकास मंत्रालय के अपर सचिव, श्री एस. गोपालन ने 12-14 मई, 1988 तक पत्तया, थाईलैंड में आयोजित तृतीय मध्यावधि योजना पर क्षेत्रीय परामर्श में भाग लिया। बैठक में विचार-विमर्श के दौरान, विश्व-समस्याओं तथा भविष्योन्मुख अध्ययनों से सम्बन्धित कार्यकलापों को इस संगठन के बौद्धिक मिशन के कारण पर्याप्त महत्व दिए जाने पर और कार्यात्मक तथा बौद्धिक कार्यकलापों के बीच में विवेकपूर्ण सन्तुलन बनाए रखने पर बल दिया गया था। विचार-विमर्श में भारत के प्रतिनिधि ने शिक्षा प्रक्रिया के ज़रिए शान्ति एवं मानवीय अधिकारों के उद्देश्य की प्रगति पर पर्याप्त बल दिया। शान्ति एवं मानव अधिकारों से सम्बद्ध कार्यकलापों को, रंगभेद, पूर्वाग्रह के सभी रूपों, असहिष्णुता, जातिवाद तथा भेदभाव को मिटाने और अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना, मानव अधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं को बढ़ाने वाले शैक्षिक कार्यक्रमों को आरम्भ तथा प्रोत्साहित करके तृतीय मध्यावधि योजना में महत्वपूर्ण स्थान दिए जाने पर बल दिया।

यूनेस्को के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग के संचार उप-आयोग की बैठक

16.7.0 यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग ने नई दिल्ली में 12 जुलाई, 1988 को अपने संचार उप-आयोग की एक बैठक श्री जी. पार्थसारथी की अध्यक्षता में आयोजित की ताकि प्रारूप विश्व संचार सम्बन्धी रिपोर्ट पर विचार किया जा सके। इस उप-आयोग ने अन्तर्राष्ट्रीय संचार सम्बन्धी मामलों पर विभिन्न सिफारिशें कीं।

जन-सामान्य की शिक्षा के लिए एशिया-प्रशान्त कार्यक्रम तथा अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष की राष्ट्रीय समन्वय समिति की बैठक

16.8.0 जन-सामान्य के लिए शिक्षा के एशिया-प्रशान्त कार्यक्रम (ए. पी. पी. ई. ए. एल.) और अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष (आई. एल. वाई) के महत्व को ध्यान में रखते हुए, ए. पी. पी. ए. एल. तथा आई. एल. वाई. पर एक राष्ट्रीय समन्वय समिति इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के अनुश्रवण तथा मूल्यांकन करने सहित नीति निर्माण, जन-जागृति बढ़ाना तथा सूचना और अनुभवों का प्रसार करने के लिए स्थापित की गई है। साक्षरता वर्ष तथा विशेष रूप से महिलाओं के लिए साक्षरता कार्यक्रमों के लिए प्रयोजनात्मक अभियानों को शुरू करने से सम्बन्धित नीतियों पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय समन्वय समिति की प्रथम बैठक 20 जुलाई, 1988 को नई दिल्ली में संपन्न हुई।

विकास के लिए शैक्षिक परिवर्तन के एशिया तथा प्रशान्त कार्यक्रम पर ग्यारहवीं क्षेत्रीय सलाहकार बैठक (ए०वी०ई०आई०डी०)

16.9.0 यूनेस्को द्वारा 2-9 अगस्त, 1988 तक बैंकाक में आयोजित विकास हेतु शैक्षणिक नव परिवर्तन के एशिया तथा प्रशान्त कार्यक्रम (ए०पी०ई०आई०डी०) पर ग्यारहवीं क्षेत्रीय सलाहकार बैठक में शिक्षा सचिव, श्री अनिल बोर्दिया ने भाग लिया। इस बैठक में जनवरी-जून, 1988 की अवधि के दौरान ए०पी०ई०आई०डी० की प्रगति की समीक्षा की गई। ए०पी०ई०आई०डी० में भाग ले रहे सदस्य राष्ट्रों में शिक्षा की उभरती प्रवृत्तियों तथा विकास और शिक्षा के भविष्य की वर्तमान कठिनाईयों का अध्ययन किया गया। इस में नव परिवर्तन के जरिए

श्री फ्रेडरिक मेयर, महानिदेशक, यूनेस्को मानव संसाधन विकास मंत्री के साथ। 1988

शिक्षा के स्तर तथा कुशलता को सुधारने तथा बढ़ाने के लिए विशेष बल दिया जाने पर भी विचार किया गया और ए०पी०ई०आई०डी० नेटवर्क और इसके सहयोग की प्रविधि को मज़बूत बनाने के नए दृष्टिकोणों पर विचार किया गया।

एशिया और प्रशान्त क्षेत्र में यूनेस्को राष्ट्रीय आयोगों का नवां क्षेत्रीय सम्मेलन

16.10.0 शिक्षा सचिव, श्री अनिल बोर्दिया ने 22-27 सितम्बर, 1988 तक पेइचिंग में आयोजित एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्र में यूनेस्को राष्ट्रीय आयोगों के नवें क्षेत्रीय सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन में यूनेस्को की तृतीय मध्य अवधि योजना पर और सांस्कृतिक विकास विश्व दशक में शुरू होने वाले कार्यकलापों पर विचारों का आदान प्रदान किया गया। इसमें अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष की तैयारी करने में शुरू किए जाने वाले उपायों तथा कार्यकलापों ए०पी०पी०ई०ए०एल० कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने और राष्ट्रीय आयोगों तथा उनमें क्षेत्रीय सहयोग की भूमिका की समीक्षा पर भी चर्चा की गई।

अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष पर क्षेत्रीय कार्यकारी दल की बैठक

16.11.0 यूनेस्को के एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्र हेतु प्रधान क्षेत्रीय कार्यालय, बैंकाक के सहयोग से 11-14 अक्तूबर, 1988 तक नई दिल्ली में अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष पर क्षेत्रीय कार्य दल की एक बैठक आयोजित की। इस कार्यकारी दल में मुख्यत: निरक्षरता की वास्तविक समस्याओं वाले एशिया तथा प्रशान्त देश के उच्च स्तरीय अधिकारी तथा नीति-निर्माता शामिल हैं। अफगानिस्तान, बंगलादेश, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, नेपाल और पाकिस्तान के प्रतिभागियों और यू० एन० डी० पी० यूनीसेफ और विश्व बैंक जैसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने इस बैठक में भाग लिया। बैठक का उद्घाटन शिक्षा तथा संस्कृति राज्य मंत्री ललितेश्वर प्रसाद शाही ने किया था। कार्यकारी दल ने विशेष रूप से बालिकाओं, महिलाओं तथा उपेक्षित जनसंख्या में निरक्षरता उन्मूलन की विभिन्न नीतियों तथा दृष्टिकोणों की प्रभावशीलता की जांच की। इस कार्यकारी दल ने ऐसे उपायों पर भी विस्तारपूर्वक विचार किया, जिनको वर्ष 2000 तक निरक्षरता उन्मूलन को ध्यान में रखत हुए अपनाया जाना चाहिए। साथ ही इस दल ने इस बात पर भी विचार किया कि अन्तर्राष्ट्रीय संगठन इस क्षेत्र के देशों की इस दिशा में वैयक्तिक तथा सामूहिक रूप से किस प्रकार सहायता कर सकते हैं।

दक्षिण एशिया में टी. सी. डी. सी. को प्रोन्नत करने के लिए उप-क्षेत्रीय संगोष्ठी

16.12.0 यूनेस्को के साथ सहयोग के भारतीय राष्ट्रीय आयोग के सहयोग से एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्र में समाज तथा मानविकी विज्ञान के लिए यूनेस्को के क्षेत्रीय एकक ने, यूनेस्को के सक्षम क्षेत्रों अर्थात् शिक्षा, सामाजिक-विज्ञानों, प्राकृतिक विज्ञानों, संस्कृति तथा संचार में दक्षिण एशिया के विकासशील देशों में तकनीकी सहयोग के कार्यकलापों को प्रोन्नत करने के लिए एक उप-क्षेत्रीय संगोष्ठी आयोजित की। संगोष्ठी नई दिल्ली में 5-9 दिसम्बर, 1988 तक चली। इसमें बंगलादेश, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान तथा श्रीलंका के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त, एशियाई जन संचार अनुसंधान और सूचना केन्द्र, (ए. एम. आई. सी.), एशियाई प्रसारण विकास प्रशान्त क्षेत्र संस्थान (ए. आई. बी. डी.), यूनेस्को, यू. एन. डी. पी. तथा ई. एस. सी. ए. पी. के प्रतिनिधियों ने भी पर्यवेक्षक के रूप में भाग लिया। इस संगोष्ठी में अन्य क्षेत्रीय संस्थाओं के टी. सी. डी. सी. अनुभव के सन्दर्भ में दक्षिण एशियाई क्षेत्र के सदस्य देशों के कार्यकलापों की समीक्षा की गई। इसमें वित्त-पोषण के संभावित स्रोत सहित निष्पादन के सर्वाधिक उपयुक्त तरीकों की सिफारिश करने की दृष्टि से आवश्यकताओं, उपलब्ध सुविधाओं तथा भावी सहयोग के क्षेत्रों का भी पता लगाया गया।

यूनेस्को का सहभागिता कार्यक्रम

16.13.1 सहभागिता कार्यक्रम के अंतर्गत, यूनेस्को सदस्य देशों की कार्यक्रमों तथा कार्यकलापों की प्रौन्नति में लगी विभिन्न संस्थाओं तथा संगठनों को नवीनीकरण परियोजनाओं को शुरू करने के लिए सहायता प्रदान करता है ताकि वे सम्मेलन द्वारा परिभाषित उद्देश्यों के कार्यान्वयन के प्रति राष्ट्रीय उप-क्षेत्रीय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर योगदान कर सकें। यूनेस्को ने 1988-1989 के दो वर्षों के दौरान, 1,12,000 यू. एस. डालर की वित्तीय सहायता के साथ 13 परियोजनाएं स्वीकृत की हैं।

16.13.2 श्री जवाहरलाल नेहरू, डा. एस राधाकृष्णन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म

शताब्दी समारोहों से स्वयं को संबद्ध करने के उद्देश्य स यूनेस्को ने सहभागिता कार्यक्रम के अंतर्गत इन सब के आयोजन की स्वीकृति दी है।

(I) जवाहरलाल नेहरू मैमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय द्वारा "एशिया और अफ्रीका तथा विश्व में जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्वतंत्रता आन्दोलन" पर संगोष्ठी, (II) भारतीय दर्शन अनुसंधान परिषद द्वारा "दर्शनशास्त्र में डा. राधाकृष्णन का योगदान, एक विवेचनात्मक मूल्यांकन" पर अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार, और (III) जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली द्वारा "मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और 20 वीं शताब्दी में इस्लाम में सुधार आन्दोलन" पर गोष्ठी।

यूनेस्को क्लब आन्दोलन

16.14.0 यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग, अपने प्रारंभ से ही इस परियोजना के साथ जुड़ा हुआ है और देश के सभी भागों में यूनेस्को क्लबों की स्थापना और उनके सुदृढ़ीकरण करने को प्रोत्साहित करने में सक्रिय रूप से लगा हुआ है। इस समय लगभग 250 यूनेस्को क्लब आयोग में पंजीकृत हैं जिन्हें यूनेस्को के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्रौन्नत करने के लिए निर्दिष्ट कार्यकलाप आयोजित करने हेतु सामग्री और वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए शिक्षा-यूनेस्को संबद्ध स्कूल परियोजना

16.15.0 इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य संस्थाओं के व्यापक नेटवर्क के जरिए अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए शिक्षा के सामान्य विकास को प्रौन्नत करना है। इस समय भारत में 36 संस्थाएं हैं जो इस परियोजना में भाग ले रही हैं और अपने लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में विभिन्न कार्यक्रमों और कार्यकलापों के आयोजन के लिए आवश्यक सामग्री और बौद्धिक सहायता के लिए सीधी यूनेस्को सचिवालय से जुड़ी हुई है। देशभर के संबद्ध स्कूलों के प्रमुखों और समन्वयकों को अपने-अपने अनुभवों के आदान-प्रदान के लिए सक्षम बनाने की दृष्टि से और इस परियोजना के कार्यान्वयन को और अधिक कारगर बनाने के लिए उपायों पर विचार करने हेतु, भारतीय राष्ट्रीय आयोग ने केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के सहयोग से 9-11 मई, 1988 तक केन्द्रीय विद्यालय, शिमला में संबद्ध स्कूलों के समन्वयकों की एक कार्यशाला आयोजित की। इस कार्यशाला में सहभागियों ने संबद्ध स्कूल परियोजना के विभिन्न पहलुओं, इसके उद्देश्यों, अध्ययन के मुख्य विषयों, प्रासंगिक कार्यकलापों और प्रचालन तंत्रों पर चर्चा की। कार्यशाला में उन उपायों पर विस्तारपूर्वक विचार किया गया जो अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना सहयोग और शान्ति की प्रौन्नति में सहायक होंगे।

16.16.0 आयोग ने उस यूनेस्को अन्तर्राष्ट्रीय कूपन योजना का क्रियान्वयन जारी रखा जो शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार के क्षेत्रों में कार्यरत संस्थाओं और व्यक्तियों की सहायतार्थ तैयार की गयी थी ताकि वे विदेशी मुद्रा तथा आयात नियंत्रण प्रक्रियाओं के बिना ही अपनी वास्तविक ज़रूरतों के अनुसार शैक्षिक प्रकाशनों, वैज्ञानिक उपस्करों, शैक्षिक फिल्में आदि आयात कर सकें। वर्ष 1988-89 के दौरान लगभग 7,35,000 रुपए के यूनेस्को कूपनों की बिक्री हुई।

भारतीय राष्ट्रीय आयोग "न्यूज़लैटर" का प्रकाशन

16.17.0 यूनेस्को तथा भारतीय राष्ट्रीय आयोग के कार्यक्रमों और कार्यकलापों के बारे में सूचना के प्रसारण के प्रयोजनार्थ राष्ट्रीय आयोग द्वारा एक अर्ध-वार्षिक न्यूज़लैटर प्रकाशित किया जाता है। न्यूज़लैटर को भारत और विदेश में व्यापक रूप से परिचालित किया जाता है।

यूनेस्को कूरियर के भारतीय भाषा संस्करणों का प्रकाशन

16.18.0 "कूरियर" विश्व की उत्कृष्ट शैक्षिक और सांस्कृतिक पत्रिका है जिसका यूनेस्को द्वारा प्रकाशन किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय आयोग ने इसके हिन्दी तथा तमिल संस्करणों का प्रकाशन जारी रखा। इस भाषा संस्करणों का शैक्षिक संस्थाओं, पुस्तकालयों, यूनेस्को क्लबों, संबद्ध स्कूलों और बहुत बड़ी संख्या में जनता में व्यापक परिचालन होता है।

स्वैच्छिक निकायों, यूनेस्को क्लबों और संबद्ध स्कूलों को वित्तीय सहायता की योजना

16.19.0 आयोग, यूनेस्को के आदर्शों और उद्देश्यों की प्रौन्नति के लिए विभिन्न नवीन कार्यकलाप/ परियोजनाएं शुरू करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों, यूनेस्को क्लबों और सम्बद्ध स्कूलों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की एक योजना चला रहा है। समीक्षाधीन

वर्ष के दौरान विभिन्न संगठनों, यूनेस्को क्लबों आदि की 42,000 रु. का सहायता अनुदान संस्वीकृत किया गया।

यूनेस्को द्वारा प्रायोजित विभिन्न सम्मेलनों/बैठकों में भारत का सहभागिता

16.20.1 भारतीय विशेषज्ञों ने यूनेस्को अथवा इसके क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रायोजित निम्नलिखित कार्यशालाओं, प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों तथा संगोष्ठियों में शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का प्रतिनिधित्व किया :-

- 22 जून से पहली जुलाई, 1988 तक बैंकाक में आयोजित शैक्षणिक प्रबंध सूचना प्रणाली में माइक्रो कम्प्यूटर की भूमिका पर क्षेत्रीय कार्यशाला।
- 13 से 31 अक्तूबर, 1988 तक टोकियो में आयोजित पढ़ने की आदतों को बढ़ावा देने तथा पुस्तक प्रौन्नति (एशिया और प्रशांत में पुस्तक प्रौन्नति पर 21वां प्रशिक्षण पाठ्यक्रम) हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- 18 से 27 अक्तूबर, 1988 तक पेइचिंग में आयोजित उपेक्षित जनसमूहों के लिए शिक्षा के अवसर की समानता पर क्षेत्रीय कार्यशाला।
- सभी के लिए शिक्षा के एशिया प्रशान्त के कार्यक्रमों के क्षेत्रीय समन्वयकों के लिए प्रथम बैठक बैंकाक में 14 से 18 नवम्बर, 1988 तक आयोजित की गई।

16.20.2 उपरोक्त बैठकों के अतिरिक्त भारतीय राष्ट्रीय आयोग ने यूनेस्को द्वारा अथवा उसके तत्वावधान में बुलाई गई करीब 34 राष्ट्रीय क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रीय बैठकों, कार्यशालाओं, सेमिनारों, सम्मेलनों आदि में भाग लेने के लिए विशेषज्ञों को मनोनीत किया। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आयोग ने बहुत से यूनेस्को अध्येताओं के नियोजन की भी व्यवस्था की तथा भारत में विभिन्न संस्थाओं में अध्ययन दौरे भी आयोजित किए।

विदेशी आगन्तुक

16.21.0 एशिया तथा प्रशांत में, सामाजिक तथा मानव विज्ञान, क्षेत्रीय एकक के सामाजिक तथा मानव विज्ञान, के क्षेत्रीय सलाहकार डा. योगेश अटल ने 26-27 मई, 1988 को नई दिल्ली का दौरा किया तथा शिक्षा सचिव और भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के सदस्य सचिव प्रो. इकबाल नारायण से भेंट की।

वैज्ञानिक अनुसंधान तथा उच्च शिक्षा प्रभाग, विज्ञान क्षेत्र, यूनेस्को पेरिस के निदेशक ने अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान से सम्बन्धित मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिए 17-22 सितम्बर, 1988 तक नई दिल्ली का दौरा किया। अन्य लोगों के अलावा, डा. जारोव ने, भारतीय राष्ट्रीय आयोग के भूतपूर्व सचिव, श्री बलदेव महाजन से भेंट की और यूनेस्को की थर्ड मिडियम टर्म योजना की रूपरेखा में शामिल किए जाने हेतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित प्रमुख कार्यक्रम 11 तथा आपसी रुचि के अन्य मामलों पर विचार विमर्श किया।

संस्कृति अध्ययन तथा प्रसार प्रभाग के कार्यक्रम विशेषज्ञ, श्री एन. कासी ने 28 से 31 जुलाई, 1988 तक नई दिल्ली का दौरा किया। अपने प्रवास के दौरान अन्य लोगों से भेंट करने के अलावा, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आयोग के तत्कालीन सचिव के साथ भी भेंट की।

सामान्य कार्यक्रमों तथा कार्यक्रम सहायता क्षेत्र के सहायक महानिदेशक, श्री टी. केलर ने 16-17 अगस्त, 1988 को नई दिल्ली का दौरा किया। उन्होंने 16 अगस्त, 1988 को शिक्षा सचिव के साथ भेंट की तथा आपसी हितों के मामलों पर विचार-विमर्श किया।

यूनेस्को सम्बन्धी बंगलादेश राष्ट्रीय आयोग के सचिव, श्री एस. एम. सैफुद्दीन ने 30 अगस्त से 4 सितम्बर, 1988 तक, नई दिल्ली का दौरा किया। एक सितम्बर, 1988 को उन्होंने शिक्षा विभाग के अपर सचिव, श्री एस. गोपालन से मुलाकात की तथा वह भारतीय राष्ट्रीय आयोग के अधिकारियों से भी मिले।

प्रो. जोन क्राकेट स्मिथ ने यूनेस्को न्यू. एन. ई. पी. कार्यक्रम 1984-1988 के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के मूल्यांकन के संबंध में 22-26 सितम्बर, 1988 तक भारत का दौरा किया। भारत में अपने प्रवास के दौरान उन्होंने पर्यावरण तथा वन मंत्रालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय शैक्षणिक आयोजना तथा प्रशासन संस्थान, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद तथा प्रौढ़

शिक्षा निदेशालय आदि में पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम से सम्बन्धित उच्च अधिकारियों से भेंट की तथा भारत में इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के मुद्दों सहित विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श किया।

यूनेस्को के महानिदेशक श्री फेडरिको मेयर तथा यूनेस्को के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने 13-16 दिसम्बर, 1988 तक भारत का दौरा किया। श्री मेयर का महानिदेशक के रूप में इस देश का यह प्रथम दौरा था। अपने प्रवास के दौरान, उन्होंने भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्री से मुलाकात की।

यूनेस्को के बजट में योगदान

16.22.0 महासम्मेलन द्वारा निर्धारित मानदण्ड के अनुसार, संगठन के बजट में यूनेस्को के प्रत्येक सदस्य राज्य का योगदान नियत किया जाता है। यूनेस्को के महासम्मेलन द्वारा अपने 24वें सत्र में भारत के योगदान का अंश अपने कुल बजट का 0.34 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। वर्ष 1988 के लिए भारत ने भारतीय रुपयों में 1,16,37,000 रुपये का योगदान दिया।

यूनेस्को का कार्यकारी बोर्ड

16.23.0 वर्ष के दौरान यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड का 129 वां और 130वां सत्र पेरिस में आयोजित किया गया था। कार्यकारी बोर्ड में भारत के सदस्य, सरदार स्वर्ण सिंह ने इन बैठकों में भाग लिया।

विश्वदाय समिति

16.24.1 1972 में अपनाई गई विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक परम्परा के संरक्षण से सम्बन्धित सम्मेलन के प्रावधानों के अनुसरण में, यूनेस्को ने एक विश्व दाय समिति का गठन किया है जो इन प्राकृतिक और सांस्कृतिक स्थानों का पता लगाएगी जो विश्व दाय सूची में शामिल करने के योग्य होंगे और विश्व दाय निधि का संचालन करेगी। इसमें 21 सदस्य हैं। भारत वर्ष 1985 में आयोजित यूनेस्को के महासम्मेलन के 23वें सत्र में इस समिति का सदस्य चुना गया था।

16.24.2 भारत के निम्नलिखित तेरह सांस्कृतिक स्मारकों और चार प्राकृतिक स्थलों को अब तक विश्वदाय की सूची में सम्मिलित किया गया है।

स्मारक

1. ताजमहल
2. अजन्ता की गुफाएं
3. एलोरा की गुफाएं
4. आगरा का किला
5. कोणार्क का सूर्य मन्दिर
6. महाबलीपुरम के स्मारक
7. गोवा के गिरिजाघर और मठ
8. खजुराहो के स्मारकों का समूह
9. हम्पी में स्मारकों का समूह
10. फतेहपुर सीकरी में स्मारकों का समूह
11. पट्टाडकल में स्मारकों का समूह
12. एलिफेन्टा की गुफाएं
13. बृहदीश्वर मन्दिर, तंजावूर

प्राकृतिक स्थल

1. काज़ीरंगा राष्ट्रीय उद्यान
2. केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान
3. मानव जीव-जन्तु आरण्य
4. सुन्दरवन राष्ट्रीय उद्यान

16.24.3 विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक दाय के संरक्षण से सम्बन्धित सम्मेलन को लोकप्रिय बनाने की दृष्टि से प्रचार के लिए इसका हिन्दी में अनुवाद किया गया और दोनों भाषाओं में मुद्रित किया गया।

सांस्कृतिक विकास के लिए विश्व दशक 1988-1997

16.25.1 द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति से लेकर पहले दो अन्तर्राष्ट्रीय विकास दशकों के परिणामों से मुख्यत: परिणामात्मक और साज-सामान के विकास पर आधारित विकास की अवधारणा की सीमाएं उजागर हुई। विकास के सांस्कृतिक आयाम पर बल देने की दृष्टि से विश्व सांस्कृतिक नीति विश्व-सम्मेलन (1982) ने सांस्कृतिक विकास के एक विश्व दशक का प्रस्ताव रखा। संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा 1986 में प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया था। दशक, 1988 में शुरू हुआ और 1997 में समाप्त होगा।

16.25.2 दशक के दोहरे लक्ष्य हैं : विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक आयामों पर अधिक बल देना और सामान्य तौर पर, सांस्कृतिक जीवन और रचनात्मक दक्षताओं को उत्प्रेरित करना। यूनेस्को द्वारा दशक मनाने के लिए एक विस्तृत कार्रवाई योजना सदस्य

राष्ट्रों को भेज दी गई है। वर्ष 1987 में आयोजित यूनेस्को के महासम्मेलन के 24वें सत्र में, सांस्कृतिक विकास के विश्व दशक की अन्तर-सरकारी समिति में भारत को चुना गया था। समिति में 26 सदस्य है।

16.25.3 दशक को मनाने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं और कार्यक्रम बनाने के लिए संस्कृति विभाग में एक कार्यदल गठित किया गया है।

ऑरोविल :

16.26.1 ऑरोविल के उचित प्रबन्ध और भावी विकास के लिए, दीर्घकालीन व्यवस्थाएं करने की दृष्टि से, संसद के दोनों सदनों ने ऑरोविल प्रतिष्ठान विधेयक (1988 का अधिनियम 54) सितम्बर, 1988 में पारित किया। अधिनियम में ऑरोविल के कार्यों के अधिग्रहण और स्थानान्तरण और इस प्रयोजन के लिए स्थापित प्रतिष्ठान में इन कार्यों को निहित करने की भी व्यवस्था है। प्रस्तावित प्रतिष्ठान में (क) शासी निकाय (ख) रेजीडेन्ट्स असेम्बली और (ग) ऑरोविल अन्तर्राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, होंगी।

16.26.2 अधिनियम में, ऑरोविल के विकास आदि के लिए, केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता की भी व्यवस्था की गई है।

16.26.3 ऑरोविल के सर्वांगीण विकास की एक स्कीम, सातवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित की गई है और इसके लिए 35.53 लाख रुपये का कुल परिव्यय रखा गया है। स्कीम में तीन महत्वपूर्ण मामलों पर विचार किया गया है : (I) बचपन के प्रारम्भिक स्तरों से प्रारम्भ करते हुए सतत् शिक्षा की आवश्यकता, (ii) ज्ञान और संस्कृति के संश्लेषण की आवश्यकता, और (iii) ऑरोविल और इर्द-गिर्द के गांवों के सर्वांगीण विकास के लिए एक स्थायी आधार प्रदान करने की आवश्यकता। इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 1988-89 के लिए 10 लाख रुपए का बजट प्रावधान रखा गया है। □□

उपलब्धियां–1985-86 से

17.1.1. गत 4 वर्षों की अवधि में सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि–जो वस्तुतः भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, वह है एक राष्ट्रव्यापी परिचर्चा के बाद मई, 1986 में संसद द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अनुमोदन। इसके बाद एक विस्तृत कार्रवाई योजना तैयार की गई जो 23 कार्य-दलों द्वारा इस नीति के प्रत्येक पहलू की जांच पर आधारित है। इस कार्रवाई योजना को भी अगस्त, 1986 में संसद द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई।

17.1.2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति–1986, निम्नलिखित दृष्टियों से, पहले प्रतिपादित 1968 की नीति से भिन्न भी है और बेहतर भी :–

- उपर्युक्त व्यापक कार्रवाई योजना की स्वीकृति।
- प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण, प्रौढ़ शिक्षा और व्यावसायीकरण इत्यादि के लिए निश्चित लक्ष्यों का निर्धारण।
- अनौपचारिक शिक्षा को एक शिक्षा पद्धति के रूप में लागू करना।
- पहली नीति में छात्रों की रोजगार योग्यता के उल्लेख मात्र से आगे जाकर शिक्षा को रोजगारोन्मुख बनाने का परोक्ष आह्वान।
- शिक्षा को मानव संसाधन विकास के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करना।
- महिला समानता से संबंधित शिक्षा के लिए ठोस उपायों का निर्धारण।
- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों, अल्पसंख्यकों, विकलांगों और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष कार्यक्रमों का प्रस्ताव।
- शिक्षा प्रबंध संबंधी कार्यक्रम का प्रस्ताव।
- ग्रामीण जनसंख्या के लिए कार्यक्रमों का सुस्पष्ट निर्धारण।
- राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे पर आधारित शिक्षा की एक राष्ट्रीय पद्धति का निर्धारण।
- नौकरियों को डिग्रियों से अलग करने का आह्वान।

2.0 सरकार द्वारा कार्रवाई-योजना के अनुरूप कई नई योजनागत स्कीमों को कार्यान्वित किया गया है। मुख्य-मुख्य स्कीमों [illegible] दिए गए हैं:–

स्कीम का नाम	उद्देश्य	समग्र स्कीम परिव्यय (रुपये करोड़ों में)	वास्तविक लक्ष्य	विशेषताएं	सहायता की दर	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड	प्रारंभिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण और इस प्रयोजन के लिए न्यूनतम स्तर पर प्राथमिक स्कूलों को भवन आधारिक संरचना उपलब्ध कराना; अतिरिक्त स्कूल शिक्षकों, अधिमानतः महिला शिक्षकों की व्यवस्था करना, शिक्षण अध्ययन सामग्री की व्यवस्था करना।	742.25	87-88 में 20% ब्लाकों का शामिल करना, 88-89 में में 30% और 89-90 में 50%	कालम 2 के समान	शिक्षकों के पदों और शिक्षण अध्ययन सामग्री के लिए राज्यों को 100% सहायता, स्कूल भवनों के लिए निधि एन.आर.ई.पी/आर.एल.ई.जी.पी. के अंतर्गत दी जाती है।	
3. शिक्षक-शिक्षा की पुनर्संरचना और पुनर्गठन।						
(i) स्कूल शिक्षकों का सामूहिक प्रशिक्षण।	शिक्षकों की व्यावसायिक दक्षता सुधारना	38.40	प्रतिवर्ष 5 लाख शिक्षकों का प्रशिक्षण	–संसाधन व्यक्तियों का प्रशिक्षण –शिक्षकों का सेवा-कालीन प्रशिक्षण	संसाधन व्यक्तियों के प्रशिक्षण और शिक्षकों के प्रशिक्षण का व्यय केन्द्र द्वारा वहन किया गया है।	
(ii) जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (डी.आई.ई.टी.एस.)	यथोपरि	288.59	400 संस्थान स्थापित किए जाने हैं।	–शिक्षकों का सेवा-पूर्व और सेवा-कालीन प्रशिक्षण –जिला शैक्षिक प्रणाली	78 लाख रुपये प्रति संस्थान	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				और अनौपचारिक तथा प्रौढ़ शिक्षा के लिए संसाधन सहायता।		
(iii) माध्यमिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढ़ीकरण	यथोपरि	132.19	250 संस्थानों को सुदृढ़ किया जाना है	–डिग्री और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाने के अलावा शिक्षकों की सेवाकालीन शिक्षा। –अन्य शैक्षिक संसाधन एजेंसियों से तालमेल रखना।		72 लाख रुपये प्रति केन्द्र
(iv) राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषदों का सुदृढ़ीकरण	यथोपरि	2.00		परिषदों की अवस्थापना और संसाधनों का सुधार		
3. अनौपचारिक शिक्षा	उन बच्चों तक शिक्षा ले जाना जो औपचारिक शिक्षा प्रणाली	230.45	शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े राज्यों और इसके	–शिक्षा के लचीले कार्य-	राज्यों और स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता निम्नलिखित दर पर :– 50% – सामान्य केन्द्रों के लिए	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	में नहीं आ सकते हैं।		अलावा राज्यों के शहरी क्षेत्रों की गंदी बस्तियों, पर्वतीय, रेगिस्तानी और जनजाति क्षेत्रों को शामिल करना जारी रखना।	क्रम —परि-योजना कार्य नीति —बेहतर पर्य-वेक्षण	90% — बालिका केन्द्रों के लिए 100% — स्वैच्छिक एजेंसियों की परियोजनाओं के लिए 100% — प्रवर्तनकारी परियोजनाओं के लिए	
4. स्कूल शिक्षा का पर्यावरण संबंधी अभि-विन्यास	कालम 1 के समान	37.50	1990 तक 100 परियोजनाएं	—पर्यावरण के संबंध में स्कूली बच्चों में सामान्य जाग-रूकता पैदा करना —सामाजिक वानिकी, नर्सरियां और पौध रोपण		राज्यों और गैर सरकारी एजेंसियों को 100% सहायता
5. स्कूलों में विज्ञान शिक्षा	स्कूलों में विज्ञान शिक्षा का सुधार	161.18	1.12 लाख स्कूलों को शामिल करना	—अपर प्राइमरी, सेकेंडरी स्कूलों की विज्ञान प्रयोग-शालाओं का उन्नयन —पुस्तकालय		विज्ञान उपकरणो के लिए 7500 रु. प्रति स्कूल। विज्ञान पुस्तकों के लिए 15,000/40,000 रु. प्रति स्कूल। प्रत्येक संसाधन केन्द्र के लिए एक लाख रु.। स्वैच्छिक एजेंसियों के लिए 100% सहायता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				सहायता —जिला विज्ञान संसाधन केन्द्रों की स्थापना —प्रवर्तनकारी परियोजनाओं के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता		
6.	शिक्षा का व्यावसायीकरण	सेकेंडरी स्कूल की शिक्षा के बाद की शिक्षा को कार्य जगत के अनुकूल बनाना।	409.82	1990 तक हायर सेकेंडरी स्तर पर 11% छात्रों को व्यावसायिक पद्धति के अंतर्गत लाना। लगभग 5000 स्कूलों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करना	—जिला व्यावसायिक सर्वेक्षण। स्कूलों के लिए व्यावसायिक उपकरण और भवन —पाठ्यचर्या और संसाधन सामग्री का उत्पादन —शिक्षक-प्रशिक्षण	25% से 100% तक की सहायता
7.	शैक्षिक प्रौद्योगिकी	शिक्षा की सुलभता और शिक्षा की कोटि में सुधार	115.90	प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों को एक लाख रंगीन टी.वी. सेटों और पांच लाख रेडियो व कैसेट प्लेयरों की सप्लाई	—शैक्षिक प्रौद्योगिकी स्टुडियो के लिए आधारिक संरचना —शैक्षिक दूर-दर्शन उत्पादन शैक्षिक	राज्य शिक्षा प्रौद्योगिकी संस्थानों के लिए 100% सहायता। रेडियो व कैसेट प्लेयरों के लिए 100% सहायता रंगीन टी.वी. सेटों के लिए 75% सहायता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				दूरदर्शन प्रतिष्ठान की स्थापना		
8.	नवोदय विद्यालय	गांवों के प्रतिभाशाली बच्चों को अच्छी कोटि की शिक्षा देने की व्यवस्था करना।	500.00	प्रत्येक जिले में एक नवोदय विद्यालय	—आवासीय —निःशुल्क भोजन, आवास और शिक्षा। —एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा देशभर में आयोजित वस्तुनिष्ठ परीक्षण द्वारा प्रवेश। —स्वायत्त नवोदय विद्यालय समिति के माध्यम से प्रशासन	केन्द्र द्वारा पूर्णतः वित्त-पोषित।
9.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय	जनसमुदाय के अधिक वर्गों के लिए विशेष-कर सुविधाहीन और पिछड़े क्षेत्रों के लोगों के लिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था ज्ञान और दक्षता के उन्नयन के लिए सतत् शिक्षा की व्यवस्था	46.00 (परियोजना प्रलेखन में प्रस्तावित)	—प्रमाणपत्र और डिप्लोमा पाठ्यक्रम विशेषकर ग्रामीण विकास, भोजन और पोषाहार, संगणक शिक्षा, जनजाति शिक्षा आदि जैसे विशेष विषयों में। —अनुदेशात्मक प्रणाली के लिए बहु माध्यम पैकेज —क्षेत्रीय केन्द्र —दक्षिण दिल्ली में 100 एकड़ भूमि में परिसर का विकास	भारत सरकार द्वारा पूरी तरह वित्त-पोषित	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10.	विश्वविद्यालय प्रणाली के अधीन संस्थाओं का समेकन और विस्तार					
11.	स्वायत्त कालेज	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यों के भाग के रूप में शुरू किए गए कार्यक्रम				
12.	अनुसंधान कार्यों का सुदृढ़ीकरण					
13.	विश्वविद्यालय और कालेज शिक्षकों के वेतनमानों का संशोधन और इन शिक्षकों का प्रशिक्षण	शिक्षकों का स्तर सुधारना तथा उच्च शिक्षा प्रणाली में प्रतिभा को आकर्षित करना तथा बनाए रखना।				
14.	तकनीकी शिक्षा के महत्वपूर्ण क्षेत्र	–नई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधारिक संरचना का सृजन। –उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार जहां कमजोरियां मौजूद हैं। –नई/उन्नत प्रौद्योगिकी के लिए कार्यक्रम।	115.00	पात्र संस्थाओं से प्राप्त परियोजनाओं के के आधार पर	–उपकरणों –प्रयोगशाला के लिए स्थान –पुस्तकों और पत्र-पत्रिकाओं –परियोजना के लिए तकनीकी स्टाफ की व्यवस्था।	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त सभी संस्थाओं के लिए भारत सरकार द्वारा 100% वित्त पोषण
15.	आधुनिकीकरण और पुरानी तकनीक को हटाना।	–नई प्रौद्यो-गिक विकास की पूर्ति के लिए आधारिक संरचना का सृजन	196.00	यथोपरि	उपकरणों और पुस्तकों की व्यवस्था	यथोपरि
16.	अनुसंधान और विकास।	–तकनीकी संस्थानों और	4.5	यथोपरि	–उपकरणों –प्रयोगशाला के लिए स्थान	यथोपरि

(1)	(2)	(3)	(4)	(5) (6)	(7)
	सहायक अनुसंधान परियोजनाओं में अनुसंधान के लिए आधारिक संरचना का सृजन।			—पुस्तकों और पत्र-पत्रिकाओं —परियोजना के लिए तकनीकी स्टाफ की व्यवस्था।	
17. राष्ट्रीय साक्षरता मिशन	15-35 के आयु-वर्ग के निरक्षर प्रौढ़ों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना।	340.00	1990 तक 300 लाख निरक्षर प्रौढ़ों को साक्षरता के अंतर्गत लाना।	राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण की स्थापना। —40 जिलों में प्रौद्योगिकी प्रदर्शन —जनशिक्षण नियलयम के माध्यम से साक्षरता का संस्थापन। —पुराने कार्य-क्रमों, आर.एल.एल.पी., एस.वी.पी. को जारी रखना, प्रशासनिक संरचना आदि का सुदृढ़ीकरण	राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण और प्रौद्योगिकी प्रदर्शन का पूर्णतः वित्तपोषण। प्रति जन शिक्षण निलयम को 14000 रु. 300 केन्द्रों के प्रति आर.ई.एल.पी. को 15.53 लाख रुपये।

नोट : समग्र योजना परिव्यय वही हैं जो सामान्यतः सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए कुल मिलाकर संबंधित योजनाओं के लिए अनुमोदित किए गए हैं और ये वार्षिक बजटों में निधियों के प्रावधान के अध्यधीन हैं।

17.3.1. नीचे दी गई तालिका में 1985-86 से शिक्षा के केन्द्रीय क्षेत्र में योजनागत और योजनेत्तर व्यय के ब्यौरे दिए गए हैं:—

(रुपये करोड़ों में)

85-86			86-87			87-88		
योजनागत	योजनेत्तर	जोड़	योजनागत	योजनेत्तर	जोड़	योजनागत	योजनेत्तर	जोड़
27.12	0.68	27.80	32.60	0.54	33.14	195.98	0.02	196.00
14.92	68.98	83.90	37.83	94.59	132.42	164.62	99.75	263.77
-	-	-	-	-	-	-	-	-
82.58	123.31	205.89	108.28	144.85	253.13	149.87	185.79	335.66
42.34	0.74	43.08	43.64	2.01	45.65	71.70	2.25	73.95
76.03	73.42	149.45	68.50	83.53	152.03	163.48	96.05	259.53
9.25	20.80	30.05	12.24	21.79	34.03	26.47	49.27	76.34
252.24	287.93	540.17	303.09	347.31	650.40	772.12	433.13	1205.25

17.3.2. ऊपर दिए गए आंकड़ों से यह देखा जा सकता है कि 1985-86 सें केन्द्रीय क्षेत्र सें शिक्षा में वास्तविक निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। योजनागत व्यय 206% बढ़ा है और समग्र व्यय 123% बढ़ा है।

17.3.3 1985-86 से प्राप्त कुछ वास्तविक उपलब्धियों का विवरण नीचे दिया गया है:—

	1985-86 में स्थिति	1988-89 में स्थिति
प्रारम्भिक शिक्षा		
केन्द्र द्वारा वित्तपोषित प्राथमिक स्कूलों के भवन - संख्या		100,000 (संचयी) - आपरेशन ब्लैक बोर्ड की संस्वीकृतियों के अधीन निर्मित किए जाने वाले प्रत्याशित
केन्द्र द्वारा वित्तपोषित प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों के पद - संख्या		75,000 (संचयी) (लगभग) - आपरेशन ब्लैकबोर्ड की संस्वीकृतियों के अधीन सृजित किए जाने वाले पद
अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र (संख्या लाख में)	1.75	3.75
अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में नामांकन (व्यक्तियों की संख्या लाख में)	32.53	88.95
स्कूल शिक्षकों का सामूहिक अनुस्थापन — अनुस्थापित शिक्षकों की संख्या		14 लाख (संचयी)
वित्तपोषित शिक्षक - प्रशिक्षण संस्थाएं- संख्या (डी.आई.ई.टी., सी.टी.ई. आदि)		240 (संचयी)
अपंगों के लिए एकीकृत शिक्षा स्कीम के अधीन सम्मिलित क्षेत्र		15 राज्य और 3 संघ राज्य क्षेत्र
केन्द्रीय राज सहायता पर राज्यों को सप्लाई किया गया सफेद प्रिंटिंग कागज (टनों में)		1987-88 से प्रतिवर्ष 80,000 टन आवंटित किया।

	1985-86 की स्थिति	1988-89 की स्थिति
माध्यमिक शिक्षा		
मेधावी ग्रामीण बच्चों के लिए नवोदय विद्यालय - संख्या	2	256
मुक्त विद्यालयों में छात्रों का नामांकन - संख्या	8,000	22,000

शैक्षिक प्रौद्योगिकी - वित्तपोषित उपस्कर		21,000 रंगीन टेलीविजन सेट 85,000 रेडियो-व-कैसेट प्लेयर स्कूलों में वितरित किए गए (संचयी) (लगभग)
शैक्षिक टी.वी. का प्रसारण		सभी हिन्दी भाषी राज्यों तथा आ.प्र. गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा में सप्ताह में 5 दिन, 45 मिनट के लिए
स्कूलों में संगणक शिक्षा शामिल किए स्कूलों की संख्या	250	1250
संशोधित पैटर्न पर व्यावसायिक शिक्षा-- सम्मिलित स्कूल -- संख्या स्वीकृत पाठ्यक्रम -- संख्या		 2000 (संचयी) लगभग 6000 (संचयी) लगभग
उच्च शिक्षा अपर स्नातक पाठ्यक्रमों की पुनर्संरचना के लिए सूचीबद्ध कालेज/विश्वविद्यालय - संख्या	3540/100	3800/117
पाठ्यचर्या विकास केन्द्र - संख्या		24 (संचयी)
गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले विश्वविद्यालय - संख्या	100	117
गुणवत्ता सुधार के लिए सहायता प्राप्त अनुसंधान परियोजनाएं - संख्या	1595	4000
सुदूर शिक्षा के लिए नामांकन (इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय) संख्या		54,000 (जनवरी, 1989)
तकनीकी शिक्षा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान से निकले छात्र- 1985-86 से कुल, 1988-89 के लिए पूर्वामान सहित, अवर-स्नातक और उत्तर स्नातक - संख्या		13,315 (इनमें वे अवर-स्नातक भी शामिल हैं जो उत्तर-स्नातक डिग्री प्राप्त करने के लिए गए हुए हैं)
क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों की प्रशिक्षण क्षमता - संख्या		
अवर-स्नातक	4026	4720

उत्तर स्नातक	571	1050
प्रशिक्षुता प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वालों की संख्या	12,831	17,352
कोटि सुधार कार्यक्रम (तकनीकी शिक्षा) के अंतर्गत दी गई प्रशिक्षण क्षमता	240	350
सामुदायिक पॉलिटेक्निक-संख्या	46	108
सामुदायिक पॉलिटेक्निकों के अंतर्गत प्रशिक्षित जनशक्ति - संख्या		44,827 86-87 से सितम्बर 88
"महत्वपूर्ण क्षेत्र" योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त परियोजनायें (आधुनिकीकरण) परियोजनाओं को शामिल करते हुए - संख्या		1960 (85-86 से 88-89)
प्रौढ़ शिक्षा		
प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र - संख्या लाखों में	1.36	2.71
प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों में नामांकन-प्रौढ़ों की संख्या - लाखों में	6.00	81.47
उत्तर-साक्षरता केन्द्र (जन शिक्षण निलयम) - संख्या		14365
छात्रवृत्तियां		
राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना - संख्या	27,000	40,000
राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति योजना - संख्या	20,000 प्रतिवर्ष	
मेधावी ग्रामीण बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की योजना - संख्या	33,000	38,000
भाषा विकास		
अहिन्दी भाषी राज्यों में केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तपोषित हिन्दी शिक्षकों के पद - संख्या	500	2500

हिन्दी में पत्राचार पाठ्यक्रमों के लिए नामांकन (केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के अंतर्गत) - संख्या	15,800	17,000
आधुनिक भारतीय भाषा शिक्षण के लिए शिक्षक-प्रशिक्षुओं का नामांकन - संख्या		339
संस्कृत के प्रचार के लिए सहायता प्राप्त स्वैच्छिक संगठन - संख्या	700	700
प्रारंभिक संस्कृत में पत्राचार पाठ्यक्रम के लिए नामांकन - संख्या	900	4000

शिक्षा का समग्र प्रसार

(i) संस्थाओं की दृष्टि से	सितम्ब 84 में स्कूलों की संख्या	सितम्ब 1987 में स्कूलों की संख्या
इण्टरमीडिएट/जूनियर कालेज	4,060	4,448
उच्चतर माध्यमिक (10+2 नई प्रणाली)	7,059	11,115
उच्चतम माध्यमिक (पुरानी प्रणाली)	3,959	897
उच्च/उत्तर बेसिक	47,816	54,845
मिडिल/सीनियर बेसिक	1,29,879	1,41,014
प्राइमरी/जूनियर बेसिक	5,19,701	5,43,677
पूर्व प्राईमरी/पूर्व बेसिक	10,274	14,765
	722,748 (7.2 लाख)	7,70761 7.7 लाख)

(ii) नामांकन की दृष्टि से	सितम्बर 84 में छात्रों की संख्या	सितम्बर 87 में छात्रों की संख्या
इण्टरमीडिएट/जूनियर कालेज	18,44,515 कालेज	19,56,639

उच्चतर/माध्यम (10+2 नई प्रणाली)	17,81,546	29,13,238
उच्चर माध्यमिक (पुरानी प्रणाली)	14,83,739	81,367
उच्च/उत्तर बेसिक	1,05,54,754	1,24,52283
मिडिल/सीनियर बेसिक	2,62,53,145	2,99,14,499
प्राइमरी/जूनियर बेसिक	8,39,32,704	9,29,43,556
पूर्व-प्राइमरी/पूर्व-बेसिक	10,33,315	14,20,705
	12,68,83,718 (12.6 करोड़)	14,16,82,287 (12.2 करोड़)

17.4.0 निम्नलिखित पैराओं में कुछ ऐसे मुख्य क्षेत्र दिए गए हैं जिन पर ध्यान केन्द्रित किया गया है तथा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 तथा कार्य योजना के सन्दर्भ में सरकार द्वारा शिक्षा को दिए गए नए दिशा-निर्देशों को दर्शाते हैं।

शिक्षा की विषय-वस्तु

17.4.1 शिक्षा की विषय-वस्तु का पुनर्अनुस्थापन किया जा रहा है। एक राष्ट्रीय कोर पाठ्यचर्या स्पष्ट की गई है जिसमें राष्ट्रीय पहचान, धर्म-निरपेक्षता, पर्यावरण का संरक्षण महिला-पुरुष की समानता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण आदि मूल्यों को पर्याप्त महत्व दिया गया है। रा.शै.अ. एवं प्र.प. तीन वर्ष की सीमावधि में समयवद्ध रीति से पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों का पुनरीक्षण कर रही है। राज्य सरकारों को यह सलाह दी गई है कि वे इसी प्रकार के कदम उठाएं। स्कूल पाठ्यपुस्तकों का राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से मूल्यांकन किया जा रहा है। ऐसी सामग्री जो अस्पृश्यता, जातिवाद, साम्प्रदायिकता आदि को प्रभावित कर सकती है, को मूल्यांकन की इस प्रक्रिया द्वारा समाप्त किया जाना है। इतिहास तथा भाषा सम्वन्धी पुस्तकों का मूल्यांकन लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है। अगले चरण में भूगोल, राजनीति-विज्ञान आदि विषयों पर पुस्तकों को लिया जाएगा। भारत के स्वतंत्रता आन्दोलन के इतिहास को भी स्कूलों में पढ़ाए जाने वाले कोर क्षेत्र के रूप में माना गया है।

17.4.2 कार्यक्रमों की पुनर्संरचना से सम्बन्धित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की योजना में आधारभूत पाठ्यक्रमों के लिए प्रावधान है ताकि भारत के सांस्कृतिक इतिहास, भारत के स्वतंत्रता आन्दोलन के इतिहास तथा राष्ट्रीय एकता को शामिल किया जा सके।

17.4.3 परिवार कल्याण कार्यक्रम को भी शिक्षा के साथ जोड़ा गया है। जनसंख्या शिक्षा परियोजना को इसके दूसरे दौर में 26 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वयन के अन्तर्गत लाया गया है। जनसंख्या शिक्षा को चुनिन्दा स्कूल विषयों के पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों में शामिल किया गया है। रा.शै.अ. एवं प्र.प. ने कोर पाठ्यचर्या में शामिल करने के लिए इस संबंध में न्यूनतम आवश्यक महत्वपूर्ण विचारों का निर्धारण किया है और आदर्श सामग्री विकसित की है। वि.अ.आ. ने जनसंख्या शिक्षा क्लब प्रारंभ किये हैं। जनसंख्या शिक्षा को, वि.अ.आ. - यू.एन.एफ.पी.ए. परियोजना के अन्तर्गत अवर-स्नातक स्तर पर पाठ्यक्रमों की पुनर्संरचना की योजना के अन्तर्गत आधारभूत और प्रायोगिक पाठ्यक्रमों के अंग के रूप में भी शामिल किया गया है। जनशिक्षा कार्यकर्ताओं को

प्रशिक्षित करने, पाठ्यचर्या विकसित करने और शिक्षण सामग्री तैयार करने के लिए कार्यदलों का गठन किया गया है। प्रौढ़ शिक्षा संदेशों के द्वारा छोटे परिवार के प्रतिमानों को भी प्रचारित किया जाता है।

विज्ञान शिक्षा में गणित को बढ़ावा देना

17.5.1 जैसा कि अनुच्छेद 17.2.0 में पहले ही कहा गया है स्कूल में विज्ञान शिक्षा की एक बृहद् योजना कार्यान्वित की जा रही है, स्कूलों की प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों इत्यादि के स्तर में सुधार लाने के लिए सहायता दी जा रही है। रा.शै.अ. एवं प्र. प. ग्रीष्मकालीन संस्थान आयोजित करने के माध्यम से अपने क्षेत्रीय कालेजों में अध्यापकों को विशेष प्रशिक्षण दे रहा है।

17.5.2 वि.अ.आ. ने गणित के क्षेत्र में शिक्षण और अनुसंधान के सुधार हेतु उपायों की सिफारिश के लिए देश के विशिष्ट गणितज्ञों का एक पैनल बनाया है। यह पैनल, सहकारी अनुसंधान और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए ''गणित के अनुप्रयोग में राष्ट्रीय संस्थान'' (एन.आई.ए.एम.) की स्थापना के लिए एक परियोजना दस्तावेज तैयार कर रहा है।

17.5.3 कालेज विज्ञान सुधार कार्यक्रम 300 से अधिक उच्च शिक्षा संस्थाओं में विज्ञान शिक्षण सुधार के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है।

माध्यमिक और उत्तर माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रमों का आधुनिकीकरण

17.6.1 व्यावसायीकरण की नई स्कीम से कार्यजगत में उसकी सुसंगतता के अनुसार उत्तर माध्यमिक शिक्षा का महत्वपूर्ण पुनर्स्थापन हुआ है। ग्रास रूट स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक संस्थाओं की सार्थक प्रबंध संरचना बनाई जा रही है। पाठ्यक्रमों के व्यावसायिक विषयों की पुनःरचना की गई है ताकि स्थानीय स्तर पर रोजगार में लगने के उद्देश्य से स्कूल के छात्र अपनी परीक्षा के बाद क्षमता प्राप्त कर सकें।

17.6.2 उच्च शिक्षा स्तर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के माध्यम से विभिन्न प्रमाण पत्र, डिप्लोमा और डिग्री पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं, ये पाठ्यक्रम उनके रोजगार अवसरों और अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं से सम्बद्ध है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्थापित पाठ्य-विवरण विकास केन्द्र इस संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है।

17.6.3 तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में उद्योग-संस्था अंतःक्रिया योजना कार्यान्वित की जा रही है। उद्योगों को तकनीकी शिक्षा संस्थाओं के शासी मंडलों में प्रतिनिधित्व दिया गया है। संस्थायें, अपनी ओर से, उद्योगों के लिए परामर्शदात्री कार्यक्रम शुरू कर रही हैं। उद्योगों में कार्यरत टैक्नोक्रेट संस्थानों की अंशकालिक संकाय सदस्यों के रूप में सेवा करते हैं। उद्योग-उन्मुख स्नातकोत्तर कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। नए पाठ्यक्रम/कार्यक्रम प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी के नए क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं। इंजीनियरी और प्रौद्योगिक संस्थान अपनी अवस्थापना को उन्नत कर रहे हैं ताकि संगणक विज्ञान, इलेक्ट्रानिकी आदि जैसी प्रौद्योगिकीयों के महत्वपूर्ण क्षेत्र में सुविधाओं का विस्तार किया जा सके। इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिक संस्थानों में आधुनिकीकरण तथा अप्रचलित पद्धतियों को हटाने की प्रक्रिया को उच्च प्राथमिकता दी गई है।

सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग

17.7.1 इन्सैट के उपयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षा प्रौद्योगिकी के लिए केन्द्र-प्रायोजित योजना को 1987-88 में संशोधित किया गया था। केन्द्रीय शिक्षा तथा प्रौद्योगिकीय संस्थान और राज्यों के शिक्षा तथा प्रौद्योगिकीय संस्थानों को सुदृढ़ किया जा रहा है। इन्सैट राज्यों (आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा) के शैक्षिक टी.वी. उत्पादन कार्यक्रमों को केन्द्र द्वारा सहायता दी जा रही है। रंगीन टी.वी. तथा रेडियो व कैसेट प्लेयरों को स्कूलों में उपयोग के लिए विस्तृत रूप से वितरित किया जाता है।

17.7.2 वि.अनु.आ., इन्सैट–1बी. सुविधाओं का उपयोग दो घंटों के लिए, उच्च शिक्षा–''देशव्यापी क्लासरूम'' पर टी.वी. कार्यक्रम के लिए कर रहा है। वि.अनु.आ. ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में 4 शैक्षिक माध्यम अनुसंधान केन्द्र और 7 श्रव्य-दृश्य अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना टी.वी. सॉफ्टवेयर के प्रशिक्षण तथा उत्पादन के लिए की है। अनुमान है कि वर्तमान गति से वि.अनु.आ., इ.गां.रा.मु.वि. तथा रा.शै.अनु.प्र. परि. की आवश्यकता को देखते हुए

1991-92 तक एक अलग शैक्षिक टी.वी. चैनल की जरूरत होगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी संस्थानों की अवस्थिति

17.8.1 सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत पंजाब, राजस्थान, गुजरात और जम्मू व कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों में पालिटेक्निकों और आई.टी.आई. को स्थापित करने की स्वीकृति दे दी गई है।

17.8.2 सामुदायिक पॉलिटेक्निक की योजना का पुनर्स्थापन किया गया है ताकि उनके द्वारा ग्रामीणों के लिए जनशक्ति विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को सुकर बनाया जा सके, जिससे कि वे रोजगार प्राप्त करने योग्य कौशल प्राप्त कर सकें। वे उपयुक्त प्रौद्योगिकीयों पर सूचना प्रसारित करने के अतिरिक्त तकनीकी तथा सामुदायिक सहायता सेवाएं भी प्रदान कर रहे हैं।

सभी स्तरों पर गुणवत्ता तथा उत्कृष्टता

17.9.0 प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण, माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण आदि के कार्यक्रमों का इस तरह निर्माण किया गया है कि उपलब्धियों की परिकल्पना न केवल परिमाणात्मक रूप में की जा सके बल्कि गुणात्मक रूप में भी की जा सके। शिक्षण का व्यावसायीकरण, बच्चों की ओर से दक्षता प्राप्त करने के प्रयासों को सर्वाधिक महत्व दिया जा रहा है। नवोदय विद्यालयों में प्रवेश, आर्थिक स्थिति का विचार किए बिना, केवल मेधावी ग्रामीण बच्चों को दिया जाता है और प्रवेश का आधार वस्तुपरक परीक्षाओं में सफलता है। वि.अनु.आ. कॉलेज विज्ञान में सुधार कार्यक्रम, मानविकी तथा समाजविज्ञान में सुधार कार्यक्रम आदि जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से कॉलेजों में गुणवत्ता तथा उत्कृष्टता को प्रोन्नत करने के लिए विशेष सहायता प्रदान करता है। अ.भा.त.शि.प. अधिनियम के बन जाने के पश्चात् अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् को कानूनी अधिकार भी प्राप्त हो गए हैं।

शिक्षा तक पहुंच

17.10.1 वंचित वर्ग की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं, कामकाजी वर्ग तथा अल्पसंख्यकों के लिए विशेष कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

17.10.2 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को प्रदान किए जाने वाले लाभ, शिक्षण संस्थाओं में दाखिले के लिए सीटों के आरक्षण, दाखिले के लिए अर्हता स्तरों में छूट, विभिन्न स्तरों पर-पूर्व-मैट्रिक से अनुसंधान स्तरों तक—छात्रवृत्तियों, परीक्षा शुल्कों में छूट, छात्रावास के आरक्षण, उपचारी शिक्षण आदि के रूप में हैं।

17.10.3 औपचारिक स्कूल प्रणाली में प्रारम्भिक स्तर पर लड़कियों के नामांकन को बढ़ावा देने के लिए, आपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना के अन्तर्गत सृजित पदों पर अध्यापिकाओं की भर्ती को प्राथमिकता दी जा रही है। अनौपचारिक शिक्षा के लिए पूर्णरूपेण बालिका केन्द्रों को उच्च स्तर की सहायता दी जा रही है। व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा में महिलाओं की परिवर्धित पहुंच को बढ़ावा दिया जा रहा है।

17.10.4 प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत श्रमिक विद्यापीठ योजना की समीक्षा की गई है। ये विद्यापीठ ग्रामीण कामगारों, महिला श्रमिकों और कामगार-उत्पादकता की ओर अधिक ध्यान दे सकें, इसके लिए उपाय किए गए हैं। प्रधानमंत्री के 15-सूत्री कार्यक्रम के अनुसार अल्पसंख्यकों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता और तकनीकी कौशल प्राप्त करने में मदद देने के लिए कदम उठाए गए है। अल्पसंख्यक-बहुल 38 विभिन्न क्षेत्रों में दस्तकारी प्रशिक्षण देने के लिए 10 पॉलिटेक्निक प्रारंभ किए गए हैं। अल्पसंख्यक-बहुल क्षेत्रों में शिक्षकों को अंग्रेजी, विज्ञान और गणित पढ़ाने का विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। इस प्रयोजन के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, उस्मानिया विश्वविद्यालय, जम्मू विश्वविद्यालय और मराठवाड़ा विश्वविद्यालय में अनुसंधान केन्द्र कार्य कर रहे हैं।

17.10.5 त्रिभाषा सूत्र के अधीन भाषा शिक्षा के लिए 15 राज्यों में उर्दू-अध्ययन के लिए सुविधाएं प्रदान की गई हैं।

17.10.6 बुनियादी तथा सज्जायुक्त केलिग्राफी में दक्षता प्रदान करने के लिए उर्दू तरक्की बोर्ड के माध्यम से केन्द्र द्वारा 35 केलिग्राफी प्रशिक्षण केन्द्रों को वित्तीय सहायता दी जा रही है।

17.10.7 उपर्युक्त सभी प्रयासों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के व्यापक ढांचे के अंतर्गत, आने वाले वर्षों में जारी रखा जाएगा और पूर्णता प्राप्त की जाएगी।

वित्तीय आवंटन

(लाख रुपए)

मदें	योजनागत/ योजनोत्तर	बजट अनुमान 1988-89 मूल	संशोधित	बजट अनुमान 1989-90
2	3	4	5	6
ल शिक्षा				
. ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड	योजनागत	13,000.00	13,000.00	13,000.00
9-14 आयुवर्ग के लिए अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र (मिश्रित)	—वही—	2940.00	1,790.00	2,340.00
. लड़कियों के लिए अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र	- वही -	1,565.00	1,052.00	1,765.00
. स्वैच्छिक एजेन्सियों को अनुदान	- वही -	400.00	750.00	700.00
	योजनेत्तर	15.00	15.00	15.00
. राजस्थान में एस. आई. डी. ए. की वित्तीय सहायता से शिक्षा-कर्मी परियोजना प्रारम्भ की गई	योजनागत	135.00	110.00	235.00
. नीदरलैंड से वित्तीय सहायता द्वारा महिलाओं की समानता के लिए शिक्षा परियोजना	योजनागत	300.00	300.00	400.00
'. स्कूल शिक्षकों के लिए व्यापक अनुस्थापन कार्यक्रम	योजनागत	1,543.00	1.080.00	570.00
ӏ. (i) जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान (डी. आई. ई. टी.) (ii) शिक्षक शिक्षा कालेज तथा उच्च शिक्षा अध्ययन संस्थान आई. ए. एस. ई.) (iii) राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद् (एस. सी. ई. आर. टी.)	योजनागत	3,447.00	3,910.00	4,430.00
9 नवोदय विद्यालय	योजनागत	6,930.00	7,930.00	7,930.00
ंध शासित क्षेत्र				
1. बाल भवन	योजनागत	50.00	50.00	50.00
	योजनेत्तर	50.00	57.00	60.00
2. खुला स्कूल	योजनागत	70.00	72.00	80.00
3. केन्द्रीय विद्यालय संगठन	योजनेत्तर	11724.60	11663.00	14043.00
4. केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन	योजनेत्तर	275.70	325.00	321.30
5. योग का संवर्द्धन	योजनागत	50.00	50.00	79.00
	योजनेत्तर	16.00	20.00	20.00

1	2	3	4	5	6
उच्च शिक्षा व अनुसंधान					
1.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	योजनागत योजनेत्तर	12900.00 17700.00	12900.00 19187.00	12800.00 20224.00
2.	भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला	योजनागत योजनेत्तर	40.00 45.00	40.00 54.00	40.00 57.00
3.	भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद्	योजनागत योजनेत्तर	65.00 —	74.00 —	65.00 —
4.	भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद्	योजनागत योजनेत्तर	40.00 74.70	40.00 74.70	40.00 78.25
5.	अखिल भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान	योजनागत योजनेत्तर	30.00 15.00	30.00 15.50	20.00 16.00
6.	भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्	योजनागत योजनेत्तर	240.00 302.00	330.00 322.00	250.00 338.00
7.	शास्त्री भारत-कनाड़ा संस्थान	योजनेत्तर	38.00	38.00	60.00
8.	विश्वविद्यालयों व कालेजों में शिक्षकों के वेतनमानों मे संशोधन	योजनेत्तर	27,200.00	20607.00	12709.00
9.	राष्ट्रीय अनुसंधान प्राध्यापक	योजनेत्तर	2.20	2.20	3.00
10.	पंजाब विश्वविद्यालय को ऋण	योजनागत	50.00	50.00	50.00
11.	डा. जाकिर हुसैन स्मारक कालेज न्यास	योजनागत योजनेत्तर	20.00 6.00	20.00 6.00	20.00 6.00
12.	भारतीय विश्वविद्यालय संघ	योजनागत योजनेत्तर	8.00 11.00	8.00 11.00	8.00 17.00
13.	जामिया मिलिया इस्लामिया	योजनागत योजनेत्तर	50.00 75.50	50.00 76.10	— —
14.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय	योजनागत	1000.00	1000.00	1100.00
15.	ग्रामीण संस्थानों की स्थापना	योजनागत	200.00	50.00	100.00
16.	प्रशासनिक मशीनरी का सुदृढ़ीकरण	योजनागत	5.00	5.00	5.00
17.	राष्ट्रीय उच्च शिक्षा परिषद्	योजनागत	25.00	10.00	10.00
18.	डिग्रियों को नौकरियों से अलग करना/राष्ट्रीय जांच सेवा की स्थापना	योजनागत	100.00	100.00	40.00
अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग					
1.	भारत में यूनेस्को प्रकाशनों के परिपूर्ण प्रलेखन और संदर्भ केन्द्र के रूप में आई. एन. सी. लाइब्रेरी का पुनर्गठन	योजनागत	2.00	1.00	2.00
2.	यूनेस्को के उद्देश्यों तथा लक्ष्यों के प्रोत्साहन के लिए समितियों की बैठकों/सम्मेलनों और प्रदर्शनियों का आयोजन	योजनागत	6.00	3.00	6.00

1.	2.	3.	4.	5	6.
3.	यूनेस्को के कार्यक्रमों तथा कार्यकलापों मे लगे स्वैच्छिक संगठनों को सुदृढ़ करना	योजनागत	2.00	2.00	2.00
4.	ओरोविले प्रबन्ध और ओरोविले का विकास	योजनागत	10.00	10.00	10.00
5.	यूनेस्को कूरियर के हिन्दी तथा तमिल संस्करणों के प्रकाशन के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग का खर्च	योजनेत्तर	12.00	18.50	15.00
6.	अन्य मदें यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग	योजनेत्तर	0.60	0.20	0.60
7.	अन्य मदें—यूनेस्को के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग के कार्यक्रमों के लिए गैर सरकारी संगठनों को अनुदान	योजनेत्तर	0.25	0.25	0.25
8.	अन्य मदें-अन्य कार्यक्रम यूनेस्को से संबंधित आतिथ्य तथा मनोरंजन योजनाएँ	योजनेत्तर	0.05	0.05	0.05
9.	यूनेस्को को अंशदान	योजनेत्तर	103.00	103.00	120.00
10.	विदेशो को भेजे जाने वाले प्रतिनिधिमण्डल-शिष्टमण्डल	योजनेत्तर	7.00	5.00	8.00
11.	विदेशी प्रतिनिधिमण्डलों द्वारा भारत का दौरा	योजनेत्तर	5.00	3.00	5.00
12.	ओरोविले प्रबन्ध	योजनेत्तर	5.00	5.00	6.00

अन्य कार्यकलाप

1.	प्रकाशन	योजनेत्तर	10.50	12.00	15.00
2.	प्रगति मैदान मे शैक्षिक तथा सांस्कृतिक विषयों का मंडप	योजनेत्तर	8.00	4.00	—
3.	राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना तथा प्रशासन संस्थान	योजनागत योजनेत्तर	50.00 82.00	50.00 82.00	60.00 85.00
4.	शास्त्री भवन में लघु संगणक केन्द्र की स्थापना (सचि:)	योजनागत	4.00	4.00	4.00
5.	मंत्रालय में आयोजना, मानीटरिंग और सांख्यिकीय व्यवस्था को सुदृढ़ करना (सचिवालय)	योजनागत	12.00	12.00	16.00
6.	सहायक सामग्री और उपस्कर-उपहार कागज (अनुमानित मूल्य)	योजनेत्तर	366.00	836.00	660.00
7.	नार्वे से उपहार कागज	योजनेत्तर	100.00	100.00	100.00
8.	वर्ष 1987-88 के लिए शैक्षिक क्षेत्रों को सफेद मुद्रण कागज उपलब्ध कराने के लिए सहायता	योजनेत्तर	2400.00	2400.00	2400.00

1.	2	3	4	5	6
9.	राज्य स्तर पर शैक्षिक सांख्यिकीय संगणकीकरण	योजनागत	10.00	10.00	10.00
10.	राज्यों में सूचना प्रबन्ध पद्धति आरम्भ करने के लिए आंकड़े एकत्रित करने के लिए केन्द्रीय सैलों की स्थापना करना।	योजनागत	100.00	—	—

पुस्तक संवर्द्धन तथा कापीराइट

1. राष्ट्रीय पुस्तक न्यास

1.	अनुरक्षण तथा स्थापन	योजनेत्तर	102.90	100.80	153.00
2.	सामान्य प्रौन्नति कार्यकलाप	योजनागत	30.00	10.50	27.00
3.	- वही -	योजनेत्तर	27.00	20.00	37.00
4.	क्षेत्रीय कार्यालय तथा पुस्तक केन्द्र	योजनागत	18.00	* 32.60	18.00
5.	आदान-प्रदान	योजनागत	7.00	5.30	7.00
6.	नेहरू भवन	योजनागत	20.00	8.00	20.00
7.	नेहरू बाल पुस्तकालय	योजनागत	25.00	* 56.20	31.50
8.	सहायता योजना	योजनागत	35.00	16.60	35.00
9.	पुस्तक प्रौन्नति कार्यकलापों को अनुदान और स्वैच्छिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता	योजनागत	6.00	5.00	6.00
10.	राष्ट्रीय पुस्तक विकास परिषद् को अनुदान	योजनागत	2.00	1.00	2.00
11.	पंजाबी पुस्तकों का पुनर्उत्पादन	योजनागत	7.00	2.30	6.00
12.	परामर्शदात्री सेवाएँ	योजनागत	—	1.00	1.00
13.	नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए सामग्री	योजनागत	1.00	1.00	1.00
14.	उत्तर साक्षरता शिक्षा के लिए प्रकाशन	योजनागत	5.00	15.00	10.00
15.	स्कूल पुस्तकालय कार्यक्रम के लिए प्रकाशन	योजनागत	5.00	5.00	5.00
16.	श्रेण्य साहित्य का प्रकाशन	योजनागत	5.00	5.00	5.00
17.	पुस्तक कुशक (किऑस्क) सहित नए बिक्री संवर्द्धन उपाय	योजनागत	10.00	10.00	5.00
18.	बाढ़ में क्षतिग्रस्त शीर्षक का पुनर्मुद्रण	योजनेत्तर	—	* 45.00	—
19.	अन्तर्राष्ट्रीय मानक पुस्तक संख्यांकन (एन. ई. आर. सी)	योजनागत	2.00	2.00	2.00
20.	विश्वविद्यालय स्तर की विदेशी पुस्तकों के प्रकाशन की योजना	योजनागत	1.50	1.00	1.50
21.	राष्ट्रीय लेखक सोसायटी की स्थापना	योजनागत	1.00	0.50	1.00
22.	डब्ल्यू. आई. पी. ओ. को भारत का अंशदान	योजनेत्तर	12.00	13.70	15.00

1	2	3	4	5	6
23.	अन्तर्राष्ट्रीय कापीराइट यूनियन (सी. ई. बी.)	योजनेत्तर	1.00	0.50	1.00
24.	विश्व पुस्तक मेला	योजनेत्तर	1.00	—	40.00
25.	पुस्तक निर्यात संवर्द्धन कार्यकलाप	योजनागत	7.00	7.00	7.00
26.	भारत में सोवियत संघ महोत्सव	योजनागत	3.50	1.00	—

* अनुपूरक अनुदानों की मांग संशोधित की जाएंगी।

छात्रवृत्तियां

1.	राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना		110.00	104.00	110.00
2.	राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति योजना		300.00	300.00	300.00
3.	राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति योजना बट्टा खाता इत्यादि।		10.00	10.00	15.00
4.	राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत वसूलियों में से राज्य सरकारों का 50% हिस्सा		22.00	22.00	22.00
5.	अनु. जा./ अनु. जन. जा. के छात्रों के मेरिट के स्तरों को बढ़ाने की योजना		50.00	50.00	50.00
6.	ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभावना छात्रों को माध्यमिक स्तर पर छात्रवृत्तियां		85.00	85.00	85.00
7.	संस्कृत से अलग अरबी, फारसी जैसी श्रेण्य भाषाओं के अध्ययन के लिए पारम्परिक संस्थाओं के उत्पादन के के लिए अनुसंधान छात्रवृत्तियां		* 1.25	1.25	1.25
8.	विदेशों में अध्ययन हेतु छात्रवृत्तियां		95.00	135.00	140.00
9.	स्वीकृत आवासीय माध्यमिक स्कूलों में छात्रवृत्तियां।		150.00	150.00	165.00
10.	हिन्दी में उत्तर मैट्रिक अध्ययन के लिए अहिन्दी भाषी राज्यों के छात्रों को छात्रवृत्तियों की सहायता योजना		29.10	26.10	34.10
11.	सामान्य सांस्कृतिक छात्रवृत्ति योजना		65.00	65.00	65.00
12.	विदेश मंत्रालय की निधि से बंगलादेश के राष्ट्रिकों के लिए छात्रवृत्तियां		इन योजनाओं के लिए बजट प्रावधान विदेश मंत्रालय द्वारा वहन किया जाता है।		
13.	श्रीलंका, अंगोला, मारीशस, और मालद्वीव के राष्ट्रिकों के लिए छात्रवृत्तियां				
14.	विदेशी सरकारों/संगठनों द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्तियों पर विदेश जाने वाले भारतीय छात्र	योजनेत्तर	10.00	10.00	10.00 (दो लाख रुपए विदेशी मुद्रा में)
15.	भारत में अध्ययन के लिए विदेशी छात्रों को छात्रवृत्तियां	योजनेत्तर	50.00	60.25	70.20

* इस प्रावधान में संस्कृत द्वारा इसी प्रयोजन के लिए किए गए 12.00 लाख का प्रावधान शामिल हैं।

1	2	3	4	5	6
भाषाओं की प्रौन्नति					
1.	हिन्दी के क्षेत्र में कार्यरत योजनागत स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान	योजनेत्तर	100.00 30.00	100.00 30.00	110.00 35.00
2.	दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा मद्रास	योजनागत योजनेत्तर	30.00 30.00	30.00 30.00	40.00 35.00
3.	विदेशों में हिन्दी का प्रचार	योजनागत योजनेत्तर	20.00 8.80	20.00 7.50	20.00 8.70
4.	केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय	योजनागत योजनेत्तर	46.00 78.00	32.00 82.50	42.50 85.50
	(i) पत्राचार पाठ्यक्रम/ कैसेटों का निर्माण	योजनागत योजनेत्तर	10.00 14.00	10.00 14.00	10.00 15.00
	(ii) पुस्तकालय	योजनेत्तर	0.60	0.50	0.60
5.	हिन्दी शिक्षक मण्डल आगरा को अनुदान	योजनागत योजनेत्तर	70.00 115.00	47.10 147.00	50.00 158.50
6.	वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग (कार्यशाला सहित)	योजनागत योजनेत्तर	15.00 39.60	15.00 41.50	15.00 45.00
7.	अहिन्दी भाषी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति (सी. एस. एस. योजना)	योजनागत	214.40	214.00	200.00
8.	अहिन्दी भाषी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में हिन्दी शिक्षक प्रशिक्षक कालेजों की स्थापना	योजनागत	55.00	55.00	40.00
9.	हिन्दी के लिए अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय	योजनागत	35.00	35.00	05.00
10.	सिंधी में पुस्तक निर्माण	योजनागत	5.00	5.00	4.00
11.	तरक्की-ए-उर्दू बोर्ड उर्दू संवर्धन ब्यूरो	योजनागत योजनेत्तर	47.60 34.00	45.95 34.25	47.00 37.50
12.	भारतीय भाषाओं का केन्द्रीय संस्थान, मैसूर	योजनागत योजनेत्तर	70.00 69.20	64.10 69.20	50.00 73.50
13.	क्षेत्रीय भाषा केन्द्र	योजनागत योजनेत्तर	40.00 90.50	34.90 90.55	40.00 102.70
14.	भारतीय भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों का निर्माण				
	(i) राज्य सरकारों को अनुदान	योजनागत योजनेत्तर	18.00 10.00	18.00 10.00	15.00 10.00
	(ii) विश्वविद्यालयों को अनुदान	योजनागत	2.00	2.00	2.00
15.	चिकित्सा (मेडिसन) में महत्वपूर्ण पुस्तकों के निर्माण के लिए राष्ट्रीय पुस्तक न्यास को अनुदान।	योजनागत योजनेत्तर	5.00 0.10	1.35 —	4.00 —

1	2	3	4	5	6
16.	स्वैच्छिक संगठनों को प्रकाशनों के लिए सहायता				
	(i) अंग्रेजी	योजनागत	4.00	5.00	4.00
	(ii) आधुनिक भारतीय भाषा	योजनागत	20.00	18.00	20.00
	(iii) हिन्दी	योजनागत	20.00	20.00	20.00
17.	स्वैच्छिक सगठनों को प्रकाशनों से भिन्न गतिविधियों के लिए सहायता				
	(i) आधुनिक भारतीय भाषा	योजनागत	3.00	1.50	2.00
18.	अंग्रेजी भाषा शिक्षण संस्थानों और अंग्रेजी के जिला केन्द्र को वित्तीय सहायता	योजनागत	50.00	30.00	35.00
19	अंग्रेजी भाषा शिक्षण संस्थान के क्षेत्रीय संस्थान को वित्तीय सहायता	योजनागत	40.00	40.00	35.00
20.	सिंधी विकास बोर्ड की स्थापना	योजनागत	17.00	शून्य	10.00
21.	शिक्षकों की नियुक्ति एम. आइ. एल.	योजनागत	20.00	शून्य	20.00
1.	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान को अनुदान	योजनागत	80.00	62.50	80.00
2.	आदर्श संस्कृत पाठशालाओं तथा अन्य स्वैच्छिक संगठनों में विख्यात वयोवृद्ध विद्वानों की सेवाओं का उपयोग	योजनागत	12.00	10.50	12.00
13.	आदर्श संस्कृत पाठशालाओं/शोध संस्थान को अनुदान	योजनागत	5.00	5.00	5.00
4.	श्रेण्य भाषाएं जिसे अरबी और फारसी की प्रौन्नति और विकास में लगे स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान	योजनागत	12.00	12.00	12.00
5.	संस्कृत साहित्य का उत्पादन	योजनागत	8.00	8.00	8.00
6.	दुर्लभ पाण्डुलिपियों की खरीद और प्रकाशन	योजनागत	3.00	3.00	3.00
7.	संस्कृत पुस्तकों की खरीद	योजनागत	12.00	12.00	12.00
8.	व्यावसायिक विषयों जैसे जीवाश्म विज्ञान पुरालेखा-शास्त्र विज्ञान तथा प्रतिभा विज्ञान में स्नातकोत्तर अध्ययनों में विशेष अनुस्थापन पाठ्यक्रम	योजनागत	3.00	3.00	3.00
9.	(क) अखिल भारतीय वक्तृत्व प्रतियोगिता तथा वैदिक सम्मेलन	योजनागत	49.00	54.00	49.00
	(ख) वैदिक पाठ की मौलिक परम्परा का संरक्षण				
	(ग) वैदिक धर्मस्व की स्थापना (वैदिक सम्मेलन का आयोजन)				
	(घ) वैदिक सम्मेलन आयोजित करना				
10.	संस्कृत शिक्षा का विकास	योजनागत	58.00	58.00	[illegible]
11.	स्वैच्छिक संस्कृत सगठनों को अनुदान	योजनागत	50.00	50.00	[illegible]

1	2	3	4	5	6
12.	सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रम	योजनागत	1.00	1.00	1.00
13.	अन्तर्राष्ट्रीय भारत विद्या और श्रेण्य भाषा संस्थान	योजनागत	35.00	35.00	30.00
14	सम्मान प्रमाण-पत्र प्रदान करना	योजनेत्तर	15.00	21.00	22.50
15.	दक्कन कालेज पूना	योजनेत्तर	10.00	10.00	15.00
16.	छात्रवृत्तियां प्रदान करना	योजनेत्तर	9.50	9.50	9.50
17	आदर्श संस्कृत पाठशाला/शा[illegible] संस्थानों को अनुदान	योजनेत्तर	50.00	50.00	60.00
18.	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान को अनुदान	योजनेत्तर	203.65	212.50	235.00

तकनीकी शिक्षा

1.	सामुदायिक पॉलिटेक्निक्स	योजनागत	100.00	100.00	150.00
		योजनेत्तर	35.00	35.00	35.00
2.	तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान	योजनागत	400.00	388.00	400.00
		योजनेत्तर	273.30	320.00	337.00
3.	उच्च तकनीशियन पाठ्यक्रम	योजनागत	25.00	25.00	15.00
		योजनेत्तर	8.00	8.00	10.00
4.	राष्ट्रीय तकनीकी जनशक्ति सूचना पद्धति	योजनागत	25.00	25.00	25.00
		योजनेत्तर	20.00	20.00	20.00
5.	ग्रामीण विकास के लिए उपयुक्त उचित प्रौद्योगिकी के लिए विशेष संस्थान तथा प्रयोगात्मक प्रायोगिक परियोजनाएं	योजनागत	40.00	40.00	20.00
6.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (तकनीकी)	योजनागत	1200.00	1200.00	1200.00
7.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान	योजनागत	2000.00	2000.00	2000.00
		योजनेत्तर	6685.60	7554.00	7726.00
8.	प्रबन्ध शिक्षा	योजनागत	50.00	50.00	20.00
		योजनेत्तर	10.00	10.00	10.00
9.	क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज	योजनागत	1000.00	1000.00	1150.00
		योजनेत्तर	1508.40	1579.00	1770.00
10.	स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों और अनुसंधान कार्य का विकास	योजनागत	50.00	55.50	150.00
		योजनेत्तर	175.00	675.00	245.00
11.	राष्ट्रीय गढ़ाई और ढलाई संस्थान, रांची	योजनागत	100.00	100.00	100.00
		योजनेत्तर	80.00	75.20	86.70
12.	राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान, बम्बई	योजनागत	100.00	89.00	100.00
		योजनेत्तर	165.00	179.00	185.00
13	आयोजना तथा वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली	योजनागत	150.00	150.00	200.00
		योजनेत्तर	118.50	103.70	118.00

1	2	3	4	5	6
14.	पुरानी घिसी-पिटी वस्तुओं को हटाना और उनका आधुनिकीकरण	योजनागत	4300.00	4300.00	4100.00
15.	तकनीकी शिक्षा के महत्वपूर्ण क्षेत्र				
	(क) उभरती हुई नई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधार-भूत ढाचे का निर्माण।				
	(ख) प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जहां कमजोरी विद्यमान है, सुविधाओं को सुदृढ़ बनाना।	योजनागत योजनेत्तर	2500.00 300.00	2500.00 300.00	1800.00 300.00
	(ग) विशिष्ट क्षेत्रों में नये तथा/और उन्नत प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रमों के कार्यक्रम				
16.	संस्थागत नेटवर्क योजना	योजनागत	100.00	100.00	100.00
17.	(क) प्रशिक्षुता प्रशिक्षण	योजनागत	250.00	198.00	200.00
	(ख) प्रशिक्षुता प्रशिक्षण के अन्तर्गत	योजनेत्तर	312.00	289.30	335.00
	नई योजनाएं	योजनेत्तर	15.00	15.00	15.00
18.	क्षेत्रीय कार्यालय	योजनेत्तर	39.60	40.00	35.90
19.	गुणवत्ता सुधार प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए अनुदान	योजनेत्तर	85.00	85.00	125.00
20.	एशियाई प्रौद्योगिकी संस्थान, बैंकाक	योजनेत्तर	10.80	11.00	12.80
21.	प्रशासनिक स्टाफ कालेज, हैदराबाद	योजनेत्तर	2.50	---	---
22.	भारतीय प्रबन्ध संस्थान	योजनागत योजनेत्तर	600.00 592.70	574.00 617.00	850.00 655.00
23.	ए. आई. सी. टी. ई. और तकनीकी शिक्षा ब्यूरो का पुर्नसंगठन और पुनर्सरचना और सुदृढ़ करना	योजनागत	100.00	100.00	200.00
24.	चुनिंदा संस्थानों को स्वायत्ता अनुदान	योजनागत	10.00	10.00	5.00
25.	असंगठित और गैर सहयोगी क्षेत्रों के लिए विद्यमान संस्थानों को सुदृढ़ करना तथा नये संस्थानों की स्थापना करना	योजनागत	20.00	20.00	10.00
26.	पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों की पुनर्सरचना	योजनागत	20.00	20.00	10.00
27.	महिलाओं के लिए आवासीय पॉलिटेक्निक की स्थापना	योजनागत	140.00	140.00	100.00
28.	विकलांगों के लिए प्रशिक्षण तथा तकनीकी शिक्षा	योजनागत	10.00	10.00	5.00

1	2	3	4	5	6
29.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र	योजनागत	10.00	4.50	10.00
30.	चुनिन्दा उच्च तकनीकी संस्थाओं में अनुसंधान और विकास।	योजनागत	100.00	100.00	100.00
31.	पाठ्यचर्या विकास केन्द्रों/सैलों की स्थापना/सुदृढ़ करना।	योजनागत	50.00	50.00	50.00
32.	सतत् शिक्षा	योजनागत	50.00	50.00	50.00
33	संस्था औद्योगिक पारस्परिक क्रिया	योजनागत	100.00	175.00	200.00
34.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, असम	योजनागत	400.00	400.00	560.00
35.	लोंगोवाल इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संस्थान	योजनागत	100.00	100.00	100.00
36.	विकासशील देशों के लिए तकनीकी परामर्श	योजनागत योजनेत्तर	— 8.75	— 8.00	50.00 8.60
37.	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान में भाग लेने के लिए सहायता	योजनेत्तर	1.25	1.25	2.00
38.	भारतीय तकनीकी शिक्षा सोसायटी	योजनेत्तर	0.50	0.55	0.50
39.	विदेशी विशेषज्ञ (भा. प्रो. स., बम्बई) विदेशी शिष्टमंडल और विदेशी विशेषज्ञ	योजनेत्तर	1.00	1.00	1.00
40.	गैर सरकारी तकनीकी संस्थाओं में छात्रावासों का निर्माण	योजनेत्तर	0.50	0.00	0.50
41.	वेतन आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन	योजनागत योजनेत्तर	— —	— 2000.00	— 2000.00
42.	भारतीय शैक्षिक परामर्शदाता लिमिटेड (ई. डी. सी. आई. एस.)	योजनागत	—	—	—
43.	भारतीय प्रबन्ध अनुभवों का प्रलेखन और गैर सहायक तथा अव्यवस्थित क्षेत्रों में कार्यक्रम प्रदान करना।	योजनागत	—	—	5.00
44.	राष्ट्रीय प्रशिक्षुता बोर्ड	योजनागत	—	—	5.00
45.	स्टाफ विकास तथा प्रशिक्षण	योजनागत	—	—	5.00
46.	प्रौद्योगिकी निरीक्षण दल	योजनागत	—	—	5.00
47.	व्यावसायिक निकायों को सहायता	योजनागत	—	—	10.00
48.	भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर में सुपर संगणक	योजनागत	—	929.00	2700.00

1	2	3	4	5	6
प्रौढ़ शिक्षा					
1.	ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजनाएं	योजनागत	4000.00	4000.00	4100.00
		योजनेत्तर	130.00	130.00	130.60
2.	उत्तर साक्षरता तथा सतत शिक्षा (जन शिक्षण निलयम)	योजनागत	100.00	100.00	1200.00
3.	प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ बनाना	योजनागत	350.00	415.00	350.00
4.	कार्यात्मक साक्षरता के लिए व्यापक कार्यक्रम	योजनागत	150.00	150.00	250.00
5.	प्रौद्योगिकी प्रदर्शन	योजनागत	1000.00	1000.00	367.00
6.	स्वैच्छिक एजेन्सियों को सहायता (राज्य संसाधन केन्द्रों तथा बाह्य मूल्यांकन के लिए अनुदानों सहित)	योजनागत	750.00	1250.00	1040.00
		योजनेत्तर	13.40	13.90	15.00
7.	श्रमिक विद्यापीठ	योजनागत	100.00	96.00	100.00
		योजनेत्तर	76.80	84.10	102.00
8.	राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण	योजनागत	75.00	50.00	25.00
9.	प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय	योजनागत	125.00	235.00	185.00
		योजनेत्तर	35.55	39.00	40.00

मानव संस्थान विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) 1987-88 से एक लाख रुपये और इससे अधिक आवर्ती सहायता अनुदान प्राप्त करने वाले प्राइवेट और स्वैच्छिक संगठनों के नाम

क्र. सं.	निजी और स्वैच्छिक/ संगठनों के नाम व पते	संगठन के संक्षिप्त कार्यकलाप	1987-88 के दौरान मुक्त की गई आवर्ती सहायता अनुदान राशि	प्रयोजन जिसके लिए अनुदान का उपयोग किया गया था	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6
स्कूल शिक्षा और शारीरिक शिक्षा					
1.	कैवल्याधाम श्रीमन माधव योग मन्दिर समिति लोनावाला, पुणे	योग के राष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान और शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम की देखभाल और विकास	26.28 लाख	योग के राष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान और शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम की देखभाल और विकास	
2.	सचिव वनस्थली विद्यापीठ, पो. वनस्थली विद्यापीठ 304022 (राजस्थान)	वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में अपने सम्पूर्ण भारतीय चरित्र के साथ एक प्रमुख संस्थान है और महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रही है।	5,00,000/- रु.	वित्तीय कठिनाइयों को पार लगाने के लिए आवर्ती घाटा पूरा करना, जिसका विद्यापीठ सामना कर रही है	समीक्षा समिति की सिफारिश के आधार पर विद्यापीठ को अनुदान दिया जा रहा है।
3.	रामकृष्ण नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा संस्थान मैसूर	i) नैतिक एवं आध्यमित्मक शिक्षा में डिग्री पाठ्यक्रम चलाना ii) कर्नाटक राज्य के सेवाकालीन हाई स्कूल अध्यापकों के लिए नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा में अल्पकालीन पाठ्यक्रम चलाना iii) भारत भर से कालेज छात्रों का समागम iv) साधारण जनता सामान्य जन समागम v) मैसूर शहर के उच्च प्राथमिक, प्राथमिक और हाई स्कूल लड़कों के लिए नैतिक और आध्यात्मिक कक्षाए	2,50,000/- रु.	रखरखाव के लिए और संस्थान को चलाने के लिए औ नैतिक व आध्यात्मिक शिक्षा में पाठ्यक्रम चलाने के लिए	
4.	उपाध्यक्ष स्पिक-मेसी, 41/42 लखनऊ रोड, नई दिल्ली	– देश भर में शैक्षिक संस्थाओं में प्राचीन परम्परा को प्रौन्नत करना – स्कूल और कालेज में प्रलेखन व्याख्यान की एक श्रृंखला का आयोजन करना – स्कूलों और कालेजों में योग-शिविरों को चलाना – लोक और शिल्प के कार्यक्रम की एक श्रृंखला का आयोजन करना – देश भर में बैठकों का आयोजन करना	10,00,000/- रु.	शैक्षिक संस्थाओं में प्राचीन परम्परा की पौन्नति के लिए	

1	2	3	4	5	6
5.	निदेशक सी. सी. आर. टी. भगवान दास रोड, नई दिल्ली	– प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना – अनुकूलन पाठ्यक्रम चलाना – प्रशिक्षित अध्यापकों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम का आयोजन करना – शिक्षा के लिए कठपुतली पर पाठ्यक्रमों का आयोजन करना – सांस्कृतिक प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजना का कार्यान्वयन	4,35,000/- रु.	सांस्कृतिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के लिए अभिनव और व्यावहारिक परियोजना के लिए	
6.	सदस्य अलारिप्पु, नई दिल्ली	i) महिलाओं, बच्चों, रंगमंच कर्मियों और स्कूल [illegible] के लिए कार्यशालाएं आयोजित करना आदि ii) शैक्षिक संस्थाओं और स्वैच्छिक संगठनों के जरिए विस्तृत कार्यकलापों के लिए थियेटर ग्रुपों का पता लगाना iii) अपनी आवश्यकताओं और स्थितियों में गहराई से देखने और अपने वातावरण को बढ़ाने और जीवित रखने के लिए प्रचार माध्यम के उपयोग के लिए ग्रामीण कलाकारों के साथ तालमेल बिठाने का प्रयास करना iv) आलेख स्क्रिप्ट्स और थियेटर से संबद्ध सामग्री को एक स्थान पर रखने का प्रयास किया जाएगा ताकि संतुलित दलों को वह तत्काल सुलभ हो सके। v) सामाजिक मुद्दों कर आधारित दो नाटक तैयार करना vi) बाल रंगमंच को प्रोत्साहन देना	2,50,000/- रु.	शिक्षा के लिए संबद्ध संचार माध्यम और थियेटर के प्रयोग की परिवर्तनकारी परियोजना के लिए	

व्यावहारिक और नवाचारी परियोजनाएँ

			रु.	
1.	उत्तराखण्ड सेवा निधि नैनीताल, उत्तर प्रदेश	शैक्षिक	8,20,000	व्यावहारिक और नवाचारी परियोजनाएँ
2.	किशोर भारती, पो. बाखेरी, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश	- वही –	2,99,650	- वही -
3.	एकलव्य प्रतिष्ठान, ई-1/208, एरिया कालोनी भोपाल, मध्य प्रदेश	- वही –	1,40,000	- वही -
4.	केरल शीश साहित्य परिषद्, त्रिचूर (केरल)	- वही –	1,00,000	- वही -
5.	भारतीय शिक्षा संस्थान, पुणे	शैक्षिक अनुसंधान	5,01,237	- वही -
6.	कृष्णामूर्ती प्रतिष्ठान, भारत	स्कूल शिक्षा	1,97,300	- वही -

1	2	3	4	5	6
अनौपचारिक शिक्षा परियोजना					
उड़ीसा			रु.		
1.	जयन्ती पथागार, पो. ब्रह्मबरादा, कटक	समाज सेवा	2,22,900	100	अनौपचारिक शिक्षा केंद्र
[illegible]	कटक जिला आदिवासी हरिजन सेवा संस्कार योजना, चटुटा [illegible] फरीकाबाट कटक	सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यकलापों का विकास	1,20,040	50	
[illegible]	[illegible] महिला समिति, [illegible], कटक	शैक्षिक	2,40,300	100	
	ग्रामीण विकास समिति के. बी. बाडिया पो. महाकालापड़ा, कटक	ग्रामीण उत्थान कार्यक्रम	2,40,300	100	
5	अन्त्योदय सेवा केन्द्र, पो. पुरूनाबसन्त, कटक	समाज सेवा	1,28,740	50	
6.	लोकनायक क्लब, बांकी, कटक	समाज सेवा	2,40,300	100	
7.	कुली, चौधुलट केन्द्रपाडा, कटक	निर्धनों का उत्थान	1,28,740	50	
8.	पाल्लिश्री, पो-गासीपुर, बाकी, कटक	शैक्षिक और सांस्कृतिक युवा कार्यकलाप	1,20,040	50	
9.	सी. वाई. एस. डी., 65 सव्यनगर, भुवनेश्वर, पुरी	विकास की प्रौन्नति	4,80,600	200	
10.	नवज्योति, पो. गरूड़गन, कटक	आर्थिक एव शैक्षिक विकास	1,28,740	50	
11.	भैरवी क्लब, पो० हदयदा, पुरी	शैक्षिक एवं सांस्कृति	1,20,040	50	
12.	युवा एवं एकात्मक विकास केन्द्र, बेसलीहासी, पुरी	सामुदायिक कल्याण	1,20,040	50	
13.	विद्युत क्लब, हलादीपदा, पो बाजपुर, पुरी	सामाजिक सांस्कृतिक एव शैक्षिक विकास	2,40,300	100	
14.	जनकल्याण समाज, गोदीबन, चण्डाका, परीव	सामाजिक सेवा	2,22,900	100	
15.	भवानीशकर क्लब गम्पुर, सिमोर परी	शैक्षिक एवं सांस्कृतिक	2,40,300	100	
16.	नीलांचल सेवा प्रतिष्ठान, बांगान, परी	सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास	2,40,300 ·	100	

1	2	3	4	5	6
			रु.		
17.	आचार्य हरिहर शिशु भवन, सत्यवादी, पो. सखीगोपाल, पुरी	बाल शिक्षा	2,40,300	100	
18.	सामुदायिक कल्याण और समृद्धिकारक समिति भुवनेश्वर, पुरी	सामाजार्थिक और शैक्षिक विकास	1,20,040	50	
19.	दहीखाई युवक संघ, पो. लोढ़ाच्छुआ, पुरी	कल्याण कार्यक्रम	1,28,740	50	
20.	एम. ओ. क्लब, कंटाबड़ा, बाघमारी, पुरी	युवा कल्याण कार्यक्रम	1,28,740	50	
21.	गोपीनाथ जूबा संघ दोरड़ा अहिणी सासन, बाली, पटना	ग्रामीण कल्याण	1,20,040	50	
22.	गनिया उन्नयन कमेटी, गनिया, पुरी	महिला एवं आर्थिक कार्यक्रम उन्नयन	1,28,740	50	
23.	विकास एम-5/11, आचार्य बिहार भुवनेश्वर, पुरी	आथिकि एवं शैक्षिक	1,28,740	50	
24.	उत्कलमणि सेवा संघ पो. बदराईपुरी, पुरी	शैक्षिक	1,28,740	50	
25.	लोक शक्ति, श्रीकान्तपुर, बालासोर	शैक्षिक	2,40,300	100	
26.	मंडल पोखरी युवक संघ, पो. मदारी, बालासोर	शैक्षिक	1,20,040	50	
27.	समग्र विकास परिषद बलियापाल, बालासोर	सामाजार्थिक विकास	1,20,040	50	
28.	नेताजी युवक संघ, बालीपोखरी, बालासोर	सामाजिक एवं सांस्कृतिक	1,28,740	50	
29.	फेलोशिप, पुराना बाजार, भद्राक, बालासोर	व्यावसायिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा	1,20,040	50	
30.	आर. ई. ए. सी. एच. जगमारा, खण्डागिरी, भुवनेश्वर, पुरी	बहुमुखी विकास	2,22,900	100	

1	2	3	4	5
			रु.	
31.	ग्रामीण पुनर्निर्माण, युवा परिषद बोइन्दा, ढोंकानल	कल्याण कार्यक्रम	1,28,740	50
32.	पी. आई. पी. ए. आर. महिमागड़ी, जोरांडा ढोंकानल	सामाजार्थिक	2,22,900	100
33.	सामाजिक सेवा सदन, बांझी कुसुम, महिसापट, ढोंकानल	एकात्मक विकास	1,28,740	100
34.	ग्रामीण विकास के लिए टैगोर सोसायटी, भुवनेश्वर	सामाजार्थिक उत्थान	6,68,700	300
35.	प्रगति युवक संघ, बिजीगोल, ढोंकानल	प्रौढ. बाल एवं महिला शिक्षा	2,40,300	100
36.	ग्रमीण महिलासमाज कल्याण विकास सेवा केंद्र, अंगुल, ढोंकानल		1,28,740	50
37.	ग्राम मंगल पथागार सलापली, बालागीर	शिक्षा एवं सामाजिक	2,40,300.	100
38.	श्री श्रीशारदेश्वरी पथागार पो. तुशरा, बोलांगीर	सामान्य कल्याण	1,28,740	50
39.	बापूजी पथागार सुख, बोलांगीर	सामान्य कल्याण	1,28 740	50
40.	अन्त्योदय चेतना केन्द्र पो. हदगढ़, केओंझर	सामाजिक आर्थिक विकास	1,28,740	50
41.	ग्रामीण पुर्ननिर्माण और उपयुक्त प्रौद्योगिकी स्वैच्छिक परिषद, कटक	समाज सेवा	1,28,740	50
42.	द. डिवाइन लाईफ सोसायटी, मेन रोड, भंजनगर, गंजाम	ग्रामीण विकास	1,28,740	50
43.	प्रगति पथागार नीमाखण्डी पथ, गंजाम	सामाजार्थिक विकास	1,28,740	50
44.	जयन्ती पथागार, नुआपाडा, गंजाम	बहुमुखी विकास	2,40,300	100

1	2	3	4	5	6
			रु.		
45.	घुमसर महिला संगठन, पो. उदयगिरी, फूलबनी	महिला शैक्षिक संगठन	2.40.300	100	
46.	मानव संसाधन और परिस्थिति विज्ञान विकास, फूलबनी	कमजोर क्षेत्रों का विकास	2.22.900	100	
47.	वनवासी सेवा समिति, बालीगुडा, फूलबनी	आदिवासियो का उत्थान	1.20.040	50	
48.	वाग्देवी क्लब, मुकुन्दपुर, पो. जनहायका, फूलबनी	गांवों का कल्याण	1.28.740	50	
49.	एस.एच.ई.डी. कालेज रोड, रायगढ़, कोरापुर	आदिवासी विकास	2.22.900	100	
50.	प्रीपेयर (भारतीय ग्रामीण पुनर्निर्माण और विपक्षी अनुक्रिया सेवा) गांधी नगर, रायगढ़, कोरपुट	समाज सेवा	2.22.900	100	
51.	सर्वोदय समिति, कोरापुट	आदिवासियों का सामाजिक आर्थिक विकास	1.20.040	50	
52.	एस. ओ. डी. ए. बारीपदा, मयूरभंज	आदिवासियों का चहुंमुखी विकास	2.22.900	100	
53.	बीनापानी युवक संघ, बातपोंदीगोदी, मयूरगंज	शिक्षा एवं समाज सेवा	1.20.040	50	
54.	अन्त्योदय चेतना मण्डल, बांराखण्ड, मोरादा, मयूरभंज	आदिवासियों का विकास	2.22.900	100	
55.	बिसोल युवा क्लब, बिसोल, पो. साना, बिसोल, मयूरगंज	शिक्षा	1.28.740	50	
56.	ढोकाया युवक संघ, केओंझर	ग्रामीण विकास	2.22.900	100	
57.	प्रगति पथागार, बेलागुंथा, गंजाम	शिक्षा	1.28.740	50	
58.	पुरानी राऊरकेला शिक्षा समिति, बालीजोड़ी, राऊरकेला	शैक्षणिक	2.40.300	100	
59.	श्री सत्यसाईं सेवा समिति, पो. देओभुवनपुर, सुन्दरगढ़	सामाजिक आर्थिक और ग्रामीण विकास	1.20.040	100	
60.	विवेकानन्द पल्ली अग्रगामी सेवा प्रतिष्ठान, सम्बलपुर	शिक्षा	1.28.740	50	

1	2	3	4	
			(रु.)	
61.	विश्वास कार्लीनिवास, खरीरार रोड कालाहांडी	ग्रामीण विकास, समाज कल्याण	2,57,700	100
62.	जगरूत श्रमिक संगठन कालाहांडी	सामाजार्थिक विकास	1,20,040	50
63.	अग्रगामी, कोरापुट	शैक्षिक	2,05,800	100
64.	गांधी सेवाश्रम, बालासोर	- वही -	2,40,300	100
65.	रामजी युवक संघ, कटक	- वही -	2,40,300	100
आन्ध्र प्रदेश				
66.	रयालासीमा सेवा समिति	सामाजिक कार्य और साक्षरता प्रोन्नति	27,03,962	300 पुराने 800 नए अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र
67.	साक्षरता गृह (आन्ध्र महिला सभा) हैदराबाद	- वही -	2,46,864	100
मध्य प्रदेश				
68.	सुल्तान उल हिन्द शैक्षिक समाज सेवा समिति	सामाजिक कार्य और साक्षरता प्रोन्नति	1,58,408	57
उत्तर प्रदेश				
69.	लोक विकास संस्थान, इलाहाबाद	अनौपचारिक शिक्षा	2,22,900	100
70.	सर्वदलीय मानव विकास केन्द्र	शैक्षिक	2,22,900	100
71.	जनकल्याण शिक्षा समिति, पावानगर	- वही -	2,22,900	100
72.	सर्वोदय शिक्षा समिति, शिकोहाबाद	- वही -	1,20,040	50
73.	सामाजिक एवं आर्थिक विकास संस्थान, लखनऊ	- वही -	2,22,900	100
74.	वनवासी सेवा आश्रम	- वही -	1,98,175	100
राजस्थान				
75.	अजमेर प्रौढ़ शिक्षा परिषद्	प्रौढ़ साक्षरता और अनौपचारिक शिक्षा	3,66,550	50 पुराने 100 नए
76.	जोधपुर प्रौढ़ शिक्षा परिषद्	- वही -	3,06,675	50 पुराने 100 नए
77.	भोरूका धर्मार्थ ट्रस्ट	ग्रामीण विकास	2,22,900	100
78.	ग्रामीण विकास विज्ञान समिति, जोधपुर	ग्रामीण विकास	2,22,900	100

1	2	3	4	5	6
गुजरात			(रु.)		
79.	गुजरात विद्यापीठ,. अहमदाबाद	उच्च शिक्षा	2,40,300	100	
दिल्ली					
80.	पी. एच. डी. ग्रामीण विकास प्रतिष्ठान, नई दिल्ली	ग्रामीण विकास प्रौढ़ अनौपचारिक शिक्षा	2,22,900	100	
81.	अखिल भारतीय समाजोत्थान समिति	शैक्षिक	2,40,300	100	
82.	रवि भारती शिक्षा समिति	- वही -	2,22,900	100	
तकनीकी शिक्षा			(रु. लाख में)		
1.	भारतीय तकनीकी शिक्षा समिति, नई दिल्ली	कोटि सुधार कार्यक्रम	20.27	शीतकालीन–ग्रीष्मकालीन स्कूलों का संचालन	
2.	इंजीनियरी और ग्रामीण प्रौद्योगिकी, संस्थान इलाहाबाद	डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रमों का संचालन	3.50	सामुदायिक विकास कार्य उच्च तकनीशियन पाठ्यक्रम	
3.	करसो वाडिया प्रौद्योगिकी संस्थान पुणे	शैक्षिक और अनुसंधान कार्यकलाप	1.00	स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए	
4.	रामगढ़िया पॉलिटेक्निक फगवाड़ा	- वही -	3.00	- वही -	
5.	थापर पॉलिटेक्निक पटियाला	- वही -	3.00	- वही -	
6.	फिरोज गांधी पॉलिटेक्निक, रायबेरेली	- वही -	3.00	- वही -	
7.	नई दिल्ली महिला पॉलिछटेक्निक, नई दिल्ली	- वही -	2.50	- वही -	
8.	पंडित जवाहरला नेहरू पॉलिटेक्निक, सनावाड	- वही -	1.25	- वही -	
9.	जन और ग्रामीण संस्थान, गारगोटी	- वही -	1.25	- वही -	
10.	बी. एण्ड बी. पॉलिटेक्निक वल्लभ विद्यानगर	- वही -	1.25	- वही -	
11.	बी. एम. पॉलिटेक्निक, बम्बई	- वही -	2.00	- वही -	
12.	सी. एम. कोठारी प्रौद्योगिक संस्थान, मद्रास	- वही -	2.54	- वही -	

1	2	3	4	5	6
			रु.		
13.	वाई. एम. सी. ए. इंजीनियरी संस्थान फरीदाबाद	- वही -	2.30	- वही -	
14.	वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान, भिवानी	- वही -	1.00	- वही -	
15.	हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकीय संस्थान, कानपुर	- वही -	1.09	- वही -	
16.	विक्टोरिया जुबली प्रौद्योगिकीय संस्थान बम्बई	- वही -	25.06	- वही -	
17.	श्री गोविन्द राम सेकसरिया प्रौद्योगिकीय संस्थान, इन्दौर	- वही -	1.00	- वही -	
18.	एम. एम. फार्मेसी कालेज अहमदाबाद	- वही -	5.00	- वही -	
19.	वालचन्द इंजीनियरी कालेज, सांगली	- वही -	6.00	- वही -	
20.	पी. एस. जी. प्रौद्योगिकी कालेज, कोयम्बटूर	- वही -	20.00	- वही -	
21.	थियागराजर इंजीनियरी कालेज मदुरै	- वही -	4.30	- वही -	
22.	राष्ट्रीय इंजीनियरी संस्थान, मैसूर	- वही -	6.49	- वही -	
23.	योजना स्कूल, नवरंगपुरा, अहमदाबाद	- वही -	15.38	- वही -	
24.	एस. जे. इंजीनियरी कालेज, मैसूर	- वही -	6.50	- वही -	
25.	गुरुनानक इंजी कालेज, लुधियाना	- वही -	1.50	- वही -	
26.	बम्बई फार्मेसी कालेज, कालीना, बम्बई	- वही -	3.00	- वही -	
27.	माधव विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, ग्वालियर	- वही -	1.50	- वही -	
28.	बिड़ला प्रौद्योगिक संस्थान, मेसरा, रांची	- वही -	4.02	- वही -	
29.	बी. एम. एस. इंजी. कालेज, बंगलौर	- वही -	10.62	- वही -	

1	2	3	4	5	6
			रु.		
30.	कोयम्बटूर प्रौद्योगिकी संस्थान, कोयम्बटूर	- वही -	5.60	- वही -	
31.	मलन्द इंजी कालेज, हासन, कर्नाटक	- वही -	13.00	- वही -	
32.	भारतीय समाज कल्याण संस्थान, कलकत्ता	- वही -	10.21	- वही -	
33.	टी. के. एम. इंजी. कालेज क्विलॉन	- वही -	3.20	- वही -	
34.	एम. एम. एम. इंजीनियरी कॉलेज, गोरखपुर	- वही -	1.5	- वही -	
35.	के. एम. कुन्दनानी फार्मेसी कालेज बम्बई	- वही -	1.50	- वही -	
36.	प्रबन्ध प्रौद्योगिकी संस्थान, गाजियाबाद	- वही -	2.50	- वही -	
37.	एस. जी. जी. एस. इंजी. कालेज, नान्देड़	- वही -	1.00	- वही -	
38.	पी. ई. एस. इंजी. कॉलेज, मडंया	- वही -	1.50	- वही -	
39.	एशियाई प्रौद्योगिकी संस्थान, बैंकाक	- वही -	2.00	भारत में एशियाई प्रौद्योगिकी संस्थान के कार्यकलाप	
भाषाओं की प्रोन्नति					
1.	आन्ध्र प्रदेश हिन्दी प्रचार सभा हैदराबाद, (आन्ध्र प्रदेश)	हिन्दी शिक्षण केन्द्रों का संचालन, हिन्दी महा-विद्यालयों और हिन्दी प्रचार केन्द्रों आदि में	1,31,865 रु.	शिक्षण केन्द्र, महाविद्यालय, प्रचारक सम्मेलन और हिन्दी डायरी का प्रकाशन	
2.	हिन्दी विद्यापीठ, देवघर, बिहार	शिक्षण कक्षाएं, टंकण और आशुलिपि कक्षाएं	1,38,600 रु.	हिन्दी शिक्षण एवं आशुलिपि और टंकण कक्षाएं, स्टाफ को वेतन, छात्रों को प्रशिक्षण भत्ता	
3.	अखिल भारतीय हिन्दी संस्था संघ, नई दिल्ली	हिन्दी प्रचार कार्यक्रम आदि	4,31,414 रु.	स्थापना व्यय और सतत हिन्दी प्रचार कार्यक्रम	
4.	कर्नाटक महिला हिन्दी सेवा समिति, बंगलौर	हिन्दी शिक्षण कक्षाएं पुस्तकालय, वाद-विवाद आदि	6,32,175 रु.	हिन्दी व्याकरण, मुद्रण, जिल्दसाजी, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, मशीनों सामग्री, मुद्रणालय के लिए उपकरणों की खरीद कक्षाओं का संचालन, पुस्तकालय, वाद-विवाद, पुरस्कार आदि	

1	2	3	4	5	6
			रु.		
5.	कर्नाटक हिन्दी प्रचार समिति बंगलौर	शिक्षण केन्द्रों पुस्तकालय आदि	2,78,975	निःशुल्क हिन्दी शिक्षण केन्द्र, लाइब्रेरी पत्रिकाओं का प्रकाशन, शिक्षण प्रशिक्षण कालेज और स्टाफ का वेतन।	
6.	मैसूर हिन्दी प्रचार परिषद्, बंगलौर	हिन्दी शिक्षण केन्द्र, टंकण और आशुलिपि कक्षाएं आदि	2,49,975	हिन्दी पुस्तकालय, हिन्दी केन्द्र, आशुलिपि और टंकण कक्षाएं तथा हिन्दी के अन्य कार्यक्रम	
7.	बम्बई हिन्दी विद्यापीठ बम्बई	शिक्षण केन्द्र, पुस्तकालय अध्ययन कक्ष, प्रचारक केन्द्र सेमिनार, नाटक आदि	3,59,900	हिन्दी शिक्षण केन्द्र, पुस्तकालय और अध्ययन कक्ष, प्रचारक सेमिनार, नाटक, स्वर्ण जयन्ती समारोह आदि।	
8.	राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा	पाठ्य पुस्तकें, सांस्कृतिक कार्य-क्रम हिन्दी प्रचारकों के लिए सेमिनारों का आयोजन	1,93,055	प्राचार्य आदि के वेतन, पाठ्य पुस्तकें, जोरहाट में हिन्दी प्रचारकों के लिए सेमिनार का आयोजन स्वर्णजयन्ती समारोह आदि	
9.	राष्ट्रभाषा शीघ्रलिपि, कॉलेज, इम्फाल	हिन्दी महाविद्यालयों आदि का संचालन	1,08,900	महाविद्यालय के प्राचार्य, शिक्षकों चपरासियों आदि के वेतन	
10.	मणिपुर राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, इम्फाल	हिन्दी शिक्षण केन्द्र महाविद्यालय आदि	1,35,300	8 महाविद्यालय और 10 विद्यालय	
11.	केरल हिन्दी प्रचार सभा, त्रिवेन्द्रम	केन्द्रीय महाविद्यालय टंकण, और आशुलिपि कक्षाएं पुरस्कार आदि	4,43,100	हिन्दी पुस्तकालय, केन्द्रीय, महा-विद्यालय हिन्दी प्रचारक, शैक्षिक पाठ्यक्रम, पुरस्कार आदि।	
12.	मद्रास, हैदराबाद, बंगलौर, एरनाकुलम, लक्षद्वीप, पांडिचेरी तिरुचिरापल्ली आदि शाखाओं के लिए दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा	निःशुल्क हिन्दी कक्षाएं, महाविद्यालय, बी. एड और स्नातकोत्तर कालेज, संगणक पाठ्यक्रम, प्रचारक विद्यालय, टंकण और आशुलिपि कक्षाएं आदि	38,58,723	निःशुल्क हिन्दी कक्षाएं, पुस्तकालय और वाचनालय, हिन्दी विद्यालय, महाविद्यालय पत्रिकाओं को प्रकाशन एकल शिक्षक विद्यालय पी.जी. काम्पलेक्स बी.एड. कॉलेज संगणक पाठ्यक्रम, शिक्षण पाठ्यक्रम, पुरस्कार आदि	
13.	नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी	हिन्दी पुस्तकालय और पुस्तको का प्रकाशन	7,80,000	निर्माण अनुदान की चौथी किश्त, सूचियों का प्रकाशन, नई हिन्दी पुस्तकों की खरीद आदि	
14.	भुवन वाणी ट्रस्ट, लखनऊ	अन्य भाषाओं से हिन्दी में पुस्तकों का प्रकाशन	9,55,480	ऑफसेट प्रिंटिंग मशीनों की खरीद, वाल्मिकी रामायण, महाभारत आदि का प्रकाशन	
15.	उत्तर पूर्वांचल राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, इटा नगर	राष्ट्रभाषा महाविद्यालय, विद्यालय, छात्रवृतियां आदि	1,82,355	आयोजन के व्यय, राष्ट्रभाषा महाविद्यालय, विद्यालय, छात्रों को छात्रवृत्तियां आदि।	
16.	जोरम हिन्दी प्रचार समिति, एजॉल	राष्ट्रभाषा विद्यालय, पत्रिकाओं का प्रकाशन आदि	1,31,250	हिन्दी के छात्रों का भ्रमण, राष्ट्रभाषा विद्यालयों की देखभाल, पत्रिकाओं का प्रकाशन, छात्रों को छात्रवृत्तियां आदि।	

1	2	3	4	5	6
			रु.		
17.	रूपायन संस्थान, बोसन्दा, जोधपुर	पुस्तकों का प्रकाशन	2,16,000	बातां री फुलवारी का प्रकाशन।	
18.	बच्चों के लिए लेखकों और चित्रकारों की परिषद्, 4 नेहरू हाउस, बी. जेड. मार्ग, नई दिल्ली	पुस्तकों का प्रकाशन	2,40,564	हिन्दी में सचित्र बाल शब्द-कोश का प्रकाशन	
19.	देरातुल मरिफिल उस्मानिया, हैदराबाद	प्रकाशन अनुसंधान	1,57,000	रख-रखाव	
20.	प्राचार्य श्री रंगलक्ष्मी आदर्श संस्कृत महाविद्यालय, वृन्दावन, मथुरा - 281121	शिक्षा	4,05,440 रु.	वेतन/छात्रवृत्तियां/आकस्मिक व्यय/ पुस्तकें, फर्नीचर, वार्षिक उत्सव, पुस्तकों का मुद्रण और मरम्मत	
21.	प्राचार्य जगदीशनारायण ब्रह्मचारी आश्रम संस्कृत महाविद्यालय, लम्मा, वाया-लोहना रोड, रामबदरपुर, जिला-दरभंगा बिहार	- वही -	4,25,398 रु.	वेतन/छात्रवृत्तियां/आकस्मिक व्यय/ फर्नीचर, पुस्तकालय, पुस्तकें इमारतों की मरम्मत	
22.	प्राचार्य भगवानदास संस्कृत महाविद्यालय पो. गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार, महारपुर (उत्तरप्रदेश)	- वही -	4,09,827 रु.	वेतन/छात्रवृत्तियां/आकस्मिक व्यय/ फर्नीचर, यात्रा और भोजन भत्ता/ पुस्तकें/भवनों की मरम्मत और पुस्तक सूचियों का मुद्रण	
23.	प्राचार्य, दीवान कृष्ण किशोर एस. डी. आदर्श संस्कृत कालेज, अम्बाला छावनी	- वही -	3,48,792 रु.	वेतन/छात्रवृत्तियां/प्रोविडेन्ट फंड/ आकस्मिक व्यय/ फर्नीचर/पुस्तकें और टंकण मशीनों की खरीद	
24.	श्री एकरसानन्द संस्कृत महा-विद्यालय मैनपुरी (उत्तर प्रदेश)	- वही -	3,34,552	छात्रवृत्तियां/आकस्मिक व्यय/ फर्नीचर पुस्तकें/भवनों की मरम्मत	
25.	मद्रास संस्कृत कालेज, और एस. एस. वी. पाठशाला, 84 सोयापीठ रोड,मिलापोर, मद्रास	- वही -	4, 32,427 रु.	वेतन/छात्रवृत्तियां/फर्नीचर-आक. व्यय/भवनों की मरम्मत	
26.	मुम्बादेवी संस्कृत महाविद्यालय द्वारा/मुंशी मार्ग, बम्बई - 7	शिक्षण	3,47,636 रु.	वेतन/छात्रवृत्तियां/आक. व्यय/ यात्रा एवं भोजन भत्ता/ पुस्तकालय की पुस्तकें	
27.	हरियाणा संस्कृत विद्यापीठ पो. भगोला, जिला फरीदाबाद हरियाणा	- वही -	4,16,309 रु.	वेतन/छात्रवृत्तियां/आक. व्यय/ भवन मरम्मत/पुस्तकें	
28.	कुप्पुस्वामी शास्त्री अनुसंधान संस्थान, 84, रोयापीठ, हाई रोड, मिलापोर, मद्रास	अनुसंधान	2,40,117 रु०.	वेतन/आक. व्यय/छात्रवृत्तियां/फर्नीचर/ प्रकाशन/भवनों की मरम्मत/ विज्ञापन	

1	2	3	4	5	6
			रु.		
29.	कालीकट आदर्श संस्कृत विद्यापीठ बालुसरैया, जिला कालीकट (केरल)	शिक्षण	4,01,991 रु.	वेतन/आक. व्यय/यात्रा एवं दैनिक भत्ता/छात्रवृत्तिया/पुस्तकें और फर्नीचर	
30.	वैदिक संशोधन मण्डल, तिलक विद्यापीठ नगर, पूना - 9, (महाराष्ट्र)	अनुसंधान	4,15,372 रु.	वेतन/आक. व्यय/और पुस्तकालय की पुस्तकें	
31.	श्री चन्द्रशेखरन्द्र सरस्वती न्याय शास्त्र संस्कृत महाविद्यालय, न. 3 ईस्ट मादा स्ट्रीट, लिटिल कांचीपुरम (तमिलनाडु)	शिक्षण	1,98,611 रु.	वेतन/छात्रवृत्तियां/आक. व्यय/फर्नीचर पुस्तकें और भवनों की मरम्मत	
32.	लक्ष्मीदेवी सर्राफ आदर्श संस्कृत महाविद्यालय काली रेखा गांव/पो. देवगढ (बिहार)	- वही -	3,96,010 रु.	वेतन/छात्रवृत्तियां/आक. व्यय/यात्रा व्यय/फर्नीचर/पुस्तकालय की पुस्तकें	
33.	राजकुमारी गणेश शर्मा, आदर्श संस्कृत पाठशाला, कोलान्ता पतरोरी (बिहार)	- वही -	2,46,033	वेतन/आक. व्यय/छात्रवृत्तियां/पुस्तकालय की पुस्तकें/यात्रा एवं दैनिक भत्ता	
34.	संस्कृत शब्दकोश परियोजना पूना	संस्कृत शब्द कोश का निर्माण	7,36,633 रु.	रख-रखाव अनुदान	
35.	राज वेद काव्य पाठशाला, डी-76/111, क्रास स्ट्रीट श्रीनगर कालोनी, कुम्बाकोनम	शिक्षण	2,16,600 रु.	वेतन/छात्रवृत्तियां	
36.	असम वेद विद्यालय, चत्राकार, गोहाटी - 781 001.	शिक्षण	2,50,080 रु.	वेतन/छात्रवृत्तियां	
37.	शंकर संस्कृत संस्कृति और प्राचीन कला अकादमी, 174/1, डब्ल्यू.ई.ए. करोलबाग, नई दिल्ली	- वही -	3,31,265 रु.	- वही -	
38.	भारतीय चतुर्धान, वेदभवन न्यास स्वदेशी हाउस, सिविल लाइन, कानपुर	- वही -	1,59,600	- वही -	
39.	राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	छात्रवृत्तियां फलोशिप आदि देते हुए विद्वानों और पारम्परिक वैदिक संस्थाओं आदि की सहायता वैदिन अध्ययन की मौखिक परम्परा की उन्नति के लिए	कोरपस फंड के रूप में 50 50 लाख रु. का उपभोग किया जाना है।	राशि बैंक में जमा करवा दी गई है।	

1	2	3	4	5	6.
प्रौढ़ शिक्षा					
आन्ध्र प्रदेश			रु.		
1.	आन्ध्र प्रदेश महिला सभा विश्वविद्यालय मार्ग, हैदराबाद (आ. प्र.) - 500007.	स्वैच्छिक संगठन किसी एक या अन्य निम्नलिखित कार्यकलापों में लगा है : 1) बालवाड़ी/आंगनवाड़ी चला रहा है 2) आई. सी. डी. एस. केन्द्र चला रहा है 3) बच्चों के कार्यों की जांच 4) माताओं को शिक्षा प्रदान करना 5) स्कूल चला रहा है 6) कालेज चला रहा है 7) तकनीकी संस्थाएं चला रहा है 8) टाईपिंग संस्थाएं चला रहा है 9) महिलाओं के लिए सिलाई पाठ्यक्रम चला रहा है 10) राष्ट्रीय दिवसों को मना रहा है 11) नेत्र शिविर आयोजित कर रहा है 12) रक्त दान शिविर आयोजित कर रहा है	14,40,000	450 प्रौ. शि. के	
2.	भागवतुल्ला चेरिटेबल न्यास येल्लामेनचिल्ली, विशाखपत्तनम, जिला (आ. प्र.) - 531055	- वही -	10,00,000	ग्रामीण एनिमेटर्स के लिए प्रशिक्षण	
3.	पददलित और सामुदायिक विकास सोसायटी, 11/96 सुमिर्था नगर, बेडवेल-516227 चुड्डापेह जिला		10,50,000	330 प्रौ. शि. के.	
4.	ग्राम नव निर्माण समिति हजूराबाद, करीमगर - 505468	- वही -	3,20,000	100	
5.	प्राच्य भाषा विद्यापीठ, राजेन्द्र नगर, गुडिवाड़ा, जिला कृष्ण - 521301	- वही -	1,20,000	60	
6.	सरदार युवक संघ रंगासमुंद्रम, बेडवेल-तह, चुड्डापेह जिला आ. प्र. 516193	- वही -	1,20,000	60	
7.	सेवा मन्दिर, हिन्दुपुर ताल्लुक अनन्तपुर जिला - 515212	- वही -	6,00,000,	300 प्रौ. शि. के	
8.	श्री वीरब्राह्मण शैक्षिक सोसायटी गोनतला - 515231 अनन्तपुर जिला आन्ध्रप्रदेश	- वही -	1,20,000	60 प्रौ. शि. के.	

1	2	3	4	5	6
असम					
9.	बेनुग्राम महिला समिति पो. ओ. नीलामजार दक्षिण खण्ड करीम गंज विकास खण्ड, जिला-करीम गंज, असम - 788720	- वही -	रु. 1,80,000	60 प्रौ. शि. के.	
10.	जनजाति समाज कल्याण आश्रम बारूआखाथ - पो. आ. बर्मा खण्ड बास्का देव जिला नलबारी असम पिन - 781346	- वही -	3,20,000	100 प्रौ. शि. के.	
11.	उदाली रहमानिया मदरसा समिति, पो. आ. उदाली बाजार (द्वारा लंका पो. आ.) नवगांव, असम - 782446.	- वही -	3,20,000	100 प्रौ. शि. के.	
बिहार					
12.	भगवान पुस्तकालय नया बाजार भागलपुर सिटी, बिहार	- वही -	3,20,000	100 प्रौ. शि. के.	
13.	भारतीय कला मंदिर डाकखाना दलतोनगंज जिला पालामु, बिहार	- वही -	1,80,000	60 प्रौ. शि. के.	
14.	प्राकृतिक आरोग्य आश्रम पो. आ. राजगीर जिला नालन्दा, बिहार	- वही -	3,20,000	100 प्रौ. शि. के.	
गुजरात					
15.	आदर्श केलवाणी मण्डल समाधिला मुलानी ता. पालीताना, जिला भावनगर - 364001	- वही -	3,14,365	100 प्रौ. शि. के.	
16.	आनन्द ताल्लुका युवक मण्डल संघ, लक्ष्मी निवास, 25, अजन्था सोसायटी आनन्द, जिला केहड़ा - 388001	- वही -	4,00,000	200 प्रौ. शि. के.	
17.	भानसाली ट्रस्ट हाईवे, राधनपुर पिन- 385346 जिला बानसकन्था, गुजरात	- वही -	1,20,000	60 प्रौ. शि. के.	
18.	भावनगर महिला संघ पनवाड़ी चौक भावनगर, गुजरात - 364001	- वही -	1,20,000	60 प्रौ. शि. के.	
19.	भारूच जिला काईवल केलवाणी मण्डल, नवा राजवाड़ा, त. नानदेड, जिला भारूच, गुजरात - 312001	- वही -	1,80,000	60 प्रौ. शि. के.	

1	2	3	4	5	6
20.	भील सेवा मण्डल दाहोद जिला पंचमहल - 389151 गुजरात	- वही -	5,82,164	300 प्रौ. शि. के.	
21.	गांधी नगर शिक्षा सोसायटी सेक्टर - 23, विराट नगर गांधी नगर - 382023	- वही -	1,20,000	60 प्रौ. शि. के.	
22.	गायत्री शिक्षण वनथाली, द्वारा ए/44 जनकपुरी सोसायटी दुन्दुसार रोड जूनागढ़ - 362001	- वही -	2,00,000	100 प्रौ. शि. के.	
23.	ग्राम सेवा समाज वनकल, ता. मंगरोल जिला सूरत - 395003 गुजरात	- वही -	2,00,000	100 प्रौ. शि. के.	
24.	गुजरात स्टेट क्राईम प्रिवेन्शन ट्रस्ट, 2, जोशी बाग अपार्टमेन्टस, सैन्ट एवियर स्कूल रोड, अहमदाबाद - 380 001	- वही -	9,60,000	300 प्रौ. शि. के.	
25.	गुजरात विद्यापीठ आश्रम रोड अहमदाबाद - 380 001. गुजरात	- वही -	10,58,000	300 प्रौ. शि. के.	
26.	सामुदायिक शिक्षा भारतीय सोसायटी, गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद - 380 001	- वही -	2,00,000	100 प्रौ. शि. के.	
27.	कामक्षीबाई देसाई समाज शिक्षण भवन ट्रस्ट संग्रहालय चौक के सामने सूरत - 395003	- वही -	2,00,000	100 प्रौ. शि. के.	
28.	कपड़वांज केलवाणी मण्डल दाकोर रोड कपड़वांज, जिला खेड़ा - 387620	- वही -	1,20,000	60 प्रौ. शि. के.	
29.	निर्माण रैना बंगलो, कागड़ीवाड एलिस ब्रिज, अहमदाबाद - 382006	- वही -	1,20,000	100 प्रौ. शि. के.	
30.	नूतन भारती पो. आ. मदनगढ़ ता. पालनपुर जिला बानसकन्था पिन - 385519	- वही -	3,20,000	100 प्रौ. शि. के.	

1	2	3	4	5	6
			रु.		
31.	श्री शिक्षण साधना केलवाणी ट्रस्ट, ता. जलिसाना जिला अहमदाबाद - 302010	- वही -	1,20,000	100 प्रौ. शि. के.	
32.	सर्वेन्ट आफ पिपुल्स सोसायटी (लोक सेवक मण्डल) 1225 देवनी शेरी, मेदविनिपोली, अहमदाबाद - 380 001.	- वही -	3,80,000	130 प्रौ. शि. के.	
33.	श्री पंचमहल केलवाणी मण्डल, डा. पो. आ. केलोल, जिला पंचमहल - 389 001	- वही -	2,00,000	100 प्रौ. शि. के.	
34.	बड़ौदरा जिला पंचायत मार्ग सेवा मण्डल, सरदार भवन, राधोपुर रोड, बड़ौदा - 390 002	- वही -	8,00,000	400 प्रौ. शि. के.	
	हरियाणा				
35.	जनता कल्याण समिति रिवाड़ी, जिला मोहिन्द्रगढ़, हरियाणा - 123 401	- वही -	9,60,000	300 प्रौ. शि. के.	
36.	पी. एच. डी. ग्रामीण विकास प्रतिष्ठान, पी. एच. डी. भवन, एशियन खेल गांव के पीछे नई दिल्ली।	- वही -	3,80,000	300 प्रौ. शि. के.	
37.	शिक्षा समिति डी.ए.वी. प्रशिक्षण कालेज सोनीपत शिवनगर, सोनीपत-पिन-131001	–वही–	3,20,000	100 प्रौ. शि. के.	
38.	विद्या महा सभा कन्या गुरुकुल, महाविद्यालय खारखोड़ा (सोनीपत) हरियाणा	–वही–	6,00,000	300 प्रौ. शि. के.	
39.	गुडिबन्धा ग्रामोदय संघ गुडिबन्धा-561209 जिला कोलार कर्नाटक	–वही–	9,60,000	300 प्रौ. शि. के.	
40.	कर्नाटक युवक कल्याण प्रतिष्ठान कनकपुरा, मेन रोड, बंगलोर-560078	–वही–	2,00,000	100 प्रौ. शि. के.	
41.	कस्तूरबा महिला सेवा समाज, धालाकेरन, जिला चित्रदुर्गा, कर्नाटक-577522	–वही–	1,20,000	60 प्रौ. शि. के.	

1	2	3	4	5	6
			रु.		
42.	कस्तूरबा सदन विजयपुर जिला चिकमंगलूर-577101 कर्नाटक	–वही–	2,00,000	100 प्रौ. शि. के.	
43.	मधुगिरी शिक्षा सोसायटी, मधुगिरी-572132 तूमकूर जिला कर्नाटक	–वही–	1,20,000	60 प्रौ. शि. के.	
44.	मलथेसा शिक्षा सोसायटी नं० 78/24 8वां क्रास, मेगादी रोड शंकरप्पा गार्डन्स बंगलौर-560023	–वही–	1,80,000	90 प्रौ. शि. के.	
45.	नवथरंगा शैक्षिक सोसायटी 131, विद्या रानया नगर बंगलौर-560023.	–वही–	2,40,000	120 प्रौ. शि. के.	
46.	नेताजी शिक्षा सोसायटी विनोवा नगर शिमोगा 577201	–वही–	1,20,000	60 प्रौ. शि. के.	
47.	नालन्दा शिक्षा समिति सं० 1181 रघवेन्द्रा ब्लाक श्रीनगर, बंगलौर-560050	–वही–	1,80,000	90 प्रौ. शि. के.	
48.	सिन्डिकेट कृषि प्रतिष्ठान, मनीपाल, पिन-576119 उदीपी ता. दक्षिण कन्नाद, जिला (कर्नाटक)	–वही–	9,60,000	90 प्रौ. शि. के.	
49.	श्री सामान्य विद्या केन्द्र नं.-87 पद्मसाधना गांधी बाजार, बंगलौर-560004	–वही–	1,80,000	60 प्रौ. शि. के.	
50.	श्री वर्ष सिधी विनायक मंडली एन.ई.ए. एक्सटेन्शन डी.नं. 2495, मगदी टाऊन 562120, बंगलौर	–वही–	2,40,000	120 प्रौ. शि. के.	
51.	सर्वोदय विद्यापीठ सं. 15, मलिकार्जुन मंदिर गली, बेसावानागुड़ी बंगलौर-560004	–वही–	2,00,000	100 प्रौ. शि. के.	
52.	श्री शारदा विद्यालय तिपापेठ, गुलेडगुड्डा ता. बादामी, जिला- बीजापुर-587203	–वही–	1,20,000	60 के. शि. के.	
केरल					
53.	कस्तूरबा गाँधी राष्ट्रीय स्मारक	–वही–	3,20,000	100	

1	2	3	4	5	6
	नेडूपूझा, पो.आ. त्रिचुर, पिन-680015 केरल		रु.	प्रौ. शि. के.	
54.	मित्र निकेतन मित्र निकेतन, पो. ओ. वेल्लानद 695543 त्रिवेन्द्रम-जिला (केरल)	–वही–	3,20,000	100 प्रौ. शि. के.	
55.	विनोबा निकेतन पो. ओ. विनोबा निकेतन जिला-त्रिवेन्द्रम केरल-695542	–वही–	2,00,000	100 प्रौ. शि. के.	
	मध्य प्रदेश				
56.	भारतीय ग्रामीण महिला संघ (एम.पी. शाखा) 146, प्रीकोन्सी कालोनी अन्नपूर्णा रोड, इन्दौर	–वही–	19,20,000	60 प्रौ. शि. के.	
57.	अमर बिहू क्रीडा मण्डल शोलापुर	–वही–	1,20,2000	60 प्रौ. शि. के.	
58.	ग्राम विकास सेवा मण्डल पो.ओ. मुल, पिन-441224 जिला-चन्द्रपुर, महाराष्ट्र	–वही–	1,20,000	60 प्रौ. शि. के.	
59.	सेनापति तॉत्या टोपे शिक्षण प्रसारक मण्डल, येओला, जिला नासिक	–वही–	1,20,000	60 प्रौ. शि. के.	
60.	एन.एफ.ई. के लिए राज्य संसाधन केन्द्र 128/2 जे.पी. नायक रोड कोट रोड, पुणे-411029	–वही–	1,78,000	ग्रामीण युवा एनिमेटर्स का प्रशिक्षण	
मणिपुर					
61.	एकीकृत ग्रामीण विकास सोसाइटी लिम लोंग, पो. ओ. इम्फाल-795130	–वही–	1,20,000	60 प्रौ. शि. के.	
62.	मणिपुर प्रौढ़ शिक्षा संघ, याखालिकाई, इम्फाल, मणिपुर।	–वही–	2,00,000	100 प्रौ. शि. के.	
63.	ग्रामीण विकास सोसायटी, वंगजिंग बाजार, वेगजिंग, पो.आ. मणिपुर-755140	–वही–	1,20,000	60 प्रौ. शि. के.	
64.	मणिपुर व्यावसायिक संस्थान मु.का. मकोला बाजार, बी.पी. ओ. लाईफ्राकोम, द्वारा तुलिहाल, एस.ओ.	–वही–	1,20,000	60 प्रौ. शि. के.	

1	2	3	4	5	6
	इम्फाल पश्चिमी-11, इम्फाल जिला मणिपुर-795140		रु.		
उड़ीसा					
65.	सांस्कृतिक विकास और सांस्कृतिक संबंध परिषद्, मैत्री, सरानी	–वही–	1,80,000	60 प्रौ. शि. के.	
66.	देनगाबोरी महिला समिति ए. ए. देनगाबोरी, ओडापाड़ा ब्लाक, धनाकनाल तालुक जिला धनाकनाल, पो. आ. इन्दिपुर	–वही–	1,80,000	60 प्रौ. शि. के.	
67.	ग्राम मंगल पेथागढ़ डा.पो.आ. सेलापानी गांव तालुक जारासिगा, खंड देओगांव जिला बालानगीर, उड़ीसा-767067	–वही–	9,60,000	300 प्रौ. शि. के.	
68.	भारतीय ग्रामीण पुनर्निर्माण एवं संकट अनुक्रिया सेवा कालेज रोड, गांधी नगर-1 डा.पो.आ. रायगढ़, कोरापुट, जिला-765001	–वही–	1,20,000	60 प्रौ. शि. के.	
69.	एन.वाई.एस.सी.पी. (सामुदायिक कार्रवाई कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय युवा संसद) पो.आ. मोट्टा खंड, कामाख्या. नगर, जिला धनकनाल, उड़ीसा-759018	–वही–	1,80,000	60 प्रौ. शि. के.	
70.	दी डिवाइन लाईफ सोसायटी भानजा नगर, ब्रांच पो.आ. भानजा नगर ब्लाक– भानजा नगर ताल्लुक गुनिसर, जिला गंजम पिन 721026	–वही–	1,80,000	60 प्रौ. शि. के.	
71.	अजमेर प्रौढ़ शिक्षा संघ, विद्युत मार्ग, ई.पी.आई. शास्त्री नगर, एक्सटेंक्शन, अजमेर-305001	–वही–	6,00,000	300 प्रौ. शि. के.	
72.	बीकानेर प्रौढ़ शिक्षा संघ, प्रौढ़ शिक्षा भवन, सरस्वती पार्क, पो. बाक्स नं. 28, बीकानेर-334001	–वही–	6,00,000	300 प्रौ. शि. के.	
73.	गांधी विद्या मंदिर सरदार सहार, चुरू-331001	–वही–	1,20,000	60 प्रौ. शि. के.	
74.	इंदिरा शिक्षा समिति वज़ीरपुर, स्टेशन रोड, गंगापुर सिटी-322201	–वही–	1,80,000	60 प्रौ. शि. के.	
75.	जोधपुर प्रौढ़ शिक्षण समिति, गांधी भवन, रेसीडिएन्सी रोड, जोधपुर-342001	–वही–	12,49,793	400 प्रौ. शि. के.	
76.	लोक शिक्षण संस्थान, पी.-87, गंगोरी बाजार, जिला जयपुर	–वही–	3,20,000	100 प्रौ. शि. के.	

1	2	3	4	5	6
			रु.		
77.	लोक भारती, देओगढ़, मेदारिया-313 001, राजस्थान	–वही–	1,20,000	60 प्रौ. शि. के.	
78.	महिला लोक जागृति समिति, जवाहर नगर, जयपुर-302004	–वही–	1,20,000	60 प्रौ. शि. के.	
79.	सेवा मंदिर, उदयपुर-313001, राजस्थान	–वही–	9,60,000	300 प्रौ. शि. के.	
80.	जिला महिला जागृति परिषद्, स्टेशन रोड, बाड़मेर-344001	–वही–	1,20,000	60 प्रौ. शि. के.	
तमिलनाडु					
81.	क्रिस्टियन शैक्षिक विकास सोसायटी, 118, नेपालय स्ट्रीट, विल्लू पुरम–605020 एस. ए. जिला (त.ना.)	–वही–	5,20,000	200 प्रौ. शि. के.	
82.	कांग्रिगेशन आफ दी सिस्टरस आफ दी क्रास आफ छावानोद होली क्रास कान्वेन्ट, कन्टोनमेन्ट, तिरूचि-620001	–वही–	5,20,000	200 प्रौ. शि. के.	
83.	डा. ऐनी बेसेन्ट, महालीर मन्दरम्, 64, मंगलम, ए.ई. कोईल स्ट्रीट, न्यू वाशरमेनगेट-600081	–वही–	1,79,785	60 प्रौ. शि. के.	
84.	गांधी निकेतन आश्रम, मदुरै जिला, टी. कालुपेथ्थी-626702	–वही–	1,80,000	60 प्रौ. शि. के	
85	जी.आर.डी. न्यास कलाईकाथिर, बिल्डिग्स, अवनाशी रोड, कोयम्बटूर-641037 (त. ना.)	–वही–	4,00,000	200 प्रौ. शि. के.	
86.	कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक न्यास, कस्तूरबा ग्राम, पो.आ. एरोडो-638803 तमिलनाडु	–वही–	1,80,000	60 प्रौ. शि. के.	
87.	केन्डास्वामी केन्द्र न्यास बोर्ड, वेलूर, सेलम-638182	–वही–	3,20,000	100 प्रौ. शि. के.	
88.	कालवी उलागम शैक्षिक सोसायटी, लाटूटारी-632202 (तमिलनाडु)	–वही–	2,00,000	100 प्रौ. शि. के.	
89.	खाजमालाई महिला संघ तिरूचरापल्ली-620023, तमिलनाडु	–वही–	3,20,000	100 प्रौ. शि. के.	
90.	कुन्ड्राकुडी थिरूवेन्नामलाई अधीनम न्यास, जिला पासूमपोन, मुथूरमलाईगम, कुन्ड्राकुड-623206 (तमिलनाडु)	–वही–	1,20,000	60 प्रौ. शि. के.	
91.	मधारनाला मन्द्रम बी. वन्दिपलायम, पो.आ., कुड्डालूर-607004 (त. ना.)	–वही–	4,00,000	200 प्रौ. शि. के.	
92.	उमालूर ग्रामीण सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक अकादमी पेरामायूर, पो.आ. मूथूनाईचोमपेथी-636304 उमालूर तालुक, सेलम जिला (त.ना.)	–वही–	2,00,000	100 प्रौ. शि. के.	

1	2	3	4	5	6
			रु.		
93.	पंजाब संघ, न. 170 से 172 पीटर्स रोड, रोयापोथ्या मद्रास-600014	–वही–	9,60,000	300 प्रौ. शि. के.	
94.	तमिलनाडु बेसिक शिक्षा सोसायटी, टी. काल्लूपेथ्थी-626702 मदुरै जिला-तमिलनाडु	–वही–	1,80,000	60 प्रौ. शि. के.	
95.	तमिलनाडु सतत शिक्षा बोर्ड न.-1, वेकटारथम नगर, ऐक्सटेक्शन, अदयार मद्रास-600020	–वही–	4,50,000	200 प्रौ. शि. के.	
96.	तमिलनाडु ग्रामीण विकास बोर्ड 13 राधा कृष्णन स्ट्रीट टी. नगर, मद्रास-600017	–वही–	3,19,973	100 प्रौ. शि. के.	
97.	वैलूर सामाजिक विकास संगठन, नं. 5-इण्डियन होम, 10वां पूर्वी, मेन रोड, गांधी नगर, वैलूर-622006 (त. ना.)	–वही–	1,20,000	60 प्रौ. शि. के.	
98.	भारतीय महिला संघ 43 ग्रीनवेज़ रोड, मद्रास-600028 तमिलनाडु	–वही–	3,79,579	130 प्रौ. शि. के.	
99.	तमिलनाडु की महिला स्वैच्छिक सेवा, 19, ईस्ट स्पर टैंक रोड, चेटपेट, मद्रास, तमिलनाडु-600031	–वही–	7,11,171	300 प्रौ. शि. के.	
100.	युवा संघ मुथुरामलिंगापुरम, डाक अरूपुकेतई, तालुक सामानाथापुरम, जिला-626105	–वही–	3,17,333	100 प्रौ. शि. के.	
उत्तर प्रदेश					
101.	आदर्श सेवा समिति, 326/1 साकेत कालोनी, गली नं. 6, मुजफ्फर नगर	–वही–	3,20,000	100 प्रौ. शि. के.	
102.	अखिल भारतीय निर्बल विकास संस्थान, तिरवागंज जिला, फारूक्काबाद (उ.प्र.)	–वही–	1,20,000	60 प्रौ. शि. के.	
103.	भगवान काली गृह शिल्प केन्द्र, जे-12/78, ए, नाती इमली, डाक खाना वाराणसी केन्ट, वाराणसी (उ.प्र.)	–वही–	1,20,000	60 प्रौ. शि. के.	
104.	भारतीय आजीवन शिक्षा परिषद् 646/647 कटरा, इलाहाबाद (उ.प्र.)	–वही–	2,00,000	100 प्रौ. शि. के.	
105.	डा. अम्बेडकर समाज सेवा मंडल, ग्राम वेस्की, डाक खाना सयेदाबाद, जिला इलाहाबाद	–वही–	3,00,000	120 प्रौ. शि. के.	
106.	ग्राम विकास सेवा संस्थान जगदीशपुर, जिला सुल्तानपुर (उ.प्र.)	–वही–	1,20,000	60 प्रौ. शि. के.	
107.	ग्राम सेवा निकेतन, 295/23, अशरफाबाद, लखनऊ-3 (उ.प्र.)	–वही–	1,20,000	60 प्रौ. शि. के.	
108.	ग्रामोदय विकास मंडल, सूरजकुंड, रामबाग, मेरठ (उ.प्र.)	–वही–	1,20,000	60 प्रौ. शि. के.	
109.	हरिजन एवं आदिवासी विकास सेवा समिति, पो.ओ. कराऊं, जिला इलाहाबाद (उ.प्र.)	–वही–	1,20,000	60 प्रौ. शि. के.	

1	2	3	4	5	6
			रु.		
110.	भारतीय साक्षरता बोर्ड, साक्षरता भवन, पो.ओ. आलम बाग, लखनऊ (उ.प्र.)	–वही–	39,05,000	120 प्रौ. शि. के.	
111.	जन कल्याण शिक्षा समिति, पावा नगर, फाजिल नगर, जिला दिओरिया (उ.प्र.)	–वही–	1,20,000	60 प्रौ. शि. के.	
112.	मायाना ग्रामोद्योग सेवा समिति, मायाना मुरारी नगर, डी.टी. रोड, खुरजा, जिला बुलंदशहर (उ.प्र.)	–वही–	3,20,000	100 प्रौ. शि. के.	
113.	महिला उद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, सालिक गंज रोड, मुट्ठी गंज, इलाहाबाद (उ.प्र.)	–वही–	1,20,000	60 प्रौ. शि. के.	
114.	निशात शिक्षा समिति अस्ताना नई बस्ती, हल्द्वानी, नैनीताल (उ.प्र.)	–वही–	3,20,000	100 प्रौ. शि. के.	
115.	नेहरू बाल मंडल प्रयाग, 23-बी., इलाहाबाद जिला, इलाहाबाद (उ.प्र.)	–वही–	2,60,000	130 प्रौ. शि. के.	
116.	राजा चेत सिंह, शिक्षा संस्थान, जे.-12/78, ए.-नाती इमली, पो.ओ. वाराणसी (कैन्ट) जिला वारणसी (उ.प्र.)	–वही–	1,20,000	60 प्रौ. शि. के.	
117.	सरस्वती पुस्तकालय एवं वाचनालय तथा खेल कूद संस्थान, (बारवारीपुर) खादीपुर-228145, जिला सुल्तानपुर (उ.प्र.)	–वही–	24,00,000	750 प्रौ. शि. के.	
118.	सर्वोदय शिक्षा सदन, लोकमान पुर, पो.आ. बड़ौत जिला इलाहाबाद (उ.प्र.)	–वही–	1,20,000	60	
119.	उ.प्र. राणा बेनी, माधव जन कल्याण, समिति गुलाब रोड़, रायबरेली (उ.प्र.)	–वही–	2,20,000	100 प्रौ. शि. के.	
120.	विनोबा सेवा आश्रम, पो. आ. रोजा जक्शन जिला शाहजहांपुर, (उ.प्र.)	–वही–	1,20,000	60 प्रौ. शि. के.	
	पश्चिम बंगाल				
121.	बंगाल समाज सेवा लीग, 1/6, राजा दिनानदारा स्ट्रीट, कलकत्ता (प. बंगाल)	–वही–	3,80,000	100 प्रौ. शि. के.	
122.	कलकत्ता शहरी कान्सोर्टियम सेवा, 16, सदर स्ट्रीट, कलकत्ता (प. बंगाल)	–वही–	4,00,000	200 प्रौ. शि. के.	
123.	लोक शिक्षा परिषद, रामा कृष्णन मिशन आश्रम, पो.ओ. नरेन्द्रपुर, जिला 24 परगना, कलकत्ता (प. बंगाल)	–वही–	2,00,000	100 प्रौ. शि. के.	
124.	रामा कृष्ण मिशन, जन शिक्षा मंदिरा, पो.ओ. बेलूर मठ, जिला हावड़ा-711202, (प. बंगाल)	–वही–	3,20,000	100 प्रौ. शि. के.	

1	2	3	4	5	6
			रु.		
125.	श्री रामाकृष्णा सत्यानंद आश्रम, ग्राम जिराबपुर, पो.ओ. बसीरत, जिला 24 परगनास्, कलकत्ता (प. बंगाल)	–वही–	6,00,000	300 प्रौ. शि. के.	
126.	बाल स्वास्थ्य संस्थान, 11 डा. बिरेश, गुहा स्ट्रीट, कलकत्ता (प. बंगाल)	–वही–	2,50,000	100 प्रौ. शि. केन्द्रों सहित अनुसंधान कार्रवाई परियोजना	
	दिल्ली				
127.	भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, डा. अम्बेडकर मार्ग, नई दिल्ली 110055	–वही–	9,60,000	300 प्रौ. शि. के.	
128.	विकास न्याय और शांति, दिल्ली केथोलिक आर्चडाओसीस चेतनालय, अशोक प्लेस, नई दिल्ली 110001	–वही–	1,20,000	60 प्रौ. शि. के.	
129.	डा. एस.वी. बालिगा, स्मारिका न्यास, लिंक हाउस, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली	–वही–	9,60,000	300 प्रौ. शि. के.	
130.	गांधी स्मारक हरिजन शिक्षा समिति, 170, बाल्मिकी कालोनी, मंदिर मार्ग, नई दिल्ली 110001	–वही–	3,20,000	100 प्रौ. शि. के.	
131.	महिला चेतना केन्द्र, एफ-26, बी.के. दत्त कालोनी, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003	–वही–	3,20,000	100 प्रौ. शि. के.	
132.	रवि भारती शिक्षा समिति, भोला नाथ नगर, शाहदरा, नई दिल्ली-110032	–वही–	3,20,000	100 प्रौ. शि. के.	
			(रु. लाखों में)		
133.	"दिपायात्तन" प्रौढ़ शिक्षा के लिए बिहार राज्य संसाधन केन्द्र, बुद्धा कालोनी, पटना।	प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के लिए शैक्षिक तथा तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए	33.06	शिक्षण/अध्ययन सामग्रियों के उत्पादन के लिए और प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र के अधिकारियो के लिए प्रशिक्षण	
134.	रजिस्ट्रार, गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद	–वही–	20.76	–वही–	
135.	कर्नाटक राज्य प्रौढ़ शिक्षा परिषद, कुवेमपु नगर, मैसूर।	–वही–	22.78	–वही–	
136.	"कनफेड" शाक्शारथा भवन, त्रिवेन्द्रम (केरल)	–वही–	7.78	–वही–	
137.	निदेशक, भारतीय शिक्षा संस्थान, 128/2, जे.पी. नेक रोड, कौथरूड, पूना	–वही–	27.78	–वही–	
138.	राजस्थान प्रौढ़ शिक्षा परिषद, सी-85, रामदास मार्ग, तिलक नगर, जयपुर।	–वही–	22.78	–वही–	

1	2	3	4	5	6
				रु.	
139.	तमिल नाडु सतत् शिक्षा बोर्ड, पश्चिम सी.टी. नगर (मद्रास)		–वही–	21.50	–वही–
140.	निदेशक, एस.आर.सी. पश्चिम बंगाल, 1/6, राजा दिवेन्द्र स्ट्रीट, कलकत्ता		–वही–	22.78	–वही–
141.	निदेशक, एस.आर.सी. जामिया मीलिया इस्लामिया, जामिया नगर, नई दिल्ली-25		–वही–	9.50	–वही–
142.	अध्यक्ष, भारतीय ग्रामीण महिला संघ, इन्दौर (म. प्र.)		–वही–	16.20	–वही–
143.	साक्षरता भवन, पो.आ. आलमबाग, कानपुर रोड, लखनऊ (उ.प्र.)		–वही–	42.20	–वही– (योजनेत्तर)

CONTENTS

1.	Introductory	1
2.	Overview	3
3.	Administration	6
4.	Elementary Education	9
5.	Secondary Education	13
6.	Higher Education and Research	36
7.	Technical Education	52
8.	Adult Education	67
9.	Education in Union Territories	74
10.	Scholarships	80
11.	Book Promotion and Copyrights	84
12.	Promotion of Languages	88
13.	Border Area Development Programme	95
14.	Twenty Point Programme, 1986 and Access to Education for the Disadvantaged	96
15.	Management, Monitoring and Evaluation	98
16.	International Cooperation	104
17.	Highlights Since 1985-86	110
	Financial Allocations	117
	Names of Private and Voluntary Organisations which received Recurring Grant-in-aid of Rs. 1 lakh and more during 1987-88.	
	Administrative Chart	149

Introductory

1.1.0 One of the basic strategies of development under the 7th Five Year Plan has been Human Resource Development. National Policy on Education, 1986 has concluded by saying :

> "The main task is to strengthen the base of the pyramid, which might come close to a billion people at the turn of the century. Equally, it is important to ensure that those at the top of the pyramid are among the best in the world. Our cultural well-springs had taken good care of both ends in the past; the skew set in with foreign domination and influence. It should now be possible to further intensify the nation-wide effort in Human Resource Development, with Education playing its multi-faceted role."

1.2.0 The United Nations Children's Fund (UNICEF), in its report on the state of the world children in 1989, has come to the findings that in several developing countries of the world, investments on Human Resource has drastically come down; that spending per head on Education has fallen by nearly 50% due to cut backs on public expenditure; that State intervention in support of Human Resource Development programmes should be placed high on the agenda and that a real development pact, "a new Marshall Plan", should be brought under implementation under which advanced nations would significantly enhance access to real resources for the developing countries, these countries, on their part, committing themselves for a re-orientation of their investment strategies towards the pattern of real development which unequivocally puts the poor first.

1.3.0 Human Resource Development calls for coordinated and all-round efforts for the development of human potential in the areas of Education, the youth, women and children, Arts, Culture and Sports.

1.4.0 Presented, in the following five parts of the report, is a picture of the performance of the Ministry of Human Resource Development on various fronts :

Part I	—	**Department of Education**
Part II	—	**Department of Culture**
Part III	—	**Department of Arts**
Part IV	—	**Department of Women and Child Development**
Part V	—	**Department of Youth Affairs & Sports**

1.5.1 In implementing the various programmes under the National Policy on Education, 1986, keeping the Human Resource Development concerns in view, the following areas were given special attention -

* Universalisation of Elementary Education;
* Adult literacy including for skill development and inculcation of values;
* Access to education for the disadvantaged sections - Scheduled Castes, Scheduled Tribes, educationally backward, minorities and women;
* Improvements in content and process of education.

1.5.2 Three important strategies followed in giving special attention to the above areas were provision of access to education outside the formal system (either through Non-Formal Education Centres or through Distance Education); use of the existing education infrastructure for the benefit of the rural poor-for manpower development, transfer of technologies etc. like under the scheme of Community Polytechnics and mass mobilisation for educational efforts (for adult literacy - for example, by utilising the services of College students, NCC cadets, NSS volunteers, ex-

servicemen etc.).

1.6.0 The Department of Culture continued its efforts for the preservation, promotion and enrichment of the cultural traditions of the country - through its infrastructure of Zonal Cultural Centres and supportive institutions. Conclusion of festivals of USSR and France in India, commencement of the Festival of India in Japan and APNA UTSAV in Bombay have been the highlights of the current year in the area of cultural dissemination abroad and at home. Cultural Exchange programmes with 56 countries and agreements with 75 countries are under implementation too, bringing the peoples of various countries of the world closer to the people of India.

1.7.0 The Department of Arts has nearly completed its task of setting up the infrastructural facilities for the Indira Gandhi National Centre for Arts (IGNCA). The five principal divisions of the IGNCA, Kala Nidhi, Kala Kosa, Janapada Sampada, Kala Darsana and Sutradhara facilitated the nucleation of the various academic programmes of the Centre. The principal activities envisaged under the Centre are :

- Creation of a computerised National Information System and Data Bank on Arts, Humanities and Cultural Heritage with supportive facilities, library, archives, etc.
- Fundamental research through programmes for production of lexicons on arts and crafts, texts of Indian Arts, reprints of writings, multi-volume encyclopaedia of Indian Arts etc.
- Documentation of folk and tribal arts and crafts; and
- Conduct of inter-disciplinary seminars.

1.8.0 A National Perspective Plan (NPP) - 1988-2000 A.D. has been finalised as a base for future strategies - so as to bring about major thrusts in the programme for women's development, particularly to raise the social and economic status of women. The Department of Women and Child Development continued its priority concentration in rendering early childhood services. The Integrated Child Development Services (ICDS) was expanded to cover nearly 2000 projects during the year - for the benefit of children in the age group of 0-6 and expectant and nursing mothers.

1.9.0 A National Policy on Youth (NPY) was placed before the Parliament in November, 1988 after extensive nation-wide consultations. The Policy envisages creation of opportunities for the development of the personality and functional capability of the youth of the country. Massive national integration camps held in different parts of the country have kept the value of national integration foremost in the minds of the youth. The Nehru Yuvak Kendra Sangathan has come to diversify its activities. The Sports Authority of India (SAI) is focussing on the training of sports-persons for Asian Games scheduled to be held at Beijing in 1990. Adventure programmes like participation in International Ski expendition to the South Pole, Talent Search by the Sports Authority of India, provision of infrastructure facilities for sports activities, initiation of the Sports Project Development Area (SPDA) scheme have been the other highlights of the activities of the Department of Youth Affairs and Sports. The Government of India have also sought to involve itself in greater measure with sports by introducing, in the Rajya Sabha, the Constitution (Sixty first) Amendment Bill, 1988, seeking transfer of "sports" from the State List to the Concurrent List in the Constitution of India.

Overview

Allocation of funds & their use

2.1.0 During the year 1987-88 the total budget allocation given for the Department of Education was Rs. 1,211 crores (Rs. 800 crores under Plan, Rs. 386 crores under Non-Plan and Rs. 25 crores under the Border Area Development Education Programme (BADEP). The entire allocation was spent. All the Plan programmes were formulated and implemented on a project oriented basis, securing the full cooperation of the States and Union Territories. Significant progress was achieved under all schemes implemented with reference to NPE, 1986 — important amongst these are Operation Blackboard, Non-Formal Education, restructuring and re-organisation of Teacher Education, Vocationalisation of education, Navodaya Vidyalayas, Education Technology, Science teaching in schools, Adult Education, Distance Education and modernisation and removal of obsolescence in Technical Education.

2.2.0 Allocation of funds for the year 1988-89 was Rs. 1595 crores (Rs. 800 crores under Plan, Rs. 45 crores under Border Area Development Programme and Rs. 750 crores under Non-Plan).

2.3.0 In ensuring effective implementation of the various programmes, special care was taken in regard to the following :

* According of sanctions through State level empowered Committees consisting of senior officers of the State Governments and Central Government. (This facilitated elimination of avoidable correspondence, promptitude in decisions and careful examination of proposals).
* Repeated mid-term consultations with State Education Secretaries and Directors at national level conferences;
* Reviews and consultations, mid-term, in the meetings of Central Advisory Board of Education and its Committees.

Elementary Education

2.4.1 Consistent with the perspective and strategies envisaged in the 7th Plan and with NPE 1986, special emphasis was laid on Elementary Education. The allocation of Rs. 233.40 crores for Elementary Education for the current year accounts for 29% of the total Plan allocation of Rs. 800 crores. During 1987-88, the following were the achievements in the drive towards the universalisation of Elementary Education :

* Central assistance extended under Operation Blackboard —27 States/UTs
* Number of Schools covered (21.43% in the country) —1.13 lakhs
* Number of additional teachers posts sanctioned —0.37 lakhs
* Number of States/UTs covered under Non-Formal Education Programme —15
* Number of NFE Centres sanctioned —1.85 lakhs
* Number of teachers oriented under the Mass Orientation of school teachers —4.55 lakhs
* Number of restructured

Teacher Education institutions sanctioned —116
(101 DIETs, 8 CTEs and 7 IASEs)

2.4.2 During 1988-89, the second phase of the above activities is in full swing. These activities have brought about a consciousness about, and set the trend for, providing at least minimum level of infrastructure to primary schools, taking education to the doorsteps of children outside the Formal School system and professionalisation of the teaching system.

2.4.3 In order that investments made by the Centre and the States in this important area of Elementary Education really brings results, action has been initiated for setting up a new Monitoring system - i.e. for assessing progress towards universalisation of Elementary Education.

2.4.4 The Department of Education had submitted to the Ninth Finance Commission, in May 1988, a statement regarding the resources required for Education in the Central Sector. The Commission in its reports for 1989-90 has recommended allocation of Rs. 200 crores for Elementary Education - for provision of school buildings in 10 educationally backward States. Apart from this, they have also recommended allocation of Rs. 41.92 crores for the upgradation of Education Sector in 12 States.

Secondary Education

2.5.1 The emphasis in the area of Secondary Education has been on making education relevant to the world of work, Science teaching, use of Education Technology and special efforts for the talented rural children. The tempo of significant progress achieved in 1987-88 in respect of the schemes meant to achieve the above objectives was continued during 1988-89 - i.e., schemes relating to vocationalisation of education, strengthening of Science teaching, Education Technology and Navodaya Vidyalayas.

2.5.2 Specific achievements during 1987-88 in the area of Secondary Education were the following:

* Assistance given to 18 States to start 3100 Vocational courses in 1000 schools;
* Assistance given to 18 States for Science Education (in respect of 6,900 schools for laboratory upgradation and 8,900 schools for library upgradation, apart from establishment of 80 District Resource Centres;)
* INSAT transmission of education programmes, mainly for the children of 6-11 age group in Hindi, Oriya, Telugu, Marathi and Gujarati for 45 minutes of five days in a week;
* Over 10,000 TV sets and 37,000 Two-in-One Radio-cum-Cassette Players provided for distribution amongst schools in 1[illegible] States;
* Opening of 256 Navodaya Vidyalayas in different parts of the country benefitting over 34,000 talented rural children;

2.5.3 Analysis of the data regarding the children of Navodaya Vidyalayas shows the following :

* Rural children	— 79%
* Children belonging to Scheduled Castes	— 18%
* Children belonging to Scheduled Tribes	— 12%
* Children coming from families below poverty line	— 41%
* Children coming from families with income less than Rs. 12,000 per annum	— 63%

Higher Education

2.6.1 In the area of Higher Education, significant progress has been achieved in Distance Education. As in January, 1989 the Indira Gandhi National Open University (IGNOU) had on its roll 54,000 students for doing various degree, diploma and certificate level courses. IGNOU has come to cover, by now, all States and UTs. barring Sikkim, Pondicherry and Lakshdweep - through its network of 12 Regional Centres and 112 Study Centres.

2.6.2 Under the various programmes of the University Grants Commission, assistance has come to be rendered for various purposes to 100 universities and over 4500 colleges. Approvals have been given for autonomous status in respect of 92 colleges. Majority of the States has also come to implement the revised and improved pay scales for teachers. Performance appraisal and Continuing Education, as integral elements of the scheme of improving the service conditions of the teachers have come under implementation. For the training of University and College teachers, 48 Academic Staff Colleges have come to be established. UGC also gave assistance to a large number of Centres of Advanced

studies and University Departments for development of research and promotion of Centres of Excellence.

Adult Education

2.7.1 The National Literacy Mission has come into action in full swing. There are 2.71 lakhs Adult Education Centres in operation with an enrolment of [illegible] million Adult learners. Over 500 voluntary agencies are involved. There are 14,000 Jana Shikshan Nilayams to provide continuing education for the neo-literates.

2.7.2 The Prime Minister launched the Mass Mobilisation campaign in May, 1988. A special programme of "Operation Literacy by Census 1991" has also been launched in certain districts in Tamil Nadu, Kerala and Gujarat. Efforts for launching this programme in other States and 10 Metropolitan cities are being taken. The programmes of the National Literacy Mission have also come to be aided by a significant techno-padagogic support system - in terms of improved Blackboards, slates and dustless chalks, solar power packs for lighting, Computerised Management Information System, application of rapid literacy methods etc.

Technical Education

2.8.1 In order to ensure orderly development of Technical Education and coordinated maintenance of standards, the All India Council for Technical Education has come to be given statutory backing by the enactment of the AICTE Act. The AICTE has formulated its own regulations, norms and standards for courses and institutions, fee and admission guidelines, models for State Directorates etc. The AICTE has also approved 39 out of the 89 proposals received for starting new institutions/courses.

2.8.2 A large number of thrust areas in Technical Education have been identified for concentration. Over 10,000 laboratories have been identified for modernisation. During 1987-88, over 700 projects for modernisation and thrust area development were cleared and equal number is expected to be cleared during the year 1988-89 as well.

2.8.3 The Community Polytechnics have come to be pressed into service for the benefit of the rural community in a significant way. As on date there are 109 Community Polytechnics. Manpower trained by them, so far is 94,000. Technical services have been rendered by them to over 3000 villages

Other on-going Programmes

2.9.0 All the on-going programmes for improving the content and process of education, providing access to education for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, minorities and women, for providing scholarships to the deserving in India and abroad, for Book Promotion and for promotion of languages were continued.

Computerisation

2.10.0 Consistent with the All India effort being made for the development of education as envisaged in NPE 1986 and POA, with the assistance of the National Information Centre (NIC) computerisation has also been introduced in the Department of Education in a significant way - both for purpose of business transaction as well as for Management Information.

International Co-operation

2.11.0 India has been actively participating, during the year in consultations organized by the UNESCO at various levels for the formulation of its Third Medium-term Plan. Meeting of Regional Working Group on International Literacy Year at New Delhi in October, 1988 and conduct of sub-regional symposium to promote Technical Co-operation among Developing Countries (TCDC) - organized in New Delhi in December, 1988 - were the other important highlights of the work done during the year by the Indian National Commission for UNESCO. The Director General of UNESCO Mr. Frederico Mayor, visited India in December, 1988 and held consultations with the senior officers of the Ministry of Human Resource Development. He also called on Minister for Human Resource Development and the Prime Minister.

Administration

Organisational Structure

3.1.1 The Department of Education, one of the constituents of the Ministry of Human Resource Development, is under the charge of Minister of State under the overall charge of Minister for Human Resource Development. The Secretariat of the Department is headed by the Secretary who is assisted by an Additional Secretary and Educational Adviser (Technical). The Department is organised into Bureaux, Divisions, Desks, Sections and Units. Each Bureau is under the charge of a Joint Secretary/Joint Educational Adviser assisted by Divisional Heads. The set-up of the Department is shown in the organisation chart appended to the report.

Subordinate Offices/ Autonomous Organisations

3.1.2. Over the years, a number of subordinate offices and organisations have come up under the Department. For co-ordination and determination of standards in higher education, the University Grants Commission was set up in 1956 by an Act of Parliament. Besides, a number of organisations have been set up to discharge specific responsibilities. Among them is the National Council of Educational Research and Training which strives to promote qualitative aspects of school education throughout the country. The other important organisations are :

— National Institute of Educational Planning and Administration, New Delhi.

— Indian Institute of Advanced Study, Shimla.

— Indian Council of Social Science Research, New Delhi.

— Indian Council of Historical Research, New Delhi.

— Indian Council of Philosophical Research, New Delhi.

— Kendriya Vidyalaya Sangathan, New Delhi.

— Navodaya Vidyalaya Samiti, New Delhi.

— Central Board of Secondary Education, New Delhi.

— Central Institute of Indian Languages, Mysore.

— Kendriya Hindi Sansthan, Agra.

— Central Institute of English and Foreign Languages, Hyderabad.

— Central Hindi Directorate, New Delhi.

— Commission for Scientific & Technical Terminology, New Delhi.

— Rashtriya Sanskrit Sansthan, New Delhi.

— National Book Trust, New Delhi.

— Indira Gandhi National Open University, New Delhi.

In the field of Technical Education, there are : Indian Institute of Science, Bangalore; Indian School of Mines, Dhanbad; National Institute of Training in Industrial Engineering, Bombay; National Institute of Foundry and Forge Technology, Ranchi; School of Planning and Architecture, New Delhi; Administrative Staff College of India, Hyderabad; four Indian Institutes of Management located at Ahmedabad, Bangalore, Calcutta and Lucknow; four Technical Teachers' Training Institutes located at Bhopal, Calcutta, Chandigarh and Madras; five Indian Institutes of Technology located at Bombay, Delhi, Kanpur, Khadagpur and Madras and seventeen Regional Engineering Colleges, spread all over the country.

Functions

3.2.0 Important functions of the Department of Education are : to evolve educational policy in all aspects and to coordinate and determine the standards of higher education and technical education; to administer Copyright Act; to improve the quality of text-books; to administer scholarships and other schemes; to coordinate programmes of assistance and other activities with the UNESCO; to develop and coordinate research in social sciences; to foster and encourage studies and research in Sanskrit and other classical languages; to develop activities in the field of non-formal education; and to promote adult education.

Vigilance Activities

3.3.1 Disciplinary proceedings against two officials (including one gazetted officer) were initiated during the year. Besides, disciplinary proceedings against three gazetted officers (two of whom belonging to Subordinate Offices) and one non-gazetted official initiated earlier were in progress.

3.3.2 Of the 48 autonomous organisations/ public sector undertaking linked with the Department of Education, 39 have so far accepted Central Vigilance Commission's advisory jurisdication. Chief Vigilance officers are in position in 18 organisations while the question of appointment of Chief Vigilance Officers is being pursued with the remaining organisations. A conference of Chief Vigilance Officers/ Officers handling vigilance work in the autonomous organisations linked with the Department of Education which have accepted jurisdiction of Central Vigilance Commission, was held on 24th October, 1988 wherein the need for effective implementation of the Action Plan on anti-corruption measures as drawn up by the Department of Personnel and Training was stressed.

3.3.3 Emphasis continued to be laid on the observance of discipline and punctuality.

Progressive use of Hindi in Official Business Transaction

3.4.1 In the very beginning of the year under report, the Annual Programme for the implementation of the Official Language Policy of the Government, for the year 1988-89, received from the Department of Official Language (Ministry of Home Affairs) was circulated in this Department, its subordinate offices and autonomous organisations with the request that all-out efforts must be made to achieve the target fixed therein as also for the review of the progress regularly in the meetings of the Departmental Official Language Implementation Committees (O.L.I.C.).

3.4.2 The position of compliance with the Official Language Act and the rules, regulations and administrative orders framed thereunder in 82 Sections of the Department, its 9 subordinate offices and 70 autonomous organisations was watched through quarterly progress reports on the progressive use of Hindi. These reports were regularly obtained from them, reviewed in the Department and shortfalls located therein were brought to the notice of the concerned offices.

3.4.3. For all the 5 Departments of the Ministry of Human Resource Development there had been only one Hindi Salahakar Samiti. A separate Hindi Salahakar Samiti for the Deptt. of Education has since been constituted in accordance with the instructions from the Deptt. of Official Language.

3.4.4 There is one Departmental O.L.I.C. in this Department. It held three meetings during the year under report. The Department of Education being a very big Department, all the Divisional Heads have been requested to constitute a separate Divisional O.L.I.C. for their respective Division to carry the awareness of the O.L. Rules upto the sectional level as also to identify the difficulties in the use of Hindi and to find their solutions. Accordingly, most of the Divisions have constituted their Divisional O.L.I.Cs. and their meetings are also being held. The remaining Divisions have been requested to expedite the setting-up of their Divisional O.L.I.Cs.

3.4.5 Two Hindi-Workshops were ogranised to promote the use of Hindi in noting and drafting and to remove the hestitation of employees in this regard. Besides, Consolidated Administrative glossaries, list of phrases in common use were also circulated to all the Sections/Officers.

3.4.6 The Parliamentary Committee on Official Language took oral evidence of the Education Secretary on 17.9.88 and its lst Sub-Committee inspected this Department on 13.1.89 with a view to review the position of use of Hindi in the Department.

3.4.7 Thirty seven employees were nominated for various courses under the Hindi Teaching Scheme of the Deptt. of Official Language. Two clerks were nominated for Hindi Typing and six Stenographers for Hindi-Stenography.

3.4.8 An Inspection Team has been constituted in this Department to assess the position of compliance with of the Official Language Rules and identify the

difficulties in the use of Hindi. This team inspected 11 offices. The reports submitted by the Inspection Team were discussed by the Senior Officers with the concerned Departmental Heads and the difficulties in this regard solved.

3.4.9 Hindi Week was celebrated in this Department from 14th to 20th September, 1988. On this occasion a Message from H.R.M., an Appeal from M.O.S. (E&C) and Instructions from Education Secretary were issued.

3.4.10 During the year under report the Department notified 9 Offices under Rule 10(4) of the O.L. Rules, 1976. Decision has also been taken to specify 45 subjects in this Department under Rules 8 (4) of the O.L. Rules 1976 for this purpose.

Publication

3.5.1 The Publication Unit brought out 45 publications in English including bilingual (English and Hindi titles) and one quarterly journal "The Education Quarterly" during 1988-89. The Education Quarterly journal entered its 40th year of publication. A monthly resume "Educational Developments at the Centre and in the States" with restricted circulation is brought out every month both in English and Hindi. Besides, the Unit brought out the INC Newsletter.

3.5.2 The Hindi Publication Unit brought out during this period 15 titles including two quarterly journals "Shiksha Vivechan" and "Sanskriti". Besides, it also brings out Hindi version of the "Unesco Newsletter"

3.6.0 Deputations/delegations sent abroad of Government Officials and non-officials during the year 1987-88.

No. of delegations/ deputations	No. of persons included in the delegations/ deputations	Total Expenditure Rs	Foreign Exchange component Rs.
63	103	28,62,677.00	19,45,795.00

3.7.0 **Budget Estimates**

(Rs. in lakhs)

Particulars	B. E. 1988-89	R. E. 1988-89	R. E. 1989-90
Demand No. 48 Department of Education	158486.00	160415.00	158142.00

Provision for :

Secretariat for the
Department including the
Pay and Accounts Offices,
Hospitality and Entertainment.
General Education, other revenue
expenditure of the Deptt.
including provisions for grants-in-aid to States/UTs on Central/ Centrally sponsored Schemes (Plan) and also provision for loans for Central and Centrally sponsored schemes.

GROWTH OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS

	1950-51	1960-61	1970-71	1980-81	1986-87
Num. of Primary Schools (000's)	210	330	408	494	537
Num. of Middle Schools (000's)	14	50	91	119	137
Num. of Secondary/Higher Secondary Schools (000's)	7	17	37	51	69
Num. of Colleges for General Education (Degree Standard & above)	542	1082	2285	3421	4151
Num. of Colleges for Professional Education (Degree & above level)	182	810	992	1156	1280*

* Relates to 1982-83

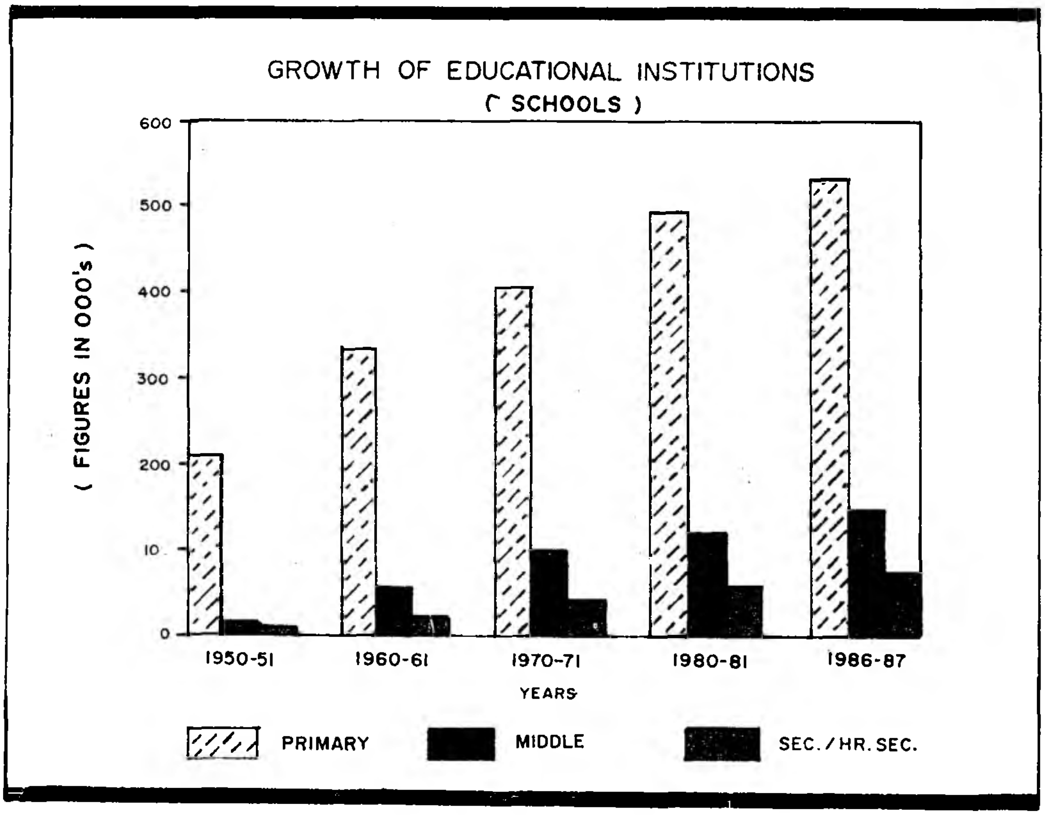

NUMBER OF STUDENTS BY EDUCATION STAGE

	1950-51	1960-61	1970-71	1980-81	1986-87
Num. of pupils in Classes (Lakh)					
I – V	192 (43.1)	350 (62.4)	570 (72.6)	738 (80.5)	900 (96.0)
VI – VIII	31 (12.9)	67 (22.5)	133 (34.2)	207 (41.9)	288 (53.14)
IX – XI / XII	14	33	76	119	176
Num. of pupils studying in degree level & above courses (Lakh)	2	6	25	30	34

Note : Figure in parenthesis indicate percentage of enrolment to total population in the age groups of 6 – 11 & 11 – 14 years.

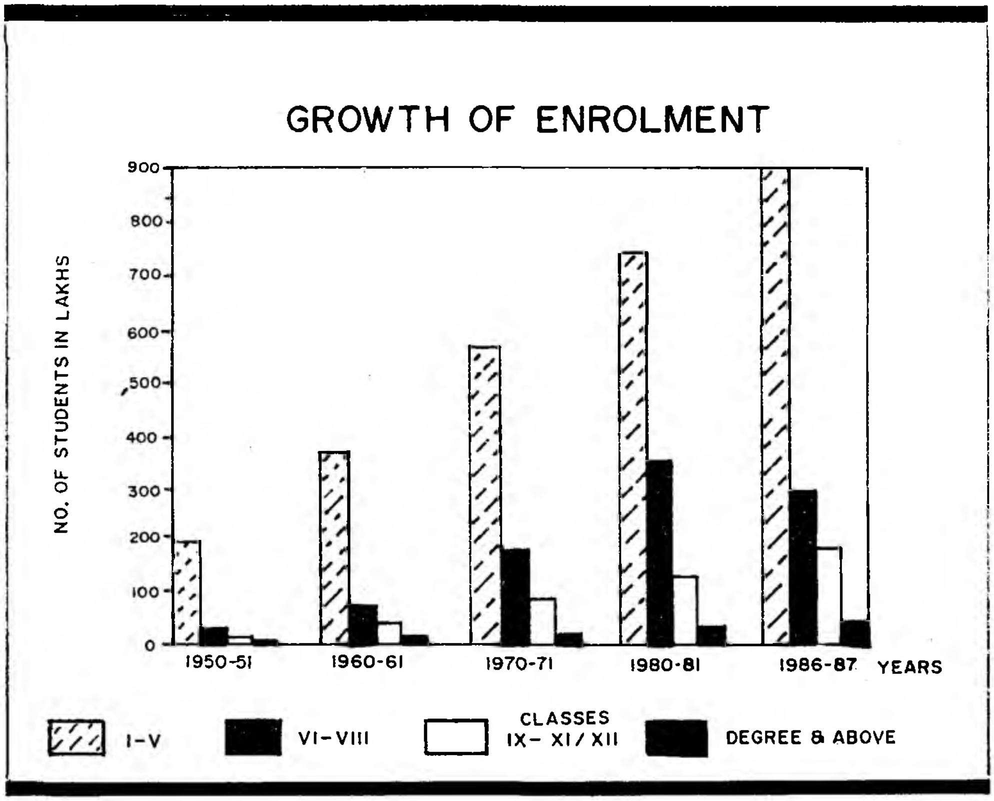

GIRLS' ENROLMENT BY STAGES

(In Lakh)

Stage	1950-51	1960-61	1970-71	1980-81	1986-87
Primary (I – V)	54 (28.1)	114 (32.6)	213 (37.4)	285 (38.6)	361 (40.1)
Middle (VI – VIII)	5 (16.1)	16 (23.9)	39 (29.3)	88 (32.9)	102 (35.4)
Secondary / Hr. Secondary / 10+2 / Intermediate (IX & above)	2 (14.3)	6 (18.2)	19 (25.0)	35 (29.4)	54 (30.7)
Higher Education (Degree & above level)	.20 (10.0)	1 (16.7)	4 (20.0)	8 (26.7)	10* (29.4)

* Relates to 1982 – 83

Note : Figures in parenthesis indicate percentage to total enrolment (Boys & Girls)

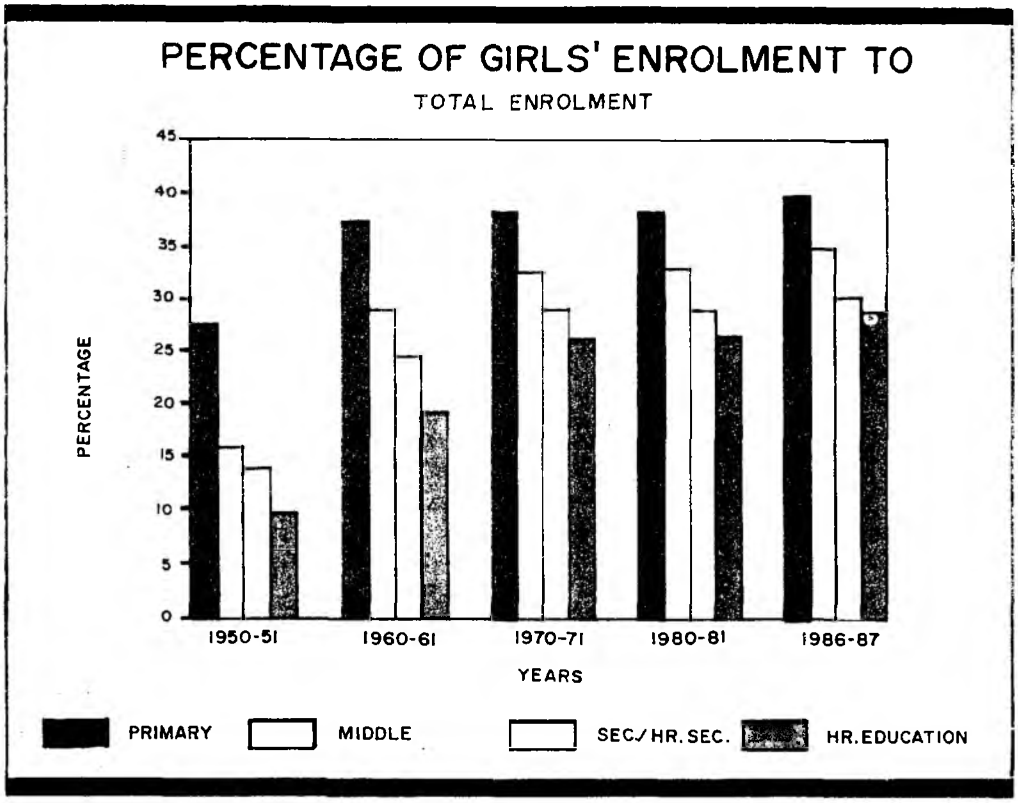

NUMBER OF TEACHERS

(In thousands)

	1950-51	1960-61	1970-71	1980-81	1986-87
Primary Schools	535	742	1060	1363	1522
Middle Schools	85	345	638	852	979
Secondary / Hr. Secondary Schools	127	296	629	912	1199

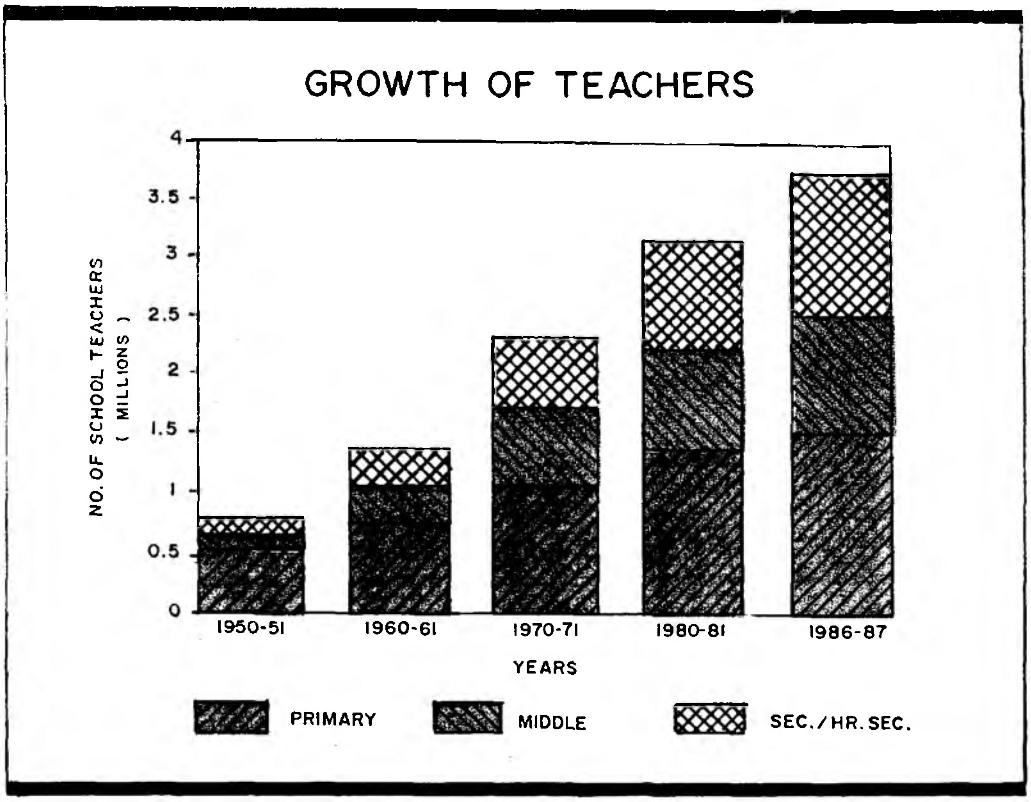

Elementary Education

Universal Elementary Education (UEE)

4.1.1 Universalisation of Elementary Education (UEE) is a basic goal of educational development. It is set forth in the Directive Principles of State Policy (Article 45 of the Constitution) dealing with provision of free and compulsory education for children. In specific terms it states: "The State shall endeavour to provide, within a period of 10 years from the commencement of this Constitution, for free and compulsory education for all children until they complete the age of 14 years".

4.1.2 Many States and Union Territories in the country have enacted laws for compulsory primary education. Due to the vast numbers involved and socio-economic compulsions keeping children away from schools, it has been difficult to enforce the penal provisions of these laws.

4.1.3 Although it has not been possible yet to attain the goal of Universal Elementary Education, remarkable progress has, indeed, been achieved in terms of educational growth in general—in all sectors.

Growth of Education

4.2.1 Growth of education since 1950-51 in terms of number of educational institutions, number of students by education stage (enrolment), girls' enrolment by stages, number of teachers is exhibited in the statements and charts.

Findings of the Fifth All India Educational Survey

4.2.2 The Fifth All India Educational Survey (1986) throws up the following findings regarding growth of education, vis-a-vis the situation that obtained at the time of the Fourth All India Educational Survey (1978):

— Increase in enrolment and number of teachers has been as shown below:

Increase in Enrolment	In all areas	In rural areas	Amongst S.Cs.	Amongst S.Ts.
	1.	2.	3.	4.
Primary Stage	26%	28.6%	49%	62%
Upper Primary Stage	51%	62.3%	102%	126%
Secondary Stage	63%	80.8%	121%	124%
Higher Secondary Stage	88%	127.5%	132%	185%
Increase in Girls' Enrolment				
Primary Stage	36%	92%		
Upper Primary Stage	64%	87%		
Secondary Stage	74%	87%		
Higher Secondary Stage	132%	329%		
Increase in the Number of Teachers				
Primary Stage	17%			
Upper Primary Stage	24%			
Secondary Stage	49%			
Higher Secondary Stage	62%			

— 32,000 habitations with a population of 300 or more are still to be provided Primary schooling facilities within a walking distance of one Kilometre;

— 13.5% of the Primary schools and 4% of Upper Primary schools are still without buildings of any kind;

— Size of untrained teachers is as follows:—

* Primary and Upper Primary Stage — 13%
* Secondary Stage — 10%
* Higher Secondary Stage — 11%

Source: NCERT

Targets for Universal Elementary Education under NPE, 1986

4.3.1 Progress achieved in various sectors of education had been reviewed and assessed at the time of formulation of National Policy on Education, 1986. So far as UEE is concerned, targets were spelt out as follows by NPE, 1986:

"A RESOLVE

The New Education Policy will give the highest priority to solving the problem of children dropping out of school and will adopt an array of meticulously formulated strategies based on micro-planning, and applied at the grass-roots level all over the country, to ensure childrens retention at school. This effort will be fully coordinated with the network of non-formal education. It shall be ensured that all children who attain the age of about 11 years by 1990 will have had five years of schooling, or its equivalent through the non-formal stream. Likewise, by 1995 all children will be provided free and compulsory education upto 14 years of age"

4.3.2 Consistent with NPE 1986, meaningful programmes have been evolved and brought under implementation in the area of Elementary Education as described in the following paragraphs:

Operation Blackboard

4.3.3 The Scheme of Operation Blackboard aims at bringing about substantial improvement in facilities in primary schools run by Government, Local Bodies, Panchayati Raj and recognised aided institutions. It has three interdependent components namely,

- Provision of a building comprising of at least two reasonable large all-weather rooms with a deep varandah and separate toilet facilities for boys and girls:
- At least two teachers in every school, as far as possible, one of them a woman; and
- Provision of essential teaching and learning materials including blackboards, maps, charts, toys and equipment for work experience.

4.3.4 Funds for construction of school buildings are to be provided mainly under National Rural Employment Programme (NREP) and Rural Landless Employment Guarantee Programme (RLEGP). Funds for other components are provided by the Department of Education. The scheme seeks to cover the Primary schools in all the blocks/Municipal areas in the country in a phased manner. The target has been to cover 20% blocks/Municipal areas during 1987-88, 30% of them during 1988-89 and 50% of them during 1989-90.

4.3.5 During 1987-88, an amount of Rs. 110.61 crores was provided as assistance to 24 States and 3 Union Territories for

- covering 1,13,417 schools (over 21% of the primary schools in the country) and
- providing 36,891 additional teachers (for schools amongst the above).

Non-formal Education (NFE)

4.4.1 The scheme of Non-formal Education (NFE) introduced during the Sixth Five Year Plan as a Centrally assisted scheme in the educationally backward States of Andhra Pradesh, Assam, Bihar Jammu and Kashmir, Madhya Pradesh and West Bengal was reorganised and expanded in 1987 to cover, in addition, Arunachal Pradesh as also urban slums, hilly, desert and tribal areas and projects for working children in all the other States. Under the revised Scheme, assistance is being given to State Governments in the ratio 50:50 and 90:10 for running general NFE centres and girls' NFE centres respectively. Hundred percent Central assistance is being given to voluntary agencies.

4.4.2 The essential features of the revised scheme are: organisational flexibility, relevance of curriculum, diversity in learning activities to relate them to the learners' needs and strengthened, decentralised management. The programme is now being implemented on a project basis. (A project is generally coterminous with a CD block comprising about 100 NFE centres). Voluntary agencies and Panchayati Raj institutions are involved in this programme in a significant way.

4.4.3 During 1987-88, an amount of Rs. 38.07 crores was spent on the implementation of this scheme. Assistance was sanctioned to 15 States/UTs for—

- running 1.85 lakh NFE Centres
- 8747 centres to be run by 104 voluntary agencies.

— Eight experimental and innovative projects.

4.4.4 For the current year, the physical Target is 2650 projects (approximately, 2,65,000 State/UT Centres and 100 projects (10,000 centres) of voluntary agencies. Emphasis during the current year is on consolidation of NFE Centres already sanctioned, particularly with a view to projectising team.

4.4.5 A monitoring system for the programme has been designed and is being field-tested. Simultaneously, computerisation to provide an appropriate decision support system and regular flow of information is being taken up with the help of Department of Electronics.

Shiksha Karmi Project

4.4.6 The Shiksha Karmi Project—a non-formal education programme brought under implementation with assistance from Swedish International Development Agency (SIDA) in ten blocks in 1987-88 was continued and expanded to 20 more blocks in 1988-89. The project represents a non-formal and innovative approach to improvement and extension in remote and backward villages. The Shiksha Karmis are not necessarily required to have formal educational qualifications required for teachers but their suitability is judged on the basis of their enthusiasm, commitment, interest and aptitude. They conduct both day and evening primary classes and it is intended that the pedagogy should be more child centred and innovative.

Mahila Samakhya

4.4.7 In persuance of para 4.2. of the National Policy on Education—1986 and chapter XII of the Programme of Action, a programme called "Mahila Samakhya" has been launched. It seeks establishment of Women's Activity Centres in 2000 villages of 10 districts in 3 states, to be covered in a phased manner by 1989-90.

4.4.8 The programme envisages training of some women in each village to work as Activators or Inspirers to catalyse discussions on problems faced by women—problems related to health, water, fuel, fodder and education and, above all, problems related to their own personality and self image in society. Such discussions would facilitate critical reflection in analysing women's life situation and would encourage group action to bring about change. A small hut with a spacious varandah is to be provided to the Mahila Sangha, (built on land offered by the village itself near a cluster of houses, for its activities). The aspirations of the women voiced in the Mahila Sanghas are to be integrated with the various programmes for education like ECCE, NFE, AE, JSN, etc. Village school teachers, non-formal and Adult Education instructors will be given opportunities to participate in intensive training programmes so that they understand the notion of their own accountability to the community i.e. the Mahila Sanghas. Hostel facilities for 100 women in residential institutions are to be set up and short-term and long-term vocational courses organised for women as well as girls in higher secondary schools.

4.4.9 The Programme seeks to draw upon the credibility and expertise of voluntary agencies working for women in programme districts. Both in formulation and launching of the programme, repeated discussions with these agencies as well as Govt. officials were held at State, District and block levels.

4.4.10 It is hoped that the programme will continue during the Eighth Five Year Plan and extend to other States as well in a phased manner. The programme was approved in September, 1988 as a Central sector scheme under which 100% financial assistance will be provided to the Mahila Samakhya Societies registered in the three states.

4.5.0 In order that text books, exercise books and examination answer sheets could be produced at reasonable prices for the benefit of school children, Government of India are operating two important schemes, particulars of which are presented below:

Supply of White Printing Paper at Concessional Rate for Educational Purposes

4.5.1 Consequent upon repeal of the Paper Control Order and the Paper (Regulation of Production) Order, 1978, with effect from the 22nd January, 1987, Government of India has substituted the same with a new scheme under which supply of white printing paper to the educational sector has been ensured. Under the new scheme, States/UTs will continue to get concessional paper at Rs. 7560 per MT. Hindustan Paper Corporation, a Government of India Enterprise, has been entrusted with the responsibility of supplying paper to the States/UTs. Hindustan Paper Corporation will supply paper to the allottees in the States/UTs at Rs. 7560/- per MT and shall claim subsidy from the Department of Education against their quoted price of Rs. 10,910/- per MT subject to the ceiling of Rs. 3000/- per MT.

4.5.2 The entire quantity of 80,000 tonnes to be allocated annually to the Educational Sector in the

States/UTs, has already been allotted during the calendar year 1988.

Receipt of White Printing Paper from Norway

4.5.3 Under the bilateral agreement between the Government of India and the Kingdom of Norway, white printing paper is received as gift from Norway for the printing of school text-books. Under the plan of operation 1988-89, Paper valued at 38 million Kroners is expected to be received. Further, Norway has agreed to provide additional paper valued at 15 million Kroners. The entire quantity will be allotted to NCERT for the printing of school text-books.

Teacher Education

4.6.1 The centrally sponsored Scheme of Restructuring and Reorganization of teacher education brought under implementation during the Seventh Plan has the following objectives.

— Imparting preservice and inservice training to school teachers to equip them with the teaching competencies.

— Provision of meaningful academic support to formal and non-formal school systems as also Adult Education through professionally organized teacher education institutions.

The scheme has the following five components viz:

— Mass Orientation of about 5,00,000 school teachers annually till 1989-90 to familiarise them with the major thrusts envisaged in the NPE and to improve their professional competence;

— Setting up of about 400 District Institutions of Education and Training (DIETs) either by upgrading suitable existing Elementary Teacher Education Institutions or, where necessary, by establishing new ones—so as to provide total academic and training support to the Elementary Education System at the District level;

— Strengthening of about 250 Secondary Teacher Education Institutions (STEIs) and development of about 50 of them as Institutions of Advanced Study in Education (IASE);

— Strengthening of State Councils of Educational Research and Training (SCERT); and

— Establishment and strengthening of Department of Education in universities.

4.6.2 During 1987-88 an amount of Rs. 32.47 crores was given as Central assistance under the above teacher education programmes to fifteen States and one Union territory for:

— Orientation of 5 lakh school teachers

— Setting up 101 DIETs

— Strengthening 15 STEIs into CTEs

— Strengthening 7 STEIs into IASEs.

4.6.3 The Department of Education organized a workshop on "Educational Research in the context of restructuring and reorganization of teacher education" on October 24-26, 1988.

4.6.4 The University Grants Commission (UGC) is working out the details of strengthening University Departments of Education.

A committed Under Secretary, Dept. of Education, Govt. of India, visits and explains teaching methods in NFE Centre, Tirupathi run by Rayalaseema Seva Samiti.

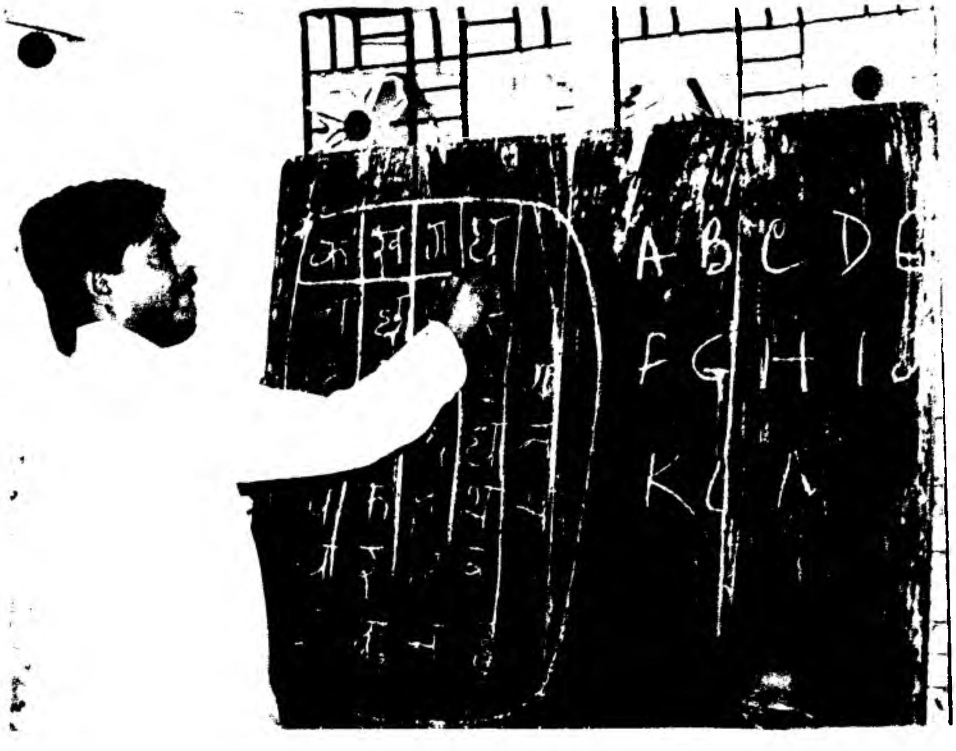

Secondary Education

5.1.0 The growth of Secondary Education has already been presented in tables and graphs under the part relating to Elementary Education.

5.2.0 Having considered that Secondary including Higher Secondary Education is terminal on the one hand for those who enter the world of work after this stage, and preparatory to higher education for others, several important schemes in this sector are in implementation under the National Policy on Education, 1986. Progress achieved under them and other on-going schemes is presented below:

Vocationalisation of Secondary Education

5.3.1 Vocational education has been accorded high priority in the National Policy on Education, 1986 which, inter-alia, states that "introduction of a systematic, well-planned and rigorously implemented programme of vocational education is crucial in the proposed educational re-organisation". The Policy has expressed the commitment that 10% of higher secondary students would be enrolled in vocational courses by 1990 and 25% by 1995.

5.3.2 Based on the guidelines laid down in the NPE and the Programme of Action and the discussions held with the State Governments and experts, a Centrally Sponsored Scheme of Vocationalisation of Secondary Education has been started with effect from 1987-88 under which assistance is provided to States/UTs for introduction of vocational courses at + 2 level in schools. The scheme envisages establishment of a Joint Council of Vocational Education at the national level, with counterpart orgaisations at the State level for policy, planning and coordination of vocational programmes being run by the various organisations/agencies. The management structure at the Central/State/District and institutional levels is to be suitably strengthened for successful implementation of this programme. Under the scheme, 100% assistance is provided to the States/UTs for conducting district vocational surveys, development of curriculum and resource materials, necessary equipment for vocational courses, construction of worksheds, training of teachers, textbook subsidy, etc. evaluation and monitoring in accordance with the norms of the scheme. Seventy five per cent of the expenditure on salaries and allowances of teachers and other vocational staff in schools and 50% of the expenditure on staff in the Vocational Wings in the Directorates of Education, SCERT and District Education Officers is borne by the Centre. However, raw-materials and contingencies, vocational guidance and examination and certification are 100% responsibility of the States. The Scheme also provides for assistance to voluntary organisations for taking up experimental and innovative programmes in the area of vocational education.

5.3.3 The Courses started under the scheme are to be so designed that there would be enough employment opportunities for the students passing out of these courses or the students would be able to go in for self-employment. An innovative project taken up by C.B.S.E. is the introduction of vocational course in General Insurance in selected C.B.S.E. Schools in metropolitan cities in collaboration with the General Insurance Corporation of India which has ensured employment to the students who successfully complete the course. The State Governments have also been advised to identify such employers in their region and develop similar courses in collaboration with them to ensure employment opportunities to the students and provide suitable trained manpower to the employers.

5.3.4 Keeping in view the long felt need of prop trained manpower in Health-related areas, an expe Committee on "Health Manpower — Planning,

Production and Management" was set up by the Ministry of Health & Family Welfare in May, 1986 under the Chairmanship of Prof. J.S. Bajaj. This Committee has recommended various vocational courses in the health sector which could be started in schools. The State Governments/UT Administrations have been requested to give due consideration to the recommendations of the Baiaj Committee while indentifying the vocational courses to be started by them.

5.3.5 During 1987-88, Central assistance amounting to Rs. 32.26 crores was sanctioned to 18 States/UTs providing for about 3100 vocational courses in about 1000 higher secondary schools. During 1988-89 also States have submitted proposals under the programmes for substantial Central assistance.

Improvement of Science Education in Schools

5.4.1 The place of science in the Scheme of general education for school children can scarcely be overemphasized. The Kothari Commission and the Education Policy Resolution (1968) accorded high priority to the teaching of science at the schools stage. However, teaching of science in schools is rather weak at present. Teaching of science required not only classroom teaching but also demonstration and experimentation. However, majority of the schools in the country do not have adequate laboratory facilities.

5.4.2 The National Policy on Education (1986) has also emphasized the need to strengthen science education programmes. It has been felt by the experts that in addition to providing proper physical facilities. it is also necessary that teachers are improved. Accordingly, a Centrally Sponsored Scheme of Improvement of Science Education in Schools has been started during the last quarter of 1987-88 under which financial assistance is provided to States/UTs for supplying science kits to upper primary schools, to upgrade science laboratories in secondary and higher secondary schools upto a desired standard, upgrading libraries in secondary and higher secondary schools and setting up of District Resource Centres for Science Education which would not only help in training of Science teachers and development of teaching-learning materials, but also serve as a forum where science teachers may come to sort out their problems and share ideas. Besides, an intensive programme of inservice training of science and mathematics teachers of schools will also be taken up under this Scheme. The Scheme also provides for assistance to voluntary organisations active in the field of science education for taking up innovative programmes for creation of scientific temper, increasing awareness and promotion of Science Education. The National Board for Higher Mathematics has been requested to examine the feasibility of taking up a programme for strengthening of teaching of Mathematics in schools with a view to preparaing students for participation in the International Mathematical Olympiad held every year.

5.4.3 During 1987-88, Central assistance amounting to Rs. 29.27 crores was sanctioned to 19 States/UTs, inter-alia, for providing science kits to about 21000 upper primary schools, upgradation of science laboratories in about 6900 secondary/higher secondary schools and establishment of District Resource Centres in 80 Districts. It is proposed to cover the remaining States during the current financial year. The scheme has also received an encouraging response from voluntary organisations. A number of proposals for taking up various programmes in the area of science education have been recieved from various voluntary agencies and assistance has already been sanctioned to Ekalvya, Bhopal; Tamil Nadu Science Forum, Madras; Pondicherry Science Forum, Pondicherry; Kerala Sastra Sahithya Parishad, Trivandrum; Bal Bhavan Society (India), New Delhi. The proposal of the National Council of Science Museums for setting up schools science centres has been approved for 25 Districts @ two in each district. These Schools Science Centres will organise various activities for promotion of science education and creation of scientific temper among students, like preparation of models and charts, organization of exhibition, plays, essay & quiz competitions, etc.

Environmental Orientation to School Education

5.5.1 Environmental concerns are becoming increasingly important with the scientific and technological developments in the world. The National Policy on Education (1986) attaches due importance to this subject and, inter alia, states that "protection of the environment" is a value which along with certain other core values, must form an integral part of curriculum at all stages of education. Accordingly, NCERT has developed a national curricular framework designed to lay down essential learning outcomes for all learners. NCERT is also developing syllabi, textbooks and other teaching-learning materials to give effect to the provisions of NPE. Teacher training arrangements are also being given environmental orientation. However, since these

programmes would be designed and implemented with the national and State level perspectives, the full intent of environmental education will not be achieved because the environmental concerns are locale-specific and, therefore, do not admit of global solution. These efforts, therefore, need to be supplemented by more intensive locale-specific efforts.

5.5.2 Accordingly, a Centrally Sponsored Scheme of Environmental Orientation to School Education has been started with effect from the current financial year under which 100% financial assistance is provided to States/UTs and voluntary organisations working in the field of environment education. Various programmes aimed at creating environmental consciousness among the students and the community would be organised on project basis in selected areas comprising homogenous ecological conditions. The project activities would include review of curriculum, preparation of revised textbooks, curricular and extra-curricular materials, preparation of general informative books/brochures/posters/audio-visual materials, adoption of monuments by schools for study and upkeep, study of ecological problems in the neighbourhood, participation in conservation projects, etc. Setting up of school nurseries will be taken as one of the preferred activities with the help of State Departments of Environment & Forest and National Wastelands Development Board. The scheme also provides for involvement of voluntary organisations in innovative projects relating to environment education.

5.5.3 During the current financial year, proposals of Himachal Pradesh, Assam and Mizoram have already been sanctioned and some others are under consideration. The scheme has received a very good response from the voluntary organisations and a number of proposals are being received for taking up projects under this scheme. Some of the proposals already sanctioned are from:

- Uttarakhand Seva Nidhi, Almora for environmental orientation to elementary education in Kumaon & Garhwal regions of Uttar Pradesh.
- Sanchal Foundation, New Delhi for a project on social imperatives of development which seeks to establish a linkage between the natural disasters and environmental degradation.
- Centre of Environment Education (CEE) Ahmedabad to act as a nodal agency for involving NGOs working in the area of environment education to take up locale-specific activities in a cluster of schools around them. The CEE will provide orientation to the key functionaries of the NGOs, will collaborate with and guide them in their programmes. The NGOS identified by CEE will be given grants through CEE which will monitor and supervise the implementation of the programme in schools.

Educational Technology Programme

5.6.1 An educational technology programme was started in the Central Sector during the Fourth Plan period in 1972 for widening access to and bringing about qualitative improvement in education.

5.6.2 In 1982, with the commissioning of INSAT transmission it was decided that production of ETV programme will be the responsibility of educational authorities. Accordingly, a scheme was prepared by the Ministry of Education for creating Educational Television (ETV) programme production facilities within the education sector on a decentralised basis by setting up a Central Institute of Educational Technology (CIET) in the NCERT and State Institutes of Educational Technology (SIETs) in six States i.e. Andhra Pradesh, Bihar, Gujarat, Maharashtra, Uttar Pradesh and Orissa and strengthening of ET Cells in other States.

5.6.3 The National Policy on Education 1986 states that, 'In order to avoid structural dualism, modern educational technology must reach out to the most distant areas and most deprived sections of beneficiaries simultaneously with the areas of comparative affluence and easy availability.' This approach would intrinsically favour the use of broadcast methods with their inherent advantage of greater reach, convenience of management and cost effectiveness. Keeping this in view, a revised scheme has been formulated by the Department which seeks to consolidate present efforts under the INSAT utilisation programme, achieve larger programme production capabilities within the education sector and extend Radio and TV coverage to one lakh and five lakh elementary schools respectively by providing receiving sets. The scheme has been finalised and started in 1987-88.

5.6.4 Programme production has commenced in CIET and SIETs. From the current academic year, responsibility for programme production, which was hitherto being shared between Doordarshan and CIET on 50:50 basis, has devolved entirely on CIET.

5.6.5 The ETV programmes are telecast daily in the morning for 3 hours and 45 minutes, on about 220 school days, covering five regional languages viz.

Hindi, Gujarati, Marathi, Oriya and Telugu on a time sharing basis (45 minutes each language). Programmes in five languages are produced and telecast for six to eight and nine to eleven year old children both in school and out of school from Monday through Friday. Programmes for the primary level teachers are telecast every Saturday. The ETV programme are relayed by all HPTs and LPTs in the six INSAT States and other Hindi speaking States.

5.6.6 CIET has produced 350 ETV programmes and 700 language versions since 1984. Ending November, 1988, the CIET had produced 50 new ETV programmes in Hindi and prepared Oriya version of these programmes. As in the earlier years, the CIET prepared the ETV component of the National programme of the Mass Orientation of School Teachers (MOST) this year also. The programmes produced in Hindi and English are preceded by synopsis of 13 different languages. The emphasis is to support different core curricular areas and print material. More than 4.5 lakh teachers receive the benefit of these programmes each year. Various training courses are organised in collaboration with international agencies of repute. Ninety four persons will be participating in various training courses during 1988-89. About thirty in-country training courses have also been organised providing training to 600 persons of SIET and CIET in various aspects of audio and video production.

5.6.7. Though the CIET has reached programme production capability of high order, SIETs have been a little slow in this regard. They have faced management problems as well as technical manpower problems. A working group was set up to examine the management structure and suggest measures to improve the functioning of SIETs. The group, among other things, recommended that an autonomous organisation in the form of a registered society should be consitituted under the aegies of the State Government to manage the affairs of SIETs. In pursuance of this, draft bye-laws have been framed and various measures are under consideration for re-organisation of the SIETs.

5.6.8 The emphasis on educational audio production in the CIET during the year has also been on core curricular areas and 72 new audio programmes were produced. Three 16 mm colour films on West Coast in a Geography series on "Land and People" were completed. In addition, two other films on 'Aravali Ranges' and 'Non-formal Education' are nearing completion. Efforts are also on to involve private producers in production of ETV programmes. The NCERT has set up a Committee to evolve modalities for involving outside producers to produce video films for CIET. SIET, Lucknow is also exploring the possibility of commissioning private producers for ETV programmes.

5.6.9 A group on use of Satellite for education was set up with Shri Kiran Karnik as convenor to go into media time requirement, manpower requirement and finances for the entire educational sector. The Group is expected to submit its report soon.

5.6.10 The new ET Scheme approved in January, 1988 envisaged supply of one lakh TV sets and five lakhs radio-cum-cassette players to elementary schools during last three years of the Seventh Five Year Plan period. During 1987-88, a total number of 10,049 TV sets and about 38,000 Radio-cum-cassette players (RCCPs) have been sanctioned to States/UTs for supply among elementary schools. To ensure standardization for purchase of TV sets and RCCPs, their design specifications were finalised in consultation with CIET, DOE, Doordarshan/AIR and these were circulated to the States along with guidelines for purchase procedures.

Computer Education in Schools

5.7.1 A Pilot Project on Computer Literacy and Studies in Schools (CLASS) was initiated in 1984-85 in 248 Secondary/Higher Secondary schools; jointly by the Department of Electronics and the Department of Education to acquaint students and teachers with the range of computer applications and its potential as a learning medium. The project continued till 1987-88 on year to year basis with addition of 1700 more schools (700 schools covered during 1987-88). Fifty three resource centres were set up to train school teachers and provide logistic support to the participating schools. Maintenance of hardware and its installation was assigned to the CMC Ltd. The NCERT was identified as the nodal agency to implement the project. Since the inception of the project till 1986-87, the project had been entirely funded by the Department of Electronics. During 1984-85, 1985-86, 1986-87 and 1987-88 the Department of Electronics allocated Rs. 2.2 crores, Rs. 4.00 crores, Rs. 4.00 crores and Rs. 90 lakhs respectively. During 1987-88, the Department of Education spent Rs. 5.39 crores for the project.

5.7.2 Efforts were made to start generation of indigenous software through NCERT and CMC. They succeeded in developing 14 packages which were supplied to schools alongwith other packages in 1987-88. CMC have developed key boards and ROMs in eleven languages so far, viz. Marathi, Oriya,

Telugu, Hindi, Tamil, Kannada, Malayalam, Gurumukhi, Gujarati, Bengali and Assamese. The work is continuing.

5.7.3 With a view to evaluating the Project experience, the Department of Electronics had entrusted an evaluation study to the Space Application Centre, Ahmedabad. Their report indicated that the 'demystification' objective of the Project was only partially achieved

5.7.4 To implement the project on a larger scale keeping in view the results of evaluation and experience gained so far for the remainder of the Seventh Plan, a proposal has been drawn up jointly by the Department of Electronics and the Department of Education aiming to cover 13,000 higher secondary schools all over the country. The total financial implications for this programme are estimated at Rs. 89.03 crores in the first year and Rs. 109.39 crores in the second year. The proposal has yet to be finally approved by the Government.

Navodaya Vidyalayas

5.8.1 In order to provide good quality modern education to the talented children predominantly from the rural areas, Government of India have launched a scheme to establish Novodaya Vidyalayas on an average one in each district. Two hundred and fifty six Navodaya Vidyalayas covering 22 States and 7 Union Territories have so far been established in the country.

5.8.2 Admission to Navodaya Vidyalayas is at the level of Class-VI. In view of the fact that most of the students so admitted would have been taught earlier through the medium of the mother-tongue/regional language, instruction is provided through the same medium upto Class-VI or VIII, during which time intensive teaching of Hindi/English both as a language subject and co-media is undertaken. Thereafter, the common medium would be Hindi/English. At this stage, there is a migration of 20% students from each Navodaya Vidyalaya to another Navodaya Vidyalaya, in a different linguistic region. The migration is mainly between Hindi and non-Hindi speaking districts. The first batch of students has migrated from Navodaya Vidyalaya, Jhajjar to Amravati and vice versa, as these two Vidyalayas have reached Class-IX stage this year. The Navodaya Vidyalayas follow the normal three language formula. At present, there are 123 Vidayalayas in Hindi Speaking States and 133 in non-Hindi Speaking States and third language has been introduced in all these Vidyalayas.

Admission

5.8.3 The basis of admission to Navodaya Vidyalayas is a test conducted by NCERT. The medium of the test is the mother-tongue or regional language. Test is largely of non-verbal nature, class-neutral and so designed as to ensure that talented children from rural schools are able to compete without suffering a disadvantage.

5.8.4 The examination for Academic Session 1988-89 was conducted on 15.05.88 in all the districts where the Navodaya Vidyalayas are functioning. The test was conducted in 18 languages.

5.8.5 Break-up of the students selected for 256 Navodaya Vidyalayas is as follows:—

Rural	10934	Boys	11298
Urban	2870	Girls	2506
	13804	SC –	2360
		ST	1602
		General	9842

5.8.6 Navodaya Vidyalayas are co-educational and primarily for children from rural areas. Hence admission of children from urban areas is restricted to a maximum of one-forth. Efforts are made to ensure that atleast one-third of the students in each Novodaya Vidyalaya are girls.

5.8.7 Reservation of seats in favour of children belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes is provided in proportion to their population in the concerned district, provided that in no district such reservation is less than the national average.

Construction Programme

5.8.8 The Central Building Research Institute, (CBRI) Roorkee, has been designated as the nodal agency for implementing the works programme for Navodaya Vidyalaya. For implementing the programme a Construction Co-ordination Committee has been set up in the Samiti. Twenty six Construction Agencies have been identified and Vidyalayas allotted to them. The Samiti has given clearance for construction of first phase of building (for classes VI to IX) in 100 Vidyalayas and of minimal structures with tubular trusses in 120 Vidyalayas.

Principals and Teachers

5.8.9 At the moment, 256 schools are functioning with 256 principals and 2719 teachers.

5.8.10 Since all Novodaya Vidyalayas are residential and located in remote areas, the following incentives have been provided to attract good teachers/Principals:

(i) Rent free, partly furnished, accommodation as available at site.

(ii) Children Education allowance at the rate of Rs. 150/- p.m. per child subject to a maximum of two children.

(iii) Free boarding facilities to House Masters and teachers staying with the students.

(iv) Free lunch to all teachers.

(v) Facility for the appointment of spouse as per Samiti's rule.

(vi) Admission of children in the Navodaya Vidyalayas where teachers are posted without admission test and free boarding facility to such children.

(vii) Teaching Allowance of Rs. 100/- p.m.

Provision of Vehicles to Navodaya Vidyalaya

5.8.11 There are some Vidyalayas which are very remotely placed and far away from the main road, market post office, bank etc. There are 60 Vidyalayas which have been identified so far and vehicles have been provided to them for official use.

Training Programme

5.8.12 Two In-service courses for Principals and ten In-service courses for various categories of teachers have been organised to acquaint them with the functioning of residential schools.

Significant Academic Activities

5.8.13— A seminar on developing curricular strategies for talented children was organised by Navodaya Vidyalaya Samiti in collaboration with NBT on 14-15 February, 1988 and as a follow up of this seminar, another workshop on 'Creative learning environment through non scholastic strategies' was organised on 22-23 November, 1988.

— Curriculum enrichment programmetic is being conducted by the Samiti in Science, Mathematics & Social Studies. This enrichment of curriculum will be useful for the teachers and students of Navodaya Vidyalayas.

— Inter-regional Science & Social Science Exhibitions were organised by the regional offices of the Samiti.

Open School

5.9.1 Open School established in 1979 by the Central Board of Secondary Education is marching ahead towards its goal for education to all who could not join regular schools due to economic, social and other constraints but are eager to enhance their educational qualifications. It is specifically emphasising to impart education to the school dropouts, women, working adults and other disadvantaged sections of the society.

Extensive Publicity Drive

5.9.2 During the year, about 36 advertisements were placed in National and Regional Newspapers all over the country to publicise Open School System among masses living in remote areas of the country. Publicity material was also sent to the Directorate of Education and Adult Education in States, affiliated schools of CBSE, sponsoring institutions and resource-cum-study centres of Open School to transmit them to other interested persons and agencies.

Strength of Students

5.9.3 Since its establishment in 1979, Open School was offering courses leading to the Secondary School Examination. To cater to the continuing education needs of those who have passed secondary examination, it introduced Sr. Sec. Courses in Science, Commerce and Humanities, as well as package Vocational Courses in Typewriting, Stenography and Secretarial Practice in the current year. 5,600 students have been enrolled for the purpose.

5.9.4 The first examination under the scheme was held in April, 1983. The enrolment has increased from 1634 in the first year to 17052 in 1987-88. During 1988-89, so far 18167 students have been enrolled and this figure is expected to go up to 20,000. The students once enrolled can remain for a maximum period of five years or till they clear all the five subjects. At present, there is a total cumulative enrolment of 57,337 students for secondary courses.

Publication

5.9.5 Open School publishes a number of booklets every year in form of despatches which is the study material of the students. In the year 1988-89 about 90 publications were brought out.

New Resource-cum-Study Centres

5.9.6 Open School organises personal contact programmes at its Resource-cum-Study Centres during the week ends and Holidays. Twenty one Resource-cum-Study Centres are already functioning for the purpose all over India, including those at Madras, Jaipur, Sikkim and Andaman & Nicobar Islands. A new centre at Calcutta is being opened now. In the year under report a new centre at Delhi was also established, namely, Mount Carmel School, Anand Niketan, New Delhi.

5.9.7 Besides Resource-cum-Study Centres, Open School accredits well established institutions for sponsoring candidates for Open School Courses and arranging contact classes for them on the lines of Resource-cum-Study Centres. Twenty four new institutions were accredited in 1988-89, thus making the total figure of 72 institutions.

5.9.8 A project report on National Open School has been prepared which is under examination. A decision on setting up the National Open School will be taken shortly.

Integrated Education for the disabled children

5.10.1 The National Policy on Education, 1986 lays emphasis on integrated education of disabled children with mild handicaps in common schools alongside the normal children with the objective of preparing such children for normal growth and to enable them to face life with courage and confidence. The old Scheme of Integrated Education for the Disabled Children has been thoroughly reviewed and revised during 1987-88 in the light of the guidelines given in the NPE and the Programme of Action prepared for implementation of the NPE. Under the scheme, 100% financial assistance is provided to the State Governments/UT Administrations/Voluntary Organisations for creating necessary facilities in the schools. Disabled children are given various kinds of facilities like books and stationery allowance, transport allowance, uniform allowance, readers allowance (for blind children), escort allowance (for severely orthopaedically—handicapped children with lower extremities disabilities), equipment allowances and hostel charges (wherever necessary). Besides, the scheme also provides for meeting the cost of salary and incentives for teachers, setting up of resource rooms and assessment rooms, training of teachers, removal of architectural barriers in schools, development and production of special instructional materials for disabled children, etc. Assistance is also given through UGC to selected universities/institutions for running training courses in special education for teachers of the handicapped children. Training facilities are provided by NCERT and Regional Colleges of Education.

5.10.2 The scheme is, at present, being implemented in 18 States and two Union Territories viz. Andhra Pradesh, Bihar, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Mizoram, Nagaland, Orissa, Punjab, Rajasthan, Sikkim, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Delhi and A & N Islands. During the year 1987-88, Central assistance amounting to Rs. 2.36 crores was sanctioned to various States/UTs and UGC.

Reimbursement of Tuition Fees charged from Girls in Classes IX-XII in all the States/UTs

5.11.1 The President of India in his Address to the Joint Session of the Parliament had announced on 17th January, 1985 that girls' education upto class XII will be made free throughout the country. In pursuance of this, a scheme for reimbursement of tuition fees charged from girls at secondary/senior secondary stage of education in Government/ Government Aided/Local Body schools to the States/UTs was formulated. The year 1982-83 has been taken as cut off year under this scheme.

5.11.2 The scheme was effective from 1.4.1985 and will remain in operation for the entire period of the seventh Five Year Plan.

Educational Concessions to the Children of Officers and Men of Armed Forces killed or disabled during Hostilities

5.12.1 The Central Government and most of the State Governments and Union Territories continued to offer educational concessions to the children of defence personnel and para-military forces killed or permanently disabled during Indo-China hostilities in 1962 and Indo-Pakistan hostilities in 1965 and 1971.

5.12.2 These concessions have been extended to the children of IPKF/CRPF personnel who were killed/disabled during action in Sri Lanka and to the children of Armed Forces personnel killed/disabled in action in Operation Meghdoot in Siachen Area.

5.12.3 In the year 1987-88, 16 students availed of such concessions.

Promotion of Yoga

5.13.1 Taking cognizance of potentialities of yoga in promotion of physical fitness, the Ministry of Human

Resource Development has been implementing, since the Second Five Year Plan a Scheme for Promotion of Yoga as a part of Ministry's over-all programme for development of physical education in the country. The scheme provides for financial assistance to yoga institutions of all-India character for maintenance as well as developmental expenditure on promotion of basic research and/or for teacher training programmes in the various aspects of Yoga other than the therapeutical aspects. Financial assistance to Yoga institutions for promotion of yoga therapeutical aspects is being extended by the Ministry of Health & Family Welfare.

5.13.2 The Kaivalyadhama Shriman Madhava Yoga Mandir Samiti, Lonavala (Pune), continues to be assisted under the scheme, both for its maintenance and developmental expenditure for research and teacher training programme.

5.13.3 Yoga was introduced in Kendriya Vidyalayas on an experimental basis as a separate subject for a period of one year in 1981-82. The experiment has since been evaluated and the KVS has decided to teach yoga in all KVs on regular basis. In the light of the directives of NPE, it is proposed to introduce yoga in schools on a fairly large scale. Accordingly, it has been decided to start a Centrally sponsored scheme for assisting schools and training institutions from 1988-89

Assistance to Agencies for Strengthening Culture/Art/Values in Education and Assistance to Educational Institutions Implementing Innovative Programmes

5.14.1 One of the guiding considerations in the management of education is giving prominance to people's involvement including association of non-governmental agencies and voluntary efforts for giving impetus to innovative ideas and practices in the field of education and culture.

5.14.2 The National Policy on Education 1986 also stipulates that education about India's cultural heritage should be strengthened and creative activities like art education etc. should be emphasised. Within this overall objective a Central Scheme for assistance to agencies for strengthening Culture/Art/Values in Education and for assistance to educational institutions implementing innovative programmes has been formulated in 1987.

The specific objectives of the schemes are :—

— strengthening cultural input in the educational content and process;

— strengthening value education in the school system, and

— implementation of pioneering or innovative programmes at the school stage.

Assistance is provided for the following purposes :

— Development of learning materials, instructional/ learning aids;

— Teacher training;

— Meetings, conferences, seminars to promote innovation and experiments;

— Innovative and experimental projects of national importance.

— Activities/programmes interlinking education with culture/art/value education activities.

— Development of infra-structure in schools assisted for innovative programmes.

5.14.3 During the year, assistance has already been extended to the following organisations under the scheme :—

(a) Ramakrishna Institute of Moral & Spiritual Education, Mysore for organising courses of in-service training of teachers of high schools in the teaching of Moral & Spiritual Education.

(b) Olcott Memorial School, Madras for giving integrated education and training in livelihood skills, physical training, and also to provide free nutritious noon meals, free books and free uniforms to a large number of students, mostly from Scheduled Caste/ Scheduled Tribe communities.

(c) Alarippu, New Delhi for organising workshops with students particularly girl guides, slum youth etc., training workshops for anganwadi workers, production of video films on women etc.

(d) Chorus Repertory Theatre, Imphal for use of theatre in Education and puppetry.

(e) Kasturba Gandhi National Memorial Trust, Indore for charitable activities for the general welfare of poor and needy women and children in the rural areas.

(f) Spic-Macay, New Delhi for promoting traditional Indian culture among the Youth

Education Secretary, Shri Anil Bordia with Children of Navodaya Vidyalaya, Leh (J&K)—after their participation in Republic Day Pageant, 1989.

1989

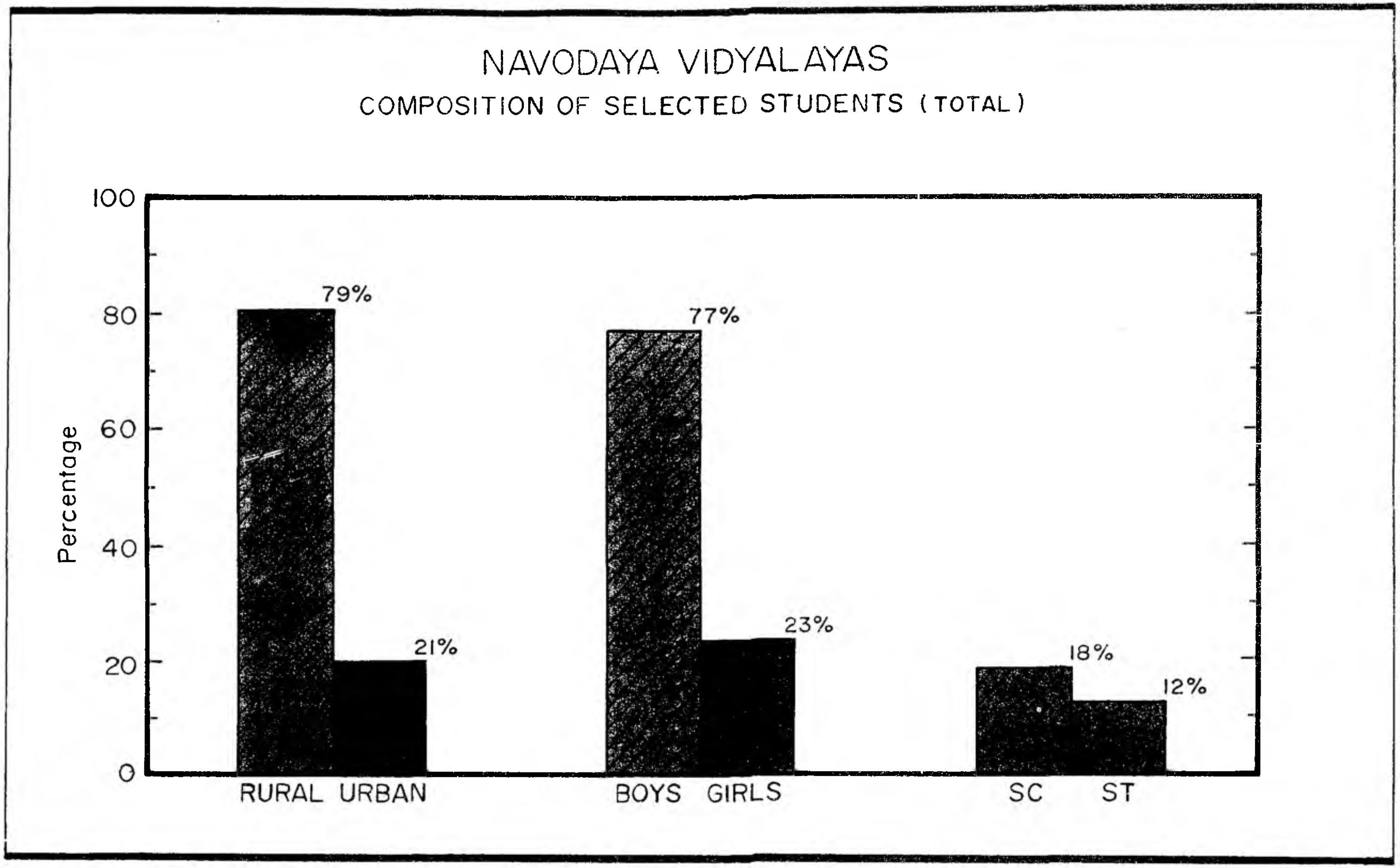
NAVODAYA VIDYALAYAS
COMPOSITION OF SELECTED STUDENTS (TOTAL)
100
80
60
40
20
0
Percentage
79%
21%
77%
23%
18%
12%
RURAL URBAN
BOYS GIRLS
SC ST

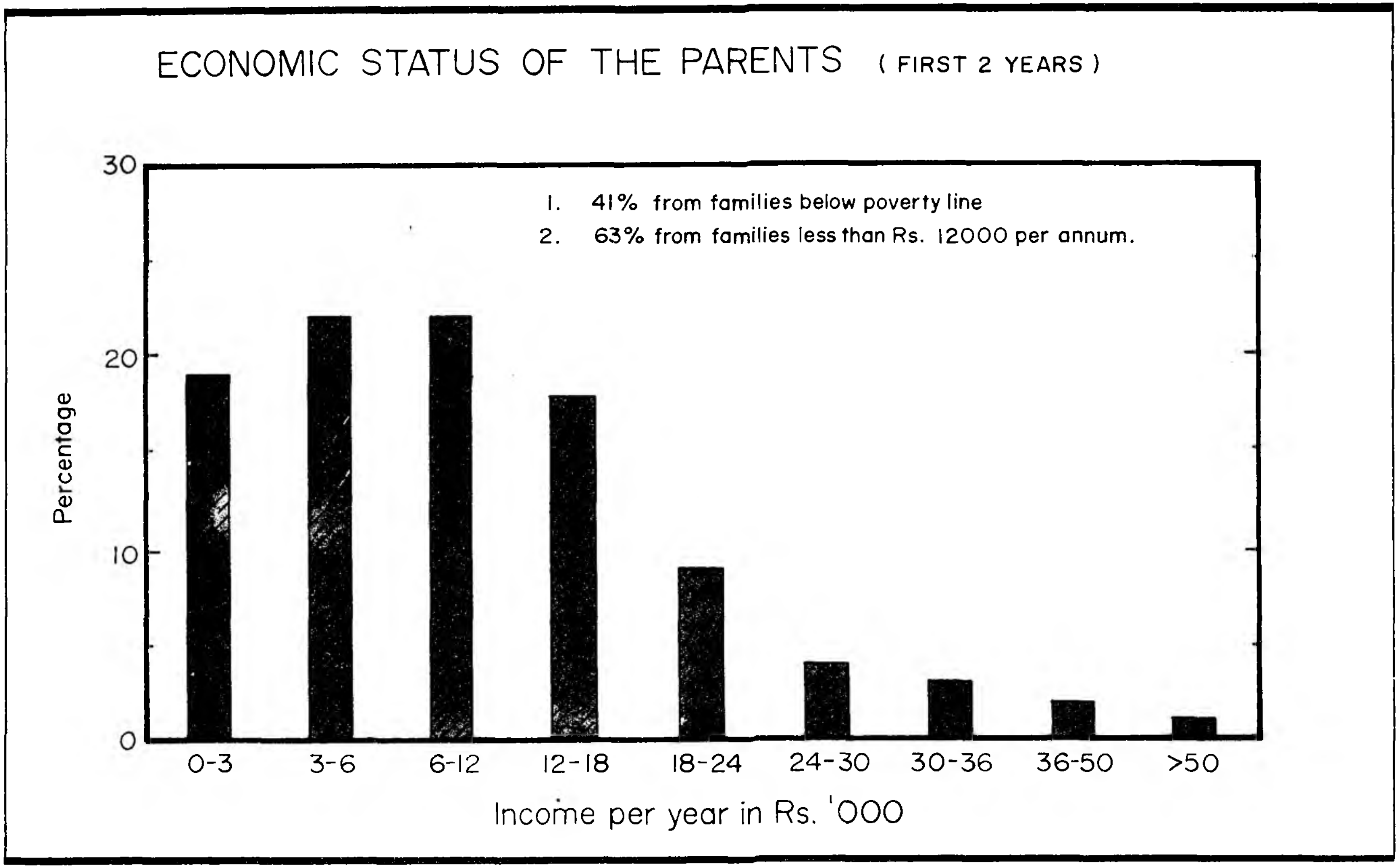
ECONOMIC STATUS OF THE PARENTS (FIRST 2 YEARS)
1. 41% from families below poverty line
2. 63% from families less than Rs. 12000 per annum.
Percentage
30
20
10
0
0-3
3-6
6-12
12-18
18-24
24-30
30-36
36-50
>50
Income per year in Rs. '000

of the country, the chief medium of which is classical Indian Music and Dance.

(g) The Centre for Cultural Resources & Training, New Delhi for preparation of a series of supplementary instructional material for school children on various aspects of Indian Culture.

(h) The Director of School Education, Nagaland for strengthening cultural inputs in educational content and process in schools through development of learning materials & instructional aids in local dialect.

National Population Education Project (NPEP)

5.15.1 Realising the potential of education in tackling the problem of growing population, the Ministry of Human Resource Development, Government of India launched the National Population Education Project with effect from April, 1980. The first cycle (1980-85) of the project has successfully been completed. The second cycle has been started w.e.f. 1st January, 1986. The Project being implemented in 26 States and Union Territories has completed third year of second cycle. The Project has been developed in collaboration with the United Nations Population Fund (UNFPA) and with the active involvement of Ministry of Health and Family Welfare which is the nodal Ministry for Population Education.

5.15.2 The main objectives of the programme are:

(i) to give students an insight into inter relationships between population growth and the process of social and economic development at the individual family society, national and international levels;

(ii) to make the children and teachers aware of the population situation in the country and targets and efforts of the Government of India in solving this problem;

(iii) to institutionalise population education in the formal education system, including universities and non-formal education programmes at the national and state levels;

(iv) to develop desirable attitudes in the teachers and students as well as the community at large towards population issues so that they make rational decisions about their family size and the quality of life that they would like to have.

5.15.3 During the Seventh Five Year Plan, the scope of the project has been expanded to cover the students and teachers at the plus two stage (Classes XI & XII) which is considered to be a very crucial target group in view of the impending entry of the students of this stage into the reproductive age-group. The financial and other inputs required by the States for implementing the projects are provided by the Ministry of HRD through NCERT The NCERT provides the technical assistance.

5.15.4 The project activities carried out by States and Union Territories focussed on development of materials for plus two-stage, non-formal education sector and training of different target groups, orientation of teachers and instructors on non-formal education centres, evaluation of different components of the project and co-curricular activities. The efforts of Population Education Cells in respect of integration of Population education elements into textbooks being revised were circumscribed by the delay in the initiation of the revision of textbooks in majority of States.

5.15.5 By the end of 1987-88 as many as 18 States and Union Territories completed the activity of development of curriculum on population education for plus two-stage. These documents will facilitate the integration of population education elements into the syllabi and textbooks being revised in the wake of implementation of NPE 1986. Sixteen States/UTs have incorporated population education elements into the syllabi. Fifteen States and UTs have developed curriculum in population education for non-formal education sector and eight of them have been able to integrate these elements into the on-going syllabi. Twenty States have developed curriculum for elementary teacher training and fourteen of them have incorporated population education elements into ongoing syllabi. The number of titles brought out on instructional and training materials on Population education during the current year was 435 as against last year's number of 367. States and Union Territories have published 21 titles for non-formal education sector. Fourteen States/UTs have brought out 41 supplementary reading materials for different stages and thirteen States/UTs brought out regular issues of Newsletter. A total of 403 programmes have been broadcast on AIR so far. Sixteen programmes on population education were telecast during the current year. Eighteen States/UTs have developed non-projective aids like posters, charts, flip charts, etc. and nine states have developed audio visual material on population education. During the year, States/UTs have oriented 1,04,971 teachers, 1761 key and resource persons and 9595 instructors of non-formal education sector. Under

Massive Teacher Orientation Programme organised in the wake of NPE about 5,00,000 teachers were oriented during May-August, 1988. Fifteen States/ UTs have conducted various types of co-curricular activities, such as essay competition, painting competition, quiz competition, elocution competition, etc. Under village adoption programme, 17 States/ UTs have adopted 137 villages where population education activities are being conducted.

Cultural Exchange Programme in the Field of School Education

5.16.1 The programme is being implemented by the Ministry in consultation with NCERT/State Governments etc.

5.16.2 During the year 1988-89, a team of 5 Indian students visited USA under Indo-US Student Exchange Programme and a team of 10 American students visited India on reciprocal basis.

Review of School Text Books

5.17.1 The Government of India had since 1981, initiated a programme of evaluation of school textbooks from the standpoint of National Integration. It is being implemented on a decentralised basis by the State Governments on guidelines prepared by the NCERT. To begin with, the review was confined to textbooks in History and languages. This programme is being undertaken with a view to promote a sense of National Integration among the students and also to identify and eliminate materials and approaches which may directly or indirectly perpetuate untouchability, recialism, regionalism, casteism, communalism, etc. The first phase of the programme has been completed in almost all the States/UTs.

5.17.2 In the second phase, the States/UTs have been requested to undertake the programme of evaluation of school textbooks in Geography, Civics, Political Science, Sociology, Economics etc. Most of the States have informed that in view of the expected changes in the curriculum in the light of the New Education Policy, 1986, new textbooks and other instructional materials have to be developed and therefore, the programme has been deferred. However, some States like Maharashtra, Gujarat, Tamil Nadu, Mizoram and the Union Territory of Delhi, have already completed the work. Haryana has also undertaken the programme of evaluating their new textbooks upto class VIII.

5.17.3 The States/UTs have also been requested to have a built-in system for continuous evaluation of textbooks as part of the system of textbook preparation and development. The NCERT has further initiated a programme of evaluation/review of some textbooks from States/UTs every year on a sample basis with a view to identify materials prejudicial to national integration and also to highlight materials that promote the ideals of national integration. The Council is organising orientation programmes for selected textbook authors from States. The Government of India is, at present, considering a proposal for setting up a Steering Committee to ensure that the work of review is continued systematically in the states.

National Awards to Teachers

5.18.1 The Scheme of National Awards to Teachers was started in the year 1958-59 with the object of raising the prestige of teachers and giving public recognition to their meritorious services. In 1967-68, the scope of the scheme was enlarged to cover the teachers of Sanskrit Pathshalas, Tols etc. run on traditional lines. In 1978, the scheme was further enlarged to cover Arabic/Persian teachers of Madrasas run on traditional lines. On the basis of recommendations received from National Commission on Teachers, the award money for the teachers was increased from Rs. 2,500 to Rs. 5,000 per award from the year 1987-88. Besides, the number of awards given to teachers under the scheme has been increased from 186 to 300 from the year 1988-89. Out of a total of 186 awards, 163 teachers were selected for National Awards during 1987. These teachers were given National Awards by the President of India at a special function on 5th September, 1988. For 1988, 200 teachers have so far been selected. These comprise 124 primary teachers and 76 secondary teachers from the States/UTs of Andhra Pradesh, Assam, Arunacha Pradesh, Bihar, Goa, Gujarat, Karnataka, Haryana, Orissa, Punjab, Meghalaya, Mizoram, Sikkim, Tamilnadu, Tripura, A & N Island, Chandigarh, Dadar & Nagar Haveli, Delhi, Pondicherry, CBSE and Kendriya Vidyalayas. Selection from the remaining States/UTs is in process. The scheme is proposed to be continued in 1989-90 also.

National Foundation for Teachers' Welfare

5.18.2 The National Foundation for Teachers' Welfare was set up in 1962 under the Charitable Endowments Act, 1890. The main objective of the Foundation is to provide relief to teachers and their

dependents who may be in indigent circumstances. Funds of the Foundation are consolidated from contributions made by the Union, State Govts/UTs and Kendriya Vidyalaya Sanghathan and the collections made by the States/UTs/KVS. The rules of the Foundation have been revised. The corpus of the Foundation have been invested in Fixed Deposits and the interest earned thereon is utilised for granting financial assistance for the following purposes:

— Construction of Shikshak Sadan

— Paid holiday to eminent teachers who have rendered meritorious service

— Support for professional education of children of school teachers

— Medical reimbursement to teachers suffering from serious ailments

— Gratuitous relief in cases of serious accidents

— Subsidy for academic activity of teachers

— Excursion Tour of Teachers in connection with the 40th Independence Celebrations and Jawaharlal Nehru Centenary Celebrations.

5.18.3 Besides the above, the Foundation awards Prof. D.C. Sharma Memorial Award to three teachers with distinguished service of not less than 30 years working in any recognised primary, middle, secondary and higher secondary school and whose service is free from blemish.

5.18.4 During the year, financial assistance from the Foundation has been granted as under:

— A sum of Rs. 10,000/- was paid to the wife of a deceased teacher serving in Kendriya Vidyalaya, Sector IV, R.K. Puram, New Delhi.

— A sum of Rs. 60,000/- (Rs. 10,000/- each) was paid to six teachers from Orissa State towards medical reimbursements.

— A sum of Rs. 84,350/- was paid to 43 eminent teachers hailing from Orissa State for paid holidays.

— 'Financial assistance' for construction of 'Shikshak Sadans', was approved in the following cases:

   * Rs. 6 lakhs for the All India Primary Teachers' Federation for completing the 'Shikshak Bhavan at Janak Puri, New Delhi.

   * Rs. 20 lakhs for construction of Shikshak Bhavan at Pune.

   * Rs. 50 lakhs for construction of five Shikshak Bhavans at Sanchi, Khujrao, Shivpuri, Mandav and Bharaghat all in Madhya Pradesh.

— In support of proposals received from different State Govts/UTs for granting financial assistance for the 'Excursion Tour of Teachers in connection with the 40th Independence Celebrations and Jawaharlal Nehru Centenary Celebrations.

— Prof. D.C. Sharma Memorial Award for 1988 has been given to the following three teachers.

   * Smt. Kamla Radhakrishnan,
     Headmistress,
     Govt. Higher Secondary School,
     Egmore, Madras.

   * Smt. Zaheda Ahmed,
     Asstt. Teacher,
     Govt. Girls High School,
     Berhampur.

   * Sri Jawaharlal Shrivastava,
     Headmaster,
     Govt. Primary School,
     Jawahar Nagar, Gwalior.

Kendriya Vidyalaya Sangathan

5.19.1 The scheme of Kendriya Vidyalayas was approved by the Government in 1962 on the recommendation of the Second Central Pay Commission for catering to the educational needs of the children of transferable Central Government employees including defence personnel who were liable to frequent transfers. A second important objective of the scheme was to promote national integration. Towards accomplishment of these objectives, KVs have the same flag, syllabus, textbooks, media of instruction, and colour of the uniform of children all over India. This policy is also reflected in staff recruitment. At present, 729 KVs are functioning under the K.V.S. as against 690 as on 30.4.1988. These Vidyalayas are controlled at the national level by the KVS which is an autonomous body under the Union Ministry of Human Resource Development. For administrative convenience, the KVS has been divided into 15 regions.

5.19.2 The KVs are making concerted efforts to improve the quality of education. The results of the KVs in Central Board of Secondary Education examination in 1988 were higher by about 9% and 16% respectively in the AISSE & AISSCE. About 15% students secured more than 75% marks and about 40.00% students secured marks between 60 to 74%. Thus 55.00% students secured first class marks. Kendriya Vidyalaya students secured highest marks in Hindi Elective, Hindi Core, Commerce, Mathematics, Chemistry and Biology this year.

5.19.3 The KV students participate in activities like NCC, scouts and Guides, Community Singing, Trekking and Rock Climbing, Sports and Games etc. About 10,000 students are trained in rock-climbing and a large number are sent for trekking every year. The KVS organised its National Sports Meet in Delhi from 11th to 20th October, 1988 in which about 3500 students from all the 15 regions participated. Earlier, during May-June, 1988, summer coaching camps in 9 games and athletics were organised. About 350 selected students were given intensive coaching. During November and December, 1988, KVS National teams participated in the SGFI meets in Football, Hockey, Volleyball, Badminton, Table Tennis, Basketball, Cricket and Athletics. Coaching Camps were held for these teams prior to their participation in the SGFI meets. The KVS State Rally of Scouts & Guides was held in Bombay from 28 to 31 December, 1988 in which about 1200 Scouts and Guides participated.

5.19.4 In accordance with the rules, fifteen per cent and seven and half per cent of the fresh admissions in every K.V. are reserved for the children of employees belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes, respectively. Efforts were made to admit scheduled caste/Scheduled tribe candidates upto this percentage in each KV, if necessary by relaxing the qualifying standards. In order to achieve the goal of admitting cent per cent SC/ST candidates against the reserved seats, it has been decided to advertise admission of SC/ST candidates in KVs indicating the percentage of seats reserved for them through leading national/ regional newspapers at the time of admission.

5.19.5 The Sangathan continued to organise programme for improving the efficiency of its staff, teaching and non-teaching, through conference and in-service education courses. During the year 1988-89, 111 in-service education courses for various categories of staff were conducted. Out of these, one was an induction course for Vice-Principals and PGTs who were selected as Principals. The course, which was conducted from 25th January, 1988 to 23rd April, 1988, was held before the participants joined duty as Principals in their respective Vidyalayas. Four teachers have been deputed to UK in connection with the English Language Teaching Project of the British Council being held from January, 1989 to April, 1989. All expenses in this regard will be paid by the British Council.

5.19.6 Advertisement for the posts of teachers for all KVs is made on all India basis and the conditions of service of teachers in all parts of the country are the same. Seniority lists are also prepared and promotions effected at all India level. Recruitment for the post of PGTs, Vice-Principals, Principals and other higher posts for all KVs are made centrally whereas for the posts of TGTs, PRTs and other categories of teachers, recruitment is made on all India basis at the regional level. Age relaxation by 5 years for applicants in North Eastern Region and Kashmir State and upto 6 years for residents of Assam is given with a view to ensure availability of teachers from these regions. Similarly to promote women's education and to attract them into teaching profession, relaxation in age by 10 years in respect of women candidates for recruitment in all categories of teaching posts has been permitted from 1987-88.

5.19.7 The KVS has started the implementation of three language formula in KVs with effect from December, 1988. Under this formula, Hindi and English will be taught as compulsory languages from class I to class X as at present. In non-Hindi-speaking States, the KVS will teach the regional Language of the States in which they are located. In Hindi-speaking States, majority of Kendriya Vidyalayas would teach one of the South-Indian languages as the third language, whereas the remaining Vidyalayas would teach one of the other modern Indian Languages.

5.19.8 The pilot project on computer literacy and studies in schools which was started in 1984-85 in 17 selected KVs was continued in the year 1988-89. The main objects of the project are:

— to provide students with a broad understanding of computers and their use, and

— to familiarise the students with the range of computer applications in all walks of human activity and computer's potential as controlling and information-processing tool.

The total number of KVs covered under this project was 309 as on 30.4.1988.

5.19.9 The Sangathan has constructed buildings for 164 KVs and 50 more buildings are under construction during the year. So far, construction of staff quarters in 72 Vidyalayas has been completed. Staff quarters are under construction in 102 KVs.

5.19.10 Keeping in view the great demand for Kendriya Vidyalayas, it has been decided to open 50 new Kendriya Vidyalayas annually in the Defence and Civil Sectors during the period 1987-90. It has also been decided to open new Kendriya Vidyalayas in the Project Sector as per norms and suitability of proposals. In pursuance of this decision, the Kendriya Vidyalaya Sangathan has issued orders for opening of 42 Kendriya Vidyalayas including 11 in project sector during the year 1988-89.

5.19.11 Having completed 25 years of their existence in the year 1988-89, the Kendriya Vidyalayas are celebrating their Silver Jubilee this year.

Central Tibetan Schools Administration

5.20.1 The Central Tibetan Schools Administration (CTSA) was set-up as an Autonomous Organisation in 1961 and registered under the Societies Registration Act (Act XXI of 1860). The object of the Society is to run, manage and assist institutions for the education of the children of Tibetan refugees who had fled to India in the wake of Chinese onslaught in Tibet in 1959 and taken asylum.

5.20.2 The Administration is running 30 schools out of which four are residential schools and 26 are day schools. The schools are scattered all over India. The enrolment in the schools is above 10,000. These schools are affiliated to CBSE and prepare students for All India Secondary School and Senior Secondary School Examination.

5.20.3 The Administration also provides facilities to Tibetan children for pursuing post-school education. Fifteen school scholarships are awarded to the students passing out of CTSA Schools every year. Eight seats have been allotted by Government of India for Tibetan Students in technology, medicine, printing and pharmacy.

5.20.4 To further the cause of education of the Tibetan children, the Administration is also providing financial assistance to schools run by other agencies/organisations like Council for Tibetan Education, Bureau of His Holiness The Dalai Lama, Special Security Frontier Education and Tibetan Nehru Memorial Foundation. There are thirteen schools which are receiving grant-in-aid from the Administration.

5.20.5 The CTSA has been making concerted efforts for improving the efficiency of teachers through In-Service Education Course. During the year, the Administration has arranged In-Service Course for Primary Teachers at Bylakuppe for 10 days from 31st December, 1988 to 9th January, 1989. The CTSA have developed its own faculty to provide In-Service Teaching Course to the teachers.

5.20.6 All the seven Senior Secondary Schools under the Administration are covered under CLASS Project and have been provided computers. To give impetus to the co-curricular activities and to inculcate and foster the spirit of co-operation, help, co-ordination and healthy competition amongst students the Administration has decided to celebrate Foundation Day centrally every year. For the first time, Foundation Day was celebrated at Mussoorie from 5th to 7th September, 1988. It has provided an opportunity to teachers working under the Administration to gauge their performance. This meet also provided an opportunity to children to exhibit their talents.

5.20.7 During the year, schools at Mundgod & Kalimpong were upgraded to Senior Secondary level. Keeping in view the national priorities and the need of Tibetan children, two vocational courses—Typewriting and Shorthand have been introduced at +2 level at CTS, Mundgod.

5.20.8 The results of the Administration during the year were as follows:—

- All India Secondary School Examination, 1988: 74.7%
- All India Sr. School Certificate Exam., 1988: 84.5%

Central Board of Secondary Education (CBSE)

5.21.1 The Central Board of Secondary Education is a society registered under the Societies Registration Act and is an autonomous organisation. The major functions of the Board are to affiliate institutions; to conduct examinations at the Secondary and Senior Secondary levels or other examinations as are entrusted to it and developing and up-dating curriculum and textual materials.

5.21.2. The Headquarters of the CBSE are situated in Delhi. An eleven storyed building of the CBSE is under construction in Preet Vihar, Delhi which is expected to be ready for occupation by March, 1989.

To facilitate and coordinate the activities of the affiliated schools in the Southern and North Eastern Regions, Regional Offices of the Board were set up at Madras in 1981 and Guwahati in 1986. As a long term welfare measure, the Board purchased 109 built up flats for about 25% of its employees at a short distance from the new building.

5.21.3 The number of CBSE affiliated schools as on 30-11-1988 stood at 2,652 which includes all the Government and Govt. aided schools of UTs of Delhi, Chandigarh & A&N Islands and states of Arunachal Pradesh and Sikkim, all Kendriya Vidyalayas, Navodaya Vidyalayas, Military Schools, Sainik Schools, Tibetan Schools, Schools run by public sector undetakings, public schools and other independent schools from all over the country and 44 schools abroad. The essential norms for affiliation laid down with regard to land, building, qualified staff, salaries etc. are being strictly adhered to in order to ensure that only those schools which have reasonably good standards are affiliated with the CBSE. With the observance of these essential requirements, the quality of schools has improved. Periodic inspection of affiliated schools was also intensified and instructions issued to remove deficiencies. Affiliation Bye-laws have been sent to schools for their guidance.

5.21.4 During the year, the Board conducted 13 examinations smoothly and effectively and the results released before the fixed schedule. The total number of candidates who took the major examinations in 1988 with pass percentage is given below:

	No. of Candidates	Pass %age
All India Senior School Certificate Examination, March, 1988	53456	83.2%
Delhi Senior School Certificate Examination, March, 1988	50843	82.8%
All India Secondary Examination, March, 1988	100303	80.4%
Delhi Secondary Examination, March, 1988	93262	66.7%
Open School Examination,		
November, 1987	09075	
May, 1988	13894	

5.21.5 The first pre-medical, pre-dental entrance examination on behalf of the Ministry of Health and Family Welfare and J.B.T./N.T.T. entrance examination on a request from the Delhi Administration were successfully completed in the year under report Results of both the examinations were declared in time.

5.21.6 The Central Board of Secondary Education undertook an English Language Teaching (ELT) Project in collaboration with the British Council. This is aimed at improving teaching-learning in English Course 'A' at the Secondary stage in the Board's affiliated schools. It is a comprehensive educational project which covers four important components—curricular development, material production, improvement of examinations, English language teaching.

5.21.7 The CBSE prepared a monograph on 'National Integration Through Schools' which is an attempt to describe how schools can help in promoting National Integration among children and how the objectives of National Integration can be made a part and parcel of their general ethos.

5.21.8 The Board encouraged the schools to join school complexes to share their resources for bringing out qualitative changes in the system by introducing innovations in various areas. Major activities undertaken by these complexes were—training programmes for the professional development of teachers; mobilisation of physical and academic resources for mutual benefit; conducting Sports Meets both for the students and the staff, and promotion of activities aimed at achieving National Integration.

National Council of Educational Research and Training

5.22.1 The National Council of Educational Research and Training (NCERT) established on 1 September, 1961, is an autonomous organisation registered under the Societies Registration Act XXI (1860). The NCERT is resource institution. In the formulation and implementation of its policies and programmes in school education and teacher education, the Ministry of HRD draws upon the expertise of the NCERT.

5.22.2 During the period under report, the NCERT made sustained and concerted efforts for improving the quality of school education and teacher education in the country and played a key role in tasks directed toward the implementation of the National Policy on Education — 1986. The scheme-wise details are given below:—

Early Childhood Care and Education (ECE)

5.22.3 The NCERT undertook several activities directed towards strengthening the Early Childhood

Care and Education Programmes. Activities related to the development of materials of educational and entertainment value for children in the age group 3 to 8 continued under the Project 'Children's Media Laboratory (CML)'. Under the 'Early Childhood Education (ECE)' Project, 10 states were assisted in strengthening the early childhood education units, in training pre-school teachers and teacher educators and in the developing learning and play materials for early childhood education. The major thrust of the activities under the ECE Project has been on establishing linkages between ECE and the programmes under the Integrated Child Development Services (ICDS). Several progrmmes were conducted for ICDS functionaries. A State Level seminar on ECE with special reference to the convergence of ECE and ICDS was organised in Karnataka. Some non-print materials for ICDS Centres were developed by Rajasthan. In Orissa about 8,000 Anganwadis were supplied with picture books and other play materials developed by NCERT. Under the ECE Project, an orientation course for resource persons and two meetings of ECE Project Coordinators from the states participating in the project were organised and four titles were brought out under the Instructional Materials Series for teachers, teacher educators and parents. In addition to these, a study on enrolment and retention in relation to pre-school experiences was launched in August, 1988 in 10 states participating in the ECE Project. As part of the effort to evolve an alternative approach to early childhood stimulation, a home-based programme in child development was tried out in tribal and urban slum areas in Orissa. Two festivals were organised in the areas of health and nutrition alongwith regular activities related to health and nutrition education for children in classes IV and V. Under the Early Childhood Education Project being implemented in schools of Municipal Corporation of Delhi, an Orientation Programme on play-way method and activity approach was organised for teachers of Class III. A radio feasibility study was launched by the NCERT in collaboration with the All India Radio Station at Kota in October, 1988 with the objective of using radio as a medium of providing enriching learning experience to the children of Anganwadis and of Classes I and II in primary schools. The NCERT organised toy-making competitions in 31 States and UTs through its Field Offices. The first prize winners of the State Level toy-making competition participated in a national workshop-cum-competition on toy making organised by the NCERT from 19 to 23 Dec., 1988. In addition to these, a workshop was organised to identify educational toys for pre-school blind children.

UEE oriented activities

5.22.4 Norms and specifications related to various items were finalised by the NCERT in collaboration with the Bureau of Indian Standards. A document entitled 'Operation Black Board : Essential Facilities at the Primary Stage—Norms and Specifications' was finalised and published for wider dissemination in the States/UTs.

5.22.5 As part of the work on the 'Study of Enrolment, Retention, Stagnation and Pupil's Achievement' undertaken under the project "Primary Education Curriculum Renewal" (PECR), the data collected from the States were analysed and a report entitled 'Pupil Achievement at the Primary Stage' was brought out. The collection and consolidation of data in respect of two studies, namely, 'Study of Pupil Achievement' and 'Impact of Community Contact Programme' under the Project "Nutrition, Health Education and Environmental Sanitation (NHEES)" were completed. Under the Area-Intensive Education Project for Human Resource Development (AIEP), NCERT organised an orientation course for the key personnel at the state level on the concept and strategies of the project. During the year under report, the project was implemented in six states and one union territory—Maharashtra, Mizoram, Orissa, Rajasthan, Tamil Nadu, Uttar Pradesh and Dadra and Nagar Haveli. The project aims at promoting integration of pre-school, primary, non-formal and adult learning activities in the community to achieve universalisation of elementary education. The key components of the project implementation include area-intensive approach, convergence of activities and resource inputs, community participation in decentralised planning and management, flexibility in all aspects of its implementation and priority to educationally backward areas and population sectors.

5.22.6 Under the project "Comprehensive Access to Primary Education (CAPE)", activities related to the development of learning materials (learning episodes) and establishment and management of learning centres for the education of out-of-school children continued. During the year 1988-89, the Project was implemented in 17 States. Six modules including a set of charts on environmental studies were printed and sent to all the learning centres established under the project in the Hindi speaking States of Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan and Uttar Pradesh. Learning materials developed under the Project were also sent to seven prominent voluntary organisations for use in

NFE Centres run by these organisations. The Council provided technical support to the States participating in the project for the development of learning materials, training of facilitators of learning centres, development of Question Banks, etc.

5.22.7 The NCERT undertook several activities to support the Centrally Sponsored Non-Formal Education Programme. The main thrust of the activities has been on the development of instructional materials and appropriate teaching-learning evaluation strategies suited to the Non-formal education programmes. The research activities undertaken include development of tools and techniques for evaluation of children's achievement at entry point, a study of the selected NFE Centres at the primary level to bring out success stories of the Centres and an analysis of curriculum and instructional materials developed for NFE Programmes in different states/union territories. The new instructional materials developed include Mathematics-Book III for use in middle level NFE Centres, eight comic books for class III for use in primary level NFE Centre and teachers' guides and work book for Mathematics for use of instructors working in the middle level NFE Centres. The Council also developed a training manual for NFE instructors and NFE supervisors of the NFE Centres adopted by NCERT. The other activities undertaken include development of training materials for NFE supervisors, development of a film on teaching-learning and training methods relate to NFE, orientation programmes for resource persons involved in implementation of NFE Programmes and orientation programmes for NFE functionaries from voluntary organisations and NFE units in States/UTs.

Reorientation of the Content and Process of Education at the School Stage

5.22.8 NCERT undertook a series of coordinated measures for re-orientation of the content and processes of education at the school stage as envisaged in the National Policy on Education 1986. The major thrust of these measures was directed towards the introduction of the norms of minimum levels of learning for the different stages of school education, development of instructional packages based on the revised syllabi, development of child-centred learning strategies and activity-based teaching methods, training of teachers and other educational personnel to improve their professional competence, and examination reforms and introduction of continuous and comprehensive evaluation to improve the teaching-learning processes. Under the "Programme of Mass Orientation of School Teachers (PMOST)", orientation programmes for about five lakh school teachers is being done through NCERT and the State Governments since 1986 in order to increase the motivation and professional competence of teachers to better equip them to play their key role in the process of reorientation of the content and processes of education at the school stage. During 1988, about 4.6 lakh teachers were oriented under the programme. The content of the orientation programme was reviewed keeping in view the experience gained during the years 1986 & 1987. On the basis of the feedback received, the content of the orientation programmes conducted during the year 1988 was redesigned to include components directed to enhance the professional competencies related to teaching in different curricular areas in addition to the components for creating an awareness about the major thrusts envisaged in the NPE. For this purpose, a revised training package comprising separate volumes for primary school teachers and secondary school teachers were prepared. Guidelines for the faculty/resource persons of the orientation/training camps were also prepared. The television support to the programme was also strengthened by including certain new programmes related to the emerging curricular concerns. The orientation programmes conducted during 1988 were evaluated by three universities, namely, Kurukshetra University, Patna University and Pondicherry University, and based on the suggestions made in the evaluation reports, the content of the orientation programmes proposed to be conducted during 1989 has been further modified to make it relevant to the requirements of the teachers.

5.22.9 As part of the effort to reorient the content and processes of education at the school stage, steps were taken to improve the evaluation practices in schools. A scheme of comprehensive continuous evaluation evolved for circulation among SCERTs/ Departments of Education and Boards of Secondary Education in States/UTs was discussed in a two-week All India Training Course for Resource Persons organised from 22 June to 5 July, 1988. A sample cumulative card along with procedures for maintaining records of pupil's achievement in scholastic and non-scholastic areas has also been prepared. The NCERT also prepared guidelines for introduction of grading and scaling in examinations conducted by different Boards of Secondary and Higher Secondary Education and organised two regional meetings of the Chairmen/Secretaries of the Boards of Secondary Education from 7 to 9 September, 1988 and on 24 and 25 November, 1988. During these meetings, the

different aspects related to the introduction of scaling and grading in the examinations conducted by the Boards of Secondary and Higher Secondary Education were discussed. NCERT also organised an eight-day workshop for training key persons on alternative evaluation procedures, such as, oral examinations, open book examinations and project work. In addition to these, the Council continued its tasks of development of conceptual materials related to educational evaluation, preparation of criterion referenced tests and training of test item writers in different subject areas.

5.22.10 In order of facilitate implementation of the tasks related to the reorientation of the content and processes of education at the school stage, NCERT formulated a scheme under which financial assistance was provided to States/UTs for undertaking activities related to renewal of curriculum and development of instructional materials, including textbooks, in different curricular areas.

Science Education related Activities

5.22.11 As part of the work related to the implementation of the Centrally-sponsored Scheme for Improvement of Science Education in Schools, NCERT organised seven training courses for training science teachers in senior/higher secondary schools in Karnataka and Madhya Pradesh. During these training courses, the participants developed certain training materials which could be utilised in the subsequent training programmes to be conducted under the scheme. The other activities carried out by NCERT in connection with the implementation of the scheme include development of a manual for organising different training programmes under the scheme, and organisation of a one-work workshop to develop instructional materials for use in training programmes for higher secondary teachers in Uttar Pradesh, a three-day orientation programme for higher secondary teachers in Uttar Pradesh, and a three-day orientation programme for secondary teachers in Bihar. The Council also organised a meeting of the representative of the nodal agencies engaged in implementation of the scheme at the State/UT level on 31 October and 1 November, 1988, and provided technical assistance to the States/UTs to carry out the different tasks envisaged under the scheme.

5.22.12 The Council continued its activities related to development of science kits for primary and upper primary schools. The kit manuals for the Primary Science Kit and the Integrated Science Kit for upper primary schools have been printed. The other activities undertaken include a survey of teachers teaching science in schools in Madhya Pradesh and Uttar Pradesh and a survey of the Status of science kits and equipment in primary schools and elementary teacher training institutes in Madhya Pradesh and Uttar Pradesh conducted under the Indo-FRG project "Improved Science Eduction in Primary and upper Primary Schools in Madhya Pradesh and Uttar Pradesh", preparation of a detailed write-up on the construction, specification and drawings of the items in the science kits and preparation of a teacher's handbook.

5.22.13 As part of the efforts to strengthen the teaching of science in schools, NCERT developed teacher's guides, laboratory manuals, supplementary reading materials and popular science materials. The Seventeenth National Science Exhibition for Children was organised from 5 to 11 November 1988 at Jammu by the NCERT in collaboration with the Government of Jammu & Kashmir.

Computer Literacy - Oriented Activities

5.22.14 Several advanced level training programmes for school teachers were organised by the NCERT and other Resource Centres under the Computer Literacy and Studies in Schools (CLASS) Project. Training programmes were organised by the Resource Centres to train teachers from the new schools participating in the project. About 1325 teachers were trained under the project during 1988 The 53 Resource Centres established under the project provided technical support to the schools participating in the project. Necessary steps were taken to procure software packages for the new schools and to select indigenous software packages for use in the new schools participating in the project. In all, about 22 indigenous software packaged were approved for supply to the new schools.

Vocationalisation - Oriented Activities

5.22.15 The NCERT undertook several activities for providing necessary technical support to the States in the planning and implementation of various programmes related to vocationalisation of education at the higher secondary stage. Nine orientation programmes were conducted on vocationalization of education for key persons from the States already offering vocational education at the +2 stage as well as for key personnel from States which are planning to launch programmes for vocationalisation. Through these orientation programmes, about 300 key persons from the union territory of Delhi and the States of Himachal Pradesh, Kerala, Madhya Pradesh and the

States in the north eastern region were oriented. The Council continued its activities for development of Minimum Vocational Competencies-Based Curricula for different vocational courses and development of comprehensive guidelines for implementation of the different aspects of the programmes for vocationlisation of education. The Council developed a model curriculum in entrepreneurship, minimum competencies-based curriculum in printing technology and book-binding, instructional materials in different vocational areas and folders for popularising vocational courses.

Teacher Education - Oriented Activities

5.22.16 In the field of teacher education, the NCERT completed three research projects during the year under report. These include the Study of the Status of Teachers in India, the Study of the Relative Effectiveness of Different Training Strategies and the Study of the Relationship of Self-concept, Attitude and Adjustment of SC/ST and non SC/ST Student Teachers with their Achievement. The NCERT continued to act as the Secretariat for the National Council for Teacher Education (NCTE) and coordinated different activities of the NCTE. A significant activity undertaken was the revision of the document 'Teacher Education Curriculum—A Framework'. A Committee was constituted to prepare the draft of the revised curricular framework for teacher education. The draft framework prepared by this Committee was discussed in a National Conference on Teacher Education Curriculum held on 14 & 15 November 1988. Based on the suggestions made at this conference, the framework has been modified and finalised. Action was also initiated for evolving a design for the Four-Year Teacher Education Programme and a design for the training programme for teachers at the +2 stage.

5.22.17 The Council provided technical assistance to States/UTs for establishment of the District Institutes of Education (DIETs). It also undertook the task of revising the project document on DIETs.

5.22.18 The Four Regional Colleges of Education, (RCE) run by the NCERT, continued to offer the Four-year integrated teacher education programme leading to B.A. Ed. or B.A. B.Ed. Degrees and B.Sc. Ed. or B.Sc. (Hons/Pass) B.Ed. Degrees, the one-year B.Ed. course and the one-year M.Ed. Course. The RCEs at Bhubaneswar and Mysore also offered two-year M.Sc. Ed. courses. The RCEs organised several extension programmes/workshops/meetings/seminars on different aspects of school education and teacher education. In addition to these, each RCE also undertook research studies related to school education and teacher education. A number of scholars were provided guidance by the RCEs for their research work for Ph.D. Degree.

SC/ST related Activities

5.22.19 The NCERT continued its research and developmental activities directed to promote education of the scheduled castes and scheduled tribes. A comparative study of educational achievements of scheduled castes and non-scheduled castes students of Class-X in Uttar Pradesh was completed during the year under report. Activities under the evaluative study of prematric scholarship scheme for scheduled caste and scheduled tribe students continued. The report in respect of 11 States (scheduled tribes, cluster-I) was completed during the year. The draft report on cluster-I (scheduled castes) has also been prepared. The collection of data in respect of cluster-II (SC/ST States) is in progress.

5.22.20 The Council continued its tasks related to preparation of primers/textbooks in tribal dialects. A workshop was organised in November, 1988, to develop textbooks for classes I & II in tribal dialects and in Devnagri Script for five tribes of Bihar, namely, Santal, Mundari, Ho, Kharia and Kurku. These textbooks are being developed in collaboration with the Central Institute of Indian Languages (CIIL), Mysore. The other activities carried out include preparation of the draft of a Primer for Class-II for Gond tribal children in Andhra Pradesh and the draft of a Primer for Class-I for Irula tribal children in Tamil Nadu. The Primer for Gond tribal children is prepared in Gondi tribal dialect, using the Telugu script while the Primer for Irula tribal children is prepared in Irula tribal dialect using the Tamil Script.

Activities related to the Education of the Educationally Backward Minorities

5.22.21 The Council continued to provide technical as well as financial support to conduct training programmes for teachers and principals in schools managed by the educationally backward minority communities, particularly the Muslims, in order to improve educational standards in these schools. During the year under report, the Council organised four 3-day seminar-cum-workshops on guidance services for managers and principals of schools managed by the educationally backward minorities. Besides these, a refresher course for career teachers in schools managed by the educationally backward minorities was organised from 26 to 28 December, 1988. The Council also has been conducting career

teachers' training courses for teachers of the schools managed by educationally backward minorities.

Activities Oriented to Education for Women's Equality

5.22.22 The NCERT has initiated several programmes and projects for empowerment of women through education. A workshop was organised in collaboration with the Central Institute of Indian Languages for developing exemplar resource materials on education for women's equality. Another workshop was organised under a research project for evolving a school-based programme for promoting equality of the sexes. Other activities carried out include identification of indicators and strategies for operationalising women's education and development, development of course outline for a diploma course on education for women's equality, development of a course outline for a six-week training programme, and a study of the Mahila Mandals in Haryana to identify the process of empowerment. In addition to these, the Council organised four regional workshops and one national workshop to orient key persons from States/UTs to the process of identification and elimination of sexist bias from educational programmes and textbooks and monitoring and evaluation of educational programmes from the view point of education for women's equality. The Council provided technical assistance to the States/UTs to establish Centres/Units for women's studies and conducted awareness generation programmes for personnel from the States of Andhra Pradesh, Himachal Pradesh, Manipur, Rajasthan and Uttar Pradesh. The participants of these programmes included college principals, school principals, educational administrators and experts in the field of women's studies.

Activities oriented to Education of the Disabled

5.22.23 The NCERT undertook several tasks related to the implementation of the Programme of Integrated Education for the Disabled. Tools have been developed for identifying learning disability in both perceptual and productive areas. These tools are being tried out for finalising them. The Council organised 7 programmes for training teachers on the methodology of identification of the disabled children. These included three programmes for training teachers in Mustori Block in Madhya Pradesh, one programme for training teachers in Mizoram and three programmes for training teachers in Chabbra Block in Rajasthan.

5.22.24 The Council organised a workshop for identifying themes and preparing briefs for video programmes for the education of the disabled children. Briefs for video programmes on themes related to learning disability, hearing impairment, mental retardation and visual impairment were developed in the workshop. Another workshop on computer assisted teaching of the devanagri script for pupils with poor motor control development was organised. The Council also organised an exhibition-cum-workshop on educational toys and games. Participants included child development specialists, curriculum specialists, general teachers and toy manufacturers. In addition to these, a two-week attachment programme for functional assessment of disabled children was conducted. Eight participants from Mizoram and Tamil Nadu were trained. Besides these, a quarterly newsletter titled, "Communication-Equal Educational Opportunity for the Disabled" was brought out in order to share information with schools having programmes for the integrated education for the disabled.

Educational Technology Oriented Activities

5.22.25 Several activities directed towards the utilisation of educational technology, including the use of radio and television, for bringing about qualitative improvement of education and for widening access to education were undertaken by the Central Institute of Educational Technology (CIET) in collaboration with the State Institutes of Educational Technology (SIETs).

The CIET organised five training programmes with a view to creating competencies within the country in production of ETV programmes. The programmes organised during the year under report included training courses on Video Editing, ETV Production and Technical Operation, Camera and Sound Recording, Studio Production and BCN-51 Maintenance. The CIET finalised a detailed case study on INSAT for education project as a part of a project sponsored by the UNESCO, Paris, undertaken to analyse developments in distance education using large scale communication systems in Asian Countries.

Support Service for Navodaya Vidyalayas

5.22.26 The NCERT conducted the selection tests for admission to the Novodaya Vidyalayas for the acedemic session 1988-89. The total number of Navodaya Vidyalayas in 1988-89 was 256. Selection tests were administered in 18 languages and conducted at 3241 centres located in 2980 Community Development Blocks spread over 256 districts in the

country. The test booklets in 18 languages were printed centrally and distributed to various centres through the offices of the Field Advisers of NCERT. The total number of candidates registered for the selection test was 4,64,382 out of which 3,71,605 candidates appeared in the test. In all 14,769 candidates were selected for admission to the Navodaya Vidyalayas. Of these, 11059 (75 per cent) candidates were from rural areas while 3710 (25 per cent) were from urban areas. The selected candidates included 10,001 (68 percent) boys and 4768 (32 per cent) girls. Of the 14,769 candidates selected for admission to the Navodaya Vidyalayas, 1775 (19 per cent) belonged to the scheduled castes while 1638 (11 per cent) belonged to the scheduled tribes. On open merit 655 candidates belonging to the scheduled castes and 551 candidates belonging to the scheduled tribes were selected. In addition to the selection tests, the Council also conducted a study of the socio-economic status of the students and physical facilities in Navodaya Vidyalayas established upto 1986

Education Survey

5.22.27 The Council brought out the preliminary report of the Fifth All India Educational Survey. The reference date of the Fifth All India Educational Survey was 30 September, 1986. In the Survey, three questionnaires, namely, Village Information Form, Urban Information Form and School Information Form were canvassed. Through the first two questionnaires, the data was collected from all the villages and all the urban areas on availability of schools as well as facilities for preprimary education, non-formal education and adult education. Through the School Information Form, data was collected from all the schools on students, teachers, buildings, facilities, equipment, etc. available in them. The data was first compiled at block/tehsil level after which the district level tables were prepared from the block tables. The state level tables were prepared from the district level tables and finally at NCERT, the national tables were prepared from the state tables received from different States/UTs.

5.22.28 The Survey data are expected to be used for educational planning, particularly for formulation of the Eighth Five Year Plan in respect of educational development. The data are also expected to be used for micro planning exercises at the block level as well as for district level educational planning. Further they are expected to be of help in effective implementation of various schemes initiated in the context of the implementation of National Policy on Education—1986, such as the Operation Black Board Scheme and Vocationalization of Higher Secondary Education.

National Talent Search

5.22.29 The NCERT conducted the second-level test for the award of the National Talent Search Scholarship on 8 May, 1988. The first-level test was conducted by the States/UTs. The second-level test was conducted at 30 centres spread over the country and 3065 students appeared at the test. Of these 750 students, including 70 SC/ST students, were selected for the award of the scholarship.

Educational Psychology, Counselling and Guidance

5.22.30 The NCERT undertook several activities in the field of Educational and Vocational Guidance. A study of the Educational-Vocational Planning, Academic and Selected Psychological and Home-Background Variables of Tribal High School Students in and around Shillong (Meghalaya) was completed. The work under the research project on "Vocational Behaviour and Adjustment of Students in Academic and Vocational Streams at +2 Stage" and under the research project for "Development of Guidance Programme to Promote Self-Employment in Vocationalised Senior Secondary Schools in Delhi" continued during the year under report. The Council continued with its Diploma Course in Educational and Vocational Guidance.

5.22.31 The NCERT organised a National Symposium on Child-Centred Education and 160 eminent educationsts, psychologists, educational administrators etc. participated in the Symposium. The other activities undertaken include development of a manual of instruction for primary teachers and teacher educators on behaviour modification techniques in class room settings, development of a manual on learning for primary teacher educators and development of a handbook on nurturing creative potential in elementary school children.

Educational Research

5.22.32 The Educational Research and Innovations Committee (ERIC) of the NCERT continued to sponsor research projects on different aspects of school education and teacher education. During 1988-89, funds for six Departmental and five out-side research projects were provided. Ten Ph. D. theses were published with the financial assistance provided by ERIC. During the year under report, eight out-side and 27 Departmental projects were completed and 31 out-side and 39 Departmental Research Projects are in progress during the year under report.

5.22.33 The manuscript of the Fourth Survey of

Educational Research has been completed and sent for publication.

5.22.34 As part of the effort to improve the quality of educational research, the Council organised two regional seminars. The first regional seminar for the Northern region was held at the University of Kashmir, Srinagar. The second regional seminar for Southern region was held at Coimbatore.

Population Education

5.22.35 The NCERT initiated several measures to intensify the implementation of the National Population Education Project. Various developmental and training activities under the population education project were undertaken during 1988-89. A workshop was organised for the development of a compendium of lessons on population education. A national workshop on population education (Quiz Competition) was organized at Bangalore.

Publication of Instructional Materials and Journals

5.22.36 A very important activity of the NCERT has been the publication of textbooks, supplementary readers, workbooks, teachers' guides, research monographs, journals etc. During the period April to December, 1988, 216 publications under different categories were brought out. These included 160 textbooks, 9 supplementary readers, 3 teachers guides, 36 other publications and 8 issues of the journals. The Council launched certain new series of books in English and Hindi for use of students at different stages of school education. These include the Reading to Learn Series, the Lotus Series and the Padhen Aur Seekhein Yojna. The Council continued to publish 6 journals, namely **Indian Education Review** (a quarterly), **Journal of Indian Education** (a bimonthly), **School Science** (a quarterly), **Primary Teacher** (a quarterly), **Primary Shikshak** (a quarterly in Hindi) and **Bhartiya Adhunik Shiksha** (a quarterly in Hindi). The journal cell of NCERT organised a workshop from 14 to 16 June, 1988 for developing a Source Book on Educational Journalism. The Council also initiated activities related to the scheme of National Awards in Educational Journalism for the year 1988-89.

Library, Documentation and Information

5.22.37 The Department of Library, Documentation and Information of NCERT continued to support research and development activities of various departments and units of NCERT. The Department not only catered to the information needs of faculty members of NCERT but also of the research scholars and educationists from all over the country. It has a very good collection of books and periodicals in the field of education and psychology and curricular and reference material relating to all the school subjects. The department also continued to organise inservice training programmes for school librarians, teachers-incharge of school libraries and librarians of teacher training colleges. A workshop on development of teacher training libraries at elementary level was organised at Trivandrum from 12 to 16 December, 1988 and 38 participants attended this workshop. The Council also provided academic support to the Board of Secondary Education, Orissa in organising inservice training programme for school librarians/teachers-in-charge of school libraries from 9 to 18 December, 1988.

Community Singing

5.22.38 The NCERT continued to organise community singing camps to train teachers in the art and techniques of community singing During the period April to December, 1988, 11 State/regional level community singing camps and two national level and one state level choir singing camps were organised. Besides these, regional committees have been constituted for promotion of the community singing programme.

International Relations

5.22.39 The NCERT continued to play its role as a major agency for implementing the provisions of bilateral cultural exchange programme in the field of school education and teacher education. Delegates and experts from 13 countries visited the NCERT during the year under report. The Council organised two six-week training programmes for the faculty members of the National Institute of Education, Maharagama, Sri Lanka. It also organised a six month training programme for four women education officers from Somalia on different aspects of non-formal education under the ITEC programme. The Council further organised a 10-day fellowship training programme for 12 fellows from Bangladesh who visited India to study the process of renewal of primary education curriculum based on the minimum levels of learning. The Council undertook three Unesco sponsored projects/studies/programmes and played a key role as an Associate Centre of the Asia and the Pacific Programme of Educational Innovations for Development (APEID) and as the Secretariat of the National Development Group

(NDG) for educational innovations. The Unesco sponsored projects/studies/programmes undertaken by the Council during the year under report include the project on Bio-technology Teaching in Developing Countries, a National Workshop on Multi-Grade Teaching in Primary Schools and a National Training Workshop on Improvement of Methods, Forms and Structures of Technical and Vocational Education. The Council organised meeting of Body of the National Development Group (NDG) on 29 June, 1988. During the year under report, 15 faculty members of NCERT participated in different programmes organised by Unesco and other international agencies like the National Institute for Educational Research (NIER), Japan.

Field Services

5.22.40 The 17 field Offices of NCERT continued liaison work in States/UTs in their jurisdiction. The Field Offices of the NCERT played a key role in the establishment of Navodaya Vidyalayas and the conduct of the selection test for admission to the Navodaya Vidyalayas. They played a crucial role in the organisation of the Orientation Camps under the programme of Mass Orientation of School Teachers (MOST). Each of the Field Offices also organised certain orientation/training programmes for teachers and teacher educators on different aspects of school education and teacher education and organised the State Level Toy-Making Competitions.

Bal Bhavan Society (India)

5.23.1 Bal Bhavan Society, India, started as an after-school activity in 1955 to provide non-formal education to the children in various fields of creative arts, science, performing arts, museum techniques, photography, astronomy, environment, physical education etc.

5.23.2 During the year, training programmes for Jammu, Arunachal Pradesh and Leh were organised to help the States to start their Bal Bhavans. Bal Bhavan organised National Workshop on Astronomy and low cost planetarium at Amerli. Bal Bhavans were started at Vindhyachal and Ramagundam, the two formations of NTPC (National Thermal Power Corporation). A training workshop at the State level for 200 teachers was organised in collaboration with Jawahar Bal Bhavan, Goa, in Panaji, Goa.

5.23.3 The children from slums and villages participated in Bal Bhavan activities. Bhule Bisre children (children not looked after) were brought twice a week the whole year; they were washed, clothed, fed and accommodated in the various activities of their choice.

5.23.4 To help the handicapped children to attend Bal Bhavan and Bal Bhavan Kendras, a Mini Bus was procured free from TELCO through Mr. & Mrs. Moolgaonkar.

5.23.5 Besides, Bal Bhavan participated in collaborative programmes with the Trade Fair Authority and put up an exhibition of children's work at Imphal, Manipur and Leh (Ladakh). This new experiment attracted thousands of parents, children and officials. Children were shown an audio-visual on Bal Bhavan and there-after participated in creative arts, display work and aero-modelling.

5.23.6 Other highlights during the year were the professional treks organised with the help of the Army in the Kashmir Valley and at Kodaikanal, Tamilnadu. Children's Workshop on environmental activities was organised in collaboration with the NCERT.

5.23.7 The children of Aero Club participated in "Bachon Ki Vaigyanik Kritiyan" exhibition. The children also gave demonstrations of I.N.S. Vikrant (SHIP) & SUBMARINES.

5.23.8 Four National Workshops were organised in performing arts, creative arts, in games and science in daily life. The State Bal Bhavan sent participants who benefited greatly by the same.

5.23.9 The Eighth All India Conference of the Directors of the Bal Bhavans was held from 21st April to 24th April, 1988. The conference envisaged that all the Bal Bhavans in the country should be brought closer to each other and their programmes monitored by the Bal Bhavan Society. The conference also recommended to enlarge the scope of the Bal Bhavan membership by including the age group of 16-18 years in the membership of the Bal Bhavans.

5.23.10 There was a steep rise in membership in Bal Bhavan and Bal Bhavan Kendras. The environmental campaign organised through out in all the Bal Bhavans in the country covered 1,65,000 children.

5.23.11 An exhibition of paintings of children of the Socialist countries was organised as also an exhibition of art work and paintings of Bulgarian children. A record number of exhibitions were organised during the year.

5.23.12 All the national and international events of importance were celebrated i.e. freedom week, environmental campaign, Harit Vahini, World

Habitat Day, U.N. Day, Human Rights Day, World Health Day, Qaumi Ekta Diwas and the Children's Day. The Board of Bal Bhavan Society decided to dedicate the National Museum of the Child to the memory of the first Prime Minister and named it as Jawaharlal National Museum of the Child.

Higher Education and Research

6.1.1 Coordination and determination of standards in higher education is a subject in the Union List and is a special responsibility of the Central Government. This responsibility is discharged mainly through the UGC which was established in 1956 under an Act of Parliament. The Indira Gandhi National Open University will also perform these functions in respect of the Open University and Distance Learning System. Besides, the Central Government have established agencies for promotion and coordination of research efforts in specialised fields. There are three such national agencies at present, namely the Indian Council of Social Science Research, Indian Council of Historical Research and the Indian Council of Philosophical Research.

6.1.2 The magnitude of the problem in maintaining standards in Higher Education could be appreciated with reference to the graph on Growth of Higher Educational Institutions presented below:

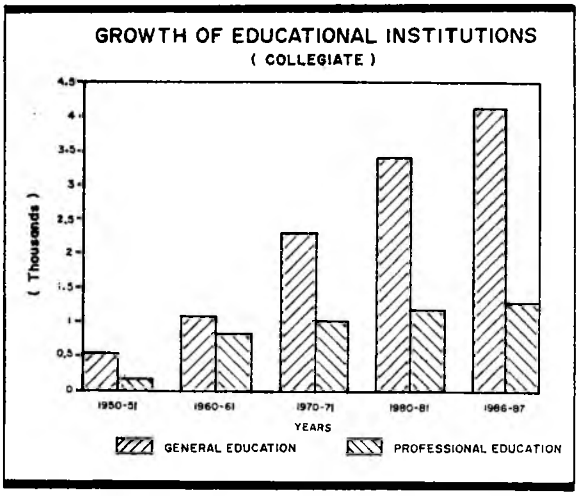

University Grants Commissions

Growth of the Higher Education System

6.2.1 At the beginning of the year 1988-89, the total student enrolment in Universities and Colleges was 38.14 lakhs. This was 1.32 lakhs more than the enrolment in the previous year. The enrolment in the University Departments was 6.37 lakhs and that in the affiliated Colleges was 31.77 lakhs.

6.2.2 Enrolment in the Faculty of Arts constituted 40.3% of the total enrolment. In the Faculties of Science and Commerce the percentage was 19.7 and 21.5 respectively. Enrolment at the first degree level was 33.57 lakhs (88%); at the postgraduate level 3.62 lakhs (9.5%); at the research level 0.42 lakhs (1.1%); and at the diploma and certificate level 0.53 lakhs (1.4%).

6.2.3 The number of teachers increased to 2.42 lakhs during the year. Of these, 0.53 lakhs were in the University Departments/University Colleges and the rest in the affiliated Colleges. Of the 53165 teachers in the Universities, 6273 were Professors, 13079 were Readers, 31580 were Lecturers and 2233 were Tutors/Demonstrators. In the affiliated Colleges, the number of senior teachers was 24923, the number of Lecturers was 155389 and that of Tutors/Demonstrators was 8496.

6.2.4 During the year under report six State Universities, namely the Kuvempu University (Shimoga), Kota Open University (Kota), University of Ajmer (Ajmer), Rajasthan Agriculture University (Bikaner), Tripura University (Agartala) and Purvanchal University (Jaunpur) were established.

Higher Education among Women

6.2.5 The enrolment of women students at the

beginning of the year 1988-89 was 11.95 lakhs as against 11.25 lakhs in the previous year. At the postgraduate level, the enrolment of women was 32.7% of the total enrolment. The enrolment of women students was the highest in Kerala (51.6%) followed by Punjab (46.6%), Delhi (44.6%), Haryana (39.7%) and Meghalaya/Nagaland (39.6%). The enrolment of women was the lowest in Bihar (15.9%).

Programme and Activities of the Commission

6.2.6 Some of the major thrust areas of the National Policy on Education which were pursued with vigour during the year were: Autonomous Colleges, Redesigning of courses, State Councils of Higher Education, Accreditation and Assessment Councils, Alternative Models of Management in Universities, National Qualifying Test for recruitment of teachers, Making research and development broad-based, Training/Orientation of teachers, Improvement of Efficiency, Youth and Sports and Education for the Minorities, Scheduled Castes/Scheduled Tribes, Handicapped and Women. A brief account of the efforts made by the Commission in respect of various schemes is given in the following paragraphs.

Autonomous Colleges

6.2.7 Based on the revised guidelines for the scheme of autonomous colleges circulated in 1987, 76 colleges (19 in Andhra Pradesh, 28 in Tamil Nadu, 25 in Madhya Pradesh and 4 in Rajasthan) have been approved for grant of autonomous status thus making a total of 95 autonomous colleges till November, 1988. Proposals made by several Colleges are under various stages of consideration by the concerned university. The states from which there has been no significant response are Bihar, Gujarat, Haryana, Kerala, Punjab, West Bengal and Assam.

State Councils of Higher Education

6.2.8 The Commission approved revised guidelines for setting up of State Councils of Higher Education which will plan and coordinate higher education at the State level. The State Council of Higher Education has been set up in Andhra Pradesh.

Re-designing of Courses

6.2.9 The scheme of restructuring under-gradua e courses in general education was introduced by the U.G.C. with a view to making the first degree courses more relevant and to link education with work/field/ practical experience and productivity. Thirty two Universities have introduced these courses in 134 colleges till November 30, 1988. In order to provide an impetus to the programme of redesigning of courses, the U.G.C. has set up 27 Curriculum Development Centres, 10 in Sciences and 17 in Humanities and Social Sciences. These Centres will review the existing curricula with a view to modernise them and to develop and prepare new teaching and reading materials. The Commission has so far received model curricula in 12 disciplines. These will be discussed by expert committees in the respective subjects and thereafter circulated to universities alongwith the recommendations of the expert committees. Meanwhile, the Commission has continued its assistance to 294 colleges which have been implementing a programme of College Science improvement besides 40 University Departments which were receiving assistance for University leadership programme in Science. Similarly, 544 colleges and 12 university departments have been receiving assistance for improvements in teaching Humanities and Social Sciences.

6.2.10 The Commission has agreed to the introduction of a three-year degree course in Physical Education, Health Education and Sports in universities and multi-faculty colleges. In the initial stages, only one college in each district having the basic minimum facilities viz. track and field gymnastic, Yoga, conditioning unit etc. will be selected for the introduction of the course. Universities/colleges were advised to send proposals for the introduction of the course. Till 31st March, 1988 proposals of 11 universities and 22 colleges were approved by the Commission for starting the course.

Consolidation of Existing Institutions

6.2.11 The National Policy on Education places the main emphasis in higher education on the consolidation of and expansion of facilities in the existing institutions. Accordingly a major part of the efforts of the Commission was devoted to the strengthening of the infrastructure in the existing Universities and Colleges. During the year, the Commission decided to provide additional allocation to universities equivalent to the spill over of the ongoing building projects from the Sixth Plan and earlier plans over and above the Seventh Plan allocation. Universities have been requested to utilise this amount towards capital works viz., construction of class rooms, laboratory, library buildings, hostels, staff quarters etc.. In view of the emphasis laid in the National Policy on Education (1986) on removal of obsolescence and consolidation of equipment in

universities and colleges, the Commission has agreed to provide assistance to Universities and Colleges for removal of obsolescence and consolidation of equipment during 1987-88.

6.2.12 As for Colleges, the guidelines for Seventh Plan development circulated last year were reviewed during 1987-88 and certain relaxations were provided. Also, in order to implement the provision of the New Education Policy, the Commission circulated to Universities and State Governments the guidelines on terms and conditions of affiliation of colleges by a University. As regards overall assistance provided to college sector, proposals were received from 2823 Colleges for basic assistance, of which those of 2683 were approved. 2259 Colleges sought assistance for development of undergraduate education of which, proposals of 1716 Colleges have been approved. In addition, the Commission had approved 114 proposals from single faculty Colleges as well as 119 from postgraduate institutions. The total amount approved for assistance to Colleges in the Seventh Plan till June 30, 1988 is Rs. 114.52 crores.

Improvement in Efficiency

6.2.13 The Commission has sanctioned computer facilities to 103 Universities. In addition, the Commission has agreed to provide mini computers to 400 Colleges during the Seventh Plan period. To begin with, 281 colleges have been selected out of which 186 have been sanctioned financial assistance for the purpose upto December, 1988. Besides using these facilities for training and research, they would be used for maintenance of student records, accounts and other data required for administration and Management.

Teacher-Recruitment Training and Performance Evaluation

6.2.14 The Commission considered the recommendations of the Committee appointed by it to work-out modalities for conduct of qualifying test for recruitment of teachers and decided that in view of the complexities of the problem, the appointment of the lecturers on the basis of the qualifying test be not enforced during 1988-89 and meanwhile modalities be worked out well in time to implement this scheme from the year 1989-90. For the orientation of newly recruited college and university lecturers, an Academic Staff Orientation Scheme has been drawn up. The content of the programme would be flexible so that universities could modify it to suit their local requirements. The programme would be multi-disciplinary in nature. Grants amounting to Rs. 3.47 crores were sanctioned to 41 universities for the setting up of Academic Staff Colleges and upto November, 1988 as many as 38 of these Staff Colleges had become functional, 45 Orientation Courses had been organised and about 2500 teachers had been given orientation. It is expected that all the 48 identified Academic Staff Colleges will become functional during 1988-89. The Task Force appointed by the Commission for evolving a system of performance evaluation of teachers and a code of professional ethics for them has completed its report on the institution of a system of performance appraisal of teachers which was sent in November, 1988 to the universities/colleges and State Governments for further action.

Strengthening Research

Special Assistance Programmes

6.2.15 The Commission continues to provide assistance to 26 Centres of Advanced Study and 75 Departments of Special Assistance in Science, Engineering and Technology and 15 Centres of Advanced Study and 58 Departments of Special Assistance in Humanities and Social Sciences. In addition, 36 Departmental Research Support Projects in Science and 13 in Humanities and Social Sciences are under implementation. The subject panels of the Commission have further identified some more Departments to be brought under these Special Assistance Programmes.

COSIST Programmes

6.2.16 Ninety five Departments have been assisted under the scheme of Strengthening Infrastructure in Science and Technology Education and Research till November 30, 1988.

Common Facilities and Services

6.2.17 Modern computer based information documentation centres have already been set up at Bangalore, Bombay and Baroda. These centres have improved the information accessibility to the teachers and students and have provided necessary bibliographic support to them alongwith making available the latest documentation in the respective disciplines. The Nuclear Science Centre at the JNU Campus has now been established as an autonomous institution of the U.G.C. as a registered society. In addition, the Inter University Centre in Astronomy and Astro Physics (IUCAA) set up at Poona University has also been given the status of autonomous society in November, 1988.

Media and Educational Technology

6.2.18 The U.G.C. has taken the initiative to utilise the time slot given for higher education and televising the TV programmes in higher education entitled "Countrywide Classroom". The Commission has agreed to provide colour television sets to Colleges in phases during the Seventh Plan period. A perspective plan for the U.G.C. INSAT Project is being formulated in which projections will be made for future INSAT time requirement in higher education. The Commission is at present supporting 4 Educational Media Research Centres (EMRCs) at the University of Poona, Gujarat University (Ahmedabad), Central Institute of English and Foreign Languages (Hyderabad) and Jamia Millia Islamia (New Delhi). Seven Audio-Visual Research Centres (AVRCs) at University of Roorkee; Osmania University; University of Jodhpur; Anna University, Madras; St. Xavier's College, Calcutta; Madurai Kamraj University, Madurai and Kashmir University, Srinagar are being supported for training of personnel and production of software. As envisaged by the Programme of Action on the National Policy of Education, the Commission has taken up a project on 'Non-broadcast Mode Educational Material' for the production of model course material in 15 subjects in the form of Audio/Video Cassettes with the help of best available teachers in the next three years. A Committee has been constituted to advise on matters relating to the preparation of the model video course material for undergraduate students. Eight production centres have been identified for the purpose. To encourage the preparation of educational programmes, the UGC had organised Video Programme Festivel this year in two phases.

Other Programmes

Introduction of New Courses

6.2.19 The Commission has been making efforts in consultation with the concerned National agencies for formulation of courses to fulfil the need for trained manpower in certain emerging areas of importance. The Commission is collaborating with the Department of Ocean Development for the development and augmentation of Ocean Sciences and Technology in the University sector. The Commission has also launched a programme to start Post-M.Sc. Course in Atmospheric Sciences in certain universities/institutions deemed to be Universities. Similarly, M.Sc. Electronics Science Course has been started in the Universities of Calcutta, Delhi and Poona. This course is being jointly supported by the Department of Electronics and the University Grants Commission. The Department of Electronics is also supporting programmes run by the Commission under the UGC-DOE Joint programme for running different manpower training courses in Computer Sciences and Application like one-year Diploma course in Computer Application; 3-year Master of Computer Application Course and B. Tech. and M. Tech. courses in Computer Sciences. Universities have also been identified to offer courses in Futurology & Futuristic studies.

Adult, Continuing and Extension Education Programmes

6.2.20 In the context of the National Literacy Mission, the Commission formulated during the year, new guidelines on adult and continuing education and extension programmes in universities under which the universities were advised to adopt specific area (s) for organising adult education including mass programme for functional literacy, prepare micro-level plans after survey of the area proposed to be adopted and identify various needs/areas which require educational interventions and utilize the expertise, infrastructure and facilities available with the university set-up and establish linkages with and secure assistance from other development agencies for execution of the programmes planned. The new guidelines are intended to provide a package assistance for all programmes, emphasising attention on women, scheduled castes/tribes and physically handicapped. The National Literacy Mission (NLM) assigns to universities/colleges an important task of covering five lakh people in 1988-89 and six lakh during 1989-90 through 25,000 and 30,000 adult education centres respectively besides involving themselves in the programme for functional literacy. Apart from continuing assistance for the activities of the population education clubs set up by the universities, the universities were advised during the year to increase the number of clubs so that grass root level activities are enhanced. The Task Force and the Resource Centres set up under the UNFPA-UGC project to provide support services in population education programmes to universities/colleges in specified areas in terms of development of curricula, training and extension programmes reported significant progress.

Scholarships and Fellowships

6.2.21 For the development of research in Universities and Colleges, the Commission provides assistance for award of junior/senior research

fellwoships in various subjects. At any given time more than 3500 fellowships are operational under this scheme.These fellowships will be awarded only to those research scholars who have qualified in national level tests conducted by the U.G.C., CSIR, GATE, AICTE etc. Tests conducted at all India level in some selected subjects by JNU and Indian Institute of Science, Bangalore have been accredited as equivalent to national tests for this purpose.

6.2.22 Teachers of outstanding eminence are awarded national fellowships for a specified period to devote themselves exclusively to research and writing. Under the scheme of Research Scientists, 200 positions have been created in the grades of Lecturers, Readers and Professors in order to provide opportunities to those who wish to pursue research as a career. Selections under this scheme are made directly by the Commission. At present over 180 research scientists are already working.

Coaching Classes for Competitive Examinations for Weaker Sections amongst Minority Communities

6.2.23 The Commission continued to provide assistance to 14 universities and 39 colleges for organising coaching classes for competitive examinations for weaker sections among the minority communities.

Facilities for Scheduled Castes/Scheduled Tribes

6.2.24 In addition to the Jr. Research Fellowships reserved for Sheduled Castes/Sheduled Tribes out of the total number of such fellowships instituted in various universities, the Commission is directly awarding every year 50 fellowships exclusively for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Similarly, the Commission has reserved 40 Research Associateships for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. In order to provide opportunities to teachers in affiliated colleges belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes for improving their qualifications by doing M.Phil./ Ph.D., the Commission has instituted 50 teacher fellowships every year.

Women's Studies

6.2.25 The Commission has been providing financial assistance to universities for undertaking well-defined projects for research in women's studies and also for the development of curriculum at the undergraduate and postgraduate levels and relevant extension activities. The Commission has also created 40 positions of part-time research associateship for women candidates in Science and Humanities including Social Sciences and Engineering & Technology. Twenty eight research projects relating to the themes of women's studies were approved for assistance upto November, 1988. Also the Standing Committee on women's studies, after examining various proposals, recommended assistance to some selected universities and colleges to set up centres/ cells for women's studies.

Establishment of Information and Library Network

6.2.26 The Commission took the initiative to prepare a project for the modernisation of Libraries and Information Centres in the country, with the application of Computer and Communication technologies during the Eighth Five Year Plan. The Network would cover all institutions of higher learning and would improve capability in information transfer and access, that provide support to scholarship, learning, research and academic pursuits.

Bilateral Exchange Programme

6.2.27 The Commission continues to implement various items under the Cultural Exchange Programmes assigned to it from time to time. These programmes involve exchange of teachers, development of bilateral academic links between institutions of higher education, joint seminars, scholarships and fellowships and assignment of foreign language teachers to universities in India. During the year 1987-88, 75 Indian teachers were able to undertake visits abroad under these programmes and 70 foreign scholars visited India.

Central Universities

Aligarh Muslim University

6.3.1 Aligarh Muslim University, Aligarh, is a premier institution of higher learning in the country and is open to all students without any distinction of caste and creed. In order to ensure the all India character of the University, the University introduced a new system of receiving applications for admission at regional centres, namely, Bombay, Calcutta, Madras, Hyderabad, Cochin, Srinagar and New Delhi.

6.3.2 The University is known for its residential character. It has 13 Halls of Residences consisting of 55 Hostels. The total strength of students is 19,041 (enrolment in the University being 12,697 and in Schools being 6344) and the number of students in Halls of Residences is about 7,928. The University admitted 5498 new students this year.

6.3.3. Six new Departments of Studies were opened

in the Faculty of Engineering and Technology and five new Centres were established under provisions of Section 5 (9) (A) of the University Act. The Departments of Mathematics and Physics have been recognised for Special Assistance by the U.G.C. The University introduced several new courses in various disciplines during the year under report. A number of courses were updated and revised.

6.3.4 The Remote Sensing Applications Centre for Research Revaluation and Geo-Engineering of the Faculty of Science has started programmes leading to M. Phil degree in Remote Sensing. The Computer Centre is providing satisfactory computing, programming consultancy and programme library facilities to teachers, research scholars and students. The Centre also helps in processing of admissions and examination results.

6.3,5 The newly created Department of Electronics Engineering consists of Electronics and Communication laboratories. It completed a major research project in the area of Integrated Circuit Fabrication from the Ministry of Defence, Government of India.

6.3.6 The Faculty of Medicine is the largest faculty comprising 18 Departments of studies. The University is making efforts to start an Early Cancer Detection Centre at its Medical College in collaboration with National Cancer Control Programme. A Cobalt Unit has been approved at a cost of Rs. 12 lakhs by the Government of India. Pace-maker In-plantation has been started in the Medical College.

6.3.7 The Women's College of the University has submitted a scheme for the establishment of a Women's Study Centre which is under consideration of the U.G.C.

6.3.8 The Interdisciplinary Biotechnology Unit of the University has set up a radio-isotopes laboratory.

6.3.9 The Academic Staff College established in July 1987, organised 8 academic staff orientation programme for the teachers recruited during the last five years. This College has been recognised as a Regional Centre by the UGC to conduct refresher courses for senior teachers in certain selected subjects.

6.3.10 The University proposes to organize international seminar to commemorate Maulana Abul Kalam Azad Birth Centenary Celebrations in collaboration with Indian Council of Cultural Relations, New Delhi.

6.3.11 The University Football Team won North Zone and All India Inter-varsity Football Championship. It also won All India Drama Festival 'Sharad Utsav' trophy.

6.3.12 A delegation consisting of 17 members of Sir Syed Memorial Society, Islamabad (Pakistan) which visited India from 15.3.1988 to 26.3.1988, was in the University from 18th March to 23rd March, 1988. Several foreign and Indian personalities also visited the University.

Banaras Hindu University

6.3.13 Certificate courses in Italian and Japanese languages were introduced from the current academic session which commenced in July, 1988. A competitive test for availing of research scholarship has been introduced.

6.3.14 The University's proposal for infrastructural support for Research in Cancer and facilities for improving teaching and patient care at the Institute of Medical Science has been approved by the U.G.C. under COSIST Programme. The Department of Electrical Engineering was sanctioned Rs. 45.20 lakhs under the Special Assistance Programme by the U.G.C. The Academic Staff College organised three Orientation Courses for teachers of the University and neighbouring Institutions. The 63rd Annual Meeting of the Association of Indian Universities was hosted by the Banaras Hindu University from 5-7 December, 1988. The University organised 10 National and 2 International seminars and hosted the East Zone Inter-Varsity Hockey Tournament during the year.

6.3.15 The University has been extending Consultancy Services through the Industrial Consultancy Centre under the Institute of Technology. Programmes of Integrated Rural Development Centre, Adult and Continuing Education Centre and ORPHIC projects funded by I.C.M.R. have had a strong package to provide rural oriented extension services for the eradication of illiteracy, ill-health and poverty from the rural areas. Some new varieties of seeds of agricultural crops were also released for cultivation under inhospitable conditions.

6.3.16 The University identified a number of areas for developing multi-disciplinary research. These include Space Science, Manpower Development, Science Museum, Energy Engineering etc. In the area of Super-conductivity the task assigned to the group in the Department of Physics has been commended by the U.G.C.

6.3.17 Some scholars from the various faculties were conferred Honours/Awards for their outstanding contribution in their respective field areas of

research/scholarship. Prof. Shri Kant Lele was selected for the Shanti Swarup Bhatnagar Prize in Engineering Science for 1987. Prof. W. K. Lele of the Department of Marathi was conferred the Gyandev Award by the University of Pune. Prof. B.C. Katiya (Neurology) has been elected as Executive Member of the World Federation of Neurology to be held in 1989. Prof. V. V. P. Kutumba Rao won the National Metallurgists' Day Award 1988.

6.3.18 The University chalked out ambitious programmes for the celebration of the Birth Centenaries of Dr. S. Radhakrishnan, Pt. Jawaharlal Nehru, Maulana Abul Kalam Azad and Sir C. V. Raman. The programmes for the year long centenary celebrations include holding of memorial lectures, seminars, exhibitions and cultural series etc.

University of Delhi

6.3.19 During the academic year 1988-89, the number of students admitted to first year of various courses of the University regular or otherwise was 65,088. This brought the total student strength of the University to 1,59,636 including 12,177 in the non-collegiate Women Education Board, 13,842 registered in the External Candidates Cell and 33,556 in the School of Correspondence Course and Continuing Education. The number of students registered for various Ph.D. and M.Phil. Courses were 2,456 and 650 respectively.

6.3.20 The number of SC/ST students admitted during the year was 4,190.

6.3.21 The number of teachers during the year was 737 including 260 Professors, 315 Readers, 145 Lecturers and 17 Research Associates.

6.3.22 The following new courses were introduced during the year:

i) M.B.A. (Public System Management)
ii) One year Intensive Course in Spanish Language.
iii) B.A. (Hons.) Applied Psychology.
iv) M. Tech. Course in Computer Science.
v) M.Sc. in Plant Molecular Biology.

6.3.23 During the year under report the University organised several lectures by eminent scholars both from India and abroad. Dr. Madan Mohan Bajaj, Department of Physics and Astrophysics was honoured with the Fellowship of International College of Nutrition.

6.3.24 Mr. Dinabandhu Sahoo, a Ph.D. student from the Department of Botany participated as the first ever Indian student in the seventh Indian Antarctic Expedition.

6.3.25 Prof. Satya Vrat, Department of Sanskrit was honoured by the Uttar Pradesh Sanskrit Academy for his contribution to (creative and critical) Sanskrit literature with an award of Rs. 25,000/-.

6.3.26 Mr. Vijay Raj Singh, Department of Physics and Astrophysics, has been honoured with the membership of the International Pain Foundation, U.S.A.

6.3.27 Prof. P.S. Gupta, Department of History has been elected a fellow of the Royal Historical Society, U.K.

6.3.28 The Vice-Chancellor, Prof. Moonis Raza, was the Leader of the Indian delegation which participated in the 26th International Geographical Congress held in August, 1988 in Sydney, Australia.

6.3.29 The University won All India Championship during 1988-89 in seven sports events: namely, Cross Country (Men & Women), Table Tennis (Men & Women), Cricket (Men) (North-Zone) and Khokho (Men) (North East Zone). The University was runners-up in five events in the All India Inter-University Championship. Shri Dharmendra Sinha created a new Inter University record in High Jump.

University of Hyderabad

6.3.30 The University started its academic year 1988-89 from July 1, 1988. Earlier the University had conducted entrance examinations at six centres outside Hyderabad for admission to various courses. During the year under Report 758 new students were admitted after selection all over the country. A special admission advertisement was issued mainly for the attention of SC/ST candidates. The minimum eligibility criteria were relaxed enabling them to appear in the admission tests. One hundred and seventy nine SCs, 27 STs and 24 physically handicapped students are on the enrolment of the University till August 1988 out of 1504. Enrolment of women students is 568 i.e. 37.20 per cent.

6.3.31 As on 31.3.1988, the University had 51 Professors, 61 Readers and 50 Lecturers. The strength of non-teaching staff is 887 comprising Group 'A', 'B', 'C' and 'D' officers.

6.3.32 The teaching work of the University during the year continued without any dislocation. Financial assistance to students was continued in the form of merit scholarships; 40 M. Phil. and Ph.D. students who had qualified in the NET conducted by

UGC/CSIR were in receipt of fellowships from University Grants Commission under "any given time basis" scheme. In addition some students secured scholarships from different agencies of the Government of India and Andhra Pradesh, under special categories. The University provided hostel accommodation for 767 students. This includes 136 SC, 18 ST, 16 physically handicapped students. Two hundred and one Women students were accommodated in the hostels.

6.3.33 The total number of research projects funded by UGC, CSIR, ICMR, DST, DAE, ICAR etc. was 72.

6.3.34 During the year under report, buildings of the School of Social Sciences, the Indira Gandhi Memorial Library, the administrative block II phase and the shopping arcade were completed and commissioned. The Sarojini Naidu School of Performing Arts, Fine Arts and Communication started functioning from this academic year with M.A. courses in Painting, Dance, Theatre Arts and Communication with the help of U.G.C. The Academic Staff College started this year. It could hold two orientation courses, one in March 1988 and the second in July-August, 1988. The U.G.C. also sanctioned about Rs. 53.00 lakhs for a new ladies hostel, construction work on which has begun.

6.3.35 The Executive Council met six times during the year. The annual meeting of the Court was held on 3rd December, 1988 and the Annual Report on the working of the University and the annual Audited Accounts for the year 1987-88, were presented and approved. The Academic Council met twice during the year in March and October, 1988.

6.3.36 Prof. Bh. Krishnamurti, appointed as Vice-Chancellor on 11.6.1986, continued during the year under report. Justice Mohammad Hidyatullah is the Chancellor of the University since 10.4.1986. The University continued sizeable number of seminars. Five teachers of the University received various awards.

6.3.37 The Annual Accounts of the University for the year 1987-88 were laid before the Parliament on 7.12.1988. The University is financed through regular grants from the University Grants Commission for Plan and non-Plan Schemes.

Indira Gandhi National Open University

6.3.38 The IGNOU started functioning from September 20, 1985. The major objectives of the University are: to provide access to higher education to large segments of the population, especially the disadvantaged groups; to organise programmes of continuing education, to upgrade knowledge and skills; and to initiate special programmes of higher education for specific target groups like women people living in the backward regions, hilly areas, etc.

Academic Programmes

6.3.39 The University started two diploma programmes in January, 1987. During 1988-89 fresh admissions were made to both these programmes. In addition, new diploma courses in Management (Module II) and Creative Writing were introduced. Admissions were made to the first batch of Undergraduate Programmes (B.A., and B.Com.) in August, 1988. The enrolment for these programmes consisted of direct admissions from the post-secondary stream as well as the successful candidates from the preparatory course offered by the University for those who have had no formal qualifications. Besides, the University introduced Certificate courses in Rural Development as well as in Food and Nutrition, during the year.

6.3.40 The University proposes to launch a Bachelor's degree course in Library and Information Science and Module III of the Diploma in Management during early 1989. The total enrolment in the various programmes of the University is expected to be 40,000 by March, 1989. The academic Programmes proposed to be introduced during 1989-90 include Diploma courses in Management Module IV, Rural Development, Food and Nutrition, Child Care and Education, Creative Writing in Hindi and Higher Education; and Certificate programmes in Water Resource Management and Energy Conservation and Management. The preparatory work for introduction of these courses is in progress.

Campus Development

6.3.41 The architects for the design and construction of the permanent campus have been selected. To begin with, the University has decided to construct some semi-permanent structures on the campus to house its offices. The contract for construction of about 60,000 sq. ft. accommodation has been awarded to Hindustan Pre-Fab Ltd. a Government of India Undertaking. Meanwhile, the University is functioning from a number of rented premises in Delhi.

Equipment and other facilities

6.3.42 A major infra-structural requirement of the University is the production facility for producing material for the print as well as electronic media. For

the present, there is greater reliance on the printed material. But the University is also simultaneously developing facilities for producing material for the electronic media. A studio for the production of audio/video programmes is being set up with equipment purchased form GCEL, a Govt. Undertaking. Under a programme of assistance signed between the Government of India and the U.K., the University has been offered substantial equipment and other material for setting up its own Production studio. The total assistance (electronics equipment, computer, consultancy and training) likely to be received from Britain is of the order of Rs. 8 crores.

The Government of Japan have also agreed to give an aid of 611 million Yen (Rs. 7.50 crores) for purchase of Japanese equipment for studioes and production facilities of the University. The agreement which was signed in October, 1988 provides for the supply of this equipment during 1988-89.

Delivery System

6.3.43 The delivery system of the University consists of effective Student Support Services of which Regional Centres and Study Centres are integral elements. At the Study Centres, part-time tutors and guides provide counselling, advice and guidance to students. They also stock all the material for all the courses and provide viewing/listening facilities for video/audio programmes. By March, 1989, the University has plans to set up 125 such Study Centres, of which 107 have been set up by December, 1988.

6.3.44 Twelve Regional Centres at present supervise and coordinate the existing Study Centres. More Regional Centres will be established with the increase in the number of Study Centres.

6.3.45 During the year 1988-89, a grant of Rs. 10 crores was sanctioned to the University.

Jawaharlal Nehru University

6.3.46 The University Grants Commission accredited the Jawaharlal Nehru University Entrance Examination conducted at 24 Centres all over the country for admission to different courses of studies in various Schools of the University at par with the National Educational Test conducted by the Commission for award of Junior Research Fellowships to candidates pursuing M.Phil./M.Tech./Ph.D. Programmes in various science disciplines. As a result of this accredition, the candidates joining aforementioned progremmes in various Schools of the University on the basis of their inter se merit in the All India Entrance Examination conducted by the University would become automatically eligible for the award of the U.G.C. Junior Research Fellowship without their having to qualify the examination conducted by the Commission for this purpose.

6.3.47 Courses for various programmes of study were re-designed and updated. A Micro Vax-II Computer system was installed at the School of Computer and Systems Sciences. Thirty five Research Projects were completed by the faculty members of various Schools while work on 69 projects was in progress. These projects had been sponsored by various national and international agencies, including Government Departments. About a dozen national and international seminars/symposia were organised by the various Centres of the University. Thirty Extension Lectures on the theme 'Major Issues in Contemporary International Relations' were held during the year. Public lectures were also organised on the occasion of the 40th Anniversary of India's Independence.

6.3.48 The Centre for Historical Studies was approved under the Special Assistance Programme of the U.G.C.

6.3.49 Sixty three thousand press clippings, 11,831 volumes and a new Reading Hall with a seating capacity of 100 seats were added to the Library. The Adult Education Unit undertook a study of socio-economic conditions of artisans, specifically the potters of Delhi. It set up about 55 adult education centres in and around J.N.U. campus. Besides providing medical aid and consultation to the students community in the campus, the Health Centre initiated a number of preventive programmes of health care.

6.3.50 Construction programmes maintained steady progress. The Library Tower block has been completed. Similarly 25 units of Transit Accommodation and 36 units of Type I quarters (Phase II) were completed by the CPWD and were occupied. The additional floor of the School of Social Sciences has also been occupied. Construction work in respect of the School of International Studies, extension block of the School of Social Sciences, the School of Environmental Sciences and the School of Languages maintained progress according to the schedule. Construction work of faculty club and guest house, community centre, students club and club for karamcharies is in advanced stage of progress.

6.3.51 The University constituted a Committee for organising the centenary celebrations of Pt. Jawahar-

lal Nehru in 1989. The programme includes holding of cultural and sports events, exhibitions, extension lectures etc.

North-Eastern Hill University

6.3.52 The North-Eastern Hill University has three Campuses in Nagaland, Mizoram and Meghalaya with Headquarters in Shillong. At present, the Shillong Campus has 18 post-graduate Departments, in addition to 4 academic Departments in the Kohima Campus and 5 in Aizawl Campus. Till date, 8 centres have been established. The two University colleges viz., the Pachhunga University College and the School of Agricultural Sciences and Rural Development are located in Mizoram and Nagaland respectively.

6.3.53 True to the aims of the university, the North-Eastern Hill University has been engaged in bringing out the social and educational excellence of the people, especially the youth, living in the three States of Meghalaya, Nagaland and Mizoram. In the last couple of years, efforts have been concentrated on constructing and developing the permanent campus of the university at Shillong. Construction of the 200 seat hostel, 50 staff quarters, another 200 seat hostel sponsored by the North Eastern Council, the Seminar Complex and the Guest House has been completed. Provision of 33 KV line for MSEB terminal to the NEHU Campus at Shillong was completed in 1987. Power and water supply has since been provided to the permanent campus. Construction of 150 staff quarters, 800 seat hostel buildings, lecture complex for schools of Physical Sciences and Life Sciences, buildings for USIC, RSIC and workshop is in progress. A 100 seat hostel at Mizoram Campus sponsored by the North Eastern Council is also in progress.

6.3.54 Construction of ring roads around Academic Complex and a football ground (Spot Complex) is likely to be completed in March, 1989.

6.3.55 During 1987 and 1988, altogether seventeen seminars and conferences were held, including three in the Mizoram Campus, Aizwal.

6.3.56 At a solemn Special Convocation held at Shillong on September 8, 1988, the University conferred the Degree of Doctor of Literature (Honoris Causa) on Rev. Mother Teresa.

Pondicherry University

6.3.57 The University, which was established on 16th October, 1985, continued to make rapid progress. The following Schools/Departments were established during the year under report:

i) Salim Ali School of Ecology,
ii) Departments of French and History,
iii) School of International Studies,
iv) Academic Staff College.

6.3.58 The non-medical departments of Physics, Chemistry and Biology of JIPMER were taken over by the University on 1.6.1987.

6.3.59 The University now has two Schools, one Institute, one Academic Staff College and eleven Departments.

6.3.60 The following new courses were introduced during the year:

1) M.A. (English and Comparative Literature)
2) M.S. (Development Economics)
3) M.A. (Functional Tamil)
4) M.Com. (Business Finance)
5) M.Sc. (Functional Mathematics)
6) M.Phil. (History)
7) M.Phil. (French)
8) Certificate course in French (Evening)
9) Certificate course in Computers (in collaboration with COSTED, Madras)
10) B.Sc. in Physical Education, Health and Sports (To commence in July, 1989)

6.3.61 In all, 7 post-graduate courses and 10 M.Phil. courses are being offered. Enrolment for Ph.D. programmes was made for the first time in the subjects of Tamil, English, French, History, Economics, Commerce, Ecology, Physics, Chemistry and Biology. The UGC approved the establishment of an English Language Training Centre in the University.

6.3.62 The University now has 14 affiliated Colleges of which 8 colleges are in Pondicherry, 2 in Karaikal, one each in Mahe and Yanam and 2 at Port Blair.

6.3.63 There are 5,677 students in the above affiliated colleges of whom 439 were SC/ST and 2,272 women students. During the period under report, these Colleges offered 37 under-graduate courses, 34 post-graduate courses, 10 post-graduate diploma/ degree courses, one M.Phil. course and Ph.D. programme in one discipline.

6.3.64 The total number of new students admitted by the University during the academic year 1987-88 was 404, of which 35 were SC, 3 were ST and 95 were women students. The total number of students on roll during the academic year 1987-88 was 430. In the year 1987-88, 38 scholars were admitted to Ph.D. programme.

6.3.65 The University had, as on 31-3-88, 18 Professors, 25 Readers, 38 Lecturers and 3 Demonstrators.

6.3.66 The University had 23 Group 'A' Officers, 7 Group 'B', 126 Group 'C' and 91 Group 'D' employees as on 31.3.88.

6.3.67 During the year, the UGC released Rs. 267.67 lakhs for construction of administrative complex, academic buildings, hostels, library building, staff quarters, sports stadium and campus development.

Vishwa Bharati

6.3.68 The total student strength during the year 1987-88 was 4515. The total strength of the teachers was 458 including 63 Professors and 148 Readers.

6.3.69 The inauguration of the Ganitra Sadan (Computer Centre) by Prime Minister, Shri Rajiv Gandhi, was another milestone in the expanding academic activities fo the University. Active steps are being taken to organise academic staff college.

6.3.70 A number of national seminars and workshops had been organised by the University with the assistance of such bodies as the UGC, DST, ICAR and ICHR. Such activities have encouraged interaction among Faculty members and students of different parts of the country. Numerous individual and departmental projects have been undertaken. Among the new ones is a project of the World Institute for Development of Economic Research (WIDER), a research body of the United Nations University to study rural poverty, social change and public policy is Eastern India with special reference to Bengal.

6.3.71 The Hindi Bhavana's Golden Jubilee Celebaration was inaugurated by Prime Minister, Shri Rajiv Gandhi, on January 16, 1988. Its contribution to researches in Hindi Language and Literature is widely acknowledged. A major success has been the publication of some of the works of Tagore in Hindi.

6.3.72 Four volumes of the popular edition of Rabindra Rachanavali have till now been published and these have been widely acclaimed by the readers. The revival of interest has been noticed in many foreign countries. Tagore's paintings have also aroused much interest in the Western World.

6.3.73 The important work of restoration of old buildings associated with the memory of Tagore has been making good progress.

6.3.74 Cultural and Literary Exchanges and collaboration with Orissa, Tripura and Bihar have proved highly rewarding.

6.3.75 The Indira Gandhi Centre for National Integration has started functioning. Its academic programme commenced with a lecture on "Secularism in India" by Prof. Nurul Hasan, Governor of West Bengal.

Establishment of New Central Universities

Jamia Millia Islamia

6.3.76 The Jamia Millia Islamia which was founded at Aligarh in 1920 during the Khilafat and Non-Cooperation Movement in response to Gandhiji's call for boycott of Government-supported educational institutions, was declared in 1962 as a deemed to be university institution under section 3 of the UGC Act. During the last few years, there has been a demand from the academic community of the Jamia, its authorities and the society in general that in view of the historic character of the institution and its services to the nation, the Jamia should be granted the status of a fullfledged university through an Act of Parliament so as to enable it to grow and achieve excellence in the field of higher education. The Government carefully considered the issue in consultation with the UGC, the Chancellor of the Jamia Millia Islamia and a few eminent educationists including Muslim scholars. Considering the genesis of the Jamia as a national institution, its contribution to the freedom struggle, its history and selfless service and its secular character, the Government decided that Jamia may be converted into a full-fledged university through an Act of Parliament on the general pattern of goverance of other Central Universities. Necessary legislation was introduced and passed during the 1988 monsoon session of Parliament. The Jamia Millia Islamia Act, 1988, came into force from 16th December, 1988.

6.3.77 The Jamia Millia Islamia has been receiving recurring and non-recurring grants from the University Grants Commission for meeting the expenditure of its university sector. For its non-university sector grants were directly sanctioned by the Department of Education.

6.3.78 Under the non-university sector, the Jamia is running its higher secondary school, middle school, nursery school and polytechnic. The total number of students on the rolls of the school and polytechnic during the academic year 1988-89 were 2628 and 300 respectively.

6.3.79 The Jamia Millia Islamia was sanctioned

grants for construction of buildings for the Jamia polytechnic, development of school campus and for providing infrastructure for the engineering stream in the secondary school.

6.3.80 With the enforcement of Jamia Millia Islamia Act, 1988 from 26th December, 1988 grants for the school sector from the year 1989-90 would be provided through the University Grants Commission, as in the case of other Central Universities.

New Universities Proposed .

6.3.81 The Government had decided to establish a Central University in Assam. A detailed project report for the establishment of the University has been prepared. The Bill for the establishment of the University is expected to be introduced in Parliament in early 1989.

6.3.82 A new Central University is proposed to be established in Nagaland at Lumani. The detailed project report has been prepared and the Bill is expected to be introduced in Parliament in early 1989.

Deemed to be University Institutions

6.3.83 Two institutions, namely, Central Institute of Higher Tibetan Education, Sarnath, (Varanasi) and Sri Avinashilingam Institute for Home Science and Higher Education for Women, Coimbatore were declared as institutions deemed to be universities under section 3 of the UGC Act, during the year under report bringing the total number of such institutions to 24.

Specialised Research Organisations

Indian Institute of Advanced Study, Shimla

6.4.1 The Indian Institute of Advanced Study, Shimla, was established in 1965 as a residential centre for advanced research for providing to scholars an environment conducive to academic research in Humanities, Indian Culture, Comparative Religion, Social Sciences and Natural Sciences. The Institute aims at free and creative enquiry into the fundamental themes and problems of life and thought. It provides facilities for advanced consultation and collaboration, besides exhaustive library and documentation facilities.

6.4.2 There were 27 Fellows on the rolls of the Institute during 1988-89 working on different topics of research. A few more scholars are expected to join shortly.

6.4.3 The Institute organised three seminars during the year under report on the following themes, in which eminent educationists from all parts of the country participated:

i) Art and Life in India since Independence
ii) Colloquium on Moral Dilemmas in the Mahabharata
iii) Self Images, Identity and Nationality

The proceedings of these seminars will be published in the form of transaction volumes.

6.4.4 Weekly group discussions/meetings of the Fellows which is one of the salient features of the academic activities of the Institute and generate a lot of interaction amongst scholars working in different disciplines were held regularly. The papers presented at such group discussions/meetings are being published in a new series called "Occassional Papers" which appear in book form. The Institute brought out several publications during the year under report and three publications are in press.

Indian Council of Historical Research

6.5.1 The Indian Council of Historical Research was set up in 1972 as an autonomous organisation to promote the objective of scientific writing of history, to sponsor historical research programmes and to inculcate an informed appreciation of the country's national and cultural heritage.

6.5.2 During 1988-89, two eminent historians were awarded National Fellowships. The Council sanctioned 28 research projects, 98 fellowship grants and 108 study-cum-travel grants to scholars. Eighty two research theses, monographs and journals were approved for publication subsidy. Fifty-seven professional organisations of historians, such as Indian History Congress, South Indian History Congress, Punjab History Congress, Orissa History Congress, Numismatics Society of India, etc., were sanctioned grants to enable them to organise seminars, symposia, etc.

6.5.3 The Council nominated historians to participate in the following Conferences/Seminars held abroad; 18th World Conference of Philosophy at Brighton; Round Table Conference on Indian Nationalism and Nehru at Budapest; 'Peasants in Struggle' at Moscow; and First SAARC History Conference at Dhaka. The Council organised a seminar of "New Archaeology in India" in which four scholars from abroad and 20 Indian scholars participated. Two Afghan scholars, two Dutch scholars and two scholars from GDR were invited to undertake research in India under the Cultural Exchange Programme.

6.5.4 Under its publication programme, the Council brought out five publications, namely, "A Topographical list of Inscriptions in Tamil Nadu and Kerala" Vol. II by T.V. Mahalingam, "Jodhpur Rajya ki Khat" by Raghubir Sinha (in Hindi), "Tarikh-i-Sorath" by Shambhu Prashad Desai in Persian, "Labour Movement in India-Documents 1918-1920" edited by A.R. Desai; "Planter Raj to Swaraj" by Amalendu Guha (second edition). Twenty two books in English, Persian, Hindi and Tamil have been sent to the press. Besides, more than 30 monographs and theses were published under the publication subsidy programme of the Council.

6.5.5 As part of the celebrations of the 40th Anniversary of India's Independence and the Birth Centenary of Pandit Jawaharlal Nehru, the ICHR organised five Workshops on the National Movement at Pondicherry, Hyderabad, Srinagar, Calcutta and Delhi.

Indian Council of Philosophical Research

6.6.1 The Indian Council of Philosophical Research was set up mainly to coordinate and review the progress of research in Philosophy, to sponsor or assist projects of research in Philosophy and to take necessary measures for the promotion of research in philosophy and allied disciplines.

6.6.2 During 1988, the Council awarded two senior fellowships, twenty-one general fellowships, four residential fellowships and one short-term fellowship, besides continuing with other fellowships awarded in the previous years.

6.6.3 Under its project of revitalisation of Indian Philosophical Traditions, the Council organised a dialogue-cum-seminar between Ulema and modern university trained scholars of Persian, Arabic and Islamic Philosophies at its Academic Centre at Lucknow. In this context, winter school at Bangalore and a summer school at Dharamshala were also organised by the Council.

6.6.4 The Council also organised an all India essay competition for the young scholars on the Topic 'Philosophy, Culture and Values' to promote talent among them. A seminar on the same theme was held at Delhi University in November, 1988. The Council provided travel grants to seven scholars for attending international conferences, seminars, etc. The Council is organising a series of lectures by Professor Richard Sorabji, an eminent scholar in Greek philosophy from UK, in about a dozen universities in India from January to March, 1989 under its programme of annual lectures.

6.6.5 The Council published five books and brought out three issues of Journal of Indian Council of Philosophical Research (JICPR).

Indian Council of Social Science Research

6.7.1 The Indian Council of Social Science Research was established in 1969 as an autonomous organisation to promote and coordinate social science research in the country.

6.7.2 The Council continued to assist research institutes of all-India character doing research in the field of social sciences and to its six regional centres. During the year under report, two new research institutes, namely, Gujarat Institute of Area Planning, Ahmedabad, and Institute for Studies in Industrial Development (temporarily located at New Delhi) were brought under its scheme of financial assistance to institutions in social sciences, making the total number of such institutes to 24. Sixty-one institutions, professional social science orgnisations, universities etc. were given grants for holding seminars, conferences, workshops and symposia.

6.7.3 Grants were sanctioned for 79 research projects The Council received completed reports in respect of 55 projects approved earlier. A number of sponsored research programmes on topics, like, Research on Women's Studies, Health for All, Theoretical and Methodological Issues in Social Science and preparation of Encyclopaedia on Social Legislation in India, are in progress.

6.7.4 The Council awarded one National Fellowship, 15 Senior Research Fellowships, seven General Fellowships, one Foundation Day Fellowships, thirty one regular doctoral fellowships, 28 short-term doctoral fellowships and 12 contingency grants. Seven training courses/workshops in research methodology in social sciences were organised.

6.7.5 National Science Documentation Centre acquired 1500 publications including 180 theses and 165 research reports. One hundered and ten Ph.D. scholars were awarded study grants for visiting libraries to collect research material. Financial assistance was also given for 24 bibliographical and documentation projects. The Data archives acquired 4 data sets which have potential for re-use. Thirty seven scholars were given help in data processing.

6.7.6 Under the scheme of publication grant, 65 theses and 16 research reports were approved for financial assistance. Thirty issues of journals in different disciplines were published during the year.

Thirty books were printed under the Publication Grant Scheme. Twenty four mimeograph research information series publications were also brought out. Two thousand four hundred scholars sent requisite information for compilation of the National Register of Social Scientists in India, out of which 1800 proformae have been proceessed.

6.7.7 Seven prominent social scientists of the country headed by Prof. Y.K. Alagh, Member, Planning Commission visited the USSR to attend the seminar on "Planning and Economic Development". An eight-member delegation of social scientists headed by Prof. S. Chakraborty, Chairman of the Council also visited the USSR for attending the meeting of Indo-Soviet Joint Commission in Social Sciences. Eight scholars each from India and China participated in a Joint seminar on rural development organised by the Council. The Joint Committee on Indo-Dutch Programme on Alternatives in Development reviewed the various activities of the Programme and finalised the research proposals for the third phase of the Programme. Under the international collaboration and exchange programmes, the Council sponsored the visit of two Chinese scholars, one Dutch scholar and two French scholars. The visit of six Indian scholars to France, 8 Indian scholars to Netherlands and three Indian scholars to China was also sponsored by the Council.

Scheme for Grants to All-India Instutitions of Higher Learning

6.8.0 The objective of the Scheme is to provide assistance to certain voluntary organisations which are functioning in the country at the all-India level and are offering programmes of education different from the conventional university system which are of particular interest to the rural community or which are innovative in character. During the year 1988-89, the following institutions have been provided financial assistance under the scheme.

- Sri Aurobindo International Centre of Education, Pondicherry
- Lok Bharati, Sanosra
- Sri Aurobindo International Institute of Educational Research, Auroville.

Bilateral/Foreign Collaboration

Shastri Indo-Canadian Institute

6.9.1 Shastri Indo-Canadian Institute is an autonomous voluntary organisation incorporated in Canada which commenced its activities in India in November, 1968 in pursuance of a Memorandum of Understanding with the Government of India. The objective of the Institute is to serve a two-fold purpose of supporting and promoting advancement of knowledge and understanding of one country among the scholars and students of the other. Grants are paid by Government of India for the operation of the activities of its Branch Office in New Delhi.

6.9.2 The Institute awarded fellowships to 11 scholars from Canada during the year 1988-89 for undertaking research in humanities, learning Indian languages and in the field of performing arts. The Institute also sponsored 6 Indian scholars for visit to Canada under various programmes.

Research Projects of foreign Scholars visiting Indian Universities etc.

6.9.3 Proposals are sponsored by foreign agencies i.e. American Institute, Shastri Indo-Canadian Institute, United States Educational Foundation in India, University of California Berkeley Professional Studies Programme in India for visit of foreign scholars for research in India. Besides, proposals are also recieved from the Indian Missions abroad, Indian Institutions, and from individual scholars for research in affiliation with institutions in the Indian University system. During the year, 182 such proposals were approved and 21 proposals were rejected.

Other Activities

Scheme of revision of pay scales to University and College teachers

6.10.1 The Scheme of revision of pay scales of teachers in Universities and Colleges was announced on 17th June, 1987. Following further discussions with the representatives of teachers/teachers' organisations, certain modifications/clarifications were made in the scheme. The modified Scheme was communicated to States/UTs on 22nd July, 1988.

6.10.2 The major ammendments incorporated in the modified scheme are the merger of the two grades of Readers; institution of a Selection Grade for Lecturers which is equivalent to the revised Reader's grades and a fixed pay of Rs. 7600/- for Vice-Chancellors. It was clarified that the qualifying test for recruitment of Lecturers is intended to be organised through a number of agencies keeping in view the requirements of the media of instruction followed by different States/Universities. Similarly provision for advance increments was made to encourage enrolment in research programmes immediately on completion of postgraduate studies. Accordingly, candidates who have M.Phil. or Ph.D.

degrees will be entitled to one and three advance increments respectively at the time of their recruitment. They will also be entitled to the benefit of corresponding years of service for the purpose of promotior. The existing Lecturers and those recruited in future without research degrees will also be eligible for the benefit in service when they acquire research degrees. Promotion to the post of Reader and placement in the Selection Grade will be through a process of selection by a Committee constituted by the University for appointment of Readers. In both cases, participation in continuing education programmes and consistantly good performance appraisal reports are essential elements in the design for career advancement. For placement of Lecturers in the Senior Scale and Selection Grade as well as for promotion to the post of Readers, the required r mber of posts would be created by upgrading the posts held by the incumbents concerned.

Revision of pay scales of Librarians and Physical Education Persdnnel

6.10.3 The pay scales of the Librarians and Physical Education personnel in Universities and Colleges have also been revised. The revised scales are the same as were approved for University and College teachers. The designation-wise details of revised scales of Librarians and Physical Education personnel are presented below :

		Designation	Revised scales of pay
A.		Universities	
	1.	Assistant Librarian/ Documentation Officer Assistant Director of Physical Education	2200-75-2800-100-4000
	2.	Assistant Librarians/ Documentation Officer (Sr. Scale) Assistant Director of Physical Education (Sr. S ale)	3000-100-3500-125-5000
	3.	Assistant Librarians/ Documentation Officer (Selection Grade) Assistant Director of Physical Education (Selection Grade)	3700-125-4950-150-5700
	4.	Deputy Librarian Deputy Director Physical Education	3700-125-4950-150-5700
	5.	Librarian Director of Physical Education	4500-150-5700-200-7300
B.		Colleges	
	1.	College Librarian Director of Physical Education	2200-75-2800-100-4000
	2.	College Librarian (Sr. Scale) Director of Physical Education (Sr. Scale)	3000-100-3500-200-5000
	3.	College Librarians/ (Selection Grade) Director of Physical Education (Selection Grade)	3700-125-4950-150-5700

The Librarians and Physical Education Personnel will also be covered by the career advancement scheme approved for University teachers.

Implementation of the Scheme

6.10.4 Most of the States have conveyed their acceptance to the Scheme. Some States have also issued the orders revising the pay scales of Teachers, Librarians and Physical Education Personnel in Universities and Colleges in their States. The State Governments which have decided to implement the scheme are: Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Goa, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Karnataka, Madhya Pradesh, Nagaland, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu and Uttar Pradesh. Some of the remaining State Governments have been seeking additional information/clarifications from the Department of Education for consideration of the scheme.

Dr. Zakir Husain Memorial College Trust

6.11.1 Dr. Zakir Husian Memorial College Trust was established in 1973 to take over the responsibility for the management and mainenance of Dr. Zakir Husain College (formerly Delhi College). The maintenance expenditure of the College, which is a constituent college of Delhi University, is shared in the ratio of 95:5 by the University Grants Commission and the Trust. In addition, the University Grants Commission sanctions grants to the College for meeting development expenditure according to the pattern of assistance laid down by the Commission for various types of programmes. The matching contribution to such development expenditure is required to be met by the Trust. Since the Trust has no resource of its own, grants are provided by the Govt. for meeting the above expenditure. The grants also include administrative expenditure of the Trust.

6.11.2 One of the major programmes decided by the Trust was to shift the college from the present premises to Minto Road area. Of the five blocks approved for construction at the new site, the Science Block was completed in 1986 and lectures commenced thereafter. The Administrative Block, the boys and girls common rooms and the canteen buildings were taken over in December, 1987 and January, 1988 respectively. The Arts and Commerce Blocks are nearing completion. The construction of the super-structure of the library is to be taken up very soon. The plans and estimates for the students and teachers hostel, living quarters of the Principal and Vice-Principal and other essential staff, gymnasium and Herbarium are awaiting clearance from the D.D.A. and the U.G.C.

Scheme of National Research Professorship

6.12.0 The Scheme of National Research Professorship was instituted in 1949 to honour distinguished academics and scholars in recognition of their contribution to knowledge in their respective fields. Between 1949 to 1965 nine distinguished scholars were honoured by this award The Scheme was revived in 1982 with the appointment of Dr. Salim Ali, a renowned ornithologist and Prof. T.M.P. Mahadevan, a distinguished Professor of Philosophy. There are at present four National Professors. They are Dr. V.K.R.V. Rao, Economist; Dr. (Justice) D.D. Basu, Constitutional Expert; Dr. C.R. Rao, Mathematician; and Dr. A. Appadorai, Political Scientist.

Association of Indian Universities

6.13.1 The Association of Indian Universities is a voluntary organisation, with universities as members, providing a forum for university administrators and academics to come together to exchange views and discuss matters of common interest. The Association acts as a Bureau of Information in higher education and brings out a number of useful publications, research papers, books and journals on higher education.

6.13.2 The Association is substantially financed from the annual subscription paid by the member-universities. The Government provides grants to the Association for undertaking research/studies in matters of importance to higher education. Financial assistance is also provided for meeting a part of its maintenance expenditure including the activities undertaken by the Research Cell set up with assistance form Government. The Research Cell has undertaken studies concerning issues on Economics of Distance Education, Survey of Science & Technology Manpower in the University Sector, University-Industry Interaction, Graduate Unemployment in India; and Financing of Non-Plan Expenditure in the University Sector. In the area of examination reforms, studies on Question Banking have been taken up. A number of Question Bank books have been published. Currently research studies in (a) University-Industry Intercation, (b) Distance Education, and (c) Question Banking are in progress.

Panjab University

6.14.0 With the re-organisation of the State of Punjab, Panjab University was declared an inter-state body Corporate under the provisions of the Punjab Re-organisation Act, 1966. The maintenance expenditure of the University is being shared at present by the Government of Punjab and the Union Territory Administration of Chandigarh in the ratio of 40:60. The developmental expenditure of the University is met mainly by the grants sanctioned by the UGC, which provides grants for specified programmes in accordance with the guidelines of the Commission. The University, however, has to provide the matching share for the development grants sanctioned by the University Grants Commission, and also finance several projects and programmes which are not covered by the Scheme of the UGC. In order to meet these requirements, the Central Government has been sanctioning an annual loan to the University. During the year 1988-89, a loan of Rs. 50 lakhs was sanctioned to the University for its development programmes.

Delinking of Degrees from Jobs-Establishment of National Testing Service

6.15.1 The National Policy on Education, 1986 visualises the establishment of a National Testing Service to facilitate the process of delinking university degrees from recruitment to services for which a University degree need to be a necessary qualification

6.15.2 The National Testing Service, when established, will (a) conduct tests on a voluntary basis to determine and certify the suitablity of candidates for specified jobs that do not require a diploma or degree qualification; (b) make the tests available for candidates taking the same on their free will (and those who are certified as qualified for specified jobs/services would be eligible for appointment to such jobs/ services without insisting on any other qualification; (c) design a series of tests on the basis of detailed job description, job analysis, etc. to identify requirements of knowledge, competence skills and aptitudes necessary for the purpose of identified jobs;

and (d) function as a well-equipped resource centre at the national level in test development, test administration, test scoring, application of computer system and optional mark reader etc.

6.15.3 The Government have approved the proposal in principle to establish a National Testing Service with the above objectives. The NTS is being set up as a registered society under the Registration of Societies Act. The Memorandum of Association and Rules have been finalised. The composition of the General Council and the Governing Body and appointment of the Chairman and the Director are nearing finalisation. As soon as these details are finalised, the NTS will be registered. It will become operational before the commencement of the financial year 1989-90.

Special Cells for SCs and STs

6.16.1 The Cell is responsible for the review of the policy regarding reservation in admission and appointment in the colleges and universities. The Cell also functions as a Liaison Unit for furnishing information regarding reservation to the Commission for the SCs and STs and the Parliament. Representations received from SC and ST teachers/students/employees in colleges and universities were examined by the Cell and taken up with the concerned authorities, wherever necessary.

6.16.2 The Parliamentary Committee on the Welfare of SCs and STs examined the reservations for and employment of SCs/STs in the UGC and Central Universities, and admission and other facilities provided to the SC/ST students and presented its 38th report to Parliament in 1988. The Cell processed the various recommendations made by the Parliament Committee in consultation with the UGC, Central Universities etc. and furnished to the Lok Sabha Sectt. the action taken notes on the recommendations of the Committee.

Rural Institutes

6.17.0 The National Policy on Education, 1986 envisages establishment of rural institutes/universities on the lines of Gandhiji's ideas on education. For implementation of a well-coordinated programme of development of rural institutes, a Cenral Council of Rural Institutes is proposed to be set up as an autonomous registered body to be fully funded by the Government. The new pattern of education through rural institutes would be based on the concept of correlation between socially useful productive work and academic activities. The rural institutes will undertake extension activities for transformation of the rural areas. The proposed Central Council would identify the rural institutes and other agencies engaged in Gandhian basic education which have potential for growth and are primarily meant for the rural areas but have not received sufficient support and encouragement over the years. The main emphasis in the next few years would be on consolidation and on expansion and support for ongoing programmes and institutions rather than on starting new ones.

National Council of Higher Education

6.18.0 The National Policy on Education, 1986 envisages the establishment of an apex body at the national level for coordination of policy in Higher Education comprising inter-alia, agriculture, medical, technical, legal and other fields in the interest of greater coordination and consistency in policy, etc.

After extensive discussion with the concerned Departments and Agencies, draft proposals for setting up a National Council for Higher Education have been formulated. These proposals were referred to the concerned Ministries and Departments for their comments/concurrence. Some of them have expressed certain reservations on these proposals. In the light of these observation, the whole proposal is being reviewed.

PROGRESS OF TECHNICAL EDUCATION

	1950-51	1960-61	1970-71	1980-81	1986-87
Engineering & Technological Colleges (Degree & above level)					
Number of Institutions	33	78	107	120	225
Enrolment (000's)	17	48	93	130	182
Engineering & Technological Colleges (Below - degree level)					
Number of Institutions	78	130	631	885	1075*
Enrolment (000's)	38	84	133	331	303*

* Relates to 1983-84

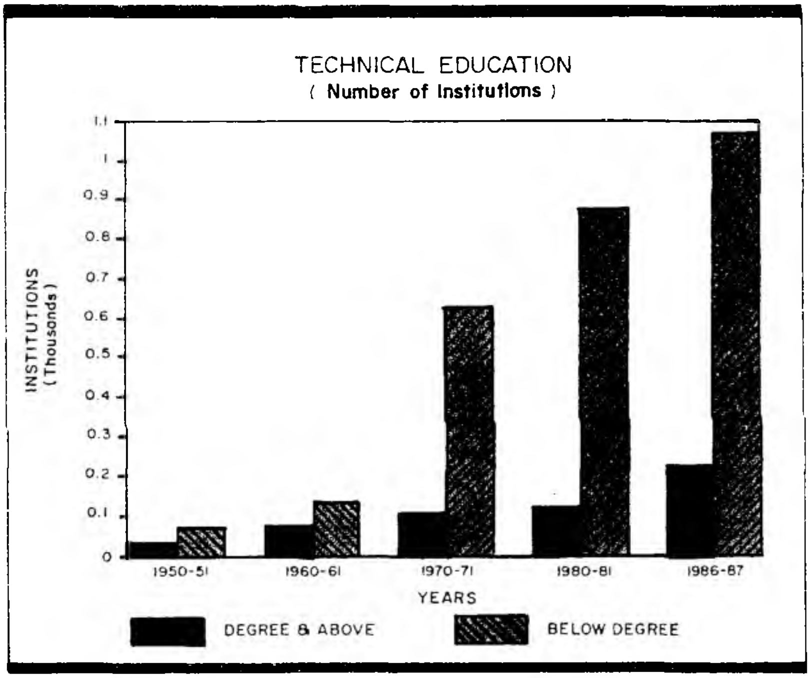

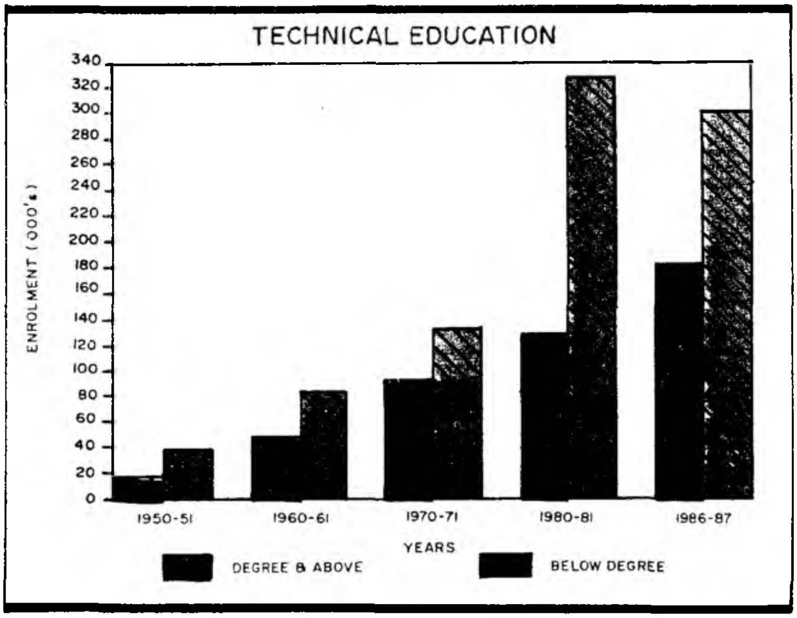

Technical Education

7.1.1 Technical education is one or the most significant components of human resource development spectrum with great potential for adding value to products and services, for contributing to the national economy, and for improving the quality of life of the people. In recognition of the importance of this sector, the successive Five Year Plans laid great emphasis on the development of technical education.

7.1.2 During the past four decades, there has been a phenomenal expansion of technical education facilities in the country as would be evidenced by the graphs presented here. But, a lot more remains to be accomplished in the field of technical education in respect of increasing its coverage and enhancing its accessibility to various categories of people, and in improving its productivity. Moreover, the changing scenario by the turn of the century in socio-economic, industrial and technological areas needs to be considered to enable the system to play its role with greater relevance and objectivity. Based on these considerations, the National Policy on Education (NPE) as well as the Programme of Action (POA) have rightly pointed to several new initiatives to further revamp the technical education system. They include: modernisation and removal of obsolescence, promoting institution-industry interaction, restructuring of courses/programmes, entrepreneurship development, promoting technical education of women, linking technical education with development sectors and application of science and technology for rural development.

7.1.3 The year under report witnessed some significant developments in the field of technical education. Considerable progress was made in implementing the various programmes and schemes based on the NPE. Vested with statutory authority, the All India Council for Technical Education (AICTE) swung into action to fulfil the tasks assigned to it. The first meeting of the statutory AICTE was held on July 6, 1988. Regulations, norms and standards for courses and institutions, fee and admission guidelines, details of accreditation for performance evalution of courses and institution, models for State Directorates, and perspective plans and Programmes of Action (POAs) of Central insititutions and States were got formulated. Several proposals for starting new institutions/courses were examined and seventy of them were approved.

7.2.0 The various programmes/schemes under technical education and their progress during the year are briefly summarised below:—

Indian Institutes of Technology

7.2.1 The five Indian Institutes of Technology (IITs) at Kharagpur, Bombay, Madras, Kanpur and Delhi were established as premier centres of education and training in engineering and applied science at the under-graduate level and to provide adequate facilities for post-graduate studies and research. These are Institutes of National Importance.

7.2.2 The IITs conduct four-year undergraduate programmes leading to Bachelor's Degree in Technology (B.Tech.)/ in various fields of engineering and technology. They also offer integrated Master's Degree courses of five-year duration in physics, chemistry, and mathematics, one-and-a half year M.Tech Degree courses in various specilisations, and one-year post-graduate Diploma courses in selected areas. In addition, the Institutes offer Ph.D. programmes in different branches of engineering, sciences, humanities and social sciences. There are also advanced centres of training and researh in each Institute in identified areas of specialisation.

7.2.3 The IITs have made great contributions in the matter of transfer of technology. A large number of Industries have benefitted from the research work done by these Institutes either under sponsorship or on their own. Over the years, they have also succeeded in developing patents and their exploitation by the industry. Through the sponsored research projects and consultancy work undertaken by the IITs and their faculty, sizeable revenue accrues to the Institutes every year.

7.2.4 Another significant contribution made by the IITs in the development of Science & Technology in the country is the assistance extended by them in the development of curricula etc. for the benefit of other engineering/technological institutions.

7.2.5 These Institutes can take pride in the quality of their students, in as much as they demonstrate by the time they graduate and pass out, high level of competence, values and maturity. Selection of the brightest students and the very high quality of training are the strengths of the IIT system, which is committed to the pursuit of excellence. During the year under report, the Insitutes continued the process of replacement of obsolete equipment and modernisation of laboratories with funds provided for this purpose.

7.2.6 The Institutes continued to help the Regional Engineering Colleges in the development of their laboratories and faculties under the Institutional Network Scheme.

7.2.7 A special preparatory course of 10 months duration was continued to improve the intake of SC/ST students in the IITs. Those SC/ST students who fail to qualify in the Joint Entrance Examination (JEE) for admission to the IITs, but score a certain minimum percentage of marks, are offered admission to this preparatory course. At the end of the preparatory course, these students are subjected to a qualifying test on the basis of which they are offered admission to the B.Tech. programme without having to appear in the JEE again. This has improved the position of intake of SC/ST students in the IITs considerably. The SC/ST students also continued to get financial support from the Institutes by way of pocket allowance, loans and discretionary grants, apart from free messing.

IIT	Admissions	Student strength	Out-turn
	(Total in 1988-89)		
	UG/PG+R	UG/PG+R	UG/PG+R
Delhi	277/799	1054/1624	209/439
Madras	267/493	1067/1281	247/481
Kanpur	268/295	1070/893	220/261
Bombay	326/606	1249/1364	268/404
Kharagpur	364/504	1477/1094	378/442

7.2.8 Each of the IITs has drawn up its own Programme of Action (POA) to implement the directives indicated in the NPE 1986. As desired by the Planning Commission, the Institutes have also formulated approach papers for the development of specific areas during the VIII Five Year Plan. The emphasis for further development will be on strengthening the infra-structural facilities including construction of additional hostels and staff quarters, modernisation of laboratories, introduction of new courses in the emerging thrust areas, removal of obsolescence of equipment, institution of new programmes for quality improvement, staff and faculty development, etc.

7.2.9 A high-powered Review Committee which evaluated the working and performance of IITs submitted its report in Februrary 1987. After due consideration and scrutiny, most of the recommendations have been referred to the IITs for implementation. Other recommendations are under consideration of the IIT Council and an Empowered Committee. Implementation of the recommendations will be monitored by the IIT Council.

7.2.10 Under the 'Assam Accord' the Government had agreed to establish an IIT in Assam. This will be the sixth IIT in the country. The site for the location of this IIT has been selected at Misa in the district of Nagaon. The Institute will have an extension centre at Guwahati. The State Government is in the process of acquiring land in both the places. A Project Team of experts has formulated the detailed project report, which is now being finalised. The budget provision for this scheme during 1988-89 was Rs. 400 lakhs.

Indian Institutes of Management

7.3.1 The four Indian Institutes of Management (IIMs) at Calcutta, Ahmedabad, Bangalore and Lucknow were established in 1961, 1962, 1972 and 1984 respectively to provide facilities for training personnel for careers in management, for conducting research and for contributing to the growth of knowledge in this important area. The Institutes offer post-graduate and fellowship programmes in management as well as executive development programmes for managers in industry. They also conduct in-service programmes for personnel from industry. During the year, the Institutes conducted

several organisation-based programmes and also undertook a large number of consultancy projects.

7.3.2 The new Institute at Lucknow started its first academic session from July 1985. It is in the process of development. The Institute has taken possession of its permanent site, where the civil construction work are in progress.

National Institute for Training in Industrial Engineering

7.4.0 The National Institute for Training in Industrial Engineering (NITIE), Bombay was established in 1963 as an autonomous body with the help of the United Nations Development Programme (UNDP) to provide facilities for training in industrial engineering and allied fields. The Institute offers post-graduate programmes in industrial engineering, post-graduate diploma programmes in industrial engineering (by research) equivalent to M.Tech., and fellowship programmes in industrial engineering equivalent to Ph.D. It organises a large variety of short term executive development programmes and senior executive programmes in the areas of industrial engineering and management techniques. The Institute is also actively engaged in research and consultancy in areas such as operations research, information systems, work systems design, computers and their applications, industrial relations, job evaluation, hazard analysis and other related management fields. The Institute has set up an extension centre at Hyderabad to cater to the needs of the industries and organisations in and around Hyderabad.

National Institute of Foundry and Forge Technology

7.5.1 The National Institute of Foundry and Forge Technology (NIFFT), Ranchi was established during 1966 in collaboration with UNDP-UNESCO as an apex institution for training and research in foundry and forge technology. It is an autonomous institution fully funded by the Government of India. The objectives of the Institute are to:

- provide training through advanced diploma courses, refresher courses, M.Tech. course and unit-based programmes required by industry.
- guide and conduct applied research in foundry and forge technology, and
- provide consultancy, testing, documentation and information services to foundry, forge and allied industries.

7.5.2 The Institute started its 15th advanced diploma course in foundry/forge technology in September 1987 with a total of 54 students. The 3rd batch of M.Tech. course with 13 students commenced in August 1987. During the year 1987-88, the Institute conducted 9 refresher courses attended by 72 sponsored candidates. Faculty members participated in various national and international seminars/symposia/conferences and presented/published 16 technical papers. The Institute interacted with several agencies and also undertook a number of research and consultancy projects.

7.5.3 The Institute has computer centre with a Horison-3,32 bit, 2 RAM system alongwith various peripherals. Newer systems are expected to be acquired in the near future. During 1988-89, the Institute had a budget provision of Rs. 180.00 lakhs.

School of Planning and Architecture

7.6.1 The School of Planning and Architecture (SPA), New Delhi was established in 1955 as a pioneer institution to provide training facilities in areas relating to human settlements and environment. It is an autonomous institution fully financed by the Government of India. The School was given the status of a 'Deemed University' in 1979 to enable it to broaden its horizons of academic programmes, to further promote research and extension programmes, and to award its own under-graduate, post-graduate and doctoral degrees.

7.6.2 The School is conducting a Bachelor's degree course in architecture with an annual sanctioned intake of 68 students in two shifts. It is also conducting Master's Degree courses in planning (with specialisations in urban and regional planning, transport planning and housing), architecture (with specialisations in urban design and architectural conservation), building engineering and management, and landscape architecture. The total intake of post-graduate courses is 110. The institution also conducts Ph.D. programmes with an intake of 10. To promote and coordinate inter-disciplinary research and extension programmes, the School has set up a Centre for Conservation Studies and a Centre for Analysis and Systems Studies in addition to the Centres for Rural Development and Environmental Studies, which are acting as resource centres for the teaching departments. The Centre for Analysis and Systems Studies has an Apollo DN-560 Computer with advanced facilities for computer aided design.

7.6.3 During the year under report, the civi

construction works of a hostel, a guest house and 71 staff quarters were taken up at the Maharani Bagh campus of the School. The School organised several seminars, workshops and short-term courses, and also undertook a number of research and consultancy projects.

Technical Teachers' Training Institutes

7.7.0 The four Technical Teachers' Training Institutes (TTTIs) at Bhopal, Calcutta, Chandigarh and Madras were established in the mid-sixties to provide in-service training to polytechnic teachers and also to undertake various activities for the overall improvement of polytechnic education. They offer long-term training programmes of 12 months/18 months duration to degree and dimploma holding teachers of polytechnics in addition to providing short-term training to teachers introducing them to curriculum development and related activities. The Institutes at Bhopal and Madras have come up to the level of offering post-graduate courses in technical teaching. Besides teacher training, these Institutes also undertake activities such as resource development, extension work, consultancy and project formulation. They are involved in educational film production, national testing services, preparation of instructional packages, etc. under a UNDP project. During the year under report, these Institutes continued their activities in various fields falling within their purview and contributed significantly to the further development of polytechnic education.

International Centre for Science and Technology Education

7.8.0 The International Centre for Science and Technology Education (ICSTE) was set up in 1986 to operate through a network of existing institutions in the country and to serve as a resource centre and a centre for co-operative research. This International Centre will also coordinate research programmes in the area of science and technology education for which little coordinated effort has been made in the country even though a number of institutions are engaged in this activity. The Centre will also cater to the needs of developing countries, and is likely to seek assistance for its programmes from international agencies such as UNESCO and UNDP. The Centre is an autonomous institution fully financed by the Government of India.

Management Education at Non-University Centres

7.9.0 Under this programme, assistance is provided to some selected non-Government, non-University institutions, which are functioning at all-India level and are offering 2-year full time and 3-year part-time post-graduate diploma courses in management studies. Assistance is given on the recommendations of the All India Board of Management Studies of the AICTE.

Regional Engineering Colleges

7.10.1 Fourteen Regional Engineering Colleges (RECs) were set up, on each in the major States, during the Second and Third Plan periods to enable the country to meet the increased need for trained engineering personnel during subsequent Plan periods. The fifteenth REC at Silchar (Assam) started functioning in November 1977, and the sixteenth one at Hamirpur in Himachal Pradesh in July 1986. Establishment of one more REC at Jalandhar in Punjab has been approved and it is expected to start functioning from the academic session 1989-90.

7.10.2 While all the RECs (except the one at Hamirpur) offer first degree courses in civil engineering, mechanical engineering and electrical engineering, many of them also offer first degree courses in chemical engineering, metallurgical engineering, electronics, production engineering, mining engineering, artchitecture and computer science. The REC at Hamirpur is presently offering first degree courses in civil engineering, electrical enginering and electronics. Fourteen RECs also conduct post-graduate courses. Of these, nine are conducting industry-oriented courses, in specialised fields such as design and production of high pressure boilers and accessories, heavy machines for steel plants, transportation engineering, industrial and marine structures, integrated power systems etc.

7.10.3 During the year under report, emphasis was laid on expansion and diversification of academic programmes, modernisation of laboratories including replacement of obsolete equipment, construction of students 'hostels and development of students' activity centres, expansion of research activities, institute-industry collaboration, and instituting new activities like continuing education programmes These Colleges made good progress in the implementation of their developmental plans. One hundred and fifty six laboratories are being developed in these Colleges under the scheme of institutional network with IITs. Four of these institutions have main frame computers, while the others have procured micro system and personal computers mainly to meet the requirements of training students.

7.10.4 In the context of the implementation of the NPE 1986, Programme of Action (POA) documents were prepared by all the RECs re-defining their institutioinal goals and targets, and projecting perspective plans to cover the remaining period of the Seventh Plan and also the Eighth Plan period. During the year under report, only a beginning could be made to undertake the activities indicated in these documents because of the limited resources made available to the REC system.

Development of post-graduate courses and research work

7.11.1 The Government of India is directly assisting 15 State Government and 24 non-Government post-graduate institutions under the central scheme of development of post-graduate education and research in engineering and technology. The scheme has made considerable contribution in promoting development of technical education in general and Research and Development (R&D) in particular. During the year under report, introduction of 7 new post-graduate courses was approved.

7.11.2 Values of research fellowship/research associateship and contingent grant were enhanced with effect from 1st April 1987 in all technical education institutions recognised by the AICTE.

7.11.3 The Graduate Aptitude Test in Engineering (GATE) examination was held in February 1988 on the basis of which admissions were made to post-graduate courses.

Quality Improvement Programme

7.12.1 The Quality Improvement Programme (QIP) was initiated in the year 1970-71 with a view to improve the quality and/standards of technical education. The following programmes are conducted under the scheme :-

(i) Faculty development, which includes
  - M. Tech and Doctoral programmes,
  - Short-term courses at QIP Centres.
  - Summer and winter school programmes through the Indian Society for Technical Education (ISTE).

(ii) Curriculum development, which includes laboratory development, preparation of instructional materials and text-books.

(iii) Practical training in industry for teachers of engineering colleges and polytechnics.

Achievements Under Quality Improvement Programme (QIP)

• Teachers trained for Ph.D.	1100
• Teachers trained for M. Tech.	1020
• Teachers trained at degree-level in Short-term courses	12600 (770 courses)
• Teachers of engineering Colleges and Polytechnics trained through Summer and Winter School programmes of Indian Society for Technical Education (ISTE)	31890

7.12.2 The M. Tech and Doctoral programmes are implemented at the 5 Indian Institutes of Technology (IITs), University of Roorkee, Indian Institute of Science (Bangalore), Banaras Hindu University, a few Regional Engineering Colleges, Anna University (Madras), and Jadavpur University (Calcutta) The programme relating to short-term courses is implemented through the above centres for engineering college teachers, and through the four Technical Teachers' Training Institutes (TTTIs) and the Institute of Engineering and Rural Technology, Allahabad for teachers of diploma level institutions. While the programme of short-term training in industry is organised by the Regional Offices of the Ministry, the summer/winter school programme is organised through the ISTE.

7.12.3 Till 1987-88, about 1020 teachers were trained for M. Tech and 1100 teachers for Ph. D. The QIP Centres organised about 770 short-term courses for degree level teachers, where about 12,600 teachers were trained. The ISTE organised 1472 short-term summer/winter school programmes for teachers of engineering colleges and polytechnics together, wherein about 31,890 teachers were trained. The TTTIs have conducted about 1520 short-term programmes for polytechnic teachers thereby training 31,000 teachers. Under the short-term programme in industry, 6,300 teachers at the degree and diploma levels were trained.

7.12.4 The Curriculum Development Cells at degree level have till now produced 250 text-books, 125 monographs, 50 manuals, 125 other publications and conducted about 175 workshops and seminars. The ISTE has also produced about 90 teachers' manuals.

Computerisation and manpower development

7.13.1 In order to create computer awareness as also to introduce various computer programmes in the existing courses in engineering and technology, the Government of India has been providing support to technical institutions for acquiring computer facility. It has been getting indigenous 'O' level computers evaluated through the National Centre for Software Technology (NCST), Bombay. On the basis of the evaluation report received from NCST, 24 systems have so far been approved. Efforts are being made to provide atleast 'O' level computers in all the approved polytechnics in the country during the seventh Plan.

7.13.2 In collaboration with the Department of Electronics, a few more polytechnics have been selected during the year under report for starting 1½ post-polytechnic diploma course in computer applications making the total number of such polytechnics 55. Three-year Master's Degree course in computer applications was approved at 14 more centres bringing the total number of such institutions to 53. Under-graduate programmes in computer science/ engineering are offered at 37 centres.

Institutional Network Scheme

7.14.1 The scheme was initiated during 1981-82 to develop and internal assistance programme of networking between well developed technological institutions such as the IITs and comparatively less developed institutions such as the RECs and State engineering colleges for development of laboratories, exchange of faculty, training of faculty members and collaborating in research programmes.

7.14.2 During the first three years of the Seventh Plan period 120 laboratories have been supported through the networking scheme and an amount of Rs. 3.00 lakhs has been released for the purpose. It is proposed to develop another 40 laboratories during 1988-89 at a cost of Rs. 100 lakhs.

7.14.3 According to the provisions of the scheme an approved project of networking is supported by the grant of an amount of Rs. 5 lakhs out of which 50% is borne by this Department and the remaining 50% by the institution concerned.

7.14.4 After having reviewed the implementation of the scheme over the years, the following changes in the operation of the scheme have been put into effect :

i) There will be less thrust on purchase of equipment and more thrust on effective 'Internal Assistance' such as faculty exchanges, joint and collaborative research, curriculum development, consultancy, provision for computer time, repairs and maintenance of equipment etc. 40% of the grant may be used for purchase of equipment and 60% for effective internal assistance.

ii) The scope of the scheme is to be developed involving linkage between academic institutions on the one hand and CSIR Research Laboratories, Defence Research Laboratories and other user agencies on the other. A broad-based scheme on institutional networking will be prepared soon.

Thrust Areas of Technical Education

(a) Strengthening of facilities in crucial areas of technology where weakness exists

7.15.1 The scheme was instituted during the Sixth Plan and modified in scope and dimensions during the Seventh Plan with the objective of strengthening facilities in technological institutions offering courses at under-graduate level in certain identified areas of technology where critical gaps exist, through (i) augmentation of physical facilities such as laboratory equipment, space, faculty and supporting staff, (ii) Diversification of courses, and (iii) preparation of base for post-graduate programmes. The identified areas of technology where weakness exists are : computer science/technology, electronics, instrumentation, material science/technology, maintenance

Crucial Areas of Technology Identified for removal of Weakness by Strengthening Infrastructure Facilities/Diversification of Courses

- Computer Science/technology
- Electronics
- Instrumentation
- Material Science/technology
- Maintenance Engineering
- Product development/design
- Bio-Conversion
- Ergonomics
- Printing Technology
- Management Science & entrepreneurship

Emerging Technologies Identified for Creation of Infrastructure

- Energy Science
- Transportation Engineering
- Micro-electronics
- Remote Sensing
- Atmospheric Science
- Reliability Engineering
- Environmental Engineering
- Water resource management
- Optical communication & fibre optics
- Laser technology
- Informatics
- Telematics
- Educational Technology
- Computer aided design/computer aided manufacture
- Micro-processors
- Robotics and artificial intelligence

engineering, product development/design, bio-conversion, ergonomics, printing technology, management science and entrepreneurship.

7.15.2 An amount of Rs.2446.75 lakhs was released during the first three years of the Seventh Plan supporting 217 projects. It is proposed to support 55 projects during 1988-89.

(b) **Creation of infrastructure in areas of emerging technologies.**

7.15.3 The scheme was instituted on an experimental basis during the Sixth Plan period with the objective of creating infrastuctural facilities for education, research and training in 14 identified areas of emerging technology in selected engineering/technological institutions. During the Seventh Plan period, the scope and dimensions of the scheme were enlarged. The objectives of the scheme are :-

— To develop infrastructure in terms of modern laboratories in identified areas of emerging technologies.

— To develop a strong base for advanced level work by identifying programmes and courses.

— To provide facilities and support for R&D activities in frontier areas of technology on a national basis so that technology gaps with reference to advanced countries are eventually bridged.

— Development of manpower.

— Facilities for training the faculty.

— Development of linkages with other institutions including R&D establishments and user agencies.

— Dissemination of information in the areas of expertise developed by the supported institutions.

7.15.4 The areas identified for support under this scheme are : energy science, transporation engineering, micro-electronics, remote sensing, atmospheric science, reliability engineering, environmental engineering, water resource management, optical communication & fibre-optics, laser technology, informatics, telematics, education technology, computer-aided design/computer aided manufacture, micro-processors, robotics and artificial intelligence.

7.15.5 During the first three years of the Seventh Plan, an amount of Rs. 2911.25 lakhs was released to support 206 projects. It is proposed to support 125 projects during 1988-89.

(c) **Programmes of new and/or improved technologies and offering new courses in specialised fields**

7.15.6 This is a new scheme instituted during 1987-88 as part of the implementation of the new National Policy on Education. The scheme has been formulated keeping in view the changing industrial scene and the pace of technology development the world over. Many new areas of technology have evolved in recent years in the conventional as well as emerging fields of technology which have relevance to the national needs, where manpower with appropriate expertise has to be developed. Forty-six new/improved areas of technology have been identified where programmes/courses will be supported under the scheme.

7.15.7 Two projects were supported during 1987-88

TECHNICAL EDUCATION IN THE CAUSE OF RURAL DEVELOPMENT

- Fifteen centres for Development of Rural Technology (CDRTs) for development of technologies relevant to rural needs
- 109 community Polytechnics engaged in transfer of technology to rural folk
- Experimental Pilot Projects for total rural development through select Community Polytechnics
- Special Institutes of Appropriate Technology for rural development

SUPPORT FOR THRUST AREAS IN TECHNICAL EDUCATION (30 AREAS SUPPORTED DURING 1985-1989)

(Some Projects)

AREA	NO. OF PROJECTS	NO. OF INSTS. INVOLVED	GRANT (Rs. IN LAKHS)
COMPUTER SCIENCE/ INFORMATICS/MICROPROCESSORS	120	50	1335
ROBOTICS/ARTIFICIAL INTELLIGENCE/CAD-CAM	89	45	1503
ELECTRONICS/MICRO ELECTRONICS	89	35	1089
INSTRUMENTATION	53	39	607
LASER TECHNOLOGY/FIBRE-OPTICS/REMOTE SENSING	51	39	722
MATERIAL SCIENCE	34	30	397
PRODUCT DEVELOPMENT/ MAINTENANCE ENGG/ RELIABILITY	32	24	589
ENVIRONMENTAL ENGINEERING	44	18	519
BIO-TECHNOLOGY	26	23	314
TRANSPORTATION	25	18	257
WATER RESOURCE MANAGEMENT	23	23	179
ENERGY SCIENCE	18	16	225

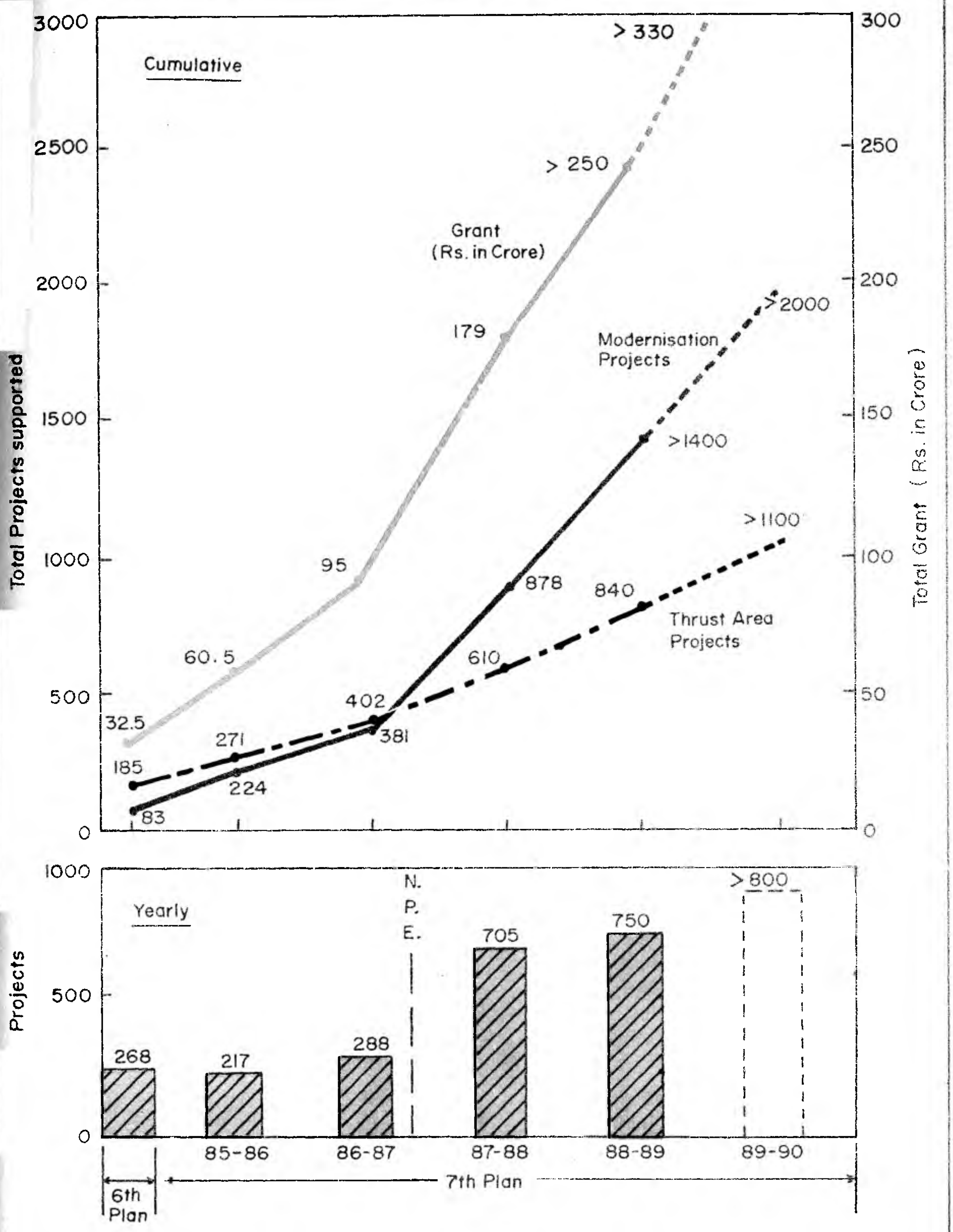

Support for Modernisation and Thrust Areas in Technical Education

Minister of State (Education & Culture) Shri L.P. Shahi chairs Seminar on Entrepreneurship Development.

Centre for Materials Science & Technology, IIT, New Delhi—Thermal analyser in materials research.

at a cost of Rs. 37.00 lakhs only. It is proposed to support 12 projects during 1988-89.

Modernisation and Removal of Obsolescence

7.16.1 The scheme was initiated during the Sixth Plan period with the objective of providing modern instruments and machinery in selected engineering colleges to meet the requirements of technological advances and curricular changes on the basis of 100% direct central assistance.

7.16.2 During the Seventh Plan and more particularly after the new National Policy on Education was adopted, the scope and dimensions of the scheme were expanded to cover IITs, RECs and other engineering colleges including technical universities and technological faculties of universities, polytechnics and removal of obsolescence of human resources. The objectives of the scheme were re-defined as follows:-

- Removal of obsolescence in machinery and equipment of laboratories and workshops in engineering and technological institutions.
- Modernisation by addition of new equipment relevant to the curricular needs as a sequel to the fast developments in technologies.
- To provide students with hand-on experience in laboratory practice in modern technologies.
- Creation of new laboratories.
- Provision of computers.
- Training and re-training of faculty and supporting staff.

7.16.3 The number of projects supported during the first three years of the Seventh Plan and the amounts of grant released each year are given below:

Year	Number of projects supported	Amount of grant released (Rs. in Lakhs)
1985-86	131	1500
1986-87	151	1800
1987-88	497	6000
1988-89	530	4300 (Proposed)

National Technical Manpower Information System

7.17.1 The scheme of National Technical Manpower Information System (NTMIS) was instituted in the year 1983-84 with the objective of providing up-to-date and meaningful manpower projections on a continuing basis to enable the concerned educational authorities to plan areas of growth in the field of engineering and technology on a systematic basis to meet the technical manpower requirements in the country. The system comprises a lead centre at the Institute of Applied Manpower Research, 21 nodal centres at selected engineering colleges/technological institutions/Boards of Apprenticeship Training and a manpower cell in the Ministry.

7.17.2 The scheme is at present being reviewed by an Expert Group. Based on the recommendations of this Group, further action will be taken to expand the scope and coverage of the scheme.

Advanced Technician Courses

7.18.0 The scheme was started in the year 1981-82 with the main objective of providing avenues for advancement of diploma holders. Under this scheme, higher courses of studies at advanced level are provided to enable technicians possessing diploma qualifications in various branches of engineering and technology to acquire higher qualifications in their specialisations and advance professionally. The quality of the pass-outs of these courses has been very well appreciated by the industrial sector. The scheme is at present being implemented through the following 9 institutions:

1. YMCA Institute of Engineering, Farida bad
2. CM Kothari Technological Institute, Madras
3. SBM Polytechnic, Bombay
4. Institute of Engineering & Rural Technology, Allahabad
5. Kamla Nehru Polytechnic for Women, Hyderabad
6. KG Engineering Institute, Bishnupur (WB)
7. Government Polytechnic, Khurai (MP)
8. Khaitan Polytechnic, Jaipur
9. Government Polytechnic, Porbandar

The scheme had a budget provision of Rs. 33.00 lakhs during 1988-89.

Centres for Development of Rural Technology

7.19.0 The scheme was instituted during 1980-81. The 15 CDRTs established at various diploma level institutions are doing exceedingly well in developing, modifying and adopting technologies relevant to rural needs.

Community Polytechnics

7.20.1 The scheme was instituted under the central sector in the year 1978-79, when 36 polytechnics were selected to serve as 'Community Polytechnics'. In addition to offering diploma courses in various branches of engineering and technology, these polytechnics are required to interact with the environment and serve as focal points to promote transfer of technology to rural areas. The activities undertaken by these polytechnics include short-term skill training in various trades/vocations to the rural youth, provision of technical and support services to the rural people, transfer, installation and maintenance of relevant items of appropriate technology already developed, tested and adopted, establishment of information and dissemination centres and undertaking experimental model projects for rural development with application of science and technology. During 1984-85, 10 polytechnics situated in close proximity to predominantly minority concentrated areas were approved as community polytechnics to impart skill training to the youth from among the minority communities. During 1988-89, the scheme was further expanded to cover 2 more polytechnics in the minority concentrated areas in the State of Assam. At present there are in all 109 Community Polytechnics under the scheme.

7.20.2 The Community Polytechnics have set up extension centres in far flung rural areas to ensure that the services and facilities under the scheme are available right at the door step of the villages. The total number of extension centres so set up in rural areas is about 236. The number of people trained since the inception of the scheme is of the order of 94,000 and the number of villages benefitted through technical services/transfer of technology is about 3600. In order to assess its utility, the scheme was recently appraised. Based on this appraisal, the scheme is being further strengthened and expanded.

Programme of Apprenticeship Training

7.21.1 The Programme of Apprenticeship Training for engineering graduates and diploma holders under the Apprentices Act 1961 (amended in 1973) continued to be implemented through the four Boards of Apprenticeship Training located at Kanpur, Calcutta, Bombay and Madras. The Boards have State-level Committee for better liaison with industry. The cost of stipend being paid to apprentices is shared by the training establishments and the Government of India.

7.21.2 The number of apprentices engaged every year as on 31st October for the last three years is shown below.

	31-10-86	31-10-87	31-10-88
Total trainees	16362	17352	21221
Graduate trainees	4658	4667	6021
Diploma holders	11704	12685	15200
Scheduled Castes	242	450	547
Scheduled Tribes	65	80	104
Minorities	767	1208	1082
Handicapped	9	2	12
Women	927	1138	1273

7.21.3 A number of supervisory development programmes for improving the quality of apprenticeship training and career guidance programmes for the final year students of a few engineering colleges and polytechnics were organised by the Board. The Boards are publishing journals containing informative articles. Some of them have prepared training manuals.

7.21.4 A new scheme of apprenticeship training for 10+2 vocational students was introduced from the year 1988-89.

Experimental Pilot Projects For Application of Science And Technology To Rural Development

7.22.0 This is a new scheme included in the seventh Five Year Plan. The scheme is intended to facilitate selected community polytechnics and/or other specialised institutions involved in this work to take up experimental model pilot projects for application of Science and Technology for total rural development of a chosen area, to make the educational efforts more relevant to the live situations in the rural areas and develop a few viable and replicable models to help and promote rural development on scientific lines. The scheme envisages a cluster of 100 villages as a single unit to be taken up for total rural development. The project is to be managed by a team of professional managers consisting of a General Manager at Head Quarters, Area Managers at the nodal centres and Managers at the village level. The coordinaing institution shall be the resource institution and will serve the Governing Council of the project, which shall comprise all interests concerned with rural development. The various community polytechnics and other institutions shall provide the necessary scientific and technological inputs. The projects would aim at multiplying the income of the area by 10 times in a period of five years, generating employment, improving productivity, promoting

self-reliance and making life richer and wholesome through scientific, technological and management inputs. The project will be validated through action research.

Special Institutes of Appropriate Technology and Rural Development

7.23.0 This is a new scheme included in the Seventh Five Year Plan. These Institutes are expected to serve as centres of excellence to develop and organise courses from certificate level to post-graduate level, and to do research in different branches of appropriate technology and rural development. In addition, they will serve as focal centres for transfer of technology and integrated rural development, and also act as resource institutions for all other institutions and organisations involved in rural development.

Asian Institute of Technology, Bangkok

7.24.1 The Asian Institute of Technology, Bangkok is an autonomous international graduate institute providing advanced education in engineering, sciences and allied fields. It enrolls about 600 students from more than 20 countries and has international faculty members. The Institute is governed by an International Board of Trustees, whose members come from different countries including India. It conducts academic programmes in nine disciplines, does research on problems relevant to Asian countries, and organises special programmes including short courses and conference.

7.24.2 The Government of India has agreed to provide the following assistance to the AIT:—

- Deputation of Indian teachers/experts in specialised areas of engineering and technology meeting the entire cost of their deputation.
- An annual grant upto Rs. 3.00 lakhs for utilisation for one or more of the following purposes:—
    a) Purchase of equipment from India,
    b) Purchase of books and payments for subscription of academic and technical journals published in India, and
    c) Expenditure on academic related activities in India.

7.24.3 During the period 1983-88, 42 Indian experts were deputed to AIT, Bangkok.

Educational Consultants India Ltd.

7.25.1 The only Public Sector Undertaking under this Ministry, Educational Consultants India Limited, New Delhi was incorporated under the Companies Act, 1956 on June 17, 1981. It functions under the guidance of a Board of Directors representing various Ministries and organisations of the Central Government. It has a part-time non-official Chairman and a full-time Managing Director.

7.25.2 During the year 1988-89, the Company diversified many of its activities including the starting of the first turn-key job for the establishment of an Electronics Design Laboratory in Bangkok, Thailand. The Company also completed the following projects in India and abroad:—

In India:

1. Establishment of the Department of Bio-Engineering and Medical Instrumentation, University of Health Science, Vijayawada.
2. Establishment of a Technical Training Institute, New Okhla Industrial Development Authority, NOIDA, U.P.
3. Evaluation of Educational Societies for allotment of land to set up schools, New Okhla Industrial Development Authority, U.P.
4. Establishment of a training nucleus for ship building industry in India, Hindustan Shipyard Limited, Visakhapatnam.
5. Preparation of Detailed Project Report for the establishment of National Testing Service in India, Ministry of Human Resource Development.
6. Establishment of a Central University in Assam, Ministry of Human Resource Development.
7. Establishment of a Central Council for Rural Institutes/Universities and setting up of Rural Institutes/Universities, Ministry of Human Resource Development.
8. Servicing of 21 projects of Bureau of Technical Education, Ministry of Human Resource Development, including Project Reports for setting up Residential Polytechnics for Women and establishment of Longowal Institute of Enginnering and Technology, Longowal (Punjab), Ministry of Human Resource Development.

Abroad:

1. Preparation of a Master Plan for Moi University, Government of Kenya.
2. Secondment of Indian teachers for secondary schools in Botswana, Ministry of Education, Republic of Botswana.
3. Inter-regional Technical Cooperation between India and African countries, UNESCO, Paris.
4. Recruitment of Principals and Vice-Principal-cum-Administrators for Embassy of India Schools in Riyadh and Jaddah, through Embassy of India, Riyadh, Saudi Arabia.

7.25.3 The Company increased its turnover by 30 per cent, while the profits increased by 100 per cent over the financial figures of last year. While growth in almost all areas of operations of the Company was maintained, there was a downward trend in the number of foreign students training programmes.

7.25.4 During 1987-88, the Company earned a profit of Rs. 38.66 lakhs after depreciation. The Company declared payment of a maiden dividend of 10% i.e. Rs. 10/- per share.

Board of Assessment for Educational Qualifications

7.26.1 The Board of Assessment for Educational Qualifications was set up by the Government of India for the purpose of recognition of academic and professional qualifications for employment to posts and services under the Central Government. The Technical Education Bureau is the Secretariat of the Board and Chairman, UPSC is the Chairman of the Board.

7.26.2 Seven academic qualifications (six Indian and one foreign) were accorded recognition during the year. A Protocol in equivalence of qualifications with USSR was also signed.

Partial Financial Assistance

7.27.1 The Bureau of Technical Education administers the scheme of 'Partial Financial Assistance' to provide financial assistance partially to teachers in the fields of science, technology and medicine towards the cost of airfare for attending international conferences abroad.

7.27.2 During the year, 10 persons who chaired conference sessions abroad, were given assistance.

Residential Polytechnics for Women

7.28.0 The scheme was sanctioned for setting up Residential Polytechnics for Women to provide appropriate formal and non-formal programmes of technical education for the benefit of women. These polytechnics will be autonomous in character and will have freedom to design, develop implement and review their courses/programmes, and to award their own diplomas and certificates duly endorsed by the concerned State Board of Technical Education. They will be fully residential in character and will offer courses in technology areas with high potential for employment.

Strengthening of Existing Institutions and Establishment of New Institutions for Non-corporate and Un-organised Sectors

7.29.0 The objective of this scheme is to establish Centres for Entrepreneurship and Management Development (CEMDEVs) and Centres for Entrepreneurship Development (CEDs) at a few selected diploma level institutions to meet the requirements of the un-organised and non-corporate sectors, which employ about 90% of the work force. To start with, it is proposed to establish four CEMDEVs in the Technical Teacher's Training Institutes at Bhopal, Calcutta, Chandigarh and Madras, which are resource institutions for the technician education system in the country.

Restructuring of Courses/Programmes in Technical Education

7.30.0 This new scheme instituted during 1987-88 as part of the implementation of the National Policy on Education provides for restructuring of courses/programmes at the diploma, degree and post-graduate levels. In 1987-88, the scheme was implemented at four institutions - two each at degree and diploma levels and a plan outlay of Rs. 10.00 lakhs was released for the purpose.

Curriculum Development

7.31.1 The scheme was started during 1987-88 as part of the implementation of the National Policy on Education with the following broad objectives:

— Updating the curriculum to meet the demands of the user agencies.

— Developing curriculum for multi-point entry and credit system both at the degree and diploma levels.

- Preparation of multi-media packages including distance education packages and learning/teaching manuals.
- Preparation of transparencies, slides, video films for laboratory and class room use.
- Assessing the needs of institutions in the States, providing feed-back to Curriculum Development Cells (CDCs) and establishing links between CDCs and institutions.

7.31.2 During 1987-88, seven existing Curriculum Development Centres at the IITs, IISc Bangalore and University of Roorkee were taken up for strengthening to facilitate them to institute several new activities and consolidate the on-going programmes. The scheme envisages establishment of Resource Development Centres, Learning Resource Centres and State-level Curriculum Development Cells.

Industry-Institute Interaction

7.32.1 The scheme of 'Industry-Institute Interaction' was approved in October 1988. The scheme envisages:

(a) Interaction between engineering colleges and industry.

(b) Interaction between polytechnics and industry.

(c) Setting up of one 'Industrial Foundation at IIT Delhi.

7.32.2 During 1988-89, it is expected that the scheme will be introduced in 18 engineering colleges and 10 polytechnics. At the college level, it is envisaged that at-least two joint research projects will be undertaken between each college and an industrial establishment. There will also be faculty exchanges between institutions and industry.

7.32.3 The Industrial Foundation proposed to be set up at IIT Delhi will be responsible for marketing the research and consultancy capabilities for the Institutes tackling scientific and technological problems sponsored by industry and other organisations, commercialisation of research results through the stages of proto-type development and industrial pilot plants, undertaking cooperative research programmes jointly with industry, disseminating technology information, and providing general technology support to industry.

Technical Education Highlights

- All India Council of Technical Education (AICTE) Act passed and brought into force.
- Researches of Indian Institutes of Technology (IITs), own and sponsored, have resulted in development of patents and their utilisation by Industries.
- Networking of IITs with other engineering/technological institutions
- Conduct of special preparatory courses for improving intake of SCs/STs to IITs.
- Decision to locate the Sixth IIT (under Assam Accord) at MISA in Nagaon - with an extension centre at Guwahati
- Approval for Regional Engineering College at Jalandhar (scheduled to start functioning in academic session, 1989-90)
- Continued emphasis on massive training of teachers of doctoral, post-graduate, graduate etc. levels through Quality Improvement Programme (QIP)
- Significant investments in areas of crucial and emerging technologies
- National Technical Manpower Information System being reviewed
- Technical education pressed into service for rural development
- Massive apprenticeship training for engineering graduates and diploma holders; introduction of apprenticeship training for PLUS TWO vocational students
- Formal and non-formal technical education for women through Residential Polytechnics

Continuing Education

7.33.1 The scheme of 'Continuing Education' was launched in February 1988 for preparation of course materials in engineering/technology areas to meet the needs of working professionals. The scheme has broadly two aspects:

(i) To prepare course materials on selected topics identified in consultation with industry and other user agencies.

(ii) To conduct a survey of continuing education requirements based on which course materials are to be prepared in future.

7.33.2 There is a third element of coordination of the material being prepared through 10 organisations, viz. the five IITs located at Delhi, Kanpur, Kharagpur, Bombay and Madras, the four TTTIs located at Chandigarh, Calcutta, Madras and Bhopal and the Indian Society for Technical Education.

7.33.3 It is expected that 137 course materials will be prepared by the end of 1988-89.

Establishment of New Institutions and Introduction of New Courses/Programmes

7.34.0 During the year under report, establishment of 15 new polytechnics in various parts of India and introduction of 55 new courses/programmes in various institutions were approved.

7.35.0 In short, technical education made significant progress during the year under report. While several new initiatives were taken to increase the coverage of technical education and enhance its accessibility, all the on-going programmes/schemes were revamped and re-oriented in the light of the directives/goals enunciated in the NPE. By and large the financial allocations made for the various programmes/schemes were optimally utilised.

Adult Education

(National Literacy Mission)

8.1.0 Promotion of literacy has been identified as one of the six National Missions with a view to applying technology and scientific research for the benefit of the deprived sections of society and the areas which are critical to the country's development. The National Literacy Mission (NLM) aims at imparting functional literacy to 80 million adult illiterates in the 15-35 age-group—30 million by 1990 and an additional 50 million by 1995. The Mission seeks to employ various strategies to achieve this objective. It is not a substitution for the ongoing programmes of adult education but seeks to make determined efforts to correct some of the deficiencies and constraints of the earlier programmes by providing new institutional structures and ensuring better utilisation of the existing infrastructure. A National Campaign for Mass Mobilisation of NLM was launched by the Prime Minister on 5th May, 1988 in New Delhi. Simultaneously, all States/UTs also launched similar campaigns at the State level. Twenty four States/UTs are reported to have organised such programmes.

Rural Functional Literacy Projects (RFLPs)

8.2.1 This is a Centrally Sponsored Scheme under which funds are provided on cent percent basis in accordance with the approved financial pattern to all the State Governments and Union Territory Administrations. The pattern of funding of RFLP has been reviewed and revised, and the new pattern has been effective w.e.f. 1.4.88. In the revised pattern, the span of supervision has been reduced and the training components have been greatly strengthened. The scheme aims at setting up projects, upto 300 centres covering one or two contiguous development blocks in each district and upto 100 centres in hilly areas in some States. During 1988-89, 513 projects covering almost all the districts of the country were continued. In all 39.40 lakh adult illiterates were enrolled under the RFLPs by the end of September, 1988 in 132291 adult education centres. Of this, women constituted 57.50% and members of Scheduled Castes and Scheduled Tribes communities formed around 25.63% and 13.8% respectively.

8.2.2 In addition to adult education centres sanctioned under RFLP, State Governments/UT administrations have also opened 109218 adult education centres under the State Adult Education Projects (SAEPs) with 32.87 lakh learners by the end of September, 1988.

Voluntary Agencies (VAs)

8.3.1 Financial assistance is provided to voluntary agencies working in the field of adult education under which registered societies are eligible to receive grants for projects of functional literacy, post-literacy through Jana Shikshan Nilayams, resource development, publications, holding of seminars, etc. In pursuance of the Strategies envisaged in the National Literacy Mission, the scheme has been liberalised and streamlined by simplifying various procedures. The concept of area development approach has been incorporated in the revised scheme, which would enable voluntary agencies to take up functional literacy projects in a compact and contiguous area in a specified time frame.

8.3.2 During the current year upto November, 1988, about 200 voluntary agencies were assisted for running 11,415 Adult Education Centres (AECs) and 964 Jana Shikshan Nilayams (JSNs).

Students Involvement In Adult Education

8.4.1 With a view to promoting involvement of

students and teachers from universities and colleges in literacy work in the age group 15-35, the University Grants Commission continued to provide financial assistance and support to 92 universities and colleges, for setting up of adult education centres through the Departments of Adult and Continuing Education attached to Universities.

8.4.2 Additionally, the Government launched a programme on 1st May, 1986 involving approximately 2 lakh NSS (National Service Scheme) and 1 lakh Non-NSS students in the universities and colleges for implementing the programme of functional literacy on a voluntary basis. Literacy kits were provided to the learners by the State Resource Centres free of cost. The entire programme is sought to be implemented in terms of voluntary efforts on the part of students. A target of 3.50 lakh NSS students, 1.50 lakh other students and 0.75 lakh NCC cadets to be involved under Mass Programme for Functional Literacy (MPFL) was set.

Strengthening of Administrative Structures (SAS) in States/UTs

8.5.0 For ensuring proper implementation of adult education programme in each State/UT financial assistance is provided to them for continuation/creation of necessary administrative structure both at the State and District levels, in accordance with financial pattern approved under the Scheme. The Scheme was revised during 1987 and additional staff both at the State and District levels was sanctioned to States/Union Territories for proper implementation, supervision, and monitoring of National Literacy Mission Programme. At present 26 States/UTs are receiving financial assistance under this Scheme. The central objective of the scheme is to create a cadre of intelligent, knowledgeable and competent persons who have the requisite perception and commitment to adult education.

Evaluation of Adult Education Programme

8.6.0 External evaluation of the adult education programme is an important input to ensure the quality of the programme. Sixteen reputed Institutes of Social Sciences Research have been identified to undertake evaluation and appraisal of the programme in 12 States of the country to be subsequently extended to other States. So far six evaluation agencies have been given financial assistance for this purpose.

Academic and Technical Support Through State Resource Centres

8.7.1 There are, in all 13 State Resource Centres which are being financed by the Department of Education and they provide necessary academic and technical support to the Adult Education Programme by way of production of materials for basic, post-literacy and continuing education, as also by way of imparting training. Additionally, 2 State Resource Centres are being run by the State Governments and 3 by University Grants Commission. Besides, 4 Research Cells were approved for Manipur and Tripura, Arunachal Pradesh and Sikkim, out of which two at Manipur and Arunachal Pradesh have been formally set up. The State Resource Centres are autonomous bodies and are managed by their Boards of Management. A financing pattern with 80 percent grant by the Central Government, 15 per cent by the State Government and 5 per cent by voluntary agencies has been laid down in respect of 13 SRCs mentioned above. The SRCs have taken up the additional responsibility of preparation of kit materials and training of Master Trainers under the Mass Programme of Functional Literacy. They have also taken up the development of software to provide necessary media support to the Adult Education Programme.

8.7.2 The functioning of all SRCs has been reviewed by an expert and corrective measures are being taken. As a measure of further de-centralisation and also to strengthen the resource support at the grassroot level, sanctions for 110 District Resource Units have been issued.

Mass Programme for Functional Literacy (MPFL)

8.8.0 One of the strategies of the NLM is to launch a mass movement so as to make literacy a people's Mission and to harness all agencies for the Mission. Apart from the students of universities and colleges who have already been involved under the MPFL, a beginning has been made this year to broad-base this programme. Significant steps taken so far are:-

(i) A Conference of Central Employers and Trade Unions was held on 7.7.1988 to discuss and finalise the modalities of their involvement. The manner in which these organisations can assist the literacy programmes is being discussed by them with their Federations/Unions.

(ii) The Railway Board took up implementation of the programme for their employees and their family members through 425 Adult Education Centres to be opened at different places in 9 Railway zones. Funds for provision of

MASS CAMPAIGN
FOR
NATIONAL LITERACY
MISSION
LAUNCHING
MAY 5, 1988

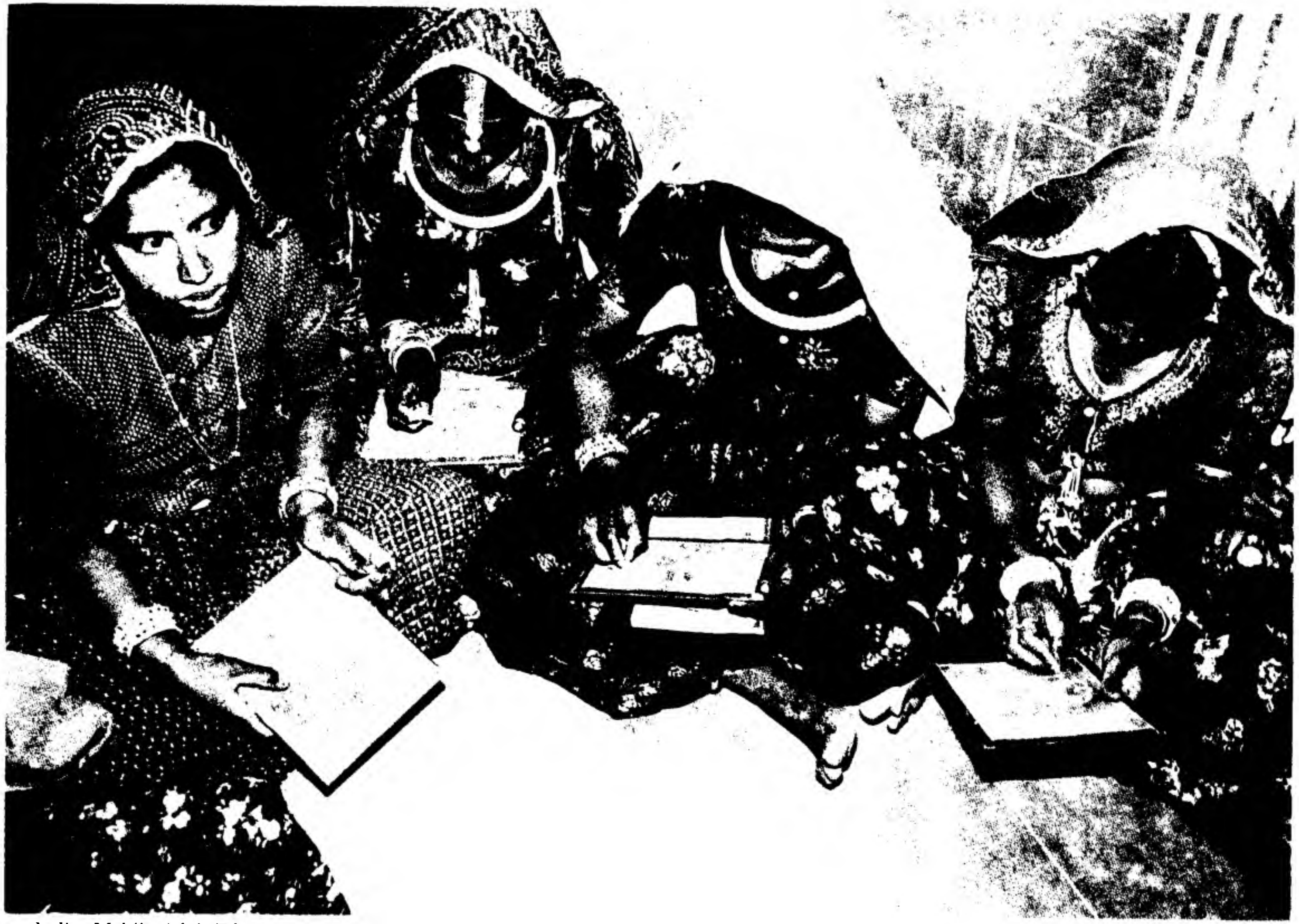

Indira Mahila Adult Education Centre, Khanakhedi Village, Srinagar, Ajmer, Rajasthan.

Nanu Bazar Donga Adivasi Adult Education Centre, Mohd. Bazar Block, Bhırbhum District, West Bengal.

literacy kits and organisation of training to Instructors were provided by the Department of Education and the rest have been provided by the Railways. Detailed action plans were formulated by zonal Railways.

(iii) Home Secretaries of all State Govts./UTs and IG (Prisons) were requested to organise functional literacy programme and vocational training courses for prisons inmates (both under trials and life convicts) who may be adults (15-35). The Union Home Secretary wrote to all Chief Secretaries in regard to this.

(iv) A Saksharata Abhiyan was launched by Gujarat Vidyapeeth, Ahmedabad in May-June, 1988 involving 2,60,000 student volunteers and covering 1,45,000 persons.

(v) In the Metropolitan city of Delhi a beginning was made for involving School students in the Mission. Seven thousand school students took pledge to eradicate illiteracy at Rajghat on 8th September, 1988 on the occasion of the International Literacy Day. A national level function was also organised at Indira Gandhi Stadium in which 10000 students took part. Since then 78 schools of Delhi have involved themselves in this programme.

Post Literacy and Continuing Education

8.9.0 As provided in the National Literacy Mission document, the Government decided in February, 1988 to establish Jana Shikshan Nilayams (JSNs) all over the country in a phased manner. This is an institutionalised set-up of post-literacy and continuing education on a permanent basis. The basic objective in providing this set-up is to ensure retention of literacy skills, provision of facilities to enable the learners to continue their learning beyond elementary literacy, and to create scope for application of their learning for improvement of their living conditions. These JSNs will re-capture and harness the cultural energy and creativity in rural areas and will help in creation of a learning society. So far 10,065 JSNs have been sanctioned to all States/UTs. These are in the process of being set up. It is expected that an additional 4300 JSNs may be sanctioned in the current year.

Technology Demonstration

8.10.1 The process of Technology Demonstration seeks to apply the findings of scientific and technological research to improve the pace and quality of the literacy programme. Forty Districts have been identified for development, transfer and application of techno-pedagogic inputs. Twenty out of them are under-endowed and the remaining twenty are well-endowed in terms of the infrastructure available in these Districts.

8.10.2 The steps taken for developing and application of various techno-pedagogic inputs are as follows:-

* The Department of Non-conventional Energy Sources (DNES) has undertaken a pilot project of installing Solar Power Packs in unelectrified villages of 5 Districts. So far 93 SPPs have been installed in Aligarh, Bikaner and Osmanabad Districts.
* The Indian Petro-chemicals Corporation Limited (IPCL) has developed improved plastic blackboards. One thousand such prototype blackboards are being field-tested in Gujarat and Maharashtra.
* The Central Electronics Limited (CEL) has field tested its projection TV in Rajasthan and Karnataka with satisfactory results.
* A Panel for Technology Demonstration has been constituted to advise on the R & D for the Science and Technology inputs for NLM in general and Technology Demonstration process in particular.

National Literacy Mission Authority

8.11.0 A National Literacy Mission Authority (NLMA) has been set by a Resolution in June, 1988. NLMA is an independent and autonomous wing of the Ministry of Human Resource Development (Department of Education) vested with executive and financial powers in its sphere of work. It is the operating and implementing organisation at the national level for all the activities envisaged in NLM. The NLMA has a Council and the Executive Committee which have been constituted through a Notification issued in June, 1988. The Council and the Executive Committee have met on several occasions and have considered various important issues concerning the NLM. These are:

(i) A critical review of NLM.

(ii) Mass mobilisation involving school students of Secondary and higher Secondary Stages.

(iii) Setting up of National Institute of Adult Education.

(iv) Delegation of financial and administrative powers to the NLMA.
(v) Technology Demonstration Process.
(vi) Imparting literacy through TV-VCP.
(vii) Organisation of Jathas or Literacy caravans.

Post Office Box No. 9999

8.12.0 A common post box number - 9999 has been allotted by the Department of Posts to the Central and State Govts./UTs. Any person who is an adult illiterate and who wants to avail of the facilities and services under NLM or any person who wants to contribute in any manner whatsoever towards the success of NLM could write to this Post Box and will get a positive response. This Post Box has already been operationalised at the National level and is being operationalised at the State and District level in due course.

Shramik Vidyapeeth (SVPs)

8.13.1 Thirty six SVPs now functioning in different industrial centres of the country represent the institutional framework for offering non-formal continuing education and polyvalent training programmes to employed workers; self-employed persons, prospective workers and family members of industrial workers, with a view to opening up employment opportunities for the unemployed workers and raising earning capacity for the employed workers. The SVPs are the only institutions for these persons who, having low educational qualifications and low income, cannot secure admission to any industrial training institute or engineering institute. The first SVP was set up in 1967 in Bombay. Out of 36 SVPs now functioning, only one is being run by the Central Government in Delhi. Three SVPs are being run by Universities, twenty-three by autonomous bodies and remaining nine by State Governments.

8.13.2 The affairs of each SVP are managed by a Board of Management headed by one honorary Chairman. The Board consists of members representing the interest of workers and the employers, educational, social and development agencies and persons evincing interest in the education and training of workers as a special segment of adults. Each SVP has a nucleus of professional staff under the control of a Director who is assisted by two or three full-time programme officers. In conducting various courses, each SVP engages services of local qualified and experienced resource persons to import different skills or organise courses relevant to specific areas on part-time basis. These instructors are paid honorarium for each lecture they deliver.

8.13.3 Before designing programmes, a socio-economic profile and work plan for operationalisation of activities have been designed in all the SVPs. The socio-economic profiles of the respective Catchment industrial areas have provided the parameters within which the SVPs will operate their programmes. Such profiles have helped the SVPs to have complete understanding of the manpower needs of the urban milieu the felt needs of the industrial workers regarding increasing their earning potential and the resources (potential and unutilised) that can be harnessed.

8.13.4 The programmes are offered in the form of course activities and follow up services, all of which constitute special services for Adult Education Workers - illiterate, semi-literate, skilled, semi-skilled, unskilled, men or women in organised or unorganised sector. In conducting programmes, SVPs seek co-operation/collaboration of various local agencies, trade unions, industrial establishments, welfare centres, development agencies and financial support agencies, etc. This practice helps in mobilization of resources available with other agencies in the form of use of premises, services of instructors, use of tools and equipments and sharing supervision and managements of the programme which would otherwise cost enormously.

8.13.5 A team has been constituted in the Ministry to make case by case critical study of the SVPs regarding their performance. Organisation of training cycle for Directors and Programme Officers of SVPs has been done. Three different training programmes have been conducted so far in Directorate of Adult Education, Delhi for SVP Directors and Programme Officers for reorientation of approach for conducting training classes in SVPs. A system of providing immediate feedback to ensure improved performance has been evolved. Certain proformae have been prescribed by DAE, Delhi for submission of reports by SVPs in regard to their ongoing programmes.

8.13.6 Under the scheme of financial assistance to SVPs, some seed money (Rs. 3.5 lakhs) is provided for running the programmes and meeting the expenditure towards salaries of staff. All the SVPs have been asked to generate their own resources to expand and strengthen their programmes. A review of financial pattern of assistance of SVPs has been done and the matter has been placed before Expenditure Finance Committee for approval.

8.13.7 At present, emphasis is being given to creation of a data base to project the consolidated impact each SVP has so far made to uplift the living conditions of its clientele. In doing so, the SVPs will undertake follow-up of the present positions of their ex-learners to ascertain how the training they received in SVP's facilitated increase in their earnings.

8.13.8 During 1987-88, as many as 5862 programmes were conducted in the SVPs, out of which 3467 were vocational courses and 2395 were other programmes. A detailed break-up of beneficiaries in these courses and programmes are given below:—

I.	Total No. of beneficiaries of courses and other activities		—	2,30,156
		Male—		88,272 (33.35%)
		Female—		1,41,884 (61.65%)
II.	Total No. of beneficiaries in vocational courses		—	67,785
	Male	— 22,935 (33.83%)		
	Female	-44,850 (66.17%)		
III.	Total No. of beneficiaries in activities other than vocational courses	—1,62,371		
	Male	—65,924 (40.60%)		
	Female	—96,447 (59.40%)		Total : 2,30,156

Break-up of Item II above

I. SC/ST participation

SC	ST	Others
13,809	2,513	51,463
(20.37%)	(3.71%)	(75.92%)

II. Literacy Status

With some education	Illiterate
55,485	12,300
(81.85%)	(18.15%)

III. Age-Group

Below 15 years	15-35 years	above 35 years
2,951	60,798	4,036
(4.35%)	(89.70%)	(5.95%)

IV. Income background

Below Rs. 500 PM	Rs. 500—Rs. 1500 PM	Rs. 1500 PM
44,571	20,666	2,548
(65.75%)	(30.49%)	(3.76%)

V. Occupational Structure

Industrial & Wage earners	Self employed	Prospective workers
9,060	15,069	43,656
(13.37%)	(22.23%)	(64.40%)

International & Unesco Matters

8.14.1 A 'Asia-Pacific Programme of Education for All' (acronym 'APPEAL'), was launched in February, 1987 which aims at eradicating illiteracy, universalising primary education and strengthening infrastructure for continuing education in Asia and the Pacific. A National Coordination Committee on APPEAL has been set up to make an appraisal of the activities undertaken in this country to formulate new programmes and to plan strategies for its implementation.

8.14.2 The UN General Assembly has also declared 1990 as the International Literacy Year (ILY). The Coordination Committee on APPEAL will also function as the Coordination Committee on ILY to plan strategies for the celebration of ILY. The Committee has so far met twice during this year. DG: UNESCO also addressed the members of this committee during his visit to India in December, 1988.

8.14.3 A representative from the Directorate of Adult Education attended the Regional Workshop on Development of Training Materials organised by UNESCO in Thailand and China from 1—23rd August, 1988.

8.14.4 A meeting of the Working Group on ILY was organised in New Delhi from 10th-14th October, 1988. It was attended by delegates from Afghanistan, Bangladesh, Indonesia, India, Iran, Nepal and Pakistan. The working group was chaired by DG: NLMA (delegate from India).

8.14.5 The UNESCO also organised a meeting of the Regional Coordination Committee of APPEAL in Bangkok from 14th-18th November, 1988 which was attended by DG: NLM, New Delhi.

8.14.6 Director, Directorate of Adult Education was deputed to attend the International Conference on Role of Government in Adult Education held in Sydney, Australia from 2nd—11th November, 1988.

Directorate of Adult Education

8.15.1 The Directorate of Adult Education (DAE) is the National Apex Resource Centre. It has initiated several steps for providing professional resource support as well as on creating mechanism for improved management of the programme at all levels.

8.15.2 The efforts to introduce Rapid Literacy Learning Methods were continued during this year also. During the year, three workshops were organised to study the scope and possibilities of rapid literacy in different parts of the country. Based on the recommendations of the workshops, follow-up activities have been initiated to prepare guidelines on Rapid Literacy Learning Methods. The central

objective of this exercise is to reduce the overall duration of learning without sacrificing the components of functionality and awareness, quicken the pace of learning and achieve higher coverage in a short time.

8.15.3 The thrust in the entire literacy promotion effort is attainment of prescribed levels of literacy and numeracy and not mere coverage. A workshop was also held on the various norms and parameters of evaluation of learning outcome.

8.15.4 To impart literacy in spoken languages, a workshop to identify the languages on which the teaching learning material is to be prepared was organised.

8.15.5 So far teaching learning materials have been prepared in the following spoken languages.

Halbi	Madhya Pradesh
Bhili	Madhya Pradesh
Nagpuria	Bihar
Braj	Uttar Pradesh
Dhundhani	Rajasthan
Marwari	Rajasthan
Haroti	Rajasthan
Dogri	Himachal Pradesh
Chamiali	Himachal Pradesh
Kinnori	Himachal Pradesh

8.15.6 As recommended by the task force on MIS and Evaluation, the existing system of monitoring and evaluation has been reviewed. For the purpose of new MIS, a feasibility study was conducted in collaboration with National Institute of Information Technology (NIIT). MIS format has been prepared and finalised after pre-test. The formats will be amenable to both physical and computerised compilation. In 40 TD districts the information will be compiled in the office of DAEO through use of computers to be installed for this purpose.

8.15.7 The Directorate continued to monitor the activities of State Resource Centres and also dissemination of information relating to implementation of the programme.

8.15.8 During the year under report 9 training programmes were organised which include 6 programmes for DAEOs, 2 for trainees of NSS and Non-NSS volunteers under MPFL and one for the DAE and SRC Directors. The main theme discussed in these programmes was, how to operationalise the National Literacy Mission for effective implementation.

8.15.9 Since media support to adult education programme has been emphasised in the National Literacy Mission document, the media agencies such as AIR, Doordarshan, DAVP, Song & Drama Division etc. are being utilised to broadcast, telecast more programmes on adult education with a view to developing the right perspective and motivation amongst the masses to support and participate.

8.15.10 During the year under review, 42 new research proposals in the field of adult education were received by the Directorate. One research report was received and three summary reports were prepared and information disseminated to the concerned. A total grant of Rs.5,33,252/- was sanctioned to various individuals and orgnaisations for undertaking eight research studies on the various aspects of adult education programme.

8.15.11 UNFPA assisted project on Population Education initiated in 1986 was continued during this year also. Under this project, the Directorate organised two Progressive Project Report meetings to review the progress made during the year.

8.15.12 The activities undertaken during the year under UNICEF assisted Project of Non-formal Education of Women and Girls were:

— Preparation of 8 video modules (Number 16-24) 'Khilti Kaliyan', Primer prepared earlier under UNICEF assisted project, 'Non-formal Education for Women & Girls'.

— Duplication of 40,000 copies each of 15 Urdu manuscripts prepared by SRC Jammu & Kashmir to support the JSNs and Adult education centres for Women. These manuscripts deal with health problems and nutrition needs of women, girls and children, safe drinking water, etc.

8.15.13 During the year under report, Directorate brought out a large number of publications on the occasion of the launching of Mass Campaign of NLM by Prime Minister on 5.5.1988 and also on the occasion of the celebration of International Literacy Day on 8.9.1988. The Newsletter (now entitled as "Literacy Mission" from August, 1988, Issue), a monthly bilingual periodical of the DAE was continued to be published every month regularly.

8.15.14 The Sixth National Poster Competition was organised with the main purpose of stimulating and encouraging creative artists all over the country to prepare visual motivational material in adult literacy. The selected posters will be sent to UNESCO, Paris

for contest to be organised in the International Literacy Year 1990.

8.15.15 The Directorate of Adult Education received foreign dignitaries and engaged programmes for them as follows:

— Attachment training programme for three adults from Malawi.

— Placement training of one adult educator in out-of-school population education from Maldives.

— Training programme for three women adult educators from Somalia in adult education and population education.

— Prof. Honn Crocket Smyth, Professor Emirtus visited DAE in connection with the evaluation of International Environmental Education Programme under UNICEF Programme, 1984-88.

— Mr. Nyi Nyi, Director, Programme Division, UNICEF Headquarters, New York visited India from 28th October to 3rd November, 1988.

Education in Union Territories

9.0.0 Education in the Union Territories continues to be a special responsibility of the Central Government. An account of the education activities undertaken during the year in respect of each of the Union Territories is given in this Chapter.

Andaman and Nicobar Islands

9.1.1 The Directorate of Education in this Union Territory is headed by a Director of Education, assisted by Assistant Directors and other officers.

9.1.2 During the year, 4 Middle Schools were upgraded to the status of Secondary Schools and 3 Secondary Schools were upgraded to Senior Secondary Schools. UT Administration also proposes to open 4 new primary schools and upgrade 5 primary schools to the middle school level.

Incentive Scheme

9.1.3 UT Administration has continued various incentive schemes for promotion of education in the Union Territory. Financial concessions in the formof mid-day-meals, uniforms, travel concessions, text books were given to the students.

9.1.4 To meet the additional requirement of teachers at elementary and secondary stage, post of 4 Headmasters, 40 Primary School Teachers, 60 Trained Graduate Teachers and 30 Post-Graduate Teachers were created.

Revision of Scholarship rates

9.1.5 UT Administration had been implemening the scheme of scholarships to the students studying outside Andaman and Nicobar Islands. Under the scheme scholarships are provided for pursuing various courses such as BA, MA, Degree in Medicine, Engineering, Fisheries, Forestry, Library, B.Ed., Ph.D. and various Certificate Courses. Scholarship rates were last revised during 1983-84. The Administration had taken up the proposal with the Ministry for revision of the rates. The Ministry has substantially enhanced the existing scholarship rates for the students of Andaman & Nicobar Islands for pursuing above-mentioned Courses/Studies, which will benefit a large number of students

Training Institutes

9.1.6 Under the Teacher's Training Programme, B.Ed. and J.B.T. courses were continued. The number of students enrolled in B.Ed. and J.B.T is 80 and 128 respectively.

Chandigarh

9.2.1 There are 332 schools in the Union Territory of Chandigarh covering children from Pre-Primary to Senior Secondary stage. These schools cater to the educational needs of more than 1 lakh students at the elementary stage and about 24,000 at the secondary stage.

Scholarships

9.2.2 Various incentives/scholarships are given to SC/ST and economically weaker sections of students. The details of the incentives given during the period under report are as shown below:

(Rupees in lakhs)

	Plan	Non-Plan
Attendance Scholarships	0.90	3.50
SC/ST Scholarships	1.25	5.50
Talent Search Scholarships	0.50	——
Text books	1.69	3.50
Uniform and Stationery	4.50	11.20
Extra Coaching	1.20	1.70

Elementary Education

9.2.3 UT Administration has been promoting elementary education in the age group of 6—14. Two new schools have been opened during 1988-89 and 4 schools have been upgraded due to additional enrolment of over 5500 children in the age group of 6—14.

Non-formal Education

9.2.4 At present, 100 centres are being run by the UT Administration in which the enrolment is about 2300. These centres also function as nurseries for the drop-outs. Ten reading rooms are being run for the welfare of this section of the society.

Vocational Education

9.2.5 Facilities for vocational education have been provided in 9 Senior Secondary Schools of the UT Administration where various trades like Stenography and Secretarial Practice, Garments Technology, Electronics, Dress Designing etc. are taught. The Administration has already started teaching. General Insurance in their schools.

Adult Education

9.2.6 Under various Adult Education programmes like Rural Functional Literacy Programme and State Adult Education Programme 6,700 learners have been covered. Fifteen Jana Shikshan Nilayams have been opened. Female Literacy House was inaugurated on 8.9.1988. This building has been constructed with the award money received from Govt. of India for promotion of female literacy.

Sports

9.2.7 Sports and Games are a regular feature of the schools in Chandigarh. To encourage participation in sports, the UT Administration organises regular tournaments and competitions. The students of the UT Administration participated in National School Games, Jawaharlal Nehru Jr. Hockey Tournament and Subroto Mukherjee Football Tournament, etc.

State Institute of Education

9.2.8 The Institute provides for qualitative improvment in school education through inservice courses, and orientation and research programmes. A Regional Institute of English has been set up to organise in-service Courses for teachers to bring about qualitative improvement in the teaching of English. Forty teachers were given orientation training during the year.

Higher Education

9.2.9 On the Higher education side, the Administration is providing education upto degree level in Arts, Science and Commerce disciplines. The colleges also provide Post-graduate courses in Music for girls. On the professional side, there are two colleges — one Govt. College of Education, and the other Govt. Home Science College.

9.2.10 The former trains graduates for the degree of Bachelor of Education, and the latter imparts education in Home Science upto degree level and for post-graduate level in various disciplines of Home Science.

9.2.11 Besides, there are seven privately managed/aided Colleges. Administration pays 95% grant-in-aid on the revenue deficit to these privately managed aided colleges.

Dadra and Nagar Haveli

9.3.1 There are 161 Primary and 8 Secondary and Senior Secondary Schools in the Union Territory, catering to the educational needs of about 18,000 students at Primary level and about 3500 students at Secondary/Senior Secondary level.

Incentive Scheme for SC/ST

9.3.2 The Administration is continuing various incentive schemes to attract SC/ST students, such as, providing free education, teaching-aid-equipment, mid-day meal, uniforms and shoes etc.

Adult Education

9.3.3 The UT Administration is running 100 centres under the Rural Functional Literacy Programme and 50 centres under State Adult Education Programme covering 3000/1500 learners respectively.

Physical Education/Sports

9.3.4 Bharat Scouts and Guides programme has been organised. About 300 students participated in the National Cadet Corps during the year. One teacher received National Award from the President of India.

Miscellaneous

9.3.5 Computer Literacy study has been introduced in the Union Territory and extended to four schools and more students were enrolled in the said Project. To attract the tribals in studies and promote Tribal

dialects, the bilingual text books project was started in two languages namely "Dawarvarli" and "Dungar Varly" in four schools.

Daman and Diu

Educational Facilities in Union Territory

9.4.1 The Union Territory of Daman and Diu came into existence on 30th May, 1987 after delinking from the erstwhile Union Territory of Goa, Daman and Diu. This Union Territory comprises two Districts viz. Daman and Diu situated on the Western Coast. Education is provided to the students within a distance of 1 Km. During 1988-89, UT Administration has decided to open 4 new Primary Schools, two each in both the Districts. Besides these, four schools have been upgraded during the year.

Mass Orientation for School Teachers

9.4.2 Under the programme 147 Primary School Teachers and 84 Secondary Teachers have been trained. Five camps were organised by the State Institute of Education, Goa and the Department of Education, Daman. UT Administration proposes to organise 4 more orientation camps during the academic year in which 100 Primary/Secondary Teachers will be covered.

Navodaya Vidyalaya

9.4.3 Two Navodaya Vidyalayas one each for Daman and Diu, have been sanctioned by the Central Government. One Navodya Vidyalaya has already started functioning with 100 students. Teaching and ministerial staff have been appointed. Construction of the new building for the two Vidyalayas is in progress.

Vocational Education

9.4.4 The Administration has started typing and tailoring classes in three schools of Rural areas in which 100 students from backward classes are taking advantage.

Technical Education

9.4.5 Two Technical High Schools and two ITIs are running in the Union Territory. Government of India has also approved starting of a Government Polytechnic College to be commenced shortly.

Adult Education

9.4.6 Thirty six centres are running at present in UT under the scheme of National Adult Education Programme. One Jana Shikshan Nilayam has been established in Daman District.

Scholarships Scheme

9.4.7 The UT Administration is continuing all scholarships/stipends schemes, such as development of girls education, book grant, national scholarship, stipend to the handicapped students, post matric scholarship to SC/ST students.

Tribal Sub-Plan

9.4.8 Under this scheme, UT Administration provides text books, uniforms and stationery etc. to the Scheduled Tribe students from Class 1 to X. An amount of Rs. 25/- per month for each Tribal girl student is also paid for promoting attendance in schools.

Delhi

9.5.1 Special emphasis has been laid by Delhi Administration on helping the students including those belonging to SC/ST. For academic improvement of SC/ST students, a number of scholarships are given to them and remedial teaching & coaching facilities are extended to them.

Educational Facilities

9.5.2 The number of schools in Delhi during 1988-89 is as under:—

	Govt. Schools	Aided Schools	Un-Aided Schools	NDMC Schools	Kendriya Vidyalayas	Total
Upper Primary Schools	223	30	126	10	—	389
Secondary Schools	169	37	71	—	—	277
Senior Secondary Schools	453	138	104	5	29	729

9.5.3 During the academic year 1988-89, Delhi Administration opened 9 Middle Schools, Upgraded 6 Middle Schools to Secondary Schools and 15 secondary schools to Senior Secondary Schools. Three Middle Schools, 2 Secondary Schools and 3 Senior Secondary Schools were also bifurcated during the year.

9.5.4 With a view to encourage girls' education in villages, about 4000 girl students residing in villages

and studying in Government Girls schools are transported to schools and back home daily on working days free of charge. During 1988-89, Directorate of Education has a budget of Rs. 7 lakhs under this scheme for convenience of rural girl students of Delhi.

Adult Education

9.5.5 Education Department of Delhi Administration is running 12 adult evening schools for the benefit of those adults who could not complete their regular education due to domestic, social and economic reasons. At present, 6000 adult learners are enrolled in these schools.

Non-Formal Education

9.5.6 The Deptt. of Education is running 74 Non-formal Education centres for those children who are not able to avail of formal education facilities. The number of beneficiaries at these centres during the last 5 years has been 10,234.

State Institute of Education

9.5.7 The State Institute of Education of UT Administration has assumed greater importance. It organises seminars & courses for the benefit of subject teachers. The Institute also looks after orientation of 30,000 teachers. It has a UNESCO Aided Project for Primary Teacher Education Evaluation. 'Dilli Shiksha', a Journal of Education is published quarterly by the SIE.

Sports Activities

9.5.8 Delhi Admn. has a stadium called 'Chattarsaal Stadium' which looks after atheletic and sports activities of Department of Education. The Administration has also 10 swimming pools. The Sports Department arranges coaching camps and prepares boys and girls for National Camps.

Science Education

9.5.9 The Science Branch of Delhi Admn. (Directorate of Education) continued its activities like National Talent Search and other science activities to promote scientific temper. It also organised workshops, study circle meetings, students' study camps for teachers and principals all over Delhi.

Patrachar Vidyalaya

9.5.10 Delhi Admn. has a Patrachar Vidyalaya, which arranges for the education of the students and also guides them for appearing in the secondary schools examination and senior school examination. Laboratory facilities for science students at secondary and senior secondary level are also made available to the students throughout the year specially during the breaks. Patrachar Vidyalaya is serving the educational needs of nearly 22,000 students.

9.5.11 Delhi Admn. gives grant-in-aid to Municipal Corporation of Delhi, NDMC, Delhi Cantt. Board, Sahitya Kala Parishad and Cultural organisation, besides assisting Punjabi, Sanskrit and Urdu academies to promote languages and literature. These Academies have been established with a view to promote and develop Punjabi, Urdu and Sanskrit in the Union Territory of Delhi.

Lakshadweep

9.6.1 The Union Territory of Lakshadweep is a centrally administered area, the Administrator being the head of all Departments of the Administration. For Education Department, Director of Education is the controlling officer, who is assisted by various educational officers and other staff. Lakshadweep consists of ten inhabited islands.

Educational Facilities

9.6.2 There are 54 Educational Institutions functioning in this Union Territory as detailed below:

1.	Junior Colleges	2
2.	High Schools	9
3.	Senior Basic Schools	4
4.	Junior Basic Schools	19
5.	Nursery Schools	9
6.	Balwadi (under LSSWA Board)	11
	Total	54

9.6.3 Nursery schools are functioning in nine islands except Bitra. The enrolment of students during the year 1988-89 is 14,523. Necessary equipment for teaching and games have been provided in all schools. There are four hostels, two each for boys and girls. All students seeking admission are accommodated. One Navodaya Vidyalaya started functioning at Minicoy.

Adult Education

9.6.4 UT Administration is continuing various Adult Education programmes. National Literacy Mission Campaign was inaugurated in the Union Territory in May, 1988. A Literacy Mission Authority has been constituted to speed up the work of eradication of illiteracy and different islands have been divided

among three agencies namely Department of Education, Nav Yuvak Kendra and LSSWA Board.

Sports

9.6.5 The UT Administration has taken various steps to promote sports and physical education in the Territory. During the year, the UT Administration filled up posts of sports boys and swimming instructors. A contingent of 4 NCC Junior Division cadets was deputed to Cochin for participation in the Republic Day parade selection camp and preparatory camps. The students of the UT Administration also participated in the National Sports Talent (Atheletics) at Bangalore.

Revision of Scholarship Rates

9.6.6 The UT Administration has been implementing a scheme of Scholarships for pursuing Matric, Post Matric, Graduate, Post Graduate courses in various disciplines. The scholarship rates have been enhanced substantially which will benefit a large number of students.

Vocational Education

9.6.7 NIEPA had conducted a study of the Union Territory for educational improvement, which emphasised the importance of vocational education in the Territory. The UT Administration proposed introduction of vocational courses based on fisheries technology and coir processing in their Secondary schools. The Union Territory approached the Ministry for creation of various posts for introduction of vocational courses. Accordingly the Department of Education has approved the creation of the following posts.

Name of the post	Number of posts
Machanical Instructors	4
Boat Driver	4
Fisherman-cum-life saver	4
Coir Craft Instructor	4
Fisher Instructor	4

9.6.8 The introduction of vocational courses from Class VIII in the UT Administration schools required approval of and recognition by the Kerala Board of Secondary Education because the schools in the Union Territory are affiliated to the Kerala Board of Secondary Education. This has been granted.

Training Programmes

9.6.9 A training programme for Headmasters and officers of the Education Department and Members of the Parent Teachers Association was conducted at Kavaratti. Eminent educationists from NIEPA and Indira Gandhi National Open University participated in the training programme. In all 52 persons participated in the programme. An orientation course for teachers on the New Education Policy, 1986 was conducted under the National Scheme of Mass Orientation in which 80 teachers participated. A training course in using science kits was also conducted in which 20 teachers participated. Six teachers from various islands also attended a six week training course in New Delhi.

Strengthening of the Educational System

9.6.10 As a Follow-up of the measures suggested by NIEPA for further improvement of the education system, the UT Administration has proposed creation of posts for Vocational Education, General Administrative set up, Academic set up, Secondary Education and Primary Education, etc. The Department of Education has sanctioned 20 posts for Vocational Education, and 24 posts for General Administration, Academic set up, Procurement Cell, etc.

Co-curricular Activities

9.6.11 Teachers Day was celebrated with enthusiasm. Children's Day was also celebrated by the UT Administration in which public meetings were organised and variety programmes such as essay competition, painting competition, drawing and other cultural competitions, boat race and swimming competition were held.

Pondicherry

9.7.0 The UT Administration of Pondicherry continued to expand their educational activities and implement various schemes during the year. Some of the important activities undertaken during the year were :

Elementary Education

9.7.1 During the Sixth Plan period there had been a massive expansion in the Elementary Education Sector which resulted in achieving nearly 100% enrolment. During the Seventh Plan the emphasis, therefore, is to strengthen the qualitative aspect of the educational system by strengthening the schools with libraries, scientific equipment, furniture, buildings, audio visual aids and other infrastructural facilities. It is proposed to clear the entire backlog of land acquisition and building proposals as well as supply of furniture and implements etc., to these

schools. The backlog in appointment of teachers in the Elementary Education Sector is also proposed to be cleared. The Plan also aims at converting all single teacher schools into double /multiple teacher schools.

9.7.2 Under Elementary Education during 1988-89, 1 Primary School, 1 Middle School, 134 additional Classes, 15 Next Higher Standards have been opened. As per target under free supply of text books, stationery and uniforms, 57,300 Poor Children have been covered.

Science Education

9.7.3 To give a fillip to scientific curiosity among children, it is proposed to set up a Science Corner in each of the middle schools and strengthen the laboratories in the Senior Secondary Schools. Similarly to prepare the children to receive benefits of INSAT facility in the wake of setting up of a T. V. Centre at Pondicherry, it is proposed to supply T. V. sets to all the remaining Middle/Secondary/Senior Secondary Schools under Audio Visual Education.

Vocational Education

9.7.4 Vocationalisation of Secondary Education and study of vocational trades in the Middle and High Schools is proposed to be encouraged further with the appointment of qualified teachers and supply of tools and raw materials. It is proposed to introduce atleast one vocational trade in each of the Senior Secondary Schools of the Union Territory.

Secondary Education

9.7.5 During 1988-89, 9 Middle Schools were upgraded into High Schools, and 2 Next Higher Standards have been opened. Additional Courses/ Vocational Courses, as proposed have been introduced in the existing senior Secondary Schools. Three High Schools have been upgraded into Senior Secondary Schools.

Teachers' Education

9.7.6 Every year 500 teachers of various categories are given in-service and orientation training in various disciplines.

University Education

9.7.7 Under University Education it is proposed to help students of this Union Territory to fulfil their aspirations of higher Education who otherwise are dependent on a few seats made available to them in the colleges of neighbouring States on reservation basis by introducing new courses in the six degree colleges. During 1988-89, two Under Graduate Courses in Arts and Science have been introduced in the existing colleges and one more branch in LLM has been started.

Technical Education

9.7.8 Under Technical Education, during 1988-89, D.C.A. course has been started in Pondicherry Engineering College. The new courses viz. (1) Refrigeration and Air Conditioning in Automobile Engineering, (2) T.V. Engineering in Electronic Engineering, (3) Building Technology in Civil Engineering, (4) Fabrication and Designing, (5) Post Diploma Course in Computer Application and (6) Letter Press Printing have been introduced.

Women's Polytechnic

9.7.9 A women's Polytechnic at Pondicherry and Polytechnic for boys and girls at Karaikal have been set up, in fulfilment of long felt need of the people of the Union Territory. The UT Administration have also taken steps to acquire the land for Junior Technical School at Mahe.

Adult Education

9.7.10 The Education Department is the nodal department for the Implementation of National Adult Education Programme in Union Territory of Pondicherry. Under the Adult Education Programme every year two training programmes are conducted regularly for supervisors and animators working under the National Adult Education Programme. During 1988-89, 1500 illiterates will be covered under this programme.

Physical Education

9.7.11 During 1988-89, under Physical Education, all Physical Education Schemes are being continued. Scholarships to the outstanding sportsmen, N.C.C. cadets and Scouts and Guides are also being given. Construction of Sports Complex is being continued.

Other Programmes—Co-Curricular Activities

9.7.12 Bal Bhavans and Commune level mini Bal Bhavans have been strengthened. Activities like film shows, video programmes were organised in various schools. While endeavouring to maintain the pace of progress achieved during the previous plan period. UT Administration has taken steps to strengthen the gains already achieved and improve its quality during the ensuing years.

Scholarships

10.0.0 The Department of Education administers a number of scholarship programmes for Indian students for further education including those offered by other Governments. The Department also provides scholarships to nationals of other countries on a bilateral basis or otherwise. The important schemes are mentioned below.

National Scholarships Scheme

10.1.0 Under this scheme, which is implemented through the State Governments/Union Territory Administrations, scholarships are awarded for post-matric studies on merit-cum-means basis. During 1988-89, 33,000 scholarships were awarded. The rates of scholarships vary from Rs. 60/-p.m. to Rs. 120/-p.m. for day scholars and Rs. 100/-p.m. to Rs. 170/-p.m. for hostellers, depending on the course of study. The income ceiling has been raised from Rs. 6000/- to Rs. 25,000/-p.a. after allowing some admissible rebates, with effect from 1.4.1988.

National Loan Scholarships Scheme

10.2.0 Under this scheme, 20,000 scholarships were awarded in 1988-89 to needy students to complete their education. The scholarships are awarded for post-matric studies on merit-cum-means basis. The scheme is being implemented through the State Governments/Union Territory Administrations.
The amount of loan varies from Rs. 720/- to Rs. 1720/- per year depending upon the course of study. The income ceiling has been raised from Rs. 6000/- to Rs. 25,000/- per annum after allowing some admissible rebates, with affect 1.4.1988.

Scheme for Upgradation of merit of SC/ST students

10.3.1 The scheme was started in 1987-88. The objective of the scheme is to upgrade the merit of SC/ST students by providing them extra coaching, both remedial and special with a view to removing their educational deficiencies in school subjects and facilitating their admission in professional courses where entry in based on competitive examination. The SC/ST students who are selected under the scheme are placed in good residential schools so that they receive better quality education, develop confidence and are in a position to interact with other students with better educational preparations. The scheme is being operated through State Governments/Union Territory Administrations.

10.3.2 The scheme has been started by providing for 1000 students (670 SCs & 330 STs) in 50 schools. Allocation of schools to different States is made on the basis of their illiterate population of SC/ST communities. Remedial coaching will start at Class-IX level and continue till a student has completed Class-XII. The remedial coaching will be given to these students for a period of 4 years from Class-IX to XII while special coaching would be provided in classes XI and XII only. Under the scheme, there is no income ceiling.

Government of India Scheme of Scholarships in Approved Residential Secondary Schools

10.4.0 The objective of the scheme is to provide educational facilities to talented but poor students (age-group 11-12 years) for studying in good residential schools. Five hundred scholarships were awarded during 1988-89 to students, the income of whose parents did not exceed Rs. 25,000/-p.a. on merit-cum-means basis. Fifty percent of these scholarships were awarded on the basis of All India merit and the remaining 50% were allocated to States/Union Territories according to their population, subject to fulfilment of minimum standards laid

down. Students belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes were given, respectively, 15% and 7½% of these scholarships. The scholarships are tenable for the entire period of secondary schooling, including the plus 2 stage of education in approved residential schools. Scholars are entitled to full amount of tuition fees, residential charges, cost of books and stationery, in addition to pocket money, uniform clothing allowance and excursion charges at the rates/ceiling decided by the Government. A travel grant is also admissible to the scholars and their escorts according to the rates prescribed for the purpose.

Scholarships to students from non-Hindi speaking States for Post-matric Studies in Hindi-1988-89

10.5.0 The object of the scheme, which was started in 1955-56, is to encourage study of Hindi in non-Hindi speaking States/Union Territories and to make available to the Governments of these States/Union Territories suitable personnel to man teaching and other posts where knowledge of Hindi is essential. Two thousand five hundred scholarships were allocated to various non-Hindi speaking States/Union Territory Administrations during 1988-89. The rates of scholarships vary from Rs. 50/- to Rs. 125/- per month, depending upon the course of study and the States/Union Territories in which study of Hindi is pursued. The scheme has been got evaluated from the Central Institute of Hindi, Agra. The committee has inter-alia suggested enhancement in the number and rates of scholarships. The recommendations are under examination.

Research Scholarships to Products of Traditional Institutions engaged in the Study of Classical Languages other than Sanskrit, like Arabic and Persian

10.6.0 Twenty scholarships are awarded every year under this scheme. In 1988-89, 20 scholars were selected for this award.

National Scholarships at Secondary Stage for Talented Children from Rural Areas

10.7.0 The number of scholarsnips awarded every year are 38000. The break-up of 38,000 scholarships allocated for 1988-89 is given below:—

		Total number of scholarships
—General Category	Three scholarships per Community Development Block	15,000
—Children of landless workers	Two scholarships per Community Development Block	10,000
—Scheduled Caste Children	Two scholarships per Community Development Block and one additional scholarship per Community Development Block having 20% more Scheduled Caste population.	11,500
—Scheduled Tribe Children	Three scholarships per Tribal Community Development Block	1,500
		38,000

The scheme is being implemented through State Governments and Union Territory Administrations.

General Cultural Scholarships Scheme

10.8.1 For promotion of goodwill and friendly relations, 180 scholarships are offered every year to the nationals of selected African, Asian and other Developing countries for undergraduate and post-graduate studies in India, particularly, in courses for which facilities are lacking in their own countries. Students are given scholarships on the basis of their Government's recommendations.

10.8.2 The value of scholarship is Rs. 750/-p.m. for undergraduate courses and Rs. 900/-p.m. for post-graduate courses. Besides, the students are paid for medical expenses and study tours. They are also paid an annual contingency allowance of Rs. 1500 to Rs. 2500 depending on the course of study.

Scholarships/Fellowships for the Nationals of Bangladesh

10.9.1 Under this scheme, 110 scholarships are offered every year to the nationals of Bangladesh for higher studies in India. These include 10 scholarships for Sanskrit and Pali studies. Selection for scholarships is made by the Government of Bangladesh in consultation with the Indian High Commission in Dhaka.

10.9.2 The value of scholarship is Rs. 750/-p.m. for under-graduate courses and Rs. 900/-p.m. for post-graduate courses. In addition, the students are paid Rs. 1500/- to Rs. 2500/-p.a. as annual contingency allowance. The expenditure on medical treatment and study tours is also reimbursed. The scholarship also covers cost of air fare (Dhaka to Calcutta) and 1st class rail fare (Calcutta to place of study in India) and for journey back home after completion of studies. The scheme is financed by the Ministry of External Affairs.

Scholarships for the nationals of Sri Lanka, Maldives, Angola, Mauritius

10.10.1 From the academic session 1988-89, the number of awards to the nationals of Sri Lanka, Maldives, Angola for higher studies in India has been increased on the recommendation of the Ministry of External Affairs. The number of scholarships offered to these countries during 1988-89 are as under:—

Sri Lanka	50
Angola	40
Maldives	20 (including 4 under General Cultural Scholarships Scheme)
Mauritius	40 (10 under GCSS + 30 additional)

10.10.2 The terms and conditions of the scholarships are same as under General Cultural Scholarships Scheme. These scholarships are financed by the Ministry of External Affairs from the budget of that Ministry.

Scholarships for study Abroad

10.11.1 Fifty scholars have been selected for award of scholarships in 1988-89 for study abroad. These scholarships are awarded for graduate study in printing technology, post-graduate studies in naval architecture and paper technology and doctoral and post-doctoral studies in humanities, sciences and technology. Only those candidates whose parental income from all sources, excluding usual standard rebates, is Rs. 1000/-p.m. (pre-revised) or less are eligible for these scholarships after taking into account the pre-revised scales.

10.11.2 The use of computer for management and administrative functions of the National/External Scholarships Division was introduced for the first time in 1987-88 and was continued in 1988-89.

Scholarships/Fellowships offered by foreign Govts. Under C.E.P. Programme

10.12.0 The External Scholarships Division under the Department of Education operates a number of programmes under which scholarships are given to Indian Students/Citizens for higher studies abroad. These awards are made available every year by various foreign Governments and agencies. Actual utilisation of these scholarships upto 30.11.88 by this Ministry countrywise is: Norway-6, Poland-1, GDR-5, Mongolia-1, Bulgaria-4, Yugoslavia-1, France-2 FRG-8 Ireland-8, Japan-9, Denmark-3, Turkey-3, USA-3, USSR-18, Thailand-4, Spain-4, Austria-1, Czechoslavakia-2, Netherland-3, Italy-28, Australia-5, Trinidad-1, New Zealand-1, Belgium-2, Greece-2.

Foreign & Commonwealth Scholarships (FCO) and Awards Scheme, U.K.

10.13.0 Under this Scheme, 9 candidates have been sent to U.K.

Commonwealth Scholarships and Fellowships offered by the Govt. of U.K./Canada

10.14.0 Under these schemes, 60 candidates have been sent abroad.

Science Research Scholarships

10.15.0 Under this scheme, during the year 1988-89, no candidate was sent abroad.

Technical Cooperation Training Programme

10.16.0 Under this Scheme, 7 candidates have been sent aborad.

Commonwealth Education Cooperation Programme

10.17.0 Under this programme, 3 Senior Educationists—

1. Dr. Lain Cooper Tayler (Canada);
2. Mr. Joseph Kuthemba Mwale (Malwi);
3. Mr. Akiiki Bombera Mujaju (Uganda) have been selected for visitorship during 1988-89.

British Council Visitorship Programme

10.18.0 Under this Programme more than 150 Scientists, Academicians & medical specialists benefited for mutual application of important developments in their areas of speciality.

Scholarships to Foreign students for Study/Training in India

10.19.0 During the year under report, India offered more than 300 scholarships to the various countries for studies in different fields as per Bilateral Cultural Exchange Programme. The countries are: Senegal, France, Federal Republic of Germany, USSR, Philippines, Belgium, Maxico, Afghanistan, Greece, Somalia, Italy, Yugaslavia, Syria, People's Democratic Republic of Yaman, Hungary, Vietnam, Bulgaria, Tunisia, Portugal, Malaysia, Sri Lanka, Baharain, Burma, Iran, Kenya, Democratic People's Republic of Korea, Mauritius, Japan, Algeria, Australia, United Arab Emirates, Sudan, Ethiopia, Jordan. Against this offer, 260 nominations were received and placements of 185 scholars were arranged. Uptil January, 1989 110 scholars have joined various institutions in India.

Commonwealth Scholarship/Fellowship plan for studies in India

10.20.0 Under this programme, 75 Scholarships are offered by the Government of India to Commonwealth countries for their nationals for post-graduate/research studies in India. Against this offer, 70 nominations were received and upto January, 1989, 20 students joined their institutions.

Dr. Amilcar Cabral Scholarship

10.21.0 Offer of one scholarship has been made under this programme for an African student.

Dr. Aneurin Bevan Memorial Fellowship

10.22.0 Offer of one/two fellowships has been made under this programme for the nationals of United Kingdom.

Technical Cooperation Scheme (TCS) of the Colombo Plan

10.23.0 Under TCS of the Colombo Plan, assistance is offered for placement of scholars coming from Colombo Plan countries namely; Afghanistan, Bhutan, Iran, Indonesia, Malaysia, Maldives, Nepal, Philippines, Sri Lanka. Nominations of about 100 scholars under this programme are received from the Ministry of Finance (Deptt. of Economic Affairs) who are the nodal Ministry for this programme. Those scholars who find placement in Indian institutions are also awarded scholarships. During the year under report, 75 scholars have been awarded scholarships under this programme.

Commonwealth Education Co-operation Plan-Training of Craft Instructors

10.24.0 Under this schemes, 10 Bursaries have been offered to the nationals of Commonwealth countries in Asia, Africa and Latin America for training of craft instructors in various trades in different institutions under the control of Director-General, Employment and Training. Two scholarships have been utilized under this programme upto January, 1989.

Dadoo Naicker Award

10.25.0 Under this programme, instituted from the year 1988-89, one scholarship is awarded to a deserving South African student of Indian origin for studies in India.

Book Promotion and Copyrights

11.0.0 Books have an important role in the field of Education. With the expansion of educational facilities in the country, there is also an increase in the demand for books in terms of quantity as well as the variety of subjects. The Book Promotion Division of the Department of Education has a number of schemes to promote the production of good quality books at reasonable prices, encourage indigenous authorship, promote the reading habit among the masses and help the Indian book industry in solving its problems. Some of the important programmes undertaken in this regard are briefly described in the following paras:

National Book Trust

11.1.1 The National Book Trust was set up in 1957, as an autonomous organisation with the objectives of producing and encouraging production of good reading material at moderate prices and fostering book-mindedness among the people. In pursuance of these objectives, the Trust has been producing books in Indian languages as well as in English, in well-defined series. The Trust organises book fairs at national and regional levels and holds seminars and symposia on various aspects of book writing. It participates, on behalf of the Indian publishing industry, in book exhibitions held abroad to promote the export of books. The Trust has two regional offices at Bangalore and Bombay and eight book centres at Amritsar, Bangalore, Bombay, Calcutta, Mysore, Hyderabad, Santiniketan and New Delhi.

Publishing Programme

11.1.2 Some of the important series under which the Trust publishes books are: India—Land and the People, National Biography, Young India, Popular Sciences, World of Today, Aadan Pradan and Nehru Bal Pustakalaya. In addition to these continuing schemes, the Trust has taken up new schemes for production of books for School Library Programmes, reading material for continuing education of neo-literates and school drop-outs and of publications of classic literature etc.

Publishing (On-going schemes)

11.1.3 Based on the demand for titles in the various series and languages during the previous years and the expected demand which may be generated during the years to come, the Trust has now embarked on a need-based language-wise publishing programme for the year 1988-89 in respect of its on-going schemes. Consequent upon the formulation of the above publishing programme, a fixed production schedule has been drawn up and it is expected that a far better number of titles than what was produced during the earlier years would be published and printed in the coming months. Between April and October, 1988 the Trust published 102 titles of which 29 are original titles and 73 are reprints.

11.1.4 Since a large number of manuscripts are now in press and production of books is being carried out in a planned manner according to a publishing programme, it is expected that the Trust would publish many more books during the current financial year.

Subsidy Scheme and Core Book Project

11.1.5 To encourage indigenous authorship, the Ministry has a scheme of subsidised publication of university level books written by Indian authors, with a view to making them available to the students at reasonable prices. This scheme is being implemented since 1970 through the National Book Trust. The Trust has during the period under review, revised the

rules of the Scheme for the Subsidised Publication of Books in order to attract greater participation by the private publishers for whom the scheme is primarily meant. Apart from simplifying the procedures revised rules project the scheme in its proper perspective in a rational manner.

Steps taken by the Trust to promote Reading Habits

11.1.6 During the current financial year, the Trust is stepping up its book promotional activities. Between now and March 1989, five major book fairs/festivals have been/are being organised in Delhi, Lucknow, Bombay, Baroda and Coimbatore.

11.1.7 In addition, the National Book Week will be celebrated in the first week of February, 1989, by holding, besides many other activities, more than 40 exhibitions simultaneously in University towns across the country.

11.1.8 As part of the Soviet Festival in India, the Trust organised Soviet Book Exhibitions in Hyderabad, Madras and Bangalore during March, April and May, 1988.

Publication of low-priced University level books of foreign origin

11.2.0 The Department of Education is operating four bilateral programmes in collaboration with the governments of UK, USA, USSR and the GDR to make available standard books of foreign origin to the Indian University students in low-priced editions. Latest editions of books are considered for coverage under these programmes and are assessed by export agencies from the standpoint of their suitability for Indian students and on the basis of Indian books of comparable standards not being available. Thereafter, suitable books are recommended for being published in English and Indian languages. By the end of 1987-88 about 763 British, 1630 American, 600 Soviet and 9 GDR books had been published under these programmes. During the current year 25 American and 33 Soviet titles have been recommended for publication.

Indo-Soviet Literature Project

11.3.0 The Indo-Soviet Committee set up for the publication of contemporary creative works of both the countries has formulated a project to publish the translation of the 20th Century Literature of India and the USSR in about 20 volumes each. The first two volumes were released during the celebrations of the Festival of India at Moscow. The content structure of Volumes 3 & 4 has also been finalised. All the 20 volumes are expected to be published by 1995.

New Import Export Policy for Books & Publications

11.4.1 The new Import-Export Policy for books & publications came into force from April 1988 and will be effective till March 1991. The salient features of the policy are as follows:

(1) Under O.G.L. educational, scientific & technical books and journals, news magazines & newspapers can be imported by all persons.

(2) Teaching aids, micro films & microfiches of educational nature, filmstrips/slides of educational nature with or without audio cassettes/video tapes of educational nature can be imported only by recognised educational, scientific, technical research institutions, libraries of such institutions, Central or State Govt. departaments, industrial units engaged in Research & Development work, registered medical institutions, hospitals, consultants, recognised chambers of commerce, productivity councils, management associations and professional bodies.

11.4.2 However, imports of foreign edition of books for which editions of authorised Indian re-prints are available will not be allowed. Foreign reprints of Indian publications will be allowed on the basis of prior written permission of the Ministry.

Book Export and Promotional Activities

11.5.1 India is one of the ten major book producing countries of the world. To promote sale of Indian books and translation/reprinting rights abroad and for securing printing jobs from abroad, steps are being taken to publicise our books through participation in international book fairs and organising special exhibitions of Indian books, by conducting market studies and commercial publicity through circulation of annotated catalogues, brochures etc.

11.5.2 In 1988-89, India participated in the international book fairs/exhibitions held in Cairo, London, Sofia, Malaysia, Beijing (China), Singapore, Frankfurt, Surabaya & Bali (Indonesia). Special exhibitions of Indian books were organised in Canberra, Sofia, Bulgaria and Brisbane.

11.5.3 As a part of celebrations of Festival of India in USSR, seven Indian book exhibitions were organised in seven cities of USSR, which are:

Tashkent, Frunze, Dushanbe, Vilnius, Kiev, Baku & Moscow. Three thousand books on different subjects were displayed in each exhibition. A special exhibition 'History of Indian Publishing' was also organised during the book exhibitions.

11.5.4 Between April-November, 1988 the National Book Trust participated and/or arranged participation of book trade in a number of over-seas exhibitions and book fairs setting up composite stalls for Indian books and by providing information to the over-seas buyers on all aspects of Indian books and publications.

11.5.5 As a result of participation in the International Book Fairs/Exhibitions abroad, export of books including journals and periodicals for the year 1988-89 is estimated to increase to Rs. 29 crores.

Raja Rammohun Roy National Educational Resources Centre

11.6.1 The Centre was established in 1972 with the main objective of promoting the writing and production of indigenous university level books. It aims at serving authors and publishers of university level books as well as research workers in the field of book production. It acts as a data bank to clear all information on indigenous textbooks. The Centre also acts as a reference library for University level standard textbooks in all regional languages, including English and Hindi. Under its scheme of on-the-spot evaluation the centre gets indigenous books evaluated on all disciplines by subject experts and recommends these standard books to Indian Universities for inclusion in the University curricula. So far eighty such panel meetings of subject experts have been held and 750 books have been adjudged standard and 105 out of these have been included in various syllabi by various Universities.

11.6.2 In order to create awareness among the teachers and the taught about the production and presence of standard indigenous books, the Centre periodically organises exhibitions of University level books at various Universities by rotation. During 1988-89, the Centre organised four exhibitions at Bhopal University; Jiwaji University, Gwalior; Bharathidasan University, Tiruchirapalli (TN); and Sri Krishnadevaraya University, Anantapur (AP).

11.6.3 The Centre is acting as a National Agency to operate the International Standard Book Numbering System in India under direction from the International ISBN Agency, Berlin. The Agency allocates ISBN to publishers free of cost. The Agency has so far registered more than 600 Indian publishers under the ISBN System.

11.6.4 The Centre is bringing out several specialised publications for the benefit of book trade and universities. Recently, it has brought out Bibliography on Book Industry and Trade. Two other publications viz. National Catalogue of ISBN titles have also been brought out. It has further brought out National Catalogue of University level books Vol. 3 containing information of more than 3000 university level textbooks.

Copyright

11.7.1 The Copyright Office was established in January, 1958 in pursuance of Section 9 of the Copyright Act, 1957. The Copyright Act has been amended by the Copyright Amendment Act of 1983 and the Copyright Amendment Act of 1984 to meet the present day requirements.

11.7.2 The Copyright Office during the year 1988 (i.e. upto 30.11.1988) has registered 718 works, the breakup of which is: 441 artistic works, 276 literary works and one record of songs. In addition to this, the Copyright Office has registered changes in particulars of Copyright entered in the Registrar of Copyright in respect of 27 artistic works and one literary work.

11.7.3 The Copyright Board, a quasi-judicial body was constituted initially in September, 1958. The jurisdiction of the Copyright Board extends to the whole of India. It hears cases—regarding rectification of Copyright registration, disputes in respect of assignment of Copyright, to grant licence in works withheld from public, to grant compulsory licence to unpublished Indian works, to grant licence to produce and publish translations, to grant licence to produce and publish works for certain purposes, and other miscellaneous matters instituted before it under the Copyright Act, 1957. The meetings of the Board are held in different zones of the country to provide facility of justice to the authors, creators and owners of intellectual property near their places of residence or occupation. During the year 1988 (upto 30.11.1988) the Board held 7 meetings, heard 201 cases, decided 15 cases and dismissed 23 cases in default.

11.7.4 India is a member of two International Conventions on Copyright, namely, the Berne Convention for the protection of Literary and Artistic Works and the Universal Copyright Convention. Both the conventions were revised at Paris in July, 1971 to incorporate special concessions to be given to

the developing countries to enable them to issue, under certain conditions, compulsory licences for reproduction/translation of books of foreign origin for educational purposes in the event these rights could not be obtained on freely negotiated terms. India has acceded to both the conventions.

Training facilities to Foreign Trainees

11.7.5 Under the World Intellectual Property Organisation Fellowship Programme, Shri M.D. Soma Weera visited India in Nov. 1988 for obtaining training in the field of Copyright.

Training facilities to Indian Trainees

11.7.6 Shri S.A. Padmanabhan, Special Officer (Book Imports) and Deputy Registrar of Copyrights in the Ministry attended the Specialised Course on Administration of Copyright and Neighbouring Rights under the WIPO's Fellowships Programme for 1988 in Switzerland in June 1988. Shri N.D. Grover, Desk Officer attended the General Introductory Course on Copyright and Neighbouring Rights under the WIPO Fellowships Programme for 1988 in Hungary from August 29 to September 13, 1988 and participated in the WIPO Worldwide Forum on Impact of Emerging Technologies on Law of Intellectual Property in Geneva, Switzerland from 14 to 16th September, 1988.

Promotion of Languages

12.0.0 Languages being Central to education, their development occupies an important place in National Policy on Education. Therefore, promotion and development of Hindi and other 14 langauges listed in the Schedule VIII of the Constitution including Sanskrit and Urdu on one hand and English as well as foreign languages on the other hand was given due attention. In fulfilling this responsibility, the Department is assisted by a number of autonomous organisations and subordinate offices, namely, Kendriya Hindi Shikshan Mandal (KHS), Agra; Rashtriya Sanskrit Sansthan (RSS), New Delhi with its 8 Vidyapeeths; Central Institute of Indian Languages (CIIL), Mysore with its four Regional Centres and two Urdu Training and Research Centres; Central Hindi Directorate (CHD), New Delhi; Commission for Scientific and Technical Terminology (CSTT), New Delhi; and Bureau for Promotion of Urdu (BPU). During the year under report, the Department continued its on-going schemes and programmes. The following are some of important activities pertaining to promotion and development of languages undertaken during 1988-89:—

Promotion and Development of Hindi

12.1.0 Ever since Second Five Year Plan, Central Assistance is being provided for appointment of Hindi teachers in upper primary to higher secondary schools in non-Hindi speaking States/Union Territories. The extent of financial assistance given under this scheme is 100%. About 7,000 Hindi teachers have been appointed so far by the non-Hindi speaking States and Union Territories during the current Five Year Plan. A similar scheme exists for giving 100% Central assistance to non-Hindi speaking States/Union Territories for establishment of Hindi teachers training colleges in those States/Union Territories. This assistance is also available to voluntary organisations for the same purpose. So far 29 colleges in different parts of the country have benefited under this scheme, of which 19 are being run by State Governments and 10 by Voluntary Hindi Organisations. The annual intake of these colleges is about 1000 trainees.

12.1.1 Since dictionaries have been found to be useful tools for language learning and language analysis, the Dictionary projects have been assigned due importance. Under these projects the Central Hindi Directorate is compiling 13 Hindi based and 13 regional languages based dictionaries. So far, Hindi-Gujarati, Hindi-Sindhi, Hindi-Urdu, Hindi-Marathi, Hindi-Assamese, Hindi-Tamil, Hindi-Telugu, Hindi-Malayalam, Hindi-Oriya dictionaries have been published. Central Hindi Directorate have also brought out five trilingual dictionaries, while 12 Hindi based and 12 regional languages based trilingual dictionaries are being compiled. They have also published one multi-lingual dictionary. A 'Tatsam' word dictionary, with 2000 entries in Hindi and 13 regional languages has also been published. Under the Cultural Exchange Programmes, Hindi-Chinese, Hindi-Arabic, Hindi-French and Hindi-Spanish dictionaries have been published.

12.1.2 Nearly 5 lakh scientific and technical terms belonging to 27 subjects covering basic sciences, applied sciences, social sciences and humanities have been evolved and published in the form of consolidated and subject-wise glossaries. Evaluation of terminology in the developed and specialised fields like Computer Science, Printing Technology and modern architecture etc. is in progress. Important journals like Unesco Doot (Hindi version of the English magazine entitled 'Unesco Courier') is also being brought out by Central Hindi Directorate. They

are also publishing quarterly Hindi Journal—"Bhasha" and annual Journal—"Varshki". Similarly, the Commission for Scientific and Technical Terminology is also publishing a Science Journal in Hindi called "Vigyan Garima Sindhu". Similar Journal for social sciences is planned for publication during this year.

12.1.3 In pursuance of the policy directive to switch over medium of instruction at university level to Hindi and regional languages, a scheme was formulated for producing university level text books in different disciplines. The Central assistance, limited to Rs. 100 lakhs for each state, was provided to 15 participating States and four Universities for gradual adoption of Hindi and Regional languages as media of higher education. A total of 8300 titles have been produced/re-produced in Hindi and other Indian languages, including 280 titles produced by the Commission for Scientific and Technical Terminology, who have been designated as a nodal agency for the scheme.

12.1.4 Financial assistance is being extended to voluntary Organisations/Societies/Trusts as well as individuals for bringing out publications with a view to promoting and propagating Hindi and other Indian languages. The assistance is provided at the rate of 80% of the total cost estimates as approved by the Government. Realising the importance of distance education, Central Hindi Directorate is implementing a scheme of teaching Hindi through correspondence courses with English, Tamil, Bangla and Malayalam as media. The enrolment in these courses during the current year is around 15,000.

12.1.5 Central Hindi Directorate has organised study tours for non-Hindi speakers in Hindi speaking areas and released travel grants to research scholars of non-Hindi speaking areas. Eight new writers' workshops were held in non-Hindi speaking areas to encourage original writings in Hindi, besides holding symposia for discussing various aspects of Indian literature in non-Hindi speaking areas.

12.1.6 Workshops for the university/college level teachers were organised by the Commission for Scientific and Technical Terminology for guiding these teachers in the use of Hindi for teaching purpose through the terminology evolved by them.

12.1.7 In pursuance of the objective to train Hindi teachers in non-Hindi speaking States, Kendriya Hindi Sansthan is conducting many important programmes i.e. running a number of training courses like Nishnat & Parangat certificate courses etc. They are conducting extension programmes for training Hindi teachers in tribal areas. A full academic course for teaching of Hindi to foreigners is being run by the Sansthan. During the current year, the Government awarded 50 scholarships to foreign students. Sansthan has also brought out a number of text-books and primers for teaching Hindi in tribal areas.

12.1.8 The Silver Jubilee of Kendriya Hindi Sansthan was inaugurated by the Prime Minister on 13.2.89. On this occasion, the following awards were given away by the Prime Minister for outstanding contributions to Hindi:

Sl. No.	Name of Awardee	Area of contribution
(A)		
1.	Shri M. Satyanarain	Teaching, training and propagation of Hindi
2.	Shri G.P. Nene	
3.	Shri Giriraj Kishore	
4.	Shri Shankar Rao Londhe	
5.	Smt. Mutubai Mane	
6.	Shri Rajni Kant Chakravarti	
7.	Shri M.K. Vailayudhan Nair	
8.	Shri S.R. Sarangpani	
9.	Shri Dattatreya Mishra	
10.	Shir Narasingh Nand Sharma	
11.	Shri H Gokulanand Sharma	
12.	Shri Narendra Anjaria	
(B)		
1.	Shri Dharamvir Bharati	Hindi Journalism and creative literature
2.	Shri Balsherri Reddy	
3.	Shri K.G. Balkrishan Pillai	
C)		
1.	Shri R.C. Mehrotra	Development of scientific and technological literature/equipment in Hindi
2.	Dr. Brij Mohan	
3.	Dr. Om Vikas	
4.	Shri Gunakar Mullay	
(D)		
1.	Dr. Prabhakar Machve	Promotion and development of Hindi
2.	Dr. Brijeshwar Verma	
3.	Dr. Hardev Bahri	
4.	Dr. N. Nagappa	
5.	Prof. Ram Singh Tomar	

12.1.9 The proposal regarding establishment of International Hindi University is under active consideration in consultation with the University Grants Commission. Comments received from UGC in this regard are under deliberations of High Level Committee.

12.1.10 To encourage voluntary organisations engaged in promotion, development and propagation of Hindi, Central Government is providing them financial assistance at the rate of 75% of their approved estimates. Around 170 organisations are receiving such assistance. Organisations like, Dakshin Bharat Hindi Prachar Sabha and Akhil Bharatiya

Hindi Sanstha Sangh are receiving 100% financial assistance.

Promotion and Development of Modern Indian Languages

12.2.1 With a view to develop and train teachers in Modern Indian Languages for implementing the Three Language Formula, the Central Institute of Indian Languages is running full academic year courses for school teachers from different States/ Union Territories at their four Regional Language Centres and two Training Research Centres. Three hundred and ninety seven teacher trainees sponsored by different State Governments in 13 languages were admitted during the year under report. In addition to this, 110 are taking correspondence courses in Tamil and Bengali on experimental basis. To develop proficiency tests is languages for measurement of language competency, the Institute has prepared test items in seven languages, while tests in other seven languages are in progress.

12.2.2 The Institute has prepared grammars, dictionaries and primers in many tribal and border area languages, besides publishing a number of books in and on tribal languages. The Bureau for Promotion of Urdu has set up a branch office at Hyderabad to give a boost to Urdu promotion activities in South India. For preserving and developing calligraphic art in Urdu, BPU has set up 36 Calligraphic Training Centres in the country, of which 6 centres are exclusively for women. About 1000 students have so far benefited by these centres. The Bureau has also brought out a number of publications in Urdu, besides a glossary of technical terms in Urdu. A research Journal in Urdu called 'Fikro Tahkeek' is also being published by the Bureau.

12.2.3 Financial assistance is being provided to voluntary organisations as well as individuals for bringing out publications with a view to promote and propagate modern Indian languages. Similarly, voluntary organisations engaged in promotional activities in various modern Indian languages receive central assistance. The pattern of assistance under the schemes correspond to those for Hindi.

12.2.4 Schemes are being implemented through the Central Hindi Directorate for promotion and development of Sindhi which includes publication assistance, financial assistance for the voluntary organisations engaged in promotion and propagation of Sindhi and awards for Sindhi Scholars.

Improvement of Proficiency in English

12.3.1 In order to bring about substantial improvement in the standards of teaching/learning of English in the country, the Government is giving assistance through the Central Institute of English and Foreign Languages (CIEFL), for the setting up at least one district centre for English language in each state. So far, 22 centres have been set up. The Government is providing assistance to Regional Institutes of English, and English Language Teaching Institutes in different States through Central Institute for strengthening them.

12.3.2 The Government has entrusted a scheme to Regional Institutes of English in collaboration with CIEFL for preparation of tests for measuring proficiency levels in English for students after standard X as well as for foreign students coming to India for advanced study. These tests for measuring English proficiency called 'TEP 10' and 'TEP 12' are at an advanced stage.

Promotion of Sanskrit and Other Classical Languages

12.4.1 Recognising the importance of Sanskrit in promoting national integration and appreciation and preservation of our cultural heritage, several programmes have been initiated by the Government for the development and promotion of Sanskrit education and learning. Programme for the propagation and development of Arabic and Persian, the other two classical languages, has also been continued. Some of the main activities undertaken during 1988-89 for promotion of Sanskrit (including Pali and Prakrit) language, literature and learning are indicated below :—

Financial Assistance to Voluntary Sanskrit Institutions Engaged in the Propagation and Development of Sanskrit

12.4.2 Under this scheme, registered voluntary Sanskrit Organisations are given recurring and non-recurring grants for salary of teachers, scholarships to students, construction and repair of buildings, furniture, library etc. Seventy five per cent of the approved expenditure on each of the above items is given as grant from the Ministry and in the case of Vedic Institutions where oral Vedic tradition is being preserved, Govt. grant covers 95% of the total approved expenditure. About 700 Sanskrit Organisations are being given financial aid during this year.

Adarsh Sanskrit Maha-Vidyalaya/Shodh Samsthas

12.4.3 Out of the Voluntary Organisations, a few

institutions having potential for future development and offering post-graduate studies are provided with financial assistance @ 95% of recurring and 75% of non-recurring expenditure. So far, 12 post-graduate teaching institutions and two post-graduate research institutions have been brought under the purview of this scheme. Three of them are in Uttar Pradesh, one in Kerala, three in Bihar, two in Haryana, two in Maharashtra and three in Tamil Nadu.

Rashtriya Sanskrit Sansthan

12.4.4 The Sansthan, an autonomous organisation under the Ministry, has been set up for preservation and propagation of Sanskrit, including research, publication, collection and preservation of manuscripts and organising training activities. Since 1970, it has established eight Kendriya Sanskrit Vidyapeethas in seven States situated at Tirupathi, Delhi, Jammu, Allahabad, Puri, Guruvayoor, Jaipur and Lucknow. In addition, it has about 39 private institutions affiliated to it for the purpose of examination. It conducts examinations and awards certificates and degrees from Prathma to Vidya-Varidhi. It also provides Teachers' training, at graduate and post-graduate levels. At present, there are 2000 students on the rolls of Sansthan's Vidyapeethas, out of which 1200 students are given scholarships for their studies and about 700 students are provided with hostel facilities.

Deemed Universities

12.4.5 Two Vidyapeethas at Delhi and Tirupathi were declared as 'Deemed Universities', on 16th November, 1987.

12.4.6 The Vidyapeethas, apart from providing training, have undertaken a number of research, development and extension activities. These are discussed below :—

The Allahabad Vidyapeetha, which specialises in collection and preservation of manuscripts, has so far collected about 50,000 manuscripts and has published several important works. It has also launched a programme of microfilming manuscripts from the Kashmir University pertaining to Kashmir Shaivism. The work is under progress.

The Tirupati Vidyapeetha has been working on the following projects :

> Agama Kosha : The Vaikhanasa Agama Kosha has been taken up for printing. It will be followed by Pancaratra and Shaivism Kosha.
>
> Tape Recording of Vedas : Vedic recitation of various sakhas have been recorded up to 1200 hours. Further work is in progress with the help of Tirupati Tirumala Davasthanam.
>
> Tape Recording of Oral Shastric Tradition: Tape Recording of Mimansa tradition has been completed and recording of Nyaya tradition has started.

Jammu Vidyapeetha : This Vidyapeetha specialises in Kashmir Shaiv Darshan and the manuscript for Kashmir Shaiv Darshan Kosha has been completed. Revision is going on. A centre at Srinagar is being opened for collection of manuscripts of this tradition.

The Delhi Vidyapeetha specialises in the preparation of a Sandarbha Kosha on Sankhya Yoga, the manuscript of which is complete. The printing of Sabara Bhasya with commentaries is in progress.

12.4.7 **Head-Quarters Office** : Sloka Vartika with Tika on Mimansa, A study on Srauta Sutras, selection from vedas for students in Sanskrit, is in progress. In all, about 155 publications have come out from the different Vidyapeethas and the Head-quarters Office of the Sansthan. Compendia volumes for students of Sanskrit literature taken up at Head-quarters Office have been completed. Seminars on Mimansa and Kashmir Shaivism were conducted at Tirupati and Srinagar respectively during the year.

12.4.8 During the year 1988, about 154 students have been registered for Vidyavaridhi course in different Vidyapeethas and about 24 scholars have been awarded the Vidyavaridhi degree.

Scholarships

12.4.9 The Rashtriya Sanskrit Sansthan has been operating the two scholarship programmes on behalf of the Ministry of Human Resource Development.

> Under Research Scholarships Scheme to Products of Sanskrit Pathshalas, a monthly stipend of Rs. 300/- is given to research scholars for a period of two years. In addition, a contingent grant of Rs. 500/- per year is also given to each student.
>
> Under Post-Matric Scholarships, Students who study Sanskrit as a subject at M.A/Acharya and Ph.D. levels in the modern stream are awarded scholarships at the rates of Rs. 100/- per month and Rs. 300/- per month respectively.

Sanskrit Dictionary Project, The Deccan College, Pune

12.4.10 Assistance is being provided to Deccan College, Pune for preparing a Sanskrit Dictionary on

Historical principles which will help research scholars in the interpretation of old and difficult Sanskrit texts. Three parts each of Volume I and II, and part I of volume III have already been published.

Utilisation of Services of Senior Eminent Sanskrit Scholars to Impart Indepth Study in Sastras

12.4.11 Under this scheme, 85 eminent Sanskrit scholars have been approved for guiding junior members of the staff and senior students in Adarsh Sanskrti Pathshalas, some important voluntary Sanskrit teaching institutions, research centres and Sanskrit Universities in the indepth study of higher texts, research and methodology. These scholars are appointed on a monthly honorarium of Rs. 1000/-.

Financial Assistance to Voluntary Organisations Engaged in the Propagation and Development of Classical Languages other than Sanskrit i.e. Arabic and Persian

12.4.12 Under this scheme, registered Voluntary Organisations working for the promotion of Arabic and Persian are given financial assistance towards salary, scholarships, furniture, library, etc. and other activities. About 200 institutions are being assisted under this scheme. Scholarships are also awarded every year to students of traditional Madrasas and Maktabs to prosecute higher research in Arabic and Persian.

Award of Certificate of Honour to Sanskrit, Arabic and Persian Scholars

12.4.13 This scheme envisages giving of President's award of Certificate of Honour to eminent Sanskrit, Arabic and Persian scholars. Every year 14 scholars—10 in Sanskrit and two each in Arabic and Persian—are selected for the award and their names are announced on the eve of Independece Day. The award carries an annual monetary grant of Rs. 10,000/- for life. Each scholar is presented with a Sanad and a Shawl at a function held at Rashtrapati Bhavan. As in the past, 14 scholars were selected for award this year.

Scheme for Development of Sanskrit through State Governments/Union Territories

Financial Assistance to Eminent Sanskrit Scholars in Indigent Circumstances

12.4.14 About 1,460 eminent scholars whose income is below Rs. 4,000/- per annum are receiving financial assistance upto Rs. 4,000/- per annum under this scheme.

Modernisation of Sanskrit Pathshalas

12.4.15 To bring about a fusion between the traditional and modern systems of Sanskrit education, Government of India is giving grant to State Governments for appointment of teachers for teaching selected modern subjects in the traditional Sanskrit pathshalas. Assistance is expected to be released to three States and Union Territories for appointment of one teacher each during 1988-89.

Providing Facilities for Teaching Sanskrit in High and Higher Secondary Schools

12.4.16 Government of India steps in to fill up the gap by giving 100% grant towards salary of Sanskrit teachers to be appointed in such High and Higher Secondary Schools where the State Governments are not in a position to provide facilities to teach Sanskrit. Three States are likely to avail of this assistance during 1988-89 for appointing nine teachers.

Scholarships to Students Studying Sanskrit in High and Higher Secondary Schools

12.4.17 In order to attract good students to the study of Sanskrit in the High and Higher Secondary schools, merit scholarships are given to Sanskrit students in IX to XII classes @ Rs. 10/- per month. About 3,000 students are getting benefit under this scheme. The proposal to increase the amount of scholarship is under consideration.

Grant to State Governments for their own schemes for promotion of Sanskrit

12.4.18 Under this scheme, a State Government is free to chalk out its own programmes for development and propagation of Sanskrit like upgrading the salary of teachers, honouring of vedic scholars, conducting Vidwat Sabha, holding of evening classes for Sanskrit, celebrating Kalidasa Samaroh, etc. Assistance under this scheme is expected to be given to five States/UTs during 1988-89.

Production of Sanskrit Literature

12.4.19 Under this scheme, assistance is given for (i) printing and publication of original works relating to Sanskrit literature, (ii) printing of out-of-print Sanskrit books, (iii) purchase of Sanskrit publications from authors and publishers for free distribution to various institutions, (iv) Sanskrit journals to improve their quality and contents, (v) preparation and publication of descriptive

Prime Minister Rajiv Gandhi Honouring Hindi Scholars, Inaugurating Silver Jubilee
of Kendriya Hindi Shikshan Mandal · 13th February 1989
at Vigyan Bhavan, New Delhi.

catalogue of Sanskrit Manuscripts and publishing critical editions of Sanskrit Manuscripts.

12.4.20 During 1988-89 (upto the end of December, 1988) 20 publications have been brought out with Government assistance. About 20 more publications are expected to be brought out during 1988-89. Besides these, Dharma Kosha Mandala, Wai, which is engaged in the work of preparation and publication of Dharam Kosha, an encyclopaedia of ancient Sanskrit Literature will receive a sizable amount of grant from Government of India during the remaining period of Seventh Five Year Plan. All India Kashiraj Trust, Varanasi is engaged in bringing out Hindi translations, English translations and critical editions of all the Mahapuranas with Government assistance.

12.4.21 About 33 journals are being assisted by Government of India by giving a grant ranging from Rs. 1500/- to 10,000/- per annum to improve their quality and contents. Government has also purchased about 200 books from individuals and publishers for free distribution to various institutions. Two catalogues/critical editions of manuscripts have been brought out in 1988-89. Five more catalogues/critical editions are expected to be published during 1988-89.

12.4.22 Besides, a massive programme for bringing out photo offset reproduction of important out-of-print Sanskrit books has been undertaken with a view to make them available at low price to the readers. About 30 books are expected to be reprinted during 1988-89.

Preservation of Oral Tradition of Vedic Studies

12.4.23 As a special incentive to preserve the oral tradition of Vedic studies, a scheme was introduced during 1978 under which each swadhyayin is expected to train two students each below the age of 12-one of them being their own son or near relative, in a particular Veda Shakha. During 1988-89, fifteen such units are receiving assistance. Under this scheme, the scholar is getting an honorarium of Rs. 1250/- p.m. and the student a stipend of Rs. 175/- p.m.

Vedic Convention

12.4.24 In order to locate and identify the areas and families where the oral vedic tradition is still alive, the Ministry holds a vedic convention every year in which scholars from all over India are invited. This year's Vedic Convention is expected to be organised in January, 1989.

All India Elocution Contest

12.4.25 This Ministry is holding an All India Elocution Contest to encourage oratorial talents in the students of traditional Sanskrit Pathshalas in various branches of Sanskrit learning. Teams of eight students alongwith a teacher from all States are invited to participate in this. This year's contest is scheduled to be held in January/February 1989.

Rashtriya Veda Vidya Pratishthan

12.4.26 Rashtriya Veda Vidya Pratishthan has been set up recently for undertaking various activities, such as supporting traditional vedic institutions and scholars, providing scholarships/fellowships etc. for promotion of oral traditions of vedic studies. The Pratishthan was inaugurated on 19th August, 1987 Rupees 20.00 lakhs have been sanctioned to the Pratishthan for utilising the same as a corpus fund during the year 1988-89.

12.4.27 In addition to it, an amount of Rs. 5.00 lakhs has been sanctioned to the Pratishthan during 1988-89 for meeting expenses on establishment and salary of staff etc. The Pratishthan has organised two workshops on Vedic Mathematics—one at Jaipur in March, 1988 and the other at Ahmedabad in October, 1988.

Vocational Training to Products of Sanskrit Pathshalas

12.4.28 This scheme was introduced with a view to enhance the employment possibilities of students passing out of Kendriya Sanskrit Vidyapeethas, Adarsh Sanskrit Mahavidyalayas, and other traditional Sanskrit institutions. It provides short-term vocational training to those students in subjects allied to Sanskrit studies, namely, Epigraphy, Manuscriptology, Ritualogy, Sanskrit printing and composing etc. For conducting these courses, registered voluntary organisations receive cent per cent grant. During 1988-89, about twelve such courses are likely to be conducted.

Activities and Functions of various Advisory Boards/Commissions

Central Sanskrit Board

12.4.29 The Central Sanskrit Board advises the Government of India on matters of policy pertaining to the propagation and development of Sanskrit in the country, regarding patterns of Sanskrit Education at different levels etc.

Grants Committee on Voluntary Sanskrit Arabic/Persian Organisations

12.4.30 The Grants Committee on Voluntary

Sanskrit, Arabic and Persian organisations considers the applications received from different institutions through respective State Governments working for the propagation and development of Sanskrit, Arabic and Persian and recommends financial assistance to them. Meetings of these Committees were held on 18/19th August, 1988, 7th December, 1988 and 16th January, 1989.

Experts Committee Constituted for Selecting Eminent Elderly Sanskrit Scholars

12.4.31 This committee scrutinises the applications and selects suitable scholars for imparting indepth coaching of Shastric subjects like Vyakarana, Nyaya, Vedanta etc. under Shastra Chudamani Scheme. Last meeting of this committee was held on 26th September, 1988.

Border Area Development Programme

13.1.0 The Border Area Development Programme covers four Border States of Gujarat, Rajasthan, Punjab and Jammu and Kashmir. A provision of Rs. 200 crores was made for the Seventh Five Year Plan for this programme, which was implemented by the Ministry of Home Affairs during 1986-87. This was transferred to the Department of Education from the year 1987-88. The intention was that the programme could be confined to Education and allied matters which are critical inputs for the development of border areas. Now, emphasis is laid, under the programme, on over-all human resource development. The efforts under this programme are a supplement to the State Educational Development Programmes, including those that may be taken up under the NREP, RLEGP, IRDP and Desert Development Programmes. Under the Programme, funds are provided for opening new schools, upgradation of schools, construction of additional class rooms, laboratories, toilets etc. in existing schools, provision of essential facilities, establishment of polytechnics and ITIs, setting up of adult education and non-formal education centres, youth programmes, cultural development activities etc.

13.2.0 For implementing the programme, the Department of Education formulated guidelines and circulated the same to the border States. They were requested to send their proposals according to these guidelines. A Sanctioning Committee under the Chairmanship of Education Secretary has been set up with respresentatives from the Planning Commission, the State Governments and the concerned Ministries to clear the proposals of the States promptly.

13.3.0 As recommended by the Sanctioning Committee, administrative approvals for various programmes/activities amounting to Rs. 36.63 crores were conveyed to State Governments and the entire budget provision of Rs. 25 crores was released to them during 1987-88. During 1988-89, against a provision of Rs. 45.50 crores (the original provision of Rs. 35.5 crores was enhanced to Rs. 45.5 crores) administrative approvals have been accorded by the Sanctioning Committees for various activities amounting to Rs. 60.69 crores (besides commitments for on-going activity) and an amount of Rs. 23.12 crores has been released to State Governments till 31.1.89

13.4.0 The National Institute of Educational Planning and Administration had organised a workshop on 19-21 September, 1988, in which concerned officers of four border States participated, for formulating norms and guidelines for preparation of block development plans and for monitoring and evaluation of the programme.

Twenty Point Programme, 1986 and Access to Education for the Disadvantaged

Education of Scheduled Castes and Scheduled Tribes

14.1.1 The Programme of Action in respect of National Policy of Education (1986) envisages a number of steps for the improvement of education status of SC/ST and other weaker sections. In order to review and advise on matters relating to educational programmes for SCs and STs at the national level, a CABE Committee has been formed (already referred to) under the Charimanship of Smt. Rajendra Kumari Bajpai, Minister of State in the Ministry of Welfare. The Second meeting of the Committee was held on 25th August, 1988. The Committee deliberated on the existing programmes, schemes, etc. meant for the educational development of the weaker sections and has come out with a number of recommendations in respect of implementing the programmes, timely disbursement of scholarships and other incentives, introduction of remedial and special coaching, micro-planning, etc.

14.1.2 Special emphasis has been laid on the removal of disparities and equalisation of educational opportunities by attending to specific needs of those who have not been able to take full advantage of the present educational provisions and facilities.

14.1.3 During the year 225 students were covered under the scheme "Upgradation of merit of SC/ST students" by special and remedial coaching in 12 approved schools in Andhra Pradesh, Assam, Orissa and Rajasthan and 113 students were selected for nomination in approved residential secondary schools all over India.

Education of Minorities

14.2.0 The programmes for the educational development of minorities were pursued during the year under report according to Prime Minister's 15 Point Directive for the improvement of minorities. A brief account of the programmes is given below :—

(i) **Vocational Training**

In the ten community polytechnics in areas of minority concentration, more than 10,000 persons were trained through short-term vocational courses in various skills/crafts.

(ii) **Coaching Classes**

The UGC implements a scheme for providing assistance to universities and colleges for coaching students from educationally backward minorities. The coaching is done by preparing the students for competitive examinations. The coaching is being conducted at present in 20 universities and 14 colleges.

(iii) **Review of Text-books**

The school text-books are being evaluated from the view point of national integration. (This has been dealt with under "School Education" as well). The aim is to remove materials and approaches which directly or indirectly perpetuate untouchability, racism, regionalism, casteism and communalism from text-books prescribed in schools and colleges with a view to promoting national integration and emotional unity. The NCERT has prescribed guidelines for developing curricula in various subjects. At the State level the SCERTs, the State Text-books Boards/Corporations have taken steps to revise the curriculum in the light of national curricular frame-work.

Education of Women

14.3.0 In the formulation of Educational Schemes, the need for providing access to education for girls/women in a significant way was kept in view. Details of such schemes have been furnished under the relevant chapters—dealing with Elementary School, Adult and Technical Education.

14.4.1 Under the 20-Point Programme, progress in Elementary, Non-Formal and Adult Education has to be closely monitored with reference to pre-determined targets. In the case of Elementary and Adult Education, targets are to be fixed, according to instructions from the Ministry of Programme Implementation and Planning Commission, in terms of enrolment. Monitoring of Non-Formal Education is to be evaluatory.

14.4.2 Consistent with NPE 1986 and POA, the Department of Education has wanted establishment of a new Monitoring system, emphasizing "retention' as well as attainment of competencies. The matter was discussed in the Planning Commission and the Ministry of Programme Implementation. Finally, it has been decided in the Cabinet Secretariat in a meeting of Committee of Secretaries that until the new Monitoring system is established, targets may be fixed and monitoring done in terms of enrolment as regards Elementary and Adult Education.

Management, Monitoring and Evaluation

Central Advisory Board of Education (CABE)

15.1.1 The Central Advisory Board of Education (CABE) consisting of Education Ministers from States, Administrators, educationists and academics continued to be the national level body, providing vital inputs for the management of education policy — by reviewing trends in the education sector, analysing implementation of programmes and advising on policy prescriptions.

15.1.2 The Board functioned through ten committees, constituted with mandate for concentrating in the following areas :

- Elementary Education (including Operation Blackboard)
- Content & Process of education, particularly at the school stage.
- Transfer of teachers.
- Housing facilities for women teachers.
- Common School System.
- Vocationalisation of Education.
- Development of languages and language teaching.
- Scheduled castes/Scheduled tribes and other educationally deprived groups.
- Management of education.
- Resources for education.

15.1.3 Presented in the following table below are particulars of the meetings of the CABE and its committees and their principal recommendations :

Meetings of the Central Advisory Board of Education, its committees and their Principal Recommendations

S. No.	Particulars of Central Advisory Board of Education & its bodies	Dates of the meetings	Principal recommendations/ business transacted.
1	2	3	4
1.	Central Advisory Board of Education	13 & 14 September, 1988	— Funding all NPE Schemes during Eighth Plan Period
			— Decentralised micro planning
			— Evolving meaningful monitoring system
			— Emphasis on value education
			— Management structures for streamlining vocational education

1	2	3	4
			— Need for establishing State Councils of Higher Education — Regular and systematic performance appraisal of teachers — Restraint in establishment of new colleges — Provision of special support services in the form of child care services in every village — Special attention to the education of tribals to retain their rich cultural identity and heritage — Implementation of foster parent scheme — Urgent need to re-establish linkage between educational institutions & specialised R&D organisations — Provision of incentives for promoting research activities in technical institutions — Setting up of a National Research Council to coordinate R & D in all sectors of higher education
2.	Committee on Transfer of Teachers	25th October, 1988	— Discussed draft report and decided that comments of the State Governments may be invited
3.	Committee on Management of Education	15th June, 1988	— Guidelines for State Advisory Board of Education, District Boards of Education and Village Education Committees finalised
4.	CABE Committee on Elementary Education including Non-Formal Education	8.7.1988	— Need to continue Central assistance for the scheme of Operation Blackboard during 8th Plan — Construction of school buildings out of NREP/RLEGP funds to be pursued with the concerned department — Forming a pool of resource persons in each State to prepare teaching and learning materials and curriculum for NFE Programmes.
5.	CABE Committee on Vocationalisation	29.7.1988	— Setting up two adhoc groups to go into the question of formulation of appropriate vocational courses for rural areas and for girls/women. — Reviewed the progress of implementation of the scheme and observed that not much action had been taken by the States : suggested that the matter should be taken up with the States strongly.
6.	CABE Committee on Scheduled Castes/ Scheduled Tribes and other educationally deprived groups	25.8.1988	— Reviewed in detail the various schemes meant for the development of educationally deprived groups and made significant suggestions. The important items discussed included monitoring proforma to monitor major programmes for educational development of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

1	2	3	4
			— Effective micro-planning for location of facilities where SC/ST Children form a significant population.
			— Rationalisation of procedure for disbursement of scholarships, preparation of primers in tribal languages
			— Establishment of nodal agencies in the States.
7.	CABE Sub-Committee on Housing Facilities for Women Teachers	21.7.1988	— The scope of the committees work to be restricted to elementary school teachers, with special attention to the problem of primary school teachers
			— A multi-pronged approach envisaged for dealing with the problem comprising inter-alia, the following:—
			a) For the rural areas, a cluster approach i.e. construction of a cluster of houses for women employees at a central place, say, Panchayat headquarters favoured.
			b) In urban areas, Working Women's Hostels, preferable with a few apartments, to provide the most cost effective answer.
			c) Teachers to be encouraged to construct own houses.
			d) Ways to be found for providing cheap houses
			e) Voluntary agencies associated with CAPART to be utilised to construct some of the clusters.

Conferences of State Education Secretaries and Directors

15.2.0 Conferences of State Education Secretaries and Directors were held too as a means of managing education. Particulars of these conferences held during the year are furnished below:

Conferences of State Education Secretaries/Directors and their important recommendations

S. No.	Particulars of participants	Date of the Conference	Important decisions
1	2	3	4
1.	Education Secretaries/ Commissioners and Directors of Higher Education, Secondary Education, Adult Education, Elementary Education, etc. of all State Governments/ UT Administrations.	17 & 18 June, 1988	— Introduction of the system of micro-level planning. — Implementation of Scheme of Operation Blackboard on a high priority basis. — Ensuring Quality of teaching at Navodaya Vidyalayas — Activising Educational Technology Cells in the States. — Improvement of programmes for training of teachers in computer literacy.

1	2	3	4
			— Implementation of three-language formula in all parts of the country on a time-bound basis.
			— Careful selection of colleges for grant of autonomous status.
			— Introduction of system of systematic performance appraisal for university and college teachers.
2.	- do -	12 Sept. 1988	— Recommended measures for effective monitoring systems in respect of universalisation of Elementary Education, Non-Formal Education and Higher Education.

Educational Statistics

15.3.1 In order to facilitate meaningful management of education, "educational statistics" was given special attention. The standing committee on "educational statistics" met on 19.12.88 (thirteenth meeting) and reviewed the progress of work undertaken by the Statistics Unit of the Department of Education.

15.3.2 The officers of the Department of Education participated in the Data Users' Conference (1981 census) organized by the Registrar General of India in April 1988.

15.3.3 The Department of Education further deputed its officers as resource personnel for training programmes on educational statistics organized by the Government of Orissa.

15.3.4 A working Group set up by the Department finalised the modalities of the Central Plan Scheme on "Computerisation of Educational Statistics in States/UTs" - for application in the educationally backward states.

15.3.5 The following publications on educational statistics were brought out during the year under report :

1. Education in India, 1976-77, Vol. III
2. Education in India, 1979-80, Vol. II
3. Education in India, 1982-83, Vol. I
4. Education in India, 1983-84, Vol. I (under print)
5. A study on Correspondence Courses in India, 1980-81.

6-12 District-wise Educational Statistics 1981-82 : Assam - Vol. V, West Bengal - Vol. VI, Punjab Vol. VII, Himachal Pradesh - Vol. VIII, Goa, Daman and Diu - Vol. IX, Bihar - Vol. X - Tamil Nadu - Vol. XI.

13. Indian Students/Trainees Going Abroad 1983-84.
14. Foreign Students studying in Indian Universities, 1983-84.
15. Selected Information on School Education 1985-86.
16. Selected Information on School Education, 1986-87.
17. Selected Educational Statistics, 1986-87.
18. Non-formal Education (College level) in India.

Computerised Management Information System (CMIS)

15.4.1 Progress was also made in developing a Computerised Management Information System (CMIS).

15.4.2 In this context, the National Informatics Centre installed eight micro computers and one computer of advanced technology having large storage capacity, with 16 terminals.

15.4.3 The Status of the projects computerised under the CMIS are given below :

S. No.	Name of the Project	Status
1.	Foreign-Students Studying in Indian Universities	1984-85 completed
2.	Indian Students Going Abroad	Completed upto 1985-86
3.	Analysis of Budgeted Expenditure	Completed for the year 1987-88
4.	Annual Action Plan in respect of the important activities of the Department and quarterly reports on its implementation for submission to Cabinet Secretariat and PM's Office.	IInd Quarterly Report submitted (1988-89)
5.	Database in respect of "Selected Educational Statistics in India"	Completed for the year 1987-88
6.	State Plan allocations and achievements during the four years of the VII Five Year Plan	Completed for the year 1988-89
7.	Development of an International Book Numbering System (A project of NERC)	Regularly supplied.
8.	Computerisation of Pay-bills and Payslips for the Officers/Staff of the Department.	Regularly supplied
9.	Education in India	1984-85 and 1985-86 in progress
10.	Simulation models for projecting Statewise gross enrolment ratios for Classes I-V and VI-VIII	Completed

15.5.0 The National Institute of Educational Planning and Adminstration (NIEPA), set up by Govt. of India as an autonomous organisation continued to undertake the following activities:

— Training and Orientation of Senior educational administrators.

— Research in progress of Educational planning and administration (two research studies completed and eleven in progress).

— Extension services and consultancy services for States and other organizations.

— Seminars, workshops and conferences on matters relevant to educational planning and administration (Forty-nine training programmes/seminars/workshops conducted upto end of November 1988 and sixteen training programmes scheduled upto 31.3.1989).

— Provision of training and research facilities to other countries and to international organizations, UNESCO, UNDP, IIEP, Commonwealth Secretariat etc.

— Provision of technical support to Government on management of education (guidelines evolved on micro-level planning. Community participation and role of village communities—in relation to School education).

Progress Report on NPE

15.6.0 The Department of Education has been bringing out periodical reports about the progress of implementation of the NPE, 1986. Implementation Reports as on 30.6.88 and 30.11.88 were brought out and circulated to all concerned, including members of the Consultative Committee of Parliament attached to the Ministry of HRD. The Consultative Committee considered these reports at its meetings held on 2nd December, 1988 and 15.2.89.

Annual Action Plan

15.7.0 Annual Action Plan (AAP) for the year 1988-89—reflecting objectives under different programmes, time-frame for accomplishment of goals, achievement of physical and financial targets for the year 1988-89—was prepared. Quarterly progress reports of AAP, 1988-89 were regularly sent to the Cabinet Secretariat.

Scheme of Assistance for Studies, Seminars, Evaluation etc. for Implementation of Education Policy

15.8.1 The Scheme of assistance for studies, seminars, evaluation etc., for implementation of education policy aims at resolving problems relating to the formulation, implementation and evaluation of education development programmes.

15.8.2 The scheme is intended to provide financial assistance to deserving institutions and individuals on the merits of each proposal having a direct bearing on the management and sponsoring of seminars, conduct of impact and evaluation studies, consultancy assignments in order to advise the Government of the best alternatives and models for making the system work.

15.8.3 Financial assistance, upto a maximum of Rs. 1 lakh is given under this scheme for each approved proposal. During 1988-89 organisation of eight seminars and two regional projects was approved. Assistance was also given for dissemination of information about educational developments and preparation of a video film on non-formal education.

15.9.1 In view of the concerns of the National Policy on Education, 1986 and POA, and in consideration of the fact that the Central Government have come to work in partnership with the State Governments in a significant way in the area of education, Monitoring and Evaluation has come to be attached special importance. In the conference of State Education Secretaries and Directors held in September, 1988, it was agreed on all sides that monitoring should not be mere assessment of financial and physical targets but should be a basic assessment of the progress towards established goals. The following areas have been identified for priority attention:

* Progress towards universalisation of Elementary Education in terms of completion of specified number of years of schooling by specific age levels, retention in schools and attainment of competencies;
* Establishment of Management Information System to assess progress in Non-Formal Education—to facilitate quantitative and qualitative assessment as well as learner evaluation;
* Progress in Science Education;
* Progress in vocationalisation;
* Conformity to academic calendars in universities;
* Progress in modernisation and development of thrust areas in Technical Education;
* Adult Literacy including learner evaluation.

15.9.2 Steps to establish monitoring systems in regard to these priority areas are under different stages of action. An Expert Committee constituted under the chairmanship of Additional Secretary, Department of Education, in fact, gave its interim recommendations for a monitoring system in respect of Universal Elementary Education etc. which were discussed in the conference of State Education Secretaries in September, 1988. Based on these discussions and on the basis of subsequent stock-taking, it is proposed to associate the Indian Institute of Management in the effort.

International Co-operation

Cooperation between India and Unesco

16.1.0 As one of the founding members of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation, India has consistently endeavoured to promote the aims and objectives of the Organisation. The Indian National Commission for Cooperation with Unesco, which was established in 1949 by the Government of India in compliance with Article VII of the Constitution of Unesco, has been playing an effective role as an advisory, executive, information and liaison body at the national level and also collaborating with the National Commissions of Asia and the Pacific Region and with Unesco's Regional Office and Centres for implementation of Unesco's programmes and activities in all the areas of its competence.

16.2.0 As a founder remember of Unesco's major regional programme of Educational Innovation for Development for Asia and the Pacific (APEID), which was launched in 1974, India has actively participated in APEID activities. A National Development Group has been established under this programme which acts as an identifier, stimulator and coordinator at national level of educational innovation for development within the country. The National Council of Educational Research and Training facilitates dissemination of information about activities of APEID, innovative experiences at the regional level and making outcomes of regional cooperation within APEID known widely in the country.

16.3.0 Another significant activity to which India has extended its full support and cooperation to Unesco is the Asia-Pacific Programme of Education for All (APPEAL) which was launched from New Delhi by Unesco in 1987. With a view to giving further fillip to this Programme and to work out measures to eradicate illiteracy by the year 2000, a Regional Working Group meeting on International Literacy Year under APPEAL was organised in collaboration with Unesco's Principal Office for Asia and the Pacific, in New Delhi from October 11-14, 1988, which was attended by high level officials and planners from Afghanistan, Bangladesh, India, Indonesia, Iran, Nepal and Pakistan. India also organised a Sub-Regional Symposium to promote activities in Unesco's field of competence for Technical Cooperation among Developing Countries (TCDC) in South Asia which was held in New Delhi from December 5-9, 1988. India participated in the Eleventh Regional Consultation meeting of APEID in August, 1988 in Bangkok and in the Ninth Regional Conference of Unesco National Commissions in Asia and the Pacific held in Beijing from September 22-27, 1988.

16.4.0 India actively collaborated with Unesco and its Regional Offices in the implementation of its activities by arranging participation of Indian experts and institutions in various workshops and symposia, arranging placements of Unesco fellows in Indian Institutions and laboratories and implementing projects under the Participation Programme of Unesco. It also continued to operate Unesco Coupons Scheme and publication of Hindi and Tamil editions of Unesco Courier and the Newsletter. A brief resume of activities undertaken during the year is given below:

Thirty-fourth Session of the Editorial Board of International Review of Education and Fortieth Session of the Governing Board of Unesco Institute of Education, Hamburg.

16.5.0 As a member of the Governing Board of the

Institute, Shri Kireet Joshi, formerly Special Secretary, Ministry of Human Resource Development, Department of Education, participated in the 34th Session of the Editorial Board of the International Review of Education (May 2, 1988); and the 40th Session of the Editorial Board of the Unesco Institute for Education (May 3—5, 1988) held in Hamburg where Unesco's Third Medium Term Plan was also discussed. In the Consultation meeting held on May 6-7, 1988, the members considered various aspects of the research priorities and action in education that Unesco could undertake during the Third Medium Term Plan.

Regional Consultation on the Third Medium Term Plan of Unesco, Pattaya, Bangkok, May 12-14, 1988

16.6.0 Shri S. Gopalan, Additional Secretary, Department of Education, Ministry of Human Resource Development, participated in the Regional Consultation on Third Medium Term Plan of Unesco held in Pattaya, Thailand from May 12-14, 1988. During the deliberations of the meeting it was emphasised that the activities relating to reflection on world problems and future-oriented studies should be given adequate importance on account of the intellectual mission of the Organisation and that there should be rational balance between operational and intellectual activities. In the deliberations, India's representative laid considerable stress on the advancement of the cause of peace and human rights through the process of education. It was urged that activities related to peace and human rights should find an important place in the Third Medium Term Plan by undertaking and encouraging activities aimed at eliminating apartheid, all forms of prejudice, intolerance, racism and discrimination as also educational programmes promoting international understanding, human rights and fundamental freedoms.

Meeting of the Sub-Commission on Communication of the Indian National Commission for Unesco

16.7.0 The Indian National Commission for Cooperation with Unesco convened a meeting of its Sub-Commission on Communication on 12th July, 1988 in New Delhi, under the Chairmanship of Shri G. Parthasarthi, to consider the Draft World Communication Report. The Sub-Commission made various recommendations on international communication issues.

Meeting of the National Coordination Committee of Asia-Pacific Programme of Education for All and International Literacy Year

16.8.0 In view of the significance of Asia-Pacific Programme of Education for All (APPEAL) and the International Literacy Year (ILY), a National Coordination Committee on APPEAL and ILY has been set up for policy planning, stimulation of public awareness and dissemination of information and experiences including monitoring and evaluation of implementation of these programmes. The first meeting of the National Coordination Committee was held in New Delhi on July 20, 1988 to consider strategies for the International Literacy Year and launching motivational campaigns for literacy programmes especially for women.

Eleventh Regional Consultation Meeting on Asia and Pacific Programme of Educational Innovation for Development (APEID)

16.9.0 Shri Anil Bordia, Education Secretary, participated in the Eleventh Regional Consultation Meeting on Asia and the Pacific Programme of Educational Innovation for Development (APEID) organised by Unesco in Bangkok from August 2-9, 1988. The meeting reviewed the progress of APEID during the period January-June, 1988, studied emerging trends and developments of education and current implications for education's future in the Member States participating in APEID. It also discussed new thrusts for improving and enhancing the quality and efficiency of education through innovation and considered new approaches for strengthening the APEID network and its methods of cooperation.

Ninth Regional Conference of Unesco National Commissions in Asia and the Pacific

16.10.0 Shri Anil Bordia, Education Secretary, participated in the Ninth Regional Conference of Unesco National Commissions in Asia and the Pacific held in Beijing from September 22-27, 1988. The Conference exchanged views on Unesco's Third Medium Term Plan and on the activities to be undertaken in the World Decade for Cultural Development. It also discussed the measures and activities to be taken in preparing the International Literacy Year, implementing APPEAL programmes and reviewed the role of National Commissions and regional cooperation among them.

Meeting of the Regional Working Group on International Literacy Year

16.11.0 Indian National Commission for Coopera-

tion with Unesco in collaboration with Unesco's Principal Regional Office for Asia and the Pacific, Bangkok convened a meeting of the Regional Working Group on International Literacy Year in New Delhi from October 11-14, 1988. The working group comprised mainly of high-level officials and policy makers from Asia and the Pacific countries which have substantial problems of illiteracy. Participants from Afghanistan, Bangladesh, India, Indonesia, Iran, Nepal and Pakistan and representatives of international organisations such as UNDP, UNICEF and World Bank attended the meeting which was inaugurated by Shri L.P. Shahi, Minister of State for Education and Culture. The Working Group examined the effectiveness of various approaches and strategies to eradicate illiteracy especially among girls, women and disadvantaged population. The Working Group also considered in detail the measures which should be taken with a view to eradicating illiteracy by the year 2000 and how international organisations could provide help to the countries of the region, individually and collectively, in this direction.

Sub-Regional Symposium to Promote TCDC in South Asia

16.12.0 Unesco Regional Unit for Social and Human Sciences in Asia and the Pacific, in collaboration with Indian National Commission for Cooperation with Unesco, organised a sub-regional symposium to promote activities for technical cooperation among developing countries in South Asia in Unesco's areas of competence viz., Education, Social Sciences, Natural Sciences, Culture and Communication. The symposium was hosted in New Delhi from December 5-9, 1988. Delegates from Bangladesh, India, Maldives, Nepal, Pakistan and Sri Lanka attended the symposium. Besides, representatives of Asian Mass Communication Research and Information Centre (AMIC), Asia Pacific Institute for Broadcasting Development (AIBD), UNESCO, UNDP and ESCAP also participated as observers. The symposium reviewed activities in member countries of South Asian region with reference to TCDC experience of other regional institutions. It also identified needs, available facilities and areas of possible collaboration with a view to recommending most suitable modalities of execution with identified possible source of funding.

Participation Programme of Unesco

16.13.1 Under the Participation Programme, Unesco provides financial assistance to various institutions and organisations of the Member States who are engaged in the promotion of programmes and activities of Unesco, for undertaking innovative projects which would contribute at the national, sub-regional, regional and international levels to the implementation of the objectives defined by the General Conference of Unesco. During the biennium 1988-1989, Unesco has approved 13 projects with a financial assistance of US$ 1,12,000.

16.13.2 In order to associate itself with the centenary celebration of Shri Jawaharlal Nehru, Dr. S. Radhakrishnan, Maulana Abul Kalam Azad, Unesco has approved, under the Participation Programme, the organisation of (i) symposium on 'Jawaharlal Nehru Liberation Movement in Asia and Africa and the World' by Jawaharlal Nehru Memorial Museum and Library; (ii) International Seminar on 'Dr. S. Radhakrishnan's contribution to Philosophy, a Critical Appraisal' by the Indian Council of Philosophical Research; and (iii) symposium on 'Maulana Abul Kalam Azad and movements of Reforms within Islam in the 20th Century' by Jamia Millia Islamia, New Delhi.

Unesco Clubs Movement

16.14.0 The Indian National Commission for Cooperation with Unesco is associated with this project right from its inception and has been actively involved in encouraging the establishment and strengthening of the Unesco Clubs in all parts of the country. There are about 250 Unesco Clubs registered with the Commission at present which are being provided with material and financial help in organising activities designed to promote the aims and objects of Unesco.

Education for International Understanding-Unesco Associated Schools Project

16.15.0 This project aims at promoting the general development of education for international understanding through widespread network of institutions. There are at present 36 institutions in India which are participating in this project and are directly linked with Unesco Secretariat for material and intellectual support required in organising various programmes and activities in furtherance of its objectives. With a view to enabling the Heads and Co-ordinators of Associated Schools in the country to exchange their experiences and to consider measures for more effective implementation of the project, the Indian National Commission in collaboration with the Kendriya Vidyalaya Sangathan, New Delhi organised a Workshop of the Co-ordinators of the Associated

Mr. Federico Mayor, Director-General, UNESCO meets Minister for Human Resource Development.

Schools in the Kendriya Vidyalayas at Shimla from May 9-11, 1988. At this Workshop, the participants discussed various aspects of the Associated Schools Project, its objectives, main themes of study, relevant activities and operational mechanism. The Workshop deliberated in detail about the measures which would help in the promotion of international understanding, cooperation and peace.

Unesco Coupons Programme

16.16.0 The Commission continued to operate the Unesco International Coupons Scheme designed to assist institutions and individuals working in the fields of education, science, culture and communication to import their bonafide requirements of educational publications, scientific equipment, educational films, etc. from abroad without undergoing the foreign exchange and import control formalities. The total sale of Unesco coupons during 1988-89 amounts to about Rs. 7,35,000/-.

Publication of INC 'Newsletter'

16.17.0 For the purpose of dissemination of information about the programmes and activities of Unesco and those of the Indian National Commission, a half-yearly Newsletter is brought out by the National Commission. The Newsletter is widely circulated in India and abroad.

Publication of Indian language editions of Unesco Courier

16.18.0 'Courier' is an outstanding educational and cultural periodical of the world which is brought out by Unesco. The Indian National Commission continued to bring out its Hindi and Tamil editions. The language versions enjoy a wide circulation amongst educational institutions, libraries, Unesco Clubs, Associated Schools and the public at large.

Scheme of Financial Assistance to Voluntary Bodies, Unesco Clubs and Associated Schools

16.19.0 The Commission is operating a scheme of financial assistance to voluntary organisations, Unesco Clubs and Associated Schools for undertaking various innovative activities/projects aimed at the promotion of the ideals and objectives of Unesco. During the year under review, grant-in-aid worth Rs. 12,000 were sanctioned to the various organisations, Unesco Clubs, etc.

Participation by India in other conferences/meetings sponsored by Unesco

16.20.1 Indian experts represented the Department of Education, Ministry of Human Resource Development in the following Workshops, Training Courses and Seminars etc. sponsored by Unesco or its Regional Offices :—

- — Regional Workshop on Role of Micro-computers with Educational Management Information System which was held in Bangkok from 22nd June to 1st July, 1988.
- — Training Course for Promotion of Reading Habits and Book Development (21st Training Course on Book Production in Asia and Pacific) which was held in Tokyo from 13th to 31st October, 1988.
- — Regional Workshop on Equality of Educational Opportunity for the Disadvantaged Population Groups held in Beijing from 18th to 27th October, 1988.
- — First meeting for Regional Coordinators of Asia Pacific Programme of Education for All held in Bangkok from 14th to 18th November, 1988.

16.20.2 In addition to the above mentioned meetings, the Indian National Commission nominated experts to participate in about 34 national, regional, international meetings, workshops, seminars, conferences, etc. convened by or under the auspices of Unesco. During the year under review, the Commission also arranged the placements of a number of Unesco fellows and organised study visits to various institutions in India.

Visitors from Abroad

16.21.0 Dr. Yogesh Atal, Regional Adviser for Social and Human Sciences, Regional Unit for Social and Human Sciences in Asia and the Pacific visited New Delhi on May 26-27, 1988, and had meetings with the Education Secretary and with Prof. Iqbal Narain, Member Secretary, Indian Council of Social Science Research.

— Dr. Zharov, Director, Division of Scientific Research and Higher Education, Science Sector, Unesco, Paris visited New Delhi from September 17-22, 1988 to discuss matters concerning the International Institute for Science and Technology. Among others, Dr. Zharov had a meeting with Shri Baldev Mahajan, formerly, Secretary, Indian National Commission and discussed Major Programme II relating to science and technology to be included in the outline of Third Medium Term Plan of Unesco and other matters of mutual interest.

— Shri N. Kasi, Programme Specialist, Division of Studies and Dissemination of Culture visited New Delhi from July 28-31, 1988. During his stay, besides other appointments, he had a meeting with the then Secretary of the Indian National Commission.

— Shri T. Keller, Assistant Director-General for the General Programmes and Programme Support Sector visited New Delhi from August 16-17, 1988. He had a meeting with the Education Secretary on August 16, 1988 and discussed matters of mutual interest.

— Shri S.M. Saifuddin, Secretary, Bangladesh National Commission for Unesco visited New Delhi from August 30 to September 4, 1988. On September 1, 1988 he called on Shri S. Gopalan, Additional Secretary, Department of Education and also met the officers of the Indian National Commission.

— Prof. John Crocker Smyth, visited India from September 22-26, 1988 in connection with the evaluation of International Environmental Education Programme under Unesco-UNEP Programme—1984-1988. During his stay in India he had meetings with the high officials concerned with environmental education programme in the Ministry of Environment and Forests, Jawaharlal Nehru University, National Institute of Educational Planning and Administration, National Council of Educational Research and Training and Directorate of Adult Education, etc. and had discussions on various subjects including aspects of implementation of this programme in India.

— Mr. Federico Mayor, Director-General of Unesco and other senior officials from Unesco paid a visit to India from 13-16 December, 1988. It was Mr. Mayor's first visit to this country as Director-General. During his stay, he called upon the President of India, the Prime Minister and the Minister of Human Resource Development.

Contribution to Unesco's Budget

16.22.0 Contribution of each Member-State of Unesco to the budget of the organisation is determined in accordance with a scale fixed by the General Conference. India's share of the contribution has been fixed by the 24th Session of the General Conference of Unesco at 0.34 per cent of its overall budget. For the year 1988 India contributed Rs. 1,16,37,000/- in Indian rupees.

Executive Board of Unesco

16.23.0 The 129th and 130th Sessions of the Executive Board of Unesco were held in Paris during the year. Sardar Swaran Singh, India's member of the Executive Board, attended these meetings.

The World Heritage Committee

16.24.1 In pursuance of the provisions of the Convention concerning the protection of the World Cultural and Natural Heritage, adopted in 1972, Unesco has constituted the World Heritage Committee to identify those natural and cultural sites which merit inclusion in the World Heritage list and to administer World Heritage Fund. It comprises twenty-one Member-States. India was elected a member of this Committee at the 23rd Session of the General Conference of Unesco held in 1985.

16.24.2 Following thirteen Cultural monuments and four natural sites from India have so far been included in the World Heritage List.

MONUMENTS

1. Taj Mahal.
2. Ajanta Caves.
3. Ellora Caves.
4. Agra Fort.
5. Sun Temple at Konark.
6. Monuments of Mahaballipuram.
7. Churches and Convents of Goa.
8. Group of Monuments of Khajuraho.
9. Group of Monuments at Hampi.
10. Group of Monuments at Fatehpur Sikri.
11. Group of Monuments at Pattadkul.
12. Elephanta Caves.
13. Brihadisvara Temple, Thanjavur.

NATURAL SITES

1. Kaziranga National Park.
2. Keoladeo National Park.
3. Manas Wild Life Sanctuary.
4. Sunderbans National Park.

16.24.3 With a view to popularizing the Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, the Convention got it translated in Hindi and printed bilingually for dissemination.

World Decade for Cultural Development 1988-1997

16.25.1 The results of the first two International Development Decades since the end of the Second World War revealed limitations of a development concept based primarily on quantitative and material

growth. In order to emphasise the cultural dimension of development, the World Conference on Cultural Policies (1982) proposed a World Decade of Cultural Development. The proposal was approved by the United Nations General Assembly in 1986. The Decade begins in 1988 and will end in 1997.

16.25.2 The twin objectives of the Decade are; greater emphasis on the cultural dimensions in the development process, and the stimulation of the creative skills and cultural life in general. Unesco has sent to Member States a detailed Plan of Action for the observance of the Decade. India was elected to the Inter-Governmental Committee for the World Decade for Cultural Development at the 24th Session of the General Conference of Unesco held in 1987. The Committee comprises 36 members.

16.25.3 A working group has been formed in the Department of Culture to make necessary arrangements and programmes for the celebration of the Decade.

Auroville

16.26.1 With a view to making long-term arrangements for proper management and further development of Auroville, both Houses of Parliament passed the Auroville Foundation Bill (Act 54 of 1988) in September, 1988. The Act provides for acquisition and transfer of the undertaking of Auroville and to vest these undertakings in a Foundation established for the purpose. The proposed Foundation shall consist of (a) the Governing Board, (b) the Residents Assembly, and (c) the Auroville International Advisory Council.

16.26.2 The Act also provides for financial assistance by the Central Government for the Development etc. of Auroville.

16.26.3 A scheme for all round development of Auroville has been included in the Seventh Five Year Plan with a total outlay of Rs. 35.55 lakhs. The scheme reflects three important concerns: (i) need for continuing education commencing from earliest stages of childhood; (ii) need for synthesis of knowledge and culture; and (iii) need to provide a stable base for all round development of Auroville and surrounding villages. For the year 1988-89 a budgetary provision of Rs. 10 lakhs has been made under the scheme.

Highlights Since 1985-86

17.1.1 The most significant achievement over the last four years - and indeed a landmark in the history of Education in India — has been the adoption by the Parliament of the National Policy on Education (NPE), in May, 1986, after a nation-wide debate. This was followed up by the formulation of a comprehensive Programme of Action (POA), based on examination of every aspect of the Policy by 23 Task Forces. The Programme of Action was adopted by the Parliament in August, 1986.

17.1.2 The National Policy on Education, 1986 was different from, and an improvement on, the earlier Policy of 1968 in the following respects :

- Adoption of a comprehensive Programme of Action as mentioned above.
- Stipulation of specific targets like for Universalisation of Elementary Education, Adult Education, Vocationalisation, etc.
- Prescription of Non-formal Education as a system.
- Overt call for employment orientation of Education, as distinct from employability of students adverted to by the earlier Policy.
- Presentation of Education in the perspective of Human Resource Development.
- Prescription of concrete steps in respect of education for women's equality.
- Offer of special programmes for SCs/STs, minorities, handicapped and educationally backward classes.
- Offer of a programme for Management of Education.
- Delineation of programmes for the rural population.
- Stipulation of a National System of education based on national curricular framework.
- Call for delinking of jobs from degrees.

17.2.0 Consistent with the Programme of Action, several new Plan Schemes have been brought under implementation by the Government. Particulars of major Schemes are furnished :

	Name of Scheme	Objectives	Over all Scheme Outlay Rs. crores	Physical Targets	Features	Rates of Assist-ance	Remarks
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Operation Blackboard	To facilitate universalisation of Elementary Education; and for this purpose, to provide building infrastructure to primary schools at minimum level; to provide additional school teachers, preferably women teachers; and to provide teaching-learning materials.	742.25	Coverage of 20% of the Blocks in 87-88, 30% in 88-89 and 50% in 89-90	As in col. 2	100% assistance to States for posts of teachers and teaching learning materials, funds for school buildings having to be provided under NREP/ RLEGP.	
2.	Restructuring and reorganization of Teacher Education						
(i)	Mass Orientation of school teachers.	To improve professional competence of teachers	38.40	Orientation of 5 lakh teachers annually.	— Orientation of Resource persons — In service training of teachers.	Cost of training of resource persons and training of teachers met by the Centre.	
(ii)	District Institutes of Education and Training (DIETs)	— do —	288.59	400 DIETs to be established.	— Pre-service & inservice education of teachers — Resource support for District Educational System & Non-formal and adult Education	Rs. 78 Lakhs per DIET	

1		2	3	4	5	6	7
(iii)	Strengthening Secondary Teacher Training Institutes.	— do —	132.19	250 Institutes to be strengthened.	— Inservice education of teachers, apart from running degree & P. G. Courses. — Networking with other Educational Resource agencies.	Rs. 72 Lakh per Centre	
(iv)	Strengthening State Councils of Educational Research & Training.	— do —	2.00		— Improvement of infrastructure & resources of SCERTs.		
3.	Non-Formal Education.	To take education to the doorsteps of children who are unable to be in the formal school system.	230.45	to continue coverage of educationally backward States and, in addition, cover urban slums, hilly, desert and tribal areas in the States	— Flexible programmes of education — Project approach — Better supervision	Assistance to States and Voluntary agencies @ 50% -For general centres. 90% -For girls' centres. 100% For Projects of voluntary agencies. 100% For innovavative projects.	
4.	Environmental Orientation to School Education	As in Col. 1	37.50	100 Projects by 1990	— Creation of general awareness among school children about environment — Raising of social forestry nurseries and plantation of saplings.	100% assistance to States and Non-Governmental Agencies	

1	2	3	4	5	6	7
5. Science Education in schools.	Improvement of science education in schools	161.18	Coverage of 1.12 lakh schools	—	Upgradation of science laboratories in upper primary, secondary and higher secondary Schools	Rs. 7500 per school for science equipment. Rs. 15,000/ 40,000 per school for science books.
				—	Library assistance	Rs. 1 lakh for each Resource Centre.
				—	Setting up District Science Resource Centres.	100% assistance to voluntary agencies.
				—	Assistance to voluntary organizations for innovative projects.	
6. Vocationalisation of Education	Making post secondary education relevant to the world of work.	409.82	11% diversion of students at higher secondary stage to vocational system by 1990.	—	District vocational surveys.	Assistance ranging from 25% to 100%.
				—	Vocational equipment and buildings for schools.	
			Introduction of vocational courses in about 5000 schools	—	Curriculum & Resource materials production.	
				—	Teacher Training	
7. Educational Technology.	Improvement of access to education and quality of education.	115.90	Supply of 1 lakh colour TV sets and 5 lakh Radio-cum-cassette players to to primary and upper primary schools	—	Infrastructure for Educational Technology Studios.	100% assistance for State Institutes of Education Technology (SIETs) 100% assistance for Radio-cum-Cassette Players. 75% assistance for colour TVs.
				—	Educational TV Production.	

1		2	3	4	5	6	7
					— Setting up Foundation for Educational TV Production		
8.	Navodaya Vidyalayas.	To provide good quality education for talented rural children.	500.00	One Navodaya School per district.	— Residential — Free boarding lodging and education — Admission by Objective tests conducted all over India by NCERT — Administration through the autonomous Navodaya Vidyalaya Samiti.	Fully funded by the Centre.	
9.	Indira Gandhi National Open University.	To provide access to Higher Education to large segments of population, specially to the disadvantaged and those in backward regions. To provide Continuing Education to upgrade knowledge and skills.	46.00 (envisaged in Project document)		— Certificate and diploma courses, particularly in special subjects like Rural Development Food & Nutrition, Computer Education, Tribal Education, etc. — Multi-media packages, for instructional system	Fully funded by Govt. of India	

1	2	3	4	5	6	7
				— Regional Centres — Campus development in 100 acres in South Delhi.		
10. Consolidation and expansion of Institutions under the University System.	Programmes taken up as part of UGC activities.					
11. Autonomous colleges.						
12. Strengthening of Research						
13. Revision of pay scales of University and College Teachers and training of these teachers	To raise status of teachers; and to attract and retain talent in the Higher Education System.					
14. Thrust Areas of Technical Education	— Creation of infrastructure in areas of emerging technologies. — Expansion of facilities in crucial areas where weakness exists. — Programmes for new/improved technologies.	115.00	Based on projects received from eligible institutions	Provision of — equipment — laboratory space — Books & journals — Technical staff for projects.	100% funding by Govt. of India for all AICTE approved institutions.	

1		2		3	4	5	6	7
15.	Modernisation and removal of obsolescence.	—	To create infrastructure to meet the new technological developments.	196.00	— do —		Provision of equipment and books	— do —
16.	Research and Development	—	To create infrastructure for Research in Tech. Instts. and support research projects	4.5	— do —	—	Provision of equipment — laboratory space — Books & Journals — Technical Staff for projects.	— do —
17.	National Literacy Mission		To impart functional literacy to adult illiterates in the age group of 15-35.	340.00	Coverage of 30 million adult illiterates by 1990.	—	Establishment of National Literacy Mission Authority	Full funding to National Literacy Mission authority and Technology demonstration
						—	Technology demonstration in 40 districts.	Rs. 14000/- per Jan Sikshan Nilayam.
						—	Institutionalisation of post-literacy through Jan Sikshan Nilayams.	Rs. 15.53 lakhs per RFLP of 300 Centres.
						—	Continuance of old activities, RFLP, SVPs, strengthening of administrative structures etc.	

Note : The overall scheme outlays are those approved for the respective schemes as a whole, generally for the VII Plan period and are subject to provision of funds in annual budgets.

17.3.1 Presented in the following Table are details of Plan and Non-Plan Expenditure in the Central Sector of Education since 1985-86.

Rupees in Crores

85-86			86-87			87-88		
Plan	Non-Plan	Total	Plan	Non-Plan	Total	Plan	Non-Plan	Total
27.12	0.68	27.80	32.60	0.54	33.14	195.98	0.02	196.00
14.92	68.98	83.90	37.83	94.59	132.42	164.62	99.75	263.77
—	—	—	—	—	—	—	—	—
82.58	123.31	205.89	108.28	144.85	253.13	149.87	185.79	335.66
42.34	0.74	43.08	43.64	2.01	45.65	71.70	2.25	73.95
76.03	73.42	149.45	68.50	83.53	152.03	163.48	96.05	259.53
9.25	20.80	30.05	12.24	21.79	34.03	26.47	49.27	76.34
252.24	287.93	540.17	303.09	347.31	650.40	772.12	433.13	1205.25

17.3.2 It may be seen from the above figures that actual investment in Education in the Central Sector has significantly increased since 1985-86. Plan expenditure increased by 206% and overall expenditure by 123%.

17.3.3. Some important physical achievements since 1985-86 are presented below:

	Position in 1985-86	Position in 1988-89
Elementary Education		
Primary School buildings funded by the Centre-nembers		1,00,000 (cumulative) expected to be constructed in terms of Operation Blackboard Sanctions.
Posts of primary school teachers funded by the Centre-numbers		75,000 (cumulative) (Approximate)—posts to be created in terms of Operation Blackboard Sanctions.
Non-Formal Education Centres—Nos. lakhs	1.75	3.75
Enrolment in Non-Formal Education Centres—No. of persons lakhs	32.53	88.95
Mass Orientation of School Teachers-numbers oriented		14 lakh (cumulative)

Teacher Training Institutions funded-numbers (DIETs, CTEs etc.)		240 (cumulative)
Coverage under the Scheme of Integrated Education for the Disabled		15 States and 3 UTs
White printing paper supplied to States on Central Subsidy-tonnes		80,000 tonnes allotted per annum since 1987-88
Secondary Education		
Navodaya Schools for talented rural children-numbers	2	256
Enrolment of students in Open Schools-numbers	8,000	22,000
Education Technology-equipment funded		21,000 colour TV sets 85,000 Radio-cum-Cassette players distributed in schools (cumulative) (Approximate).
Transmission of Educational TV		All Hindi speaking States and A.P., Gujarat, Maharashtra and Orissa-for 45 minutes, 5 days in a week
Computer Education in Schools-number of Schools covered	250	1250
Vocational Education on the revised pattern—		
• Schools covered-numbers		2000 cumulative
• Courses sanctioned-numbers		6000 approximate
Higher Education		
Colleges/Universities listed for restructuring of Under-graduate courses-numbers	3540/100	3800/117

Curriculum development Centres-numbers		24 (cumulative)
Universities covered under Quality improvement programme-numbers	100	117
Research Projects supported for Quality improvement-numbers	1595	4000
Enrolment for distance education (Indira Gandhi National Open University-numbers		54000 (Jan., 89)
Technical Education Out-turn of Indian Institutes of Technology-total since 1985-86, projection for 1988-89 included, under-graduates-and post-graduates number		13,315 (inclusive of Under-graduates having gone for Post-graduation)
Training capacity of Regional Engineering Colleges-numbers		
Under graduates	4026	4720
Post graduates	571	1050
Numbers benefited under Apprenticeship Training Programme	12,831	17,352
Training capacity provided under Quality Improvement Programme (Technical Education)	240	350
Community Polytechnics-Numbers	46	108

Manpower trained under Community Polytechnics-numbers			44827 (86-87 to September 88)
Projects supported under "Thrust Area" Schemes (including "Modernisation Projects-numbers			1960 (85-86 to 88-89)
Adult Education			
Adult Education Centres-numbers in lakhs	1.36		2.71
Enrolment in Adult Education Centres-number of adults in lakhs	6.00		81.47
Post literacy Centres (Jan Sikshan Nilayams)-numbers			14365
Scholarships			
National Scholarship Scheme-numbers	27,000		40,000
National Loan Scholarship Scheme-numbers		20,000 per annum	
Scheme of Scholarship for talented rural children-numbers	33,000		38,000
Language development			
Posts of Hindi teachers in Non-Hindi States funded by the Centre-numbers	500		2500
Enrolment for correspondence course in Hindi (under Central Hindi Directorate) numbers	15,800		17,000

Enrolment of teacher-trainees for Modern Indian Language teaching-numbers		339
Voluntary organizations assisted for propagating Sanskrit-numbers	700	700
Enrolment for correspondence course in elementary Sanskrit-numbers	900	1000

Overall expansion of Education

(i) In terms of Institutions

	No. of Schools in Sept. '84	No. of Schools in Sept. '87
Intermediate/Junior Colleges	[illegible]	[illegible]
Hr. Sec. (10+2New pattern)	7,059	[illegible]
Hr. Sec. (Old pattern)	3,959	[illegible]
High/Post Basic	47,816	[illegible]
Middle/Senior Basic	1,29,879	[illegible]
Primary/Junior Basic	5,19,791	[illegible]
Pre-primary/Pre-basic.	[illegible]	[illegible]
	7,22,748 (7.2 lakhs)	7,70,761 (7.7 lakhs)

(ii) In terms of enrolment

	No. of students in Sept. '84 as	No. of students in Sept. '87
Intermediate/Jr. Colleges	18,44,515	19,56,639

Hr. Sec. (10+2 New pattern)	17,81,546	29,13,238
Hr. Sec. (Old pattern)	14,83,739	81,367
High/Post Basic	1,05,54,754	1,24,52,283
Middle/Senior Basic	2,62,53,145	2,99,14,499
Primary/Jr. Basic	8,39,32,704	9,29,43,556
Pre-Premiary/Pre-basic	10,33,315	14,20,705
	12,68,88,718 (12.6 crores)	14,16,82,287 (14.2 crores)

17.4.0 Presented in the following paragraphs are some of the major areas of concentration which [illegible] the new directions that have been given to [illegible] by the Government in the light of the National Policy on Education 1986 and the Programme of Action.

Content of Education

17.4.1 Content of education has come under reorientation. A National Core Curriculum has been spelt out giving considerable importance for values—national identity, secularism, protection of environment, equality of sexes, scientific temper etc. The [illegible] curriculum, syllabi and text books in a time bound manner over a three year time frame. State Governments have been advised to take similar steps. School text-books are under evaluation from the point of view of national integration. Materials which may influence untouchability, racialism, casteism, communalism etc. are to be eliminated by this process of evaluation. Evaluation of history and langauge books has been completed in almost all the States. In the next phase, books on Geography, Political Science etc. would be covered History of India's freedom movement has been identified too as a core area to be taught in schools.

17.4.2 The UGC scheme for restructuring Courses provides for Foundation Courses so as to cover Cultural History of India, History of Freedom Movement in India and national integration.

17.4.3 Family Welfare programme has also been integrated with Education. The Population Education Project, in its second cycle has been brought under implementation in 26 States/UTs. Population Education has been incorporated into the syllabi and textbooks of selected school subjects. NCERT has identified minimum essential core ideas in this regard for incorporation in the core curriculum and has developed exemplar material. The UGC has introduced the scheme of population education clubs. Population Education has also been included as part of Foundation and Applied Courses under the scheme of restructuring courses at under-graduate level under the UGC-UNFPA Project. Task forces have been set up to train population education functionaries, develop curriculum, produce learning materials etc. Small family norm is also propagated through Adult literacy messages.

Promotion of Mathematics and Science Education

17.5.1 As already brought out in para 17.2.0, a major

scheme for Science Education in schools has been brought under implementation, assistance being provided for upgradation of school laboratories, libraries etc. The NCERT is offering special training to teachers in its Regional Colleges by organising Summer Institutes.

17.5.2 UGC has constituted a panel of distinguished mathematicians of the country to recommend measures for improvement of teaching and research in mathematics. This panel is preparing a project document for establishment of "National Institute in Application of Mathematics" (NIAM) for promoting cooperative research and training programmes.

17.5.3 COSIP (College Science Improvement Programme) has come to be implemented in over 300 higher educational institutions for improvement of science teaching.

Modernisation of courses at Secondary and Post-Secondary level

17.6.1 The new scheme of vocationalisation has brought about a significant reorientation of Post-Secondary education in terms of its relevance to the world of work. A meaningful management structure is being built up from the level of the institutions at the grass-roots upto the national level. The vocational content of the courses has been redesigned to facilitate achievement of terminal competencies on the part of the school graduates for the purpose of engagement in local level employments.

17.6.2 At Higher Education level diversified certificate, diploma and degree courses have been introduced through IGNOU-relating them to employment opportunities and needs of the economy. The Curriculum Development Centres set up by the University Grants Commission are playing a significant role in this respect.

17.6.3 In the Technical Education sector, a scheme of industry-Institution interaction has been brought under implementation. Industries are given representation in the Governing bodies of Technical Education institutions. The institutions, on their side, are taking up consultancy programmes for industries. Practising technocrats in industries serve the institutions as part-time faculty members. Industry oriented Post-graduate programmes have been introduced. New areas of technology have been identified for offering new courses/programmes. Engineering and technological institutions are having their infrastructure upgraded so as to expand facilities in crucial areas of technologies like Computer Science, Electronics etc. Modernisation and removal of obsolescence in Engineering and Technological institutions has been given high priority.

Use of Information and Communication Technology

17.7.1 The Centrally sponsored scheme for Education Technology under the INSAT utilisation programme was revised in 1987-88. The Central Institute of Education Technology and the State Institutes of Education Technology are being strengthened. Education TV production programmes of the INSAT States (Andhra Pradesh, Bihar, Gujarat, Maharshtra, Uttar Pradesh and Orissa) are being assisted by the Centre. Colour TVs and Radio-cum-Cassette Players are distributed extensively for school uses.

17.7.2 The UGC utilises INSAT—I.B. facilities for two hours of Television programme on Higher Education—"Country-wide Class Room". The UGC has set up four Educational Media Research Centres (EMRCs) and seven Audio-visual Research Centres (AVRCs) in Universities and Colleges for training and production of TV software. It is estimated that the requirement of UGC, IGNOU and NCERT by 1991-92—at the present pace—may call for a separate educational TV channel.

Location of Technical institutions in rural areas

17.8.1 Polytechnics and ITIs have been sanctioned to be set up in the border areas of Punjab, Rajasthan, Gujarat and J&K under the Border Area Development Programme.

17.8.2 The scheme of the Community Polytechnics

has been reoriented so as to facilitate implementation, by them, of manpower development programmes for villagers to enable them to acquire employable skills. They are also rendering technical and community support services in rural areas, apart from disseminating information on appropriate technologies.

Quality and excellence at all levels

17.9.0 The programmes for universalisation of elementary education, vocationalisation of secondary education etc. have been designed such that achievements are envisaged not merely in quantitative terms but also in qualitative terms. Professionalisation of teaching, attainment of competencies on the part of the children etc. are being given paramount importance. Admissions to the Navodaya Vidyalayas are provided only to talented rural children, irrespective of their economic status, admissions being allowed on the basis of success in objective tests. The University Grants Commission provides special assistance for promotion of quality and excellence in colleges through various programmes like College Science Improvement Programme (COSIP), Humanities and Social Sciences Improvement Programme (COHSSIP) etc. The All India Council for Technical Education has been clothed with legal powers with the enactment of the AICTE Act.

Access to Education

17.10.1 In order to cater to the needs of the disadvantaged, special programmes are being implemented—for SCs, STs, for women, for the working class and minorities.

17.10.2 Benefits extended to the SCs. and STs. are in terms of reservation of seats for admissions in educational institutions, relaxation in qualifying standards for admissions, scholarships at various levels—Pre-Matric to research levels—exemption from fees for examinations, reservation of hostel accommodation, remedial coaching etc.

17.10.3 In order that enrolment of girls in formal school system at the elementary level is promoted, preference is being given for recruitment of women teachers against posts created under the scheme of Operation Blackboard. Exclusive Girls' Centres for Non-Formal Education are given higher levels of assistance. Increased access for women to vocational, technical and professional education is being promoted.

17.10.4 The scheme of Shramik Vidyapeeths under the Adult Education programme has been reviewed. These Vidyapeeths have been brought to pay greater attention to rural workers, women workers and workers' productivity. As per Prime Minister's 15-Point programme, steps have been taken to help minorities succeed in competitive examinations and acquire technical skills. Ten Polytechnics have come to impart craft training in 38 different Centres of minority concentration. Special training is given in English, Science and Mathematics teaching to the teachers in minority concentration areas. Research Centres, for this purpose, are operating in Jamia Milia Islamia, Aligarh Muslim University, Osmania University, Jammu University and Marathwada University.

17.10.5 Under the Three Language formula, for Language education, facilities have been provided for learning Urdu in 15 States.

17.10.6 Thirty-five Caligraphy Training Centres are being funded by the Centre through the Bureau for Promotion of Urdu for imparting skills in respect of basic as well as decorative calligraphy.

17.10.7 All the above efforts, will be pursued and perfected over the years to come, within the broad framework of NPE parameters.

FINANCIAL ALLOCATIONS

(IN LAKHS OF RUPEES)

Sl. No.	Items	Plan/ Non-Plan	Budget Estimates 1988-89 Original	Revised	Budget Estimates 1989-90
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	School Education				
1.	Operation Blackboard	Plan	13,000.00	13,000.00	13,000.00
2.	Non-formal Education Centres (Composite) for 9-14 age group	Plan	2,940.00	1,790.00	2,340.00
3.	Non-formal Education Centres for girls	Plan	1,565.00	1,052.00	1,765.00
4.	Grants to Voluntary Agencies	Plan	400.00	750.00	700.00
		Non Plan	15.00	15.00	15.00
5.	Shiksha Karmi Project in Rajasthan undertaken with financial assistance from S.I.D.A.	Plan	135.00	110.00	235.00
6.	Education for Women's Equality Project with assistance from Netherlands	Plan	300.00	300.00	400.00
7.	Mass Orientation Programme for school teachers	Plan	1,543.00	1,080.00	570.0C
8.	Others:— (i) District Institutes of Education and Training (DIET) (ii) College of Teacher Education and Institute of Advanced Study in Education (IASE) (iii) State Councils of Educational Research & Training (SCERTs)	Plan	3,447.00	3,910.00	4,430.00
9.	Navodaya Vidyalaya	Plan	6,930.00	7,930.00	7,930.00
	Union Territories				
1.	Bal Bhavan	Plan	50.00	50.00	50.00
		Non-Plan	50.00	57.00	60.00
2.	Open School	Plan	70.00	72.00	80.00
3.	Kendriya Vidyalaya Sangathan	Non-Plan	11724.60	11663.00	14043.00
4.	Central Tibetan Schools Administration	Non-Plan	275.70	325.00	321.30
5.	Promotion of Yoga	Plan	50.00	50.00	79.00
		Non-Plan	16.00	20.00	20.00

1	2	3	4	5	6
Higher Education & Research					
1.	University Grants Commission	Plan	12900.00	12900.00	12800.00
		N. Plan	17700.00	19187.00	20224.00
2.	Indian Institute ot Advanced Study, Simla	Plan	40.00	40.00	40.00
		N. Plan	45.00	54.00	57.00
3.	Indian Council of Philosophical Research	Plan	65.00	74.00	65.00
		N. Plan	—	—	—
4.	Indian Council of Historical Research	Plan	40.00	40.00	40.00
		N. Plan	74.70	74.70	78.25
5.	All India Institute of Higher Learning	Plan	30.00	30.00	20.00
		N. Plan	15.00	15.50	16.00
6.	Indian Council of Social Science Research	Plan	240.00	330.00	250.00
		N. Plan	302.00	322.00	338.00
7.	Shastri Indo Canadian Institute	N. Plan	38.00	38.00	60.00
8.	Revision of salary scales of teachers in University & Colleges	N. Plan	27200.00	20607.00	12709.00
9.	National Research Professors	N. Plan	2.20	2.20	3.00
10.	Loan to Punjab University	Plan	50.00	50.00	50.00
11.	Dr. Zakir Hussain Memorial College Trust	Plan	20.00	20.00	20.00
		N. Plan	6.00	6.00	6.00
12.	Association of Indian Universities	Plan	8.00	8.00	8.00
		N. Plan	11.00	11.00	17.00
13.	Jamia Millia Islamia	Plan	50.00	50.00	—
		N. Plan	75.50	76.10	—
14.	Indira Gandhi National Open University	Plan	1000.00	1000.00	1100.00
15.	Establishment of Rural Institutes	Plan	200.00	50.00	100.00
16.	Strengthening of Administrative Machinery	Plan	5.00	5.00	5.00
17.	National Council of Higher Education	Plan	25.00	10.00	10.00
18.	Delinking of degrees from jobs/Establishment of National Testing Service	Plan	100.00	100.00	40.00
International Cooperation					
1.	Reorganisation of INC Library into a full fledged Documentation and Reference Centre for Unesco Publications in India	Plan	2.00	1.00	2.00
2.	Holding of meeting of Committee/Conference and organisation of exhibitions in furtherence of Unesco's aims and objectives.	Plan	6.00	3.00	6.00

2	3	4	5	6
3. Strengthening of Voluntary Organisations engaged in Unesco's Programme and activities.	Plan	2.00	2.00	2.00
4. Auroville Management and Development of Auroville.	Plan	10.00	10.00	10.00
5. Expenditure of Indian National Commission for Publication of Hindi and Tamil Editions of Unesco Courier.	N. Plan	12.00	18.50	15.00
6. Other items-Indian National Commission for Cooperation with Unesco.	N. Plan	0.60	0.20	0.60
7. Other Items-Grants to Non-Governmental Organisations for the Programme of Indian National Commission for Unesco.	N. Plan	0.25	0.25	0.25
8. Other Items-Other Programmes-Hospitality and Entertainment Schemes connected with Unesco.	N. Plan	0.05	0.05	0.05
9. Contribution to Unesco.	N. Plan	103.00	103.00	126.00
0. Deputation and Delegations abroad.	N. Plan	7.00	5.00	8.00
1. Visit of Foreign Delegations to India.	N. Plan	5.00	3.00	5.00
2. Auroville Management.	N. Plan	5.00	5.00	6.00
ther Activities				
1. Publications	N. Plan	10.50	12.00	15.00
2. Educational & Cultural Themes Pavilion at Pragati Maidan	N. Plan	8.00	4.00	—
3. National Institute of Educational Planning and Administration	Plan	50.00	50.00	60.00
	N. Plan	82.00	82.00	85.00
4. Installation of Mini-Computer Terminal at Shastri Bhavan (Sectt.)	Plan	4.00	4.00	4.00
5. Strengthening of Planning, Monitoring & Statistical Machinery in the Ministry (Sectt.)	Plan	12.00	12.00	16.00
6. Aid Materials & Equipments Gift Paper (Notional Value)	Non Plan	366.00	836.00	660.00
7. Gift Paper from Norway (Incidental Expenses)	Non Plan	100.00	100.00	100.00
8. Subsidy for supply of white printing paper to Educational sector for the year 1988-89	Non Plan	2400.00	2400.00	2400.00

1	2	3	4	5	
9.	Computerisation of Educational Statistics at State Level	Plan	10.00	10.00	10.0
10.	Establishment of Central Cells for Data Collection in States for introduction of Management Information System	Plan	100.00	—	
Book Promotion and Copyright					
1. National Book Trust					
1.	Maintenance & Establishment	Non-Plan	102.90	100.80	153.0
2.	Normal Promotional Activities	Plan	30.00	10.50	27.0
3.	- do -	Non Plan	27.00	20.00	37.0
4.	Regional Offices & Book Centres	Plan	18.00	* 32.60	18.0
5.	Aadan Pradan	Plan	7.00	5.30	7.0
6.	Nehru Bhavan	Plan	20.00	8.00	20.0
7.	Nehru Bal Pustakalaya	Plan	25.00	* 56.20	31.5
8.	Subsidy Scheme	Plan	35.00	16.60	35.0
9.	Grants for Book Promotional Activities and Financial Assistance to Voluntary Organisations	Plan	6.00	5.00	6.0
10.	Grants to NBDC	Plan	2.00	1.00	2.0
11.	Reproduction of books in Punjabi	Plan	7.00	2.30	6.0
12.	Consultancy Services	Plan	—	1.00	1.0
13.	Material for Blind Students	Plan	1.00	1.00	1.0
14.	Publications for Post-Literacy Education	Plan	5.00	15.00	10.0
15.	Publications for School Library Programme	Plan	5.00	5.00	5.0
16.	Publication of Classic Literature	Plan	5.00	5.00	5.0
17.	New Sale Promotion Measures including Book Kiosks	Plan	10.00	10.00	5.0
18.	Reprint of titles damanged in floods	Non-Plan	—	* 45.00	-
19.	I.S.B.N. (NERC)	Plan	2.00	2.00	2.0
20.	Scheme for Publication of University Level Foreign Books	Plan	1.50	1.00	1.5
21.	Setting up of National Author's Society	Plan	1.00	0.50	1.0
22.	India's Contribution to WIPO	Non-Plan	12.00	13.70	15.0
23.	International Copyright Union CEP	Non-Plan	1.00	0.50	1.0
24.	World Book Fair	Non-Plan	1.00	—	40.0
25.	Book Export Promotional Activities	Plan	7.00	7.00	7.0
26.	Festival of USSR in India	Plan	3.50	1.00	-

* Demand for Supplementary grants is to be processed.

1	2	3	4	5	6
Scholarships					
1.	National Scholarships Scheme.		110.00	109.00	110.00
2.	National Loan Scholarships Scheme.		300.00	300.00	300.00
3.	National Loan Scholarships Scheme-Write off etc.		10.00	10.00	15.00
4.	50% shares of the State Govts. in respect of recoveries under National Loan Scholarship Schemes		22.00	22.00	22.00
5.	Scheme for Upgradation of merit of SC/ST students.		50.00	50.00	50.00
6.	Scholarships at Secondary stage for talented children from rural areas.		85.00	85.00	85.00
7.	Research scholarships of products of Traditional Institutions in the study of classical languages other than Sanskrit like Arabic, Persian.		1.25	1.25	1.25
8.	Scholarships for Study Abroad*		95.00	135.00	140.00
9.	Scholarships in approved residential secondary schools.		150.00	150.00	165.00
10.	Grant-in-aid scheme of scholarships to students from non-Hindi speaking States for Post-Matric studies in Hindi.		29.10	26.10	34.10
11.	General Cultural Scholarships Scheme.		65.00	65.00	65.00
12.	Scholarships for nationals of Bangladesh—funds with Ministry of External Affairs		Budget provision for these schemes is made by Ministry of External Affairs.		
13.	Scholarships for the nationals of Sri Lanka, Angola, Mauritius and Maldives				
14.	Indian scholars going abroad against scholarships offered by foreign governments/organisations	Non Plan	10.00	10.00	10.00 (Rupees two lakhs in foreign exchange
15.	Scholarships to foreign students for studies in India.	Non Plan	50.00	60.25	70.20
Promotion of Languages					
1.	Grants to Voluntary Organisations working in the field of Hindi.	Plan	100.00	100.00	110.00
		Non-Plan	30.00	30.00	35.00
2.	Dakshin Bharat Hindi Prachar Sabha, Madras	Plan	30.00	30.00	40.00
		Non-Plan	30.00	30.00	35.00
3.	Propagation of Hindi Abroad	Plan	20.00	20.00	20.00
		Non-Plan	8.80	7.50	8.70
4.	Central Hindi Directorate	Plan	46.00	32.00	42.50
		Non-Plan	78.00	82.50	85.50

* This provision includes in the provision of Rs. 12.0 Lakhs made by Sanskrit for the same purposes.

1	2	3	4	5	6
	(i) Correspondence Courses/Preparation of Cassettes.	Plan Non-Plan	10.00 14.00	10.00 14.00	10.00 15.00
	(ii) Library	Non-Plan	0.60	0.50	0.60
5.	Grants to Hindi Shikshan Mandal, Agra,	Plan Non-Plan	70.00 115.00	47.10 147.00	50.00 158.50
6.	Commission for Scientific and Technical Terminology (including workshop)	Plan Non-Plan	15.00 39.60	15.00 41.50	15.00 45.00
7.	Appointment of Hindi Teachers in Non-Hindi speaking States/UTs (CSS scheme)	Plan	214.40	214.00	200.00
8.	Establishment of Hindi Teachers Training Colleges in Non-Hindi speaking States/UTs	Plan	55.00	55.00	40.00
9.	International University for Hindi.	Plan	35.00	35.00	05.00
10.	Production of Books in Sindhi.	Plan	5.00	5.00	4.00
11.	Taraqqi-e-Urdu Board Bureau for Promotion of Urdu.	Plan Non-Plan	47.60 34.00	45.95 34.25	47.00 37.50
12.	Central Institute of Indian Languages, Mysore.	Plan Non-Plan	70.00 69.20	64.10 69.20	50.00 73.50
13.	Regional Language Centres	Plan Non-Plan	40.00 90.50	34.90 90.55	40.00 108.70
14.	Production of University level Books in Indian Languages:				
	(i) Grants to State Governments.	Plan Non-Plan	18.00 10.00	18.00 10.00	15.00 10.00
	(ii) Grants to University	Plan	2.00	20.00	2.00
15.	Grants to NBT for Production of Core Books on Medicine	Plan Non-Plan	5.00 0.10	1.35 —	4.00 —
16.	Assistance to Voluntary Organisations for Publications:				
	(i) English	Plan	4.00	5.00	4.00
	(ii) Modern Indian Lang.	Plan	20.00	18.00	20.00
	(iii) Hindi	Plan	20.00	20.00	20.00
17.	Assistance to Voluntary Organisation for Activities other than Pub.				
	(i) Modern Indian Lang.	Plan	3.00	1.50	2.00
18.	Financial Assistance to English Languages Teaching Institute & District Centre for English	Plan	50.00	30.00	35.00
19.	Financial Assistance to Regional Instt. of English-English Language Teaching and Institutes.	Plan	40.00	40.00	35.00
20.	Establishment of Sindhi Vikas Board.	Plan	17.00	Nil	10.00
21.	M.I.L. Appointment of Teachers.	Plan	20.00	Nil	20.00
Sanskrit					
1.	Grants to Rashtriya Sanskrit Sansthan.	Plan	80.00	62.50	80.00
2.	Utilisation of eminent elderly scholars in Adarsh Skt. Pathshalas & other voluntary Snakrit Organisations.	Plan	12.00	10.50	12.00
3.	Grants to Adarsh Skt. Pathshalas/Shodh Sansthans.	Plan	5.00	5.00	5.00
4.	Grants to voluntary organisation working for the Propagation and development of classical languages i.e. Arabic/Persian.	Plan	12.00	12.00	12.00

1	2	3	4	5	6
5.	Production of Sanskrit Literature.	Plan	8.00	8.00	8.00
6.	Purchase and publication of rare manuscripts.	Plan	3.00	3.00	3.00
7.	Purchase of Sanskrit Books.	Plan	12.00	12.00	12.00
8.	Special Orientation Courses in Post-Graduate studies in vocational disciplines like Pateography, Epigraphy and Iconography.	Plan	3.00	3.00	3.00
9.	a) All India Elocution Contests & Vedic convention. b) Preservation of oral traditions of vedic recitation. c) Establishment of vedic endowment (holding of vedic convention)	Plan	49.00	54.00	49.00
10.	Development of Sanskrit Education	Plan	58.00	58.00	57.00
11.	Grants of Voluntary Skt. Organisations	Plan	50.00	50.00	50.00
12.	Cultural Exchange Programme.	Plan	1.00	1.00	1.00
13.	International Institute of Indology and Classical Languages.	Plan	35.00	35.00	30.00
14.	Award of Certificate of Honour.	Non-Plan	15.00	21.00	22.50
15.	Deccan College, Poona.	Non-Plan	10.00	10.00	15.00
16.	Award of Scholarships	Non-Plan	9.50	9.50	9.50
17.	Grants to Adarsh Skt Pathshalas/ Shodh Samsthans.	Non-Plan	50.00	50.00	60.00
18.	Grants to Rashtriya Skt. Sansthan.	Non-Plan	203.65	212.50	235.00
Technical Education					
1.	Community Polytechnics	Plan	100.00	100.00	150.00
		Non-plan	35.00	35.00	35.00
2.	Technical Teachers' Training Institutes	Plan	400.00	388.00	400.00
		Non-plan	273.30	320.00	337.00
3.	Advanced Technician Courses	Plan	25.00	25.00	15.00
		Non-plan	8.00	8.00	10.00
4.	National Technical Manpower Information System.	Plan	25.00	25.00	25.00
		Non-plan	20.00	20.00	20.00
5.	Special Institutes for Appropriate Technology for Rural Development and Experimental Pilot Projects for Integrated Rural Development.	Plan	40.00	40.00	20.00
6.	University Grants Commission Schemes (Tech.)	Plan	1200.00	1200.00	1200.00
7.	Indian Institutes of Technology	Plan	2000.00	2000.00	2000.00
		Non-plan	6685.60	7554.00	7726.00
8.	Management Education	Plan	50.00	50.00	20.00
		Non-plan	10.00	10.00	10.00
9.	Regional Engineering Colleges	Plan	1000.00	1000.00	1150.00
		Non-plan	1508.40	1579.00	1770.00
10.	Development of P.G. Courses & Research Work	Plan	50.00	55.50	150.00
		Non-plan	175.00	675.00	245.00
11.	N I F F T, Ranchi	Plan	100.00	100.00	100.00
		Non-plan	80.00	75.20	86.70

1	2	3	4	5	6
12.	N I T I E, Bombay	Plan Non-plan	100.00 165.60	89.00 179.00	100.00 185.00
13.	School of Planning and Architecture, New Delhi.	Plan Non-plan	150.00 118.50	150.00 103.70	200.00 118.00
14.	Modernisation & Removal of Obsolescence	Plan	4300.00	4300.00	4100.00
15.	Thrust Areas of Technical Education.				
	a) Creation of Infrastructure in Areas of Emerging Technologies b) Strengthening of facilities in crucial Areas of Technology where weakness exists c) Programmes of New and/or improved Technologies, offering new courses in specialised fields	Plan Non-plan	2500.00 300.00	2500.00 300.00	1800.00 300.00
16.	Institutional Network Schemes	Plan	100.00	100.00	100.00
17.	a) Apprenticeship Training	Plan Non-plan	250.00 312.00	198.00 289.30	200.00 335.00
	b) New Schemes under Apprenticeship Training	Non-plan	15.00	15.00	15.00
18.	Regional Offices	Non-plan	39.60	40.00	35.90
19.	Grants for Quality Improvement Programme Training	Non-plan	85.00	85.00	125.00
20.	Asian Institute of Technology, Bangkok.	Non-plan	10.80	11.00	12.80
21.	Administrative Staff College, Hyderabad.	Non-plan	2.50	—	—
22.	Indian Institutes of Management	Plan Non-plan	600.00 592.70	574.00 617.00	850.00 655.00
23.	Re-organising and Re-structuring and Strengthening of AICTE and Bureau of Technical Education.	Plan	100.00	100.00	200.00
24.	Grant of Autonomy to Selected Institutions	Plan	10.00	10.00.	5.00
25.	Strengthening existing Institutions and Establishment of new Institutions for un-organised and non corporate Sectors	Plan	20.00	20.00	10.00
26.	Restructuring Courses/Programmes	Plan	20.00	20.00	10.00
27.	Setting up of Residential Polytechnics for women	Plan	140.00	140.00	100.00
28.	Training and Technical Education for Handicapped	Plan	10.00	10.00	5.00
29.	International Centre for Science and Technology	Plan	10.00	4.50	10.00
30.	Research and Development in Selected Higher Technical Institutions	Plan	100.00	100.00	100.00
31.	Establishing/Strengthening Curriculum Development Centres/Cells etc.	Plan	50.00	50.00	50.00
32.	Continuing Education	Plan	50.00	50.00	50.00
33.	Institution—Industry Interaction	Plan	100.00	175.00	200.00
34.	Indian Institute of Technology, Assam.	Plan	400.00	400.00	560.00
35.	Longowal Institute of Engineering and Technology.	Plan	100.00	100.00	100.00

1	2	3	4	5	6
36.	Technical Consultancy for Developing Countries.	Plan	—	—	50.00
		Non-plan	8.75	8.00	8.60
37.	Assistance for participation for other Scientific Research	Non-plan	1.25	1.25	2.00
38.	Indian Society for Technical Education	Non-plan	0.50	0.55	0.50
39.	Foreign Experts (IIT Bombay) Foreign Delegations and Foreign Experts	Non-plan	1.00	1.00	1.00
40.	Construction of Student Hostels in Non-Govt. Technical Institutions.	Non-plan	0.50	—	0.50
41.	Implementing Pay Committee	Plan	—	—	—
	Recommendations	Non-plan	—	2000.00	2000.00
42.	Educational Consultants India Ltd. (ED.CIL)	Plan	—	—	—
43.	Documentation of Indian Management experiences and offering programmes for non-corporate and un-organised sectors.	Plan	—	—	5.00
44.	National Accreditation Board	Plan	—	—	5.00
45.	Staff Development and Training	Plan	—	—	5.00
46.	Technology Watch Group	Plan	—	—	5.00
47.	Assistance to Professional Bodies	Plan	—	—	10.00
48.	Super Computer at IISc. Bangalore	Plan	—	929.00	2700.00
Adult Education					
1.	Rural Functional Literacy	Plan	4000.00	4000.00	4100.00
	Projects	Non-plan	130.00	130.00	230.00
2.	Post Literacy Continuing Education (JSNs)	Plan	1000.00	1000.00	1200.00
3.	Strengthening of Administrative Structures	Plan	350.00	415.00	350.00
4.	Mass Programme of Functional Literacy	Plan	150.00	150.00	250.00
5.	Technology Demonstration	Plan	1000.00	1000.00	367.00
6.	Assistance to Voluntary Agencies (Including	Plan	750.00	1250.00	1040.00
	grants to State Resource Centres & External Evaluation)	Non-plan	13.40	13.90	15.00
7.	Shramik Vidyapeeths	Plan	100.00	96.50	100.00
		Non-plan	76.80	64.10	102.00
8.	National Literacy Mission Authority	Plan	75.00	50.00	25.00
9.	Directorate of Adult Education	Plan	125.00	235.50	185.00
		Non-plan	35.05	39.00	40.00

NAMES OF PRIVATE AND VOLUNTARY ORGANISATIONS WHICH RECEIVED RECURRING GRANT—IN—AID OF Rs. 1 LAKH AND MORE DURING 1987-88.

Sl. No. 1	Name of the Private and Voluntary organisation with address	Brief Activities of the Organisation	Amount of Recurring grant-in-aid released during 1987-88.	Purpose for which the grant was utilised	REMARKS
School Education and Physical Education					
1.	Kaivalyadhama Sreeman Madhava Yoga Mandir Samiti, Lonavala, Pune.	Maintenance and development of national level research and teacher training Programme of Yoga.	Rs. 26.28 lakhs	Maintenance and development of national level research and teacher training Programme of Yoga.	
2.	The Secretary, Banasthali Vidyapith, P.O. Banasthali Vidyapith-304022 (Rajasthan)	Banasthali Vidyapith, Rajasthan is a premier Institution in the field of women's education with its all India character and is doing excellent work in the field of women's Education.	Rs. 5,00,000/-	To meet the recurring deficit to tide over the financial difficulties which the Vidyapith is facing.	The grant is being released to Vidyapith on the basis of recommendation of the Review Committees.
3.	Ramakrishna Institute of Moral and Spiritual Education, Mysore.	i) To conduct Degree Course in Moral & Spiritual Education. ii) To conduct short term courses in Moral & Spiritual education for in-service high school teachers of Karnataka State. iii) The Retreat of college students from all over India. iv) The Retreat for General Public. v) Moral & Spiritual Classes for upper, primary & High School boys of Mysore City.	Rs. 2,50,000/-	For the maintenance and running of the Institute and for conducting the courses is Moral and Spiritual Education	
4.	The Vice-Chairman, Spic-Macey, 41/42, Lucknow Road, New Delhi.	— To promote classical heritage in educational Institutions all over the country. — To organise a Series of Lecture documentation in school and college. — To conduct Yoga Camps in schools & colleges. — To organise a series of folk and Craft programme — To organise (Baithaks) all over the country.	Rs. 10,00,000/-	For the promotion of classical heritage in Educational Institutions.	

1	2	3	4	5
5.	The Director, C.C.R.T., Bhagwan Das Road, New Delhi.	— To conduct training programme. — To conduct Orientation courses. - To organise refresher courses for trained teachers. — To organise course on puppetry for education — Implementation of the cultural talent search scholarship scheme.	Rs. 4,35,000/-	For Innovative and experimental Project for implementation of the NPE for cultural Education.
6.	The Member, Alarippu, New Delhi.	i) To organise workshops for women, children theatre workers, school teachers etc. ii) To identify the theatre groups for extending activities through educational institutions & Voluntary organisations. iii) To attempt interaction with village based artists for use of media for growing & surviving in their milieu and to look deeper into their conditions and needs. iv) An attempt will be made to put together scripts and theatre related material at one place-easily accessible to modest groups. v) To prepare two plays based on social issues. vi) To encourage children's theatre.	Rs. 2,50,000/-	For the project Innovative use of Theatre and related Communication media for Education.

Experimental And Innovative Projects

1.	Uttarakhand Sewa Nidhi, Nainital, U.P.	Educational	8,20,000	Experimental and Innovative project
2.	Kishore Bharati, P.O. Bankheri, Hoshangabad, M.P.		2,99,650	—do—
3.	Eklavya Foundation, E-1/208, Arera Colony, Bhopal, M.P.		1,40,000	—do—
4.	Kerala Sashi Sahitya Parishad, Trichur (Kerala)		1,00,000	—do—
5.	Indian Institute of Education, Pune.	Educational Research	5,01,237	—do—
6.	Krishnamurthi Foundation, India	School Education	1,97,300	—do—

1	2	3	4	5
	Non-Formal Education Project			
	ORISSA			
1.	Jayanti Pathagar, Post-Bramhabarada, Cuttack	Social Service	2,22,900	100 No[illegible] form[illegible] educatic[illegible] centr[illegible]
2.	Cuttack Zilla Adivasi Harijan Seva Sanskar Yojana, Chatta Post-Farikabad, Cuttack.	Development of Social and Cultural Activities	1,20,040	5[illegible]
3.	Jyotirmayee Mahila Samiti, Badagaon, Cuttack	Educational	2,40,300	10[illegible]
4.	Rural Development Society, K.B. Bandia, Post Mahakalapara, Cuttack	Rural Uplift programme	2,40,300	10[illegible]
5.	Antyodaya Seva Kendra, Post-Purunabasant, Cuttack	Social Service	1,28,740	5[illegible]
6.	Lokanayak Club, Banki, Cuttack	Social Service	2,40,300	10[illegible]
7.	Culi, Choudhulat Kendrapara, Cuttack	Upliftment of the poor	1,28,740	5[illegible]
8.	Pallishree, Post-Gasipur, Banki, Cuttack	Educational and Cultural	1,20,040	5[illegible]
9.	CYSD, 65, Satyanagar, Bhubaneswar, Puri	Promotion of Youth Activities Development	4,80,600	20[illegible]
10.	Navajoti, Post-Garudgan, Cuttack	Economic & Edu. Development	1,28,740	5[illegible]
11.	Bhairavi Club, Post-Hadpada, Puri	Educational and Cultural	1,20,040	5[illegible]
12.	Centre for Youth and Integrated Development Baselisahi, Puri.	Community Welfare	1,20,040	5[illegible]
13.	Bidyut Club, Haladipada, Post-Bajpur, Puri	Social Cultural and Educational Development	2,40,300	10[illegible]
14.	Janakalyan Samaj, Godiban, Chandaka, Puri	Social Service	2,22,900	10[illegible]
15.	Bhabanisankar Club, Gampur, Simore, Puri	Educational and Cultural	2,40,300	10[illegible]
16.	Nilachal Seva Partisthan, Banagan, Puri	Social, Economic and Educational Development	2,40,300	10[illegible]
17.	Acharya Harihar Sishu Bhavan, Satyabadi, Post-Sakhigopal, Puri	Childrens' Education	2,40,300	10[illegible]
18.	Community Welfare and Enrichment Society Bhubaneswar, Puri	Socio-Economic and and Educational Development	1,20,040	[illegible]
19.	Dahikhai Yuvak Sangh, Post-Lodhachua, Puri	Welfare Programme	1,28,740	
20.	MO Club, Kantabada, Baghamari, Puri	Youth Welfare Programme	1,28,740	
21.	Gopinath Juba Sangh, Dorda Ahini Sasan, Balipatna.	Rural Welfare	1,20,040	
22.	Gania Unnayan Committee, Gania, Puri	Advancement of Women and Economic Programme	1,28,740	

1	2	3	4	5
23.	VIKASH, M-5/11, Acharya Vihar, Bhubaneswar, Puri	Economic and Educational	1,28,740	50
24.	Utkalmani Seva Sangh, Post-Badaraipur Puri	Educational	1,28,740	50
25.	Lokashakti, Sri Kanthapur, Balasore	Educational	2,40,300	100
26.	Mandal Pokhari Jubak Sangh, Post Madari, Balasore	Educational	1,20,040	50
27.	Samagra Bikash Parishad, Baliapal, Balasore	Socio Economic Development	1,20,040	50
28.	Netajee Jubak Sangh, Balipokhari, Balasore	Social and Cultural	1,28,740	50
29.	Fellowship, Puruna Bazar, Bhadrak, Balasore	Vocational and Health Educational	1,20,040	50
30.	REACH, Jagamara, Khandagiri, Bhubaneswar, Puri	All round development	2,22,900	100
31.	Youth Association for Rural Reconstruction Boinda, Dhenkanal	Welfare Programmes	1,28,740	50
32.	PIPAR, Mahimagadi, Joranda, Dhenkanal	Socio-economic	2,22,900	100
33.	Samajik Seva Sadan, Banjhi Kusum Mahisapat, Dhenkanal	Integrated Development	1,28,740	100
34.	Tagore Society for Rural Development, Bhubaneswar	Socio-economic uplift	6,68,700	300
35.	Pragati Jubak Sangh Bijigol, Dhenkanal	Adult Child and Women Education	2,40,300	100
36.	Rural Women Development Service Centre, Angul, Dhenkanal	Social Welfare	1,28,740	50
37.	Gram Mangal Pathagar Salapali, Bolangir	Education and Social	2,40,300	100
38.	Sri Sri Saradeswari Pathagar, Post-Tushra, Bolangir	General Welfare	1,28,740	50
39.	Bapuji Pathagar Sukha, Bolangir	General Welfare	1,28,740	50
40.	Antyodaya Chetana Kendra, Post-Hadgarh, Keonjhar	Socio-economic Development	1,28,740	50
41.	Voluntary Association for Rural Reconstruction and Appropriate Technology, Cuttack	Social Service	1,28,740	50
42.	The Divine Life Society, Main Road, Bhanjanagar, Ganjam.	Rural Development	1,28,740	50
43.	Pragati Pathagar, Nimakhandi, Pantha, Ganjam	Socio-economic development	1,28,740	50
44.	Jayanti Pathagar Nuapada, Ganjam	All round development	2,40,300	100
45.	Ghumusar Mahila Sangathana, Post-Udayagiri, Phulbani	Women organisation educational	2,40,300	100
46.	Society for Human Resource and Ecological Development, Phulbani	Development of weaker sectors	2,22,900	100
47.	Banabasi Seva Samiti, Baliguda, Phulbani	Well being of tribal	1,20,040	50
48.	Bagdevi Club, Makundapur, Post Janhapanka, Phulbani	Welfare of villages	1,28,740	50
49.	SHED, College Road, Rayagada, Koraput	Tribal development	2,22,900	100

1	2	3	4	5
50.	Prepare (Indian Rural Reconstruction and Disaster Response Service) Gandhi Nagar, Rayagada, Koraput	Social Service	2,22,900	100
51.	Sarvodaya Samiti, Koraput	Socio-Economic Development of Tribals	1,20,040	50
52.	SODA, Baripada, Mayurbhanj	All round development of tribals	2,22,900	100
53.	Binapani Jubak Sangh, Batpondigondi, Mayurbhanj	Education and Social Service	1,20,040	50
54.	Antyodaya Chetana Mandal, Barakand, Morada, Mayurbhanj	Development of Tribals	2,22,900	100
55.	Bisol Youth Club, Bisol, Post-Sana, Bisol, Mayurbhanj	Education	1,28,740	50
56.	Dhokotha Jubak Sangh, Keonjhar	Rural Development	2,22,900	100
57.	Pragati Pathagar, Belaguntha, Ganjam.	Education	1,28,740	50
58.	Old Rourkela Education Society, Balizodi, Rourkela	Education	2,40,300	100
59.	Sri Satyasai Seva Samiti, Post-Deobhubanpur, Sundargarh	Socio-Cultural and Rural Development	1,20,040	50
60.	Vivekananda Palli Agragami Seva Pratisthan, Sambalpur	Education	1,28,740	50
61.	Viswas, Kalinivas, Kharirar Road, Kalahandi	Rural Development Social Welfare	2,57,700	100
62.	Jagrut Shramik, Sangathana, Kalahandi	Socio-economic development	1,20,040	50
63.	Agragamee, Koraput	Educational	2,05,800	100
64.	Gandhi Sevashram, Balasore	—do—	2,40,300	100
65.	Ramjee Yuvak Sangh, Cuttack	—do—	2,40,300	100
ANDHRA PRADESH				
66.	Rayalaseema Seva Samiti	Social work and Promotion of Literacy	27,03,962	300 old 800 New NFE centres
67.	Literacy House (Andhra Mahila Sabha) Hyderabad	—do—	2,46,864	100
MADHYA PRADESH				
68.	Sultan-ul-Hind Educational Social Service Society	—do—	1,58,408	57
UTTAR PRADESH				
69.	Lok Vikas Sansthan, Allahabad	NFE	2,22,900	100
70.	Sarvodaliya Manav Vikas Kendra	Educational	2,22,900	100
71.	Jankalyan Siksha Samiti, Pawanagar	—do—	2,22,900	100
72.	Sarvodaya Siksha Samiti, Shikohabad	—do—	1,20,040	50
73.	Samajik Evam Arthik Vikas Sansthan, Lucknow	—do—	2,22,900	100
74.	Banwasi Seva Ashram	—do—	1,98,175	100
RAJASTHAN				
75.	Ajmer Adult Education Association	Adult Literacy and NFE	3,66,550	50 old, 100 new
76.	Jodhpur Adult Education Association	—do—	3,06,675	50 old, 100 new

1	2	3	4	5
77.	Bhoruka Charitable Trust	Rural development	2,22,900	100
78.	Gramin Vikas Vigyan Samiti, Jodhpur	Rural development	2,22,900	100
GUJARAT				
79.	Gujarat Vidyapeeth, Ahmedabad	Higher Education	2,40,300	100
DELHI				
80.	PHD Rural Development Foundation, New Delhi	Rural Development	2,22,900	100
81.	Akhil Bhartiya Samajoddhan Samiti	Adult Education/NFE Educational	2,40,300	100
82.	Ravi Bharati Siksha Samiti	—do—	2,22,900	100

Technical Education

1.	Indian Society for Technical Education New Delhi.	Quality improvement programmes	20.27 Lakhs	Conducting Winter/ Summer Courses
2.	Institute of Engg. & Rural Tech., Allahabad.	Conducting diploma level courses	3.50 "	Community develop ment work, advance technical courses
3.	Cursow Wadia Institute for Technology, Pune.	Academic & research activities	1.00 "	For post graduate courses
4.	Ramgarhia Polytechnic, Phagwara.	-do-	3.00 "	-do-
5.	Thaper Polytechnic, Patiala.	-do-	3.00 "	-do-
6.	Feroze Gandhi Polytechnic, Raebareli.	-do-	3.00 "	-do-
7.	New Delhi Polytechnic for Women, New Delhi.	-do-	2.50 "	-do-
8.	Pt. J. N. Polytechnic, Sanawad.	-do-	1.25 "	-do-
9.	Civil & Rural Institute, Gargoti.	-do-	1.25 "	-do-
10.	B&B Polytechnic, Vallabhvidya Nagar	-do-	1.25 "	-do-
11.	B. M. Polytechnic, Bombay.	-do-	2.00 "	-do-
12.	C. M. Kothari Technology Institute, Madras.	-do-	2.54 "	-do-
13.	Y.M.C.A. Institute of Engineering, Faridabad.	-do-	2.30 "	-do-
14.	Technological Institute of Textiles, Bhiwani.	-do-	1.00 "	-do-
15.	Harcourt Butler Technological Institute, Kanpur.	-do-	1.09 "	-do-
16.	Victoria Jubilee Technologial Institute, Bombay.	-do-	25.06 "	-do-

1	2	3	4	5
17.	Shri Govindram Seksaria Technological Institute, Indore.	-do-	1.00 "	-do-
18.	L. M. College of Pharmacy, Ahmedabad.	-do-	5.00 "	-do-
19.	Walchand College of Engg., Sangli.	-do-	6.00 "	-do-
20.	P.S.G. College of Technology, Coimbatore.	-do-	20.00 "	-do-
21.	Thiagarajar College of Engg., Madurai.	-do-	4.30 "	-do-
22.	National Institute of Engg., Mysore.	-do-	6.49 "	-do-
23.	School of Planning, Navrangpura, Ahmedabad.	-do-	15.38 "	-do-
24.	S. J. College of Engg., Mysore.	-do-	6.50 "	-do-
25.	Guru Nanak College of Engg., Ludhiana.	-do-	1.50 "	-do-
26.	Bombay College of Pharmacy, Kalina, Bombay.	-do-	3.00 "	-do-
27.	Madhav Institute of Technology & Science, Gwalior.	-do-	1.50 "	-do-
28.	Birla Instt. of Technology, Mesra, Ranchi.	-do-	4.02 "	-do-
29.	B.M.S. College of Engg., Bangalore.	-do-	10.62 "	-do-
30.	Coimbatore Instt. of Technology, Coimbatore.	-do-	5.60 "	-do-
31.	Malnad College of Engg. Hasan, Karnataka.	-do-	13.00 "	-do-
32.	Indian Institute of Social Welfare, Calcutta.	-do-	10.21 "	-do-
33.	T.K.M. College of Engg. Quilon.	-do-	3.20 "	-do-
34.	M.M.M. College of Engg., Gorakhpur.	-do-	1.50 "	-do-
35.	K. M. Kundnani College of Pharmacy, Bombay.	-do-	1.50 "	-do-
36.	Institute of Management Technology, Ghaziabad.	-do-	2.50 "	-do-
37.	S.G.G.S. College of Engineering, Nanded.	-do-	1.00 "	-do-
38.	P.E.S. College of Engg. Mandya.	-do-	1.50 "	-do-
39.	Asian Institute of Technology, Bangkok.	-do-	2.00 "	Academic activities of AIT in India

1.	2.	3.	4.	5.
Promotion of Languages				
1.	Andhra Pradesh Hindi Prachar Sabha Hyderabad (A.P.)	Running of Hindi Teaching centres, Hindi Mahavidyalayas and Hindi Prachar centres, etc.	Rs. 1,31,865	Teaching centres, Mahavidyalayas, Pracharak Sammelan & Publication of Hindi diary.
2.	Hindi Vidyapith Deoghar, Bihar.	Teaching classes type-writing & shorthand classes.	Rs. 1,38,600	Hindi Teaching & shorthand and typewriting classes, salaries to staff, stipend to students.
3.	Akhil Bharatiya Hindi Sanstha Sangh, New Delhi.	Hindi propagation programmes, etc.	Rs. 4,31,414	Establishment expenditure and continuing Hindi propagation programmes.
4.	Karnataka Mahila Hindi Seva Samiti, Bangalore.	Hindi teaching classes, libraries, debates, etc.	Rs. 6,32,175	Hindi composition, printing, binding training courses, purchase of machines, material, equipment for printing press, running of classes, libraries, debates, prizes, etc.
5.	Karnataka Hindi Prachar Samiti, Bangalore.	Running of teaching centres, library, etc.	Rs. 2,78,975	Free Hindi teaching centres, library, pub. of magazines, Teachers' training colleges and salaries to staff.
6.	Mysore Hindi Prachar Parishad, Bangalore.	Hindi teaching centres, typewriting & shorthand classes, etc.	Rs. 2,49,975	Hindi libraries, Hindi centres, shorthand & typing classes and other programmes of Hindi.
7.	Bombay Hindi Vidyapith, Bombay.	Teaching centres, library, reading rooms, pracharak centres, seminar, drama, etc.	Rs. 3,59,900	Hindi teaching centres, library & reading rooms, pracharak seminar, drama, golden jubilee ceremoney etc.
8.	Rashtrabhasha Prachar Samiti, Wardha.	Text books, cultural programmes, organisation of seminars for Hindi pracharaks, etc.	Rs. 1,93,055	Salaries of Principal, etc. text books, organisation of Hindi pracharaks seminar at Jorhat golden jubilee programmes, etc.
9.	Rashtrabhasha Sheeghralipi College, Imphal.	Running of Hindi Maha Vidyalayas,. etc.	Rs. 1,08,900	Salaries to Principal, teachers, peon etc. of Hindi Mahavidyalaya
10.	Manipur Rashtrabhasha Prachar Samiti, Imphal.	Hindi teaching centres Mahavidyalayas, etc.	Rs. 1,35,300	8 Mahavidyalayas and 10 vidyalayas.
11.	Kerala Hindi Prachar Sabha, Trivandrum.	Kendriya Mahavidyalaya, typewriting & shorthand classes, prizes, etc.	Rs. 4,43,100	Hindi libraries, Kendriya Mahavidyalayas, Hindi pracharak, refresher courses, prizes, etc.
12.	Dakshin Bharat Hindi Prachar Sabha - For its branches at Madras, Hyderabad, Bangalore, Ernakulam, Lakshadweep,	Free Hindi classes, Mahavidyalayas, B. Ed. and Post-graduate colleges, computer courses, pracharak	Rs. 38,58,723	Free Hindi classes, library & reading rooms, Hindi vidyalayas, mahavidyalayas, publication of. magazines single teacher vidyalayas, P. G. complexes, B. Ed. colleges,

1.	2.	3.	4.	5.
	Pondicherry, Trichirapalli. etc.	vidyalayas, typewriting & shorthand classes etc.		computer courses, refresher courses, prizes, etc.
13.	Nagari Pracharini Sabha, Varanasi.	Hindi library and publication of books.	Rs. 7,80,000	4th instalment of building grant, publication of catalogue, purchase of new Hindi books, etc.
14.	Bhuvan Vani Trust Lucknow.	Publication of books in Hindi from other languages.	Rs. 9,55,480	Purchase of off-set printing machines, publication of Valmiki Ramayana, Mahabharat etc.
15.	Uttar Poorvanchal Rashtrabhasha Prachar Samiti, Itanagar	Rashtrabhasha Mahavidyalayas, vidyalayas, scholarships, etc.	Rs. 1,82,355	Organisational expenses, Rashtrabhasha Mahavidyalayas, Vidyalayas, scholarships of students, etc.
16.	Zoram Hindi Prachar Samiti, Aiozawl.	Rashtrabhasha vidyalayas, public. of magazines, etc.	Rs. 1,31,250	Excursion of Hindi students maintenance of Rashtrabhasha vidyalaya, pub. of magazine, etc.
17.	Rupayan Sansthan, Barunda, Jodhpur	Pub. of books.	Rs. 2,16,000	Pub. of Batari Phulwari.
18.	Association of Writers and Illustrators for children, 4, Nehru House, B. Z. Marg., New Delhi.	Pub. of books.	Rs. 2,40,564	Pub. of Sachitra Balshabad Kosh in Hindi.
19.	Dairatul Marrifil Osmania, Hyderabad.	Publication, Research	Rs. 1,57,000	Maintenance
20.	The Principal, Shri Rang Laxmi Adarsh Skt. Mahavidyalaya, Vrindaban, Mathura - 281121.	Teaching	Rs. 4,05,440	Salary/scholarships/ Contingencies/books, furniture, Annual function, printing of books and repairs.
21.	The Principal, Jagdish Narayan Brahmchari Ashram, Skt. Mahavidyalaya, Lagma, Via-Lohna Road, Rambhadharpur, Distt. Darbhanga (Bihar).	- do -	Rs. 4,25,398	Salary/scholarships/ contingencies/furniture library books, Repairs of buildings.
22.	The Principal, Bhagwan Das Sanskrit M. V., PO : Gurukul Kangri, Haridwar, Saharanpur (U.P.)	- do -	Rs. 4,09,827	Salary/scholarships/ contingencies/furniture TA & DA/books/Repairs of building and printing of booklet.
23.	The Principal, Dewan Krishna Krishsore S. D., Adarsh Sanskrit College, Ambala Cantt.	- do -	Rs. 3,48,792	Salary/scholarships/ PF/contingencies/ furniture/Books and Purchase of typewriter.
24.	Shri Ekarasanand Sanskrit Mahavidyalaya, Mainpuri (U.P.)	- do -	Rs. 3,34,552	Scholarships/contingenies/ Furniture/books/ Repair of buildings.

1	2	3	4	5
25.	The Madras Skt. College, and SSV Pathshala, 84-Royapeeth Road, Mylapore, Madras.	- do -	Rs. 4,32,427	Salary/scholarships/ furniture/contingencies/ Repair of buildings.
26.	Mumbadevi Sanskrit M.V., C/O Bharatiya Vidya Bhavan, K. M. Mushi Marg, Bombay - 7.	Teaching	Rs. 3,47,636	Salary/scholarships/ Contingencies/TA & DA/ Library books.
27.	Haryana Sanskrit Vidyapeeth, PO : Bhagola, Dist. Faridabad, Haryana.	- do -	Rs. 4,16,309	Salary/scholarships/ Contingencies/TA & DA/ Building repairs/Books.
28.	Kuppuswami Sastri Research Institute, 84-Royapeetha High Road, Mylapore, Madras	Research	Rs. 2,40,117	Salary/Contingency/ Scholarships/Furniture/ Publication/Repair of buildings/Advertisement.
29.	Calicut Adarsh Sanskrit Vidyapeeth, Ballussary, Distt. Calicut (Kerala)	Teaching	Rs. 4,01,991	Salary/Contingency/TA & DA/ scholarships/books and furniture.
30.	Vaidika Samsodhana Mandala Tilak Vidyapeeth Nagar, Poona - 9 (Maharashtra).	Research	Rs. 4,15,372	Salary/Contingencies and Library books.
31.	Sri Chandrasekharendra Saraswati N'ayaya Sastra Sanskrit Mahavidyalaya, No. 3, East Mada Street, Little Kancheepuram (T. Nadu.)	Teaching	Rs. 1,98,611	Salary/scholarships/ Contingencies/Furniture/ Books and Repair of buildings.
32.	Lakshmi Devi Sharaff Adarsh Sanskrit Mahavidyalaya, Kali Rekha, Vill/PO, Deogarh (Bihar).	- do -	Rs. 3,96,010	Salary/Scholarships/ Contingencies/TA/Furniture/ Library books.
33.	Rajkumari Ganesh Sharma, Adarsh Sanskrit Pathshala, Kolhanta Patori (Bihar).	-do -	Rs. 2,46,033	Salary/scholarships/ Contingencies/Lib. books/ TA & DA.
34.	Sanskrit Dictionary Project, Poona.	Preparation of Skt. Dictionary	Rs. 7,36,633	Maintenance grant
35.	Raja Veda Kavya Pathshala, D. 76/111, Cross Street, Srinagar Colony, Kumbakonam.	Teaching	Rs. 2,16,600	Salary/Scholarships
36.	Assam Veda Vidyalaya, Chatraker, Gauhati - 781001.	Teaching	Rs. 2,50,080	Salary/Scholarships
37.	Shankara Academy of Sansakrit Culture and Classical Arts, 17A/1, WEA, Karol Bagh, New Delhi.	- do -	Rs. 3,31,265	- do -
38.	Bharatiya Chaturdhan Ved Bhawan Nyas, Swadeshi House, Civil Lines, Kanpur.	- do -	Rs. 1,59,600	- do -

1	2	3.	4	5
39.	Rashtriya Veda Vidya Pratishthan, Shastri Bhawan, New Delhi.	Supporting traditional vedic institutions & scholars, providing scholarships/ fellowships etc. for promotion of oral tradition of vedic studies.	Rs. 50.00 Lakhs to be utilised as corpus fund.	The amount has been deposited in the bank.
Adult Education				
Andhra Pradesh				
1.	Andhra Mahila Sabha University Road Hyderabad (A.P.) -500 007	Voluntary Organisations are engaged in any one or the other following activities:— 1) Running Balwadi/ Anganwadi 2) Running ICDS Centre 3) Immuniation of Children work 4) Education of mothers 5) Running School 6) Running College 7) Running a technical Instt. 8) Running typing Instt. 9) Running tailoring course for women 10) Celebration of National days 11) Organised eye camp 12) Organised blood donation camp	14,40,000/	450 AECs
2.	Bhagvatulla Charitable Trust Yellamanchilli Vishakhapatnam Distt. (A.P.)-531 055	—do—	10,00,000/-	For training of rural animators
3.	Downtrodden & Community Development Society 11/96 Sumithra Nagar Badwel-516 227 Cuddapah Distt.	—do—	10,50,000/-	330

1	2	3	4	5
4.	Grama Nava Nirman Samithi, Huzurabad Karimnagar-505 468	—do—	3,20,000/-	100
5.	Prachya Bhasha Vidya Peeth Rajendranagar Gudivada Distt. Krishna-521 301	—do—	1,20,000/-	60
6.	Sardar Youth Assn. Rangasamudram Badvel Tq. Cuddapah Distt. A.P.-516 193	—do—	1,20,000/-	60
7.	Sevamandir Hindupur Hindupur Taluka Anantpur Distt. -515 212	—do—	6,00,000/-	300 AECs
8.	Shree Veerabrahman Educational Society Gorantla-515 231 Anantapur Distt. Andhra Pradesh.	—do—	1,20,000/-	60 AECs
Assam :				
9.	Benugram Mahila Samiti Block South Karimganj Development Block Distt. Karimganj Assam-788 722	—do—	1,80,000	60 AECs
10.	Janajati Samaj Kalyan Ashram Baruakhat, P.O. Barama Block Baska Dev. Distt. Nalbari Assam Pin-781 346	—do—	3,20, 000/-	100 AECs
11.	Udali Rahmania Madrassa Committee P.O. Udalli Bazar (Via Lanka P.O.) Nowgong, Assam-782 446.	—do—	3,20,000/	100 AECs
Bihar :				
12.	Bhagwan Pustakalaya Naya Bazar Bhagalpur City Bihar	—do—	3,20,000/-	100 AECs
13.	Bharatiya Kala Mandir At and P.O. Daltonganj Distt. Palamu, Bihar	—do—	.1,80,000/-	60 AECs

1	2	3	4	5
14.	Prakratik Arogyoshram P.O. Rajgir Distt. Nalanda, Bihar	—do—	3,20,000/-	100 AECs
Gujarat :				
15.	Adarsh Kalvani Mandal Samadhiala Mulani Tq. Palitana Distt. Bhavnagar-364 001	—do—	3,14,365/-	100 AECs
16.	Anand Taluka Yuvak Mandal Association Lakshmi Niwas 25, Ajantha Society Anand, Dt. Khoda-388 001	—do—	4,00,000/-	200 AECs
17.	Bhansali Trust Highway, Radhanpur Pin-385 Banaskantha Distt. Banaskantha Gujarat	—do—	1,20,000/-	60 AECs
18.	Bhavnagar Mahila Sangh Panwadi Chowk Bhavanagar Gujarat-364 001	—do—	1,20,000/-	60 AECs
19.	Bharuch Jilla Kaival Kelavani Mandal Nava Rajuwadia Tq. Nanded, Distt. Bharuch Gujarat-312 001	—do—	1,80,000/-	60 AECs
20.	Bhil Seva Mandal Dahod Dt. Panchmahal-389 151 Gujarat	—do—	5,82,164/-	300 AECs
21.	Gandhinagar Education Society, Sector-23 Virat Nagar Gandhi Nagar-382 023	—do—	1,20,000/-	60 AECs
22.	Gayatri Shixan Vanasthali C/o A/44 Janak Puri Society Dhundusar Road Junagarh-362 001	—do—	2,00,000/-	100 AECs
23.	Gram Seva Samaj Vankal, Tq. Mangrol Distt. Surat-395 003 Gujarat.	—do—	2,00,000/-	100 AECs
24.	Gujarat State Crime Prevention Trust 2 Joshi Bag Apartments St. Xaviers School Road Ahmedabad-380 001.	—do—	9,60,000/	300 AECs

1	2	3		5
25.	Gujarat Vidhyapeeth Ashram Road Ahmedabad-380 001. Gujarat.	—do—	10,58,000/-	300 AECs
26.	Indian Society for Community Education Gujarat Vidyapeeth Ahmedabad-380 001	—do—	2,00,000/-	100 AECs
27.	Kamjhibhai Desai Samaj Shikshana Bhavan Trust Opp. Museum Chowk Surat-395 003	—do—	2,00,000/-	100 AECs
28.	Kapadwanj Dakor Road Kapadwanj Distt. Kheda-387 620	—do—	1,20,000/-	60 AECs
29.	Nirman Rena's Bungalow Kagdiwad Elis Bridge Ahmedabad-382 006	—do—	1,20,000/-	60 AECs
30.	Nootan Bharati P.O. Madhangadh T. Palanpur Distt. Banaskantha Pin-385 519	—do—	3.20.000/-	100 AECs
31.	Shri Shixen Sadhana Kelvani Trust Jalisana Tq. Viramgam Dt. Ahmedabad-302 010	—do—	1,20,000/-	60 AECs
32.	Servants of People Society (Lok Sevak Mandal) 1225 Devni Sheri Madvinipole Ahmedabad-380 001	—do—	3,80,000/-	130 AECs
33.	Panchmahal Kelvani Mandal At & P.O. Kalol Distt. Panchmahal 389 001	—do—	2,00,000/-	100 AECs
34.	Vadodara Jilla Panchat Marg Seva Mandal Sardar Bhavan Radhopura Road Vadodara-390 002	—do—	8,00,000/-	400 AECs
Haryana:				
35.	Janta Kalyan Samiti Rewari Distt. Mohindergarh Haryana-123 401	—do—	9,60,000/-	300 AECs

1	2	3	4	5
36	PHD Rural Development Foundation PHD House Opp. Asian Games Village New Delhi-110 016	—do—	3,80,000/-	130 AECs
37.	Shiksha Samiti D.A.V. Training College/ Sonepat, Shiv Nagar, Sonepat, Pin-131 001	—do—	3,20,000/-	100 AECs
38.	Vidya Maha Sabha Kanya Gurukul Mahavidyalaya Kharkhoda (Sonepat) Haryana	—do—	6,00,000/-	300 AECs
Karnataka :				
39.	Gidibanda Gramodyog Sangha, Gudibanda 561 209 Kolar Distt. Karnataka	—do—	9,60,000/-	300 AECs
40.	Karnataka Youth Welfare Federation, Kanakapura Main Road, Bangalore-560 078 Karnataka	—do—	2,00,000/-	100 AECs
41.	Kasturba Mahila Seva Samaj, Challakern Distt. Chitradurga Karnataka-577 522	—do—	1,20,000/-	60 AECs
42.	The Kasturba Sadan Vijayapur, Distt. Chikmaglur-577 101 Karnataka	—do—	2,00,000/-	100 AECs
43.	Madhugiri Education Society Madhugiri-572 132 Tumkur Distt Karnataka	—do—	1,20,000/-	60 AECs
44.	Malthesha Education Society, No. 78/24 8th Cross, Magadi Road Shankarappa Gardens Bangalore-560 023.	—do—	1,80,000/-	90 AECs
45.	Navatharanga Educational Society, 131 Vidyaranyanagar Bangalore-560 023.	—do—	2,40,000/-	120 AECs
46.	Netaji Education Society Vinobanagar-Shimoga-577 201 Karnataka	—do—	1,20,000/-	60 AECs
47.	Nalanda Education Society No. 1181 Raghavendra Block			

1	2	3	4	5
	Srinagar, Bangalore-560 050.	—do—	1,80,000/-	90 AECs
48.	Syndicate Agriculture Foundation, Manipal Pin-576 119 Udupi Tq. Dakshina Kannada Distt. Karnataka	—do—	9,60,000/-	300 AECs
49.	Sri Samanya Vidya Kendra No. 87 Padmasadana, Gandhi Bazar, Bangalore-560 004.	—do—	1,80,000/-	60 AECs
50.	Shri Varashidhi Vinayaka Mandali, N.E.S. Extension D. No. 2495, Magadi Town-562 120, Bangalore	—do—	2,40,000/-	120 AECs
51.	Sarvodaya Vidya Peetha No. 15, Mallikarjuna Temple Street, Basavanagudi Bangalore-560 004	—do—	2,00,000/-	100 AECs
52.	Shri Sharda Vidyalaya Tipapeth, Guledgudda Tq. Badami Distt. Bijapur-587 203 (Karnataka)	—do—	1,20,000/-	60 AECs
Kerala:				
53.	Kasturba Gandhi National Memorial Trust, Nedupuzha P.O. Trichur Pin-680 015, Kerala	—do—	3,20,000/-	100 AECs
54.	Mitraniketan Mitraniketan, P.O. Vallanad-695 543 Trivandrum Distt (Kerala)	—do—	3,20,000/-	100 AECs
55.	Vinobaniketan P.O. Vinobaniketan Distt. Trivandrum Kerala-695 542	—do—	2,00,000/-	100 AECs
Madhya Pradesh:				
56.	Bharatiya Grameen Mahila Sangh. (M.P. Branch) 146, Preconce Colony Annapurana Road, Indore	—do—	19,20,000/-	600 AECs
Maharashtra:				
57.	Amar Bihu Krida Mandal, Sholapur	—do—	1,20,000/-	60 AECs
58.	Gram Vikas Seva Mandal P.O. Mul, Pin-441 224			

1	2	3	4	5
	Distt. Chandrapur Maharashtra		1,20,000/-	60 AECs
59.	Senapati Tayta Tope Shikshan Prasarak Mandal, Yeola, Distt. Nasik	—do—	1,20,000/-	60 AECs
60.	State Resource Centre For NFE 128/2, J.P. Naik Road Koth Road, Pune-411 029	—do—	1,78,000/-	Training of Rural Youth Animators
Manipur :				
61.	Integrated Rural Development Society Linglong P.O. Imphal-795 130	—do—	1,20,000/-	60 AECs
62.	Manipur Adult Education Association, Thakhallikai Imphal, Manipur	—do—	2,00,000/-	100 AECs
63.	Rural Development Society Wangjing Bazar P.O. Wangjing Manipur-755 103	—do—	1,20,000/-	60 AECs
64.	The Manipur Vocational Institute, H.Q. Mekola Bazar, B.P.O. Laiphrakom Via—Tulihal, S.O. Imphal West-II, Imphal Distt., Manipur-795 140	—do—	1,20,000/-	60 AECs
Orissa :				
65.	Council of Cultural Growth & Cultural Relation Maitre Sarani, Cuttack-753 001	—do—	1,80,000/-	60 AECs
66.	Dengaborai Mahila Samiti A. Dengaborai, Odapada Block Dhenkanal Taluk Distt. Dhenkanal P.O. Indipur.	—do—	1,80,000/-	60 AECs
67.	Gram Mangal Pathagar At. P.O. Salepali Vill. Taluk Jarasingha Block Deogoan Distt. Balangir Orissa-676 067	—do—	9,60,000/-	300 AECs
68.	India Rural Reconstruction & Disaster Response Service College Road, Gandhi Nagar-I At/PO Rayagada, Koraput Dist-765 001.	—do—	1,20,000/-	60 AECs
69.	NYSCAP (National Yuva Sansad for Community Action			

1	2	3	4	5
	Programme) P.O. Motta Block Kamakhya Nagar, Distt. Dhenkanal, Orissa-759 018.	—do—	1,80,000/-	60 AECs
70.	The Divine Life Society Bhanjanagar Branch P.O. Bhanjanagar Block Bhanjanagar Taluk Ghunisur Distt. Ganjam Pin-721 026	—do—	1,80,000/-	60 AECs
Rajasthan :				
71.	Ajmer Adult Education Association Vidyoot Marg E.P.I. Shastri Nagar Extension Ajmer-305 001.	—do—	6,00,000/-	300 AECs
72.	Bikaner Adult Education Association Prodh Shiksha Bhavan Sarswati Park P. Box. No. 28, Bikaner-334 001	—do—	6,00,000/-	300 AECs
73.	Gandhi Vidya Mandir Sardarshahr Chru-331 001	—do—	1,20,000/-	60 AECs
74.	Indira Shiksha Samiti Wazirpur Station Road Gangapur City-322 201	—do—	1,80,000/-	60 AECs
75.	Jodhpur Proudh Shikshan Samiti, Gandhi Bhavan, Residency Road Jodhpur-342001	—do—	12,49,793/-	400 AECs
76.	Lok Shikshan Sansthan P-87, Gangori Bazar Distt. Jaipur.	—do—	3,20,000/-	100 AECs
77.	Lok Bharti Deogarh Madaria-313 001 Rajasthan	—do—	1,20,000/-	60 AECs
78.	Mahila Lok Jagrati Samiti Jawahar Nagar Jaipur-302 004	—do—	1,20,000/-	60 AECs
79.	Seva Mandir Udaipur-313 001 Rajasthan	—do—	9,60,000/-	300 AECs
80.	Zila Mahila Jagarati Parishad Station Road Barmer-344 001	—do—	1,20,000/-	60 AECs

1	2	3	4	5
Tamil Nadu :				
81.	Christian Educational Development Society, 118 Napalaya Street, Villupuram - 605 020 S. A. Distt. (T.N.)	- do -	5,20,000	200 AECs
82.	Congregation of the Sisters of the Cross of Chavanod, Holy Cross Convent Cantonment Trichy - 620 001.	- do -	5,20,000	200 AECs
83.	Dr. Annie Besant Mahalier Mandram 64 Mangamnal, A. E. Koil Street, New Washermanget - 600 081.	- do -	1,79,785	60 AECs.
84.	Gandhi Niketan Ashram Madurai Distt. T. Kallupatty - 626 702.	- do -	1,80,000	60 AECs
85.	GRD Trust Kalaikathir Buildings Avanashi Road, Coimbatore - 641 037 (TN).	- do -	4,00,000	200 AECs
86.	Kasturba Gandhi National Memorials Trust Kasturba Gram P.O. Erodo - 638 803. Tamil Nadu.	- do -	1,80,000	60 AECs
87.	Kandarsami Kandar's Trust Board Valur Salem - 638 182.	- do -	3,20,000	100 AECs.
88.	Kalvi Ulagam Educational Society Lattari - 632 202 Tamil Nadu.	- do -	2,00,000	100 AECs
89.	Khajamalai Ladies Assn., Tiruchirapali - 620 023. Tamil Nadu.	- do -	3,20,000	100 AECs
90.	Kundrakudi Thiruvannamalai Adheenam, Dt. Pasumpon Muthuramalingam Kundrakudi - 623 206. Tamil Nadu.	- do -	1,20,000	60 AECs
91.	Madhar Nala Mandram, B. Vandipalayam P.O. Cuddalore - 607 004. Tamil Nadu.	- do -	4,00,000	200 AECs
92.	Umalur Rural Socio Economic & Cultural Academy Peramachur, P.O. Muthunaichempatty - 636 304, Omalur Taluk, Salems Distt. (T. N.)	- do -	2,00,000	100 AECs

1	2	3	4	5
93.	Punjab Association No. 170 to 172, Petres Road Royapettah Madras - 600 014.	- do -	9,60,000	300 AECs
94.	Tamil Nadu Basic Education Society T. Kallupatti - 626 702 Madurai Distt. (T. N.)	- do -	1,80,000	60 AECs
95.	Tamil Nadu Board of Continuing Education Venkataratham Nagar, Extension Adyar Madras - 600 200.	- do -	4,50,000	200 AECs
96.	Tamil Nadu Board of Rural Development 13, Radhkrishnan Street, T. Nagar, Madras - 600 017.	- do -	3,19,973	100 AECs
97.	Vellore Social Development Organisation No. 5 Indian Home, 10th East, Main Road Gandhinagar, Vellore - 622 006 (T.N.)	- do -	1,20,000	60 AECs
98.	Women's Indian Assn. 43, Greenways Road, Madras - 600 028. (T. N.)	- do -	3,79,579	130 AECs.
99.	Women's Voluntary Service of Tamil Nadu 19 East Spur Tank Road, Chetpet, Madras - 600 031 (Tamil Nadu).	- do -	7,11,171	300 AECs
100.	Youth Association Muthuramalingapuram Post Aruppukettai Taluk Ramanathapuram Distt. 626 105.	- do -	3,17,333	100 AECs
Uttar Pradesh :				
101.	Adarsh Seva Samiti 326/1, Saket Colony, Gali No. 6, Muzaffar Nagar	- do -	3,20,000	100 AECs
102.	Akhil Bharatiya Nirbal Vikas Sansthan Tirwaganj Distt. Farrukhabad (U.P.)	- do -	1,20,000	60 AECs
103.	Bhagwan Kali Grih Silp Kendra J-12/78 A, Nati Imli P. O. Varanasi (Cantt.) Varanasi (U.P.)	- do -	1,20,000	60 AECs
104.	Bhartiya Ajiwan Shiksha Parishad 646/647 Katra, Allahabad (U.P.)	- do -	2,00,000	100 AECs
105.	Dr. Ambadkar Samaj Seva Mandal, Vill. Veski P. O. Saidabad Distt. Allahabad.	- do -	3,00,000	120 AECs
106.	Gram Vikas Seva Sansthan Jagdishpur Distt. Sultanpur (U.P.)	- do -	1,20,000	60 AECs

1	2	3	4	5
107.	Gram Seva Niketan 295/23, Ashrafabad Lucknow - 3 (U.P.)	- do -	1,20,000	60 AECs
108.	Gramodaya Vikas Mandal Suraj Kund, Ram Bagh, Meerut (U.P.)	- do -	1,20,000	60 AECs
109.	Harijan Evam Adivasi Vikas Seva Samiti P.O. Karaon Distt. Allahabad (U.P)	- do -	1,20,000	60 AECs
110	Indian Literacy Board Literacy House P. O. Alam Bagh, Lucknow (U.P.)	- do -	39,05,000	1200 AECs
111.	Jan Kalyan Shiksha Samiti, Pawa Nagar, Fazil Nagar, Distt. Deoria (U.P.)	- do -	1,20,000	60 AECs
112.	Mayana Gramodyog Seva Samiti, Mayana, Murari Nagar, G. T. Road, Khurza, Dt. Bulandshahar (U.P.)	- do -	3,20,000	100 AECs
113.	Mahila udyog Prashikshan Kendra Salik Ganj Road, Muthiganj, Allahabad (U.P.)	- do -	1,20,000	60 AECs
14.	Nishat Shiksha Samiti, Astana Nai Basti, Haldwani, Nainital (U.P.)	- do -	3,20,000	100 AECs
15.	Nehru Bal Mandal Prayag, 23-B Allahapur, Distt. Allahabad (U.P.)	- do -	2,60,000	130 AECs
16.	Raja Chet Singh Shiksha Sansthan, J-12/78, A-Nati Imli P.O. Varanasi (Cantt.) Dt. Varanasi (U.P.)	- do -	1,20,000	60 AECs
17.	Saraswati Pustakalaya Evam Vachanalaya Tatha Khel-Kood Sanstha, (Barwaripur) Kadipur - 228 145 Dt. Sultanpur (U.P.)	- do -	24,00,000	750 AECs
18.	Sarvodaya Shiksha Sadan, Lokmanpur, P.O. Baraut Dt. Allahabad (U.P.)	- do -	1,20,000	60 AECs
19.	U. P. Rana Beni Madhav Jan Kalyan Samiti Gulab Road, Rae Bareli (U.P.)	- do -	2,00,000	100 AECs
20.	Vinoba Seva Ashram P.O. Roja Junction Distt. Shahjahanpur (U.P.)	- do -	1,20,000	60 AECs

1	2	3	4	5
West Bengal :				
121.	Bengal Social Service League 16 Raja Dinandra Street, Calcutta (W. B.)	- do -	3,80,000	100 AECs
122.	Calcutta Urban Service Consortium, 16 Suddar Street, Calcutta (W. B.)	- do -	4,00,000	200 AECs
123.	Lok Shiksha Parishad Ramakrishna Mission Ashram P.O. Narenderpur Dt. 24-Parganas, Calcutta (W. B.)	- do -	2,00,000	100 AECs
124.	Rama Krishna Mission Janasikshamandira P.O. Balur Math Dt. Howrah - 711 202 (W. B.)	- do -	3,20,000	100 AECs
125.	Shree Ramakrishna Satyananda Ashram Vill. Jirabpur P. O. Basirhat, Distt. 24-Parganas, Calcutta (W. B)	- do -	6,00,000	300 AECs
126.	The Institute of Child Health 11 Dr. Biresh Guha Street, Calcutta (W. B.)	- do -	2,50,000	Action Research project included in 100 AECs
Delhi :				
127.	Bhartiya Adim Jati Sevak Sangh Dr. Ambedkar Marg, New Delhi - 110 055.	- do -	9,60,000	300 AECs
128.	Development Justice & Peace, Delhi Catholic Archdiocese Chetanalaya, Ashok Place, New Delhi - 110 001.	- do -	1,20,000	60 AECs
129.	Dr. A. V. Baliga Memorial Trust Link House, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi - 110 011.	- do -	9,60,000	300 AECs
130.	Gandhi Smarak Harijan Shiksha Samiti, 170 Balmiki Colony, Mandir Marg, Mandir Marg, New Delhi - 110 001.,	- do -	3,20,000	100 AECs
131.	Mahila Chetna Kendra F. 26, B. K. Dutt Colony Lodhi Road, New Delhi - 110 003.	- do -	3,20,000	100 AECs

1	2	3	4	5
132.	Ravi Bharati Shiksha Samiti, Bhola Nath Nagar, Shahdra, Delhi - 110 032.	- do -	3,20,000	100 AECs
133.	'Deepayatan' Bihar State Resource Centre for Adult Edn. Budha Colony, Patna.	For providing academic tech. support to Adult Education Programme.	33,06,000	For production of teaching/learning material and training of field functionaries in the Adult Education
134.	Registrar, Gujarat Vidyapeeth, Ahmedabad.	- do -	20,76,000	- do -
135.	Karnataka State Adult Education Council Kuvempunagar, Mysore.	- do -	22,78,000	- do -
136.	'KANFED' Shakshartha Bhawan, Trivandrum (Kerala)	- do -	7,78,000	- do -
137.	Director Indian Instt. of Education 128/2 JP Naik Road, Kotharod, Pune	- do -	27,78,000	- do -
138.	Rajasthan Adult Edn. Council, C-85, Ramdas Marg, Tilak Nagar, Jaipur.	- do -	22,78,000	- do -
139.	Tamil Nadu Board of Cont. Edn. West C. T. Nagar, Madras.	- do -	22,50,000	- do -
140.	Director, SRC, West Bengal 1/6, Raja Dinendra Stree Calcutta.	- do -	22,78,000	- do -
141.	Director, SRC Jamia Millia Islamia, Jamia Nagar, New Delhi. 25	- do -	9,50,000	- do -
142.	Chairman, Bhartiya Grameen mahila Sangh Indore (M.P.)	- do -	16,20,000	- do -
143.	Literacy House, P. O. Alambagh, Kanpur Road, Lucknow (U.P.)	- do -	42,20,000	- do - (Non-Plan)

NIEPA DC
D05410
Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B, Sri Aurobindo Marg, New Delhi-110016
DOC. No. D-5410
Date 13-9-90